

मूल निवासियों के अधिकारों पर संदर्भ नियमावली: हिंदी संस्करण

संदर्भ नियमावली

माननीय सर्वोच्च न्यायालय
के अनुसंधान एवं योजना केंद्र

हिंदी अनुवादक

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग
एवं
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दुर्ग
छत्तीसगढ़

- यह संदर्भ नियमावली अनुसूचित जनजातियों और मूल निवासियों के संवैधानिक, विधायी और नीतिगत अधिकारों का व्यापक विश्लेषण प्रस्तुत करती है। इसमें भारत सहित नौ देशों के तुलनात्मक अध्ययन के माध्यम से मूल निवासियों की सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों और सर्वोत्तम प्रथाओं को उजागर किया गया है।

नीति-निर्माताओं, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं, शोधकर्ताओं और न्यायिक अधिकारियों के लिए एक आवश्यक संसाधन

The image shows the exterior of a two-story building with a white facade and red horizontal bands. A large, light blue sign with blue text is mounted on the front. The sign reads 'जिला एवं सत्र न्यायालय' (District and Sessions Court) and 'दुर्ग (छ.ग.)' (Durg (C.G.)). The building has a covered entrance with steps leading up to a dark doorway. There are green trees on the left and right sides of the building. A motorcycle is parked on the left side in the foreground.

जिला एवं सत्र न्यायालय
दुर्ग (छ.ग.)

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अनुसंधान एवं योजना केंद्र
द्वारा प्रकाशित "मूल निवासियों के अधिकारों पर संदर्भ
नियमावली" के हिंदी अनुवाद संस्करण हेतु
गठित कमेटी



श्री के. विनोद कुजूर
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
दुर्ग, छ. ग.



श्रीमती सुषमा लकड़ा
अध्यक्ष, स्थायी लोक अदालत
दुर्ग, छ. ग.



श्री उमेश कुमार भागवतकर
सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
दुर्ग, छ. ग.



कु. आरती ध्रुव
अष्टम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी,
दुर्ग, छ. ग.

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग द्वारा संदेश



श्री के. विनोद कुजूर
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
दुर्ग, छ. ग.

भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अनुसंधान एवं योजना केंद्र द्वारा संकलित "मूल निवासियों के अधिकारों पर संदर्भ नियमावली" (Reference Manual on Rights of Indigenous Peoples) को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग की आधिकारिक वेबसाइट पर प्रस्तुत करते हुए मुझे अत्यंत गर्व और संतोष की अनुभूति हो रही है। न्याय का मूल उद्देश्य केवल कानूनी विवादों का समाधान करना ही नहीं है, बल्कि समाज के सबसे वंचित और हाशिए पर रहने वाले समूहों, विशेषकर हमारे जनजातीय भाई-बहनों को उनके संवैधानिक और वैधानिक अधिकारों के प्रति सचेत और सशक्त बनाना भी है।

छत्तीसगढ़ की पावन धरा, जो अपनी समृद्ध जनजातीय संस्कृति, परंपराओं और वनों के लिए विश्व विख्यात है, यहाँ के मूल निवासियों के लिए न्याय तक सहज पहुँच सुनिश्चित करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। हमारी मुख्य दूरदृष्टि यह रही है कि यह महत्वपूर्ण कानूनी ज्ञान केवल बड़े शहरों या अंग्रेजी भाषा तक सीमित न रहे। बस्तर के सुदूर वनांचलों से लेकर जशपुर के दुर्गम क्षेत्रों में निवास करने वाले हमारे जनजातीय भाई-बहन, जो अंग्रेजी भाषा से सहज रूप से अवगत नहीं हैं, वे भी अपनी सरल और बोधगम्य भाषा में इस नियमावली को पढ़कर अपने जल, जंगल, जमीन, सांस्कृतिक पहचान और संवैधानिक अधिकारों के प्रति जागरूक हो सकें।

इसी परिकल्पना को साकार करने के लिए हमने इस विस्तृत कानूनी दस्तावेज को स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप इसका सटीक हिंदी अनुवाद तैयार कराया है, ताकि जटिल विधिक भाषा किसी भी नागरिक के लिए ज्ञान के मार्ग में बाधा न बने। इस संपूर्ण दूरदर्शी पहल के सफल क्रियान्वयन हेतु हम छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश (प्रमुख संरक्षक, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण) एवं माननीय कार्यकारी अध्यक्ष, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के अमूल्य मार्गदर्शन, सतत प्रेरणा और उच्च स्तरीय पर्यवेक्षण के प्रति सहृदय आभार व्यक्त करते हैं। न्यायिक इतिहास के इस महत्वपूर्ण मोड़ पर, जहाँ हम मूल निवासियों के अधिकारों को मानवाधिकारों के एक अपरिहार्य हिस्से के रूप में देख रहे हैं, यह नियमावली हमारे जिले के न्यायिक अधिकारियों, अधिवक्ताओं और नीति निर्माताओं के लिए एक मार्गदर्शक का कार्य करेगी।

मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि जब तक अधिकार कागजों से निकलकर आम जनमानस की भाषा और समझ तक नहीं पहुँचते, तब तक न्याय का वास्तविक लक्ष्य अधूरा रहता है। जिला न्यायालय दुर्ग की यह पहल डिजिटल विधिक साक्षरता की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है। मैं इस परियोजना को मूर्त रूप देने वाली पूरी टीम की सराहना करता हूँ और आशा करता हूँ कि यह प्रकाशन भविष्य में जनजातीय न्यायशास्त्र पर होने वाली चर्चाओं और सुधारों के लिए एक सुदृढ़ आधार स्तंभ बनेगा। हम आने वाले समय में इस विषय पर सामूहिक विमर्श और निरंतर संवाद की मंगल कामना करते हैं।

अस्वीकरण (DISCLAIMER)

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA), दुर्ग (छत्तीसगढ़) द्वारा तैयार यह अनुवादित संस्करण मूल अंग्रेजी दस्तावेज ("Reference Manual on Rights of Indigenous Peoples") का हिंदी अनुवाद है; यह अनुवादित संस्करण केवल सामान्य पठन, अध्ययन, संदर्भ एवं विधिक जागरूकता के उद्देश्य से मानव प्रयास तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के सहयोग से तैयार किया गया है ताकि हितधारक और आम नागरिक इसे सुगमता से समझ सकें। यद्यपि अनुवाद में पूर्ण सटीकता बनाए रखने का हर संभव प्रयास किया गया है, फिर भी इसमें अनजाने में हुई किसी भी भाषाई या अर्थ संबंधी त्रुटि/खामी के लिए पाठकगण क्षमा प्रदान करें।

यह पुस्तक केवल एक सूचनात्मक संदर्भ सामग्री है जो किसी भी व्यक्ति, समुदाय या संस्था को कोई कानूनी अधिकार, दावा, पात्रता या दायित्व प्रदान या सृजित नहीं करती है, तथा किसी भी प्रकार के संशय, विसंगति, व्याख्या में अंतर या विवाद की स्थिति में मूल अंग्रेजी संस्करण ही सर्वोपरि, अंतिम और प्रमाणिक माना जाएगा; साथ ही, हाइपरलिंक एवं संदर्भ स्रोतों के मिलान में किसी भी प्रकार का भ्रम या त्रुटि न हो, इस हेतु मूल अंग्रेजी संस्करण के हेडर, फुटर, पाद-टिप्पणियों एवं वेब लिंक्स को यथावत रखा गया है।

द्वारा जारी:

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA)

दुर्ग (छत्तीसगढ़)



मूल निवासियों के अधिकारों पर संदर्भ पुस्तिका



अनुसंधान एवं योजना केंद्र (सीआरपी)
द्वारा तैयार किया गया
भारत का सर्वोच्च न्यायालय
नवंबर, 2025

उपलब्धियां

हम न्यायमूर्ति बी.आर.गवाई के प्रति अपना गहरा आभार व्यक्त करते हैं। बी.आर. गवाई, भारत के मुख्य न्यायाधीश, जिनके मार्गदर्शन और अनुसंधान और योजना केंद्र ('सीआरपी') को निरंतर प्रोत्साहन के कारण इस संदर्भ नियमावली को अंतिम रूप दिया गया है। हम श्री शेखर सी. मुंघाटे, एलडी को भी धन्यवाद देते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के महासचिव को, पूरी प्रक्रिया के दौरान उनके निरंतर मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद। हम सीआरपी के कर्मचारियों को उनकी शोध सहायता और समर्थन के लिए भी आभारी हैं। हम जयदीप फाइंडोरिया, सुप्रिया राय और निकेत नलिन को भी कॉपी एडिटिंग में उनकी सहायता के लिए धन्यवाद देते हैं।

तैयारकर्ता

अनुसंधान एवं योजना केंद्र (सीआरपी) भारत का सर्वोच्च न्यायालय (2025)

योगदानकर्ता

डॉ. अनुराग भास्कर, अतिरिक्त रजिस्ट्रार-सह-निदेशक, सीआरपी पद्मजा मेनन, सलाहकार (अनुसंधान) सीआरपी भूमिका बब्बर, लॉ क्लर्क-सह-रिसर्च एसोसिएट, सीआरपी मेघा बिंदल, लॉ क्लर्क-सह-रिसर्च एसोसिएट, सीआरपी

इनपुट प्रदाता

शुभम कुमार, सलाहकार (अनुसंधान) सीआरपी

राजेश रंजन, सलाहकार (अनुसंधान) सीआरपी सृष्टि शर्मा, सलाहकार (अनुसंधान) सीआरपी

शांभवी गुप्ता, लॉ क्लर्क-कम-रिसर्च एसोसिएट, सीआरपी

आवरण रूपांकन

अजयेंद्र नाथ त्रिपाठी, सलाहकार (प्रौद्योगिकी) सीआरपी

अनुक्रमणिका

संक्षेपाक्षर की सूची	4
मामलों की सूची	7
अध्याय I. परिचय.....	11
1. उद्देश्य	11
2. कार्यप्रणाली और शामिल क्षेत्राधिकार	12
3. परिभाषा: 'स्वदेशी लोग' कौन हैं?	13
अध्याय II. अंतर्राष्ट्रीय मानक	23
1. आत्मनिर्णय, स्वशासन, सहभागिता, परामर्श और स्वतंत्र पूर्व-सूचित सहमति	26
2. भूमि, वन और संसाधन	35
3. आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक सुरक्षा उपाय	41
4. बोली	47
5. शिक्षा	50
6. पारंपरिक ज्ञान	53
7. स्वदेशी कानूनी प्रणाली और न्याय तक पहुंच	56
8. सतत पर्यावरण प्रबंधन	61
परिशिष्ट ए: स्वदेशी अधिकारों के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानूनी ढांचा	66
परिशिष्ट बी: स्वदेशी अधिकारों के संरक्षण से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय कानूनी उपकरणों के अनुसमर्थन या अपनाने की देशवार स्थिति	74
अध्याय III. भारतीय संवैधानिक, विधायी और संस्थागत ढाँचे	80
1. अनुसूचित जनजातियों के साथ ऐतिहासिक व्यवहार	80
1.1 औपनिवेशिक काल से पहले का उत्पीड़न	80
1.2 औपनिवेशिक 'अन्यीकरण'	81
1.3 संवैधानिक सभा की बहसों में मान्यता	88
2. संवैधानिक पदनाम	94
2.1 अनुसूचित जनजातियाँ	94
2.2 अनुसूचित क्षेत्र	95
3. संवैधानिक सुरक्षा उपाय	99

3.1 समानता और गैर-भेदभाव.....	99
3.2 शिक्षा और सार्वजनिक रोजगार में आरक्षण.....	102
3.3 राजनीतिक प्रतिनिधित्व और स्वशासन	107
3.4 भूमि एवं संसाधनों पर स्वायत्तता	114
3.5 सांस्कृतिक एवं धार्मिक स्वतंत्रताएँ.....	116
4. विधायी सुरक्षा.....	119
4.1 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989.....	119
4.2 पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996.....	124
4.3 अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारंपरिक वनवासी (वन अधिकार मान्यता) अधिनियम, 2006	127
4.4 भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित मुआवजे और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013	130
खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957.....	135
व्यक्तिगत कानून	136
श्रम कानून.....	140
5. संस्थागत पहल	141
प्रमुख कल्याणकारी योजनाएँ	141
सरकारी निकाय	150
अध्याय IV. तुलनात्मक संवैधानिक, विधायी और संस्थागत उपाय.....	155
1. नॉर्डिक देश.....	155
1.1 नॉर्वे	155
1.2 स्वीडन	163
1.3 फिनलैंड.....	166
2. ओशिनिया	170
2.1 ऑटोरोआ (न्यूजीलैंड)	170
2.2 ऑस्ट्रेलिया	177
3. उत्तरी अमेरिकी देश	185
3.1 कनाडा	185
3.2 संयुक्त राज्य अमेरिका	192
4. दक्षिण अमेरिकी देश.....	199
4.1 इक्वेडोर	199
4.2 कोलंबिया	204
4.3 ब्राज़िल	209
परिशिष्ट सी: आगे पढ़ने के लिए सुझाए गए लेख.....	213
अध्याय V. निष्कर्ष	222

संक्षेपाक्षर की सूची

एटीएसआईसी	आदिवासी और टोरेस स्ट्रेट द्वीपवासियों आयोग	सीबीडी	संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन, 1992
सीसीडी	संरक्षण सह-विकास	सीडीई	शिक्षा में भेदभाव के खिलाफ सम्मेलन, 1950
सीईडीएडब्ल्यू	महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन पर सम्मेलन, 1979	सी ई आर डी	नस्लीय भेदभाव उन्मूलन समिति
सीईएससीआर	आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर समिति	सीएनपीआई	राष्ट्रीय स्वदेशी नीति परिषद
सीआरसी	बाल अधिकारों पर सम्मेलन, 1989	डीएपीएसटी	अनुसूचित जनजातियों के लिए विकास कार्य योजना
डीएमएफ	जिला खनिज फाउंडेशन	ईएमआरएस	एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय
एफ आई आर	प्रथम सूचना रिपोर्ट	एफपीआईसी	स्वतंत्र, पूर्व और सूचित सहमति
एफआरए, 2006	वन अधिकार अधिनियम, 2005	एफ यू एन ए आई	स्वदेशी लोगों का राष्ट्रीय फाउंडेशन
जी आर ए टी के	आनुवंशिक संसाधन और संबंधित पारंपरिक ज्ञान, 2024	हामा, 1956	हिंदू दत्तक ग्रहण एवं भरण-पोषण अधिनियम, 1955
एचएमए, 1955	हिंदू विवाह अधिनियम, 1955	एचएमजीए, 1956	हिंदू अल्पसंख्यक एवं संरक्षकता अधिनियम, 1955
एचआरसी	मानवाधिकार समिति	एचएसए, 1956	हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1955
आईसीसीपीआर	नागरिक एवं राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय समझौता, 1955	आईसीईआरडी	नस्लीय भेदभाव के सभी रूपों के उन्मूलन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, 1955
आईसीईएससी आर	आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय समझौता, 1955	आईएलओ	अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन

आईपीसी, 1860	भारतीय दंड संहिता, 1850	आईएसए, 1925	भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925
लारैक्ट, 2013	भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन अधिनियम, 2013	एमएफपी	लघु वन उत्पाद
एमएमडीआरसी एटी, 1957	खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957	एमएसपी	न्यूनतम समर्थन मूल्य
एन.सी.एस.टी.	राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग	एनईएसटीएस	जनजातीय छात्रों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा समिति
एनएसटीएफडी सी	राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम	एन टी आर आई	राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान
ओएचसीएचआर	संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय	ओआईपीसी	स्वदेशी नीति समन्वय कार्यालय
ओटीएफडी	अन्य पारंपरिक वनवासी	पेसा अधिनियम, 1996	पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार) अधिनियम, 1995
पीएफएम	सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली	पीएम-जनमान	प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान
पीएमएजीवाई	प्रधानमंत्री आदिआदर्श ग्रामयोजना	पीएमजेवीएम	प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन
पीओएसीटी , 1989	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989	पीवीटीजी	विशेष रूप से संवेदनशील जनजातीय समूह
एससीए	राज्य चैनलिंग एजेंसी	एसडीजी	सतत विकास लक्ष्य
एस एच जी	स्वयं सहायता समूह	एसआईए	सामाजिक प्रभाव आकलन
एसएमए, 1954	विशेष विवाह अधिनियम, 1954	ट्राई-ईसीई	जनजातीय अनुसंधान सूचना, शिक्षा, संचार और कार्यक्रम
ट्राइफेड	जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ, भारतीय लिमिटेड	ट्रिप्स	बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार संबंधी पहलुओं पर समझौता, 1995
टी.आर.आई	जनजातीय अनुसंधान संस्थान	यूजीसी	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

संयुक्त राष्ट्र	संयुक्त राष्ट्र	यू एन ड्रिप	संयुक्त राष्ट्र की स्वदेशी लोगों के अधिकारों पर घोषणा
यूनेस्को	संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन	यूएनपीएफआईआई	स्वदेशी मुद्दों पर संयुक्त राष्ट्र स्थायी मंच
यूएनडब्ल्यूजीआईपी	संयुक्त राष्ट्र स्वदेशी आबादी कायम समूह	वीडीएसएचजी	वन्धन स्वयं सहायता समूह
वीडीवीके	वनधनविकास केंद्र	वीजीएफएन	वुनटुट ग्विचिन फर्स्ट नेशन
वीजीजीटी	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के संदर्भ में भूमि, मत्स्य पालन और वन के कार्यकाल के उत्तरदायी शासन पर स्वैच्छिक दिशानिर्देश, 2012	डब्ल्यूआईपीओ	विश्व बौद्धिक संपदा संगठन
डब्ल्यू टी ओ	विश्व व्यापार संगठन		

मामलों की सूची

भारत

1. महाराष्ट्र राज्य में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को जाति प्रमाण पत्र जारी करने पर कार्रवाई समिति बनाम भारत संघ (1994) 5 एससीसी 244।
2. अंजन कुमार व. यूनियन ऑफ इंडिया (2006) 3 एस सी सी 257।
3. भैयाराम मुंडा बनाम अनिरुद्ध पाटार (1970) 2 एस सी सी 825।
4. चेब्रो लु लीलाप्रसाद राव बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, 2020 एससीसी ऑनलाइन एससी 383।
5. दीना बनाम नारायण सिंह, 1968 एससीसी ऑनलाइन एससी 326।
6. डॉ. सूरजमणि स्टेला कुजूर बनाम दुर्गाचरण हंसदाह (2001) 3 एस सी सी 13।
7. फेडरेशन ऑफ इंडियन मिनरल इंडस्ट्रीज बनाम यूनियन ऑफ इंडिया (2017) 16 एस सी सी 186।
8. फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बनाम जगदीश बलराम बहिरा (2017) 8 एस सी सी 670।
9. हरिराम भाम्भी बनाम सत्यनारायण, 2021 आई एन एस सी 701।
10. हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण बनाम निर्मला देवी, 2025 एस सी सी ऑनलाइन एस सी 1049।
11. इंदौर विकास प्राधिकरण बनाम मनोहरलाल (2020) 8 एस सी सी 129।
12. इंद्र साहनी बनाम भारत संघ, 1992 अनुपूरक (3) एस सी सी 217।
13. इन रे टी. एन. गोदावर्मन थिरुमुलपाद बनाम भारत संघ, 2024 आई एन एस सी 997।
14. जरनैल सिंह बनाम लक्ष्मी नारायण गुप्ता (2018) 10 एस सी सी 396।
15. कैलास बनाम महाराष्ट्र राज्य (2011) 1 एस सी सी 793।
16. कमला नेति बनाम भूमि अधिग्रहण अधिकारी (2023) 3 एस सी सी 528।
17. खुमान सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य (2019) एससीसी ऑनलाइन एससी 1104।
18. कुमारी माधुरीपतिल व. अपर आयुक्त, जनजातीय विकास (1994) 6 एससीसी 241।
19. लिंगप्पा पोचन्ना अप्पेलवरव। महाराष्ट्र राज्य (1985) 1 एससीसी 479।
20. एम. नागराज बनाम यूनियन ऑफ इंडिया (2006) 8 एस सी सी 212।
21. मधु किश्वर बनाम स्टेट ऑफ बिहार (1996) 5 एससीसी 125।
22. महानंदी कोलफील्ड्स लिमिटेड v. मैथियास ओराम, 2022 आई एन एस सी 1158।
23. मर्री चंद्र शेखर बनाम डीन, सेठ जी. एस. मेडिकल कॉलेज (1990) 3 एससीसी 130।
24. नंदिनी सुंदर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य (2011) 7 एससीसी 547।
25. नर्मदा बचाओ आंदोलन बनाम भारत संघ, 2000 (10) एससीसी 664।
26. दलित मानवाधिकारों पर राष्ट्रीय अभियान बनाम भारत संघ (2017) 2 एससीसी 432।
27. उड़ीसा माइनिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम पर्यावरण और वन मंत्रालय (2013) 6 एससीसी 476।
28. पाटन जमाल वली बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, 2021 एससीसी ऑनलाइन एससी 343।
29. पृथ्वी राज चौहान बनाम भारत संघ (2020) 4 एस सी सी 727।
30. एस. जगन्नाथ बनाम भारत संघ (1997) 2 एस सी सी 87।
31. समथ व. आंध्र प्रदेश राज्य (1997) 8 एससीसी 191।
32. एस. आर. बोम्म बनाम भारत संघ (1994) 3 एससीसी 1.

33. कर्नाटक राज्य बनाम अप्पा बालू इंगले, 1995 अनुपूरक (4) एससीसी 469।
34. केरल राज्य बनाम एन.एम. थॉमस (1976) 2 एससीसी 310।
35. केरल राज्य बनाम पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज (2009) 8 एससीसी 46।
36. मध्य प्रदेश राज्य बनाम रामकृष्ण बलोठिया (1995) 3 एससीसी 221।
37. महाराष्ट्र राज्य बनाम मिलिंद (2001) 1 एससीसी 4।
38. नागालैंड राज्य बनाम रतन सिंह, 1966 एससीसी ऑनलाइन एससी 114।
39. सुभाष काशीनाथ महाजन बनाम महाराष्ट्र राज्य (2018) 6 एससीसी 454।
40. सुकन्या शांता बनाम यूनियनऑफ इंडिया, 2024एस सी सी ऑनलाइन एस सी 2694।
41. टी.एन.गोदावर्मन थिरुमुल्कपैड बनाम यूनियनऑफइंडिया, 19972 एस सी सी267।
42. तिरिथकुमार व.दादुराम, 2024 आईएनएससी 1005.
43. यूनियन ऑफ इंडिया बनाम राकेश कुमार (2010) 4 एस सी सी 50।
44. यूनियन ऑफ इंडिया बनाम स्टेटऑफमहाराष्ट्र (2020) 4एससीसी 761।
45. विलास पांडुरंग पवार बनाम महाराष्ट्र राज्य (2012) 8 एस सी सी 795.

नॉर्वे

1. फेमंड सिज्ते मामला, नॉर्वे का सर्वोच्च न्यायालय, एचआर-2018-872-ए (2018)।
2. फिनमार्क एस्टेट बनाम काराजोक सामी एसोसिएशन, नॉर्वे का सर्वोच्च न्यायालय, एचआर-2024-982-एस (2024)।
3. फोसेन मामला, नॉर्वे का सर्वोच्च न्यायालय, एचआर-2021-1975-एस (2021)।
4. सारा मामला, नॉर्वे का सर्वोच्च न्यायालय, एचआर-2017-2428-ए (2017)।

स्वीडन

1. नॉर्डमलिंग, स्वीडन का सर्वोच्च न्यायालय, टी 4028-07 (2011)।
2. करयुक्त पर्वत, स्वीडन का सर्वोच्च न्यायालय, एन जे ए1981 धारा 1 (1981)।
3. गिरजासस *मामला, स्वीडन का सर्वोच्च न्यायालय, टी853-18 (2020)।*

न्यूजीलैंड

1. एलिस बनाम आर, न्यूजीलैंड का सर्वोच्च न्यायालय, एनजेडएससी 114 (2022)।
2. न्यूजीलैंड माओरी परिषद बनाम अटॉर्नी जनरल, न्यूजीलैंड का सर्वोच्च न्यायालय, एनजेडएलआर 641 (1987)।
3. वाकातु की संपत्तियां बनाम अटॉर्नी जनरल, न्यूजीलैंड का सर्वोच्च न्यायालय, एनजेडएससी 17 (2017)।
4. ते रुनांगाओ व्हारेकाउरी रेकोहु इंक बनाम अटॉर्नी जनरल, न्यूजीलैंड अपील न्यायालय, 2 एनजेडएलआर 301 (सीए) (1993)।
5. ते वेही बनाम क्षेत्रीय मत्स्य अधिकारी, न्यूजीलैंड का सर्वोच्च न्यायालय, 1 एनजेडएलआर 682 (1986)
6. ट्रांस-तस्मान रिसोर्सेज लिमिटेड बनाम द तारानाकी-वांगानुई कंजर्वेशन बोर्ड, न्यूजीलैंड का सर्वोच्च न्यायालय, एनजेडएससी 127 (2021)

ऑस्ट्रेलिया

1. डेविड एलन गेरहार्डी बनाम रॉबर्ट जॉन ब्राउन, ऑस्ट्रेलिया का उच्च न्यायालय, 159 ए.एल.जे.आर. 311 (1985)।
2. माब बनाम क्वींसलैंड, ऑस्ट्रेलिया का उच्च न्यायालय, 175 सीएलआर 1 एफसी92/014 (1992)

कनाडा

1. कैल्डर एट अल. बनाम अटॉर्नी-जनरल ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया, कनाडा का सर्वोच्च न्यायालय, एससीआर 313 (1973)।
2. डेलगमुक बनाम ब्रिटिश कोलंबिया, कनाडा का सर्वोच्च न्यायालय, एससीआर 1010 (1997)।
3. डिक्सन बनाम वुंटुटग्विचिन फर्स्ट नेशन, कनाडा का सर्वोच्च न्यायालय, एससीसी 10 (2024)।
4. हैडा नेशन बनाम ब्रिटिश कोलंबिया (वन मंत्री), कनाडा का सर्वोच्च न्यायालय, एससीआर 511 (2004)।
5. मिकिसेव क्री फर्स्ट नेशन बनाम कनाडा (गवर्नर जनरल काउंसिल), कनाडा का सर्वोच्च न्यायालय, एससीआर 765 (2018)।
6. ओटोरियो (अटॉर्नी जनरल) बनाम रेस्टूल, कनाडा का सर्वोच्च न्यायालय, एससीसी 27 (2024)।
7. आर.वी. सिओई, कनाडा का सर्वोच्च न्यायालय, 1एससीआर 1025 (1990)।
8. आर.वी. स्पैरो, कनाडा का सर्वोच्च न्यायालय, 1एससीआर 1075 (1990)।
9. आर.वी. वैंडरपीट, कनाडा का सर्वोच्च न्यायालय, 2एससीआर 507 (1996)।

संयुक्त राज्य अमेरिका

1. चैरोकी नेशन बनाम जॉर्जिया, संयुक्त राज्य अमेरिका का सर्वोच्च न्यायालय, 30 यू.एस.1 (1831)।
2. मैकगर्ट बनाम ओक्लाहोमा, संयुक्त राज्य अमेरिका का सर्वोच्च न्यायालय, 140 एस.सी.टी. 2452 (2020)।
3. ओक्लाहोमा बनाम कास्त्रो-हर्टा, संयुक्त राज्य अमेरिका का सर्वोच्च न्यायालय, 142 एस.सी.टी. 2486, 2500-01 (2022)।
4. ओलिवेंट बनाम सुकामिश इंडियन ट्राइब्स, संयुक्त राज्य अमेरिका का सर्वोच्च न्यायालय, 435 यू.एस. 191 (1978)।
5. एकतरफा क्रो डॉग मामला, संयुक्त राज्य अमेरिका का सर्वोच्च न्यायालय, 109 यू.एस. 556 (1883)।
6. यूनाइटेड स्टेट्स बनाम एंटेलोप, संयुक्त राज्य अमेरिका का सर्वोच्च न्यायालय, 430 यू.एस. 641 (1977)।
7. यूनाइटेड स्टेट्स बनाम माजुरी, संयुक्त राज्य अमेरिका का सर्वोच्च न्यायालय, 419 यू.एस. 544 (1975)।
8. यूनाइटेड स्टेट्स बनाम व्हीलर, संयुक्त राज्य अमेरिका का सर्वोच्च न्यायालय, 435 यू.एस. 313 (1978)।
9. विलियम्स बनाम ली, संयुक्त राज्य अमेरिका का सर्वोच्च न्यायालय, 358 यू.एस. 217 (1959)।
10. वॉर्सेस्टर बनाम जॉर्जिया, संयुक्त राज्य अमेरिका का सर्वोच्च न्यायालय, 31 यू.एस. 515 (1832)।

इक्वाडोर

1. सिनांगो समुदाय के ए आईसीओ, ऊर्जा एवं गैर-नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन मंत्री, इक्वाडोर का संवैधानिक न्यायालय, निर्णय संख्या 273-19-जेपी/22 (2022)।
2. विक्टर मैनुअल ओलिवो पल्लो, ला कोचा समुदाय मामला, इक्वाडोर का संवैधानिक न्यायालय, निर्णय संख्या 0731-10-ईपी (2014)।

कोलंबिया

1. सेंटर ऑफ सोशल जस्टिस स्टडी सेट. ए एल. वी. प्रेसीडेंसी ऑफ द रिपब्लिकेट.ए.एल., सुप्रीम कोर्ट ऑफ कोलंबिया, जजमेंट टी-622/16 (2016)।
2. ग्रुपो डी इंटरस पब्लिको यूनिवर्सिडैड डी लॉस एंडीज़ एट। अल. बनाम कांग्रेसो डी कोलम्बिया, कोलम्बिया का संवैधानिक न्यायालय, निर्णय सी-335/07 (2008)।
3. कोलंबिया का संवैधानिक न्यायालय, निर्णयसी-054(2023)।
4. स्वदेशी समुदायों में नाबालिग लड़कियों से जुड़े नागरिक विवाहों और संघों की शून्यता, कोलंबिया का संवैधानिक न्यायालय, निर्णयसी-039/25(2025)।
5. कोलंबियाई अमेज़न के स्वदेशी लोगों का संगठन (OPIAC) बनाम गणतंत्र के राष्ट्रपति, कोलंबिया का संवैधानिक न्यायालय, निर्णय SU-383/03 (2003)।

6. पाएज़ स्वदेशी समुदाय मामला, कोलंबिया का संवैधानिक न्यायालय, निर्णय T-523/97 (1997)।
7. कोलंबिया का संवैधानिक न्यायालय, निर्णय टी -530 (2016)।
8. कोलंबिया का संवैधानिक न्यायालय, निर्णय

ब्राज़ील

1. *रापोसासेराडोसोल, ब्राजील का सर्वोच्च संघीय न्यायालय, एडीआई3239 (2009)*

अध्याय I: परिचय

1. उद्देश्य

मूल निवासी (स्वदेशी लोग), 70 देशों में लगभग 370 मिलियन व्यक्ति,¹ दुनिया के सबसे बेदखल, वंचित और हाशिए पर रहने वाले समूहों में से हैं, जिन्हें कभी-कभी 'चौथी दुनिया' के रूप में जाना जाता है।² हालांकि वैश्विक आबादी का केवल 6 प्रतिशत हिस्सा है, वे ग्रह की जैव विविधता के लगभग 80 प्रतिशत और पारिस्थितिक रूप से अक्षुण्ण परिदृश्य के 40 प्रतिशत के संरक्षक हैं।³ स्वदेशी लोगों का उनकी पैतृक भूमि, पारंपरिक क्षेत्रों और प्राकृतिक संसाधनों के साथ संबंध उनके अस्तित्व के लिए केंद्रीय है।⁴ किसी क्षेत्र के मूल निवासी माने जाने वाले लोगों के वंशज होने के बावजूद, उपनिवेशीकरण, विजय, बस्ती और कब्जे के कारण मूल निवासी को बाहर रखा गया है, और उनकी अंतर्निहित संप्रभु शक्तियों की अनदेखी की गई है।⁵ फिर भी, स्वदेशी लोग प्रतिरोध, संपर्क और/या गैर-स्वदेशी समुदायों के साथ सहयोग के उथल-पुथल भरे इतिहास के माध्यम से सहस्राब्दियों से अपनी अनूठी पहचान बनाए रखने में कामयाब रहे हैं।⁶

इस पृष्ठभूमि में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अनुसंधान और योजना केंद्र ने भारत के लिए अद्वितीय संवैधानिक, विधायी और संस्थागत तंत्र पर विशेष ध्यान देने के साथ, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तरों पर मान्यता प्राप्त स्वदेशी लोगों के अधिकारों को उजागर करने के लिए यह संदर्भ नियमावली तैयार की है। अतः यह संदर्भ नियमावली निम्नलिखित उद्देश्यों को पूरा करने का प्रयास करती है:

- अंतर्राष्ट्रीय कानूनी साधनों की पहचान करें जो स्वदेशी लोगों के आत्मनिर्णय, स्व-शासन, भागीदारी और परामर्श के अधिकारों की स्पष्ट रूप से या निहित रूप से रक्षा करते हैं; भूमि, वन और संसाधन; आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक सुरक्षा; भाषाएं; शिक्षा; पारंपरिक ज्ञान; न्याय तक पहुंच; और टिकाऊ पर्यावरण प्रबंधन।
- स्वदेशी अधिकारों के संबंध में भारत के पूर्व-औपनिवेशिक, औपनिवेशिक और उत्तर-औपनिवेशिक ऐतिहासिक प्रक्षेपवक्र को प्रासंगिक बनाना, आज के अधिकार-आधारित दृष्टिकोण के विकास को चित्रित करना।
- अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए भारत द्वारा अपनाए गए संवैधानिक, विधायी और नीतिगत उपायों की व्याख्या करें,

¹ United Nations Department of Economic and Social Affairs, *State of the World's Indigenous Peoples, Climate Crisis*, Vol. VI (Apr. 2025), p. no. 3; United Nations Permanent Forum on Indigenous Issues, *Indigenous Peoples, Indigenous Voices*, p. no. 1, available at: https://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/5session_factsheet1.pdf (last visited on Oct. 5, 2025).

² Katja Göcke, "Indigenous Peoples in International Law", in Brigitta Hauser-Schäublin (ed.), *Adat and Indigeneity in Indonesia: Culture and Entitlements between Heteronomy and Self-Ascription* 20 (Göttingen University Press, 2017).

³ United Nations Department of Economic and Social Affairs, *State of the World's Indigenous Peoples, Climate Crisis*, Vol. VI (Apr. 2025), p. no. 3.

⁴ *Ibid.*

⁵ United Nations Permanent Forum on Indigenous Issues, *Indigenous Peoples, Indigenous Voices*, p. no. 2, available at: https://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/5session_factsheet1.pdf (last visited on Oct. 5, 2025).

⁶ United Nations Department of Economic and Social Affairs, *State of the World's Indigenous Peoples, Climate Crisis*, Vol. I (May 2011), p. nos. 1, 2.

जिसमें उनकी पहचान की संवैधानिक मान्यता और समानता और गैर-भेदभाव के उनके अधिकार; आरक्षण; राजनीतिक प्रतिनिधित्व और स्व-शासन; संसाधनों पर स्वायत्तता; सांस्कृतिक और धार्मिक स्वतंत्रता; और सामाजिक-आर्थिक न्याय शामिल हैं।

- स्वदेशी लोगों के आत्मनिर्णय, स्व-शासन और भागीदारी के अधिकारों को संबोधित करने में चुनिंदा क्षेत्राधिकारों द्वारा नियोजित विविध रणनीतियों का तुलनात्मक विवरण प्रदान करें; भूमि, वन और संसाधनों का स्वामित्व और/या उपयोग; संस्कृति, परंपरा, धर्म और भाषा का संरक्षण; प्रथागत कानूनी प्रणालियाँ; परामर्श; और सकारात्मक कार्यवाई।
- स्वदेशी लोगों के अधिकारों की मान्यता, संरक्षण और संवर्धन में वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं पर प्रकाश डालें जो संभावित रूप से भारतीय घरेलू ढांचे के भीतर संवैधानिक, कानूनी या प्रशासनिक सुधार को सूचित कर सकते हैं।
- स्वदेशी अधिकारों से संबंधित कानूनी, न्यायिक और विद्वतापूर्ण संसाधनों के भंडार के रूप में कार्य करना, आगे के शोध को सुविधाजनक बनाने के साथ-साथ हितधारकों, कानूनी व्यवसायियों, नीति निर्माताओं, शिक्षाविदों और अन्य इच्छुक पक्षों को स्वदेशी लोगों से संबंधित समेकित जानकारी (हालांकि गैर-विस्तृत) तक पहुंचने में सक्षम बनाना।

2. कार्यप्रणाली और शामिल क्षेत्राधिकार

यह संदर्भ नियमावली एक तुलनात्मक दृष्टिकोण द्वारा पूरक, सैद्धांतिक कानूनी अनुसंधान में स्थापित एक गुणात्मक पद्धति को अपनाती है। भारत में अनुसूचित जनजातियों पर विशेष ध्यान देने के साथ, वैश्विक, क्षेत्रीय और घरेलू स्तरों पर स्वदेशी लोगों को दी गई संवैधानिक, वैधानिक और संस्थागत गारंटी का पता लगाने के लिए, यह संदर्भ नियमावली निम्नलिखित प्राथमिक स्रोतों पर निर्भर करती है:

- अंतर्राष्ट्रीय कानूनी उपकरण (चाहे बाध्यकारी हों या नहीं)
- संवैधानिक प्रावधान;
- विधायी अधिनियम;
- न्यायिक घोषणाएं;
- नीतिगत ढांचे;
- ऐतिहासिक रिकॉर्ड, अन्य बातों के साथ।

यह संदर्भ नियमावली उद्धृत प्राथमिक स्रोतों की व्याख्या और स्पष्टीकरण में सहायता के लिए अंतर-सरकारी, सरकारी और गैर-सरकारी निकायों के दस्तावेजों के साथ-साथ अकादमिक प्रकाशनों सहित माध्यमिक स्रोतों पर भी ध्यान आकर्षित करती है।

भारत पर मुख्य रूप से ध्यान केंद्रित करते हुए, यह संदर्भ नियमावली स्वदेशी अधिकारों के संरक्षण के लिए निम्नलिखित देशों में स्थापित संवैधानिक, विधायी

और नीतिगत उपायों को भी चित्रित करती है:

- नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड (नॉर्डिक)
- आटेरोआ (न्यूजीलैंड) ऑस्ट्रेलिया (ओशिनिया)
- कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका (उत्तरी अमेरिका)
- इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील (दक्षिण अमेरिका)

उपर्युक्त क्षेत्राधिकारों को निम्नलिखित कारकों को ध्यान में रखते हुए तुलनात्मक अध्ययन के लिए सावधानीपूर्वक चुना गया है:

- अपनी क्षेत्रीय सीमाओं के भीतर स्वदेशी लोगों की एक महत्वपूर्ण आबादी की उपस्थिति;
- स्वदेशी लोगों और उनके अधिकारों को मान्यता देने के लिए विभिन्न प्रकार के संवैधानिक, वैधानिक और नीतिगत मॉडल; और
- आर्थिक प्रगति, भौगोलिक स्थानों और स्वदेशी लोगों के साथ ऐतिहासिक बातचीत की प्रकृति में विविधता।

यह संदर्भ नियमावली स्वदेशी अधिकारों के व्यापक संदर्भ में अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों को पहचानने, उनकी रक्षा करने और बढ़ावा देने के लिए भारतीय दृष्टिकोण को स्थापित करने की आवश्यकता से निर्देशित है। यह संदर्भ नियमावली अंतर्राष्ट्रीय मानकों, संवैधानिक, विधायी और नीतिगत सर्वोत्तम प्रथाओं और स्वदेशी लोगों के अधिकारों को सुरक्षित करने में न्यायिक सक्रियता की रूपरेखा को उजागर करने का भी काम करती है जो अनुसूचित जनजातियों और अन्य आदिवासी समुदायों के लिए एक मजबूत सुरक्षात्मक पारिस्थितिकी तंत्र तैयार करने की दिशा में भारतीय संसदीय, कार्यकारी और न्यायिक प्रयासों को सूचित कर सकती है।

3. परिभाषा: 'स्वदेशी लोग' कौन हैं?

व्युत्पत्ति के अनुसार, 'इंडिगेनाए' शब्द लैटिन शब्द 'इंडिजेनस' से निकला है, जो उन लोगों को दर्शाता है जो एक निश्चित स्थान पर पैदा हुए थे, इसके विपरीत 'एडवेने', जिसका अर्थ है वे जो कहीं और से आए थे।⁷

'स्वदेशी' इसलिए यह सुझाव देता है कि जिस समूह को यह संदर्भित करता है, वह विशेष स्थान पर मौजूद होने वाला पहला समूह था, जो किसी दिए गए क्षेत्र में उनकी उपस्थिति के रूप में "समय में प्राथमिकता" की अंतर्निहित अवधारणा पर आधारित था, यदि प्राचीन अधिभोग नहीं।⁸ ऐतिहासिक रूप से, 'स्वदेशी' लेबल का उपयोग औपनिवेशिक शक्तियों और औपनिवेशिक प्रभुत्व के तहत रहने वाले लोगों के बीच अंतर करने के लिए किया जाता था।⁹ इस संदर्भ में, स्वदेशी आबादी को "आधुनिक दुनिया की कठिन परिस्थितियों में अभी तक खुद से खड़े होने में असक्षम लोगों"

⁷ Erica-Irene A. Daes, *Working paper on the concept of indigenous people*, UN Doc E/CN.4/Sub.2/ACU/1996/2 (Jun. 10, 1996), para. 10.

⁸ *Ibid.*; Benedict Kingsbury, "'Indigenous Peoples' in International Law: A Constructivist Approach to the Asian Controversy" 92(3) *The American Journal of International Law* 422 (1998).

⁹ Erica-Irene A. Daes, *Working paper on the concept of indigenous people*, UN Doc E/CN.4/Sub.2/ACU/1996/2 (Jun. 10, 1996), para. 12; Benedict Kingsbury, "'Indigenous Peoples' in International Law: A Constructivist Approach to the Asian Controversy" 92(3) *The American Journal of International Law* 426 (1998).

के रूप में वर्णित किया गया है।¹⁰ उनके 'पिछड़ेपन' के कारण, उन्हें 'उन्नत' राष्ट्रों के संरक्षण की आवश्यकता के रूप में देखा गया, ¹¹ बल "अपनी भलाई के लिए", मुख्यधारा के समाज में उनका "एकीकरण", इस प्रकार उनकी सांस्कृतिक, पारंपरिक, भाषाई, धार्मिक और जातीय विशेषताओं को दबाना या नष्ट करना, एक ऐसी रणनीति जिसे 16वीं शताब्दी से 20वीं शताब्दी तक अच्छी तरह से अपनाया गया था।¹² अपने चरम पर, एकीकरण के उपायों के कड़े कार्यान्वयन के कारण अक्सर स्वदेशी आबादी के मानवाधिकारों का घोर उल्लंघन और इससे भी बदतर, उनका जातीय नरसंहार होता है।¹³

आज, हालाँकि 'स्वदेशी लोगों' की कोई सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत कानूनी परिभाषा नहीं है, लेकिन 'स्वदेशी' पहचान की अवधारणा के लिए कई प्रयास किए गए हैं।¹⁴ अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आई. एल. ओ.) स्वदेशी और जनजातीय जनसंख्या सम्मेलन, 1957 (सामान्यतः आई. एल. ओ. सम्मेलन सं. 107) इस संबंध में पहला अंतर्राष्ट्रीय प्रयास था। आईएलओ कन्वेंशन नं. 107 ने निम्नलिखित शब्दों में 'आदिवासी आबादी' और 'स्वदेशी आबादी' की विशेषता बताई: ¹⁵ "(क) स्वतंत्र देशों में जनजातीय या अर्ध-जनजातीय आबादी के सदस्य जिनकी सामाजिक और आर्थिक स्थितियाँ राष्ट्रीय समुदाय के अन्य वर्गों द्वारा पहुँचाए गए स्तर की तुलना में कम उन्नत स्तर पर हैं, और जिनकी स्थिति पूरी तरह से या आंशिक रूप से उनके अपने रीति-रिवाजों या परंपराओं या विशेष कानूनों या विनियमों द्वारा विनियमित की जाती है; (ख) स्वतंत्र देशों में जनजातीय या अर्ध-जनजातीय आबादी के सदस्य जिन्हें विजय या उपनिवेशीकरण के समय देश में रहने वाली आबादी या उस भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित आबादी से उनके वंश के कारण स्वदेशी माना जाता है और जो अपनी कानूनी स्थिति के बावजूद उस राष्ट्र की संस्थाओं की तुलना में उस समय के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संस्थानों के अनुरूप अधिक रहते हैं जिससे वे संबंधित हैं।

उपरोक्त सूत्रीकरण के अनुसार, सभी स्वदेशी आबादी को प्रकृति में अनिवार्य रूप से आदिवासी के रूप में परिभाषित किया गया है,

¹⁰The Covenant of the League of Nations, 1920, art. 22.

¹¹*Ibid.*

¹²Katja Göcke, "Indigenous Peoples in International Law", in Brigitta Hauser-Schäublin (ed.), *Adat and Indigeneity in Indonesia: Culture and Entitlements between Heteronomy and Self-Ascription* 20 (Göttingen University Press, 2017); Walter Kälin, "Assimilation, Forced", in *Max Planck Encyclopedia of Public International Law* (2020), available at: <https://opil.ouplaw.com/display/10.1093/law:epil/9780199231690/law-9780199231690-e754> (last visited on Nov. 11, 2025): "Assimilation, i.e. the process of absorption into a society or culture, can be understood in legal/administrative or cultural terms. Legal and administrative assimilation can be defined as imposing one's own legal and administrative system on a foreign territory, e.g. a colony or an occupied territory. Meanwhile, cultural assimilation describes the process of growing internalization of and participation in the culture and values of a given society, eventually leading to the cultural absorption of members of minorities or immigrants into the dominant society."

¹³Russell Lawrence Barsh, "Revision of ILO Convention No. 107" 81(3) *The American Journal of International Law* 759 (1987).

¹⁴United Nations Office of High Commissioner of Human Rights, *Indigenous Peoples and the United Nations Human Rights System*, Fact Sheet No. 9/Rev. 2 (2013), p. no. 2.

¹⁵The Indigenous and Tribal Populations Convention, 1957 (No. 107), art. 1.1.

जबकि सभी आदिवासी आबादी स्वदेशी नहीं हैं।¹⁶ आदिवासी और स्वदेशी आबादी के इस चित्रण की सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण रूप से, उनके चित्रण के लिए "कम उन्नत चरण" के रूप में भारी आलोचना की गई, जो 'आदिम' और 'हीनता' की कल्पना को देखते हुए उपनिवेशवाद में गहराई से निहित है।¹⁷

आईएलओ कन्वेंशन नं. 107 की इसके 'एकीकरणवादी' दृष्टिकोण के कारण भी निंदा की गई,¹⁸ जो आदिवासी और स्वदेशी आबादी को अपने आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास पर स्वायत्तता की गारंटी देने में विफल रहा।¹⁹ इसके बजाय, 'एकीकरणवादी' दृष्टिकोण ने राज्यों से आग्रह किया कि वे गैर-भेदभावपूर्ण आधार पर, राष्ट्रीय प्रगति में जनजातीय और स्वदेशी आबादी की भागीदारी, कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों के रूप में उनका समावेश, उन्हें प्रभावित करने वाले मामलों पर निर्णय लेने में सीमित सहयोग, और उनके विशिष्ट रीति-रिवाजों, परंपराओं और कानूनी प्रणालियों के लिए सम्मान सुनिश्चित करें, लेकिन "केवल एकीकरण कार्यक्रमों के उद्देश्यों के साथ संगत सीमा तक"।²⁰ राज्यों ने, 'एकीकरण' के दृष्टिकोण को अपनाते हुए, राज्यों ने "अपनी एकता बनाए रखने" के बहाने आदिवासी और स्वदेशी आबादी पर "ऐसे अभूतपूर्व दबाव" डाले, जिनसे "उनकी सांस्कृतिक पहचान और यहाँ तक कि उनके अस्तित्व पर भी खतरा" पैदा हो गया। इसलिए²¹ स्वदेशी संगठन आई. एल. ओ. कन्वेंशन नं. 107 और इसके द्वारा प्रदान किए गए सुरक्षात्मक सुरक्षा उपाय, जिन्हें स्वदेशी आवाजों से परामर्श या विचार-विमर्श किए बिना तैयार किया गया था।²²

स्वदेशी समुदायों में फैली निराशा और असंतोष को ध्यान में रखते हुए, आईएलओ ने आईएलओ कन्वेंशन नंबर 107 की जगह 'मूल निवासी और आदिवासी जन कन्वेंशन, 1989' (जिसे आम तौर पर आईएलओ कन्वेंशन नंबर 169 कहा जाता है) को लागू किया, जिसमें 'आदिवासी लोगों'

¹⁶Erica-Irene A. Daes, *Working paper on the concept of indigenous people*, UN Doc E/CN.4/Sub2/ACU/1996/2 (Jun. 10, 1996), para. 23.

¹⁷Douglas Sanders, "Indians, Amer Indians, Tribes and Peoples" 20(3) *India International Centre Quarterly* 30 (1993).

¹⁸The Indigenous and Tribal Populations Convention, 1957 (No. 107), preamble: "Having decided upon the adoption of certain proposals with regard to the protection and integration of indigenous and other tribal and semi-tribal populations in independent countries, which is the sixth item on the agenda of the session... Considering that there exist in various independent countries indigenous and other tribal and semi-tribal populations which are not yet integrated into the national community and whose social, economic or cultural situation hinders them from benefiting fully from the rights and advantages enjoyed by other elements of the population... Considering that the adoption of general international standards on the subject will facilitate action to assure the protection of the populations concerned, their progressive integration into their respective national communities, and the improvement of their living and working conditions..."

¹⁹Russell Lawrence Barsh, "Revision of ILO Convention No. 107" 81(3) *The American Journal of International Law* 756 (1987).

²⁰*Id.* at 757.

²¹*Id.* at 758.

²²Lee Sweptson, "Indigenous Peoples' Voices: Indigenous Participation in ILO Convention No. 169", in Richard Potz and René Kuppe (eds.) *International Yearbook of Legal Anthropology* 115 (Brill, Vol. 12, 2004); Russell Lawrence Barsh, "Revision of ILO Convention No. 107" 81(3) *The American Journal of International Law* 758-759 (1987).

²³The Indigenous and Tribal Populations Convention, 1957 (No. 107), however, continues to remain in force in numerous countries having significant indigenous populations, including India. The Indigenous and Tribal Peoples Convention, 1989 (No. 169) has been ratified only by 24 countries thus far.

और 'मूल निवासियों' को इस प्रकार फिर से परिभाषित किया गया: ²⁴.

(क) स्वतंत्र देशों में जनजातीय लोग जिनकी सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक स्थितियां उन्हें राष्ट्रीय समुदाय के अन्य वर्गों से अलग करती हैं, और जिनकी स्थिति पूरी तरह से या आंशिक रूप से उनके अपने रीति-रिवाजों या परंपराओं या विशेष कानूनों या विनियमों द्वारा नियंत्रित की जाती है;

(ख) स्वतंत्र देशों में ऐसे लोग जिन्हें विजय या उपनिवेशीकरण या वर्तमान राज्य सीमाओं की स्थापना के समय देश में रहने वाली आबादी या एक भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित आबादी से उनके वंश के कारण स्वदेशी माना जाता है और जो अपनी कानूनी स्थिति के बावजूद अपने स्वयं के कुछ या सभी सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक संस्थानों को बनाए रखते हैं।

आईएलओ कन्वेंशन नं. 169 ने जनजातीय लोगों के बारे में अपने विवरण को उन लोगों के लिए बदल दिया, जिनकी सामाजिक और आर्थिक स्थितियां कम उन्नत स्तर पर हैं, जिनकी सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक स्थितियां उन्हें राष्ट्रीय समुदाय के अन्य वर्गों से अलग करती हैं। आईएलओ कन्वेंशन नं. 169 ने आदिवासी लोगों के रूप में सभी स्वदेशी लोगों की अवधारणा में भी संशोधन किया, इसके बजाय उन्हें विशेष रूप से उन लोगों के रूप में चित्रित किया जो "विजय या उपनिवेशीकरण या वर्तमान राज्य सीमाओं की स्थापना के समय देश में रहने वाली आबादी, या एक भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित हैं। अधिक विशेष रूप से, आई. एल. ओ. सम्मेलन सं. 169 में स्पष्ट रूप से मान्यता दी गई है कि किसी की आदिवासी या स्वदेशी पहचान मूल रूप से उनकी अपनी स्वयं की पहचान से निर्धारित होती है, ²⁵ इस प्रकार राज्यों को "औपनिवेशिक काल के बाद की विकृतियों के रूप में स्वदेशीता और आदिवासी [पहचान] की श्रेणियों को आसानी से त्यागने" से रोकता है। ²⁶ आईएलओ कन्वेंशन नं. 169 ने 'आबादी' शब्द को 'लोगों' के साथ भी प्रतिस्थापित किया, प्रथम दृष्टया जनजातीय और स्वदेशी अधिकारों के संरक्षण के लिए काफी कानूनी निहितार्थ हैं- 'लोग' कानूनी रूप से अपने मानवाधिकारों के संरक्षण के हकदार हैं, जिसमें आत्मनिर्णय का अधिकार भी शामिल है, ²⁷ जबकि 'आबादी' का कोई न्यायिक महत्व नहीं है। ²⁸ फिर भी, आईएलओ कन्वेंशन नं. 169 ने यह स्पष्ट करते हुए इस तरह के निष्कर्ष को पहले ही रोकने का प्रयास किया कि 'लोगों' शब्द का "अंतरराष्ट्रीय कानून

²⁴The Indigenous and Tribal Peoples Convention, 1989 (No. 169), art. 1.1.

²⁵*Id.* art. 1.2.

²⁶Peter Bille Larsen and Jérémie Gilbert, "Indigenous rights and ILO Convention 169: Learning from the Past and Challenging the Future" 24 *The International Journal of Human Rights* 84 (2020).

²⁷Douglas Sanders, "Indians, Amerindians, Tribes and Peoples" 20 (3) *India International Centre Quarterly* 31-32 (1993); Sharon Venne, "The New Language of Assimilation: A Brief Analysis of ILO Convention 169" 2 (2) *The EAFORD International Review of Racial Discrimination* 56 (1989).

²⁸Sharon Venne, "The New Language of Assimilation: A Brief Analysis of ILO Convention 169" 2 (2) *The EAFORD International Review of Racial Discrimination* 55 (1989).

के तहत इस शब्द से जुड़े अधिकारों के संदर्भ में कोई मतलब नहीं निकाला जाएगा",²⁹ और ऐसा खास तौर पर उनके आत्म-निर्णय के अधिकार को सीमित करने के इरादे से किया गया था।³⁰ इसके अलावा, हालांकि आईएलओ कन्वेंशन नं. 169 ने अपने पूर्ववर्ती के स्पष्ट 'एकीकरणवादी' दृष्टिकोण से परहेज किया, इसके कई प्रावधानों में निहित भाषा का अर्थ यह है कि आदिवासी और स्वदेशी लोग "पिछड़े और अविकसित" हैं या उनकी "जीवन शैली हीन और अस्वीकार्य है"।³¹ तदनुसार, आईएलओ कन्वेंशन नं. 169 का "गैर-स्वदेशी दृष्टिकोण" से तैयार किए जाने के लिए भी कड़ी आलोचना की गई है,³² इस प्रक्रिया में स्वदेशी समुदायों की भूमिका को "अप्रत्यक्ष और भागीदारी के अपमानजनक स्तर" तक सीमित कर दिया गया है।³³

संयुक्त राष्ट्र (यूएन) ने स्वदेशी आबादी के खिलाफ भेदभाव की समस्या के मौलिक अध्ययन के माध्यम से, 'स्वदेशी लोगों' को परिभाषित करने का भी प्रयास किया, स्वदेशी आबादी के खिलाफ भेदभाव पर संयुक्त राष्ट्र के विशेष रिपोर्टर, जोस आर. मार्टिनेज कोबो को यह ज़िम्मेदारी दिया गया था। उनकी प्रारंभिक रिपोर्ट में, आंशिक रूप से निम्नलिखित कामचलाऊ परिभाषा, आईएलओ कन्वेंशन नं. 107, प्रस्तावित किया गया था:

"स्वदेशी आबादी उन लोगों के मौजूदा वंशजों से बनी होती है जो एक देश के वर्तमान क्षेत्र में पूरी तरह से या आंशिक रूप से उस समय रहते थे जब एक अलग संस्कृति या जातीय मूल के व्यक्ति दुनिया के अन्य हिस्सों से वहां पहुंचे थे, उन पर विज हावी हुए और जीत, बसावट या अन्य साधनों से उन्हें कमजोर या औपनिवेशिक स्थिति में ला दिया; जो आज एक राज्य संरचना के तहत देश की संस्थाओं की तुलना में अपने विशेष सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक रीति-रिवाजों और परंपराओं के अनुरूप रहते हैं, जिसमें मुख्य रूप से आबादी के अन्य वर्गों की राष्ट्रीय, सामाजिक और सांस्कृतिक विशेषताएं शामिल हैं जो प्रमुख हैं"।³⁴

फिर भी, 1986 में प्रस्तुत अपनी अंतिम रिपोर्ट में, विशेष प्रतिवेदक ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि 'स्वदेशी' पहचान की परिभाषा स्वदेशी समुदायों पर ही छोड़ दी जानी चाहिए: "बुनियादी दावा यह होना चाहिए कि स्वदेशी आबादी को दूसरे समूहों के मुकाबले खुद के बारे में उनकी अपनी सोच और समझ के आधार पर पहचाना जाए; उन्हें बाहरी समाजों या ऐसे समाजों के प्रभावशाली वर्गों की सोच और मूल्यों के आधार पर परिभाषित करने की कोई कोशिश नहीं होनी चाहिए।"³⁵ विशेष प्रतिवेदक ने, फिर भी, अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण से निम्नलिखित 'स्वदेशी लोगों' की परिभाषा:

²⁹The Indigenous and Tribal Peoples Convention, 1989 (No. 169), art. 1.3.

³⁰Sharon Venne, "The New Language of Assimilation: A Brief Analysis of ILO Convention 169" 2(2) *The EAFORD International Review of Racial Discrimination* 55 (1989).

³¹*Id.* at 57, 59, citing The Indigenous and Tribal Peoples Convention, 1989 (No. 169), arts. 2, 7.

³²*Id.* at 54, 65.

³³Dikshit Sarma Bhagabati, "How to Be Indigenous in India?" 35 *Law and Critique* 104 (2024).

³⁴José R. Martínez, *Commission of Human Rights, Sub-Commission on Prevention of Discrimination of Minorities*, UN Doc E/CN.4/Sub.2/L.566 (Jun. 29, 1972), paras. 34-35.

³⁵José R. Martínez Cobo, *Study of the Problem of Discrimination against Indigenous Populations*, Vol. V, UN Doc E/CN.4/Sub.2/1986/7/Add.4 (1986), para. 368.

की सिफारिश की: ³⁶

"स्वदेशी समुदाय, लोग और राष्ट्र वे हैं जो अपने क्षेत्रों में विकसित पूर्व आक्रमण और पूर्व औपनिवेशिक समाजों के साथ एक ऐतिहासिक निरंतरता रखते हैं, जो खुद को उन क्षेत्रों या उनके कुछ हिस्सों में प्रचलित समाजों के अन्य क्षेत्रों से अलग मानते हैं। वे वर्तमान में समाज के गैर-प्रमुख क्षेत्रों का निर्माण करते हैं और अपने सांस्कृतिक पैटर्न, सामाजिक संस्थानों और कानूनी प्रणालियों के अनुसार लोगों के रूप में अपने निरंतर अस्तित्व के आधार के रूप में अपने पैतृक क्षेत्रों और अपनी जातीय पहचान को संरक्षित करने, विकसित करने और आने वाली पीढ़ियों को प्रसारित करने के लिए दृढ़ हैं।

इस ऐतिहासिक निरंतरता में एक या अधिक की वर्तमान तक पहुँचने वाली विस्तारित अवधि के लिए निम्नलिखित कारकों में निरंतरता शामिल हो सकती है: (क) पैतृक भूमि का कब्जा, या कम से कम उनमें से कुछ भाग का; (ख) इन भूमि के मूल निवासियों के साथ सामान्य वंशावली; (ग) सामान्य रूप से संस्कृति, या विशिष्ट अभिव्यक्तियों में (जैसे धर्म, आदिवासी प्रणाली के तहत रहना, एक स्वदेशी समुदाय की सदस्यता, पोशाक, आजीविका के साधन, जीवन शैली, आदि।) (घ) भाषा (चाहे वह एकमात्र भाषा के रूप में, मातृभाषा के रूप में, घर या परिवार में संचार के आदतन साधन के रूप में, या मुख्य, पसंदीदा, आदतन, सामान्य या सामान्य भाषा के रूप में उपयोग की जाती है) (ङ) देश के कुछ हिस्सों में या दुनिया के कुछ क्षेत्रों में निवास; (च) अन्य प्रासंगिक कारक।

इसके अलावा, विशेष प्रतिवेदक ने एक 'स्वदेशी व्यक्ति' को ऐसे परिभाषित किया "जो स्वदेशी (समूह चेतना) के रूप में आत्म-पहचान के माध्यम से इन स्वदेशी आबादी से संबंधित है और इन आबादी द्वारा इसके सदस्यों में से एक के रूप में मान्यता प्राप्त और स्वीकार किया जाता है"।³⁷ 'आत्म-पहचान' के व्यक्तिपरक मानदंड के अलावा, विशेष प्रतिवेदक द्वारा प्रस्तावित 'स्वदेशी लोगों' की परिभाषा ने निम्नलिखित वस्तुनिष्ठ मानदंडों की पहचान की: ऐतिहासिक निरंतरता; विशिष्टता; गैर-प्रभुत्व; और भविष्य की पीढ़ियों को उनके पैतृक क्षेत्रों और लोगों के रूप में पहचान को संरक्षित, विकसित और प्रसारित करने का दृढ़ संकल्प।³⁸ पूर्वगामी में से, "आक्रमण-पूर्व और पूर्व-औपनिवेशिक समाजों के साथ ऐतिहासिक निरंतरता" के संकेतक की "उपनिवेशवाद के अस्तित्ववादी टूटने की घोर उपेक्षा करने और स्वदेशी विश्व दृष्टिकोण में महानगरीय आक्रमण को कम करने" के लिए आलोचना की गई है।³⁹ हालांकि स्वदेशी लोग की अपनी अलग वंशावली, संस्कृति, धर्म, भाषा और आजीविका होती है, फिर भी वे "मुख्यधारा के लोगों के साथ मेल-जोल और टकराव" से होने वाले सामाजिक बदलावों से अछूते नहीं रहते। इस वजह से, 'ऐतिहासिक निरंतरता' शब्द का सख्ती से इस्तेमाल करना सही नहीं है - "अपनी पारंपरिक जीवन शैली को छोड़ने का मतलब स्वदेशीता का क्षरण नहीं है"।⁴⁰ इसके अलावा, उपनिवेशीकरण या पर्यावरणीय संकटों के प्रत्यक्ष परिणाम के रूप में, स्वदेशी लोग

³⁶Id.atparas.379-380.

³⁷Id.atpara.381.

³⁸United Nation Office of High Commissioner of Human Rights, *Indigenous Peoples and the United Nations Human Rights System*, Fact Sheet No.9/Rev.2(2013), p.nos.2-3.

³⁹Dikshit Sarma Bhagabati, "How to Be Indigenous in India?" 35 *Law and Critique* 101 (2024).

⁴⁰Id.at101,110.

अक्सर विस्थापित हुए हैं, जो उनकी पैतृक भूमि के कब्जे से जुड़ी 'ऐतिहासिक निरंतरता' को तोड़ते हैं।⁴¹ इसके अलावा, खानाबदोश जीवन शैली रखने वाले कुछ स्वदेशी लोग पारंपरिक रूप से खुद को किसी विशेष पैतृक क्षेत्र से बंधे नहीं मानते हैं।⁴² पैतृक भूमि पर कब्जा और/या स्वामित्व, हक को 'ऐतिहासिक निरंतरता' के संकेतक के रूप में मानना 'इस बात की परवाह किए बिना कि ये समुदाय स्वयं अपने रहने के स्थानों को कैसे देखते हैं', इसलिए 'स्वदेशीता' का एक गलत और अप्रचलित प्रमाण है।⁴³

आई. एल. ओ. कन्वेंशन नं. 107, आई. एल. ओ. सम्मेलन सं. 169, और स्वदेशी आबादी के खिलाफ भेदभाव की समस्या का अध्ययन, और परिणामी विविधता आलोचनाओं ने, यह पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया कोई "एक निश्चित अर्थ वाला सटीक तकनीकी शब्द नहीं है"।⁴⁴ वास्तव में, स्वदेशी लोगों की एक सार्वभौमिक परिभाषा नहीं हो सकती है " [क्योंकि] स्वदेशी लोग अलग-अलग और बदलते परिवेश में रहते हैं।"⁴⁵ इस बात को संयुक्त राष्ट्र कार्य समूह (यूएनडब्ल्यूजीआईपी) के अध्यक्ष-रिपोर्टर ने साफ़ तौर पर माना था। यह ग्रुप 1982 में स्पेशल रिपोर्टर जोस आर. मार्टिनेज़ कोबो की सिफ़ारिश पर बनाया गया था: ⁴⁶ 'स्वदेशी की अवधारणा एक सटीक, समावेशी परिभाषा में सक्षम नहीं है जिसे दुनिया के सभी क्षेत्रों में एक ही तरह से लागू किया जा सके। हालाँकि, उन मुख्य बातों की पहचान करने पर ज़्यादा सहमति बन सकती है जो संयुक्त राष्ट्र प्रणाली और क्षेत्रीय अंतर-सरकारी संगठनों के कामकाज में "स्वदेशी लोगों" को दूसरे समूहों से अलग करती हैं... ।'⁴⁷ स्वदेशी प्रतिनिधियों ने इस बात पर भी सहमति व्यक्त की कि चूंकि "स्वदेशी लोगों की कोई एकल स्वीकृत परिभाषा मौजूद नहीं है जो उनकी विविधता को दर्शाता है... "स्वदेशी लोगों" की अवधारणा की परिभाषा आवश्यक या वांछनीय नहीं है" ⁴⁸ इसी के अनुसार, स्वदेशी अधिकारों की रक्षा के प्रयासों को मार्गदर्शन देने के सीमित उद्देश्य से, यूएनडब्ल्यूजीआईपी ने 'स्वदेशी' पहचान की अवधारणा से जुड़े कुछ ऐसे कारकों की पहचान की जो पूरी सूची तो नहीं हैं, लेकिन महत्वपूर्ण हैं: ⁴⁹

(क) एक विशिष्ट क्षेत्र के कब्जे और उपयोग के संबंध में समय में प्राथमिकता;

(ख) सांस्कृतिक विशिष्टता का स्वेच्छिक चिरस्थायीकरण, जिसमें निम्नलिखित पहलू शामिल हो सकते हैं -

भाषा, सामाजिक संगठन, धर्म और आध्यात्मिक मूल्य, उत्पादन के तरीके, कानून और

⁴¹Id.at102.

⁴²Id.at106.

⁴³Id.at108.

⁴⁴BenedictKingsbury, "IndigenousPeoples'inInternationalLaw:AConstructivistApproachtotheAsianControversy" 92(3)*TheAmericanJournalofInternationalLaw*420(1998).

⁴⁵World Bank, *Operation Manual on Indigenous People* (Apr. 2013), para. 3, available at: <https://thedocs.worldbank.org/en/doc/2e32d9beec85a16da0bac98d14df191-0290012023/original/OP-4-10-Indigenous-Peoples.pdf> (lastvisitedonOct.8,2025).

⁴⁶S. JamesAnaya, "IndigenousPeoplesin International Law", *CulturalSurvivor* (Mar.25, 2010).

⁴⁷Erica-IreneADaes, *Workingpaperontheconceptofindigenouspeople*, UNDocE/CN.4/Sub2/ACU/1996/2(Jun.10, 1996), para. 9.

⁴⁸Id.atpara.34.

⁴⁹Id.atparas.69-70.

संस्थान;

(ग) आत्म-पहचान, साथ ही अन्य समूहों द्वारा या राज्य प्राधिकरणों द्वारा एक विशिष्ट सामूहिक पहचान के रूप में मान्यता; तथा

(घ) क्या अधीनता, हाशिए पर डालना, बेदखल करना, बहिष्कार या भेदभाव का अनुभव, ये स्थितियाँ बनी रहती हैं या नहीं।

नतीजतन, 2007 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाए गए स्वदेशी लोगों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र घोषणा जिसे (यूएनडीआरआईपी)⁵⁰ द्वारा तैयार किए गए मसौदे से बनाया गया था, ने भी 'स्वदेशी लोगों' की परिभाषा देने से भी परहेज किया।⁵¹ इसके बजाय, यूएनडीआरआईपी ने 'आत्म-पहचान' और इस बात पर जोर दिया कि यह स्वदेशी लोगों को खुद स्वदेशी के रूप में अपनी पहचान तय करनी है⁵² "स्वदेशी लोगों को अपनी पहचान या सदस्यता उनके रीति-रिवाजों और परंपराओं के अनुसार निर्धारित करने का अधिकार है"।⁵³

भारत में, 'स्वदेशी' पहचान का विचार और भी अधिक विवादास्पद है।⁵⁴ जबकि भारत के संविधान द्वारा जनजातीय समुदायों को विशिष्ट संरक्षण दिया गया है जिन्हें आमतौर पर 'आदिवासी' कहा जाता है, इसका शाब्दिक अर्थ "मूल निवासी", है⁵⁵ उन्हें कानूनी रूप से 'अनुसूचित जनजाति' के रूप में नामित करके,⁵⁶ स्पष्ट रूप से स्वीकार नहीं किया गया है कि वे भारत के मूल निवासी हैं, इसके उलट, 1982 से भारत का यह कहना रहा है⁵⁷ कि 'स्वदेशी लोगों' की जो अवधारणा⁵⁸ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बनी है, वह भारतीय संदर्भ⁵⁹ में लागू नहीं होती। भारत का तर्क है कि "स्वदेशी लोग उन मूल निवासियों की संतानें हैं जिन्होंने बाहरी लोगों द्वारा कब्जे या हमले का सामना किया है।"⁶⁰ तदनुसार, यूएनडीआरआईपी को अपनाने के समय, भारत ने जोर देकर कहा कि 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार से अपनी स्वतंत्रता के बाद से,

⁵⁰The United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, 2007.

⁵¹Katja Göcke, "Indigenous Peoples in International Law", in Brigitta Hauser-Schäublin (ed.), *Adapt and Indigeneity in Indonesia: Culture and Entitlements between Heteronomy and Self-Ascription* 19 (Göttingen University Press, 2017); United Nations Human Rights Council, Working Group of the Commission on Human Rights to elaborate a draft declaration in accordance with paragraph 5 of the General Assembly res. 49/214 of 23 December 1994, UN Doc A/RES/61/295 (Jun. 29, 2006), available at: <https://hrlibrary.umn.edu/hrcouncil2-2006.html> (last visited on Oct. 5, 2025).

⁵²United Nations Department of Economic and Social Affairs, *State of the World's Indigenous Peoples*, Vol. I (May 2011), p. no. 5.

⁵³The United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, 2007, art. 33.1.

⁵⁴Virginus Xaxa, "Tribes as Indigenous People of India" 34 (51) *Economic and Political Weekly* 3589 (1999).

⁵⁵Richard W. Timm, *The Adivasis of Bangladesh* (Minority Rights Group, 1991); J. Rehman, "Indigenous peoples at risk: a survey of the indigenous peoples of South Asia", in B. K. R. Burman and B. G. Verghese (eds.), *Tribal/Indigenous Condition* (Konark Publisher, 1998).

Aspiring to Be: The

⁵⁶The Constitution of India, 1950, art. 366(25).

⁵⁷Dikshit Sarma Bhagabati, "How to Be Indigenous in India?" 35 *Law and Critique* 95-96 (2024).

⁵⁸*Ibid.*

⁵⁹Lakshmi Puri, *Statement on Behalf of the Delegation of India to the United Nations Working Group on indigenous populations*, UN Files (Aug. 12, 1983); Benedict Kingsbury, "'Indigenous Peoples' in International Law: A Constructivist Approach to the Asian Controversy" 92 (3) *The American Journal of International Law* 433 (1998).

⁶⁰The Government of India, *Observations*, UN Doc E/CN.4/Sub.2/1984/2/Add.2.

सभी भारतीयों को भारत का मूल निवासी माना जाता है। चाहे, 'मूल निवासियों' और बाद में बसने वालों के बीच अंतर क्यों न हो, ⁶¹ "क्योंकि, सदियों के प्रवास, अवशोषण और भेदभाव के बाद, यह कहना असंभव है कि कौन पहले आया" ⁶² इस प्रकार यह कहा गया कि आदिवासी भारत के लिए स्वदेशी नहीं हैं ⁶³ क्योंकि "भारत की जनजातियों में देश के अन्य लोगों जैसी ही जातीय, नस्लीय और भाषाई विशेषताएँ हैं, और वहाँ के तीन से चार सौ मिलियन लोग भारत के अन्य लोगों से किसी न किसी तरह अलग हैं"। ⁶⁴

क्या आदिवासी वास्तव में भारत के मूल निवासियों के रूप में मूल निवासी हैं, जिन्हें पारंपरिक रूप से 'स्वदेशी लोगों' के रूप में माना जा सके, यह अपने आप में काफी विवादास्पद है। ⁶⁵ एक दृष्टिकोण से पता चलता है कि "जब लोगों के आंतरिक आंदोलनों का इतिहास ज्ञात नहीं है, तो किसी न किसी जनजाति को मिट्टी का मूल मालिक मानना पूरी तरह से अवैज्ञानिक है। यह तर्क देना संभव है कि भले ही जनजातियाँ उस क्षेत्र के आदिवासी न हों जिस पर वे अब कब्जा कर रहे हैं, वे भारत के मूल निवासी हैं, और उस हद तक उन्हें आदिवासी कहा जा सकता है। ⁶⁶ एक विपरीत दृष्टिकोण में कहा गया है: "यहाँ भारत में सदियों और सहस्राब्दियों से अलग-अलग भाषा, नस्ल, संस्कृति, धर्म के साथ आबादी के आंदोलन की लहरें रही हैं। जनजातियों के रूप में वर्णित समूह या समुदाय भी इस प्रक्रिया से बाहर नहीं रहे हैं। इसे देखते हुए, यह निर्धारित करने के लिए कि कौन मूल निवासी हैं और कौन अप्रवासी हैं, इतिहास में कितना पीछे जाना चाहिए?" ⁶⁷ एक संबंधित दृष्टिकोण बताता है कि 'मूल' निवासियों के बारे में बात करना मुश्किल है, क्योंकि आदिवासी परंपराएं स्वयं अपने पूर्वजों के प्रवास का बार-बार उल्लेख करती हैं। इस बात के काफी सबूत हैं कि कई समूहों को उन क्षेत्रों से बाहर निकाल दिया गया था जहाँ वे पहले बसे थे और उन्हें कहीं और शरण लेनी पड़ी थी। ⁶⁸

एक सामंजस्यपूर्ण दृष्टिकोण यह बताता है कि हालांकि कुछ आदिवासी समुदाय भारत के मूल निवासी हो सकते हैं, लेकिन सभी आदिवासी समुदाय नहीं हैं, और परिणामस्वरूप, 'आदिवासी' और 'स्वदेशी' पहचानों को पर्यायवाची होने की आवश्यकता नहीं है: "कुछ आदिवासी समूह ऐसे हैं जिन्हें मूल निवासी माना जा सकता है और कुछ ऐसे हैं जिन्हें नहीं" ⁶⁹ आईएलओ कन्वेंशन नं. 107 (भारत द्वारा अनुमोदित) भी स्वदेशी आबादी को आदिवासी आबादी के एक उपसमूह के रूप में मानता है, ⁷⁰ हालांकि बाद में आईएलओ कन्वेंशन नं. 169 आदिवासी लोगों को स्वदेशी लोगों से अलग बताता है। ⁷¹ बाद वाला नज़रिया उन समुदायों के बीच समर्थन मिलता प्रतीत होता है

⁶¹ International Work Group for Indigenous Affairs, *The Indigenous World 2020* (34th edn., 2020), p.no.234.

⁶² Benedict Kingsbury, "Indigenous Peoples' in International Law: A Constructivist Approach to the Asian Controversy" 92(3) *The American Journal of International Law* 434-435 (1998).

⁶³ Douglas Sanders, "Indians, AmerIndians, Tribes and Peoples" 20(3) *India International Centre* 36 (1993).

⁶⁴ Benedict Kingsbury, "Indigenous Peoples' in International Law: A Constructivist Approach to the Asian Controversy" 92(3) *The American Journal of International Law* 435 (1998).

⁶⁵ Virginius Xaxa, "Tribes as Indigenous People of India" 34(51) *Economic and Political Weekly* (1999).

⁶⁶ Govind Sadashiv Ghurye, *The Scheduled Tribes of India* (Popular Prakashan, 1963).

⁶⁷ Virginius Xaxa, "Tribes as Indigenous People of India" 34(51) *Economic and Political Weekly* 3591 (1999).

⁶⁸ Shyama Charan Dube, *Tribal Heritage of India: Ethnicity, Identity and Interaction* (Vikas Publishing House Pvt. Ltd., 1977).

⁶⁹ Virginius Xaxa, "Tribes as Indigenous People of India" 34(51) *Economic and Political Weekly* 3592 (1999).

⁷⁰ The Indigenous and Tribal Populations Convention, 1957 (No. 107), art. 1.1.

⁷¹ The Indigenous and Tribal Peoples Convention, 1989 (No. 169), art. 1.1.

जो भारत में 'स्वदेशी' के रूप में अपनी पहचान बनाते हैं⁷² 'स्वदेशी' पहचान 'आत्मसम्मान और गर्व की भावना को उजागर करती है और इससे जुड़े कुछ अधिकार और विशेषाधिकार हैं (कम से कम अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून में)⁷³ जबकि 'जनजाति' शब्द का उपयोग आम तौर पर 19वीं शताब्दी से निम्न और हीन समाज को इंगित करने के लिए किया जाता रहा है, ⁷⁴ या 'आदिम' के पर्याय के रूप में।⁷⁵

चाहे आदिवासियों (सभी या कुछ) को भारत का मूल निवासी माना जाए या नहीं, भारत का संविधान, उनके ऐतिहासिक अभाव, हाशिए पर जाने और शक्तिहीनता पर विशेष ध्यान देते हुए, उन्हें 'अनुसूचित जनजाति' के रूप में संरक्षित करता है, उनके राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक अधिकारों की गारंटी देता है।⁷⁶ भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने, कैलास बनाम महाराष्ट्र राज्य में, उल्लेख किया है कि "अब आम तौर पर स्वीकार किया गया कि भारत के मूल निवासी पूर्व-द्रविड़ आदिवासी थे यानी वर्तमान आदिवासियों (अनुसूचित जनजातियों) के पूर्वज... भारत के मूल निवासियों के वंशज हैं।"⁷⁷

चाहे भारतीय हो या व्यापक वैश्विक संदर्भ में, यह स्पष्ट है कि कोई भी परिभाषा "दुनिया के स्वदेशी लोगों की पूर्ण विविधता को पूरी तरह से बताने में सक्षम नहीं है।⁷⁸ 'स्वदेशी लोग' एक विषम मोनोलिथ नहीं हैं; इसलिए, स्वदेशी लोगों को एक सामूहिक 'वे' के रूप में संदर्भित करना आदर्श नहीं है।⁷⁹ इस तरह का संदर्भ स्वदेशी लोगों के 'अन्यकरण' की ओर भी ले जाता है।⁸⁰

पूर्वगामी को स्वीकार करने के बाद, यह संदर्भ नियमावली स्वदेशी लोगों को केवल मसौदा तैयार करने में आसानी के लिए एक समुदाय के रूप में संदर्भित करती है, और कम से कम, यह नहीं दर्शाती है कि सभी स्वदेशी लोग अपनी संस्कृति, परंपराओं, भाषाओं, धर्मों, आजीविका और अन्य विशेषताओं में समरूप हैं। इसके अलावा, इस संदर्भ नियमावली में, 'स्वदेशी लोग' वाक्यांश एक विशिष्ट क्षेत्र के मूल निवासी सभी लोगों को शामिल करता है, जिस नाम से वे खुद को पहचानते हैं, या उन्हें सौंपा जाता है, अर्थात्, आदिवासी, प्रथम लोग, मूल निवासी, आदिवासी, जनजातियाँ, जनजातियाँ, पहाड़ी निवासी, शिकारी-संग्रहकर्ता, खानाबदोश, किसान, पहाड़ी लोग, अन्य बातों के साथ।⁸¹

⁷² Mahendra Ved, "We are tribals, not indigenous" *The Times of India*, Sep. 30, 2004.

⁷³ Virginius Xaxa, "Tribes as Indigenous People of India" 34(51) *Economic and Political Weekly* 3595 (1999).

⁷⁴ *Ibid.*

⁷⁵ B.K.R. Burman and B.G. Verghese, *Aspiring to Be: The Tribal/Indigenous Condition* (Konark Publisher, 1998).

⁷⁶ Dikshit Sarma Bhagabati, "How to Be Indigenous in India?" 35 *Law and Critique* 93-123 (2024).

⁷⁷ *Kailas v. State of Maharashtra* (2011) 1 SCC 793, paras. 19, 26.

⁷⁸ United Nations Office of High Commissioner of Human Rights, "About Indigenous Peoples and Human Rights" available at: <https://www.ohchr.org/en/indigenous-peoples/about-indigenous-peoples-and-human-rights> (last visited on Sep. 23, 2025)

⁷⁹ Dikshit Sarma Bhagabati, "How to Be Indigenous in India?" 35 *Law and Critique* 96 (2024).

⁸⁰ *Ibid.*

⁸¹ United Nations Permanent Forum on Indigenous Issues, *Indigenous Peoples, Indigenous Voices*, p.no.2, available at: https://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/5session_factsheet1.pdf (last visited on Oct. 5, 2025).

अध्याय II: अंतर्राष्ट्रीय मानक

अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से उनकी चिंताओं के लिए बहुत कम या कोई ध्यान नहीं मिलने के दशकों बाद,⁸² स्वदेशी मुद्दों को संबोधित करने और इस मोर्चे पर वैश्विक सहयोग की आवश्यकता पर जोर देने वाला पहला अंतर्राष्ट्रीय मंच आई. एल. ओ. था। जैसा कि अध्याय I में दिखाया गया है, हालांकि आई. एल. ओ. कन्वेंशन नं. 107 ने स्वदेशी लोगों के अधिकारों की रक्षा करने और उन्हें आगे बढ़ाने की मांग की, लेकिन उन्हें अच्छी प्रतिक्रिया नहीं मिली। आईएलओ कन्वेंशन नं. 107 द्वारा नियोजित 'आत्मसातवादी' दृष्टिकोण को देखते हुए, स्वदेशी लोगों ने नए अंतर्राष्ट्रीय मानकों की मांग की, यह मांग, विशेष रूप से संयुक्त राष्ट्र के विशेष रिपोर्टर, जोस आर. मार्टिनेज कोबो द्वारा किए गए स्वदेशी आबादी के खिलाफ भेदभाव की समस्या के आलोक में अध्ययन की गई थी।⁸³ इसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आधुनिक स्वदेशी अधिकार प्रणाली की नींव रखी, और यूएनडब्ल्यूजीआईपी का निर्माण किया, जो स्वदेशी लोगों से संबंधित मामलों से निपटने के लिए विशेष जनादेश के साथ पहला संयुक्त राष्ट्र तंत्र था, जिसमें उनके अधिकारों के संरक्षण के लिए मानकों का विकास करना शामिल था।⁸⁴ 1993 में, यूएनडब्ल्यूजीआईपी ने स्वदेशी लोगों के अधिकारों पर एक मसौदा घोषणा प्रस्तुत की, जिसे 1994 में भेदभाव की रोकथाम और अल्पसंख्यकों के संरक्षण पर उप-आयोग द्वारा अनुमोदित किया गया था।⁸⁵ जून 2006 में, मानवाधिकार परिषद के पहले सत्र में, स्वदेशी लोगों के अधिकारों पर मसौदा घोषणा को अपनाया गया था।⁸⁶ इसके बाद, 13 सितंबर 2007 को, इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा यूएनडीआरआईपी के रूप में अपनाया गया।⁸⁷

हालांकि, यूएनडीआरआईपी कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है, स्वदेशी लोगों के अधिकारों से संबंधित सबसे व्यापक अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेज है, जो दुनिया भर में स्वदेशी लोगों के अस्तित्व, गरिमा और कल्याण के लिए न्यूनतम मानकों का एक सार्वभौमिक ढांचा स्थापित करता है।⁸⁸ यूएनडीआरआईपी मौजूदा मानवाधिकार मानकों और मौलिक स्वतंत्रताओं के बारे में विस्तार से बताता है क्योंकि वे स्वदेशी लोगों की अनूठी स्थिति पर लागू होते हैं, और सामूहिक अधिकारों को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून में पहले

⁸²United Nations Human Rights Office of the High Commissioner, *The United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples: A Manual for National Human Rights Institutions*, UN Doc HR/PUB/13/2 (Aug. 2013), p. no. 10.

⁸³*Id.* at 4.

⁸⁴Erica-Irene A. Daes, *Draft Declaration on the Rights of Indigenous Peoples: revised working paper/submitted by the Chairperson-Rapporteur, pursuant to Sub-Commission resolution 1992/33 and Commission on Human Rights resolution 1993/31*, UN Doc E/CN.4/Sub.2/1993/26 (Jun. 8, 1993), p. no. 1.

⁸⁵United Nations Department of Economic and Social Affairs, *United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples: Historical Overview*, available at: <https://social.desa.un.org/issues/indigenous-peoples/united-nations-declaration-on-the-rights-of-indigenous-peoples> (last visited on Sep. 27, 2025).

⁸⁶United Nations Human Rights Office of the High Commissioner, *Human Rights Council Concludes First Session* (Jun. 29, 2006).

⁸⁷United Nations General Assembly, *Resolution adopted by the General Assembly on 13 September 2007*, GA Res 61/295 (Oct. 2, 2007).

⁸⁸United Nations Permanent Forum on Indigenous Issues, *Frequently Asked Questions, Declaration on the Rights of Indigenous Peoples* (2007), available at: https://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/faq_drips_en.pdf (last visited on Oct. 29, 2025).

कभी नहीं दिए गए प्रमुखता का स्तर प्रदान करते हैं।⁸⁹ साथ ही, आईएलओ कन्वेंशन नं. 107 के जवाब में आईएलओ ने आईएलओ कन्वेंशन नं. 169 बनाया, जिसने अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत स्वदेशी लोगों की सुरक्षा के लिए एक व्यापक ढांचा प्रदान किया। आईएलओ कन्वेंशन नं. 169 ने तब से कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा स्वदेशी लोगों की सुरक्षा के लिए नीतियों और कार्यक्रमों के विकास के लिए एक आधार के रूप में भी काम किया है।⁹⁰ आज, आईएलओ कन्वेंशन नं. 169 को सबसे उन्नत बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि माना जाता है जिसे विशेष रूप से स्वदेशी लोगों के अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है। स्वदेशी लोगों के कुछ अधिकार भी अंतरराष्ट्रीय संधियों द्वारा स्पष्ट रूप से संरक्षित हैं, जिनमें बाल अधिकारों पर कन्वेंशन, 1989 (सीआरसी)⁹¹, जैविक विविधता पर कन्वेंशन, 1982 (सीबीडी)⁹² और जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन, 1992 शामिल हैं।⁹³

अन्य अंतरराष्ट्रीय कानूनी साधन, हालांकि स्वदेशी अधिकारों को स्पष्ट रूप से संबोधित नहीं करते हैं, लेकिन जिन्हें स्वदेशी संदर्भ में लागू किया गया है, उनमें नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय समझौता, 1966 (आई. सी. सी. पी. आर.) आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय समझौता, 1966 (आई. सी. ई. एस. सी. आर.) सभी प्रकार के नस्लीय भेदभाव के उन्मूलन पर अंतर्राष्ट्रीय समझौता, 1965 (आई. सी. ई. आर. डी.) और महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन पर समझौता, 1979 (सी. ई. डी. ए. डब्ल्यू.) शामिल हैं। आईसीसीपीआर के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए जिम्मेदार मानवाधिकार समिति (एचआरसी) ने स्वदेशी लोगों के आत्मनिर्णय के अधिकार को मान्यता देने के लिए अपने प्रावधानों की व्यापक रूप से व्याख्या की है।⁹⁴ इसी तरह, आईसीईएससीआर के कार्यान्वयन की निगरानी करने वाली आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों की समिति (सीईएससीआर) ने भी पर्याप्त आवास, भोजन, शिक्षा, स्वास्थ्य, जल और बौद्धिक संपदा के लिए स्वदेशी लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए अपने प्रावधानों को लागू किया है।⁹⁵ आईसीईआरडी के पर्यवेक्षण के साथ काम करने वाली नस्लीय भेदभाव उन्मूलन समिति (सीईआरडी) ने स्वदेशी लोगों के खिलाफ भेदभाव का मुकाबला करने के लिए अपने प्रक्रियात्मक तंत्र को तैनात किया है।⁹⁶ इसके अलावा, महिलाओं के खिलाफ भेदभाव उन्मूलन समिति ने विशेष रूप से कमजोर और वंचित समूह के रूप में

⁸⁹United Nations Human Rights Office of the High Commissioner, *The United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples: A Manual for National Human Rights Institutions*, UN Doc HR/PUB/13/2 (Aug. 2013), p. no. 5.

⁹⁰United Nations, *State of the World's Indigenous Peoples*, Vol. I (May 2011), p. no. 2.

⁹¹The Convention on the Rights of the Child, 1989.

⁹²The United Nations Convention on Biological Diversity, 1992.

⁹³The United Nations Framework Convention on Climate Change, 1992.

⁹⁴United Nations Special Rapporteur on the Rights of Indigenous Peoples, *International Standards*, available at: <https://www.ohchr.org/en/special-procedures/sr-indigenous-peoples/international-standards> (last visited on Sep. 25, 2025).

⁹⁵*Ibid.*

⁹⁶*Ibid.*

स्वदेशी महिलाओं की स्थिति पर विशेष ध्यान दिया है।⁹⁷

संयुक्त राष्ट्र की पूरी प्रणाली में, स्वदेशी लोगों के अधिकारों पर और ध्यान आकर्षित करने के लिए कई उपाय भी शुरू किए गए हैं। इनमें 1985,⁹⁸ में स्वदेशी आबादी के लिए संयुक्त राष्ट्र स्वेच्छिक कोष की स्थापना, 1993 में विश्व के स्वदेशी लोगों के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष की घोषणा और 1995 में शुरू होने वाले विश्व के स्वदेशी लोगों के लगातार दो अंतर्राष्ट्रीय दशकों को अपनाना शामिल है।⁹⁹ इसी तरह, स्वदेशी लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए, संयुक्त राष्ट्र ने अलग-अलग जनादेश के साथ कई तंत्र स्थापित किए हैं:

- स्वदेशी मुद्दों पर संयुक्त राष्ट्र स्थायी मंच (यूएनपीएफआईआई) की स्थापना 2000 में आर्थिक और सामाजिक परिषद के एक उच्च स्तरीय सलाहकार निकाय के रूप में स्वदेशी लोगों के आर्थिक और सामाजिक विकास, संस्कृति, पर्यावरण, शिक्षा, स्वास्थ्य और मानवाधिकारों से संबंधित चिंताओं को दूर करने के लिए की गई थी।¹⁰⁰ यूएनपीएफआईआई संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के भीतर स्वदेशी मुद्दों से निपटने की पहलों के समन्वय को प्रोत्साहित करने के लिए भी जिम्मेदार है।¹⁰¹
- स्वदेशी लोगों के अधिकार पर विशेष प्रतिवेदक को पहली बार 2001,¹⁰² में नियुक्त किया गया था, जिसे स्वदेशी लोगों के मानवाधिकारों के पूर्ण और प्रभावी संरक्षण के लिए मौजूदा बाधाओं को दूर करने के तरीकों और साधनों की जांच करने का काम सौंपा गया था; इस संबंध में सर्वोत्तम प्रथाओं की पहचान, आदान-प्रदान और बढ़ावा देना; मानवाधिकारों और स्वदेशी लोगों की मौलिक स्वतंत्रताओं के कथित उल्लंघन से

⁹⁷United Nations Department of Economic and Social Affairs, *CEDAW General Recommendation No. 24: Article 12 of the Convention (Women and Health)*, UN Doc A/54/38/Rev.1 (1999), ch.1, para.6.

⁹⁸United Nations General Assembly, *United Nations Voluntary Fund for Indigenous Populations*, GA Res 40/131, UN Doc A/RES/40/131 (Dec. 13, 1985); The United Nations Voluntary Fund on Indigenous Populations was established to assist representatives of indigenous communities and organizations to participate in the deliberations of the Working Group on Indigenous Populations. The General Assembly expanded the mandate of the Fund vide Resolution 56/140, Resolution 63/161 and Resolution 65/198 to assist representatives to participate in sessions of the Permanent Forum, the Expert Mechanism, the Human Rights Council and the human rights treaty bodies.

⁹⁹United Nations General Assembly, *International Decade of the World's Indigenous People*, GA Res 48/163, UN Doc A/RES/48/163 (Feb. 18, 1994); General Assembly Resolution 48/163 established the first International Decade of the World's Indigenous People (1995-2004), under the coordination of the United Nations High Commissioner for Human Rights. A second International Decade (2005-2014) was established by Resolution 59/174, under the coordination of the Under-Secretary General for Economic and Social Affairs. A Trust Fund was established in 1995 and 2004 to fund projects and programmes for the respective decades.

¹⁰⁰United Nations Economic and Social Council, *Establishment of a Permanent Forum on Indigenous Issues*, ESC Dec 2000/22, UN Doc E/RES/2000/22 (Jul. 28, 2000).

¹⁰¹United Nations Human Rights Office of the High Commissioner, *The United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples: A Manual for National Human Rights Institutions*, UN Doc HR/PUB/13/2 (Aug. 2013), p.no.4.

¹⁰²United Nations Commission on Human Rights, *Human rights and indigenous issues*, UN Doc E/CN.4/RES/2001/57 (Apr. 24, 2001), p.no.2; The mandate was continued by the Human Rights Council and, in its Resolution 15/14, the title of "Special Rapporteur on the Situation of Human Rights and Fundamental Freedoms of Indigenous People" was modified to "Special Rapporteur on the Rights of Indigenous Peoples".

से संबंधित सभी प्रासंगिक स्रोतों से जानकारी और संचार एकत्र करना, अनुरोध करना, प्राप्त करना और आदान-प्रदान करना; और ऐसे उल्लंघनों को रोकने और सुधारने के लिए उचित उपायों के लिए सिफारिशें और प्रस्ताव तैयार करना।¹⁰³

- स्वदेशी लोगों के अधिकारों पर विशेषज्ञ तंत्र की स्थापना 2007 में मानवाधिकार परिषद को स्वदेशी लोगों के अधिकारों से संबंधित मामलों पर विषयगत सलाह प्रदान करने के लिए की गई थी।¹⁰⁴ विशेषज्ञ तंत्र ने अब तक अपने काम को स्वदेशी लोगों के शिक्षा, निर्णय लेने और न्याय तक पहुंच के अधिकारों के साथ-साथ स्वदेशी लोगों के अधिकारों और उनकी भावना को आगे बढ़ाने और उनकी रक्षा करने में भाषाओं और संस्कृति की भूमिका पर केंद्रित किया है।¹⁰⁵

इस अध्याय के निम्नलिखित खंड उस तरीके का विस्तृत विवरण प्रदान करते हैं जिसमें अंतर्राष्ट्रीय कानूनी प्रणाली स्वदेशी लोगों के आत्मनिर्णय, स्व-शासन और भागीदारी; भूमि, वन और संसाधन; आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संरक्षण; भाषाएं; शिक्षा; पारंपरिक ज्ञान; न्याय तक पहुंच; और टिकाऊ पर्यावरण प्रबंधन अधिकारों की गारंटी और सुरक्षा करती है।

स्वदेशी अधिकारों के संरक्षण के लिए प्रासंगिक अंतर्राष्ट्रीय कानूनी उपकरणों, चाहे वे संधियाँ हों, घोषणाएँ हों या मार्गदर्शक सिद्धांत हों, के प्रावधानों का एक सैपशॉट अनुलग्नक ए में दिया गया है। भारत और इस संदर्भ नियमावली में तुलनात्मक अध्ययन के लिए चुने गए चुनिंदा राज्यों द्वारा इन अंतर्राष्ट्रीय कानूनी साधनों के अनुसमर्थन या अपनाने की स्थिति अनुलग्नक बी में प्रस्तुत की गई है।

1. आत्मनिर्णय, स्व-शासन, भागीदारी, परामर्श और स्वतंत्र, पूर्व और सूचित सहमति

सभी लोगों के आत्मनिर्णय के अधिकार को विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय कानूनी साधनों और प्रथागत अंतर्राष्ट्रीय कानून में भी एक मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है।¹⁰⁶ यह उपनिवेशवाद के उन्मूलन आंदोलन में निहित है, और इसमें आंतरिक और बाहरी पहलू शामिल हैं, और यह सुनिश्चित करने के लिए तैयार किया गया है कि दबे-कुचले लोग अपनी स्वायत्तता को पुनर्प्राप्त सकें, अपने भाग्य की अध्यक्षता कर सकें, अपने लिए निर्णय लेने और अपने संसाधनों को नियंत्रित करने में सक्षम हों सकें।¹⁰⁷ मोटे तौर पर, आत्मनिर्णय के अधिकार में

¹⁰³United Nations Human Rights Office of the High Commissioner, *The United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples: A Manual for National Human Rights Institutions*, UN Doc HR/PUB/13/2 (Aug. 2013), p.no.5.

¹⁰⁴United Nations Human Rights Office of the High Commissioner, *Expert mechanism on the rights of indigenous peoples*, UN Res 6/36 (Jun. 18, 2007).

¹⁰⁵*Ibid.*

¹⁰⁶International Covenants on Civil and Political Rights, and on Economic, Social and Cultural Rights, 1966, art. 1.

¹⁰⁷United Nations Human Rights Council, *Free, prior and informed consent: a human rights-based approach, Study of the Expert Mechanism on the Rights of Indigenous Peoples*, UN Doc A/HRC/39/62 (Aug. 10, 2018), para. 6; Antonio Cassese, *Self-Determination of Peoples: A Legal Reappraisal* (Cambridge University Press, 1995); United Nations

लोगों को जबरदस्ती से मुक्त होने, गरिमा के साथ जीने और अपने सभी अन्य अधिकारों का समान रूप से आनंद लेने का अधिकार शामिल है, जिसमें उनके भविष्य के लिए जिम्मेदार होने का अधिकार, पूरी तरह से सूचित होना और स्वतंत्र रूप से इनकार करने या प्रस्तावों, योजनाओं, परियोजनाओं, कार्यक्रमों और प्रस्तावों को स्वीकार करने की स्थिति में होना शामिल है जो उन्हें या उनके संसाधनों को प्रभावित करते हैं।¹⁰⁸

स्वनिर्णय के अपने अधिकार के आधार पर, स्वदेशी लोगों के पास स्वशासन, स्वतंत्र निर्णय लेने और संस्थागत आत्मनिर्भरता की लंबी परंपराएं हैं। यह अच्छी तरह से समझा जाता है कि "स्वदेशी लोगों द्वारा उन्हें और उनकी भूमि, क्षेत्रों और संसाधनों को प्रभावित करने वाले विकास पर नियंत्रण उन्हें अपने संस्थानों, संस्कृतियों और परंपराओं को बनाए रखने और मजबूत करने और उनकी आकांक्षाओं और जरूरतों के अनुसार उनके विकास को बढ़ावा देने में सक्षम बनाएगा।"¹⁰⁹ यह अवधारणा इस मान्यता से उपजी है कि स्वदेशी लोगों के 'अंतर्निहित' अधिकार हैं जो उनकी राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक संरचनाओं और उनकी संस्कृतियों, आध्यात्मिक परंपराओं, इतिहास और दर्शन, विशेष रूप से उनकी भूमि, क्षेत्रों और संसाधनों पर उनके अधिकारों से प्राप्त होते हैं।¹¹⁰

आत्म-निर्णय के अपने अधिकार के तहत, स्वदेशी लोगों के पास हमेशा से ही यह अंतर्निहित शक्ति रहा है कि वे अपनी 'राष्ट्रों' और अन्य राजनीतिक सत्ताओं के बीच बाध्यकारी समझौते कर सकें। ऐतिहासिक रूप से, सरकारों के साथ पारस्परिक रूप से बातचीत करने के लिए संप्रभु राष्ट्रों के रूप में संगठित स्वदेशी लोग और बाध्यकारी संधियों को समाप्त करना, एक दूसरे के अधिकारों और दायित्वों पर सहमति से सहमत होना,¹¹¹ के कई क्षेत्रों में कई सौ वर्षों के लिए कई ऐसी संधियों के अधिकार को पहचानती है स्वदेशी लोगों के माध्यम से राजनीतिक और प्रशासनिक निर्णय लेने में भाग लेने के लिए उनकी अपनी प्रक्रियाओं के अनुसार उनके द्वारा चुने गए प्रतिनिधि, और अपने स्वयं के रखरखाव और विकास के लिए स्वदेशी संस्थान। यह प्रथा आज भी कई देशों में बनी हुई है जहाँ ऐसी संधियाँ देश का कानून बनी हुई हैं, भले ही वे अक्सर पूरी तरह से लागू नहीं किया गया है

¹¹²

आत्मनिर्णय के अधिकार से 'स्वतंत्र, पूर्व और सूचित सहमति' (एफपीआईसी)¹¹³ की धारणा प्रवाहित होती है जो केवल संबंधित लोगों के साथ परामर्श करने या उनके हितों से जुड़े मामलों पर निर्णय लेने में उनकी भागीदारी आमंत्रित करने की तुलना में अधिक कठिन दायित्व है। महत्वपूर्ण बात यह है कि एफपीआईसी में सहमति न देने का विकल्प भी शामिल है। संयुक्त राष्ट्र ने मूलनिवासी लोगों के संदर्भ में एफ. पी. आई. सी. की अवधारणा को इस प्रकार परिभाषित किया है: -

General Assembly, *Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples*, UN Doc A/RES/1514(XV) (Dec. 14, 1960), p. nos. 1-2.

¹⁰⁸ United Nations Human Rights Council, *Expert Mechanism on the Rights of Indigenous Peoples*, UN Doc A/HRC/39/62 (Aug. 10, 2018), para. 6.

Free, prior and informed consent: a human rights-based approach, Study of the

¹⁰⁹ The United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, 2007, preamble, para. 10.

¹¹⁰ *Id.* preamble, para. 7.

¹¹¹ United Nations Human Rights Council, *Expert Mechanism on the Rights of Indigenous Peoples*, UN Doc A/HRC/39/62 (Aug. 10, 2018), para. 4.

Free, prior and informed consent: a human rights-based approach, Study of the

¹¹² *Ibid.*

¹¹³ *Id.* at para. 3.

"स्वतंत्र का तात्पर्य है कि कोई जबरदस्ती, धमकी या हेरफेर नहीं है; पूर्व का तात्पर्य है कि किसी भी प्राधिकरण या गतिविधियों के प्रारंभ से पहले पर्याप्त रूप से सहमति मांगी जानी चाहिए और स्वदेशी परामर्श सर्वसम्मति प्रक्रियाओं की समय आवश्यकताओं के प्रति सम्मान किया जाना चाहिए; और सूचित का तात्पर्य है कि ऐसी जानकारी दी जाए जिसमें कई पहलू शामिल हों, जैसे किसी भी प्रस्तावित परियोजना या गतिविधि की प्रकृति, आकार, गति, प्रतिवर्तीता और दायरे, परियोजना के उद्देश्य के साथ साथ इसकी अवधि, स्थान और प्रभावित क्षेत्रों, संभावित आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और पर्यावरणीय प्रभाव का प्रारंभिक मूल्यांकन, जिसमें संभावित जोखिम, परियोजना के निष्पादन में शामिल होने वाले कर्मचारी शामिल हों; और परियोजनाएं जुड़ी प्रक्रियाएँ शामिल हो सकती हैं।"¹¹⁴

इस प्रकार एफपीआईसी स्वदेशी लोगों के अपने राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक प्राथमिकताओं को आत्म-निर्धारित करने के अधिकार की अभिव्यक्ति है और स्वदेशी लोगों के तीन परस्पर संबंधित अधिकारों का गठन करता है, जैसे परामर्श करने का अधिकार, भाग लेने का अधिकार, और उनकी भूमि, क्षेत्रों और संसाधनों का अधिकार।¹¹⁵

निम्नलिखित उप-धारा अंतरराष्ट्रीय कानूनी साधनों का पता लगाती है जो स्वदेशी लोगों के आत्मनिर्णय के अधिकार और भागीदारी, परामर्श और एफपीआईसी से जुड़े अधिकारों की स्पष्ट रूप से या निहित रूप से पुष्टि करते हैं:

1.1. स्वदेशी लोगों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र घोषणा, 2007

आत्मनिर्णय और स्वशासन

अनुच्छेद 3 स्वनिर्णय का मौलिक अधिकार प्रदान करता है, जो स्वदेशी लोगों को "स्वतंत्र रूप से अपनी राजनीतिक स्थिति निर्धारित करने और अपने स्वयं के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास को आगे बढ़ाने" में सक्षम बनाता है।¹¹⁶ अनुच्छेद 4 स्पष्ट करता है कि आत्मनिर्णय के अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए, स्वदेशी लोगों को स्वायत्तता या स्वशासन का अधिकार है। यह स्वायत्तता उनके "आंतरिक और स्थानीय मामलों" से संबंधित मामलों तक फैली हुई है, जिसमें "उनके स्वायत्त कार्यों के वित्तपोषण" के तरीके शामिल हैं।¹¹⁷ अनुच्छेद 5 स्वदेशी लोगों के "राज्य के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन में पूरी तरह से भाग लेने के अपने अधिकार को बनाए रखते हुए, अपने विशिष्ट राजनीतिक, कानूनी, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संस्थानों को बनाए रखने और मजबूत करने के अधिकार को मान्यता देता है।¹¹⁸ अनुच्छेद 33 आत्म-पहचान के महत्व को रेखांकित करता है, जो स्वदेशी लोगों को "अपने रीति-रिवाजों और परंपराओं के अनुसार अपनी पहचान या

¹¹⁴United Nations Human Rights Office of the High Commissioner, "What is the exact meaning of free, prior and informed consent?, Consultation and free, prior and informed consent (FPIC)" (Sep. 2013), available at: <https://www.ohchr.org/en/indigenous-peoples/consultation-and-free-prior-and-informed-consent-fpic> (last visited on Oct. 7, 2025).

¹¹⁵United Nations Human Rights Council, *Free, prior and informed consent: a human rights-based approach, Study of the Expert Mechanism on the Rights of Indigenous Peoples*, UN Doc A/HRC/39/62 (Aug. 10, 2018), para. 14.

¹¹⁶The United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, 2007, art. 3.

¹¹⁷*Id.* art. 4.

¹¹⁸*Id.* art. 5.

सदस्यता निर्धारित करने" की अनुमति देता है।¹¹⁹ अनुच्छेद 34 स्वदेशी लोगों के "अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार मानकों के अनुसार अपनी संस्थागत संरचनाओं और अपने विशिष्ट रीति-रिवाजों, आध्यात्मिकता, परंपराओं, प्रक्रियाओं, प्रथाओं और उन मामलों में जहां वे मौजूद हैं, न्यायिक प्रणालियों या रीति-रिवाजों को बढ़ावा देने, विकसित करने और बनाए रखने के अधिकार को स्वीकार करता है।¹²⁰ नतीजतन, स्वदेशी लोगों को अपने स्वयं के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास को निर्धारित करने और अपने लाभ के लिए अपने स्वयं के प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन करने का अधिकार है। स्वदेशी लोगों के साथ परामर्श करने और उनके एफ. पी. आई. सी. प्राप्त करने के कर्तव्य आत्मनिर्णय के अधिकार के महत्वपूर्ण तत्व हैं।¹²¹

भागीदारी और परामर्श

अनुच्छेद 18 यह स्थापित करता है कि "स्वदेशी लोगों को उन मामलों में निर्णय लेने में भाग लेने का अधिकार है जो उनकी प्रक्रियाओं के अनुसार स्वयं चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से उनके अधिकारों को प्रभावित करेंगे, साथ ही साथ अपने स्वयं के स्वदेशी निर्णय लेने वाले संस्थानों को बनाए रखने और विकसित करने का अधिकार है"।¹²² अनुच्छेद 41 संयुक्त राष्ट्र प्रणाली और अन्य अंतर-सरकारी संगठनों से यूएनडीआरआईपी के प्रावधानों को पूरी तरह से साकार करने में योगदान करने की अपेक्षा करता है, जिसमें "उन्हें प्रभावित करने वाले मुद्दों पर स्वदेशी लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के तरीके और साधन" स्थापित करना शामिल है।¹²³ विशेषज्ञ तंत्र ने नोट किया है कि आत्मनिर्णय एक निरंतर प्रक्रिया है जो यह सुनिश्चित करती है कि स्वदेशी लोग निर्णय लेने में भाग लेते रहें और अपने भाग्य पर नियंत्रण रखें।¹²⁴

एफपीआईसी

राज्यों का दायित्व है कि वे निम्नलिखित में से कोई भी कार्रवाई करने से पहले स्वदेशी लोगों के एफपीआईसी की तलाश करें:

- स्वदेशी लोगों को उनकी भूमि या क्षेत्रों से स्थानांतरित करना;¹²⁵
- "कानून या प्रशासनिक उपायों" को अपनाना जो स्वदेशी लोगों को प्रभावित करते हैं;¹²⁶
- स्वदेशी भूमि पर "खतरनाक सामग्री का भंडारण या निपटान";¹²⁷ और
- उन परियोजनाओं का उपक्रम जो स्वदेशी लोगों के "भूमि या क्षेत्रों

¹¹⁹ *Id.* art. 33.1.

¹²⁰ *Id.* art. 34.

¹²¹ United Nations Human Rights Council, *Final study on indigenous peoples and the right to participate in decision-making. Report of the Expert Mechanism on the Rights of Indigenous Peoples*, UN Doc A/HRC/EMRIP/2011/2 (May 26, 2011) paras. 17-26.

¹²² The United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, 2007, art. 18.

¹²³ *Id.* art. 41.

¹²⁴ United Nations Human Rights Council, *Progress report on the study on indigenous peoples and the right to participate in decision-making-Report of the Expert Mechanism on the Rights of Indigenous Peoples*, UN Doc A/HRC/15/35 (Aug. 23, 2010), para. 31.

¹²⁵ The United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, 2007, art. 10.

¹²⁶ *Id.* art. 19.

¹²⁷ *Id.* art. 29.2.

और अन्य संसाधनों" के अधिकार को प्रभावित करते हैं, जिसमें "खनिज, पानी या अन्य संसाधनों का विकास, उपयोग या शोषण" शामिल है।¹²⁸

इसके अलावा, अनुच्छेद 28 के अनुसार, स्वदेशी लोग जिनकी भूमि को उनकी स्वतंत्र, पूर्व और सूचित सहमति के बिना जब्त कर लिया गया है, ले लिया गया है, कब्जा कर लिया गया है या क्षतिग्रस्त कर दिया गया है, वे क्षतिपूर्ति या अन्य उचित निवारण के हकदार हैं जिसमें आकार और गुणवत्ता में समान भूमि, या न्यायसंगत, उचित और न्यायसंगत मुआवजा शामिल हो सकता है।¹²⁹ इसी तरह, अनुच्छेद 11 के तहत, स्वदेशी लोग भी अपनी एफपीआईसी के बिना ली गई "सांस्कृतिक, बौद्धिक, धार्मिक और आध्यात्मिक संपत्ति" के संबंध में निवारण के हकदार हैं।¹³⁰

विशेषज्ञ तंत्र के अनुसार, एफपीआईसी का अधिकार आत्मनिर्णय के अधिकार का एक "अभिन्न तत्व" है, और स्वदेशी लोगों के अधिकारों, अस्तित्व, गरिमा और कल्याण के लिए मौलिक महत्व के मामलों में सर्वोत्कृष्ट है।¹³¹ इसी तरह, स्वदेशी लोगों के अधिकारों पर विशेष प्रतिवेदक ने जोर देकर कहा है कि "स्वदेशी लोगों के जीवन या क्षेत्रों पर एक महत्वपूर्ण प्रत्यक्ष प्रभाव एक मजबूत धारणा स्थापित करता है कि प्रस्तावित उपाय स्वदेशी लोगों की सहमति के बिना आगे नहीं बढ़ना चाहिए। कुछ संदर्भों में, अनुमान स्वदेशी सहमति के अभाव में उपाय या परियोजना के निषेध में कठोर हो सकता है।¹³²

1.2. स्वदेशी और जनजातीय लोक सम्मेलन, 1989 और स्वदेशी और जनजातीय जनसंख्या सम्मेलन, 1957

आत्मनिर्णय और स्वशासन

आईएलओ कन्वेंशन नं. 169 स्वदेशी लोगों के लिए आत्म-पहचान के महत्व को रेखांकित करता है।

अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि आईएलओ कन्वेंशन नं. 169 उन स्वदेशी लोगों पर लागू होता है जो इस तरह से 'आत्म-पहचान' करते हैं।¹³³ हालाँकि, स्वदेशी के रूप में आत्म-पहचान के अधिकार को पहले के आई. एल. ओ. कन्वेंशन नं. 107 से मान्यता नहीं दी गई है।

भागीदारी और परामर्श

आईएलओ कन्वेंशन नं. 169 के अनुच्छेद 2 में कहा गया है कि "इन लोगों के अधिकारों की रक्षा करने और उनकी अखंडता के लिए सम्मान की गारंटी देने के लिए संबंधित लोगों की भागीदारी के साथ, समन्वित और व्यवस्थित

¹²⁸*Id.* arts. 32.1, 32.2.

¹²⁹*Id.* art. 28.

¹³⁰*Id.* art. 11.2.

¹³¹United Nations Human Rights Council, *Final study on indigenous peoples and their right to participate in decision-making, Report of the Expert Mechanism on the Rights of Indigenous Peoples*, UN Doc A/HRC/EMRIP/2011/2 (May 26, 2011), p.no. 17.

¹³²United Nations Human Rights Council, *Promotion and Protection of All Human Rights, Civil, Political, Economic, Social and Cultural Rights, Including the Right to Development, Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights and fundamental freedoms of indigenous people*, UN Doc A/HRC/12/34 (Jul. 15, 2009), para. 47.

¹³³The Indigenous and Tribal Peoples Convention, 1989 (No. 169), art. 1.2.

कार्रवाई को विकसित करने की जिम्मेदारी सरकार की होगी।"¹³⁴ इसके अलावा, "जब भी विधायी या प्रशासनिक उपायों पर विचार किया जा रहा है जो उन्हें सीधे प्रभावित कर सकते हैं" स्वदेशी लोगों के साथ परामर्श अनिवार्य है;¹³⁵ "उनकी भूमि से संबंधित ऐसे संसाधनों के अन्वेषण या शोषण" से पहले;¹³⁶ और "उनकी भूमि को अलग करने या उन्हें अपने समुदाय के बाहर प्रसारित करने" के लिए निर्णय लेने में।¹³⁷ अनुच्छेद 22 विशेष व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के संगठन और संचालन में स्वदेशी लोगों की स्वैच्छिक भागीदारी के साथ-साथ सहयोग और परामर्श का भी प्रावधान करता है।¹³⁸

इस बीच, आईएलओ कन्वेंशन नं. 107, अनुच्छेद 5 राज्यों को इसके प्रावधानों को लागू करने में, स्वदेशी आबादी और उनके प्रतिनिधियों के "सहयोग की तलाश" करने¹³⁹ और "नागरिक स्वतंत्रता की इन आबादी के बीच विकास और वैकल्पिक संस्थानों की स्थापना या भागीदारी" को प्रोत्साहित करने का आदेश देता है।¹⁴⁰

एफपीआईसी

आईएलओ कन्वेंशन नं. 169 के अनुच्छेद 16 में कहा गया है कि स्वदेशी लोगों को दूसरी जगह ले जाना एक खास उपाय के तौर पर ज़रूरी समझा जाता है, तो ऐसा विस्थापन इन लोगों की केवल "स्वतंत्र और सूचित सहमति" से ही होगा।¹⁴¹ फिर भी, इस संबंध में एक छूट दी गई है: "जहाँ उनकी सहमति प्राप्त नहीं की जा सकती, वहाँ ऐसा स्थानांतरण केवल राष्ट्रीय कानूनों और विनियमों द्वारा स्थापित उचित प्रक्रियाओं का पालन करते हुए ही किया जाएगा, जिसमें जहाँ उपयुक्त हो, सार्वजनिक पूछताछ भी शामिल है, ताकि संबंधित लोगों को अपनी बात प्रभावी ढंग से रखने का मौका मिल सके।"¹⁴²

इसकी तुलना में, आईएलओ कन्वेंशन नं. 107, एफपीआईसी का दायरा सीमित और केवल आई. एल. ओ. कन्वेंशन सं. 169 में निहित पूर्वगामी छूट को समाहित करता है।: स्वदेशी आबादी को "राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित कारणों से, या राष्ट्रीय आर्थिक विकास या उक्त आबादी के स्वास्थ्य के हित में, राष्ट्रीय कानूनों और विनियमों के अनुसार, उन्हें उनके निवास क्षेत्र से उनकी स्वतंत्र सहमति के बिना नहीं हटाया जाएगा।"¹⁴³

¹³⁴*Id.* art. 2.1.

¹³⁵*Id.* art. 6.1.a.

¹³⁶*Id.* art. 15.2.

¹³⁷*Id.* art. 17.2.

¹³⁸*Id.* art. 22.3.

¹³⁹The Indigenous and Tribal Populations Convention, 1957 (No. 107), art. 5.a.

¹⁴⁰*Id.* art. 5.c.

¹⁴¹The Indigenous and Tribal Peoples Convention, 1989 (No. 169), art. 16.2.

¹⁴²*Ibid.*

¹⁴³The Indigenous and Tribal Populations Convention, 1957 (No. 107), art. 12.1.

1.3. नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय समझौता, 1966

आत्मनिर्णय और स्वशासन

अनुच्छेद 1 सभी लोगों को आत्मनिर्णय के अधिकार की गारंटी देता है।¹⁴⁴ अनुच्छेद 1 में आगे कहा गया है कि सभी लोगों को अपने उद्देश्यों के लिए अपनी प्राकृतिक संपत्ति और संसाधनों का स्वतंत्र रूप से निपटान करने का अधिकार है।¹⁴⁵ अनुच्छेद 1 राज्यों को "आत्मनिर्णय के अधिकार की प्राप्ति को बढ़ावा देने और... संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के प्रावधानों के अनुरूप उस अधिकार का सम्मान करने" के लिए भी बाध्य करता है।¹⁴⁶ चूँकि अनुच्छेद 1 सामान्य रूप से सभी लोगों पर लागू होता है, यह स्वदेशी लोगों पर भी लागू होता है।¹⁴⁷

भागीदारी और परामर्श

अनुच्छेद 25 प्रत्येक नागरिक को "प्रत्यक्ष रूप से या स्वतंत्र रूप से चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से सार्वजनिक मामलों के संचालन में भाग लेने और मतदान करने और वास्तविक आवधिक चुनावों में चुने जाने का अधिकार प्रदान करता है"।¹⁴⁸ हालांकि एक सामान्य प्रावधान, अनुच्छेद 25 को राजनीतिक भागीदारी के लिए स्वदेशी लोगों के विशिष्ट अधिकारों की रक्षा के रूप में समझा गया है क्योंकि नागरिकों के बीच नस्ल, रंग, लिंग, भाषा, धर्म, राजनीतिक या अन्य राय, राष्ट्रीय या सामाजिक मूल, संपत्ति, जन्म या अन्य स्थिति के आधार पर किसी भी भेदभाव की अनुमति नहीं है।¹⁴⁹

1.4. आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय वाचा, 1966

आत्मनिर्णय और स्वशासन

आई. सी. सी. पी. आर. के समान, आई. सी. ई. एस. सी. आर. का अनुच्छेद 1 यह भी निर्धारित करता है कि सभी लोगों को आत्मनिर्णय का अधिकार है।¹⁵⁰ कई देशों ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि उनके क्षेत्रों में स्वदेशी समुदाय आईसीसीएससीआर और आईसीसीपीआर के अनुच्छेद 1 के दायरे में आते हैं।¹⁵¹

भागीदारी और परामर्श

सी. ई. एस. सी. आर. ने अपनी सामान्य टिप्पणी नं. 21, ने विशेष रूप से राज्यों के दायित्व का उल्लेख किया है:

¹⁴⁴The International Covenant on Civil and Political Rights, 1966, art. 1.1.

¹⁴⁵*Id.* art. 1.2.

¹⁴⁶*Id.* art. 1.3.

¹⁴⁷Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, *Reporting under the International Covenant on Civil and Political Rights, Training Guide* (2021), p. no. 20.

¹⁴⁸The International Covenant on Civil and Political Rights, 1966, arts. 25.a, 25.b.

¹⁴⁹United Nations Human Rights Committee, *General Comment No. 25: Article 25 (Participation in Public Affairs and the Right to Vote) The Right to Participate in Public Affairs, Voting Rights and the Right of Equal Access to Public Service*, UN Doc CCPR/C/21/Rev.1/Add.7 (Jul. 12, 1996), para. 3.

¹⁵⁰The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, 1966, art. 1.1.

¹⁵¹United Nations Committee on Economic, Social and Cultural Rights, *ICESCR, UN Doc E/C.12/SWE/5* (Sept. 6, 2006), para. 7.

Fifth Period Report on the implementation of

“... स्वदेशी लोगों से संबंधित व्यक्तियों की भागीदारी की अनुमति दें और उन्हें प्रोत्साहित करें... उन कानूनों और नीतियों के डिजाइन और कार्यान्वयन में जो उन्हें प्रभावित करते हैं।”¹⁵² तदनुसार, सीईएससीआर ने यह भी सिफारिश की कि पनबिजली परियोजनाओं के निर्माण से पहले, एक राज्य व्यापक प्रभाव आकलन और प्रभावित स्वदेशी समुदायों के साथ व्यापक परामर्श करने के लिए कर्तव्यबद्ध है, जिससे उन्हें अपने विचार प्रस्तुत करने और निर्णय लेने को प्रभावित करने के लिए वास्तविक अवसर प्रदान किए जा सकें।¹⁵³

एफपीआईसी

सामान्य टिप्पणी नं. 21 में, सीईएससीआर ने राज्यों से "अपने विशिष्ट अधिकारों के दायरे में आने वाले सभी मामलों में स्वदेशी लोगों की स्वतंत्र, पूर्व और सूचित सहमति के सिद्धांत का सम्मान करने" और "जब उनके सांस्कृतिक संसाधनों, विशेष रूप से उनके जीवन शैली और सांस्कृतिक अभिव्यक्ति से जुड़े लोगों का संरक्षण जोखिम में हो तो उनकी स्वतंत्र और सूचित पूर्व सहमति प्राप्त करने" का आह्वान किया है।¹⁵⁴ सी. ई. एस. सी. आर. ने आगे उल्लेख किया कि सांस्कृतिक जीवन में भाग लेने के अधिकार में स्वदेशी लोगों का भूमि, क्षेत्रों और संसाधनों की बहाली या वापसी का अधिकार शामिल है, जो पारंपरिक रूप से स्वदेशी समुदायों द्वारा उपयोग और आनंद लिया जाता है, अगर उनके एफ. पी. आई. सी. के बिना लिया जाता है।¹⁵⁵ सी. ई. एस. सी. आर. ने संसाधन दोहन के संबंध में स्वदेशी लोगों की सहमति प्राप्त करने की आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला है और कहा है कि यह "गहराई से चिंतित है कि संबंधित समुदायों की पूर्ण सहमति के बिना अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों को प्राकृतिक निष्कर्षण रियायतें दी गई हैं।"¹⁵⁶ सी. ई. एस. सी. आर. ने यह भी खेद के साथ कहा कि "स्वदेशी लोगों के पारंपरिक भूमि को उनकी सहमति के बिना, लकड़ी, खनन और तेल कंपनियों द्वारा नुकसान दिया है या उन पर कब्जा कर लिया है, जिससे उनकी संस्कृति और पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन बिगड़ गया है।"¹⁵⁷

¹⁵² United Nations Committee on Economic, Social and Cultural Rights, General Comment No. 21, Right to everyone to take part in cultural life (art. 15, para. 1(a) of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights), UN Doc E/C.12/GC/21 (Dec. 21, 2009), para. 55e.

¹⁵³ United Nations Committee on Economic, Social and Cultural Rights, Consideration of Reports Submitted by States Parties under Articles 15 and 17 of the Covenant, Concluding Observations of the Committee on Economic, Social and Cultural Rights, UN Doc E/C.12/ETH/CO/1-3 (May 31, 2012), para. 24.

¹⁵⁴ United Nations Committee on Economic, Social and Cultural Rights, General Comment No. 21, Right to everyone to take part in cultural life (art. 15, para. 1(a) of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights), UN Doc E/C.12/GC/21 (Dec. 21, 2009), para. 37.

¹⁵⁵ *Id.* at para. 36.

¹⁵⁶ United Nations Committee on Economic, Social and Cultural Rights, Consideration of Reports Submitted by States Parties Under Articles 15 and 17 of the Covenant, Concluding Observations of the Committee on Economic, Social and Cultural Rights, UN Doc E/C.12/1/Add.100 (Jun. 7, 2004), para. 12.

¹⁵⁷ United Nations Committee on Economic, Social and Cultural Rights, Report on the Twenty-Fifth, Twenty-Sixth and Twenty-Seventh Sessions, Consideration of Reports of States Parties, U.N. Doc E/C.12/2001/17 (2002), para. 761.

1.5. नस्लीय भेदभाव के सभी रूपों के उन्मूलन पर अंतर्राष्ट्रीय समझौता, 1965

भागीदारी, परामर्श और एफपीआईसी

सी. ई. आर. डी. ने आई. सी. ई. आर. डी. की व्याख्या और अनुप्रयोग में स्वदेशी लोगों के साथ परामर्श और सूचित सहमति दोनों का आह्वान किया है। सीईआरडी ने इसकी सामान्य अनुशंसा सं. 23 में, राज्यों से "यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया कि स्वदेशी लोगों के सदस्यों को सार्वजनिक जीवन में प्रभावी भागीदारी के संबंध में अधिकार हैं और उनके अधिकारों और हितों से सीधे संबंधित कोई भी निर्णय उनकी सूचित सहमति के बिना नहीं लिया जाता है।"¹⁵⁸ सीईआरडी ने यह भी सिफारिश की है कि संवैधानिक वार्ता प्रक्रियाओं के दौरान एफपीआईसी के सिद्धांत का सम्मान किया जाना चाहिए और स्वदेशी लोगों के प्रतिनिधियों की भागीदारी के महत्व को रेखांकित किया है।¹⁵⁹ सी. ई. आर. डी. ने यह सुनिश्चित करने के लिए राज्यों के दायित्व को भी दोहराया है कि एफ. पी. आई. सी. के लिए स्वदेशी लोगों के अधिकार का उनकी भूमि और संसाधनों के उपयोग को प्रभावित करने वाली परियोजनाओं की योजना और कार्यान्वयन में विशेष रूप से सम्मान किया जाए।¹⁶⁰

1.6. जैविक विविधता पर सम्मेलन, 1992

भागीदारी और एफपीआईसी

सीबीडी निर्णय वी/16 के लिए पार्टियों का पांचवां सम्मेलन अपने सामान्य सिद्धांतों में एफपीआईसी के कार्यान्वयन के लिए एक दृढ़ प्रतिबद्धता व्यक्त करता है: "स्वदेशी और स्थानीय समुदायों के पारंपरिक ज्ञान, नवाचार और प्रथाओं तक पहुंच पूर्व सूचित सहमति या पूर्व सूचित अनुमोदन के अधीन होनी चाहिए।"¹⁶¹ निर्णय वी/16 आगे "पक्षों से आह्वान करता है कि वे जैविक विविधता के संरक्षण और सतत उपयोग के लिए प्रासंगिक अपने पारंपरिक ज्ञान, नवाचारों और प्रथाओं के उपयोग से संबंधित निर्णय लेने में प्रभावी ढंग से शामिल होने के लिए स्वदेशी और स्थानीय समुदायों की क्षमता को बढ़ाने और मजबूत करने के लिए उपाय करें।"¹⁶²

¹⁵⁸United Nations Committee on the Elimination of Racial Discrimination, General Recommendation No. 23: Indigenous Peoples, UN Doc A/52/18 (Aug. 18, 1997), para. 4(d).

¹⁵⁹United Nations Committee for the Elimination of Racial Discrimination, Early warning letter to the Government of Nepal (Mar. 13, 2009), available at: <https://www.lahurnip.org/uploads/resource/file/cerd-committee%27s-first-early-warning-letters-to-nepal-government-eng.pdf> (last visited on Oct. 10, 2025).

¹⁶⁰United Nations Committee on the Elimination of Racial Discrimination, Consideration of report submitted by States parties under article 9 of the Convention Concluding observations of the Committee on the Elimination of Racial Discrimination, CERD/C/LAO/CO/16-18 (Apr. 13, 2012) para. 17; United Nations Committee on the Elimination of Racial Discrimination, Consideration of reports submitted by States parties under article 9 of the convention, Concluding observations of the Committee on the Elimination of Racial Discrimination, CERD/C/CAN/CO/19-20 (Apr. 4, 2012).

¹⁶¹Parshuram Tamang, An Overview of the Principle of Free, Prior and Informed Consent and Indigenous Peoples in International and Domestic Law and Practices, UN DESA, UN Doc PFII/2004/WS.2/8 (2005), para. 14.

¹⁶²Ibid.

2. भूमि, वन और संसाधन

भूमि और क्षेत्र मूल रूप से स्वदेशी लोगों की पहचान के लिए महत्वपूर्ण हैं-उनके पारंपरिक व्यवसायों, शिल्प और अन्य सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों सहित उनके जीवन का अनुठा तरीका, हमेशा उनकी पैतृक भूमि, जंगलों और प्राकृतिक संसाधनों तक उनकी पहुंच और अधिकारों पर निर्भर रहा है।¹⁶³ स्वदेशी अर्थव्यवस्था का आधार बनाने के अलावा, स्वदेशी लोग भूमि के साथ एक गहरा आध्यात्मिक संबंध भी साझा करते हैं, अक्सर प्रकृति के तत्वों या उन पवित्र स्थलों की पूजा करते हैं जहां उनके पूर्वजों को दफनाया जाता है।¹⁶⁴ इसलिए, स्वदेशी लोग लगातार भूमि का स्थायी रूप से उपयोग करने और अपने लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए पानी, मिट्टी, वनस्पतियों और जीवों को संरक्षित करने का प्रयास करते हैं। स्वदेशी लोगों के अस्तित्व के लिए भूमि और क्षेत्रों की केंद्रीयता को स्वीकार करते हुए, यूएनपीएफआईआई ने दोहराया:¹⁶⁵

*"भूमि दुनिया भर के स्वदेशी लोगों के जीवन और संस्कृतियों की नींव है। यही कारण है कि भूमि, क्षेत्रों और प्राकृतिक संसाधनों पर उनके अधिकार की रक्षा अंतर्राष्ट्रीय स्वदेशी लोगों के आंदोलन और हर जगह स्वदेशी लोगों और संगठनों की एक प्रमुख मांग है। यह भी स्पष्ट है कि अधिकांश स्थानीय और राष्ट्रीय स्वदेशी लोगों के आंदोलन उन नीतियों और कार्यों के खिलाफ संघर्षों से उभरे हैं जिन्होंने उनके प्रथागत भूमि कार्यकाल और संसाधन प्रबंधन प्रणालियों को कमजोर और भेदभाव किया है, उनकी भूमि को जब्त कर लिया है, उनकी सहमति के बिना उनके संसाधनों को निकाला है और उनके विस्थापन और उनके क्षेत्रों से बेदखल कर दिया है। अपनी भूमि, क्षेत्रों और प्राकृतिक संसाधनों पर उनके अधिकारों तक पहुंच और सम्मान के बिना, स्वदेशी लोगों की विशेष, विशिष्ट संस्कृतियों का अस्तित्व खतरे में है। भूमि अधिकार, भूमि तक पहुंच और उस पर और उसके संसाधनों पर नियंत्रण दुनिया भर के स्वदेशी लोगों के लिए केंद्रीय हैं, और वे अपने भौतिक और सांस्कृतिक अस्तित्व के लिए ऐसे अधिकारों और पहुंच पर निर्भर करते हैं। अलग-अलग लोगों के रूप में जीवित रहने के लिए, स्वदेशी लोगों और उनके समुदायों को अपने क्षेत्रों, भूमि और संसाधनों का स्वामित्व, संरक्षण और प्रबंधन करने में सक्षम होने की आवश्यकता है।"*¹⁶⁶

निम्नलिखित उप-धारा उन प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय कानूनी साधनों की पहचान करती है जो स्वदेशी लोगों के भूमि, वन और प्राकृतिक संसाधनों के अधिकार की रक्षा करते हैं।

2.1. स्वदेशी लोगों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र घोषणा, 2007

प्रस्तावना स्पष्ट रूप से स्वीकार करती है कि "स्वदेशी लोगों द्वारा उन्हें और उनकी भूमि, क्षेत्रों और संसाधनों को प्रभावित करने वाले विकास पर नियंत्रण उन्हें अपने संस्थानों, संस्कृतियों और परंपराओं को बनाए रखने और मजबूत करने और उनकी आकांक्षाओं और जरूरतों के अनुसार उनके विकास को बढ़ावा देने में

¹⁶³United Nations, *State of the World's Indigenous Peoples*, Vol. I, (May 2011), p. no. 53.

¹⁶⁴*Ibid.*

¹⁶⁵*Id.* at 54.

¹⁶⁶United Nations Permanent Forum on Indigenous Issues, *Report on the Sixth Session (14-25 May 2007)*, UN Doc. E/2007/43 (2007), paras. 5, 6.

सक्षम बनाएगा।”¹⁶⁷ यू. एन. डी. आर. आई. पी. के कई प्रावधान भूमि, क्षेत्रों और संसाधनों पर स्वदेशी लोगों के अधिकारों को संबोधित करते हैं:

- अनुच्छेद 25 स्वदेशी लोगों के “पारंपरिक रूप से स्वामित्व वाली या अन्यथा कब्जे वाली और उपयोग की जाने वाली भूमि, क्षेत्रों, जल और तटीय समुद्रों और अन्य संसाधनों के साथ अपने विशिष्ट आध्यात्मिक संबंध को बनाए रखने और मजबूत करने” के अधिकार की पुष्टि करता है;¹⁶⁸
- अनुच्छेद 26(3) राज्यों पर यह दायित्व डालता है कि वे “इन ज़मीनों, क्षेत्रों और संसाधनों को कानूनी मान्यता दें... और ऐसा करते समय संबंधित मूल निवासियों की रीति-रिवाजों, परंपराओं और ज़मीन के मालिकाना हक की प्रणालियों का उचित सम्मान करें”;¹⁶⁹
- अनुच्छेद 27 में प्रावधान है कि राज्यों को “अपनी भूमि, क्षेत्रों और संसाधनों से संबंधित स्वदेशी लोगों के अधिकारों को पहचानने और न्याय करने के लिए संबंधित स्वदेशी लोगों के साथ मिलकर एक निष्पक्ष, स्वतंत्र, निष्पक्ष, खुली और पारदर्शी प्रक्रिया की स्थापना और कार्यान्वयन करना चाहिए”;¹⁷⁰
- अनुच्छेद 28 स्वदेशी लोगों के “निवारण के अधिकार को मान्यता देता है, जिसमें उनकी भूमि और संसाधनों के लिए उनके एफपीआईसी के बिना ली गई भूमि और संसाधनों के लिए उचित और न्यायसंगत मुआवजा शामिल हो सकता है”;¹⁷¹
- अनुच्छेद 29 स्वदेशी लोगों के एफपीआईसी के बिना उनकी भूमि पर “खतरनाक सामग्री के भंडारण या निपटान” को प्रतिबंधित करता है, साथ ही साथ “उनकी भूमि या क्षेत्रों और संसाधनों की उत्पादक क्षमता के संरक्षण और संरक्षण” के उनके अधिकार को मान्यता देता है;¹⁷²
- अनुच्छेद 30 “स्वदेशी लोगों की भूमि या क्षेत्रों के सैन्य उपयोग को विनियमित करता है, जब तक कि एक प्रासंगिक सार्वजनिक हित द्वारा उचित न हो”;¹⁷³ और राज्यों को उनकी भूमि के संरक्षण और संरक्षण के अधिकार को परिभाषित करने या उनकी प्राथमिकताओं को प्रभावित करने वाली रणनीतियों को विकसित करने या विकसित करने की आवश्यकता है।¹⁷⁴

2.2. स्वदेशी एवं जनजातीय लोक सम्मेलन, 1989 तथा स्वदेशी एवं जनजातीय जनसंख्या सम्मेलन, 1957
आईएलओ कन्वेंशन का अनुच्छेद 7 नं. 169 स्वदेशी लोगों के “विकास की प्रक्रिया के लिए अपनी प्राथमिकताएं तय करने के अधिकार की रक्षा करता है क्योंकि यह उन भूमि को प्रभावित करता है जिन पर वे कब्जा करते हैं या अन्यथा उपयोग करते हैं।”¹⁷⁵ अनुच्छेद 13 “भूमि” को “क्षेत्रों की अवधारणा को शामिल करने के रूप में परिभाषित करता है, जो उन क्षेत्रों के कुल पर्यावरण को शामिल करता है जिन

¹⁶⁷ The United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, 2007 (promulgated).

¹⁶⁸ Id. art. 25.

¹⁶⁹ Id. art. 26.3.

¹⁷⁰ Id. art. 27.

¹⁷¹ Id. art. 28.1.

¹⁷² Id. arts. 29.1, 29.2.

¹⁷³ Id. art. 30.1.

¹⁷⁴ Id. arts. 32.1, 32.2.

¹⁷⁵ The Indigenous and Tribal Peoples Convention, 1989 (No. 169), art. 7.1.

पर संबंधित लोग कब्जा करते हैं या अन्यथा उपयोग करते हैं"।¹⁷⁶ अनुच्छेद 13 राज्यों को "भूमि या क्षेत्रों के साथ उनके संबंधों से संबंधित लोगों की संस्कृतियों और आध्यात्मिक मूल्यों के लिए विशेष महत्व" का सम्मान करने के लिए भी बाध्य करता है।¹⁷⁷ अनुच्छेद 14 राज्यों से "उन भूमि पर संबंधित लोगों के स्वामित्व और कब्जे के अधिकारों को मान्यता देने की अपेक्षा करता है जिन पर वे पारंपरिक रूप से कब्जा करते हैं", साथ ही "उन भूमि का उपयोग करने के उनके अधिकार की रक्षा करते हैं जिन पर विशेष रूप से उनके द्वारा कब्जा नहीं किया गया है, लेकिन जिन पर पारंपरिक रूप से उनकी पहुंच थी।"¹⁷⁸ अनुच्छेद 15 "अपनी भूमि से संबंधित प्राकृतिक संसाधनों से संबंधित लोगों के अधिकारों" की गारंटी देता है, और किसी भी संसाधन अन्वेषण या शोषण से पहले स्वदेशी लोगों के साथ परामर्श को अनिवार्य करता है।¹⁷⁹ अनुच्छेद 16 स्वदेशी लोगों को "उनके कब्जे वाली ज़मीन" से हटाने पर रोक लगाता है, सिवाय तब के जब ऐसा करना किसी "खास वजह" से ज़रूरी हो और उनकी FPIC (फ्री, प्रायर और इन्फॉर्मड कंसेंट) ली गई हो।¹⁸⁰ अनुच्छेद 16 ऐसे विस्थापित स्वदेशी लोगों के अधिकार को भी सुरक्षित करता है "जैसे ही स्थानांतरण के आधार का अस्तित्व समाप्त हो जाता है, वे अपनी पारंपरिक भूमि पर लौट सकते हैं।"¹⁸¹ अनुच्छेद 17 में कहा गया है कि "इन लोगों के सदस्यों के बीच भूमि अधिकारों के संचरण के लिए संबंधित लोगों द्वारा स्थापित प्रक्रियाओं का सम्मान किया जाएगा", और यह कि दूसरों को "उनके रीति रिवाजों का लाभ उठाने या उनके सदस्यों की ओर से भूमि के स्वामित्व, कब्जे या उपयोग को सुरक्षित करने के लिए कानूनों की समझ की कमी से रोका जाएगा"।¹⁸² अनुच्छेद 18 "संबंधित लोगों की भूमि पर अनधिकृत घुसपैठ या उपयोग के लिए... पर्याप्त दंड" की स्थापना का आदेश देता है और राज्यों को ऐसे अपराधों को रोकने के लिए उपाय करने का कार्य देता है।¹⁸³ अनुच्छेद 19 राष्ट्रीय कृषि कार्यक्रमों का आह्वान करता है कि वे "स्वदेशी लोगों को 'आबादी के अन्य वर्गों के बराबर' सुविधाएँ मिल सकें। इसमें 'सामान्य जीवन जीने के लिए ज़रूरी चीज़ों को उपलब्ध कराने के लिए और ज़मीन देने' और 'उनके पास पहले से मौजूद ज़मीन के विकास को बढ़ावा देने के लिए ज़रूरी साधन उपलब्ध कराने' की बात कही गई है।"¹⁸⁴

आई. एल. ओ. कन्वेंशन का अनुच्छेद 11 सं. 107 उन भूमि पर स्वदेशी आबादी के "सामूहिक या व्यक्तिगत स्वामित्व के अधिकार" को भी मान्यता देता है जिन पर ये आबादी पारंपरिक रूप से कब्जा करती है।¹⁸⁵ अनुच्छेद 12 "राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित कारणों से या राष्ट्रीय आर्थिक विकास के हित में या उक्त आबादी के स्वास्थ्य के लिए राष्ट्रीय कानूनों और विनियमों के अनुसार" को छोड़कर, स्वदेशी आबादी को उनकी स्वतंत्र सहमति के बिना "उनके अभ्यस्त क्षेत्रों से" हटाने पर रोक लगाता है।¹⁸⁶ यदि एक "असाधारण उपाय"

¹⁷⁶Id.art.13.2.

¹⁷⁷Id.art.13.1.

¹⁷⁸Id.art.14.1.

¹⁷⁹Id.art.15.

¹⁸⁰Id.arts.16.1,16.2.

¹⁸¹Id.art.16.3.

¹⁸²Id.arts.17.1,17.3.

¹⁸³Id.art.18.

¹⁸⁴Id.art.19.

¹⁸⁵The Indigenous and Tribal Populations Convention, 1957 (No.107), art.11.

¹⁸⁶Id.art.12.1.

के रूप में स्वदेशी आबादी को हटाना आवश्यक है," तो अनुच्छेद 12 यह भी आदेश देता है कि उन्हें "कम से कम पहले उनके द्वारा कब्जा की गई भूमि के बराबर गुणवत्ता वाली भूमि प्रदान की जाए"।¹⁸⁷ अनुच्छेद 13 की अपेक्षा है कि "भूमि के स्वामित्व और उपयोग के अधिकारों के संचरण के लिए प्रक्रियाएं जो संबंधित आबादी के रीति-रिवाजों द्वारा स्थापित की गई हैं" का सम्मान किया जाए,¹⁸⁸ और "साथ ही, ऐसे उपाय किए जाने चाहिए जिनसे "जो लोग संबंधित आबादी का हिस्सा नहीं हैं, वे इन रीति-रिवाजों या कानूनों की जानकारी न होने का फायदा उठाकर उस आबादी के सदस्यों की ज़मीन का मालिकाना हक या इस्तेमाल का अधिकार हासिल न कर सकें"।"¹⁸⁹ अनुच्छेद 14 में कहा गया है कि राष्ट्रीय कृषि कार्यक्रमों को अतिरिक्त भूमि के प्रावधान या पहले से ही उनके कब्जे वाली भूमि को विकसित करने के साधनों के प्रावधान में स्वदेशी आबादी के साथ राष्ट्रीय समुदाय के अन्य वर्गों के समान व्यवहार करना चाहिए।¹⁹⁰

2.3. भेदभाव (रोजगार और व्यवसाय) समझौता, 1958

भेदभाव (रोजगार और व्यवसाय) कन्वेंशन, 1958 (जिसे आमतौर पर आई. एल. ओ. कन्वेंशन नं. 111)¹⁹¹ आईएलओ ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि उनकी पारंपरिक भूमि और संसाधनों तक पहुंच या नियंत्रण की कमी स्वदेशी लोगों के लिए व्यवसाय के समान अवसरों तक पहुंच में एक महत्वपूर्ण बाधा हो सकती है, जिससे भेदभाव का एक रूप बनता है: भूमि और प्राकृतिक संसाधनों तक पहुंच आम तौर पर स्वदेशी लोगों के लिए अपने पारंपरिक व्यवसायों में संलग्न होने का आधार है। इसलिए जिन भूमि पर वे पारंपरिक रूप से कब्जा करते हैं, उनके स्वामित्व और कब्जे की मान्यता, पारंपरिक गतिविधियों के लिए उपयोग की जाने वाली भूमि तक पहुंच और जिन क्षेत्रों में वे रहते हैं, उनके पर्यावरण की रक्षा के उपाय स्वदेशी लोगों को अपने पारंपरिक व्यवसायों को आगे बढ़ाने में सक्षम बनाने के लिए महत्वपूर्ण हैं।¹⁹²

2.4. नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय समझौता, 1966

अनुच्छेद 1 सभी लोगों के आत्मनिर्णय के अधिकार की गारंटी देता है, जिसमें "अपनी प्राकृतिक संपत्ति का स्वतंत्र रूप से निपटान" और उनके "निर्वाह के साधनों" को सुरक्षित करना शामिल है।¹⁹³ यद्यपि विशेष रूप से स्वदेशी लोगों के अधिकारों को संबोधित नहीं किया गया है, अनुच्छेद 1 को एचआरसी द्वारा उनकी पारंपरिक भूमि, क्षेत्रों और संसाधनों के अधिकार के संरक्षण के लिए व्यापक रूप से लागू किया गया है। उदाहरण के लिए, भूमि और संसाधन आवंटन से संबंधित एक राष्ट्रीय उपाय के जवाब में, एचआरसी ने कहा: "समिति यह भी सिफारिश करती है कि अंतर्निहित आदिवासी अधिकारों को समाप्त करने की प्रथा को समझौता के अनुच्छेद 1 के

¹⁸⁷Id.art.12.2.

¹⁸⁸Id.art.13.1.

¹⁸⁹Id.art.13.2.

¹⁹⁰Id.art.14.

¹⁹¹The Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No.111).

¹⁹²International Labour Standards Department, *Eliminating discrimination against indigenous and tribal peoples in employment and occupation: A Guide to ILO Convention No.111* (2007), p.no.14.

¹⁹³The International Covenant on Civil and Political Rights, 1966, art. 1.2.

के साथ असंगत के रूप में छोड़ दिया जाए।”¹⁹⁴. एचआरसी ने अनुच्छेद 1 में आत्मनिर्णय के अधिकार और अनुच्छेद 27,¹⁹⁵ के अनुसार अपनी संस्कृति का आनंद लेने के लिए स्वदेशी लोगों सहित अल्पसंख्यकों के अधिकार के बीच अंतर-संबंध को भी नोट किया है, जिसमें उनकी भूमि और संसाधनों, निर्वाह और पवित्र स्थलों की सुरक्षा शामिल है: “स्वदेशी व्यक्तियों के खिताब और हितों को उनकी मूल भूमि में बहाल करने और उनकी रक्षा करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए... स्वदेशी अल्पसंख्यकों (शिकार, मछली पकड़ने और इकट्ठा होने) की अर्थव्यवस्था के पारंपरिक रूपों की निरंतरता और स्थिरता को सुरक्षित करना और ऐसे अल्पसंख्यकों के लिए धार्मिक या सांस्कृतिक महत्व के स्थलों की सुरक्षा... को अनुच्छेद 27 के तहत संरक्षित किया जाना चाहिए”।¹⁹⁶.

2.5. आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतराष्ट्रीय समझौता, 1966

सीईएससीआर ने स्वदेशी लोगों के अपने पारंपरिक क्षेत्रों और प्राकृतिक संसाधनों के अधिकारों की रक्षा के लिए आईसीईएससीआर के प्रावधानों की व्याख्या उनके आत्मनिर्णय और सांस्कृतिक अस्तित्व के एक आवश्यक पहलू के रूप में की है। अपनी सामान्य टिप्पणी में नं. 21, सी. ई. एस. सी. आर. ने कहा कि “स्वदेशी लोगों के सांस्कृतिक जीवन का मजबूत सांप्रदायिक आयाम उनके अस्तित्व, कल्याण और पूर्ण विकास के लिए अपरिहार्य है, और इसमें उन भूमि, क्षेत्रों और संसाधनों का अधिकार शामिल है, जिन पर उन्होंने पारंपरिक रूप से स्वामित्व, कब्जा या अन्यथा उपयोग या अधिग्रहण किया है।”¹⁹⁷. सी. ई. एस. सी. आर. ने स्वदेशी लोगों के आत्मनिर्णय के अधिकार के संबंध में प्राकृतिक संसाधनों तक पहुंच के अधिकार का भी स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है: “समझौता के अनुच्छेद 1, पैराग्राफ 2 में कर्तव्य का उल्लेख करते हुए, जो यह प्रदान करता है कि लोग ‘अपने निर्वाह के साधनों से वंचित नहीं हो सकते हैं’, राज्यों के दिलों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि स्वदेशी लोगों की आजीविका को सुरक्षित करने के लिए पानी

¹⁹⁴United Nations International Covenant on Civil and Political Rights Human Rights Council, *Consideration of reports submitted by States parties under article 40 of the Covenant- Concluding observations of the Human Rights Committee, Canada*, UN Doc CCPR/C/79/Add.105 (Apr. 7, 1999), para. 8; United Nations International Covenant on Civil and Political Rights Human Rights Council, *Consideration of Reports Submitted by State Parties under Article 40 of the Covenant- Concluding observations of the Human Rights Committee, Mexico*, UN Doc No. CCPR/C/79/Add.109 (Jul. 27, 1999), para. 19; United Nations International Covenant on Civil and Political Rights Human Rights Council, *Consideration of reports submitted by States parties under article 40 of the Covenant- Concluding observations of the Human Rights Committee, Norway*, UN Doc No. CCPR/C/79/Add.112 (1999), paras. 10, 17; and United Nations International Covenant on Civil and Political Rights Human Rights Council, *Consideration of reports submitted by States parties under article 40 of the Covenant- Concluding observations of the Human Rights Committee, Australia*, UN Doc No. CCPR/CO/69/AUS (2000), para. 8.

¹⁹⁵The Human Rights Committee, *Guidelines for the treaty-specific document to be submitted by States parties under article 40 of the International Covenant on Civil and Political Rights*, UN Doc CCPR/C/2009/1 (Nov. 22, 2010), para. 28; United Nations Human Rights Committee, *Apirana Mahuika et al. v. New Zealand*, Communication No. 547/1993, New Zealand, UN Doc No. CCPR/C/70/D/547/1993 (Nov. 16, 2000), para. 9.2.

¹⁹⁶United Nations Human Rights Committee, *Concluding observations of the Human Rights Committee: Australia*, UN Doc No. CCPR/CO/69/AUS (2000), paras. 10, 11.

¹⁹⁷United Nations Committee on Economic, Social and Cultural Rights, *General Comment No. 21, Right to everyone to take part in cultural life*, art. 15, para. 1(a) of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, UN Doc E/C.12/GC/21 (Dec. 21, 2009), para. 36.

तक पर्याप्त पहुंच है।¹⁹⁸

2.6. नस्लीय भेदभाव के सभी रूपों के उन्मूलन पर अंतर्राष्ट्रीय समझौता, 1965

अनुच्छेद 1 "विशेष रूप से कुछ नस्लीय या जातीय समूहों या व्यक्तियों की पर्याप्त उन्नति सुनिश्चित करने के लिए विशेष उपायों को अपनाने की अनुमति देता है, जिन्हें ऐसी सुरक्षा की आवश्यकता होती है जो उनके समान आनंद या मानवाधिकारों और मौलिक स्वतंत्रताओं के प्रयोग को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हो।"¹⁹⁹ इसके अलावा, अनुच्छेद 5 नस्लीय भेदभाव के खिलाफ व्यक्तियों के अधिकार और "कानून के समक्ष समानता"²⁰⁰ के उनके अधिकार को सुरक्षित करता है, जिसमें "संपत्ति के मालिक होने का अधिकार" भी शामिल है।²⁰¹ सी. ई. आर. डी. ने इन अधिकारों "को ऐतिहासिक रूप से स्वदेशी आबादी द्वारा कब्जा की गई या उपयोग की जाने वाली भूमि और संसाधनों के स्वामित्व और नियंत्रण के संबंध में लागू किया है। सी. ई. आर. डी. ने इसकी सामान्य अनुशंसा सं. 23, में राज्यों से "अपनी सांप्रदायिक भूमि, क्षेत्रों और संसाधनों के स्वामित्व, विकास, नियंत्रण और उपयोग के लिए स्वदेशी लोगों के अधिकारों को पहचानने और उनकी रक्षा करने" का आह्वान किया है।²⁰² इसके अलावा, स्वदेशी लोगों की भूमि और संसाधन अधिकारों से संबंधित मामलों को संबोधित करने के लिए सी. ई. आर. डी. की प्रारंभिक चेतावनी और तत्काल कार्रवाई प्रक्रियाओं का तेजी से उपयोग किया जा रहा है।²⁰³

2.7. बाल अधिकारों पर समझौता, 1989

अनुच्छेद 30 स्पष्ट रूप से अन्य के अलावा, स्वदेशी बच्चों के सांस्कृतिक अधिकारों की रक्षा करता है,²⁰⁴ जिसे बाल अधिकारों पर समिति ने उनकी पारंपरिक भूमि और संसाधनों के अधिकार के रूप में भी व्याख्या की है: "अनुच्छेद 30 के तहत अधिकारों का आनंद, विशेष रूप से किसी की संस्कृति का आनंद लेने का अधिकार, जीवन का एक तरीका हो सकता है जो क्षेत्र और उसके संसाधनों के उपयोग से निकटता से जुड़ा हुआ है। यह विशेष रूप से अल्पसंख्यक का गठन करने वाले स्वदेशी समुदायों के सदस्यों के बारे में सच हो सकता है।"²⁰⁵

2.8. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा, 2012 के संदर्भ में भूमि, मत्स्य पालन और वनों के कार्यकाल के जिम्मेदार शासन पर स्वैच्छिक दिशानिर्देश राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा, 2012

वीजीजीटी के संदर्भ में भूमि, मत्स्य पालन और वनों के कार्यकाल के जिम्मेदार शासन पर स्वैच्छिक दिशानिर्देश स्वदेशी समुदायों के संबंध में

¹⁹⁸International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, General Comment No. 15: The right to water (arts. 11 and 12), UN Doc No. E/C.12/2002/11 (Jan. 20, 2003), para. 7.

¹⁹⁹The International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, 1965, art. 1.4.

²⁰⁰*Id.* art. 5.

²⁰¹*Id.* art. 5.d.v.

²⁰²United Nations Committee on the Elimination of Racial Discrimination, *Peoples*, UN Doc A/52/18 (Aug. 18, 1997), para. 5.

General Recommendation No. 23: Indigenous

²⁰³Birgitte Feiring, *Indigenous peoples' Rights to Lands, Territories and Resources* (International Land Coalition, 2013), p. no. 25.

²⁰⁴The United Nations Convention on the Rights of the Child, 1989, art. 30.

²⁰⁵United Nations Committee on the Rights of the Child, *Day of general discussion on the rights of indigenous children: recommendations*, UN Doc CRC/C/133 (Dec. 4, 2003), para. 4.

सांस्कृतिक, पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभाव आकलन को नियंत्रित करने के लिए सीबीडी के तत्वावधान में विकसित किए गए हैं।²⁰⁶ वी. जी. जी. टी. कमजोर और हाशिए पर पड़े लोगों पर जोर देने के साथ "सभी के लाभ के लिए" भूमि, मत्स्य पालन और वनों के प्रबंधन में सुधार के लिए सिद्धांत और सिफारिशें निर्धारित करता है।²⁰⁷ स्वदेशी लोगों के संदर्भ में, वी. जी. जी. टी. में राज्यों से यह स्वीकार करने की आवश्यकता है कि भूमि, मत्स्य पालन और वनों का स्वदेशी लोगों और पारंपरिक कार्यकाल प्रणालियों वाले अन्य समुदायों के लिए सामाजिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, आर्थिक, पर्यावरणीय और राजनीतिक मूल्य है।²⁰⁸ तदनुसार, वी. जी. जी. टी. में कहा गया है कि भूमि कार्यकाल अधिकारों को मान्यता देने या आवंटित करने की प्रक्रिया में, राज्यों को "पहले सभी मौजूदा कार्यकाल अधिकारों और अधिकार धारकों की पहचान करनी चाहिए, चाहे वे दर्ज हों या नहीं", साथ ही "प्रथागत कार्यकाल प्रणाली" वाले प्रभावित स्वदेशी लोगों से परामर्श करना चाहिए।²⁰⁹

2.9 सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा, 2015

संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाया गया 2030 एजेंडा, गरीबी और भूख को उनके सभी रूपों और आयामों में समाप्त करने का प्रयास करता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि "कोई भी पीछे न छूटे"।²¹⁰ स्वदेशी लोगों के लिए, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य (एस. डी. जी.) गरीबी में कमी को प्राथमिकता देते हैं, विशेष रूप से उनके भूमि अधिकारों की मान्यता के माध्यम से: 2030 तक कृषि उत्पादकता और छोटे पैमाने के खाद्य उत्पादकों, विशेष रूप से महिलाओं, स्वदेशी लोगों, पारिवारिक किसानों, चरवाहों और मछुआरों की आय को दोगुना करना, जिसमें भूमि, अन्य उत्पादक संसाधनों तक सुरक्षित और समान पहुंच शामिल है।²¹¹

3. आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक सुरक्षा उपाय

आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार वे मानवाधिकार हैं जो कार्यस्थल, सामाजिक सुरक्षा, पारिवारिक जीवन, सांस्कृतिक जीवन में भागीदारी और आवास, भोजन, पानी, स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा तक पहुंच से संबंधित हैं।²¹²

इसमें जीवन स्तर के पर्याप्त स्तर का अधिकार, वैज्ञानिक प्रगति से लाभ के साथ-साथ साहित्यिक और कलात्मक प्रस्तुतियों में नैतिक और भौतिक हितों का संरक्षण भी शामिल है।²¹³ हालांकि अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कानून देशों को लोगों के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों को

²⁰⁶ Secretariat of the Convention on Biological Diversity, *Akwé:Kon Voluntary Guidelines for the Conduct of Cultural, Environmental and Social Impact Assessment regarding Developments Proposed to Take Place on, or which are Likely to Impact on, Sacred Sites and on Lands and Waters Traditionally Occupied or Used by Indigenous and Local Communities* (2004), available at: <https://www.cbd.int/doc/publications/akwe-brochure-en.pdf> (last visited on Oct. 5, 2025).

²⁰⁷ Food and Agriculture Organization of the United Nations, *Voluntary Guidelines on the Responsible Governance of Tenure of Land, Fisheries and Forests in the Context of National Food Security* (2012), para. 1.1.

²⁰⁸ *Id.* at para. 9.1.

²⁰⁹ *Id.* at para. 7.3.

²¹⁰ United Nations General Assembly, *Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development: Resolution adopted by the General Assembly on 25 September 2015*, UN Doc A/RES/70/1 (Oct. 2015), preamble, para. 2.

²¹¹ *Id.* Goal 2, Target 2.3.

²¹² The Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, *Frequently Asked Questions on Economic, Social and Cultural Rights*, available at: <https://www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet33en.pdf> (last visited on Oct. 5, 2025).

²¹³ *Ibid.*

सुरक्षित करने का निर्देश देता है, लेकिन ज़रूरी संसाधनों की उपलब्धता के कारण "इन अधिकारों को पूरी तरह से हासिल करने" में बाधा आ सकती है।²¹⁴ स्वदेशी लोगों के लिए, अपने स्वयं के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के संरक्षण के संबंध में आत्मनिर्णय के अपने अधिकार का प्रयोग करने में ज्यादातर मामलों में उनकी असमर्थता एक अतिरिक्त बाधा है।²¹⁵ इसलिए स्वदेशी लोगों के लिए विशेष प्रतिवेदक ने जोर देकर कहा है: "यह राज्यों का कर्तव्य है कि वे स्वदेशी लोगों के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों का सम्मान करें, उनकी रक्षा करें और उन्हें पूरा करें, जो न केवल स्वदेशी लोगों के अधिकारों पर विशिष्ट साधनों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता पर आधारित है, जैसे कि यूएनडीआरआईपी और आईएलओ कन्वेंशन नं। 169, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय समझौता और अन्य लागू मानवाधिकार उपकरणों के तहत उनके कर्तव्य का एक अभिन्न तत्व है" ²¹⁶ और इन अन्य अंतर्राष्ट्रीय कानूनी साधनों से उपजी राज्यों की जिम्मेदारियों और दायित्वों का विवरण नीचे दिया गया है:

3.1. स्वदेशी लोगों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र घोषणा, 2007

यू. एन. डी. आर. आई. पी. अपनी प्रस्तावना में, मानता है कि "मूल निवासियों को ऐतिहासिक अन्याय का सामना करना पड़ा है, जिसकी वजहों में उनके उपनिवेशीकरण और उनकी ज़मीन, इलाकों और संसाधनों से उन्हें बेदखल किया जाना शामिल है; इस वजह से वे, खास तौर पर, अपनी ज़रूरतों और हितों के अनुसार विकास के अपने अधिकार का इस्तेमाल नहीं कर पाए हैं।"²¹⁷ अनुच्छेद 5 स्वदेशी लोगों के "राज्य के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन में पूरी तरह से भाग लेने के अपने अधिकार को बनाए रखते हुए, अपने विशिष्ट राजनीतिक, कानूनी, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संस्थानों को बनाए रखने और मजबूत करने" के अधिकार की पुष्टि करता है।²¹⁸ अनुच्छेद 8 स्वदेशी लोगों के सांस्कृतिक मूल्यों और पहचान की रक्षा करता है, ताकि उनकी "जबरन आत्मसात या उनकी संस्कृति के विनाश" को रोका जा सके।²¹⁹ इसके अलावा, अनुच्छेद 9 स्वदेशी लोगों के "संबंधित समुदाय या राष्ट्र की परंपराओं और रीति-रिवाजों के अनुसार, एक स्वदेशी समुदाय या राष्ट्र से संबंधित होने के अधिकार" को मान्यता देता है।²²⁰ अनुच्छेद 11 उनकी संस्कृतियों की अतीत, वर्तमान और भविष्य की अभिव्यक्तियों को बनाए रखने, उनकी रक्षा करने और विकसित करने की क्षमता सहित उनकी "सांस्कृतिक परंपराओं और रीति-रिवाजों का अभ्यास करने और उन्हें पुनर्जीवित करने के अधिकार" को स्वीकार करता है।²²¹ अनुच्छेद 13 स्वदेशी लोगों के इतिहास, भाषाओं, मौखिक परंपराओं, दर्शन, लेखन प्रणालियों और साहित्य सहित अपनी सांस्कृतिक विरासत को "पुनर्जीवित करने, उपयोग करने,

²¹⁴This is evident from the formulation of The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, 1966, art. 2.1: "Each State Party to the present Covenant undertakes to take steps, individually and through international assistance and co-operation, especially economic and technical, to the maximum of its available resources, with a view to achieving progressively the full realization of the rights recognized in the present Covenant by all appropriate means, including particularly the adoption of legislative measures."

²¹⁵United Nations Human Rights Council, Special Rapporteur on Rights of Indigenous Peoples, *Rights of Indigenous Peoples, Including Their Economic, Social and Cultural Rights in The Post-2015 Development Framework Note by The Secretary-General*, UN Doc A/69/267 (Aug. 6, 2014), p. no. 2.

²¹⁶*Id.* at para. 13.

²¹⁷The United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, 2007, preamble, para. 6.

²¹⁸*Id.* art. 5.

²¹⁹*Id.* art. 8.

²²⁰*Id.* art. 9.

²²¹*Id.* art. 11.1.

विकसित करने और प्रसारित करने" के अधिकार की रक्षा करता है।²²²

अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि स्वदेशी लोगों को अपनी "संस्कृतियों, परंपराओं, इतिहास और आकांक्षाओं को शिक्षा और सार्वजनिक जानकारी दोनों में प्रतिबिंबित करने" का अधिकार है।²²³ अनुच्छेद 17 स्वदेशी बच्चों को "आर्थिक शोषण" और ऐसे किसी भी काम को करने से बचाने का प्रावधान करता है जो खतरनाक हो सकता है, या बच्चे की शिक्षा में बाधा डाल सकता है, या बच्चे के स्वास्थ्य या शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, नैतिक या सामाजिक विकास के लिए हानिकारक हो सकता है। इसमें बच्चों की विशेष संवेदनशीलता और उनके सशक्तिकरण के लिए शिक्षा के महत्व को ध्यान में रखा गया है।²²⁴ अनुच्छेद 20 स्वदेशी लोगों को अपनी "राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक प्रणालियों" को बनाए रखने और विकसित करने और पारंपरिक आर्थिक गतिविधियों में संलग्न होने का अधिकार स्थापित करता है, साथ ही यह भी सुनिश्चित करता है कि यदि वे अपने निर्वाह के साधनों से वंचित हैं तो वे न्यायसंगत और निष्पक्ष निवारण के हकदार हैं।²²⁵ संबंधित रूप से, अनुच्छेद 21 और 22 "शिक्षा, रोजगार, व्यावसायिक प्रशिक्षण और पुनर्प्रशिक्षण, आवास, स्वच्छता, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा"²²⁶ जैसे क्षेत्रों में स्वदेशी लोगों की "आर्थिक और सामाजिक स्थितियों" में सुधार के अधिकार की गारंटी देते हैं, जिसमें "स्वदेशी बुजुर्गों, महिलाओं, युवाओं, बच्चों और विकलांग व्यक्तियों" जैसे कमजोर समूहों के अधिकारों और जरूरतों को बचाने पर विशेष ध्यान दिया गया है।²²⁷ अंत में, अनुच्छेद 23 और 24 स्वदेशी लोगों को अपने विकास के लिए प्राथमिकताएं और रणनीतियां तय करने, अपने विकास पर असर डालने वाले कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से भाग लेने, और बिना किसी भेदभाव के पारंपरिक सामाजिक और स्वास्थ्य सेवाओं के सर्वोत्तम संभव स्तर तक पहुँचने का अधिकार देते हैं।²²⁸

3.2. स्वदेशी एवं जनजातीय लोक सम्मेलन, 1989 तथा स्वदेशी एवं जनजातीय जनसंख्या सम्मेलन, 1957

आईएलओ कन्वेंशन नं. 169, अनुच्छेद 2 राज्यों को "उनकी सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान, उनके रीति-रिवाजों और परंपराओं और उनके संस्थानों के संबंध में" स्वदेशी लोगों के "सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अधिकारों की पूर्ण प्राप्ति" को बढ़ावा देने के लिए "समन्वित और व्यवस्थित कार्रवाई" विकसित करने के लिए बाध्य करता है।²²⁹ अनुच्छेद 7 स्वदेशी लोगों के "अपनी प्राथमिकताएं खुद तय करने... और अपने आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास पर यथासंभव नियंत्रण रखने" के अधिकार को मान्यता देता है।²³⁰ तदनुसार, अनुच्छेद 7 राज्यों को यह सुनिश्चित करने के लिए भी बाध्य करता है कि "जब भी उचित हो, स्वदेशी लोगों पर नियोजित विकास गतिविधियों के सामाजिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और पर्यावरणीय प्रभाव का

²²²Id.art.13.1.

²²³Id.art.15.1.

²²⁴Id.art.17.2.

²²⁵Id.art.20.

²²⁶Id.art.21.1.

²²⁷Id.art.22.1.

²²⁸Id.arts.23,24.

²²⁹The Indigenous and Tribal Peoples Convention, 1989 (No. 169), art. 2.

²³⁰Id.art. 7.1.

आकलन करने के लिए अध्ययन किए जाएं।²³¹ अनुच्छेद 10 राज्यों से घरेलू आपराधिक कानूनों के तहत दंड लगाते समय स्वदेशी लोगों की "आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विशेषताओं" को ध्यान में रखने की अपेक्षा करता है।²³² अनुच्छेद 20 राज्यों से "चिकित्सा और सामाजिक सहायता, व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य, सभी सामाजिक सुरक्षा लाभों और किसी भी अन्य व्यावसायिक रूप से संबंधित लाभों और आवास" के संबंध में स्वदेशी श्रमिकों के खिलाफ "किसी भी भेदभाव को रोकने के लिए हर संभव प्रयास" करने की अपेक्षा करता है।²³³ अनुच्छेद 22 में कहा गया है कि स्वदेशी श्रमिकों के विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम "संबंधित लोगों के आर्थिक वातावरण, सामाजिक और सांस्कृतिक स्थितियों और व्यावहारिक जरूरतों पर आधारित" होंगे।²³⁴ अनुच्छेद 23 स्वदेशी लोगों के "हस्तशिल्प, ग्रामीण और समुदाय आधारित उद्योगों, और निर्वाह अर्थव्यवस्था और पारंपरिक गतिविधियों" को उनकी संस्कृतियों के रखरखाव और उनकी आर्थिक आत्मनिर्भरता और विकास में महत्वपूर्ण कारकों के रूप में मान्यता देता है।²³⁵ अनुच्छेद 24 राज्यों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का विस्तार स्वदेशी लोगों तक करने का आदेश देता है।²³⁶ अनुच्छेद 25 में निर्धारित किया गया है कि स्वास्थ्य सेवाओं की योजना और प्रशासन स्वदेशी लोगों के सहयोग से किया जाएगा, और उनकी आर्थिक, भौगोलिक, सामाजिक और सांस्कृतिक स्थितियों के साथ-साथ उनकी पारंपरिक निवारक देखभाल, उपचार प्रथाओं और दवाओं के लिए जिम्मेदार होगा।²³⁷ अनुच्छेद 27 में कहा गया है कि स्वदेशी लोगों के लिए शिक्षा कार्यक्रम "उनकी विशेष जरूरतों को पूरा करने के लिए उनके सहयोग से विकसित और कार्यान्वित किए जाएंगे, और उनके इतिहास, उनके ज्ञान और प्रौद्योगिकियों, उनकी मूल्य प्रणालियों और उनकी आगे की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक आकांक्षाओं को शामिल करेंगे।²³⁸ अनुच्छेद 25 में स्वास्थ्य सेवाओं को "संबंधित लोगों के सहयोग से नियोजित और प्रशासित" करने और पारंपरिक निवारक देखभाल और उपचार प्रथाओं को शामिल करने की आवश्यकता है।²³⁹

आई. एल. ओ. सम्मेलन की प्रस्तावना सं. 107 में कहा गया है कि "विभिन्न स्वतंत्र देशों में स्वदेशी और अन्य जनजातीय और अर्ध-जनजातीय आबादी मौजूद हैं जो अभी तक राष्ट्रीय समुदाय में एकीकृत नहीं हैं और जिनकी सामाजिक, आर्थिक या सांस्कृतिक स्थिति उन्हें आबादी के अन्य तत्वों द्वारा प्राप्त अधिकारों और लाभों से पूरी तरह से लाभान्वित होने से रोकती है।"²⁴⁰ अनुच्छेद 2 राज्यों को स्वदेशी आबादी के "सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास" को बढ़ावा देने और "उनके जीवन स्तर" को बढ़ाने का आदेश देता है।²⁴¹ अनुच्छेद 3 राज्यों से यह सुनिश्चित करने के लिए "विशेष उपाय" करने की अपेक्षा करता है कि स्वदेशी आबादी की "सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक स्थितियां" उन्हें "उस देश के सामान्य कानूनों के लाभों का आनंद

²³¹Id.art.7.3.

²³²Id.art.10.1.

²³³Id.art.20.2.c.

²³⁴Id.art.22.3.

²³⁵Id.art.23.1.

²³⁶Id.art.24.

²³⁷Id.art.25.2.

²³⁸Id.art.27.1.

²³⁹Id.art.25.2.

²⁴⁰The Indigenous and Tribal Populations Convention, 1957 (No.107), preamble, para.5.

²⁴¹Id.art.2.2.b.

लेने से नहीं रोकती हैं जिससे वे संबंधित हैं", बशर्ते कि "इन उपायों का उपयोग अलगाव की स्थिति बनाने या बढ़ाने के साधन के रूप में नहीं किया जाता है" और एक बार इस तरह के विशेष संरक्षण की आवश्यकता नहीं होने पर उन्हें बंद कर दिया जाता है।²⁴² अनुच्छेद 4 में कहा गया है कि स्वदेशी आबादी को एकीकृत करते समय, सांस्कृतिक और धार्मिक मूल्यों और मौजूदा सामाजिक नियंत्रण के रूपों को उनके सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन को सुविधाजनक बनाने की दिशा में ध्यान में रखा जाना चाहिए।²⁴³ अनुच्छेद 6 में कहा गया है कि "स्वदेशी आबादी के जीवन की स्थितियों और काम और शिक्षा के स्तर में सुधार" को "समग्र आर्थिक विकास की योजनाओं में उच्च प्राथमिकता" दी जाएगी।²⁴⁴ अनुच्छेद 15 राज्यों को "चिकित्सा और सामाजिक सहायता, रोजगार चोटों की रोकथाम, श्रमिकों के मुआवजे, औद्योगिक स्वच्छता और आवास" के संबंध में स्वदेशी श्रमिकों के खिलाफ "सभी भेदभाव को रोकने के लिए हर संभव प्रयास" करने के लिए बाध्य करता है।²⁴⁵ अनुच्छेद 16 स्वदेशी श्रमिकों को व्यावसायिक प्रशिक्षण के अवसरों में समानता की रक्षा करता है,²⁴⁶ और अनुच्छेद 17 स्वदेशी आबादी को "आर्थिक वातावरण, सांस्कृतिक विकास के चरण और व्यावहारिक जरूरतों के सावधानीपूर्वक अध्ययन" के आधार पर विशेष प्रशिक्षण सुविधाओं की गारंटी देता है।²⁴⁷ अनुच्छेद 18 राज्यों से स्वदेशी आबादी की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करते हुए और "उनके कलात्मक मूल्यों और सांस्कृतिक अभिव्यक्ति के विशेष तरीकों" में सुधार करते हुए, स्वदेशी आबादी के "आर्थिक विकास के कारकों" के रूप में हस्तशिल्प और ग्रामीण उद्योगों को प्रोत्साहित करने की अपेक्षा करता है।²⁴⁸ अनुच्छेद 19 के अनुसार, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को स्वदेशी आबादी तक "उत्तरोत्तर विस्तारित" किया जाना चाहिए।²⁴⁹ अनुच्छेद 20 के तहत, राज्यों का कर्तव्य है कि वे "सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक स्थितियों के व्यवस्थित अध्ययन" के आधार पर और "सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास के सामान्य उपायों" के साथ समन्वय में स्वदेशी आबादी को "पर्याप्त स्वास्थ्य सेवाएं" प्रदान करें।²⁵⁰

3.3 आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय वाचा, 1966

अनुच्छेद 1 "सभी लोगों" के आत्मनिर्णय के अधिकार को मान्यता देता है, जिसमें "स्वतंत्र रूप से अपने आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास को आगे बढ़ाने" का अधिकार भी शामिल है।²⁵¹ अनुच्छेद 15 सभी व्यक्तियों के "सांस्कृतिक जीवन में भाग लेने" के अधिकार की गारंटी देता है, और राज्यों से संस्कृति के अधिकार की "पूर्ण प्राप्ति" प्राप्त करने के लिए कदम उठाने की अपेक्षा करता है।²⁵² अपनी सामान्य टिप्पणी सं. 21, सीईएससीआर टिप्पणी सं. 21 विशेष रूप से स्वदेशी सांस्कृतिक अधिकारों को संबोधित करता है, इस बात पर जोर देते हुए कि स्वदेशी लोगों के सांस्कृतिक अधिकारों में अक्सर सामूहिक आयाम होते हैं

²⁴²Id.arts.3.1,3.2.a.

²⁴³Id.art.4.a.

²⁴⁴Id.art.6.

²⁴⁵Id.art.15.2.c.

²⁴⁶Id.art.16.

²⁴⁷Id.art.17.

²⁴⁸Id.art.18.

²⁴⁹Id.art.19.

²⁵⁰Id.art.20.

²⁵¹The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, 1966, art. 1.1.

²⁵²Id.art.15.

जिनके लिए विशेष सुरक्षात्मक उपायों की आवश्यकता होती है।²⁵³ सी. ई. एस. सी. आर. ने कहा है कि "हर किसी को समुदाय के सांस्कृतिक जीवन में स्वतंत्र रूप से भाग लेने का अधिकार है", जिसमें स्वदेशी लोग भी शामिल हैं।²⁵⁴ इसमें स्वदेशी लोगों के अपने सांस्कृतिक संस्थानों, पैतृक भूमि, प्राकृतिक संसाधनों और पारंपरिक ज्ञान के अधिकार और विकास का अधिकार भी शामिल है।²⁵⁵

3.4 नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय समझौता, 1966

अनुच्छेद 27 राज्यों को "जातीय, धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यकों" को "अपनी संस्कृति का आनंद लेने, अपने धर्म को मानने और उसका पालन करने, या अपनी भाषा का उपयोग करने" के अधिकार से वंचित करने पर प्रतिबंध लगाता है।²⁵⁶ अपनी सामान्य टिप्पणी में नं. 23, एच. आर. सी. ने कहा: "संस्कृति कई रूपों में सामने आती है, खासकर स्वदेशी लोगों के मामले में जिसमें ज़मीन के संसाधनों के इस्तेमाल से जुड़ी एक खास जीवन शैली शामिल है। इस अधिकार में मछली पकड़ना या शिकार करना जैसी पारंपरिक गतिविधियाँ, और कानून द्वारा संरक्षित रिजर्व में रहने का अधिकार शामिल हो सकता है। इन अधिकारों का आनंद लेने के लिए सुरक्षा के लिए सकारात्मक कानूनी उपायों और अल्पसंख्यक समुदायों के सदस्यों की उन फैसलों में प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित करने के उपायों की आवश्यकता हो सकती है जो उन्हें प्रभावित करते हैं।"²⁵⁷

3.5 बाल अधिकारों पर समझौता, 1989

अनुच्छेद 30 राज्यों को स्वदेशी बच्चों को "अपनी संस्कृति का आनंद लेने, अपने धर्म का पालन करने या अपनी भाषा का उपयोग करने" के अधिकार से वंचित करने से रोकता है।²⁵⁸

3.6 नस्लीय भेदभाव के सभी रूपों के उन्मूलन पर अंतर्राष्ट्रीय समझौता, 1965

अनुच्छेद 5 राज्यों को सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अधिकारों के उपभोग में "सभी रूपों में नस्लीय भेदभाव को प्रतिबंधित और समाप्त करने और नस्ल, रंग या राष्ट्रीय या जातीय मूल के भेदभाव के बिना सभी के अधिकार की गारंटी देने" के लिए आदेश देता है,²⁵⁹ इन अधिकारों में काम करने, ट्रेड यूनियन बनाने और उनमें शामिल होने, आवास, सार्वजनिक स्वास्थ्य, चिकित्सा देखभाल, सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक सेवाओं, शिक्षा और प्रशिक्षण; सांस्कृतिक गतिविधियों में समान भागीदारी; और आम जनता के

²⁵³United Nations Committee on Economic, Social and Cultural Rights, General Comment No. 21, Right to everyone to take part in cultural life (art. 15, para. 1(a), of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights), UN Doc E/C.12/GC/21 (Dec. 21, 2009), para. 37.

²⁵⁴Id. at para. 4.

²⁵⁵Id. at para. 3.

²⁵⁶The International Covenant on Civil and Political Rights, 1966, art. 27; The Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, Reporting under the International Covenant on Civil and Political Rights, Training Guide (2021), p. no. 20.

²⁵⁷United Nations International Human Rights Instruments, General Comment No. 23, Compilation of General Comments and General Recommendations Adopted by Human Rights Treaty Bodies, UN Doc. HRI/GEN/1/Rev.1 (Jul. 29, 1994), para. 6(2).

²⁵⁸The United Nations Convention on the Rights of the Child, 1989, art. 30.

²⁵⁹The International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination 1965, art. 5.e.

के इस्तेमाल के लिए बनी किसी भी जगह या सेवा (जैसे ट्रांसपोर्ट, होटल, रेस्तरां, कैफे, थिएटर और पार्क) तक पहुंच शामिल है।²⁶⁰ इसके अलावा, सी. ई. आर. डी. ने अपनी सामान्य अनुशंसा सं. 23, ने राज्यों से स्वदेशी लोगों की विशिष्ट संस्कृति, इतिहास, भाषा और जीवन के तरीके को पहचानने और उनका सम्मान करने का आह्वान किया है; यह सुनिश्चित करें कि स्वदेशी लोग भेदभाव से मुक्त हों; स्वदेशी लोगों के सांस्कृतिक विशेषताओं के अनुरूप स्थायी आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए स्थितियां प्रदान करें; और सार्वजनिक जीवन में स्वदेशी लोगों की प्रभावी भागीदारी को प्रोत्साहित करें।²⁶¹

3.7. अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए समझौता, 2003

प्रस्तावना इस बात को मान्यता देती है कि "समुदाय, विशेष रूप से स्वदेशी समुदाय, समूह और कुछ मामलों में, व्यक्ति, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के उत्पादन, सुरक्षा, रखरखाव और पुनर्निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इस प्रकार सांस्कृतिक विविधता और मानव रचनात्मकता को समृद्ध करने में मदद करते हैं।"²⁶²

3.8. सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों की विविधता के संरक्षण और संवर्धन पर सम्मेलन, 2005

प्रस्तावना "अल्पसंख्यकों और स्वदेशी लोगों से संबंधित व्यक्तियों सहित संस्कृतियों की जीवंतता के महत्व को स्वीकार करती है, जैसा कि उनकी पारंपरिक सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों को बनाने, प्रसारित करने और वितरित करने और उन तक पहुंच बनाने की स्वतंत्रता में प्रकट होता है, ताकि वे अपने स्वयं के विकास के लिए लाभान्वित हो सकें।"²⁶³ अनुच्छेद 2 "अल्पसंख्यकों और स्वदेशी लोगों से संबंधित व्यक्तियों की संस्कृतियों सहित" सभी संस्कृतियों के लिए समान गरिमा और सम्मान के सिद्धांत की गणना करता है।²⁶⁴ अनुच्छेद 7 सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों को बढ़ावा देने के उपायों का प्रावधान करता है "जिसमें महिलाओं के साथ-साथ अल्पसंख्यकों और स्वदेशी लोगों सहित विभिन्न सामाजिक समूहों की विशेष परिस्थितियों और जरूरतों पर उचित ध्यान देते हुए अपनी सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों का निर्माण, उत्पादन, प्रसार, वितरण और उन तक पहुंच शामिल है"²⁶⁵

4. भाषाएँ

भाषा किसी व्यक्ति की पहचान का एक अहम हिस्सा है²⁶⁶ और जानकारी को समझने व उसके आदान-प्रदान के लिए ज़रूरी है। यह लोगों को एक-दूसरे से बातचीत करने, विचारों का आदान-प्रदान करने,

²⁶⁰Id.arts.5.e.i-vi,5.f.

²⁶¹United Nations Committee on the Elimination of Racial Discrimination, General Recommendation No. 23: Indigenous Peoples, Gen. Rec. No. 23, UN Doc A/52/18 (Aug. 18, 1997), para. 4.

²⁶²Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage, 2003, preamble, para. 6.

²⁶³Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions, 2005, preamble, para. 15.

²⁶⁴Id. art. 2(3).

²⁶⁵Id. art. 7(1)(a).

²⁶⁶United Nations, State of the World's Indigenous Peoples, Vol. I (May 2011), p. no. 57.

ज्ञान हासिल करने और रचनात्मक रूप से खुद को व्यक्त करने में मदद करती है। जानकारी की समझ और आदान-प्रदान के लिए आवश्यक है,²⁶⁷ इसलिए अलग-अलग समुदायों की अनूठी पहचान, उनके पारंपरिक ज्ञान और साहित्यिक कलाओं के साथ-साथ मानव जाति की सांस्कृतिक विविधता की रक्षा के लिए भाषाओं का संरक्षण आवश्यक है।²⁶⁸ दुनिया भर के स्वदेशी लोगों को अक्सर आत्मसात करने वाली नीतियों के कारण, कई स्वदेशी भाषाएँ, विशेष रूप से वे जो मौखिक रूप से उपयोग की जाती हैं लेकिन जिनमें कोई लिखित वर्णमाला नहीं है (और इसलिए कभी भी प्रलेखित नहीं की गई हैं) विशेष रूप से विलुप्त होने का खतरा है।²⁶⁹ इसके जवाब में, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने, स्वदेशी लोगों द्वारा दशकों की वकालत के परिणामस्वरूप, स्वदेशी भाषाओं को पहचानने और संरक्षित करने की दिशा में काम किया है, जैसा कि नीचे चित्रित किया गया है:

4.1. स्वदेशी लोगों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र घोषणा, 2007

यू. एन. डी. आर. आई. पी. में स्वदेशी लोगों के भाषाई अधिकारों को संबोधित करने वाले कई प्रावधान हैं। अनुच्छेद 13 स्वदेशी लोगों को “अपने इतिहास, भाषाओं, मौखिक परंपराओं, दर्शन, लेखन प्रणालियों और साहित्य को पुनर्जीवित करने, उपयोग करने, विकसित करने और भविष्य की पीढ़ियों को प्रसारित करने और समुदायों, स्थानों और व्यक्तियों के लिए अपने स्वयं के नामों को नामित करने और बनाए रखने का अधिकार प्रदान करता है”²⁷⁰ अनुच्छेद 13 यह सुनिश्चित करने के लिए “प्रभावी उपायों” को अपनाने के लिए राज्यों के दायित्व को भी सुनिश्चित करता है कि स्वदेशी लोग “राजनीतिक, कानूनी और प्रशासनिक कार्यवाही में अपनी बात समझ सकें और दूसरों को समझा सकें; जहाँ ज़रूरी हो, वहाँ अनुवाद या दूसरे उचित तरीकों का इंतज़ाम किया जाए”²⁷¹ अनुच्छेद 14 स्वदेशी लोगों के “अपनी भाषाओं में शिक्षा प्रदान करने वाली अपनी शैक्षिक प्रणालियों और संस्थानों को स्थापित करने और नियंत्रित करने” के अधिकार को मान्यता देता है।²⁷² एक परिणाम के रूप में, अनुच्छेद 14 यह भी निर्धारित करता है कि राज्यों को “स्वदेशी व्यक्तियों, विशेष रूप से बच्चों, जिनमें उनके समुदायों से बाहर रहने वाले बच्चे भी शामिल हैं, के लिए, जब भी हो सके, अपनी संस्कृति में और अपनी भाषा में शिक्षा पाने के लिए” “असरदार उपाय” अपनाने होंगे।²⁷³ अपनी संस्कृतियों, परंपराओं, इतिहास और आकांक्षाओं की गरिमा और विविधता के लिए स्वदेशी लोगों के अधिकार को अनुच्छेद 15 में मान्यता दी गई है, जो इस बात पर भी प्रकाश डालता है कि स्वदेशी भाषाओं के संरक्षण को शिक्षा और सार्वजनिक जानकारी में उचित रूप से प्रतिबिंबित किया जाना चाहिए।²⁷⁴ अंत में, अनुच्छेद 16 स्वदेशी लोगों को “अपनी भाषाओं में अपना मीडिया स्थापित करने और बिना किसी भेदभाव के गैर-स्वदेशी मीडिया के सभी रूपों तक पहुंच” का अधिकार प्रदान करता है”²⁷⁵

²⁶⁷The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, *Background paper for “Thematic Debate: Protection of Indigenous and Endangered Languages and the Role of Languages in Promoting EFA in the Context of Sustainable Development*, UN Doc. 180EX/INF.8(2008), p.no.2.

²⁶⁸United Nations, *State of the World’s Indigenous Peoples*, Vol.I (May 2011), p. no.57.

²⁶⁹*Id.* at 58.

²⁷⁰The United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, 2007, art.13.1.

²⁷¹*Id.* art.13.2.

²⁷²*Id.* art.14.1.

²⁷³*Id.* art.14.3.

²⁷⁴*Id.* art.15.1.

²⁷⁵*Id.* art.16.1.

4.2. स्वदेशी और जनजातीय लोक सम्मेलन, 1989 और स्वदेशी और जनजातीय जनसंख्या सम्मेलन, 1957

आई. एल. ओ. सम्मेलन की प्रस्तावना नं. 169 अपनी भाषाओं को बनाए रखने और विकसित करने के लिए स्वदेशी लोगों की आकांक्षाओं को स्वीकार करता है।²⁷⁶ विशेष रूप से, अनुच्छेद 28 स्वदेशी बच्चों को "जहां भी व्यवहार्य हो", यह अधिकार देता है कि उन्हें "अपनी मूल भाषा में या उस समूह की सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली भाषा में पढ़ना-लिखना सिखाया जाए, जिससे वे जुड़े हैं।"²⁷⁷ भले ही व्यवहार्य न हो, राज्यों को इस उद्देश्य को प्राप्त करने के तरीके तैयार करने के लिए स्वदेशी लोगों के साथ परामर्श करने के लिए अनिवार्य किया गया है।²⁷⁸ अनुच्छेद 28 राज्यों को "स्वदेशी भाषाओं के विकास और अभ्यास को संरक्षित करने और बढ़ावा देने के लिए" उपाय अपनाने का आदेश देता है।²⁷⁹ जहां राज्यों द्वारा स्वदेशी लोगों के संबंध में उपाय किए जाते हैं, तो अनुच्छेद 30 के तहत अपेक्षा है कि, जहां आवश्यक हो, उन्हें "लिखित अनुवाद के माध्यम से और इन लोगों की भाषाओं में जन संचार के उपयोग के माध्यम से" इस संबंध में उनके अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में बताया जाए।²⁸⁰

आईएलओ कन्वेंशन नं. 107, अनुच्छेद 23 स्वदेशी बच्चों के "अपनी मातृभाषा में पढ़ने और लिखने के अधिकार की रक्षा करता है, या जहां यह व्यावहारिक नहीं है, उस समूह द्वारा सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली भाषा में जिससे वे संबंधित हैं।"²⁸¹ हालांकि, आईएलओ कन्वेंशन नं. 107, इसके 'एकीकरणवादी' दृष्टिकोण के कारण, यह निर्धारित करता है कि राज्यों को "मातृभाषा या स्थानीय भाषा से राष्ट्रीय भाषा या देश की आधिकारिक भाषाओं में से किसी एक में प्रगतिशील परिवर्तन के लिए" प्रावधान करना चाहिए।²⁸² अनुच्छेद 23, फिर भी, राज्यों को "मातृभाषा या स्थानीय भाषा को संरक्षित करने" के लिए "जहां तक संभव हो" उपाय करने के लिए बाध्य करता है।²⁸³ अनुच्छेद 26, आई. एल. ओ. कन्वेंशन सं. 169, उन्हें प्रभावित करने वाले सरकारी उपायों के बारे में स्वदेशी आबादी के साथ उनकी अपनी भाषाओं में संचार का आह्वान करता है।²⁸⁴

4.3. नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय वाचा, 1966

अनुच्छेद 27 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि "... अल्पसंख्यकों से संबंधित व्यक्तियों को उनके समूह के अन्य सदस्यों के साथ समुदाय में अपनी भाषा का उपयोग करने के अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा।"²⁸⁵ हालांकि अनुच्छेद 27 "जातीय, भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों" के अधिकारों की रक्षा करता है, आईसीसीपीआर ने स्पष्ट किया है

²⁷⁶The Indigenous and Tribal Peoples Convention, 1989 (No.169), preamble, para. 5.

²⁷⁷Id.art.28.1.

²⁷⁸Id.art.28.1.

²⁷⁹Id.art.28.3.

²⁸⁰Id.art.30.

²⁸¹The Indigenous and Tribal Populations Convention, 1957 (No.107), art.23.1.

²⁸²Id.art.23.2.

²⁸³Id.art.23.3.

²⁸⁴Id.art.26.

²⁸⁵The International Covenant on Civil and Political Rights, 1966, art. 27.

कि यह स्वदेशी लोगों के भाषाई अधिकारों के संरक्षण के लिए भी लागू है।²⁸⁶

4.4. बाल अधिकारों पर समझौता, 1989

विशेष रूप से स्वदेशी बच्चों के संबंध में, अनुच्छेद 30 स्पष्ट रूप से "अपनी भाषा का उपयोग करने" के उनके अधिकार की गारंटी देता है"²⁸⁷

4.5. नस्लीय भेदभाव के सभी रूपों के उन्मूलन पर अंतर्राष्ट्रीय समझौता, 1965

आईसीईआरडी का उद्देश्य "नस्ल, लिंग, भाषा या धर्म के भेद के बिना सभी के लिए मानवाधिकारों और मौलिक स्वतंत्रताओं के लिए सार्वभौमिक सम्मान और पालन को बढ़ावा देना और प्रोत्साहित करना है।"²⁸⁸ तदनुसार, सीईआरडी ने अपनी सामान्य अनुशंसा सं. 23 में राज्यों का दायित्व है कि वे "सुनिश्चित करें कि स्वदेशी समुदाय अपनी भाषाओं को संरक्षित करने और अभ्यास करने के लिए अपने अधिकारों का प्रयोग कर सकते हैं..."²⁸⁹

5. शिक्षा.

ज्ञान, भाषाओं और परंपराओं के संचरण के लिए शिक्षा एक महत्वपूर्ण वाहन है। विशेष रूप से स्वदेशी लोगों के लिए, जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक मोर्चों पर व्यापक रूप से हाशिए पर हैं, शिक्षा समानता, गरिमा और न्याय की खोज में एक महत्वपूर्ण उपकरण है।²⁹⁰ इसलिए स्वदेशी समुदायों ने अपनी भाषाओं, आध्यात्मिक मान्यताओं, प्रथागत मूल्यों और सामुदायिक भागीदारी के आधार पर अपनी शिक्षा प्रणालियों को बनाए रखा है।²⁹¹ हालांकि, राज्य की स्कूली शिक्षा प्रणालियों में स्वदेशी बच्चों के जबरन प्रवेश के कारण उनकी अनूठी सांस्कृतिक पहचान का क्षरण हुआ है।²⁹² इसलिए यह आवश्यक है कि स्वदेशी शिक्षा प्रणालियों को संरक्षित और मुख्यधारा में लाया जाए और सभी स्वदेशी लोगों की शिक्षा तक पहुंच इस तरह से सुनिश्चित की जाए जो सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त हो,²⁹³ जैसा कि निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय कानूनी साधनों द्वारा प्रदर्शित किया गया है:

²⁸⁶United Nations Human Rights Commission, *CCPR General Comment No. 23, The rights of minorities (art. 27)*, UN Doc CCPR/C/21/Rev.1/Add.5 (Apr. 8, 1994), para. 3.2.

²⁸⁷The United Nations Convention on the Rights of the Child, 1989, art. 30.

²⁸⁸The International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination 1965, preamble, para. 1.

²⁸⁹United Nations Committee on the Elimination of Racial Discrimination, *General Recommendation No. 23: Indigenous Peoples*, UN Doc A/52/18 (Aug. 18, 1997), para. 4(e).

²⁹⁰United Nations Department of Economic and Social Affairs, *State of the World's Indigenous Peoples, Education*, Vol. III (Dec. 2017), p. no. 3.

²⁹¹*Id.* at 5.

²⁹²Antonio Voce, Leyland Cecco, et al., "‘Cultural genocide’: the shameful history of Canada’s residential schools— mapped" *The Guardian*, Sep. 6, 2021.

²⁹³United Nations Department of Economic and Social Affairs, *State of the World's Indigenous Peoples, Education*, Vol. III (Dec. 2017), p. no. 5.

5.1. स्वदेशी लोगों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र घोषणा, 2007

यूएनडीआरआईपी की प्रस्तावना "स्वदेशी परिवारों और समुदायों के अपने बच्चों के पालन-पोषण, प्रशिक्षण, शिक्षा और कल्याण के लिए साझा जिम्मेदारी बनाए रखने के अधिकार" को मान्यता देती है।²⁹⁴ स्वदेशी लोगों की शिक्षा का अधिकार उनके भाषाई अधिकारों से अटूट रूप से जुड़ा हुआ है। अनुच्छेद 14 में कहा गया है कि स्वदेशी लोगों को "अपनी शैक्षिक प्रणालियों और अपनी भाषाओं में शिक्षा प्रदान करने वाले संस्थानों को स्थापित करने और नियंत्रित करने का अधिकार है, जो उनके शिक्षण और सीखने के सांस्कृतिक तरीकों के लिए उपयुक्त है"²⁹⁵ अनुच्छेद 14 यह भी दोहराता है कि स्वदेशी लोग, विशेष रूप से बच्चे, बिना किसी भेदभाव के "सभी स्तरों और शिक्षा के रूपों" के हकदार हैं।²⁹⁶ परिणामस्वरूप, अनुच्छेद 14 में कहा गया है कि राज्यों को, "स्वदेशी लोगों के साथ मिलकर", "स्वदेशी व्यक्तियों, विशेष रूप से बच्चों के लिए प्रभावी उपाय करने चाहिए, जिनमें वे भी शामिल हैं जो अपने समुदायों से बाहर रहते हैं, जब भी संभव हो, अपनी संस्कृति और अपनी भाषा में शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं।"²⁹⁷

5.2. स्वदेशी और जनजातीय लोक सम्मेलन, 1989 और स्वदेशी और जनजातीय जनसंख्या सम्मेलन, 1957

आई. एल. ओ. कन्वेंशन नं. 169, अनुच्छेद 26 स्वदेशी लोगों को "सभी स्तरों पर कम से कम शेष राष्ट्रीय समुदाय के साथ समान आधार पर शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार देता है।"²⁹⁸ अनुच्छेद 27 की अपेक्षा है कि राज्यों द्वारा स्वदेशी लोगों के सहयोग से "उनकी विशेष जरूरतों को पूरा करने के लिए, और... उनके इतिहास, उनके ज्ञान और प्रौद्योगिकियों, उनकी मूल्य प्रणालियों और उनकी आगे की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक आकांक्षाओं को शामिल करने के लिए" शिक्षा कार्यक्रमों को तैयार और कार्यान्वित किया जाए।²⁹⁹ अनुच्छेद 27 आगे स्वदेशी लोगों के अपने "शैक्षणिक संस्थानों और सुविधाओं" की स्थापना के अधिकार को मान्यता देता है, जिसके लिए राज्य उचित संसाधन प्रदान करने के लिए कर्तव्यबद्ध हैं।³⁰⁰ अनुच्छेद 28 में कहा गया है कि स्वदेशी बच्चों को "अपनी स्वदेशी भाषा में पढ़ना और लिखना सिखाया जाना चाहिए" जहां व्यावहारिक हो, साथ ही "राष्ट्रीय भाषा में धाराप्रवाहता प्राप्त करने" का अवसर भी होना चाहिए।³⁰¹ अनुच्छेद 29 निर्दिष्ट करता है कि स्वदेशी लोगों की शिक्षा का उद्देश्य सामान्य ज्ञान और कौशल प्रदान करना होना चाहिए जो उन्हें अपने और राष्ट्रीय समुदाय दोनों में पूरी तरह से और समान रूप से भाग लेने में सक्षम बनाता है।³⁰² अनुच्छेद 31 राज्यों को यह सुनिश्चित करने का आदेश देता है कि "इतिहास की पाठ्यपुस्तकें और अन्य शैक्षिक सामग्री स्वदेशी लोगों के समाजों और संस्कृतियों का एक निष्पक्ष, सटीक और सूचनात्मक चित्रण प्रदान करती हैं"

²⁹⁴The United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, 2007, preamble, para. 13.

²⁹⁵*Id.* art. 14.1.

²⁹⁶*Id.* art. 14.2.

²⁹⁷*Id.* art. 14.3.

²⁹⁸The Indigenous and Tribal Peoples Convention, 1989 (No. 169), art. 26.

²⁹⁹*Id.* art. 27.1.

³⁰⁰*Id.* art. 27.3.

³⁰¹*Id.* arts. 28.1, 28.2.

³⁰²*Id.* art. 29.

ताकि राष्ट्रीय समुदाय के किसी भी वर्ग, विशेष रूप से स्वदेशी लोगों के साथ सीधे संपर्क में रहने वाले लोगों के खिलाफ किसी भी पूर्वाग्रह को समाप्त किया जा सके।³⁰³

आई. एल. ओ. कन्वेंशन नं. 107, अनुच्छेद 21, आई. एल. ओ. सम्मेलन सं. 169, "शेष राष्ट्रीय समुदाय के साथ समान आधार पर सभी स्तरों पर शिक्षा प्राप्त करने" के लिए स्वदेशी आबादी के अधिकार को सुरक्षित करता है।³⁰⁴ हालांकि, आई. एल. ओ. कन्वेंशन नं. 107, अनुच्छेद 22 में यह प्रावधान है कि शिक्षा कार्यक्रमों को "जातीय सर्वेक्षणों" के आधार पर "राष्ट्रीय समुदाय में सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक एकीकरण की प्रक्रिया में इन आबादी के स्तर पर अनुकूलित किया जाए"।³⁰⁵ इसके अलावा अनुच्छेद 24 में कहा गया है कि स्वदेशी बच्चों को सामान्य ज्ञान और कौशल प्रदान किए जाएंगे ताकि वे "राष्ट्रीय समुदाय में एकीकृत हो सकें"।³⁰⁶ फिर भी, अनुच्छेद 23 स्वदेशी बच्चों के "अपनी मातृभाषा में पढ़ने और लिखने के अधिकार की रक्षा करता है, या जहां यह व्यावहारिक नहीं है, वहाँ उस भाषा में सिखाया जाए जिसका इस्तेमाल मुख्य रूप से उनके समुदाय के लोग करते हैं।"³⁰⁷ अनुच्छेद 25 राज्यों को ऐसे शैक्षिक उपायों को अपनाने के लिए बाध्य करता है जो स्वदेशी आबादी के प्रति राष्ट्रीय समुदाय के अन्य वर्गों द्वारा रखे गए पूर्वाग्रहों को समाप्त करेंगे।³⁰⁸

5.3. बाल अधिकारों पर समझौता, 1989

सीआरसी के कई प्रावधान सभी बच्चों के शिक्षा के अधिकार के विभिन्न पहलुओं की गारंटी देते हैं। अनुच्छेद 28 राज्यों से इस अधिकार को उत्तरोत्तर और समान अवसर के आधार पर प्राप्त करने की दृष्टि से बच्चे के शिक्षा के अधिकार को मान्यता देने का आह्वान करता है।³⁰⁹ अनुच्छेद 29 यह निर्धारित करता है कि बच्चे की शिक्षा को उनके "व्यक्तित्व, प्रतिभा और मानसिक व शारीरिक क्षमताओं" का सर्वांगीण विकास करना होना चाहिए। साथ ही, इसमें मानवाधिकारों और उनकी अपनी "सांस्कृतिक पहचान, भाषा और मूल्यों" के प्रति सम्मान की भावना को बढ़ावा देना और उन्हें एक स्वतंत्र समाज में जिम्मेदार जीवन जीने के लिए तैयार करना भी शामिल है।³¹⁰ स्वदेशी बच्चों के विशेष संदर्भ में, अनुच्छेद 30 राज्यों को यह सुनिश्चित करने के लिए बाध्य करता है कि उन्हें "अपने समूह के अन्य सदस्यों के साथ समुदाय में, अपनी संस्कृति का आनंद लेने, अपने धर्म का पालन करने या अपनी भाषा का उपयोग करने के अधिकार से वंचित नहीं किया जाता है।"³¹¹

5.4 आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय समझौता, 1966

अनुच्छेद 13 यह स्थापित करता है कि शिक्षा का उद्देश्य "मानव व्यक्तित्व का पूर्ण विकास"

³⁰³Id.art.31.

³⁰⁴The Indigenous and Tribal Populations Convention, 1957 (No.107), art.21.

³⁰⁵Id.art.22.

³⁰⁶Id.art.24.

³⁰⁷Id.art.23.1.

³⁰⁸Id.art.25.

³⁰⁹The United Nations Convention on the Rights of the Child, 1989, art.28.1.

³¹⁰Id.art.29.1.

³¹¹Id.art.30.

और "मानवाधिकारों और मौलिक स्वतंत्रताओं" के लिए सम्मान को मजबूत करना चाहिए।³¹² अनुच्छेद 14 उन राज्यों को संबोधित करता है जिन्होंने अभी तक मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा हासिल नहीं की है, "उन्हें एक निर्धारित समय सीमा के भीतर इस सिद्धांत के प्रगतिशील कार्यान्वयन के लिए एक विस्तृत कार्य योजना बनाने की आवश्यकता है"³¹³

5.5 शिक्षा में भेदभाव के खिलाफ समझौता, 1960

शिक्षा में भेदभाव के खिलाफ कन्वेंशन, 1960 (सीडीई) के अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि "किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को किसी भी प्रकार की या किसी भी स्तर पर शिक्षा तक पहुंच से वंचित करना" भेदभाव का गठन करता है।³¹⁴ हालांकि सीडीई विशेष रूप से स्वदेशी लोगों के शिक्षा के अधिकार को संबोधित नहीं करता है, अनुच्छेद 1 'भेदभाव' को "नस्ल, रंग, लिंग, भाषा, धर्म, राजनीतिक या अन्य राय, राष्ट्रीय या सामाजिक मूल, आर्थिक स्थिति या जन्म के आधार पर"³¹⁵ किसी भी भेद, बहिष्कार, सीमा या वरीयता (...) को शामिल करने के रूप में वर्णित करता है। इसके अलावा, अनुच्छेद 4 राज्यों से "एक राष्ट्रीय नीति तैयार करने, विकसित करने और लागू करने" की अपेक्षा करता है जो "शिक्षा के मामले में अवसर और व्यवहार की समानता को बढ़ावा देगा"।³¹⁶ सीडीई के प्रावधानों पर राज्यों द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर सभी को शिक्षा के अधिकार का विस्तार करने और अपनी संबंधित शिक्षा प्रणालियों को, विशेष रूप से, स्वदेशी लोगों सहित, सभी स्तरों पर सबसे कमजोर समूहों के लिए, समावेशी बनाने के लिए भरोसा किया गया है।³¹⁷

6. पारंपरिक ज्ञान

'पारंपरिक ज्ञान', स्वदेशी संदर्भ में, "दुनिया भर के स्वदेशी लोगों द्वारा बनाए और विकसित किए गए ज्ञान, जानकारी, प्रथाओं और प्रतिनिधित्वों के जटिल निकायों और प्रणालियों को संदर्भित करता है, जो प्राकृतिक पर्यावरण के साथ अनुभव और बातचीत के धन से आकर्षित होता है और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में मौखिक रूप से प्रेषित होता है"³¹⁸ पारंपरिक ज्ञान आम तौर पर सामूहिक रूप से लोगों का होता है, और कहानियों, गीतों, कलाकृति, मान्यताओं, प्रथागत मानदंडों, वैज्ञानिक, कृषि, तकनीकी और पारिस्थितिक ज्ञान और उन्हें लागू करने के कौशल सहित विभिन्न रूप लेता है।³¹⁹ स्वदेशी लोगों का पारंपरिक ज्ञान उनके आत्मनिर्णय के अधिकार से भी निकटता से संबंधित है, क्योंकि

³¹²The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, 1966, art. 13.1.

³¹³*Id.* art. 14.

³¹⁴The Convention against Discrimination in Education, 1960, art. 1.1.a.

³¹⁵*Id.* art. 1.1.

³¹⁶*Id.* art. 4.

³¹⁷United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, *Indigenous peoples' right to education: overview of the measures supporting the right to education for indigenous peoples reported by Member States in the context of the ninth Consultation on the 1950 Convention and Recommendation against Discrimination in Education*, ED/PLS/EDP/2019/03/REV(2019).

³¹⁸United Nations, *State of the World's Indigenous Peoples*, Vol. I (May 2011), p. nos. 64, 65.

³¹⁹*Ibid.*

यह उन्हें अपनी भूमि, समुदायों, संसाधनों और विरासत का प्रबंधन, नियंत्रण और शासन करने के लिए सुसज्जित करता है।³²⁰ अब यह भी अच्छी तरह से स्वीकार किया जाता है कि स्वदेशी लोगों को उनके पारंपरिक ज्ञान के संरक्षण से वंचित करना उनके मानवाधिकारों का उल्लंघन है।³²¹ तदनुसार, निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय कानूनी साधन स्वदेशी लोगों के पारंपरिक ज्ञान की रक्षा करते हैं”:

6.1. स्वदेशी लोगों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र घोषणा, 2007

यूएनडीआरआईपी का अनुच्छेद 31 स्वदेशी लोगों के "अपने... पारंपरिक ज्ञान... के साथ-साथ उनके विज्ञान, प्रौद्योगिकियों और संस्कृतियों की अभिव्यक्तियों को बनाए रखने, नियंत्रित करने, संरक्षित करने और विकसित करने के अधिकार की पुष्टि करता है, जिसमें मानव और आनुवंशिक संसाधन, बीज, दवाएं, जीवों और वनस्पतियों के गुणों का ज्ञान, मौखिक परंपराएं, साहित्य, डिजाइन, खेल और पारंपरिक खेल और दृश्य और प्रदर्शन कलाएं शामिल हैं”³²² अनुच्छेद 31 इस तरह के पारंपरिक ज्ञान पर "अपनी बौद्धिक संपदा को बनाए रखने, नियंत्रित करने, रक्षा करने और विकसित करने" के उनके अधिकार को भी मान्यता देता है, और राज्यों को यह सुनिश्चित करने के लिए स्वदेशी लोगों के सहयोग से "प्रभावी उपाय" करने की आवश्यकता होती है ताकि वे इन अधिकारों का प्रयोग करने में सक्षम हों।³²³

6.2. स्वदेशी और जनजातीय लोगों का सम्मेलन, 1989

अनुच्छेद 27 की अपेक्षा है कि स्वदेशी लोगों के "इतिहास, उनके ज्ञान और प्रौद्योगिकियों, उनकी मूल्य प्रणालियों" को राज्यों द्वारा स्वदेशी लोगों पर लक्षित शिक्षा कार्यक्रमों और सेवाओं में शामिल किया जाए।³²⁴

6.3. जैविक विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, 1992

अनुच्छेद 8 राज्यों को "जैविक विविधता के संरक्षण और स्थायी उपयोग के लिए प्रासंगिक पारंपरिक जीवन शैली को मूर्त रूप देने वाले स्वदेशी और स्थानीय समुदायों के ज्ञान, नवाचारों और प्रथाओं का सम्मान, संरक्षण और रखरखाव करने और ऐसे ज्ञान, नवाचारों और प्रथाओं के धारकों के अनुमोदन और भागीदारी के साथ उनके व्यापक अनुप्रयोग को बढ़ावा देने और इस तरह के ज्ञान नवाचारों और प्रथाओं के उपयोग से उत्पन्न होने वाले लाभों के न्यायसंगत साझाकरण को प्रोत्साहित करने" का आदेश देता है।³²⁵

6.4. बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार संबंधी पहलुओं पर समझौता, 1995

बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार संबंधी पहलुओं पर समझौता, 1995 (ट्रिप्स समझौता)³²⁶ बौद्धिक संपदा अधिकारों के संरक्षण और प्रवर्तन के लिए न्यूनतम मानक निर्धारित करता है, जिसमें

³²⁰Id. at 65.

³²¹Mattias Ahren, *An introduction to the WIPO Intergovernmental Committee on Intellectual Property, Genetic Resources, Traditional Knowledge and Expressions of Folklore Indigenous Affairs*, 66 (2002).

³²²The United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, 2007, art. 31.1.

³²³Id. art. 31.

³²⁴The Indigenous and Tribal Peoples Convention, 1989 (No. 169), arts. 27.1, 27.2.

³²⁵The United Nations Convention on Biological Diversity, 1992, art. 8j.

³²⁶The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, 1995.

जिसमें पेटेंट, प्रतिलिपिधिकार, व्यापार चिह्न, भौगोलिक संकेत और औद्योगिक डिजाइन शामिल हैं। हालांकि ट्रेड्समार्क समझौता विशेष रूप से स्वदेशी लोगों के पारंपरिक ज्ञान की रक्षा नहीं करता है, व्यवहार में, इसके तंत्र का उपयोग इस उद्देश्य के लिए किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, ट्रेड्समार्क औषधीय पौधों और बीजों के पेटेंट की सुविधा प्रदान करता है जो स्वदेशी लोगों द्वारा उगाए और उपयोग किए जाते हैं, जैसे कि किनोआ, अयाहुआस्का, मैक्सिकन येलो बीन्स, मका, सांग्रे डी ड्रैगो, हुडिया, आदि।³²⁷ इसके अलावा, प्रतिलिपिधिकार का उपयोग पारंपरिक सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों की रक्षा के लिए किया जा सकता है, जैसे कि लोककथा, संगीत, नृत्य और दृश्य कला, जो अक्सर एक स्वदेशी समुदाय के पारंपरिक ज्ञान का एक अभिन्न अंग होते हैं।³²⁸ फिर भी, बौद्धिक संपदा अधिकार ढांचे को दुनिया भर के स्वदेशी लोगों के पारंपरिक ज्ञान के संरक्षण के लिए अधिक उत्तरदायी होने की आवश्यकता है।³²⁹

6.5 बौद्धिक संपदा, आनुवंशिक संसाधन और संबद्ध पारंपरिक ज्ञान पर समझौता, 2024

विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (डब्ल्यूआईपीओ) के तत्वावधान में बौद्धिक संपदा, आनुवंशिक संसाधन और संबद्ध पारंपरिक ज्ञान पर संधि, 2024 बौद्धिक संपदा, आनुवंशिक संसाधन और संबद्ध पारंपरिक ज्ञान पर संधि, 2024 (जीआरएटीके संधि) विशेष रूप से बौद्धिक संपदा, आनुवंशिक संसाधनों और पारंपरिक ज्ञान के बीच परस्पर संबंध को संबोधित करती है। जी. आर. ए. टी. के. संधि की प्रस्तावना न केवल यू. एन. डी. आर. आई. पी. को स्पष्ट रूप से स्वीकार करती है और इसके उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है,³³⁰ बल्कि यह भी पुष्टि करती है कि जी. आर. ए. टी. के. संधि को लागू करने में "स्वदेशी लोगों और स्थानीय समुदायों को शामिल करने के लिए सर्वोत्तम प्रयास किए जाने चाहिए"।³³¹ अनुच्छेद 3 एक अनिवार्य पेटेंट प्रकटीकरण आवश्यकता को निर्धारित करता है, जिसके अनुसार अगर कोई आविष्कार आनुवंशिक संसाधनों या उनसे जुड़े पारंपरिक ज्ञान पर आधारित है तो पेटेंट आवेदक आनुवंशिक संसाधनों की उत्पत्ति के देश या स्वदेशी लोगों या स्थानीय समुदायों का जिन्होंने संबंधित पारंपरिक ज्ञान प्रदान किया है का खुलासा करने के लिए बाध्य हैं।³³² इसके अलावा, अनुच्छेद 6 के अनुसार, "आनुवंशिक संसाधनों की सूचना प्रणाली (जैसे डेटाबेस) और आनुवंशिक संसाधनों से जुड़े पारंपरिक ज्ञान" की स्थापना बनाए जा रहे हों, तो जहाँ लागू हो, स्वदेशी लोगों से परामर्श किया जाए।³³³ अनुच्छेद 10 राज्यों से राज्यों की विधानसभा में "मान्यता प्राप्त पर्यवेक्षकों के रूप में स्वदेशी लोगों और स्थानीय समुदायों के प्रतिनिधियों की प्रभावी भागीदारी को प्रोत्साहित करने" का आह्वान करता है।³³⁴ इस प्रकार जीआरएटीके संधि एक महत्वपूर्ण कदम है, जो इस संबंध में यूएनडीआरआईपी के गैर-बाध्यकारी प्रावधानों

³²⁷United Nations, *State of the World's Indigenous Peoples*, Vol. I (May 2011), p. no.20.

³²⁸Carlos Maria Correa and Abdulqawi A. Yusuf (eds.) *Intellectual Property and International Trade: The TRIPS Agreement* (Kluwer Law International, 2016).

³²⁹Dina Haryati Sukardi, Tahura Malagano, et. al., "International Legal Framework for Traditional Knowledge and Intellectual Property Rights" 11(10) *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding* 359-360 (2024).

³³⁰The WIPO Treaty on Intellectual Property, Genetic Resources and Associated Traditional Knowledge, 2024, preamble, para. 7.

³³¹*Id.* preamble, para. 8.

³³²*Id.* art. 3.2.a.

³³³*Id.* art. 6.1.

³³⁴*Id.* art. 10.1(c).

को स्वदेशी लोगों के पारंपरिक ज्ञान पर बौद्धिक संपदा अधिकारों की रक्षा के लिए एक बाध्यकारी कानूनी कर्तव्य में बदल देता है।

6.6. आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, 1966

अनुच्छेद 15 किसी भी “वैज्ञानिक, साहित्यिक या कलात्मक रचना के परिणामस्वरूप नैतिक और भौतिक हितों के संरक्षण से लाभ उठाने के अधिकार” की गारंटी देता है।³³⁵ सी. ई. एस. सी. आर. ने अपनी सामान्य टिप्पणी सं. 17 में इस बात पर जोर दिया है कि अनुच्छेद 15 के कार्यान्वयन से संबंधित जानकारी भाषाई अल्पसंख्यकों और स्वदेशी लोगों की भाषाओं में भी प्रकाशित की जानी चाहिए ताकि वे अनुच्छेद 15 के तहत साहित्यिक, दृश्य या प्रदर्शन कला के अपने पारंपरिक ज्ञान के लिए सुरक्षा प्राप्त कर सकें।³³⁶

6.7 सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों की विविधता के संरक्षण और संवर्धन पर समझौता, 2005

प्रस्तावना “अमूर्त और भौतिक धन के स्रोत के रूप में पारंपरिक ज्ञान के महत्व को पहचानती है, और विशेष रूप से स्वदेशी लोगों की ज्ञान प्रणालियों, और सतत विकास में इसके सकारात्मक योगदान के साथ-साथ इसके पर्याप्त संरक्षण और संवर्धन की आवश्यकता” को पहचानती है।³³⁷

7. स्वदेशी कानूनी प्रणालियाँ और न्याय तक पहुँच

स्वदेशी लोगों ने अपने गहरे समृद्ध और आत्मनिर्भर सांस्कृतिक मानदंडों के साथ, हमेशा न्याय की अपनी अवधारणाओं के आधार पर और एक अंतर्निहित अधिकार के रूप में न्यायिक प्रणालियों और कानूनों के अपने ढाँचे का उपयोग किया है,³³⁸ जो मौखिक परंपराओं के माध्यम से आने वाली पीढ़ियों को सौंपे गए हैं।³³⁹ हालांकि, राज्यों ने अक्सर स्वदेशी लोगों के प्रथागत कानूनों और कानूनी प्रणालियों को नजरअंदाज, कम या कमजोर किया है,³⁴⁰ उन्होंने न्याय के एक संकीर्ण दृष्टिकोण को अपनाया है जो स्वदेशी लोगों की संस्कृतियों, परंपराओं और मूल्यों की अनदेखी करता है, और सामान्य घरेलू कानूनी प्रणालियों पर बोझ बढ़ाता है।³⁴¹ स्वदेशी कानूनी

³³⁵The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, 1966, art. 15.1.c.

³³⁶The United Nations Committee on Economic, Social and Cultural Rights, *General Comment No. 17, The right of everyone to benefit from the protection of the moral and material interests resulting from any scientific, literary or artistic production of which he or she is the author* (art. 15, para. 1(c) of the Covenant), UN Doc E/C.12/GC/17 (Jan. 12, 2006), para. 18(b)(iii).

³³⁷Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions, 2005, preamble, para. 8.

³³⁸The United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, 2007, preamble, para. 7.

³³⁹The United Nations General Assembly Human Rights Council, *Access to justice in the promotion and protection of the rights of indigenous peoples: restorative justice, indigenous juridical systems and access to justice for indigenous women, children and youth, and persons with disabilities- Study by the Expert Mechanism on the Rights of Indigenous Peoples*, UN Doc A/HRC/27/65 (Aug. 7, 2014), para. 7.

³⁴⁰*Id.* at para. 8.

³⁴¹Whitney Bell, “Book Note: Canada’s Indigenous Constitution,” 48(3-4) *Osgoode Hall Law Journal* 6–9 (2010).

प्रणालियाँ स्वदेशी लोगों को न्याय तक बेहतर पहुँच प्रदान करने में भी महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि वे स्वदेशी क्षेत्रों से बाहर यात्रा करने की आवश्यकता को कम करते हैं, कम खर्चीले होते हैं, भ्रष्टाचार और भेदभाव के लिए कम प्रवण होते हैं, और एक आम भाषा में और सांस्कृतिक रूप से सुलभ तरीके से न्याय देने वाले स्वदेशी समुदाय के भीतर के व्यक्तियों को शामिल करते हैं।³⁴²

विशेष रूप से स्वदेशी लोगों के सामूहिक भूमि अधिकारों के संदर्भ में, प्रथागत कानून और पैतृक क्षेत्रों के खिताब महत्वपूर्ण हैं। विशेषज्ञ प्रणाली ने इसलिए "स्वदेशी लोगों के रीति-रिवाजों, प्रथागत कानून और परंपराओं के लिए उचित सम्मान के साथ" ऐसी भूमि की कानूनी मान्यता और संरक्षण का आह्वान किया है।³⁴³ विशेषज्ञ प्रणाली ने "स्वदेशी लोगों के शासन संरचनाओं, उनके कानूनों और विवाद समाधान प्रक्रियाओं सहित" को पहचानने की आवश्यकता को भी रेखांकित किया।³⁴⁴ विशेषज्ञ प्रणाली ने राज्यों से संघर्ष समाधान प्रक्रियाओं का उपयोग करने का भी आग्रह किया है जो "संबंधित स्वदेशी लोगों के रीति-रिवाजों, परंपराओं, नियमों और कानूनी प्रणालियों को ध्यान में रखते हैं", जिसमें "न्याय मंडलियों और पुनर्स्थापनात्मक न्याय मॉडल जैसे पारंपरिक प्रणाली शामिल हैं जहां स्वदेशी बुजुर्ग और अन्य पारंपरिक ज्ञान रखने वाले सहायक हो सकते हैं"।³⁴⁵ निम्नलिखित उप-धारा अंतरराष्ट्रीय कानूनी साधनों को सूचीबद्ध करती है जो स्वदेशी लोगों के न्याय तक पहुँचने के अधिकार की रक्षा करते हैं और आगे बढ़ाते हैं, चाहे वे अपनी स्वदेशी कानूनी प्रणालियों के माध्यम से हों, या सामान्य घरेलू अदालत के माध्यम से हों।

7.1. स्वदेशी लोगों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र घोषणा, 2007

अनुच्छेद 5 में कहा गया है कि "स्वदेशी लोगों को राज्य के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन में पूरी तरह से भाग लेने के अपने अधिकार को बनाए रखते हुए, अपने विशिष्ट... कानूनी... संस्थानों को बनाए रखने और मजबूत करने का अधिकार है।"³⁴⁶ स्वदेशी लोगों के "पारंपरिक रूप से स्वामित्व वाली या अन्यथा कब्जा की गई या उपयोग की गई" भूमि, क्षेत्रों और संसाधनों के अधिकार की मान्यता या निर्णय के विशिष्ट संदर्भ में, अनुच्छेद 27 राज्यों से "संबंधित स्वदेशी लोगों के साथ मिलकर एक निष्पक्ष, स्वतंत्र, निष्पक्ष, खुली और पारदर्शी

³⁴²United Nations General Assembly Human Rights Council, *Access to justice in the promotion and protection of the rights of indigenous peoples: restorative justice, indigenous juridical systems and access to justice for indigenous women, children and youth, and persons with disabilities- Study by the Expert Mechanism on the Rights of Indigenous Peoples*, UN Doc A/HRC/27/65 (Aug. 7, 2014), para. 20.

³⁴³United Nations General Assembly Human Rights Council, *Human Rights Bodies and Mechanisms Study on Lessons Learned and Challenge to Achieve the Implementation of The Right of Indigenous Peoples to Education- Report of the Expert Mechanism on the Rights of Indigenous Peoples*, UN Doc A/HRC/12/33 (Aug. 31, 2009), para. 11.

³⁴⁴United Nations General Assembly Human Rights Council, *Access to justice in the promotion and protection of the rights of indigenous peoples: restorative justice, indigenous juridical systems and access to justice for indigenous women, children and youth, and persons with disabilities- Study by the Expert Mechanism on the Rights of Indigenous Peoples*, UN Doc A/HRC/27/65 (Aug. 7, 2014), para. 9.

³⁴⁵United Nations Human Rights Council, *Expert Mechanism on the Rights of Indigenous Peoples, Comment on the Human Rights Council's Guiding Principles on Business and Human Rights as related to Indigenous Peoples and the Right to Participate in Decision-Making with a Focus on Extractive Industries*, UN Doc A/HRC/EMRIP/2012/CRP.1 (Jul. 4, 2012), paras. 46, 55.

³⁴⁶The United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, 2007, art. 5.

प्रक्रिया की स्थापना और कार्यान्वयन करने की अपेक्षा करता है, जो स्वदेशी लोगों के कानूनों, परंपराओं, रीति-रिवाजों और भूमि कार्यकाल प्रणालियों को उचित मान्यता देता है”³⁴⁷

अनुच्छेद 34 आगे स्वदेशी लोगों के “अपनी... न्यायिक प्रणालियों या रीति-रिवाजों को बढ़ावा देने, विकसित करने और बनाए रखने” के अधिकार की पुष्टि करता है, बशर्ते वे “अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार मानकों के अनुसार” हों।³⁴⁸ अनुच्छेद 35 के अनुसार, स्वदेशी लोगों को “अपने समुदाय के प्रति व्यक्तियों की जिम्मेदारियों को निर्धारित करने” का भी अधिकार है।³⁴⁹ स्वदेशी कानूनों, रीति-रिवाजों और प्रणालियों की मान्यता के अलावा, अनुच्छेद 40 स्वदेशी लोगों के संघर्ष समाधान प्रक्रियाओं तक पहुंचने के अधिकार को स्वीकार करता है जो त्वरित, न्यायसंगत और निष्पक्ष हैं, साथ ही साथ उनके व्यक्तिगत या सामूहिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए प्रभावी उपचार, “संबंधित स्वदेशी लोगों के रीति-रिवाजों, परंपराओं और कानूनी प्रणालियों और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकारों पर उचित विचार करते हैं”।³⁵⁰

7.2. स्वदेशी एवं जनजातीय लोक सम्मेलन, 1989 तथा स्वदेशी एवं जनजातीय जनसंख्या सम्मेलन, 1957

आईएलओ कन्वेंशन नं. 169 का अनुच्छेद 8 आदेश देता है कि जब राष्ट्रीय कानून और विनियम स्वदेशी लोगों पर लागू होते हैं, तो उनके “रीति-रिवाजों या प्रथागत कानूनों” को “उचित सम्मान” दिया जाना चाहिए।³⁵¹ अनुच्छेद 8 स्वदेशी लोगों को “अपने रीति-रिवाजों और संस्थानों को बनाए रखने के अधिकार” की भी गारंटी देता है, बशर्ते कि वे “राष्ट्रीय कानूनी प्रणाली और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त मानवाधिकारों द्वारा परिभाषित मौलिक अधिकारों के साथ असंगत न हों”³⁵² अनुच्छेद 9 में कहा गया है कि एक स्वदेशी लोगों के सदस्य द्वारा किए गए अपराधों का मुकदमा चलाने के लिए, ऐसे स्वदेशी समुदाय द्वारा “पारंपरिक रूप से अभ्यास किए जाने वाले तरीकों” का “राष्ट्रीय कानूनी प्रणाली और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त मानवाधिकारों के साथ संगत सीमा तक” सम्मान किया जाना चाहिए।³⁵³ अनुच्छेद 9 में आगे यह अपेक्षा की गई है कि ऐसे मामलों से निपटने वाले अधिकारियों द्वारा दंडात्मक मामलों से संबंधित स्वदेशी लोगों के रीति-रिवाजों को ध्यान में रखा जाए।³⁵⁴ अनुच्छेद 10 में कहा गया है कि जब किसी राज्य के सामान्य कानूनों के तहत स्वदेशी लोगों पर दंड लगाया जाता है, तो संबंधित स्वदेशी लोगों की “आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विशेषताओं” का हिसाब रखा जाता है, और यह प्राथमिकता “जेल में कारावास के अलावा सजा के तरीकों” को दी जानी चाहिए।³⁵⁵ अनुच्छेद 12 स्वदेशी लोगों को “उनके अधिकारों के प्रभावी संरक्षण के लिए व्यक्तिगत रूप से या उनके प्रतिनिधि निकायों के माध्यम से कानूनी कार्यवाही” करके न्याय तक पहुंच की गारंटी देता है।³⁵⁶ न्यायिक उपचारों के लिए स्वदेशी लोगों की प्रभावी पहुंच के लिए, अनुच्छेद 12 यह सुनिश्चित करने के लिए ऐसे उपायों

³⁴⁷Id.art.27.

³⁴⁸Id.art.34.

³⁴⁹Id.art.35.

³⁵⁰Id.art.40.

³⁵¹The Indigenous and Tribal Peoples Convention, 1989 (No. 169), art. 8.1.

³⁵²Id.art.8.2.

³⁵³Id.art.9.1.

³⁵⁴Id.art.9.2.

³⁵⁵Id.arts.10.1,10.2.

³⁵⁶Id.art.12.

को अपनाने का भी आह्वान करता है कि स्वदेशी लोग "कानूनी कार्यवाही को समझ सकें और अपनी बात समझा सकें; जहाँ ज़रूरी हो, वहाँ इंटरप्रिटेशन (अनुवाद) की सुविधा या अन्य प्रभावी तरीकों के ज़रिए ऐसा किया जाए।"³⁵⁷

इसकी तुलना में, आईएलओ कन्वेंशन नं. 107 अपने एकीकरणवादी दृष्टिकोण के कारण स्वदेशी 'आबादी' के कानूनों, रीति-रिवाजों और कानूनी प्रणालियों के लिए सीमित सुरक्षा प्रदान करता है। अनुच्छेद 7 में कहा गया है कि स्वदेशी आबादी के अधिकारों और कर्तव्यों को परिभाषित करते समय उनके प्रथागत कानूनों का "ध्यान रखा जाएगा"।³⁵⁸ अनुच्छेद 7 स्वदेशी आबादी को "अपने रीति-रिवाजों और संस्थानों को बनाए रखने" का अधिकार भी प्रदान करता है, लेकिन केवल तब तक जब तक वे "राष्ट्रीय कानूनी प्रणाली या एकीकरण कार्यक्रमों के उद्देश्यों के साथ असंगत नहीं हैं"।³⁵⁹ एक स्वदेशी आबादी के सदस्य द्वारा किए गए अपराधों या अपराधों के संबंध में, अनुच्छेद 8 में यह निर्धारित किया गया है कि "जहां तक संभव हो, ऐसे स्वदेशी समुदाय द्वारा अभ्यास किए जाने वाले "सामाजिक नियंत्रण के तरीकों" का उपयोग "राष्ट्रीय समुदाय के हितों और राष्ट्रीय कानूनी प्रणाली के अनुरूप हद तक" किया जाना चाहिए।³⁶⁰ अनुच्छेद 8 में आगे यह प्रावधान किया गया है कि जहां पूर्वगामी व्यवहार्य नहीं है, वहां संबंधित अधिकारियों द्वारा दंडात्मक मामलों के संबंध में ऐसी स्वदेशी आबादी के रीति-रिवाजों को ध्यान में रखा जाएगा।³⁶¹ अनुच्छेद 10 विशेष रूप से स्वदेशी आबादी को "निवारक निरोध के अनुचित अनुप्रयोग" के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है, साथ ही "उनके मौलिक अधिकारों के प्रभावी संरक्षण के लिए कानूनी कार्यवाही करने" के उनके अधिकार की गारंटी देता है।³⁶² किसी राज्य के सामान्य कानूनों के तहत स्वदेशी आबादी पर दंड लगाने में, अनुच्छेद 10 की अपेक्षा है कि "उनके सांस्कृतिक विकास के स्तर को ध्यान में रखा जाए" और "जेल में बंद करने के बजाय पुनर्वास के तरीकों को प्राथमिकता दी जाए।"³⁶³

7.3 बाल अधिकारों पर समझौता, 1989

अनुच्छेद 12 सभी बच्चों के लिए "बच्चे को प्रभावित करने वाली किसी भी न्यायिक और प्रशासनिक कार्यवाही में, या तो सीधे, या एक प्रतिनिधि या एक उपयुक्त निकाय के माध्यम से, राष्ट्रीय कानून के प्रक्रियात्मक नियमों के अनुरूप तरीके से सुनवाई का अवसर सुनिश्चित करता है।"³⁶⁴ बाल अधिकार समिति ने अपनी सामान्य टिप्पणी नं. 11, जिसने स्वदेशी बच्चों के लिए न्याय तक पहुँच के लिए कई बाधाओं की पहचान की, कि अनुच्छेद 12 का प्रभावी कार्यान्वयन एक दुभाषिए को निःशुल्क प्रदान करने और सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील तरीके से कानूनी सहायता की गारंटी देने जैसे उपायों की गारंटी देता है।³⁶⁵ अनुच्छेद 40 में कहा गया है कि यदि बच्चों पर अपराध करने का आरोप लगाया जाता है, तो "जब भी उचित

³⁵⁷ Ibid.

³⁵⁸ The Indigenous and Tribal Populations Convention, 1957 (No. 107), art. 7.1.

³⁵⁹ Id. art. 7.2.

³⁶⁰ Id. art. 8.a.

³⁶¹ Id. art. 8.b.

³⁶² Id. art. 10.1.

³⁶³ Id. arts. 10.2, 10.3.

³⁶⁴ The United Nations Convention on the Rights of the Child, 1989, art. 12.2.

³⁶⁵ United Nations Committee on the Rights of the Child, General Comment No. 11 (2009), Indigenous children and their rights under the Convention on the Rights of the Child, UN Doc CRC/C/GC/11 (Jan. 12, 2009), para. 76.

और वांछनीय हो", न्यायिक कार्यवाही का सहारा नहीं लिया जाता है।³⁶⁶ इस संबंध में, बाल अधिकार समिति ने दोहराया है कि "किसी बच्चे की गिरफ्तारी, हिरासत या कारावास का उपयोग केवल अंतिम उपाय के रूप में किया जा सकता है।"³⁶⁷ स्वदेशी बच्चों के मामले में, बाल अधिकारों पर समिति ने समुदाय आधारित कार्यक्रमों और सेवाओं के विकास की सिफारिश की है जो स्वदेशी बच्चों, उनके परिवारों और समुदायों की जरूरतों और संस्कृतियों पर विचार करते हैं।³⁶⁸ विशेष रूप से, बाल अधिकारों पर समिति ने राज्यों से स्वदेशी लोगों द्वारा विकसित और कार्यान्वित किशोर न्याय प्रणालियों को पर्याप्त संसाधन प्रदान करने का आह्वान किया।³⁶⁹

7.4 नस्लीय भेदभाव के सभी रूपों के उन्मूलन पर अंतर्राष्ट्रीय समझौता, 1965

अनुच्छेद 6 "सक्षम राष्ट्रीय अधिकरणों और अन्य राज्य संस्थाओं" के माध्यम से नस्लीय भेदभाव के खिलाफ सभी को "प्रभावी संरक्षण और उपचार" की गारंटी देता है, जिसमें नस्लीय भेदभाव के कारण हुई किसी भी क्षति के लिए "न्यायसंगत और पर्याप्त क्षतिपूर्ति या संतुष्टि" प्राप्त करने का अधिकार शामिल है।³⁷⁰ इसकी सामान्य अनुशंसा सं. 23, सी. ई. आर. डी. ने, स्वदेशी लोगों को उनकी एफ. पी. आई. सी. के बिना "पारंपरिक रूप से स्वामित्व वाली या अन्यथा बसे हुए या उपयोग किए जाने वाले अपनी भूमि और क्षेत्रों से वंचित" होने के संदर्भ में, राज्यों को यह सुनिश्चित करने की सिफारिश की है कि स्वदेशी लोगों को पुनर्स्थापन का अधिकार है, जहां तथ्यात्मक रूप से संभव है; यदि नहीं, तो स्वदेशी लोग "न्यायसंगत, निष्पक्ष और त्वरित मुआवजे" के हकदार हैं, जो "जहां तक संभव हो भूमि और क्षेत्रों का रूप लेना चाहिए"³⁷¹

7.5 आपराधिक न्याय प्रणालियों में कानूनी सहायता तक पहुंच पर संयुक्त राष्ट्र के सिद्धांत और दिशानिर्देश, 2012

सिद्धांत 1 में कहा गया है कि "राज्यों को अपनी राष्ट्रीय कानूनी प्रणालियों में उच्चतम संभव स्तर पर कानूनी सहायता के अधिकार की गारंटी देनी चाहिए, जिसमें संविधान में लागू होने पर भी शामिल है।"³⁷² विशेष रूप से, सिद्धांत 10 यह सुनिश्चित करने के लिए विशेष उपायों को अपनाने का आह्वान करता है कि कुछ "विशेष जरूरतों वाले समूह, जिनमें... स्वदेशी और आदिवासी लोग शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं" को कानूनी सहायता तक पहुंच में समानता है।³⁷³ इसके अलावा, दिशानिर्देश 11 राज्यों को राष्ट्रीय कानूनी सहायता योजनाओं को तैयार करते समय इस बात पर और जोर देती है कि राष्ट्रीय कानूनी सहायता योजनाएँ बनाते समय राज्य "... स्वदेशी और आदिवासी लोगों सहित लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं, विशिष्ट समूहों की जरूरतों को ध्यान में रखें"³⁷⁴

³⁶⁶The United Nations Convention on the Rights of the Child, 1989, art. 40.3.

³⁶⁷United Nations Committee on the Rights of the Child, General Comment No. 11 (2009), *Indigenous children and their rights under the Convention on the Rights of the Child*, UN Doc CRC/C/GC/11 (Jan. 12, 2009), para. 74.

³⁶⁸*Id.* at para. 75.

³⁶⁹*Ibid.*

³⁷⁰The International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, 1965, art. 6.

³⁷¹United Nations Committee on the Elimination of Racial Discrimination, General Recommendation No. 23: *Indigenous Peoples*, UN Doc A/52/18 (Aug. 18, 1997), para. 5.

³⁷²The United Nations Principles and Guidelines on Access to Legal Aid, 2012, principle 1.

³⁷³*Id.* principle 10.

³⁷⁴*Id.* guideline 11.

दिशानिर्देश 11 में यह भी सिफारिश की गई है कि बच्चों के साथ काम करने वाले कानूनी सहायता प्रदाताओं को "बच्चों के अधिकारों और जरूरतों पर बुनियादी अंतःविषय प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहिए... और विशेष ध्यान के साथ... बच्चे जो... स्वदेशी समूहों के सदस्य हैं उनके विकास के मनोवैज्ञानिक और अन्य पहलुओं पर प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहिए...", ³⁷⁵।

8. सतत पर्यावरण प्रबंधन

अनादिकाल से, स्वदेशी लोगों का प्रकृति के साथ एक जटिल संबंध रहा है, जो उनकी सांस्कृतिक प्रथाओं के माध्यम से उनके पर्यावरण, पारिस्थितिकी तंत्र, वनस्पतियों और जीवों और आनुवंशिक विविधता को संरक्षित करता है। ³⁷⁶ नतीजतन, स्वदेशी लोगों द्वारा बसे क्षेत्र अक्सर उच्च जैविक विविधता और पारिस्थितिक संतुलन के क्षेत्रों के साथ मेल खाते हैं। ³⁷⁷ स्वदेशी लोगों की विशिष्ट ज्ञान प्रणालियाँ पीढ़ियों से गुजर रही हैं, ³⁷⁸ अपनी पैतृक भूमि के प्रति उनका आध्यात्मिक लगाव, और भविष्य की पीढ़ियों के लिए क्षेत्रों और संसाधनों को संरक्षित करने की उनकी सांस्कृतिक जिम्मेदारी, सतत विकास के लिए सर्वोत्कृष्ट रही हैं। ³⁷⁹ प्रकृति के साथ उनका घनिष्ठ संबंध उन्हें इसके सर्वश्रेष्ठ संरक्षक बनने के लिए भी तैयार करता है। ³⁸⁰ साथ ही, स्वदेशी लोगों को भी स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण में फलने-फूलने और जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों से संरक्षित होने का अधिकार है। ³⁸¹ हालांकि, अभ्यास से पता चलता है कि स्वदेशी हितों को शायद ही कभी ऐसी नीतियों को तैयार करने में ध्यान में रखा जाता है जो स्वदेशी लोगों के अपने पैतृक भूमि, पारंपरिक क्षेत्रों और प्राकृतिक संसाधनों पर कब्जा करने या उनका उपयोग करने के अधिकारों को प्रभावित करती हैं। इस कठोर वास्तविकता के आलोक में, निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय कानूनी ढांचा स्वदेशी लोगों के अधिकारों और कर्तव्यों को उनके प्राकृतिक पर्यावरण की तुलना में मान्यता देता है:

8.1. स्वदेशी लोगों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र घोषणा, 2007

यूएनडीआरआईपी की प्रस्तावना स्पष्ट रूप से स्वीकार करती है कि "स्वदेशी ज्ञान, संस्कृतियों और पारंपरिक प्रथाओं का सम्मान पर्यावरण के सतत और न्यायसंगत विकास और उचित प्रबंधन में योगदान देता है" ³⁸² इसके अलावा, अनुच्छेद 29 स्वदेशी लोगों के

³⁷⁵ Ibid.

³⁷⁶ United Nations Department of Economic and Social Affairs, *State of the World's Indigenous Peoples, Climate Crisis*, Vol. VI (Apr. 2025), p. no. 17.

³⁷⁷ World Wildlife Fund, *International and Terralingua, Indigenous and Traditional Peoples of the World and Ecoregion Conservation: An Integrated Approach to Conserving the World's Biological and Cultural Diversity* (2000), p. no. 7.

³⁷⁸ Fulvio Mazzocchi, "A deeper meaning of sustainability: Insights from indigenous knowledge" 7(1) *Anthropocene Review* 77-93 (2020).

³⁷⁹ United Nations, *State of the World's Indigenous Peoples*, Vol. I (May 2011), p. no. 84.

³⁸⁰ Ibid.

³⁸¹ United Nations Environment Program, United Nations Development Program, and Office of the High Commissioner for Human Rights, *Joint statement of United Nations entities on the right to a healthy environment* (Mar. 8, 2021), available at: <https://www.unep.org/news-and-stories/statements/joint-statement-united-nations-entities-right-healthy-environment> (last visited on Oct. 10, 2025).

³⁸² The United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, 2007, preamble, para. 11.

"पर्यावरण के संरक्षण और संरक्षण और उनकी भूमि या क्षेत्रों और संसाधनों की उत्पादक क्षमता" के अधिकार की पुष्टि करता है।³⁸³ इस संबंध में, अनुच्छेद 29 राज्यों से "इस तरह के संरक्षण और संरक्षण के लिए स्वदेशी लोगों के लिए सहायता कार्यक्रमों" को स्थापित करने और संचालित करने की भी अपेक्षा करता है।³⁸⁴ इसके अलावा, अनुच्छेद 29 राज्यों से उनके एफपीआईसी के बिना "स्वदेशी लोगों की भूमि या क्षेत्रों में खतरनाक सामग्री के भंडारण या निपटान" को रोकने के लिए "प्रभावी उपाय" करने की अपेक्षा करता है।³⁸⁵ अनुच्छेद 32 स्वदेशी लोगों के अपनी भूमि या क्षेत्रों पर किसी भी विकास, अन्वेषण या संसाधन शोषण के लिए "न्यायसंगत और निष्पक्ष निवारण" के अधिकार को मान्यता देता है; साथ ही, राज्यों को "ऐसी गतिविधियों के प्रतिकूल पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने के लिए उचित उपाय..." करना चाहिए।³⁸⁶

8.2. स्वदेशी और जनजातीय लोगों का सम्मेलन, 1989

अनुच्छेद 4 स्वदेशी लोगों के पर्यावरण की रक्षा के लिए विशेष उपायों को अपनाने का आदेश देता है।³⁸⁷ इसी तर्ज पर, अनुच्छेद 7 राज्यों से "स्वदेशी लोगों" के सहयोग से, उन क्षेत्रों के "पर्यावरण की रक्षा और संरक्षण के लिए उपाय करने की" अपेक्षा करता है जहां वे रहते हैं।³⁸⁸ अनुच्छेद 7 स्वदेशी लोगों के विकास की प्रक्रिया के लिए अपनी प्राथमिकताएं तय करने के अधिकार का भी समर्थन करता है क्योंकि यह उन भूमि को प्रभावित करता है जिन पर वे कब्जा करते हैं या अन्यथा उपयोग करते हैं।³⁸⁹ तदनुसार, अनुच्छेद 7 राज्यों को स्वदेशी लोगों के सहयोग से संभावित विकास गतिविधियों के पर्यावरणीय प्रभाव का आकलन करने के लिए "जब भी उपयुक्त हो" अध्ययन करने के लिए बाध्य करता है और परिणामों को ऐसी गतिविधियों के "कार्यान्वयन के लिए मौलिक मानदंड" के रूप में उपयोग करता है।³⁹⁰ इसके अलावा, अनुच्छेद 32 में कहा गया है कि राज्यों को पर्यावरण संरक्षण सहित विभिन्न क्षेत्रों में "अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के माध्यम से, सीमाओं के पार स्वदेशी और आदिवासी लोगों के बीच संपर्क और सहयोग को सुविधाजनक बनाने के लिए" उचित उपाय करने चाहिए।³⁹¹

8.3. जैव विविधता पर सम्मेलन, 1992

प्रस्तावना "जैविक संसाधनों पर पारंपरिक जीवन शैली को मूर्त रूप देने वाले कई स्वदेशी और स्थानीय समुदायों की घनिष्ठ और पारंपरिक निर्भरता, और जैविक विविधता के संरक्षण और इसके घटकों के स्थायी उपयोग के लिए प्रासंगिक पारंपरिक ज्ञान, नवाचारों और प्रथाओं के उपयोग से उत्पन्न होने वाले लाभों को समान रूप से साझा करने की वांछनीयता" को मान्यता देती है।³⁹² इस संबंध में, अनुच्छेद 8 (जे) राज्यों को ऐसे पारंपरिक ज्ञान, नवाचारों और

³⁸³Id.art.29.1.

³⁸⁴Ibid.

³⁸⁵Id.art.29.2.

³⁸⁶Id.art.32.3.

³⁸⁷The Indigenous and Tribal Peoples Convention, 1989 (No. 169), art. 4.1.

³⁸⁸Id.art.7.3.

³⁸⁹Id.art.7.1.

³⁹⁰Id.art.7.3.

³⁹¹Id.art.32.

³⁹²The United Nations Convention on Biological Diversity, 1992, preamble, para. 12.

प्रथाओं का "सम्मान, संरक्षण और रखरखाव" करने और "धारकों की मंजूरी और भागीदारी के साथ उनके अनुप्रयोग को बढ़ावा देने और उनके उपयोग से न्यायसंगत लाभ-साझाकरण को प्रोत्साहित करने" के लिए बाध्य करता है।³⁹³ अनुच्छेद 10 विशेष रूप से राज्यों को "पारंपरिक सांस्कृतिक प्रथाओं के अनुसार जैविक संसाधनों के प्रथागत उपयोग की रक्षा और प्रोत्साहित करने के लिए बाध्य करता है जो संरक्षण या स्थायी उपयोग आवश्यकताओं के अनुकूल हैं"।³⁹⁴ जैव विविधता के संरक्षण के लिए, अनुच्छेद 17 और 18 राज्यों से "स्वदेशी और पारंपरिक ज्ञान" और "स्वदेशी और पारंपरिक प्रौद्योगिकियों" के उपयोग से संबंधित जानकारी के आदान-प्रदान के लिए एक दूसरे के साथ सहयोग करने का भी आह्वान करते हैं।³⁹⁵

8.4. स्वदेशी पीपुल्स अर्थ चार्टर, 1992

स्वदेशी लोगों ने अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से अपना स्वयं का पृथ्वी चार्टर भी विकसित किया है, जो वैश्विक स्तर पर सतत विकास के लिए स्वदेशी दृष्टिकोण का दस्तावेजीकरण करने और आधिकारिक और नागरिक समाज शिखर सम्मेलनों को प्रभावित करने का एक अग्रणी प्रयास है।³⁹⁶ वक्तव्य 57 इस बात पर प्रकाश डालता है कि जलवायु परिवर्तन, जो स्वदेशी लोगों और पूरी मानवता को प्रभावित करते हैं, पारिस्थितिक लय को भी बाधित करते हैं, हमारे जीवन की गुणवत्ता को खराब करते हैं और हमारी निर्भरता को बढ़ाते हैं।³⁹⁷ वक्तव्य 58 उन वनों की ओर ध्यान आकर्षित करता है जो पारिस्थितिक संतुलन के विनाश पर विचार किए बिना विकास और आर्थिक लाभ के नाम पर नष्ट किए जा रहे हैं, और लकड़ी, पशु और खनिज उद्योगों को कटाई रियायतों और प्रोत्साहनों को रद्द करने की मांग करता है।³⁹⁸ वक्तव्य 59 इस बात पर जोर देता है कि स्वदेशी लोग जैव विविधता के संरक्षण को महत्व देते हैं लेकिन वैज्ञानिक या लोककथाओं के उद्देश्यों के लिए इसके एक निष्क्रिय हिस्से के रूप में माने जाने को अस्वीकार करते हैं।³⁹⁹ वक्तव्य 60 इस बात की वकालत करता है कि स्वदेशी रणनीतियों का उपयोग राष्ट्रीय पर्यावरण नीतियों के लिए एक रूपरेखा के रूप में किया जाना चाहिए।⁴⁰⁰ वक्तव्य 67 प्रकृति के साथ स्वदेशी लोगों के सामंजस्यपूर्ण संबंधों को मान्यता देता है, और राज्यों से स्वदेशी सतत विकास मॉडल, विकास रणनीतियों और सांस्कृतिक मूल्यों को ज्ञान के विशिष्ट और महत्वपूर्ण स्रोतों के रूप में सम्मान करने का आग्रह करता है।⁴⁰¹

8.5 पर्यावरण और विकास पर रियो घोषणा, 1992

सिद्धांत 22 विशेष रूप से उस महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करता है जो स्वदेशी लोग "अपने ज्ञान और पारंपरिक प्रथाओं के कारण पर्यावरण प्रबंधन और विकास" में निभाते हैं, और तदनुसार

³⁹³Id. art. 8.j.

³⁹⁴Id. art. 10.c.

³⁹⁵Id. arts. 17.2, 18.4.

³⁹⁶United Nations Economic and Social Council, Other matters, including meetings and seminars and the Voluntary Fund for Indigenous Populations: information received from indigenous peoples' and non-governmental organizations, UN Doc E/CN.4/Sub.2/AC.4/1994/12 (Jun. 6, 1994).

³⁹⁷The Indigenous Peoples Earth Charter, 1992, statement 57.

³⁹⁸Id. statement 58.

³⁹⁹Id. statement 59.

⁴⁰⁰Id. statement 60.

⁴⁰¹Id. statement 67.

राज्यों से "सतत विकास की उपलब्धि में अपनी प्रभावी भागीदारी को सक्षम करने" का आह्वान करता है।⁴⁰²

8.6. एजेंडा 21, 1992

एजेंडा 21 का अध्याय 26 प्राकृतिक पर्यावरण के संरक्षण और स्थायी प्रबंधन में "स्वदेशी लोगों और उनके समुदायों की भूमिका को पहचानने और मजबूत करने" के विषय को संबोधित करता है।⁴⁰³ अध्याय 26 "प्राकृतिक पर्यावरण और इसके सतत विकास और स्वदेशी लोगों के सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक और भौतिक कल्याण के बीच अंतर्संबंध" की पुष्टि करता है और यह आवश्यक है कि घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय कार्यवाही "पर्यावरणीय रूप से ध्वनि और टिकाऊ विकास को लागू करने... स्वदेशी लोगों और उनके समुदायों की भूमिका को पहचानने, समायोजित करने, बढ़ावा देने और मजबूत करने" के लिए हो।⁴⁰⁴ अध्याय 26 "राष्ट्रीय स्तर पर स्वदेशी भूमि को "पर्यावरणीय रूप से अस्वस्थ" और "सांस्कृतिक रूप से अनुचित" गतिविधियों से बचाने के लिए⁴⁰⁵ उपयुक्त नीतियों और या कानूनी साधनों को अपनाने या मजबूत करने" का भी आह्वान करता है।⁴⁰⁶ अध्याय 26 सतत विकास को बढ़ावा देने में स्वदेशी लोगों के "पारंपरिक ज्ञान" और "संसाधन प्रबंधन प्रथाओं" के मूल्य पर भी जोर देता है।⁴⁰⁷ अध्याय 26 आगे स्वदेशी लोगों की "सांस्कृतिक, आर्थिक और भौतिक कल्याण" के लिए "नवीकरणीय संसाधनों और पारिस्थितिकी तंत्र" पर "पारंपरिक और प्रत्यक्ष निर्भरता" के महत्व पर प्रकाश डालता है।⁴⁰⁸ अध्याय 26 स्वदेशी लोगों के "जीवन की गुणवत्ता" में सुधार के लिए "उत्पादन के वैकल्पिक, पर्यावरण के अनुकूल साधन" खोजने की भी वकालत करता है।⁴⁰⁹ अध्याय 26 "संसाधन प्रबंधन और संरक्षण रणनीतियों" से संबंधित "नीतियों, कानूनों और कार्यक्रमों के राष्ट्रीय निर्माण में स्वदेशी लोगों की सक्रिय भागीदारी" सुनिश्चित करने की प्रासंगिकता को भी रेखांकित करता है।⁴¹⁰

8.7. सभी प्रकार के वनों के प्रबंधन, संरक्षण और सतत विकास पर वैश्विक सहमति के लिए सिद्धांतों का वक्तव्य, 1992

हालांकि गैर-कानूनी रूप से बाध्यकारी, सिद्धांतों का वक्तव्य एक आधिकारिक दस्तावेज है जो राज्यों से अपनी संबंधित राष्ट्रीय वन नीतियों के निर्माण और कार्यान्वयन में "स्थानीय समुदायों और स्वदेशी लोगों... और वनवासियों सहित इच्छुक पक्षों की भागीदारी को बढ़ावा देने और अवसर प्रदान करने" का आह्वान करता है।⁴¹¹ यह राज्यों को अपनी राष्ट्रीय वन नीतियों में "स्वदेशी लोगों, उनके समुदायों और अन्य समुदायों और वनवासियों की पहचान,

⁴⁰²The Rio Declaration on Environment and Development, 1992, principle 22.

⁴⁰³The Rio Conference on Environment and Development, Agenda 21, 1992, ch. 26.

⁴⁰⁴*Id.* ch. 26. 1.

⁴⁰⁵*Id.* ch. 26. 3. a. i.

⁴⁰⁶*Id.* ch. 26. 3. a. ii.

⁴⁰⁷*Id.* ch. 26. 3. a. iii.

⁴⁰⁸*Id.* ch. 26. 3. a. iv.

⁴⁰⁹*Id.* ch. 26. 3. a. vi.

⁴¹⁰*Id.* ch. 26. 3. b, 26. 3. c.

⁴¹¹The Forest Principles, 1992, principle 2. d.

संस्कृति और अधिकारों को पहचानने और उनका विधिवत समर्थन करने" की भी सिफारिश करता है।⁴¹² इसके अलावा, वनों के संरक्षण और सतत विकास के लिए, राज्यों को "उपयुक्त स्वदेशी क्षमता और स्थानीय ज्ञान" का सम्मान, विकास, उस पर भरोसा और क्षतिपूर्ति करने की आवश्यकता है।⁴¹³

⁴¹²*Id.* principle 5.a.

⁴¹³*Id.* principle 13.d.

परिशिष्ट ए: स्वदेशी अधिकारों के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानूनी ढांचा

	आत्मनिर्णय, स्वशासन, सहभागिता, परामर्श और एफपीआईसी	भूमि, वन और संसाधन	आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक सुरक्षा उपाय	बोली	शिक्षा	परंपरागत ज्ञान	स्वदेशी कानूनी व्यवस्थाएं और न्याय तक पहुंच	सतत पर्यावरण प्रबंधन
संयुक्त राष्ट्र स्वदेशी लोगों के अधिकारों घोषणा 2007	स्वभाग्यनिर्णय और स्व-शासन अनुच्छेद 3 अनुच्छेद 4 अनुच्छेद 5 अनुच्छेद 33 अनुच्छेद 34 भागीदारी और परामर्श: अनुच्छेद 18 अनुच्छेद 41 एफपीआईसी: अनुच्छेद 10 अनुच्छेद 11	प्रस्तावना, अनुच्छेद 10 अनुच्छेद 25 अनुच्छेद 26 अनुच्छेद 27 अनुच्छेद 28 अनुच्छेद 29 अनुच्छेद 30 अनुच्छेद 32	प्रस्तावना, अनुच्छेद 6 अनुच्छेद 5 अनुच्छेद 8 अनुच्छेद 9 अनुच्छेद 11 अनुच्छेद 13 अनुच्छेद 15 अनुच्छेद 17 अनुच्छेद 20 अनुच्छेद 21 अनुच्छेद 22 अनुच्छेद 23 अनुच्छेद 24	अनुच्छेद 13 अनुच्छेद 14 अनुच्छेद 15 अनुच्छेद 16	प्रस्तावना, अनुच्छेद 13 अनुच्छेद 14	अनुच्छेद 31	अनुच्छेद 5 अनुच्छेद 27 अनुच्छेद 34 अनुच्छेद 35 अनुच्छेद 40	प्रस्तावना, अनुच्छेद 11 अनुच्छेद 29 अनुच्छेद 32

અનુચ્છેદ 19								
અનુચ્છેદ 28								
અનુચ્છેદ 29								
અનુચ્છેદ 32								

स्वदेशी और आदिवासी लोग सम्मेलन, 1989	आत्मनिर्णय और स्वशासन अनुच्छेद 1 भागीदारी और परामर्श: अनुच्छेद 2 अनुच्छेद 6 अनुच्छेद 15 अनुच्छेद 17 एफपीआईसी: अनुच्छेद 16 अनुच्छेद 22	अनुच्छेद 7 अनुच्छेद 13 अनुच्छेद 14 अनुच्छेद 15 अनुच्छेद 16 अनुच्छेद 17 अनुच्छेद 18 अनुच्छेद 19	अनुच्छेद 2 अनुच्छेद 7 अनुच्छेद 10 अनुच्छेद 22 अनुच्छेद 23 अनुच्छेद 24 अनुच्छेद 25 अनुच्छेद 27	प्रस्तावना, अनुच्छेद 5 अनुच्छेद 28 अनुच्छेद 30	अनुच्छेद 26 अनुच्छेद 27 अनुच्छेद 28 अनुच्छेद 29 अनुच्छेद 31	अनुच्छेद 27	अनुच्छेद 8 अनुच्छेद 9 अनुच्छेद 10 अनुच्छेद 12	अनुच्छेद 4 अनुच्छेद 7 अनुच्छेद 32

स्वदेशी और आदिवासी आबादी सम्मेलन, 1957	स्वभाग्य निर्णय और स्व- शासन अनुच्छेद 1 भागीदारी और परामर्श: अनुच्छेद 5 एफपीआईसी: अनुच्छेद 12	अनुच्छेद 11 अनुच्छेद 12 अनुच्छेद 13 अनुच्छेद 14	प्रस्तावना, अनुच्छेद 5 अनुच्छेद 2 अनुच्छेद 3 अनुच्छेद 4 अनुच्छेद 6 अनुच्छेद 15 अनुच्छेद 16 अनुच्छेद 17 अनुच्छेद 18	अनुच्छेद 23 अनुच्छेद 26	अनुच्छेद 21 अनुच्छेद 22 अनुच्छेद 23 अनुच्छेद 24 अनुच्छेद 25		अनुच्छेद 7 अनुच्छेद 8 अनुच्छेद 10	

			अनुच्छेद 19 अनुच्छेद 20					
भेदभाव (रोजगार और व्यवसाय) सम्मेलन, 1958		अनुच्छेद 2						
आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय समझौता, 1966	आत्मनिर्णय और स्वशासन: अनुच्छेद 1 सहभागिता और परामर्श: अनुच्छेद 15 अनुच्छेद 16 अनुच्छेद 17	अनुच्छेद 11 अनुच्छेद 12 अनुच्छेद 15	अनुच्छेद 1 अनुच्छेद 15		अनुच्छेद 13 अनुच्छेद 14	अनुच्छेद 15		

नागरिक एवं राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय समझौता, 1966	आत्मनिर्णय और स्वशासन: अनुच्छेद 1 सहभागिता और परामर्श:	अनुच्छेद 1 अनुच्छेद 27 अनुच्छेद 40	अनुच्छेद 27	अनुच्छेद 27				
---	--	--	-------------	-------------	--	--	--	--

	अनुच्छेद 25							
संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार सम्मेलन 1989		अनुच्छेद 30	अनुच्छेद 30	अनुच्छेद 30	अनुच्छेद 28 अनुच्छेद 29 अनुच्छेद 30		अनुच्छेद 12 अनुच्छेद 40	
नस्लीय भेदभाव के सभी रूपों के उन्मूलन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 1965		अनुच्छेद 1 अनुच्छेद 5	अनुच्छेद 5	प्रस्तावना, पैरा 1			अनुच्छेद 6	
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के संदर्भ में भूमि, मत्स्य पालन और वनों के स्वामित्व के उत्तरदायी शासन पर स्वैच्छिक दिशानिर्देश, 2012		प्रारंभिक उद्देश्य 1						

सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा, 2015		लक्ष्य 2 उद्देश्य 2.3						
स्वदेशी लोगों का पृथ्वी चार्टर, 1992								कथन 57 कथन 58 कथन 59 कथन 60 कथन 67
रियो पर्यावरण एवं विकास घोषणापत्र, 1992								सिद्धांत 22
एजेंडा 21								अध्याय 26
संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन, 1992						अनुच्छेद 8(जे)		प्रस्तावना, पैरा. 12 अनुच्छेद 8(जे) अनुच्छेद 10(सी)

								अनुच्छेद 17 अनुच्छेद 18
बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार संबंधी पहलुओं पर समझौता, 1995						अनुच्छेद 14 (कॉपीराइट) अनुच्छेद 27 (पेटेंट)		
अनुच्छेद 14 (कॉपीराइट) अनुच्छेद 27 (पेटेंट)			प्रस्तावना, अनुच्छेद 6					
सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों की विविधता के संरक्षण और संवर्धन पर सम्मेलन, 2005			प्रस्तावना, पैरा. 15 अनुच्छेद 2(3) अनुच्छेद 7			प्रस्तावना, अनुच्छेद 8		
सभी प्रकार के								सिद्धांत 2(घ)

वनों के प्रबंधन, संरक्षण और सतत विकास पर वैश्विक सहमति के सिद्धांत का बयान, 1992								सिद्धांत 5(क) सिद्धांत 13(घ)
बौद्धिक संपदा, आनुवंशिक संसाधन और संबंधित पारंपरिक ज्ञान पर WIPO संधि, 2024						प्रस्तावना, पैरा.7 प्रस्तावना, पैरा.8 अनुच्छेद 3 अनुच्छेद 6 अनुच्छेद 10		
शिक्षा में भेदभाव के विरुद्ध सम्मेलन, 1960					अनुच्छेद 1 अनुच्छेद 4			

कानूनी सहायता तक पहुंच संबंधी संयुक्त राष्ट्र के सिद्धांत और दिशानिर्देश, 2012							सिद्धांत 1 सिद्धांत 10 दिशानिर्देश 11	
--	--	--	--	--	--	--	--	--

परिशिष्ट बी: स्वदेशी अधिकारों के संरक्षण से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय कानूनी उपकरणों के अनुसमर्थन या अपनाने की देशवार स्थिति

	ऑस्ट्रेलिया	आओटेरो आ (न्यूजीलैंड)	कनाडा	अमेरिका	कोलंबिया	इक्वेडोर	ब्राज़िल	नॉर्वे	फिनलैंड	स्वीडन	भारत
संयुक्त राष्ट्र की स्वदेशी लोगों के अधिकारों पर घोषणा, 2007 - बाध्यकारी नहीं	13 सितंबर 2007 को इसके खिलाफ मतदान किया, लेकिन बाद में अप्रैल 2009 में इसका समर्थन किया।	13 सितंबर 2007 को इसके खिलाफ मतदान किया, लेकिन बाद में अप्रैल 2010 में इसका समर्थन किया।	शुरुआत में सितंबर 2007 में इसके खिलाफ़ वोट दिया गया, लेकिन नवंबर 2010 में इसका समर्थन किया गया	13 सितंबर 2007 को इसके खिलाफ मतदान किया, लेकिन बाद में 12 जनवरी 2011 को इसका समर्थन किया।	13 सितंबर 2007 को इसके खिलाफ मतदान किया, लेकिन बाद में 12 जनवरी 2011 को इसका समर्थन किया।	13 सितंबर 2007 को पक्ष में मतदान किया गया	13 सितंबर 2007 को पक्ष में मतदान किया गया	13 सितंबर 2007 को पक्ष में मतदान किया गया	13 सितंबर 2007 को पक्ष में मतदान किया गया	13 सितंबर 2007 को पक्ष में मतदान किया गया	2007 में पक्ष में मतदान किया

स्वदेशी एवं जनजातीय सम्मेलन, 1989 बाध्यकारी	अनुसम र्थित नहीं	अनुसम र्थित नहीं	अनुसम र्थित नहीं	अनुसम र्थित नहीं	7 अगस्त 1991 को अनुमो दित	15 मई 1998 को अनुमोदित	25 जुलाई 2002 को अनुमोदित	19 जून को अनुमोदित 1990	अनुसम र्थित नहीं	अनुसम र्थित नहीं	अनुसम र्थित नहीं
स्वदेशी और	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	की पुष्टि की	की पुष्टि की	की पुष्टि की	नहीं	नहीं	नहीं	की पुष्टि की

जनजातीय जनसंख्या सम्मेलन, 1957 बाध्यकारी	की पुष्टि की	की पुष्टि की	की पुष्टि की	की पुष्टि की	4 मार्च 1969 को, लेकिन वर्तमान में लागू नहीं है।	3 अक्टूबर 1969 को, लेकिन वर्तमान में लागू नहीं है	18 जून 1965 को, लेकिन वर्तमान में लागू नहीं है	की पुष्टि की	की पुष्टि की	की पुष्टि की	29 सितंबर 1958 को
आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय समझौता, 1966 बाध्यकारी	10 दिसंबर 1975 को अनुमोदित	28 दिसंबर 1978 को अनुमोदित	19 मई 1976 को अभिग्रहण	8 जून को अनुमोदित 1992	29 अक्टूबर 1969 को अनुमोदि त	6 मार्च 1969 को अनुमोदि त	24 जनव री 1992 को अभिग म	13 सितंबर 1972 को अनुमोदित	19 अगस्त 1975 को अनुमो दित	6 दिसंबर 1971 को अनुमोदित	10 अप्रैल 1979 को अभिग्रहण हुआ
नागरिक एवं राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय समझौता, 1966 बाध्यकारी	13 अगस्त 1980 को अनुमो दित	28 दिसंबर 1978 को अनुमोदित	19 मई 1976 को अभिग्रहण	8 जून को अनुमोदित 1992	29 अक्टूबर 1969 को अनुमोदि त	6 मार्च 1969 को अनुमोदि त	24 जनव री 1992 को अभिग म	13 सितंबर 1972 को अनुमोदित	19 अगस्त 1975 को अनुमो दित	6 दिसंबर 1971 को अनुमोदित	10 अप्रैल 1979 को अभिग्रहण हुआ
संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार सम्मेलन	17 दिसंबर 1990 को अनुमोदित	6 अप्रैल को अनुमोदित 1993	13 दिसंबर 1991 को अनुमोदित	16 फरवरी 1995 को हस्ताक्षरित, लेकिन	28 जनवरी 1991 को अनुमोदित	23 मार्च 1990 को अनुमोदित	24 सितंबर 1990 को अनुमोदित	8 जनवरी 1991 को अनुमोदित	20 जून को अनुमोदित 1991	29 जून को अनुमोदित 1990	11 दिसंबर 1992 को अभिगम

द चाइल्ड 1989 <i>बाध्यकारी</i>				अधिसूचित नहीं							
नस्तीय भेदभाव के सभी रूपों के उन्मूलन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, 1965 <i>बाध्यकारी</i>	30 सितंबर 1975 को अनुमोदित	22 नवंबर 1972 को अनुमोदित	14 अक्टूबर 1970 को अनुमोदित	21 अक्टूबर 1994 को अनुमोदित	2 सितंबर 1981 को अनुमोदित	22 सितंबर 1966 को अभिग्रहण हुआ	27 मार्च 1968 को अनुमोदित ।	6 अगस्त 1970 को अनुमोदित	14 जुलाई को अनुमोदित 1970	6 दिसंबर 1971 को अनुमोदित	3 दिसंबर 1968 को अनुमोदित
भेदभाव (रोजगार और व्यवसाय) सम्मेलन, 1958 <i>बाध्यकारी</i>	15 जून को अनुमोदित 1973	3 जून को अनुमोदित 1983	26 नवंबर 1964 को अनुमोदित	अनुसमर्थित नहीं	4 मार्च 1969 को अनुमोदित	10 जुलाई को अनुमोदित 1962	26 नवंबर 1965 को अनुमोदित	24 सितंबर 1959 को अनुमोदित	23 अप्रैल 1970 को अनुमोदित	20 जून को अनुमोदित 1962	3 जून को अनुमोदित 1960
पर्यावरण और विकास पर रियो घोषणापत्र, 1992	अर्थसबमिट में 3-14 जून 1992 को प्रकाशित	अर्थसबमिट में 3-14 जून 1992 को प्रकाशित	अर्थसबमिट में 3-14 जून 1992 को प्रकाशित	अर्थसबमिट में 3-14 जून 1992 को प्रकाशित	अर्थसबमिट में 3-14 जून 1992 को प्रकाशित	अर्थसबमिट में 3-14 जून 1992 को प्रकाशित	अर्थसबमिट में 3-14 जून 1992 को प्रकाशित	अर्थसबमिट में 3-14 जून 1992 को प्रकाशित	अर्थसबमिट में 3-14 जून 1992 को प्रकाशित	अर्थसबमिट में 3-14 जून 1992 को प्रकाशित	अर्थसबमिट में 3-14 जून 1992 को प्रकाशित

गैर-बाध्यकारी (179 देशों द्वारा सर्वसम्मति से अपनाया गया)											
संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन, 1992 <i>बाध्यकारी</i>	18 जून 1993 को अनुमोदित	16 सितंबर 1993 को अनुमोदित	4 दिसंबर 1992 को अनुमोदित	4 जुलाई 1993 को हस्ताक्षर किए गए लेकिन अनुसमर्थित नहीं किया गया	28 नवंबर 1994 को अनुमोदित	23 फरवरी 1993 को अनुमोदि त।	28 फरवरी 1994 को अनुमोदि त	9 जुलाई को अनुमोदित 1993	27 जुलाई को अनुमोदित 1994	16 दिसंबर 1993 को अनुमोदित	18 फरवरी 1994 को अनुमोदि त
बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार संबंधी पहलुओं पर समझौता, 1995 बाध्यकारी (विश्व व्यापार संगठन के	हस्ताक्षर तिथि: 15 अप्रैल 1994 लागू तिथि: 1 जनवरी 1995	हस्ताक्षर किए गए 15 अप्रैल 1994 लागू हुए: 1 जनवरी 1995	हस्ताक्षर किए गए 15 अप्रैल 1994 लागू हुए: 1 जनवरी 1995	हस्ताक्षर किए गए 15 अप्रैल 1994 लागू हुए: 1 जनवरी 1995	हस्ताक्षर किए गए 15 अप्रैल 1994 लागू हुए: 1 जनवरी 1995	हस्ताक्षर किए गए 15 अप्रैल 1994 लागू हुए: 1 जनवरी 1995	हस्ताक्षर किए गए 15 अप्रैल 1994 1 जनवरी 1995 से लागू हुआ	विश्व व्यापार संगठन (WTO) के संस्थापक सदस्य के रूप में 15 अप्रैल 1994 को हस्ताक्षर किए गए। यह 1 जनवरी	विश्व व्यापार संगठन (WTO) के संस्थापक सदस्य के रूप में 15 अप्रैल 1994 को हस्ताक्षर किए गए। 1 जनवरी	विश्व व्यापार संगठन (WTO) के संस्थापक सदस्य के रूप में 15 अप्रैल 1994 को हस्ताक्षर किए गए। 1 जनवरी	विश्व व्यापार संगठन (WTO) के संस्थापक सदस्य के रूप में 15 अप्रैल 1994 को हस्ताक्षर किए गए। 1 जनवरी

सभी सदस्य ट्रिप्स के हस्ताक्षरकर्ता हैं)								1995 से लागू हुआ।	1995 को लागू हुआ।	1995 को लागू हुआ।	1995 को लागू हुआ।
---	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए सम्मेलन, 2003 <i>बाध्यकारी</i>	अनुसमर्थित नहीं	अनुसमर्थित नहीं	अनुसमर्थित नहीं	अनुसमर्थित नहीं	19 मार्च 2008 को अनुमोदित	13 फरवरी 2008 को अनुमोदित	1 मार्च 2006 को अनुमोदित	17 जनवरी 2007 को अनुमोदित	21 फरवरी 2013 को स्वीकृत	26 जनवरी 2011 को अनुमोदित	9 सितंबर 2005 को अनुमोदित
सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों की विविधता संरक्षण संवर्धन सम्मेलन, 2005 <i>बाध्यकारी</i>	18 सितंबर 2009 को ग्रहण किया गया	5 अक्टूबर 2007 को अभिग्रहण	28 नवंबर 2005 को स्वीकृत	अनुसमर्थित नहीं	19 मार्च 2013 को अभिगम	8 नवंबर 2006 को अभिग्रहण हुआ	16 जनवरी 2007 को अनुमोदित	17 जनवरी 2007 को अनुमोदित	18 दिसंबर 2006 को स्वीकृत	18 दिसंबर 2006 को स्वीकृत	15 दिसंबर 2006 को अनुमोदित
बौद्धिक संपदा, आनुवंशिक संसाधन और संबंधित पारंपरिक ज्ञान पर डब्ल्यूआईपीओ संधि 2024 <i>गैर-बाध्यकारी</i>	हस्ताक्षर 24 मई 2024	अभी तक हस्ताक्षरित या अनुमोदित नहीं	अभी तक हस्ताक्षरित या अनुमोदित नहीं	अभी तक हस्ताक्षरित या अनुमोदित नहीं	हस्ताक्षर 24 मई 2024	हस्ताक्षर 21 मई 2025	हस्ताक्षर 21 मई 2025	अभी तक हस्ताक्षरित या अनुमोदित नहीं	अभी तक हस्ताक्षरित या अनुमोदित नहीं	अभी तक हस्ताक्षरित या अनुमोदित नहीं	अभी तक हस्ताक्षरित या अनुमोदित नहीं

यूनेस्को शिक्षा में भेदभाव के सम्मेलन, 1960 <i>बाध्यकारी</i>	29 नवंबर 1966 को स्वीकृत	12 फरवरी 1963 को अनुमोदित	अधिसूचित	अनुसमर्थित नहीं	अनुसमर्थित नहीं	5 मार्च 1979 को स्वीकृत	19 अप्रैल 1968 को अनुमोदित	8 जनवरी 1963 को अनुमोदित	18 अक्टूबर 1971 को अनुमोदित	21 मार्च 1968 को अनुमोदित	अनुसमर्थित नहीं
कानूनी सहायता तक पहुंच संबंधी संयुक्त राष्ट्र के सिद्धांत और दिशानिर्देश, 2012 <i>गैर-बाध्यकारी</i> (संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा बिना मतदान के सर्वसम्मति से अपनाया गया)	28 मार्च 2013 को अपनाया गया	28 मार्च 2013 को अपनाया गया	28 मार्च 2013 को अपनाया गया	28 मार्च 2013 को अपनाया गया	28 मार्च 2013 को अपनाया गया	28 मार्च 2013 को अपनाया गया	28 मार्च 2013 को अपनाया गया	28 मार्च 2013 को अपनाया गया	28 मार्च 2013 को अपनाया गया	28 मार्च 2013 को अपनाया गया	28 मार्च 2013 को अपनाया गया

अध्याय III: भारतीय संवैधानिक, विधायी और संस्थागत तंत्र

यह अध्याय उन संवैधानिक, विधायी और संस्थागत उपायों का पता लगाता है जो भारत में 'अनुसूचित जनजातियों' और अन्य जनजातीय समुदायों के अधिकारों की गारंटी के लिए तैयार किए गए हैं। पूर्व-औपनिवेशिक और औपनिवेशिक काल में जनजातीय समुदायों के साथ जिस तरह का व्यवहार किया गया है, उसके ऐतिहासिक संदर्भ को विस्तार से बताते हुए, यह अध्याय 'अनुसूचित जनजाति' पहचान के संवैधानिक पदनाम, और समानता और गैर-भेदभाव के उनके अधिकारों, शिक्षा और सार्वजनिक रोजगार में आरक्षण, राजनीतिक प्रतिनिधित्व और स्व-शासन, संसाधनों पर स्वायत्तता और सांस्कृतिक और धार्मिक स्वतंत्रताओं का वर्णन करता है। यह अध्याय उन वैधानिक प्रावधानों को और स्पष्ट करता है जो अनुसूचित जनजातियों को शोषण से स्पष्ट रूप से या निहित रूप से बचाते हैं, उनकी पैतृक भूमि पर उनके अधिकारों को सुरक्षित करते हैं, उनकी प्रथागत प्रथाओं को पहचानते हैं और सामाजिक और आर्थिक न्याय को बढ़ावा देते हैं। इस अध्याय में अनुसूचित जनजातियों के संरक्षण, उन्नति और सशक्तिकरण के लिए स्थापित कल्याणकारी योजनाओं, पहलों और प्रशासनिक तंत्रों की रूपरेखा भी दी गई है।

1. अनुसूचित जनजातियों के साथ हुए ऐतिहासिक व्यवहार

1.1. पूर्व-औपनिवेशिक दमन

प्राचीन ग्रंथों में अक्सर आदिवासी समुदायों को 'डाकू जनजातियों' या 'बाहरी लोगों' के रूप में दर्शाया गया है, जो समाज के हाशिए पर रहते हैं (कब्रिस्तानों, पहाड़ों और उपवनों पर) 'मृतकों के कपड़े पहनते हैं' और 'हमेशा एक जगह से दूसरी जगह भटकते रहते हैं'।⁴¹⁴ जनजातीय समुदायों को "विधिरहित, विवेकहीन, अमानवीय", "भयानक और भयावह", "मांस खाने वाले" और "शराब पीने वाले" के रूप में भी वर्णित किया गया था।⁴¹⁵ विशेष रूप से, दास्य, म्लेच्छ, द्रविड़, पुलिंडा, शबरा, भिल्ला और बारबरा जनजातियों को अराजकता और भ्रष्टा से जुड़े होने के रूप में माना जाता था-विशेष रूप से, दास्य को लुटेरों, राक्षसों या बहिष्कृतों के रूप में देखा जाता था; बारबरा को विदेशी या पहाड़ी लोगों के रूप में देखा जाता था जो ब्राह्मण अनुष्ठानों में भाग लेने के योग्य नहीं थे; और भिल्ला को 'अलग' या 'बहिष्कृत' के रूप में देखा जाता था।⁴¹⁶

मनुस्मृति सहित अन्य ग्रंथों ने आगे वन जनजातियों और 'कम जन्मे' माने जाने वाले लोगों को स्वाभाविक रूप से चोरी सहित निषिद्ध व्यवसायों का चित्रण किया गया, और उन्हें नैतिक और कानूनी व्यवस्था से बाहर माना गया।⁴¹⁷ इस प्रकार ऐसे समुदायों को अनुष्ठानों में भाग लेने या गवाह के रूप में

⁴¹⁴Georg Böhler, *The Law of Manu: Translated, with Extracts from Seven Commentaries* 414 (Clarendon Press, 1886); Anastasia Piliavsky, "The 'Criminal Tribe' in India before the British" 57(2) *Comparative Studies in Society and History* 330 (2015).

⁴¹⁵Anastasia Piliavsky, "The 'Criminal Tribe' in India before the British" 57(2) *Comparative Studies in Society and History* 330 (2015).

⁴¹⁶*Id.* at 330-331.

⁴¹⁷Georg Böhler, *The Law of Manu: Translated, with Extracts from Seven Commentaries* 192, 238, 410, 499 (Clarendon Press, 1886).

कार्य करने से रोक दिया गया था, ⁴¹⁸ और ऐसे "जंगली चोरों" की संपत्ति को स्वतंत्र रूप से लेने की अनुमति दी गई थी। ⁴¹⁹ कुछ आख्यानो के अनुसार, डकैती को एक 'पारिवारिक व्यवसाय' के रूप में माना जाता था; परिणामस्वरूप, आदिवासी गांवों को 'चोर बस्तियों' के रूप में संदर्भित किया जाता था, जिससे आदिवासी समुदायों की पीढ़ियों को गुफाओं और जंगलों में रहने के लिए प्रेरित किया जाता था। ⁴²⁰

यह बहिष्कृत व्यवहार 16वीं शताब्दी तक अच्छी तरह से जारी रहा, जिसमें गुजर, जाट, कोली, मीना, भट्टी, मेवाती और भील जैसे समुदाय भी 'डाकू जातियों' की खराब प्रतिष्ठा प्राप्त कर रहे थे। ⁴²¹ मुगल सम्राट बाबर ने अपनी पत्रिका में उल्लेख किया कि जाट और गुजर अक्सर गांवों को लूटने के लिए पहाड़ियों से उतरते थे, उन्हें "मूर्खतापूर्ण उत्पीड़क" करार देते थे। ⁴²² सत्रहवीं शताब्दी के मध्य तक, औरंगजेब के 1672 के फरमान के साथ सभी ग्रासिया जनजातियों को "आदतन डकैत" और "दुष्ट पुरुष" औपचारिक रूप करार दिया गया था। ⁴²³ आदिवासी समुदायों की इस तरह की नकारात्मक रूढ़िवादिता स्वाभाविक रूप से विचलित होने के रूप में, "अपराध करने के लिए उनकी जाति के कानूनों द्वारा शपथ", को बाद में औपनिवेशिक काल के दौरान अंग्रेजों द्वारा आधिकारिक रूप से संहिताबद्ध किया गया, इस प्रकार उनके प्रणालीगत हाशिए, अधीनता और उत्पीड़न को मजबूत और सामान्य किया गया जो अंग्रेजों के भारत में आने से बहुत पहले से प्राचीन काल से बना हुआ था। ⁴²⁴

1.2. औपनिवेशिक 'अन्यीकरण'

ब्रिटिश शासन के तहत, जनजातीय समुदायों को उनके अधिकारों की रक्षा के उद्देश्य से, बल्कि उनके द्वारा बसे क्षेत्रों के विनियमन को सुविधाजनक बनाने के लिए, कानूनी मान्यता दी गई थी। भूमि, संसाधनों और राजस्व के मामले में शासन करना मुश्किल माना जाता था। ⁴²⁵ इस औपनिवेशिक ढांचे के भीतर, आदिवासी समुदायों को "स्थिता के बाहर" की आबादी के रूप में माना गया, जिससे वे न केवल प्रशासनिक ढांचे के लिए, बल्कि सामाजिक व्यवस्था के लिए भी बाहरी स्थिति में आ गए। ⁴²⁶ बड़े पैमाने पर दूरदराज के पहाड़ी और वन क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासी समुदाय, जो शिकार, इकट्ठा करने या स्थानांतरित खेती पर निर्भर थे, को सामूहिक रूप से 'आदिवासी' या 'आदिम जनजातियों' या 'जंगल जनजातियों' के रूप में वर्गीकृत किया गया था,

⁴¹⁸Anastasia Piliavsky, "The 'Criminal Tribe' in India before the British" 57(2) *Comparative Studies in Society and History* 331(2015).

⁴¹⁹*Ibid.*

⁴²⁰Helen M. Johnson, "Rāuhineya's Adventures, the Rāuhineya carita", in Group of his Pupils (eds.), *Studies in Honor of Maurice Bloomfield* 159-96 (Yale University Press, 1920); Anastasia Piliavsky, "The 'Criminal Tribe' in India before the British" 57(2) *Comparative Studies in Society and History* 331(2015).

⁴²¹Anastasia Piliavsky, "The 'Criminal Tribe' in India before the British" 57(2) *Comparative Studies in Society and History* 335(2015).

⁴²²*Id.* at 335-336.

⁴²³Jadunath Sarkar, *Mughal Administration* 111 (M. C. Sarkar, 1952); Anastasia Piliavsky, "The 'Criminal Tribe' in India before the British" 57(2) *Comparative Studies in Society and History* 335-336(2015).

⁴²⁴Louis A. Knafla (ed.), *Crime, Gender, and Sexuality in Criminal Prosecutions* 124 (Greenwood Publishing Group, 2002); Anastasia Piliavsky, "The 'Criminal Tribe' in India before the British" 57(2) *Comparative Studies in Society and History* 326(2015); Sukanya Shanthav, *Union of India, 2024 SCC On Line SC 2694*, para. 113-114.

⁴²⁵Susana B. C. Devalle, "Tribe in India: The Fallacy of a Colonial Category", in David N. Lorenzen (ed.), *Studies on Asia and Africa from Latin America* 71-116 (El Colegio de Mexico, 1990).

⁴²⁶Virginus Xaxa, "Tribes as Indigenous People of India" 34(51) *Economic and Political Weekly* 3591(1999).

जिन्हें आमतौर पर 'आदिवासी' भी कहा जाता है।⁴²⁷ यह वर्गीकरण क्रमिक जनगणना रिपोर्टों में भी परिलक्षित होता है, जहां आदिवासी समुदायों को 'वन जनजातियों', 'जीववादी' या 'आदिवासी धर्मों' का पालन करने वाले जैसे शब्दों के तहत वर्गीकृत किया गया था।⁴²⁸ सरकारी दस्तावेजों में 'आदिवासी जनजातियों' का भी उल्लेख किया गया है, जिन्होंने ब्रिटिश भारत के पहाड़ी और वन क्षेत्रों में, 'अदृश्य दुनिया' के इर्द-गिर्द केंद्रित विश्वास प्रणालियों का अभ्यास करना जारी रखा, उन्हें 'आदिम लोग' के रूप में वर्णित किया।⁴²⁹ इन विशेषताओं के परिणामस्वरूप, एक तरफ आदिवासी समुदायों और दूसरी तरफ गैर-आदिवासी आबादी और औपनिवेशिक अधिकारियों के बीच धर्म, संस्कृति और परंपरा के मामलों पर तनाव व्याप्त था।⁴³⁰ जिसके विरुद्ध में, आदिवासी समुदायों और उनके निवासियों को नियंत्रित करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा कई विशेष कानून बनाए गए।

1.2.1. 'आपराधिक जनजातियाँ'

ऐसा ही एक कानून आपराधिक जनजाति अधिनियम, 1871 था, जिसने कुछ 'आपराधिक जनजातियों' के 'पंजीकरण, निगरानी और नियंत्रण' और आदिवासी समुदायों सहित हाशिए के समूहों को दंडित करने के लिए एक वैधानिक आधार प्रदान किया।⁴³¹ इसकी धारा 2 गवर्नर जनरल को किसी भी "जनजाति, गिरोह या व्यक्तियों के वर्ग" को "आपराधिक जनजाति" के रूप में घोषित करने के लिए अधिकृत करती है, यदि स्थानीय सरकार के पास "विश्वास करने का कारण" था कि वे "गैर-ज़मानती अपराधों को बार-बार करने के आदी थे"।⁴³² इसी तरह, धारा 4 ने स्थानीय सरकार को एक 'भटकने वाली जनजाति' को अपराधी के रूप में परिभाषित करने के लिए अधिकृत किया, जिसका कोई निश्चित निवास स्थान नहीं था, सिवाय इसके कि वे यह प्रदर्शित कर सकें कि वे एक वैध व्यवसाय में लगे हुए थे।⁴³³

धारा 13 और 14 ने स्थानीय सरकार को 'आपराधिक जनजातियों' के लिए बस्ती का स्थान निर्धारित करने की अनुमति दी, जिनके पास निवास का कोई निश्चित स्थान नहीं था।⁴³⁴ धारा 18 और 19 ने आगे

⁴²⁷ Bhangya Bhukya, "The Mapping of the Adivasi Social: Colonial Anthropology and Adivasis" 43(39) *Economic and Political Weekly* 103-109 (2008).

⁴²⁸ Virginius Xaxa, "Transformation of Tribes in India: Terms of Discourse" 34(24) *Economic and Political Weekly* 1519-24 (1999).

⁴²⁹ Indian Statutory Commission, "Report of the Indian Statutory Commission Volume 1-Survey" (May 1930), p.no.32.

⁴³⁰ Virginius Xaxa, "Politics of Language, Religion and Identity: Tribes in India" 40(13) *Economic and Political Weekly* 1363-1370 (2005).

⁴³¹ Anurag Bhaskar, *The Foresighted Ambedkar: Ideas That Shaped Indian Constitutional Discourse* 24 (Penguin Random House, 2024).

⁴³² The Criminal Tribes' Act, 1871, s. 2: "If the Local Government has reason to believe that any tribe, gang or class of persons is addicted to the systematic commission of non-bailable offences, it may report the case to the Governor General in Council, and may request this permission to declare such tribe, gang or class to be a criminal tribe."

⁴³³ The Criminal Tribes' Act, 1871, s.4: "If such tribe, gang or class has no fixed place of residence, the report shall state whether such tribe, gang or class follows any lawful occupation, and stated; whether such occupation is, in the opinion of the Local Government, the real occupation of such tribe, gang or class, or a pretence for the purpose of facilitating the commission of crimes, and shall set forth the grounds on which such opinion is based; and the report shall also specify the place of residence in which also proposed such wandering tribe, gang or class is to be settled under the provisions hereinafter contained, and the livelihood and means of arrangements which are proposed to be made for enabling it to earn its living therein."

⁴³⁴ The Criminal Tribes' Act, 1871, s. 13: "Any tribe, gang or class, which has been declared to be criminal, and which has no fixed place of residence, may be settled in a place of residence prescribed by the Local Government."

एक 'आपराधिक जनजाति' से संबंधित लोगों के दैनिक जीवन पर व्यापक नियंत्रण और कोड़े मारने जैसे शारीरिक दंड को लागू करने को अधिकृत किया।⁴³⁵

बाद में, आपराधिक जनजाति अधिनियम, 1911 को पूर्ववर्ती आपराधिक जनजाति अधिनियम, 1871 को निरस्त करने के लिए पारित किया गया था। आपराधिक जनजाति अधिनियम, 1911 का अनुप्रयोग, अपने पूर्ववर्ती के विपरीत, केवल⁴³⁶ जनजातीय क्षेत्रों तक ही सीमित नहीं था, बल्कि पूरे ब्रिटिश भारत तक विस्तारित था।⁴³⁷ इसके अलावा, धारा 3 ने स्थानीय सरकार को किसी भी उच्च प्राधिकरण की अनुमति या परामर्श के बिना, किसी भी "जनजाति, गिरोह या व्यक्तियों के वर्ग" को के आपराधिक जनजाति रूप में घोषित करने के लिए अधिकृत किया, यदि उसके पास "यह विश्वास करने का कारण" था कि वे "गैर-ज़मानती अपराधों को बार-बार करने के आदी थे"।⁴³⁸ इसके अलावा, कठोर धारा 24 ने 'आपराधिक जनजाति' के पंजीकृत सदस्यों को दंडित करने के लिए एक ठोस कानूनी आधार प्रदान किया, जहां एक अदालत का विचार था कि वे "चोरी या डकैती करने वाले थे, या करने में सहायता करने वाले थे" या "चोरी या डकैती करने के

The Criminal Tribes' Act, 1871, s. 14: "Any tribe, gang or class which has been declared to be criminal, or any part thereof, may, by other place. order of the Local Government, be removed to any other place of residence."

⁴³⁵The Criminal Tribes' Act, 1871, s. 18: "The Local Government may, with the previous consent of the Governor General in Council, make rules to prescribe—(1) the form in which the registers shall be made by the said Magistrate; (2) the mode in which the said Magistrate shall publish the notice prescribed in section eight, and the means by which the persons whom it concerns, and the Headmen, Village-Watchmen and landowners or occupiers of the village, in which such persons reside, shall be informed of its publication; (3) the mode in which the notice prescribed in section eleven shall be given; (4) the limits within which persons whose names are on the register shall reside; (5) conditions as to holding passes, under which such persons may be permitted to leave the said limits; (5) conditions to be inserted in any such pass as to (a) the places where the holder of the pass may go or reside; (b) the officers before whom, from time to time, he shall be bound to present himself; (c) and the time during which he may absent himself; (7) conditions as to answering at roll-call or otherwise, in order to satisfy the said Magistrate or persons authorized by him, that the persons whose names are on the register are actually present at given times within the said limits; (8) the inspection of the residences and villages of any such tribe, gang or class, and the prevention or removal of contrivances for enabling the residents therein to conceal stolen property, or to leave their place of residence without leave; (9) the terms upon which registered persons may be discharged from the operation of this Act; (10) the mode in which criminal tribes shall be settled and removed; (11) the control and supervision of reformatory settlements; (12) the works on which, and the hours during which, persons placed in a reformatory settlement shall be employed, the rates at which they shall be paid, and the disposal, for the benefit of such persons, of the surplus proceeds of their labour after defraying the whole or such part of the expenses of their supervision and control as to the Local Government shall seem fit; (13) the discipline to which persons endeavouring to escape from any such settlement, or otherwise offending against the rules for the time being in force, shall be submitted; the periodical visitation of such settlement, and the removal from it of such persons as it shall seem expedient to remove; (14) and generally to carry out the purposes of this Act."

The Criminal Tribes' Act, 1871, s. 19: "Any person violating any of the rules made under section eighteen shall be punished with rigorous imprisonment for a term which may extend to six months, or with fine, or with whipping, or with all or any two of those punishments; and, on any second conviction for a breach of any of the said rules, with rigorous imprisonment which may extend to one year, or with fine, or with whipping to be inflicted in the manner prescribed by any law in force for the time being in relation to whipping, or with all or any two of those punishments."

⁴³⁶The Criminal Tribes Act, 1871, s. 1: "This section and section twenty extend to the whole of British India: the rest of this Act extends only to the territories under the governments of the Lieutenant-Governors of the North-Western Provinces and the Panjáb, respectively, and under the administration of the Chief Commissioner of Oudh."

⁴³⁷The Criminal Tribes Act, 1911, s. 1(2): "It extends to the whole of British India."

⁴³⁸The Criminal Tribes Act, 1911, s. 3: "If the Local Government has reason to believe that any tribe, gang or class of persons is addicted to the systematic commission of non-bailable offences, it may, by notification in the local official Gazette, declare that such tribe, gang or class is a criminal tribe for the purposes of this Act."

अवसर की प्रतीक्षा कर रहे थे”⁴³⁹ अपराधिक जनजाति अधिनियम, 1911 के तहत दंड, बार-बार दोषी ठहराए जाने के मामले में अपनी उंगली के निशान लेने से इनकार करने⁴⁴⁰ जैसे अपराधों के लिए छह महीने तक के कारावास से लेकर सात साल तक के कारावास या आजीवन परिवहन तक के कारावास तक थे।⁴⁴¹

तत्पश्चात, अपराधिक जनजाति अधिनियम, 1924 अधिनियमित किया गया, जिससे अपराधिक जनजाति अधिनियम, 1911 निरस्त हो गया। जबकि अपराधिक जनजाति अधिनियम, 1924 ने पूर्ववर्ती अपराधिक जनजाति अधिनियम, 1911 के अधिकांश प्रावधानों को बरकरार रखा, इसने 'अपराधिक जनजातियों' के संबंध में प्रशासनिक नियंत्रण और पुलिस शक्तियों को संशोधित और विस्तारित किया। उदाहरण के लिए, धारा 22 के तहत, सब-इंस्पेक्टर या उससे ऊपर के रैंक के अधिकारियों को यह अधिकार दिया गया था कि वे बिना वारंट के किसी भी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकें, जिसने “अपराधिक जनजाति अधिनियम, 1924” के तहत बनाए गए नियमों का उल्लंघन किया हो या जिस पर ऐसा करने का उचित संदेह हो।⁴⁴² तदनुसार, अपराधिक जनजाति अधिनियम, 1871, 1911 और 1924 ने आदिवासी समुदायों से जुड़े पहले से मौजूद सामाजिक कलंक को 'जन्मजात अपराधी' के रूप में ब्रांडिंग करके मजबूत किया।

1.2.2. 'अनुसूचित जिले', 'पिछड़े क्षेत्र', 'बहिष्कृत क्षेत्र' और 'आंशिक रूप से बहिष्कृत क्षेत्र'

अनुसूचित जिला अधिनियम, 1874 को प्रशासनिक प्रभाग बनाने के लिए अधिनियमित किया गया था, जिसे 'अनुसूचित जिलों' (जैसे संथाल परगना और छोटानागपुर)⁴⁴³ के रूप में जाना जाता है, जिसमें आदिवासी समुदायों को

⁴³⁹The Criminal Tribes Act, 1911, s.24: “Whoever, being a registered member of any criminal tribe, is found in any place under such circumstances as to satisfy the Court—(a) that he was about to commit, or aid in the commission of, theft or robbery, or (b) that he was waiting for an opportunity to commit theft or robbery, shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to three years, and shall also be liable to fine which may extend to one thousand rupees.”

⁴⁴⁰The Criminal Tribes Act, 1911, s.21: “Whoever, being a member of a criminal tribe, without lawful excuse, the burden of proving which shall lie upon him,—(a) fails to appear in compliance with a notice issued under section 5 or section 7, or (b) intentionally omits to furnish any information required under those sections, or, (c) when required to furnish information under either of those sections, furnishes a true information which he knows or has reason to believe to be false, or (d) refuses to allow his finger-impressions to be taken, may be arrested without warrant, and shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to six months, or with fine which may extend to two hundred rupees, or with both.”

⁴⁴¹The Criminal Tribes Act, 1911, s.23: “(1) Whoever, being a member of any criminal tribe, and, having been convicted of any of the offences under the Indian Penal Code (XLV of 1850) specified in the Schedule, is hereafter convicted of the same or any other offence specified in the said schedule, shall, in the absence of special reasons to the contrary to be mentioned in the judgment of the Court, be punished,— (a) on a second conviction, with imprisonment for a term of not less than seven years, and (b) on a third conviction, with transportation for life. (2) Nothing in this section shall affect the liability of such persons to any further or other punishment to which they may be liable under the Indian Penal Code or any other law.”

⁴⁴²The Criminal Tribes Act, 1924, s.22(3): “Any person who commits or is reasonably suspected of having committed an offence made punishable by this section which is not a cognizable offence as defined in the Code of Criminal Procedure, 1898 (V of 1898), may be arrested without a warrant by any officer in charge of a police station or by any police officer not below the rank of a sub-inspector.”

⁴⁴³The Scheduled Districts Act, 1874, s.1: “Local extent. —This Act extends in the first instance to the whole of British India other than the territories mentioned in the first schedule (hereto) annexed, and it shall come into force in each of the Scheduled Districts on the issue of a notification under Section 3 relating to such District. Interpretation clause. —In this Act the term “Scheduled Districts” means the territories mentioned in the first schedule hereto annexed; and, from the date fixed

नेतृत्व चयन के पारंपरिक तरीकों सहित अपनी प्रथागत प्रथाओं के अनुसार अपने स्थानीय मामलों को विनियमित करने की अनुमति दी गई थी।⁴⁴⁴ शेष ब्रिटिश भारत में लागू कानून इन अनुसूचित जिलों पर स्वतः लागू नहीं होते थे; इसके बजाय, गवर्नर जनरल के पास इन क्षेत्रों के लिए विशेष कानून बनाने का अधिकार था।⁴⁴⁵ यद्यपि जनजातीय समुदायों को और अधिक शोषण और हाशिए पर डालने से बचाने के लिए एक व्यवस्था के रूप में तैयार किया गया था, अनुसूचित जिला अधिनियम, 1874, उन्हें गैर-जनजातीय आबादी से अलग-थलग करने की औपनिवेशिक प्रवृत्ति को दर्शाता था, ताकि किसी भी संभावित विद्रोह को रोका जा सके।⁴⁴⁶

बाद में भारत सरकार अधिनियम, 1919 के तहत, 'पिछड़े क्षेत्रों' की अवधारणा पेश की गई, जिसमें मुख्य रूप से आदिवासी समुदायों द्वारा बसे कुछ क्षेत्रों को शामिल किया गया।⁴⁴⁷ धारा 21 ने 'पिछड़े क्षेत्रों' पर लागू कानूनों को अधिनियमित करने के लिए संसद की विधायी क्षमता को सीमित कर दिया, इसके बजाय गवर्नर-जनरल को ब्रिटिश भारत में किसी भी क्षेत्र को 'पिछड़े क्षेत्र' के रूप में घोषित करने और आवश्यक समझने पर यह तय करने की अनुमति दी कि सामान्य कानून वहां कैसे लागू होंगे, जिसमें संसद के अधिनियमों को 'पिछड़े क्षेत्र' पर पूरी तरह से लागू होने से रोकना या उनके आवेदन को संशोधित करना शामिल है,⁴⁴⁸

भारतीय सांविधिक आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, जिसे आमतौर पर साइमन कमीशन रिपोर्ट के रूप में जाना जाता है, ब्रिटिश भारत के⁴⁴⁹ 'पिछड़े क्षेत्रों' ने 2,07,900 वर्ग मील (लगभग 13 मिलियन की आबादी के साथ) के क्षेत्र को कवर किया।⁴⁵⁰ इन 'पिछड़े क्षेत्रों' में से, मद्रास में लक्षद्वीप द्वीप समूह और मिनिक्ॉय, बंगाल में चटगाँव पहाड़ी क्षेत्र, पंजाब में स्पीति, बिहार और उड़ीसा में बर्मा और अंगुल

in the resolution next hereinafter mentioned, it shall also include any other territory to which the Secretary of State for India, by resolution in Council, may declare the provisions of the thirty-third of Victoria, Chapter III, Section 1, to be applicable."

⁴⁴⁴ *Union of India v. Rakesh Kumar* (2010) 4 SCC 50, para. 2.

⁴⁴⁵ Nandini Sundar, *The Making of the 5th and 6th Schedule*, Talk delivered at 5th Annual History for Peace Conference, The Idea of the Indian Constitution (Jul. 2019), available at: <https://www.historyforpeace.pw/post/the-making-of-the-5th-and-6th-schedule> (last visited on Sep. 29, 2025).

⁴⁴⁶ Virginius Xaxa, "Tribes and Indian National Identity" 23(1) *The Brown Journal of World Affairs* 227-228 (2016).

⁴⁴⁷ *Id.* at 227.

⁴⁴⁸ The Government of India Act, 1919, s. 21(2): "The Governor-General in Council may declare any territory in British India to be a 'backward tract', and may, by notification, with such sanction as aforesaid, direct that the principal Act and this Act shall apply to that territory subject to such exceptions and modifications as may be prescribed in the notification. Where the Governor-General in Council has, by notification, directed as aforesaid, he may, by the same or subsequent notification, direct that any Act of the Indian Legislature shall not apply to the territory in question or any part thereof, or shall apply to the territory or any part thereof subject to such exceptions or modifications as the Governor-General thinks fit, or may authorize the governor in council to give similar directions as respects any Act of the local legislature."

⁴⁴⁹ Indian Statutory Commission, "Report of the Indian Statutory Commission Volume 1-Survey" (May 1930). The Simon Commission was formed under the Chairmanship of Sir John Simon to review the working of the system of the government established by the Government of India Act, 1919, and inquired into how the constitutional reforms were functioning in British India, particularly, the system of government, the growth of education, and the development of representative institutions.

⁴⁵⁰ Indian Statutory Commission, "Report of the Indian Statutory Commission Volume 1-Survey" (May 1930), p. no. 159.

जैसे कुछ क्षेत्रों को इतना पिछड़ा माना जाता था कि उन्हें सुधारों से पूरी तरह से बाहर रखा गया था। इस बीच, शेष 'पिछड़े क्षेत्रों' में, गवर्नर जनरल द्वारा किए गए अपवादों और संशोधनों के अधीन, ब्रिटिश भारत के सामान्य कानून लागू हुए।⁴⁵¹ मद्रास, बॉम्बे, बंगाल और बिहार और उड़ीसा, असम और बर्मा जैसे क्षेत्रों की प्रेसीडेंसी इन विशेष प्रशासनिक व्यवस्थाओं के अंतर्गत आती थी, जिसमें इन क्षेत्रों की विशेषताओं और निवासियों के अनुसार कानून लागू किए गए थे।⁴⁵²

साइमन कमीशन रिपोर्ट ने इन क्षेत्रों की विषमता पर जोर देते हुए कहा कि दार्जिलिंग जिले के कुछ हिस्सों में बंगाली आबादी रहती थी, जबकि आसपास के हिमालयी क्षेत्रों में अलग-अलग धर्म, भाषा और रीति-रिवाजों के साथ कई 'पहाड़ी जनजातियां' रहती थीं।⁴⁵³ साइमन कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार, छोटानागपुर क्षेत्र में लगभग समान 'आदिवासी' और 'अर्ध-आदिवासी जनजातियों' की आबादी थी,⁴⁵⁴ जबकि मध्य प्रांतों (उपजाऊ मैदानों और व्यापक पहाड़ी और वन क्षेत्रों दोनों द्वारा चिह्नित) में गोंड और अन्य जनजातियों का निवास था, जिन्होंने "अपनी भाषा और अपने स्वयं के जीववादी धर्म" को बनाए रखा।⁴⁵⁵ साइमन कमीशन रिपोर्ट ने मद्रास एजेंसी को विशेष कानूनों के तहत प्रशासित एक क्षेत्र के रूप में वर्णित किया जो इसके "आदिम निवासियों के अनुरूप था, जो विशिष्ट 'जीववादी और आदिवासी धर्मों' का पालन करते थे और" बाहरी हस्तक्षेप के प्रति संवेदनशीलता से चिह्नित बड़े पैमाने पर अविकसित क्षेत्रों में रहते थे"।⁴⁵⁶ इसी तरह, साइमन कमीशन रिपोर्ट ने असम के 'पिछड़े क्षेत्रों' को 'जंगली पहाड़ी लोगों' और 'मैदानी सभ्यता' के विपरीत विच्छेदन में चित्रित किया।⁴⁵⁷

पूर्वगामी दृष्टिकोण को भारत सरकार अधिनियम, 1935 द्वारा मजबूत किया गया था, जिसने बड़े पैमाने पर जनजातीय समुदायों की आबादी वाले क्षेत्रों को 'बहिष्कृत क्षेत्रों' और 'आंशिक रूप से बहिष्कृत क्षेत्रों' के रूप में वर्गीकृत किया था। बहिष्कृत क्षेत्रों को सीधे राज्यपाल द्वारा विधायी हस्तक्षेप के बिना प्रशासित किया जाता था, जबकि आंशिक रूप से बहिष्कृत क्षेत्रों में प्रांतीय विधानसभाओं की सीमित निगरानी होती थी।⁴⁵⁸ इन प्रावधानों के पीछे का इरादा आदिवासी समुदायों को "उन्नत समुदायों द्वारा शोषण" के रूप में वर्णित औपनिवेशिक अधिकारियों से अलग करना था, हालांकि व्यवहार में, इसने संसाधन समृद्ध आदिवासी क्षेत्रों पर औपनिवेशिक नियंत्रण को मजबूत करने में सक्षम बनाया।⁴⁵⁹ वास्तव में, ब्रिटिश औपनिवेशिक राज्य की स्थापना आदिवासी समुदायों की पैतृक भूमि के अधिग्रहण के आधार पर की गई थी, जिसने भूमि और प्रकृति

⁴⁵¹*Ibid.*

⁴⁵²*Id.* at 54-82.

⁴⁵³*Id.* at 62.

⁴⁵⁴*Id.* at 69.

⁴⁵⁵*Id.* at 71.

⁴⁵⁶*Id.* at 56.

⁴⁵⁷*Id.* at 75.

⁴⁵⁸The Government of India Act, 1935, ch. V: "Excluded Areas and Partially Excluded Areas."

⁴⁵⁹B. Shiva Rao, II *The Framing of India's Constitution: A Study* 371-373 (The Indian Institute of Public Administration, 1967).

के साथ साझा किए गए पारंपरिक सहजीवी संबंधों को बाधित कर दिया था।⁴⁶⁰ नतीजतन, जिस तरह से औपनिवेशिक शासन के दौरान आदिवासी समुदायों के साथ प्रतिकूल व्यवहार किया गया, उसकी भारी आलोचना की गई।⁴⁶¹

1.2.3. गोलमेज सम्मेलन

हालांकि साइमन कमीशन रिपोर्ट ने आदिवासी समुदायों के "आत्म-सम्मान के नुकसान, उनके युद्ध जैसे कौशल में विश्वास, उनके आदिवासी देवताओं में विश्वास और उनके पितृसत्तात्मक रीति-रिवाजों में निर्बाध आनंद" पर अफसोस जताते हुए सुझाव दिया कि आदिवासी समुदायों की अनूठी सांस्कृतिक पहचान को नष्ट करने से बचने के लिए प्रगति धीरे-धीरे होनी चाहिए,⁴⁶² इसकी व्यापक रूप से निंदा की गई और भारतीय जनता ने इसे खारिज कर दिया।⁴⁶³ इसलिए, ब्रिटिश सरकार ने 1930 से 1932 के बीच गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए। इन सम्मेलनों का मकसद आज़ाद भारत के लिए एक संभावित संवैधानिक ढांचे पर विचार-विमर्श करना था। इनमें ब्रिटिश सरकार और भारतीय समुदायों के प्रतिनिधियों को एक साथ लाया गया, जिनमें डॉ. बी.आर. अंबेडकर भी शामिल थे, जो 'दलित वर्गों' के प्रमुख प्रवक्ता के रूप में उभरे।⁴⁶⁴ जब बड़े मुद्दों पर आम सहमति नहीं बन सकी, तो गोलमेज सम्मेलनों से सामने आई सिफारिशों को चर्चा के लिए ब्रिटिश संसद को श्वेत पत्र के रूप में भेजा गया।⁴⁶⁵ जवाब में, ब्रिटिश संसद ने एक संयुक्त समिति का गठन किया, जिसमें ब्रिटिश भारत और रियासतों के प्रतिनिधि शामिल थे।⁴⁶⁶

इस संयुक्त समिति से पहले, डॉ. अम्बेडकर और डॉ. जे. एच. हॉटन ने 'अवसादग्रस्त' और 'आदिम' वर्गों के संरक्षण के सवाल पर बहस की।⁴⁶⁷ डॉ. अम्बेडकर ने स्पष्ट किया कि डॉ. अंबेडकर ने साफ़ किया कि 'पिछड़े' और 'आदिम' वर्गों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व

⁴⁶⁰ Government of India, "Committee of Members of Parliament and Experts Constituted to Make Recommendations on Law Concerning Extension of Provisions of the Constitution (Seventy-Third Amendment) Act, 1992 to Scheduled Areas" (Ministry of Rural Development, 1995).

⁴⁶¹ Bhangya Bhukya, "The Mapping of the Adivasi Social: Colonial Anthropology and Adivasis" 43(39) *Economic and Political Weekly* 103-109 (2008).

⁴⁶² Indian Statutory Commission, "Report of the Indian Statutory Commission Volume 1-Survey" (May 1930), p.no. 76.

⁴⁶³ Anurag Bhaskar, *The Foresighted Ambedkar: Ideas That Shaped Indian Constitutional Discourse* 113 (Penguin Random House, India, 2024).

⁴⁶⁴ *Id.* at 113-125; Depressed classes is a loose term that referred to the *Dalits*, those considered 'untouchables', as well as the Scheduled Castes. Poona Pact 1932, available at: <https://www.constitutionofindia.net/historical-constitution/poona-pact-1932-b-r-ambedkar-and-m-k-gandhi> (last visited on Nov. 5, 2025).

⁴⁶⁵ Anurag Bhaskar, *The Foresighted Ambedkar: Ideas That Shaped Indian Constitutional Discourse* 125 (Penguin Random House, India, 2024).

⁴⁶⁶ *Id.* at 126.

⁴⁶⁷ Vasant Moon (ed.), II *Dr. Babasaheb Ambedkar: Writings and Speeches* 736-742 (Ministry of Social Justice and Empowerment, 2019); Indian Statutory Commission, "Report of the Indian Statutory Commission Volume 1-Survey" (May 1930), p.no. 32: "Primitive peoples do not claim to belong to any particular religion: they only know of their own beliefs, and are therefore unconscious of religious classifications."; Anurag Bhaskar, *The Foresighted Ambedkar: Ideas That Shaped Indian Constitutional Discourse* 128 (Penguin Random House, India, 2024): "Dr. Ambedkar was strongly in favour of the inclusion of what the British called 'primitive tribes' (sic) in the political system."

से बाहर रखने से वे अपनी बात रखने की क्षमता खो देंगे और शिक्षा व कल्याण के ज़रूरी सुधारों में बाधा आएगी।⁴⁶⁸ डॉ. अम्बेडकर ने यह भी बताया कि 'आदिम' वर्गों के हितों की रक्षा केवल राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों के माध्यम से, उन्हें पर्याप्त विधायी प्रतिनिधित्व दिए बिना नहीं की जा सकती है।⁴⁶⁹ डॉ. अम्बेडकर ने इसलिए राजनीतिक प्रणाली में 'आदिम' वर्गों को शामिल करने के पक्ष में जोर देते हुए, यह स्पष्ट करते हुए तर्क दिया कि "एक मंत्री से उन आदिम लोगों में रुचि रखने की उम्मीद नहीं की जा सकती है जो विधानमंडल का हिस्सा नहीं हैं"।⁴⁷⁰ विशेष रूप से, उन्होंने कहा कि यदि आदिवासी समुदाय भारतीय राजनीतिक प्रणाली का हिस्सा बन जाते हैं, तो उन्हें 'दलित' वर्गों में 'कई दोस्त' मिलेंगे।⁴⁷¹ इसके बाद, स्वतंत्र भारत के लिए एक संवैधानिक तंत्र के निर्माण की प्रक्रिया में, अल्पसंख्यकों और जनजातीय समुदायों के लिए विशिष्ट गारंटी सहित भारतीय नागरिकों के लिए मौलिक अधिकारों का एक अलग चार्टर तैयार करने में संविधान सभा की सहायता के लिए कैबिनेट मिशन प्लान⁴⁷² द्वारा एक सलाहकार समिति नियुक्त की गई थी।⁴⁷³ इस उद्देश्य के लिए, तीन उप-समितियों का गठन किया गया: एक मौलिक अधिकार उप-समिति, एक अल्पसंख्यक उप-समिति, और एक जनजातीय और बहिष्कृत क्षेत्र उप-समिति।⁴⁷⁴

1.3. संवैधानिक सभा की बहसों में मान्यता

जनजातीय समुदायों ने संविधान के निर्माण को औपचारिक रूप से समान नागरिकों और अलग-अलग लोगों दोनों के रूप में मान्यता प्राप्त करने के अवसर के रूप में देखा, और अपनी पारंपरिक शासन प्रणालियों के आधार पर संवैधानिक डिजाइन और लोकतंत्र के रूपों के लिए ठोस वैकल्पिक विचारों की पेशकश की।⁴⁷⁵ हालाँकि, संविधान सभा में आदिवासी समुदायों के केवल छह सदस्य शामिल थे, जिनमें से जयपाल सिंह मुंडा और जेजेएम निकोल्स रॉय की एकमात्र सक्रिय आवाजें थीं

⁴⁶⁸ Vasant Moon (ed.), *I.Dr. Babasaheb Ambedkar: Writings and Speeches* 739-742 (Ministry of Social Justice and Empowerment, New Delhi, 2019).

⁴⁶⁹ *Id.* at 740.

⁴⁷⁰ *Id.* at 741.

⁴⁷¹ *Ibid.*; Anurag Bhaskar, *The Foresighted Ambedkar: Ideas That Shaped Indian Constitutional Discourse* chap. 9 (Penguin Random House, 2024).

⁴⁷² The Cabinet Mission Plan was a statement made by the Cabinet Mission and the Viceroy, Lord Wavell, on May 16, 1946, that contained proposals regarding the constitutional future of India in the wake of Indian political parties and representatives not coming to an agreement. Cabinet Mission Plan (Cabinet Mission, 1946), Constitution of India, available at: <https://www.constitutionofindia.net/historical-constitution/cabinet-mission-plan-cabinet-mission-1946/> (last visited on Nov. 8, 2025).

⁴⁷³ Advisory Committee on Fundamental Rights, Minorities and Tribal and Excluded Areas, available at: <https://www.constitutionofindia.net/committees/advisory-committee-on-fundamental-rights-minorities-and-tribal-and-excluded-areas-24-january-1947/> (last visited on Oct. 29, 2025).

⁴⁷⁴ Anurag Bhaskar, *The Foresighted Ambedkar: Ideas That Shaped Indian Constitutional Discourse* 208 (Penguin Random House, India, 2024); Granville Austin, *The Indian Constitution: Cornerstone of a Nation* 66-67 (Oxford University Press, 1999).

⁴⁷⁵ Nandini Sundar, "We Will Teach India Democracy: Indigenous Voices in Constitution Making" 52(1) *The Journal of Imperial and Commonwealth History* 181-213 (2024).

जिन्होंने आदिवासी समुदायों की पहचान, अंतर्निहित अधिकारों और अपेक्षाओं के बारे में उत्साहपूर्वक बात की।⁴⁷⁶

जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित करने के संविधान सभा के संकल्प को दोहराते हुए उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया, तो⁴⁷⁷ जयपाल सिंह मुंडा, एक प्रमुख आदिवासी नेता, ने उद्देश्य प्रस्ताव के समर्थन में सम्मोहक टिप्पणी की:

"..... जैसा कि हम जंगलों में रहते हैं, हम जानते हैं कि इस प्रस्ताव का समर्थन करने का क्या अर्थ है। 30 मिलियन से अधिक आदिवासी की ओर से... (चीयर्स) मैं इसका समर्थन करता हूँ क्योंकि यह एक ऐसा संकल्प है जो इस देश में हर दिल में धड़कने वाली भावनाओं को व्यक्त करता है। इस संकल्प के शब्दों से मेरा कोई विवाद नहीं है। एक जंगली के रूप में, एक आदिवासी के रूप में, मुझे प्रस्ताव की कानूनी पेचीदगियों को समझने की उम्मीद नहीं की जाती है। लेकिन मेरा सामान्य ज्ञान मुझे बताता है, मेरे लोगों का सामान्य ज्ञान मुझे बताता है कि हम में से हर एक को स्वतंत्रता के उस रास्ते पर चलना चाहिए और एक साथ लड़ना चाहिए। महोदय, अगर भारतीय लोगों का कोई समूह है जिसके साथ घटिया व्यवहार किया गया है तो वह मेरे लोग हैं। पिछले 6,000 वर्षों से उनके साथ अपमानजनक व्यवहार किया जा रहा है, उनकी उपेक्षा की जा रही है। सिंधु घाटी सभ्यता का इतिहास, जिसका मैं एक बच्चा हूँ, यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि यह नए लोग हैं जहाँ तक मेरा संबंध है, आप में से अधिकांश घुसपैठिये हैं ये नए लोग हैं जिन्होंने मेरे लोगों को सिंधु घाटी से जंगल की ओर खदेड़ दिया है... मेरे लोगों का पूरा इतिहास विद्रोहों और अव्यवस्थाओं से विरामित भारत के गैर-आदिवासियों द्वारा निरंतर शोषण और विस्थापन का है... मेरे लोग आपके नस्लवाद, हिंदुओं और बाकी सभी के नस्लवाद के कारण 6,000 वर्षों से पीड़ित हैं... मेरे लोग, आदिवासी-वे भी भारतीय हैं।"⁴⁷⁸

जयपाल सिंह मुंडा ने भी बार-बार अंतर्निहित अधिकार रखने वाले जनजातीय समुदायों को अल्पसंख्यकों से अलग किया:

"मुझे खेद है कि इस सदन में दलों और अल्पसंख्यकों के संदर्भ में बहुत अधिक चर्चा हुई है। महोदय, मैं अपने लोगों को अल्पसंख्यक नहीं मानता। हम आज सुबह सदन में पहले ही सुन चुके हैं कि दलित वर्ग भी खुद को आदिवासी मानते हैं, जो इस देश के मूल निवासी हैं।"

⁴⁷⁶Nandini Sundar, *The Making of the 5th and 6th Schedule*, Talk delivered at 5th Annual History for Peace Conference, The Idea of the Indian Constitution (Jul. 2019), available at: <https://www.historyforpeace.pw/post/the-making-of-the-5th-and-6th-schedule> (last visited on Sep. 29, 2025).

⁴⁷⁷Stages of Constitution Making, First Session of the Constituent Assembly, Constitution of India, available at: <https://www.constitutionofindia.net/stages-of-constitution-making/> (last visited on Nov. 1, 2025).

⁴⁷⁸Constituent Assembly Debates on December 19, 1946, available at: <https://www.constitutionofindia.net/debates/19-dec-1946/#85134> (last visited on Nov. 1, 2025).

*"यदि आप बाहरी जातियों और अन्य लोगों जैसे लोगों को जोड़ते जाते हैं जो सामाजिक रूप से किसी व्यक्ति की भूमि में नहीं हैं, तो हम अल्पसंख्यक नहीं हैं। किसी भी मामले में, हमारे पास निर्देशात्मक अधिकार हैं जिन्हें कोई भी नकारने की हिम्मत नहीं करता है मुझे नहीं और कहने की जरूरत है।"*⁴⁷⁹

उन्होंने कहा, "मैं नहीं मानता कि आदिवासी अल्पसंख्यक हैं। मैंने हमेशा यह माना है कि जो लोग इस देश के मूल मालिक हैं, भले ही वे कुछ ही हों, उन्हें कभी भी अल्पसंख्यक नहीं माना जा सकता है।"

*उनके पास निर्देशात्मक अधिकार हैं जिनसे कोई इनकार नहीं कर सकता।"*⁴⁸⁰

इसके अलावा, जयपाल सिंह मुंडा ने उन लोकतांत्रिक परंपराओं पर प्रकाश डाला जो पहले से ही प्राचीन भारत के आदिवासी गणराज्यों में प्रचलित थीं:

*"महोदय, मेरा कहना है कि आप मेरे लोगों को लोकतंत्र नहीं सिखा सकते। मैं फिर से कहना चाहूंगा कि भारत-आर्य समूहों के आने से ही लोकतंत्र के वे बचे-खुचे निशान खत्म हो रहे हैं... वहाँ कई जनजातीय गणराज्य थे, जिनमें से कुछ बहुत बड़े इलाकों में फैले हुए थे।"*⁴⁸¹

"महोदय, फिर से कई जनजातीय गणराज्य होंगे, जो भारतीय स्वतंत्रता की लड़ाई में अग्रणी होंगे... आइए हम एक साथ स्वतंत्रता के लिए लड़ें, एक साथ बैठें और एक साथ काम करें। तभी हमें वास्तविक स्वतंत्रता मिलेगी।"

⁴⁸²

जयपाल सिंह मुंडा ने संविधान सभा द्वारा तैयार किए जा रहे संवैधानिक ढांचे से जनजातीय समुदायों द्वारा मांगी गई सुरक्षा की प्रकृति को भी स्पष्ट किया:

"महोदय, मेरे लोगों को पर्याप्त सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है जैसा कि पंडित जवाहर लाल नेहरू ने कहा है। उन्हें मंत्रियों से सुरक्षा की आवश्यकता होती है, आज यही स्थिति है। हम किसी विशेष सुरक्षा की मांग नहीं करते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे साथ हर दूसरे भारतीय की तरह व्यवहार किया जाए। मैं पंडित जवाहर लाल नेहरू को उनकी बात पर मानता हूँ। मैं आप सभी से कहता हूँ कि अब हम एक नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं, स्वतंत्र भारत का एक नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं, जहां अवसरों की समानता है, जहां किसी की उपेक्षा नहीं की जाएगी। मेरे समाज में जाति का कोई सवाल ही नहीं है। हम सब बराबर हैं। क्या कैबिनेट मिशन ने हमारे साथ लापरवाही भरा बर्ताव नहीं किया? क्या 3 करोड़ से ज्यादा लोगों को पूरी तरह नज़रअंदाज़ नहीं किया गया? क्या नियमों में कोई ऐसा प्रावधान होगा जिससे अधिक आदिवासियों को शामिल करना संभव हो सके? और आदिवासियों से मेरा तात्पर्य है,

⁴⁷⁹ Constituent Assembly Debates on December 19, 1946, 1946/#85139 (last visited on Sep. 30, 2025).

⁴⁸⁰ Constituent Assembly Debates on December 19, 1946, 1946/#85139 (last visited on Sep. 30, 2025).

⁴⁸¹ Constituent Assembly Debates on December 19, 1946, 1946/#85141 (last visited on Sep. 30, 2025).

⁴⁸² Constituent Assembly Debates on December 19, 1946, 1946/#85142 (last visited on Sep. 30, 2025).

available at: <https://www.constitutionofindia.net/debates/19-dec-1946/#85139>

available at: <https://www.constitutionofindia.net/debates/19-dec-1946/#85139>

available at: <https://www.constitutionofindia.net/debates/19-dec-1946/#85141>

available at: <https://www.constitutionofindia.net/debates/19-dec-1946/#85142>

महोदय, न केवल पुरुषों से बल्कि महिलाओं से भी...⁴⁸³

उन्होंने कहा, " हम चाहते हैं कि हमारे साथ दूसरों की तरह व्यवहार किया जाए। अतीत में, प्रमुख राजनीतिक दलों को धन्यवाद, ब्रिटिश सरकार को धन्यवाद और प्रत्येक प्रबुद्ध भारतीय नागरिक को धन्यवाद, पहले, बड़ी राजनीतिक पार्टियों, ब्रिटिश सरकार और हर जागरूक भारतीय नागरिक की वजह से हमें अलग-थलग रखा गया और मानो किसी चिड़ियाघर में बंद कर दिया गया। अतीत में सभी लोगों का यही रवैया रहा है। अब हमारा मुद्दा यह है कि आपको हमारे साथ मिलना-जुलना होगा। हम आपके साथ मिलने के लिए तैयार हैं, और यही कारण है कि हम आपको हमारे पास आने के लिए मजबूर करेंगे, क्योंकि हमें आपके पास जाना होगा, कि हमने जहां तक विधानमंडलों का संबंध है, सीटों के आरक्षण पर जोर दिया है।⁴⁸⁴

जयपाल सिंह मुंडा ने संविधान सभा को यह भी याद दिलाया कि आदिवासी समुदायों ने कभी भी अलग निर्वाचन क्षेत्रों की मांग नहीं की थी, बल्कि संयुक्त निर्वाचन क्षेत्रों में केवल आरक्षित सीटों की मांग की थी।⁴⁸⁵ उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत सरकार अधिनियम, 1935 के तहत, कुल 1585 में से राज्य विधानसभाओं के केवल 24 आदिवासी मंत्री थे, जिनका संसद में कोई आदिवासी प्रतिनिधित्व नहीं था।⁴⁸⁶ इसलिए उन्होंने उन रियासतों से अपील की, जहाँ आदिवासी समुदायों को प्रतिनिधित्व से पूरी तरह वंचित रखा गया था, और उम्मीद जताई कि "भारतीय भारत की भावना" वहाँ भी फैलेगी।

⁴⁸⁷

जयपाल सिंह मुंडा ने आदिवासी समुदायों के लिए प्रतिनिधित्व संबंधी गारंटी को कम करने के बारे में भी चिंता जताई, जैसा कि मूल कैबिनेट मिशन ज्ञापन और कमांड पेपर में इसके पुनर्मुद्रित संस्करण में कहा गया है:

"जयपाल सिंह: ... जब मुझे पहली बार कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत मेमोरेंडम की एक कॉपी दी गई, तो सेक्शन 20 में भाषा इस प्रकार थी: - नागरिकों, अल्पसंख्यकों और आदिवासी और बहिष्कृत क्षेत्रों के अधिकारों पर सलाहकार समिति में प्रभावित हितों का पूर्ण प्रतिनिधित्व होना चाहिए (ध्यान दें 'पूर्ण प्रतिनिधित्व होना चाहिए').....

⁴⁸³ Constituent Assembly Debates on December 19, 1946, 1946/#85134 (last visited on Nov. 1, 2025).

available at: <https://www.constitutionofindia.net/debates/19-dec-1946/#85134>

⁴⁸⁴ Constituent Assembly Debates on December 19, 1946, 1946/#85139 (last visited on Sep. 30, 2025).

available at: <https://www.constitutionofindia.net/debates/19-dec-1946/#85139>

⁴⁸⁵ "We have not asked and, in fact, we have never had separate electorates; only a small portion of the Adibasis, that part of it which was converted to various religious and particularly to the Christian religions of the West, had a separate electorate but the vast majority, wherever it was enfranchised, was on a general electorate with reservation of seats. So, as far as the Adibasis are concerned there is no change whatever. But numerically there is a very big change". Constituent Assembly Debates on August 27, 1947, available at: <https://www.constitutionofindia.net/debates/27-aug-1947/#90776> (last visited on Sep. 30, 2025).

⁴⁸⁶ "Under the 1935 Act, throughout the Legislatures in India, there were altogether only 24 Adibasi M. L. As. out of a total of 1,585, as far as the Provincial Legislatures were concerned and not a single representative at the Centre". Constituent Assembly Debates on August 27, 1947, available at: <https://www.constitutionofindia.net/debates/27-aug-1947/#90776> (last visited on Sep. 30, 2025).

⁴⁸⁷ Constituent Assembly Debates on August 27, 1947, available at: <https://www.constitutionofindia.net/debates/27-aug-1947/#90776> (last visited on Sep. 30, 2025).

जयपाल सिंह: अब, जब मैं कमांड पेपर 6821 में उसका पुनर्मुद्रण पढ़ता हूँ, तो वही पैराग्राफ 20 अलग तरह से पढ़ा जाता है। इसमें लिखा है: "नागरिकों, अल्पसंख्यकों और जनजातीय और बहिष्कृत क्षेत्रों के अधिकारों पर सलाहकार समिति में उचित प्रतिनिधित्व होगा।"

सरदार हरनाम सिंह: यह केवल एक टाइपिंग की त्रुटि है। मूल पाठ में "प्रभावित हितों का पूर्ण प्रतिनिधित्व होना चाहिए" शब्द शामिल थे।

जवाहरलाल नेहरू: क्या ऐसा है?

सरदार हरनाम सिंह: "मैं निश्चित हूँ।" ⁴⁸⁸

जयपाल सिंह मुंडा ने सार्वजनिक रोजगार से संबंधित आश्वासनों के अनुदान से आदिवासी समुदायों के बहिष्कार पर भी अफसोस जताया:

"मुझे गहरा खेद है कि सबसे जरूरतमंद, आदिवासियों के सबसे योग्य समूह को पूरी तरह से तस्वीर से बाहर कर दिया गया है। हम किसी भी असमान शर्तों पर आरक्षण नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जब तक हम नियुक्ति के लिए आवश्यक मानकों पर आते हैं, हमें तस्वीर से बिल्कुल भी बाहर नहीं रखा जाना चाहिए।" ⁴⁸⁹

सलाहकार समिति के गठन के संबंध में, जयपाल सिंह मुंडा ने अन्य अल्पसंख्यकों की तुलना में आदिवासी समुदायों के असमान प्रतिनिधित्व पर सवाल उठाए और आदिवासी महिला प्रतिनिधियों की पूरी तरह से अनुपस्थिति की ओर भी ध्यान आकर्षित किया:

"महोदय, प्रस्तावक और समर्थक ने संकेत दिया है कि इस सलाहकार समिति में स्वभाव, वितरण कैसे किया गया है। यह विशेष रूप से आदिवासी लोगों के लिए जीवन और मृत्यु का मामला है... मैं उन अल्पसंख्यक समुदायों को भी बधाई देता हूँ जो संख्यात्मक रूप से अधिक सीटें प्राप्त करने में सफल रहे हैं। मुझे इन सब से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन हकीकत यह है कि उन्हें उनके हक से कहीं अधिक सीटें दी गई हैं, जबकि जब हम अपने लोगों, इस देश के वास्तविक और सबसे प्राचीन लोगों के पास आते हैं, तो स्थिति अलग होती है। लेकिन मैं नाराज़ नहीं हूँ... मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हम संख्या पर निर्भर नहीं हैं सलाहकार समिति में दिए जाने वाले मतों की संख्या। हम बेपरवाह हो गए हैं। मैंने सरदार पटेल या आपके पास हमारे अधिकारों के बारे में, हमारे दावों के बारे में और हमारे बकाया के बारे में कोई प्रतिनियुक्ति नहीं भेजी। मैं इसे सदन और सलाहकार समिति की समझदारी पर छोड़ता हूँ कि वे आखिरकार छह हजार साल से चले आ रहे अन्याय को ठीक करेंगे... मैं और सीटों की मांग नहीं कर रहा हूँ; मैंने कोई संशोधन पेश नहीं किया है, न ही मैं कोई संशोधन ला रहा हूँ, लेकिन मैं इस सदन और इस देश का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूँ कि यहाँ हम सभी की परीक्षा हो रही है। अब तक हमारे लिए यह कहना बहुत आसान रहा है कि यह अंग्रेज हैं यह अंग्रेज हैं"

⁴⁸⁸ Constituent Assembly Debates on December 19, 1946, available at: <https://www.constitutionofindia.net/debates/19-dec-1946/#85135> (last visited on Nov. 1, 2025).

⁴⁸⁹ Constituent Assembly Debates on August 27, 1947, available at: <https://www.constitutionofindia.net/debates/27-aug-1947/#90779> (last visited on Sep. 30, 2025).

जिन्होंने आपके लिए आंशिक रूप से बहिष्कृत क्षेत्र और बहिष्कृत क्षेत्र बनाकर आपको चिड़ियाघर में रखा है। क्या आप अलग तरह से व्यवहार करते हैं? यह सवाल मैं पूछ रहा हूँ। मैं सलाहकार समिति से पूछता हूँ। मुझे इसमें अपना नाम मिलता है। जबकि, मैं यह बताने के लिए बाध्य हूँ कि सलाहकार समिति में किसी भी आदिवासी महिला का नाम नहीं है। इसे कैसे छोड़ दिया गया? सलाहकार समिति में कोई आदिवासी महिला सदस्य नहीं है। समिति के सदस्यों के चयन के लिए जिम्मेदार लोगों के साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि उन्हें शामिल किया जाना चाहिए, लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि इस बात पर गंभीरता से विचार नहीं किया गया है। इसी तरह, जैसा कि मैं तेरह को दोहराता हूँ या जो भी आंकड़ा तय किया गया है मैं स्वीकार करता हूँ कि, मैं अब और नहीं कहता, लेकिन मैं उस अज्ञानता को उजागर करना चाहता हूँ जो इस आंकड़े के सुझाव में, या उस मामले के लिए, जनजातीय क्षेत्रों के सदस्यों के नामांकन में उजागर हुई है। पूरे भारत में आदिवासी आबादी की स्थिति पर नज़र डालिए। मुझे इससे कोई विवाद नहीं है। हर दस साल में होने वाली जनगणना में जो गड़बड़ियाँ हुई हैं, उनके बावजूद ताज़ा आँकड़ा 254 लाख है, मैं इसे मानता हूँ। अब इसमें हम पाते हैं कि भारत में सबसे बड़ा आदिवासी समूह मुंडा भाषा बोलने वाली जनजाति है। अगर आप 1941 के उनके आँकड़ों को जोड़ें, तो पाएँगे कि उनकी संख्या लगभग 43 लाख है। इसके बाद गोंड जनजाति का नंबर आता है। अब हमें गोंड समुदाय का एक प्रतिनिधि मिला है; मुझे खुशी है कि ऐसा एक प्रतिनिधि है। इसके बाद भील्स आते हैं, 23 लाख। इस समिति में कोई भील नहीं है। इस तरह, हम ओराओं के पास जाते हैं, 11 लाख के साथ, इस समिति में कोई ओराओं नहीं है। अध्यक्ष महोदय, समय बहुमूल्य है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहीं और कहा था कि हम हर दिन जो कुछ भी करते हैं, उस पर लगभग 10,000 रुपये का खर्च आता है। मुझे लगता है कि 2.5 करोड़ आदिवासियों की ज़िंदगी की कीमत रोज़ाना 10,000 रुपये से कहीं ज़्यादा है। यह एक ऐसा मौका है जब मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ, अगर आप मुझे इजाज़त दें। मैंने यह भी देखा है कि किसी न किसी वजह से, मौलिक अधिकार समिति में कोई भी आदिवासी सदस्य नहीं है।⁴⁹⁰

जेजेएम निकोलस रॉय ने जनजातीय समुदायों के लिए स्वायत्तता की आवश्यकता पर बात की, और जोर देकर कहा कि संवैधानिक ढांचा आत्मसात करने के बजाय आत्मनिर्णय की धारणा पर आधारित होना चाहिए:

"सरकारी रिपोर्ट यह है कि पहाड़ों के लोगों की अपनी संस्कृति है जो मैदानी इलाकों से काफी अलग है। सामाजिक संगठन गाँव, कबीले और जनजाति का होता है और दृष्टिकोण और संरचना आम तौर पर दृढ़ता से लोकतांत्रिक होती है। जाति या पर्दा की कोई व्यवस्था नहीं है और बाल विवाह की प्रथा नहीं है।"⁴⁹¹

"तो, यह पहाड़ी जनजातियों की संस्कृति है। भारत को समानता और असली लोकतंत्र की उस भावना या सोच को अपनाना चाहिए जो इन आदिवासी लोगों में है। उन्हें एक पल के लिए भी यह नहीं सोचना चाहिए कि ये लोग

⁴⁹⁰ Constituent Assembly Debates on January 24, 1947, available at: <https://www.constitutionofindia.net/debates/24-jan-1947/#85977> (last visited on Nov. 1, 2025).

⁴⁹¹ Constituent Assembly Debates on September 6, 1949, available at: <https://www.constitutionofindia.net/debates/06-sep-1949/#117934> (last visited on Nov. 9, 2025).

*अपना लोकतंत्र और समानता छोड़ दें और किसी ऐसी दूसरी संस्कृति में घुल-मिल जाएं जो उनकी अपनी संस्कृति से बिल्कुल अलग हो और जिसे वे अपने समाज के लिए बिल्कुल भी सही न मानते हों।*⁴⁹²

जयपाल सिंह मुंडा और जेजेए निकोल्स रॉय के ये हस्तक्षेप ने आदिवासी समुदायों की आशंकाओं और आकांक्षाओं को उनके संवैधानिक भविष्य के बारे में स्पष्ट रूप से व्यक्त किया, न केवल एक हाशिए पर पड़े समूह के रूप में उनके अधिकारों की गारंटी के रूप में, बल्कि न्याय, प्रतिनिधित्व और औपचारिक मान्यता के मुद्दे के रूप में। नतीजतन, जहां ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन ने जनजातीय समुदायों को ऐसे विषयों के रूप में चिह्नित किया, जिन्हें शासित करने की आवश्यकता थी, संविधान सभा ने उन्हें निर्धारित अधिकारों और संवैधानिक संरक्षण के योग्य एक विशिष्ट पहचान वाले नागरिकों के रूप में अवधारणा देना शुरू कर दिया।

2. संवैधानिक पदनाम

जनजातीय समुदायों के ऐतिहासिक अधीनता, संरचनात्मक नुकसान और सामाजिक अलगाव और/या बहिष्कार को स्वीकार करते हुए, भारत का संविधान भारतीय आबादी के एक अंतर्निहित हिस्से के रूप में विशेष रूप से उनके अधिकारों, अधिकारों और हितों की रक्षा करने के लिए एक सचेत और निरंतर विकसित प्रयास को दर्शाता है, साथ ही यह सुनिश्चित करता है कि उनकी विशिष्ट सामाजिक, सांस्कृतिक, पारंपरिक, भाषाई और धार्मिक पहचान इस प्रक्रिया में नष्ट न हो।

2.1. अनुसूचित जनजातियाँ

जब संविधान अपनाया गया, तो ज्यादातर आदिवासी समुदायों को 'अनुसूचित जनजाति' के तौर पर मान्यता दी गई और उन्हें विशेष सुरक्षा की गारंटी दी गई। अनुच्छेद 366 (25) में "अनुसूचित जनजातियों" को ऐसी जनजातियों या जनजातीय समुदायों या ऐसी जनजातियों या जनजातीय समुदायों के भीतर के समूहों के रूप में परिभाषित किया गया है, जिन्हें संविधान के प्रयोजनों के लिए अनुच्छेद 342 के तहत अनुसूचित जनजाति माना जाता है।⁴⁹³ अनुच्छेद 342 भारत के राष्ट्रपति को, संबंधित राज्य के राज्यपाल के साथ परामर्श करने के बाद, ऐसे राज्यों में अनुसूचित जनजातियों के रूप में मान्यता प्राप्त जनजातियों या जनजातीय समुदायों को निर्दिष्ट करने के लिए अधिकृत करता है।⁴⁹⁴ अनुसूचित जनजातियों की सूची में बाद में कोई भी समावेश या बहिष्कार केवल संसद द्वारा अधिनियमित कानून के माध्यम से किया जा सकता है।⁴⁹⁵ नतीजतन, सभी समुदाय जो आदिवासी के रूप में अपनी पहचान बनाते हैं या जिन्हें आदिवासी समुदायों के रूप में संदर्भित

⁴⁹² Constituent Assembly Debates on September 6, 1949, available at: <https://www.constitutionofindia.net/debates/06-sep-1949/#117935> (last visited on Nov. 9, 2025).

⁴⁹³ The Constitution of India, 1950, art. 366(25).

⁴⁹⁴ The Constitution of India, 1950, art. 342: "Scheduled Tribes. (1) The President may with respect to any State or Union territory, and where it is a State after consultation with the Governor thereof, by public notification specify the tribes or tribal communities or parts of or groups within tribes or tribal communities which shall for the purposes of this Constitution be deemed to be Scheduled Tribes in relation to that State or Union territory, as the case may be."

⁴⁹⁵ The Constitution of India, 1950, art. 342: "Scheduled Tribes. (2) Parliament may by law include in or exclude from the list of Scheduled Tribes specified in a notification issued under clause (1) any tribe or tribal community or part of or group within any tribe or tribal community, but save as aforesaid a notification issued under the said clause shall not be varied by any subsequent notification."

या माना जाता है, उनके पास संविधान में 'अनुसूचित जनजाति' का पदनाम (और संबंधित अधिकार) स्वचालित रूप से नहीं होता है।

महाराष्ट्र राज्य बनाम मिलिंद के मामले में, उच्चतम न्यायालय की दो-न्यायाधीशों की पीठ ने यह अभिनिर्धारित किया कि एक बार अनुच्छेद 342 (1) के अधीन जारी की गई राष्ट्रपति की अधिसूचना में किसी जनजातीय समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में निर्दिष्ट किया जाता है, तो यह राज्य सरकारों या न्यायालयों या अधिकरणों या किसी अन्य प्राधिकारी के लिए अनुसूचित जनजातियों की सूची को संशोधित, संशोधित या परिवर्तित करने के लिए खुला नहीं है।⁴⁹⁶ सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा: "यह तय करने या घोषित करने के लिए कि किसी जनजाति या जनजातीय समुदाय के भीतर किसी भी हिस्से या समूह को सामान्य नाम में शामिल किया गया है, कोई भी जांच करने या कोई सबूत पेश करने की अनुमति नहीं है, भले ही संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950 में संबंधित प्रविष्टि में इसका विशेष रूप से उल्लेख नहीं किया गया हो"⁴⁹⁷ उच्चतम न्यायालय ने आगे स्पष्ट किया कि *भैयाराम मुंडा बनाम अनिरुद्ध पातर*⁴⁹⁸ और *दीना बनाम नारायण सिंह*⁴⁹⁹ में उच्चतम न्यायालय के पूर्ववर्ती दो-न्यायाधीशों की पीठ के निर्णयों में यह कहते हुए सही विधि निर्धारित नहीं की गई थी कि ऐसी जांच अनुज्ञेय थी या ऐसा साक्ष्य ग्राह्य था।⁵⁰⁰

उपलब्ध सबसे हाल के आंकड़ों के अनुसार (भारत की जनगणना, 2011 के आधार पर)⁵⁰¹ देश में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या 10,454,716 है, जो कुल राष्ट्रीय जनसंख्या का लगभग 8.6 प्रतिशत है। इनमें से 94,083,844 लोग ग्रामीण क्षेत्रों में और 10,461,872 लोग शहरी क्षेत्रों में रहते हैं। जिन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अनुसूचित जनजातियों की आबादी का बहुत अधिक अनुपात है, उनमें लक्षद्वीप (94.8 प्रतिशत), मिजोरम (94.4 प्रतिशत), नागालैंड (86.5 प्रतिशत), मेघालय (86.1 प्रतिशत), अरुणाचल प्रदेश (68.8 प्रतिशत), मणिपुर (40.9 प्रतिशत) और सिक्किम (33.8 प्रतिशत) शामिल हैं। तुलनात्मक रूप से बड़े भौगोलिक क्षेत्रों वाले राज्यों में, अनुसूचित जनजातियों की सबसे अधिक सांद्रता छत्तीसगढ़ (30.6 प्रतिशत) झारखंड (26.2 प्रतिशत) ओडिशा (22.8 प्रतिशत) मध्य प्रदेश (21.1 प्रतिशत) गुजरात (14.8 प्रतिशत) राजस्थान (13.5 प्रतिशत) और महाराष्ट्र (9 प्रतिशत) राज्यों में है।⁵⁰²

2.2. अनुसूचित क्षेत्र

1822 के विनियमन एक्स ने "गैर-विनियमित" क्षेत्रों का विचार पेश किया, जो ऐसे क्षेत्र थे जो कहीं और लागू सामान्य कानूनों द्वारा शासित नहीं होंगे। इन स्थानों पर, कार्यपालिका गवर्नर-जनरल के अधिकार के तहत व्यापक विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करती थी। यह दृष्टिकोण अंततः प्रशासनिक व्यवस्थाओं

⁴⁹⁶ *State of Maharashtra v. Milind* (2001) 1 SCC 4, para. 15.

⁴⁹⁷ *Id.* at para. 36.

⁴⁹⁸ *Bhaiya Ram Mundav. Anirudh Patar* (1970) 2 SCC 825.

⁴⁹⁹ *Dinav. Narayan Singh* (1968) SCC OnLine SC 326.

⁵⁰⁰ *State of Maharashtra v. Milind* (2001) 1 SCC 4, para. 36.

⁵⁰¹ Government of India, "Annual Report 2023-24" (Ministry of Tribal Affairs, 2024), p. no. 154.

⁵⁰² *Ibid.*

में विकसित हुआ जिसने बाद में स्वतंत्र भारत के संविधान की पांचवीं और छठी अनुसूचियों के लिए अवधारणा का निर्माण किया।⁵⁰³

1870 के भारत सरकार अधिनियम ने "कठिन" या "पिछड़े" क्षेत्रों के लिए अलग कानून की अनुमति देकर इस विशेष दृष्टिकोण को मजबूत किया। 1874 से, अनुसूचित जिला अधिनियम के तहत सरकार को यह निर्दिष्ट करने की आवश्यकता थी कि इन जिलों में कौन से कानून लागू होंगे। 1919 के भारत सरकार अधिनियम ने इसी तरह के प्रावधान रखे और स्वशासन का केवल एक संकीर्ण रूप जोड़ा। विधायिकाओं द्वारा पारित कानून स्वचालित रूप से आदिवासी क्षेत्रों में तब तक नहीं फैले जब तक कि कार्यपालिका उन्हें लागू करने का विकल्प नहीं चुनती।⁵⁰⁴

भारत सरकार अधिनियम, 1935 के तहत बनाए गए पूर्ववर्ती 'बहिष्कृत क्षेत्र' और 'आंशिक रूप से बहिष्कृत क्षेत्र' संविधान की पांचवीं और छठी अनुसूचियों में 'अनुसूचित क्षेत्रों' में विकसित हुए।⁵⁰⁵ अनुच्छेद 244 में कहा गया है कि पांचवीं अनुसूची अधिकांश राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण को नियंत्रित करती है, जबकि छठी अनुसूची विशेष रूप से असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के अनुसूचित क्षेत्रों पर लागू होती है।⁵⁰⁶ इसके अलावा, संविधान (बाईसवां संशोधन) अधिनियम, 1969 के ज़रिए जोड़े गए अनुच्छेद 244क के तहत संसद को यह अधिकार दिया गया है⁵⁰⁷ कि वह छठी अनुसूची के पैरा 20 की तालिका के भाग 1 में बताए गए सभी या कुछ आदिवासी इलाकों को मिलाकर असम के भीतर एक स्वायत्त राज्य बना सके और ऐसे स्वायत्त राज्य के लिए विधानमंडल या मंत्रिपरिषद का गठन कर सके।⁵⁰⁸

⁵⁰³ Abhay Xaxa and Ganesh N Devy, *Being Adivasi* (Penguin Random House India 2021) 52.

⁵⁰⁴ Id at p. no. 59.

⁵⁰⁵ Nandini Sundar, *The Making of the 5th and 6th Schedule*, Talk delivered at 5th Annual History for Peace Conference, The Idea of the Indian Constitution (Jul. 2019) available at: <https://www.historyforpeace.pw/post/the-making-of-the-5th-and-6th-schedule> (last visited on Sep. 29, 2025).

⁵⁰⁶ The Constitution of India, 1950, art. 244: "Administration of Scheduled Areas and Tribal Areas. — (1) The provisions of the Fifth Schedule shall apply to the administration and control of the Scheduled Areas and Scheduled Tribes in any State other than the States of Assam, Meghalaya, Tripura and Mizoram. (2) The provisions of the Sixth Schedule shall apply to the administration of the tribal areas in the States of Assam, Meghalaya, Tripura and Mizoram."

⁵⁰⁷ The Constitutional (Twenty-Second Amendment) Act, 1969, s. 2.

⁵⁰⁸ The Constitution of India, 1950, art. 244A: "Formation of an autonomous State comprising certain tribal areas in Assam and creation of local Legislature or Council of Ministers or both therefor. — (1) Notwithstanding anything in this Constitution, Parliament may, by law, form within the State of Assam an autonomous State comprising (whether wholly or in part) all or any of the tribal areas specified in Part I of the table appended to paragraph 20 of the Sixth Schedule and create therefor — (a) a body, whether elected or partly nominated and partly elected, to function as a Legislature for the autonomous State, or (b) a Council of Ministers, or both with such constitution, powers and functions, in each case, as may be specified in the law. (2) Any such law as is referred to in clause (1) may, in particular, — (a) specify the matters enumerated in the State List or the Concurrent List with respect to which the Legislature of the autonomous State shall have power to make laws for the whole or any part thereof, whether to the exclusion of the Legislature of the State of Assam or otherwise; (b) define the matters with respect to which the executive power of the autonomous State shall extend; (c) provide that any tax levied by the State of Assam shall be assigned to the autonomous State in so far as the proceeds thereof are attributable to the autonomous State; (d) provide that any reference to a State in any article of this Constitution shall be construed as including a reference to the autonomous State; and (e) make such supplemental, incidental and consequential provisions as may be deemed necessary. (3) An amendment of any such law as aforesaid in so far as such amendment relates to any of the matters specified in sub-clause (a) or sub-clause (b) of clause (2) shall have no effect unless the amendment is passed in each House of

पांचवीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों वाले प्रत्येक राज्य में जनजातीय सलाहकार परिषदों की स्थापना का प्रावधान है।⁵⁰⁹ ऐसे राज्यों के राज्यपाल के पास अनुसूचित क्षेत्रों के संबंध में राष्ट्रपति को वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने की विशेष संवैधानिक जिम्मेदारी है।⁵¹⁰ राष्ट्रपति के पास आदेशों के माध्यम से अनुसूचित क्षेत्रों की घोषणा, परिवर्तन या पुनर्परिभाषित करने और उनके प्रशासन के लिए आवश्यक आकस्मिक प्रावधान करने की भी शक्ति है।⁵¹¹ इसके विपरीत, छठी अनुसूची स्वायत्त जिला और क्षेत्रीय परिषदों की एक प्रणाली स्थापित करती है, जो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि, वन प्रबंधन, विरासत, सामाजिक रीति-रिवाजों और स्थानीय शासन से संबंधित मामलों में विधायी, न्यायिक और कार्यकारी शक्तियों के साथ निहित हैं।⁵¹²

Parliament by not less than two-thirds of the members present and voting. (4) Any such law as is referred to in this article shall not be deemed to be an amendment of this Constitution for the purposes of article 358 notwithstanding that it contains any provision which amends or has the effect of amending this Constitution.”

⁵⁰⁹The Constitution of India, sch. V, part B: “4. Tribes Advisory Council. —(1) There shall be established in each State having Scheduled Areas therein and, if the President so directs, also in any State having Scheduled Tribes but not Scheduled Areas therein, a Tribes Advisory Council consisting of not more than twenty members of whom, as nearly as may be, three-fourths shall be the representatives of the Scheduled Tribes in the Legislative Assembly of the State: Provided that if the number of representatives of the Scheduled Tribes in the Legislative Assembly of the State is less than the number of seats in the Tribes Advisory Council to be filled by such representatives, the remaining seats shall be filled by other members of those tribes. (2) It shall be the duty of the Tribes Advisory Council to advise on such matters pertaining to the welfare and advancement of the Scheduled Tribes in the State as may be referred to them by the Governor. (3) The Governor may make rules prescribing or regulating, as the case may be, — (a) the number of members of the Council, the mode of their appointment and the appointment of the Chairman of the Council and of the officers and servants thereof; (b) the conduct of its meetings and its procedure in general; and (c) all other incidental matters.”

⁵¹⁰The Constitution of India, sch. V, part A: “3. Report by the Governor to the President regarding the administration of Scheduled Areas. —The Governor of each State having Scheduled Areas therein shall annually, or whenever so required by the President, make a report to the President regarding the administration of the Scheduled Areas in that State and the executive power of the Union shall extend to the giving of directions to the State as to the administration of the said areas.”

⁵¹¹The Constitution of India, sch. V, part C: “5. Scheduled Areas. —(1) In this Constitution, the expression “Scheduled Areas” means such areas as the President may by order declare to be Scheduled Areas. (2) The President may at any time by order —(a) direct that the whole or any specified part of a Scheduled Area shall cease to be a Scheduled Area or a part of such an area; (aa) increase the area of any Scheduled Area in a State after consultation with the Governor of that State; (b) alter, but only by way of rectification of boundaries, any Scheduled Area; (c) on any alteration of the boundaries of a State or on the admission into the Union or the establishment of a new State, declare any territory not previously included in any State to be, or to form part of, a Scheduled Area; (d) rescind, in relation to any State or States, any order or orders made under this paragraph, and in consultation with the Governor of the State concerned, make fresh orders redefining the areas which are to be Scheduled Areas; and any such order may contain such incidental and consequential provisions as appear to the President to be necessary and proper, but save as aforesaid, the order made under sub-paragraph (1) of this paragraph shall not be varied by any subsequent order.”

⁵¹²The Constitution of India, sch. VI, part D: “3. Powers of the District Councils and Regional Councils to make laws. —(1) The Regional Council for an autonomous region in respect of all areas within such region and the District Council for an autonomous district in respect of all areas within the district except those which are under the authority of Regional Councils, if any, within the district shall have power to make laws with respect to —(a) the allotment, occupation or use, or the setting apart, of land, other than any land which is a reserved forest for the purposes of agriculture or grazing or for residential or other non-agricultural purposes or for any other purpose likely to promote the interests of the inhabitants of any village or town: Provided that nothing in such law shall prevent the compulsory acquisition of any land, whether occupied or

सर्वोच्च न्यायालय ने लिंगप्पा पोचन्ना एप्पेलवार बनाम महाराष्ट्र राज्य,⁵¹³ के मामले में तीन न्यायाधीशों की पीठ के माध्यम से कहा कि "संविधान की योजना के तहत, अनुसूचित जनजातियों को एक वर्ग के रूप में शोषण के खिलाफ विशेष सुरक्षा की आवश्यकता है", ⁵¹⁴ यह देखते हुए कि अनुसूचित जनजातियां, जिनकी संस्कृति और जीवन शैली कृषि पर आधारित है और भूमि के स्वामित्व से अटूट रूप से जुड़ी हुई है, को "उनकी भूमि पर आक्रमण" की रोकथाम की आवश्यकता है। ⁵¹⁵ उच्चतम न्यायालय ने राय दी कि अनुच्छेद 244 और 244-ए, जो पांचवीं और छठी अनुसूचियों के माध्यम से अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष प्रावधान करते हैं, "राज्य के सभी अंगों के लिए आवश्यक विशेष देखभाल और कर्तव्य पर जोर देते हैं ताकि आदिवासियों के अस्तित्व, अखंडता और गरिमा के संरक्षण और संरक्षण के लिए सकारात्मक और कठोर उपाय किए जा सकें।" ⁵¹⁶

अनुच्छेद 339 केंद्र सरकार को अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन करने और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण को सुरक्षित करने का अधिकार देता है। ⁵¹⁷ इस उद्देश्य के लिए, राष्ट्रपति को राज्यों में ऐसे मामलों पर रिपोर्ट करने के लिए एक आयोग नियुक्त करने का आदेश दिया गया है, और वह इसकी संरचना, शक्तियों और प्रक्रियाओं को परिभाषित करने के लिए अधिकृत है। ⁵¹⁸ इसके अलावा, अनुच्छेद 339 अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए आवश्यक मानी जाने वाली योजनाओं के निर्माण और कार्यान्वयन के संबंध में राज्य सरकारों को निर्देश जारी करने के लिए केंद्र सरकार की कार्यकारी शक्ति का विस्तार करता है। ⁵¹⁹

एस.आर.बोम्मई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, ⁵²⁰ के मामले में ऐतिहासिक निर्णय में उच्चतम न्यायालय की नौ-न्यायाधीशों की पीठ

unoccupied, for public purposes by the Government of the State concerned in accordance with the law for the time being in force authorising such acquisition; (b) the management of any forest not being a reserved forest; (c) the use of any canal or water-course for the purpose of agriculture; (d) the regulation of the practice of jhum or other forms of shifting cultivation;

(e) the establishment of village or town committees or councils and their powers; (f) any other matter relating to village or town administration, including village or town police and public health and sanitation; (g) the appointment or succession of Chiefs or Headmen; (h) the inheritance of property; (i) marriage and divorce; (j) social customs. (2) In this paragraph, a "reserved forest" means any area which is reserved forest under the Assam Forest Regulation, 1891, or under any other law for the time being in force in the area in question. (3) All laws made under this paragraph shall be submitted forthwith to the Governor and, until assented to by him, shall have no effect."

⁵¹³ *Lingappa Pochanna Appellwar v. State of Maharashtra* (1985) 1 SCC 479.

⁵¹⁴ *Id.* at para. 14.

⁵¹⁵ *Ibid.*

⁵¹⁶ *Ibid.*

⁵¹⁷ The Constitution of India, 1950, art. 339: "Control of the Union over the administration of Scheduled Areas and the welfare of Scheduled Tribes."

⁵¹⁸ The Constitution of India, 1950, art. 339: "Control of the Union over the administration of Scheduled Areas and the welfare of Scheduled Tribes. — (1) The President may at any time and shall, at the expiration of ten years from the commencement of this Constitution by order appoint a Commission to report on the administration of the Scheduled Areas and the welfare of the Scheduled Tribes in the States. The order may define the composition, powers and procedure of the Commission and may contain such incidental or ancillary provisions as the President may consider necessary or desirable."

⁵¹⁹ The Constitution of India, 1950, art. 339: "Control of the Union over the administration of Scheduled Areas and the welfare of Scheduled Tribes. — (2) The executive power of the Union shall extend to the giving of directions to a State as to the drawing up and execution of schemes specified in the direction to be essential for the welfare of the Scheduled Tribes in the State."

⁵²⁰ *S.R. Bommai v. Union of India* (1994) 3 SCC 1.

ने उन उदाहरणों के संबंध में, जिनमें राष्ट्रपति को यह संतुष्ट करने की आवश्यकता है कि किसी राज्य का शासन संविधान के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है, संकेत दिया कि उदाहरण के लिए, यदि कोई राज्य अनुच्छेद 339 (2) के तहत केंद्र सरकार द्वारा जारी निर्देशों का पालन करने में विफल रहता है, तो "यह निर्देशात्मक सिद्धांतों में परिकल्पित आदिवासियों को सामाजिक-आर्थिक न्याय प्राप्त करने के संवैधानिक उद्देश्य को बढ़ाने में संवैधानिक तंत्र की विफलता होगी।⁵²¹

3. संवैधानिक सुरक्षा उपाय

3.1. समानता और गैर-भेदभाव

संविधान, अपने मौलिक अधिकारों के ढांचे के माध्यम से, सभी को समानता की गारंटी देता है और भेदभाव को प्रतिबंधित करता है, साथ ही साथ अनुसूचित जनजातियों सहित ऐतिहासिक रूप से वंचित समूहों के पक्ष में सुरक्षात्मक उपायों का प्रावधान करता है। न्यायपालिका इन सुरक्षा उपायों की व्याख्या करने और उन्हें लागू करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अनुसूचित जनजातियों को पर्याप्त समानता प्राप्त हो।

3.1.1. संवैधानिक आधार

अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता और कानून के समान संरक्षण के अधिकार को सुनिश्चित करता है।⁵²² अनुच्छेद 15 किसी भी नागरिक के खिलाफ केवल धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित करता है,⁵²³ विशेष रूप से, दुकानों, सार्वजनिक रेस्तरां, होटलों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों तक उनकी पहुंच के संबंध में, और कुओं, तालाबों, स्नान घाटों, सड़कों और सार्वजनिक रिसॉर्ट्स का उपयोग पूरी तरह से या आंशिक रूप से राज्य निधि से बाहर रखा जाता है।⁵²⁴ इसी तरह, अनुच्छेद 16 सार्वजनिक रोजगार में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता सुनिश्चित करता है,⁵²⁵ के साथ-साथ धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान, निवास या उनमें से किसी के आधार पर सार्वजनिक रोजगार में भेदभाव को प्रतिबंधित करता है।⁵²⁶ ऐतिहासिक रूप से कुछ हाशिए पर पड़े समुदायों के साथ किए गए दमनकारी व्यवहार को दूर करने के लिए, अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता की प्रथा को

⁵²¹ *Id.* at para. 221.

⁵²² The Constitution of India, 1950, art. 14: "Equality before law. - The State shall not deny to any person equality before the law or the equal protection of the laws within the territory of India."

⁵²³ The Constitution of India, 1950, art. 15(1): "The State shall not discriminate against any citizen on grounds only of religion, race, caste, sex, place of birth or any of them."

⁵²⁴ The Constitution of India, 1950, art. 15(2): "No citizen shall, on grounds only of religion, race, caste, sex, place of birth or any of them, be subject to any disability, liability, restriction or condition with regard to — (a) access to shops, public restaurants, hotels and places of public entertainment; or (b) the use of wells, tanks, bathing ghats, roads and places of public resort maintained wholly or partly out of State funds or dedicated to the use of the general public."

⁵²⁵ The Constitution of India, 1950, art. 16: "Equality of opportunity in matters of public employment. - (1) There shall be equality of opportunity for all citizens in matters relating to employment or appointment to any office under the State."

⁵²⁶ The Constitution of India, 1950, art. 16: "Equality of opportunity in matters of public employment. - (2) No citizen shall, on grounds only of religion, race, caste, sex, descent, place of birth, residence or any of them, be ineligible for, or discriminated against in respect of, any employment or office under the State."

समाप्त करता है, ⁵²⁷ जबकि अनुच्छेद 23 और 24, क्रमशः मानव, बेगार और जबरन श्रम के अन्य रूपों में तस्करी का निषेध करते हैं, ⁵²⁸ और कारखानों, खानों या अन्य खतरनाक व्यवसायों में चौदह वर्ष से कम आयु के बच्चों के रोजगार को गैरकानूनी बनाता है। ⁵²⁹

अनुच्छेद 39 सभी नागरिकों के लिए आजीविका के पर्याप्त साधन सुनिश्चित करने, समान काम के लिए समान वेतन, धन एकाग्रता की रोकथाम, और श्रमिकों, पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य और शक्ति की सुरक्षा के लिए राज्य की नीति का निर्देश देता है। ⁵³⁰ इसके अलावा, 42वें संशोधन, ⁵³¹ द्वारा प्रस्तुत अनुच्छेद 39ए, राज्य को यह सुनिश्चित करने का निर्देश देता है कि कानूनी प्रणाली का संचालन समान अवसर के आधार पर न्याय को बढ़ावा देता है। यह उचित कानून या योजनाओं द्वारा मुफ्त कानूनी सहायता के प्रावधानों को अनिवार्य करता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी नागरिक आर्थिक या अन्य अक्षमताओं के कारण न्याय प्राप्त करने की क्षमता से वंचित न रहे। ⁵³² इसके अलावा, अनुच्छेद 41 राज्य को बेरोजगारी, वृद्धावस्था, बीमारी और विकलांगता के मामलों में काम करने, ⁵³³ शिक्षा और सार्वजनिक सहायता के अधिकार को सुरक्षित करने के लिए प्रभावी प्रावधान करने के लिए बाध्य करता है। अनुच्छेद 43 राज्य से सभी मजदूरों के लिए जीवन निर्वाह मजदूरी और काम की मानवीय स्थितियों

⁵²⁷The Constitution of India, 1950, art. 17: “Abolition of Untouchability. — “Untouchability” is abolished and its practice in any form is forbidden. The enforcement of any disability arising out of “Untouchability” shall be an offence punishable in accordance with law.”

⁵²⁸The Constitution of India, 1950, art. 23: “Prohibition of traffic in human beings and forced labour. — (1) Traffic in human beings and begar and other similar forms of forced labour are prohibited and any contravention of this provision shall be an offence punishable in accordance with law. (2) Nothing in this article shall prevent the State from imposing compulsory service for public purposes, and in imposing such service the State shall not make any discrimination on grounds only of religion, race, caste or class or any of them.”

⁵²⁹The Constitution of India, 1950, art. 24: “Prohibition of employment of children in factories, etc. — No child below the age of fourteen years shall be employed to work in any factory or mine or engaged in any other hazardous employment.”

⁵³⁰The Constitution of India, 1950, art. 39: “Certain principles of policy to be followed by the State. — The State shall, in particular, direct its policy towards securing — (a) that the citizens, men and women equally, have the right to an adequate means of livelihood; (b) that the ownership and control of the material resources of the community are so distributed as best to subserve the common good; (c) that the operation of the economic system does not result in the concentration of wealth and means of production to the common detriment; (d) that there is equal pay for equal work for both men and women; (e) that the health and strength of workers, men and women, and the tender age of children are not abused and that citizens are not forced by economic necessity to enter avocations unsuited to their age or strength; (f) that children are given opportunities and facilities to develop in a healthy manner and in conditions of freedom and dignity and that childhood and youth are protected against exploitation and against moral and material abandonment.”

⁵³¹The Constitution (Forty-second Amendment) Act, 1976, s. 7.

⁵³²The Constitution of India, 1950, art. 39A: “Equal justice and free legal aid. — The State shall secure that the operation of the legal system promotes justice, on a basis of equal opportunity, and shall, in particular, provide free legal aid, by suitable legislation or schemes or in any other way, to ensure that opportunities for securing justice are not denied to any citizen by reason of economic or other disabilities.”

⁵³³The Constitution of India, 1950, art. 41: “Right to work, to education and to public assistance in certain cases. — The State shall, within the limits of its economic capacity and development, make effective provision for securing the right to work, to education and to public assistance in cases of unemployment, old age, sickness and disablement, and in other cases of undeserved want.”

को सुरक्षित करने और ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत या सहकारी आधार पर कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने का आह्वान करता है।

534

3.1.2. न्यायिक व्याख्याएँ

ऊपर बताई गई संवैधानिक गारंटियाँ, भले ही खास तौर पर अनुसूचित जनजातियों की सुरक्षा नहीं करतीं, लेकिन अदालतों ने इनकी ऐसी व्याख्या की है जिससे यह पक्का हो सके कि ये अधिकार सिर्फ दिखावे की चीज़ बनकर न रह जाएं, बल्कि दूसरे हाथिए पर पड़े समूहों के साथ-साथ अनुसूचित जनजातियों के फ़ायदे के लिए भी पूरी तरह से लागू हों। सुप्रीम कोर्ट ने 'केरल राज्य बनाम एन.एम. थॉमस'⁵³⁵ मामले में सात जजों की बेंच के अपने अहम फ़ैसले में अनुच्छेद 14, 15 और 16 के दायरे के बारे में कहा कि संविधान सभी नागरिकों के लिए - जिनमें सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े लोग भी शामिल हैं - दर्जे और मौक़े की समानता की कल्पना करता है।⁵³⁶ जस्टिस ए.एन. रे ने अपनी अलग राय में कहा: "[अगर] अनुसूचित...[जन]जातियों के सदस्य - जिन्हें इस कोर्ट ने पिछड़ा वर्ग माना है - प्रशासनिक दक्षता की कम से कम ज़रूरी शर्त को पूरा कर सकते हैं, तो समानता लागू करने और असमानता को ख़त्म करने के लिए उन्हें न सिर्फ़ प्रतिनिधित्व बल्कि प्राथमिकता भी दी जा सकती है.....प्रशासनिक दक्षता का पूरा ध्यान रखते हुए पिछड़ा वर्ग के सदस्यों को प्राथमिकता देने का मतलब ही सभी नागरिकों के लिए मौक़े की समानता हो सकता है"⁵³⁷

इसके अलावा, उच्चतम न्यायालय ने *कर्नाटक राज्य बनाम अप्पा बालू इंगले*,⁵³⁸ के मामले में अपने दो-न्यायाधीशों की पीठ के फ़ैसले में अनुच्छेद 17 का हवाला देते हुए पुष्टि की: "न्यायाधीशों को समाज को मजबूत करने और दलितों और जनजातियों को सार्वजनिक साधनों या सार्वजनिक उपयोग के लिए समर्पित स्थानों या जनता के लिए खुली सुविधाओं के स्थानों आदि तक पहुंच प्रदान करने के लिए कानून की प्रगति को आकार देने के कर्तव्य के लिए बुलाया जाता है। न्यायिक समीक्षा द्वारा, चौड़े के संवैधानिक शब्दों में गौरवशाली सामग्री और तुच्छ बोध को मुखर और श्रव्य बनाया जाना चाहिए, जिससे उन्हें जीवन, अभिव्यक्ति और बल की निरंतरता मिल सके, जब उन्हें अन्यथा भुला दिया जा सकता है या अनदेखा किया जा सकता है।"⁵³⁹ सर्वोच्च न्यायालय ने आगे कहा: "इसलिए, न्यायाधीशों को समय और समाज की ज़रूरतों को समझते हुए मानवीय स्थितियों पर ध्यान देना चाहिए; जीने के अधिकार को सार्थक बनाना चाहिए और संविधान व विधायिका की इच्छा को लागू करना चाहिए... ताकि छुआछूत को ख़त्म किया जा सके; दलितों और आदिवासी समुदायों को समानता का अधिकार दिया जा सके; सामाजिक एकता को हकीकत का रूप दिया जा सके और भाईचारे को असलियत बनाया जा सके।"⁵⁴⁰

ऐतिहासिक भेदभाव को स्वीकार करते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने *नंदिनी सुंदर बनाम छत्तीसगढ़*

⁵³⁴The Constitution of India, 1950, art. 43: "Living wage, etc., for workers.—The State shall endeavour to secure, by suitable legislation or economic organisation or in any other way, to all workers, agricultural, industrial or otherwise, work, a living wage, conditions of work ensuring a decent standard of life and full enjoyment of leisure and social and cultural opportunities and, in particular, the State shall endeavour to promote cottage industries on an individual or co-operative basis in rural areas."

⁵³⁵State of Kerala v. N.M. Thomas (1976) 2 SCC 310.

⁵³⁶Id. at para. 44.

⁵³⁷Ibid.

⁵³⁸State of Karnataka v. Appa Balu Ingale, 1995 Supp (4) SCC 469.

⁵³⁹Id. at para. 34.

⁵⁴⁰Id. at para. 35.

राज्य,⁵⁴¹ में आदिवासी युवाओं को उग्रवाद विरोधी अभियानों में सहायता के लिए विशेष पुलिस अधिकारियों के रूप में भर्ती करने की नीति के संबंध में, सर्वोच्च न्यायालय ने पाया कि इस तरह के रोजगार की शोषणकारी प्रकृति अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन करती है क्योंकि यह "...इससे ऐसे युवा भी उतने ही खतरों का सामना करते हैं जितने नियमित बल के सदस्य करते हैं..." और "...अपनी कम शिक्षा के कारण, वे ऐसे सही ढंग से तैयार किए गए ट्रेनिंग प्रोग्राम का फ़ायदा भी नहीं उठा पाएंगे जो उनके काम, ज़िम्मेदारियों, अनुशासन के नियमों और उनकी जान व सेहत को होने वाले खतरों के हिसाब से हो..."⁵⁴² सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि उनकी नियुक्तियों की अस्थायी और अनिश्चित प्रकृति, सेवा के बाद सुरक्षा की कमी के साथ, एक अमानवीय रवैये का खुलासा करती है, जो ऐसे युवाओं के जीवन को बहुत कम या कोई महत्व नहीं देता है।⁵⁴³

3.2. शिक्षा और सार्वजनिक रोजगार में आरक्षण

शिक्षा और सार्वजनिक रोजगार में आरक्षण मुख्य तंत्र हैं जिनके माध्यम से संविधान शैक्षणिक संस्थानों और सार्वजनिक सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करके अनुसूचित जनजातियों सहित हाशिए पर रहने वाले समूहों के लिए पर्याप्त समानता,⁵⁴⁴ प्राप्त करना चाहता है।

3.2.1. संवैधानिक आधार

प्रथम संशोधन,⁵⁴⁵ द्वारा अंतःस्थापित अनुच्छेद 15 (4) के साथ-साथ नब्बेवें संशोधन⁵⁴⁶ के माध्यम से प्रस्तुत अनुच्छेद 15 (5) अनुसूचित जनजातियों की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान बनाने को अधिकृत करता है, जिसमें सार्वजनिक और निजी शैक्षणिक संस्थानों में उनके प्रवेश के लिए सीटें आरक्षित करना शामिल है, चाहे वे सरकारी धन से सहायता प्राप्त हों या गैर-सहायता प्राप्त हों।⁵⁴⁷ अनुच्छेद 16 (4) "नागरिकों के किसी भी पिछड़े वर्ग के पक्ष में सार्वजनिक सेवा में पदों पर नियुक्तियों में आरक्षण की अनुमति देता है, जो राज्य की राय में, राज्य के तहत सेवाओं में पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व नहीं करता है"।⁵⁴⁸ सत्ततरवें

⁵⁴¹Nandini Sundar v. State of Chhattisgarh (2011) 7 SCC 547.

⁵⁴²Id. at paras. 74-75.

⁵⁴³Id. at paras. 78-80.

⁵⁴⁴Food Corporation of India v. Jagdish Balaram Bahira (2017) 8 SCC 670, para. 56.

⁵⁴⁵The Constitution (First Amendment) Act, 1951, s. 2.

⁵⁴⁶The Constitution (Ninety-third Amendment) Act, 2005, s. 2.

⁵⁴⁷The Constitution of India, 1950, art. 15(4): "Nothing in this article or in clause (2) of article 29 shall prevent the State from making any special provision for the advancement of any socially and educationally backward classes of citizens or for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes."

15(5): "Nothing in this article or in sub-clause (g) of clause (1) of article 19 shall prevent the State from making any special provision, by law, for the advancement of any socially and educationally backward classes of citizens or for the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes insofar as such special provisions relate to their admission to educational institutions including private educational institutions, whether aided or unaided by the State, other than the minority educational institutions referred to in clause (1) of article 30."

⁵⁴⁸The Constitution of India, 1950, art. 16: "Equality of opportunity in matters of public employment. - (4) Nothing in this article shall prevent the State from making any provision for the reservation of appointments or posts in favour of any backward class of citizens which, in the opinion of the State, is not adequately represented in the services under the State."

संशोधन, ⁵⁴⁹ द्वारा प्रस्तुत अनुच्छेद 16 (4ए) ने अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में आरक्षण को सार्वजनिक सेवाओं में "किसी भी वर्ग या पदों के वर्गों के लिए, परिणामी वरिष्ठता के साथ, पदोन्नति के मामलों" तक बढ़ा दिया, यदि उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। ⁵⁵⁰ एक्यासीवां संशोधन, ⁵⁵¹ द्वारा अंतःस्थापित अनुच्छेद 16 (4बी) स्पष्ट करता है कि यदि किसी दिए गए वर्ष में आरक्षित रिक्तियां खाली रहती हैं, तो उन्हें आगे बढ़ाया जा सकता है और बाद के वर्षों में भरा जा सकता है; इन रिक्तियों को एक अलग श्रेणी के रूप में माना जाता है और वर्ष में कुल आरक्षण की पचास प्रतिशत सीमा की ओर नहीं गिना जाता है। ⁵⁵² हालांकि यह मौलिक अधिकार नहीं है, अनुच्छेद 335 में कहा गया है कि अनुसूचित जनजातियों के दावों को केंद्र या राज्य सरकार की सेवाओं में नियुक्तियों में ध्यान में रखा जाएगा, बशर्ते कि वे प्रशासन की दक्षता के रखरखाव के साथ असंगत न हों। ⁵⁵³ अस्सीवें संशोधन के माध्यम से, अनुच्छेद 335, ⁵⁵⁴ में एक परंतुक जोड़ा गया था जो अनुसूचित जनजातियों के लिए पदोन्नति के मामलों में योग्यता अंकों और मूल्यांकन के मानकों में छूट की अनुमति देता है। ⁵⁵⁵

साथ में, पूर्वगामी प्रावधान संविधान के दोहरे दृष्टिकोण को दर्शाते हैं, जो औपचारिक समानता को एक सार्वभौमिक अधिकार के रूप में स्थापित करते हैं, साथ ही साथ अनुसूचित जनजातियों के लिए सामाजिक न्याय के एक आवश्यक उपकरण के रूप में सकारात्मक कार्रवाई के माध्यम से पर्याप्त समानता को आगे बढ़ाते हैं। राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत भी इस दृष्टि को सुदृढ़ करते हैं। अनुच्छेद 38 राज्य से न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक आधार पर सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित करके लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने और आय, स्थिति और अवसरों में असमानताओं

⁵⁴⁹The Constitution (Seventy-seventh Amendment) Act, 1995, s. 2, and amended by The Constitution (Eighty-fifth Amendment) Act, 2001, s. 2 to grant consequential seniority in promotions.

⁵⁵⁰The Constitution of India, 1950, art. 16. "Equality of opportunity in matters of public employment.-(4A) Nothing in this article shall prevent the State from making any provision for reservation in matters of promotion, with consequential seniority, to any class or classes of posts in the services under the State in favour of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes which, in the opinion of the State, are not adequately represented in the services under the State."

⁵⁵¹Constitution (Eighty-first Amendment) Act, 2000, s. 2.

⁵⁵²The Constitution of India, 1950, art. 16. "Equality of opportunity in matters of public employment.-(4B) Nothing in this article shall prevent the State from considering any unfilled vacancies of a year which are reserved for being filled up in that year in accordance with any provision for reservation made under clause (4) or clause (4A) as a separate class of vacancies to be filled up in any succeeding year or years and such class of vacancies shall not be considered together with the vacancies of the year in which they are being filled up for determining the ceiling of fifty per cent. reservation on total number of vacancies of that year."

⁵⁵³The Constitution of India, 1950, art. 335: "Claims of Scheduled Castes and Scheduled Tribes to services and posts. — The claims of the members of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes shall be taken into consideration, consistently with the maintenance of efficiency of administration, in the making of appointments to services and posts in connection with the affairs of the Union or of a State: Provided that nothing in this article shall prevent in making of any provision in favour of the members of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes for relaxation in qualifying marks in any examination or lowering the standards of evaluation, for reservation in matters or promotion to any class or classes of services or posts in connection with the affairs of the Union or of a State."

⁵⁵⁴The Constitution (Eighty-second Amendment) Act, 2000, s. 2.

⁵⁵⁵The Constitution of India, 1950, art. 16: "Provided that nothing in this article shall prevent in making of any provision in favour of the members of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes for relaxation in qualifying marks in any examination or lowering the standards of evaluation, for reservation in matters of promotion to any class or classes of services or posts in connection with the affairs of the Union or of a State."

को कम करने की अपेक्षा करता है।⁵⁵⁶ अनुच्छेद 46 राज्य को अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने का निर्देश देता है।⁵⁵⁷

3.2.2. न्यायिक व्याख्याएँ

संविधान के तहत सकारात्मक कार्रवाई के दायरे को परिभाषित करने के लिए न्यायिक व्याख्या केंद्रीय रही है। उच्चतम न्यायालय की सात न्यायाधीशों की पीठ ने इस बात की जांच की कि क्या केरल राज्य और अधीनस्थ नियम, 1988, केरल राज्य बनाम एन.एम.थॉमस के मामले में संविधान के अनुरूप हैं।⁵⁵⁸ उच्चतम न्यायालय ने कहा कि पिछड़े वर्गों के पक्ष में आरक्षण और छूट समानता के लिए अपवाद नहीं हैं, बल्कि अनुच्छेद 14 के तहत इसके अर्थ के लिए आंतरिक हैं। न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर ने इस फैसले में, व्यापक संवैधानिक दृष्टि के भीतर आरक्षण को शामिल करते हुए, प्रसिद्ध रूप से टिप्पणी की कि⁵⁵⁹ "समान अवसर एक आशा है, न कि एक खतरा"।

इस दृष्टिकोण को इंद्र साहनी बनाम भारत संघ के ऐतिहासिक निर्णय में स्पष्ट किया गया था।⁵⁶⁰ यह मामला, जिसे मंडल आयोग मामले के रूप में भी जाना जाता है, केंद्र सरकार द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन की वैधता से संबंधित है, जिसमें दूसरी पिछड़ा वर्ग समिति की सिफारिशों के अनुसरण में सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए 27 प्रतिशत रिक्तियों को सीधी भर्ती द्वारा भरा जाना है। नौ न्यायाधीशों की पीठ ने अपने फैसले में अनुच्छेद 16 (4) के तहत अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण को बरकरार रखा। हालांकि, अदालत ने तीन महत्वपूर्ण सीमाएं पेश कीं: (i) यह सिद्धांत कि कुल आरक्षण सामान्य रूप से 50 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकता है, (ii) आरक्षण लाभों का लाभ उठाने से 'क्रीमी लेयर' का बहिष्कार, और (iii) मौजूदा पदोन्नति-आधारित आरक्षण के साथ पदोन्नति में आरक्षण पर रोक पांच वर्षों के लिए जारी रहेगी।⁵⁶¹

इसके जवाब में, संसद ने संविधान में अनुच्छेद 16 (4ए) और (4बी) को क्रमशः 77वें और 80वें संशोधनों के माध्यम से पेश किया।⁵⁶² इन संशोधनों की जांच

⁵⁵⁶The Constitution of India, 1950, art. 38: "State to secure a social order for the promotion of welfare of the people. — (1) The State shall strive to promote the welfare of the people by securing and protecting as effectively as it may a social order in which justice, social, economic and political, shall inform all the institutions of the national life. (2) The State shall, in particular, strive to minimise the inequalities in income, and endeavour to eliminate inequalities in status, facilities and opportunities, not only among individuals but also among groups of people residing in different areas or engaged in different vocations."

⁵⁵⁷The Constitution of India, 1950, art. 46: "Promotion of educational and economic interests of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other weaker sections. — The State shall promote with special care the educational and economic interests of the weaker sections of the people, and, in particular, of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, and shall protect them from social injustice and all forms of exploitation."

⁵⁵⁸State of Kerala v. N.M. Thomas (1976) 2 SCC 310.

⁵⁵⁹Id. at para. 142.

⁵⁶⁰Indra Sawhney v. Union of India, 1992 Supp (3) SCC 217.

⁵⁶¹Id. at para. 860.

⁵⁶²The Constitution (Seventy-seventh Amendment) Act, 1995, s. 2; The Constitution (Eighty-first Amendment) Act, 2000, s. 2; Article 16(4A) was further amended vide The Constitution (Eighty-fifth Amendment) Act, 2002, s. 2.

एम. नागराज बनाम भारत संघ,⁵⁶³ के मामले में सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर के अधिकार की चौड़ाई और विस्तार के आलोक में की गई थी। पाँच-न्यायाधीशों की पीठ ने उनकी वैधता को बरकरार रखा लेकिन संवैधानिक सीमाएँ लगा दीं। न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि पदोन्नति में आरक्षण के लिए प्रावधानों को सक्षम करने की अनुमति है, ऐसे लाभ प्रदान करने से पहले राज्यों को तीन शर्तें स्थापित करनी चाहिए: (i) समूह का पिछड़ेपन, (ii) सेवाओं में प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता, और (iii) अनुच्छेद 335 के तहत प्रशासनिक दक्षता बनाए रखना। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि अनुच्छेद 14, 15 और 16 के तहत समानता संहिता मूल संरचना का हिस्सा है, जिससे अत्यधिक या अनियंत्रित नीति को सीमित किया जा सकता है।⁵⁶⁴

इस स्थिति पर *जरनैल सिंह बनाम लक्ष्मी नारायण गुप्ता*,⁵⁶⁵ में पुनः विचार किया गया था, जहाँ उच्चतम न्यायालय ने इस प्रश्न पर विचार किया कि क्या एम. नागराज के निर्णय को सात-न्यायाधीशों की पीठ को भेजा जाना चाहिए। पाँच न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि पदोन्नति में आरक्षण देने से पहले अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के 'पिछड़ेपन' पर मात्रात्मक आंकड़े एकत्र करने की आवश्यकता अनावश्यक है, क्योंकि इन समूहों को पिछड़ा माना जाता है। हालाँकि, प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता प्रदर्शित करने और प्रशासन में दक्षता बनाए रखने की आवश्यकताएँ लागू होती रहती हैं।⁵⁶⁶

चेब्रोलू लीला प्रसाद राव बनाम आंध्र प्रदेश राज्य मामले में, आंध्र प्रदेश के पुराने राज्य द्वारा जारी उस सरकारी आदेश की वैधता को चुनौती दी गई थी,⁵⁶⁷ जिसमें राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों के स्कूलों में शिक्षकों के पदों के लिए अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को 100 प्रतिशत आरक्षण दिया गया था (जिसमें से 33.33 प्रतिशत पद महिलाओं के लिए थे)। अदालत ने अपनी पाँच न्यायाधीशों की पीठ के माध्यम से 100 प्रतिशत आरक्षण को रद्द करते हुए कहा कि अत्यधिक आरक्षण *इंदिरा साहनी* के फैसले में परिकल्पित 50 प्रतिशत की अधिकतम सीमा के सिद्धांत का उल्लंघन करता है।⁵⁶⁸ हालाँकि, फैसले की आलोचना आदिवासी चिंताओं की अनदेखी करने और ऐसी भाषा का उपयोग करने के लिए की गई है जिसे असंवेदनशील माना गया है।⁵⁶⁹ यह तर्क दिया गया है कि इस तरह की टिप्पणियों के साथ, न्यायालय ने कानून के तत्काल प्रश्न से परे जाकर आरक्षण के मूलभूत तर्क को कम करते हुए कई टिप्पणियाँ कीं। यह भी बताया गया है कि आरक्षण लाभों के वितरण के संबंध में न्यायालय के दावों में अनुभवजन्य आधार की कमी है।⁵⁷⁰

*मैरी चंद्र शेखर राव बनाम डीन*⁵⁷¹ के मामले में, सेठ जी.एस. मेडिकल कॉलेज, न्यायालय ने इस प्रश्न को संबोधित किया कि क्या एक राज्य में अनुसूचित जनजाति से संबंधित व्यक्ति दूसरे राज्य में प्रवास करने के बाद

⁵⁶³ *M. Nagaraj v. Union of India* (2006) 8 SCC 212.

⁵⁶⁴ *Id.* at para. 121.

⁵⁶⁵ *Jarnail Singh v. Lachmi Narain Gupta* (2018) 10 SCC 396.

⁵⁶⁶ *Id.* at paras. 31-35.

⁵⁶⁷ *Chebrolu Leela Prasad Rao v. State of Andhra Pradesh* (2020) SCC OnLine SC 383.

⁵⁶⁸ *Id.* at 168.

⁵⁶⁹ Anurag Bhaskar, "When It Comes to Dalit and Tribal Rights, the Judiciary in India Just Does Not Get It" *The Wire*, May 3, 2020.

⁵⁷⁰ *Id.*

⁵⁷¹ *Marri Chandra Shekhar Rao v. Dean, Seth G. S. Medical College* (1990) 3 SCC 130.

उसी स्थिति का दावा कर सकता है। यह अभिनिर्धारित किया गया था कि आरक्षण का लाभ स्वचालित रूप से सभी राज्यों में नहीं बढ़ाया जा सकता है। “समाज के कमज़ोर वर्गों की स्थिति सुधारने के लिए आरक्षण ज़रूर लागू किया जाना चाहिए, लेकिन ऐसा करते समय इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि समुदाय के दूसरे वर्गों की जायज़ उम्मीदों को नज़र अंदाज़ न किया जाए।”⁵⁷²

इस पर भरोसा करते हुए, *महाराष्ट्र राज्य बनाम भारत संघ*,⁵⁷³ में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को जाति प्रमाणपत्र जारी करने संबंधी कार्यवाही समिति के मामले में पांच न्यायाधीशों की पीठ ने इस मुद्दे पर विचार किया कि क्या एक राज्य में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित कोई व्यक्ति जो दूसरे राज्य में प्रवास करता है, जहां एक ही नाम के साथ एक जाति या जनजाति को अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, बाद वाले राज्य में उपलब्ध समान लाभों का दावा करने का हकदार होगा। यह देखा गया कि किसी दिए गए राज्य में अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल करने के लिए किसी विशेष जाति या जनजाति को निर्दिष्ट करना “उस राज्य में उस जाति, जनजाति या वर्ग को होने वाले नुकसान और सामाजिक कठिनाइयों की प्रकृति और सीमा पर निर्भर करेगा जो किसी अन्य राज्य में पूरी तरह से गैर-निहित हो सकता है जिसमें उससे संबंधित व्यक्ति प्रवास कर सकते हैं।”⁵⁷⁴ इस प्रकार, यह अभिनिर्धारित किया गया कि केवल इसलिए कि एक जाति/जनजाति को एक राज्य में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, इसका आवश्यक रूप से यह अर्थ नहीं है कि यदि दूसरे राज्य में समान नामकरण वाली दूसरी जाति है, तो पूर्व से संबंधित व्यक्ति बाद वाले राज्य की अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य के लिए स्वीकार्य अधिकारों और लाभों का हकदार होगा।⁵⁷⁵

इसके आधार पर, *अंजन कुमार बनाम भारत संघ*,⁵⁷⁶ के मामले में न्यायालय ने इस प्रश्न पर विचार किया था कि क्या आदिवासी महिला और गैर-आदिवासी पुरुष के बीच विवाह की एक शाखा अनुसूचित जनजाति के दर्जे का दावा कर सकती है और अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकती है। दो-न्यायाधीशों की पीठ ने दोहराया कि एक जाति या जनजाति प्रमाण पत्र “वितरित करने के लिए इनाम” नहीं है; इसके बजाय, इस तरह के दावे को बनाए रखने के लिए, यह दिखाना होगा कि उन्हें “सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से विकलांगता का सामना करना पड़ा।” दो-न्यायाधीशों की पीठ ने दोहराया कि जाति या जनजाति प्रमाण पत्र “वितरित किया जाने वाला इनाम” नहीं है; इसके बजाय, ऐसे दावे को कायम रखने के लिए, किसी को यह करना होगा दिखाएँ कि वे “सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से विकलांगता से पीड़ित थे।” यह अभिनिर्धारित किया गया था कि जिन लोगों को इस तरह के नुकसान नहीं होते हैं, वे अनुसूचित जनजाति के दर्जे का दावा नहीं कर सकते हैं और झूठे प्रमाणपत्र जारी करना या प्राप्त करना अनुच्छेद 14 और 21.577 के तहत समानता के जनादेश को कम करता है⁵⁷⁷

हाल ही में, *भारतीय खाद्य निगम बनाम जगदीश बलराम बहिड़ा*,⁵⁷⁸ के मामले में सर्वोच्च न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने उन व्यक्तियों से जुड़े मामलों के एक समूह पर विचार किया, जिन्होंने एक लाभार्थी समूह से संबंधित होने के दावे के आधार पर सार्वजनिक रोजगार की मांग की थी, जो जांच पर अमान्य पाया गया था। न्यायालय ने उदाहरणों के एक बड़े समूह का पता लगाया। इसमें *कुमारी*

⁵⁷² Id. at para. 20.

⁵⁷³ Action Committee on Issue of Caste Certificate to SCs and STs in the State of Maharashtra v. Union of India (1994) 5 SCC 244.

⁵⁷⁴ Id. at para. 16.

⁵⁷⁵ Ibid.

⁵⁷⁶ Anjan Kumar v. Union of India (2006) 3 SCC 257.

⁵⁷⁷ Id. at paras. 14-15.

⁵⁷⁸ Food Corporation of India v. Jagdish Balaram Bahira (2017) 8 SCC 670.

माधुरी पाटिल बनाम अतिरिक्त आयुक्त, जनजातीय विकास,⁵⁷⁹ जैसे मामले शामिल थे, जिसमें न्यायालय ने आरक्षण के लिए निर्दिष्ट अनुसूचित जाति या जनजाति के उम्मीदवारों के दावों की जांच के लिए दिशा-निर्देश तैयार किए थे। इसमें शामिल थे: (क) जाति प्रमाण पत्र जारी करना; (ख) राज्य सरकार द्वारा गठित की जाने वाली जांच समितियों द्वारा जाति और जनजाति के दावों की जांच और सत्यापन; (ग) दावे की प्रामाणिकता की जांच करने की प्रक्रिया; (घ) जाति प्रमाण पत्र को रद्द करना और जप्त करना जहां दावा गलत या वास्तविक नहीं पाया गया है; (ङ) नियुक्ति की समाप्ति, किसी शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश रद्द करने या उम्मीदवार के आरक्षित श्रेणी से संबंधित होने के आधार पर प्राप्त निर्वाचन कार्यालय से अयोग्यता के संदर्भ में लाभों को वापस लेना; और (च) आपराधिक अपराध के लिए अभियोजन।⁵⁸⁰ इन दिशा-निर्देशों ने 2001 के महाराष्ट्र अधिनियम XXIII के संहिताकरण के लिए व्यापक सिद्धांतों के रूप में कार्य किया, जिसे आगे चुनौती दी गई। पीठ ने *महाराष्ट्र राज्य बनाम मिलिंद*,⁵⁸¹ के फैसले पर भी चर्चा की, जिसमें न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 341 और 342 के तहत जारी राष्ट्रपति के आदेशों के लाभों को एक धोखेबाज द्वारा हड़पने की अनुमति देना आरक्षण के उद्देश्य को नकार देगा।

अंत में, पीठ ने यह कहते हुए कि "जाति के दावे के आधार पर मिले फायदों को वापस लेना, उस दावे के गलत पाए जाने और अमान्य घोषित होने का एक ज़रूरी नतीजा है, इसलिए इसमें पूर्वव्यापीता का कोई मुद्दा उत्पन्न नहीं होगा"।⁵⁸² न्यायालय ने किसी कल्याणकारी उपाय के लाभों से वास्तविक लाभार्थी को वंचित करने के खतरों को रेखांकित करते हुए कहा: "जब कोई व्यक्ति जो किसी जाति, जनजाति या वर्ग से संबंधित नहीं है, जिसके लिए आरक्षण अभिप्रेत है, उसके सदस्य के रूप में पारित करना चाहता है, तो ऐसी रणनीति संविधान के साथ धोखाधड़ी का गठन करती है।"⁵⁸³ इस प्रकार, *कुमारी माधुरी पाटिल बनाम अतिरिक्त आयुक्त, जनजातीय विकास*⁵⁸⁴ और 2001 के महाराष्ट्र अधिनियम XXIII के निर्णय में दिशानिर्देशों को इस क्षेत्र को धारण करने के लिए अभिनिर्धारित किया गया था।

इस प्रकार, समानता का भारतीय मॉडल एक संवैधानिक दर्शन को दर्शाता है जो लक्षित सकारात्मक उपायों के साथ सार्वभौमिक अधिकारों को जोड़ता है और जातियों और जनजातियों की अंतर्निहित असमानताओं को पहचानता है। हालांकि, साथ ही, यह सुनिश्चित करता है कि इन प्रावधानों का दुरुपयोग या दुरुपयोग न हो। इस प्रकार, ये आरक्षण और सुरक्षात्मक भेदभाव अपवाद नहीं हैं, बल्कि सभी के लिए ठोस न्याय के लक्ष्य को प्राप्त करने के साधन हैं।

3.3 राजनीतिक प्रतिनिधित्व और स्वशासन

भारत का संविधान अनुसूचित जनजातियों के लिए राजनीतिक प्रतिनिधित्व और स्व-शासन

⁵⁷⁹ *Kumari Madhuri Patil v. Additional Commissioner, Tribal Development* (1994) 6 SCC 241.

⁵⁸⁰ *Food Corporation of India v. Jagdish Balam Bahira* (2017) 8 SCC 670, para. 69.2

⁵⁸¹ *State of Maharashtra v. Milind* (2001) 1 SCC 4.

⁵⁸² *Food Corporation of India v. Jagdish Balam Bahira* (2017) 8 SCC 670, para. 69.7.

⁵⁸³ *Id.* at para. 2.

⁵⁸⁴ *Kumari Madhuri Patil v. Additional Commissioner, Tribal Development* (1994) 6 SCC 241.

सुनिश्चित करने के लिए एक विस्तृत रूपरेखा प्रदान करता है, जो उनके ऐतिहासिक हाशिए को पहचानता है और इस प्रकार, संरचनात्मक सुरक्षा उपायों की आवश्यकता है। संविधान के भाग XVI में विशेष रूप से कुछ वर्गों से संबंधित प्रावधान हैं। उदाहरण के लिए, अनुच्छेद 330 से 334 लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण को अनिवार्य करता है।

3.3.1. संवैधानिक आधार

अनुच्छेद 330 विशेष रूप से लोकसभा से संबंधित है, जबकि अनुच्छेद 332 राज्य विधानसभाओं से संबंधित है। अनुच्छेद 330 निर्दिष्ट करता है कि प्रत्येक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में, अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में आरक्षित सीटों की संख्या उस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की कुल आबादी में उनके हिस्से के अनुपात में, उस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को आवंटित कुल सीटों के सापेक्ष होनी चाहिए।⁵⁸⁵ इसी तरह, अनुच्छेद 332 में राज्य की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है, जैसा कि अनुच्छेद के तहत किया गया है। 330.586

⁵⁸⁵The Constitution of India, 1950, art. 330: “Reservation of seats for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the House of the People. —(1) Seats shall be reserved in the House of the People for — (a) the Scheduled Castes; (b) the Scheduled Tribes except the Scheduled Tribes in the autonomous districts of Assam; and (c) the Scheduled Tribes in the autonomous districts of Assam. (2) The number of seats reserved in any State or Union territory for the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes under clause (1) shall bear, as nearly as may be, the same proportion to the total number of seats allotted to that State or Union territory in the House of the People as the population of the Scheduled Castes in the State or Union territory or of the Scheduled Tribes in the State or Union territory or part of the State or Union territory, as the case may be, in respect of which seats are so reserved, bears to the total population of the State or Union territory. (3) Notwithstanding anything contained in clause (2), the number of seats reserved in the House of the People for the Scheduled Tribes in the autonomous districts of Assam shall bear to the total number of seats allotted to that State a proportion not less than the population of the Scheduled Tribes in the said autonomous districts bears to the total population of the State. Explanation.—In this article and in article 332, the expression “population” means the population as ascertained at the last preceding census of which the relevant figures have been published: Provided that the reference in this Explanation to the last preceding census of which the relevant figures have been published shall, until the relevant figures for the first census taken after the year 2025 have been published, be construed as a reference to the 2001 census.”

⁵⁸⁶The Constitution of India, 1950, art. 332: “Reservation of seats for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the Legislative Assemblies of the States. —(1) Seats shall be reserved for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, except the Scheduled Tribes in the autonomous districts of Assam, in the Legislative Assembly of every State. (2) Seats shall be reserved also for the autonomous districts in the Legislative Assembly of the State of Assam. (3) The number of seats reserved for the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes in the Legislative Assembly of any State under clause (1) shall bear, as nearly as may be, the same proportion to the total number of seats in the Assembly as the population of the Scheduled Castes in the State or of the Scheduled Tribes in the State or part of the State, as the case may be, in respect of which seats are so reserved, bears to the total population of the State. (3A) Notwithstanding anything contained in clause (3), until the taking effect, under article 170, of the re-adjustment, on the basis of the first census after the year 2025, of the number of seats in the Legislative Assemblies of the States of Arunachal Pradesh, Meghalaya, Mizoram and Nagaland, the seats which shall be reserved for the Scheduled Tribes in the Legislative Assembly of any such State shall be,—(a) if all these seats in the Legislative Assembly of such State in existence on the date of coming into force of the Constitution (Fifty-seventh Amendment) Act, 1987 (hereafter in this clause referred to as the existing Assembly) are held by members of the Scheduled Tribes, all these seats except one; (b) in any other case, such number of seats as bears to the total number of seats, a proportion not less than the number (as on the said date) of members belonging to the Scheduled Tribes in the existing Assembly bears to the total number of seats in the existing Assembly. (3B) Notwithstanding anything contained in clause (3), until the re-adjustment, under article 170,

इसके अलावा, अनुच्छेद 330ए में लोकसभा में महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण का भी प्रावधान है, जिसमें निर्दिष्ट किया गया है कि अनुच्छेद 330 के तहत आरक्षित सीटों की कुल संख्या का एक तिहाई अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित महिलाओं के लिए आरक्षित होगा।⁵⁸⁷ इसी तरह, अनुच्छेद 332ए राज्य की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण के लिए अनुच्छेद 330ए की तरह ही प्रावधान करता है।⁵⁸⁸ अनुच्छेद 334 इन आरक्षणों पर समय सीमा का भी प्रावधान करता है।⁵⁸⁹ शुरू में, सीमा दस साल के लिए निर्धारित की गई थी।⁵⁹⁰ हालांकि, 45वें, 79वें, 95वें और 104वें सहित क्रमिक संवैधानिक संशोधनों ने समुदायों के सामने निरंतर सामाजिक-आर्थिक नुकसान को स्वीकार करते हुए अवधि को 80 वर्षों तक बढ़ा दिया है।

इसके अलावा, संविधान में 73वें और 74वें संशोधनों ने भाग IX

takes effect on the basis of the first census after the year 2025, of the number of seats in the Legislative Assembly of the State of Tripura, the seats which shall be reserved for the Scheduled Tribes in the Legislative Assembly shall be, such number of seats as bears to the total number of seats, a proportion not less than the number, as on the date of coming into force of the Constitution (Seventy-second Amendment) Act, 1992, of members belonging to the Scheduled Tribes in the Legislative Assembly in existence on the said date bears to the total number of seats in that Assembly. (4) The number of seats reserved for an autonomous district in the Legislative Assembly of the State of Assam shall bear to the total number of seats in that Assembly a proportion not less than the population of the district bears to the total population of the State. (5) The constituencies for the seats reserved for any autonomous district of Assam shall not comprise any area outside that district.

(5) No person who is not a member of a Scheduled Tribe of any autonomous district of the State of Assam shall be eligible for election to the Legislative Assembly of the State from any constituency of that district. Provided that for elections to the Legislative Assembly of the State of Assam, the representation of the Scheduled Tribes and non-Scheduled Tribes in the constituencies included in the Bodoland Territorial Areas District, so notified, and existing prior to the constitution of Bodoland Territorial Areas District, shall be maintained."

⁵⁸⁷The Constitution of India, 1950, art. 330A: "Reservation of seats for women in the House of the People.-(1) Seats shall be reserved for women in the House of the People. (2) As nearly as may be, one-third of the total number of seats reserved under clause (2) of article 330 shall be reserved for women belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes. (3) As nearly as may be, one-third (including the number of seats reserved for women belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes) of the total number of seats to be filled by direct election to the House of the People shall be reserved for women."

⁵⁸⁸The Constitution of India, 1950, art. 332A: "Reservation of seats for women in the Legislative Assemblies of the States.— (1) Seats shall be reserved for women in the Legislative Assembly of every State. (2) As nearly as may be, one-third of the total number of seats reserved under clause (3) of article 332 shall be reserved for women belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes. (3) As nearly as may be, one-third (including the number of seats reserved for women belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes) of the total number of seats to be filled by direct election in the Legislative Assembly of every State shall be reserved for women."

⁵⁸⁹The Constitution of India, 1950, art. 334: "Reservation of seats and special representation to cease after certain period.— Notwithstanding anything in the foregoing provisions of this Part, the provisions of this Constitution relating to—(a) the reservation of seats for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in the House of the People and in the Legislative Assemblies of the States; and (b) the representation of the Anglo-Indian community in the House of the People and in the Legislative Assemblies of the States by Nomination, shall cease to have effect on the expiration of a period of eighty years in respect of clause (a) and seventy years in respect of clause (b) from the commencement of this Constitution: Provided that nothing in this article shall affect any representation in the House of the People or in the Legislative Assembly of a State until the dissolution of the then existing House or Assembly, as the case may be."

⁵⁹⁰*Ibid.*

और IXA को पेश किया, जिसने पंचायती राज और नगरपालिका प्रणालियों को संवैधानिक बना दिया।⁵⁹¹ ये संशोधन, अनुच्छेद 243डी और 243टी के माध्यम से, पंचायतों और नगर पालिकाओं में अनुसूचित जनजातियों के लिए उनकी आबादी के अनुपात में सीटों के आरक्षण का प्रावधान करते हैं। इसने यह सुनिश्चित किया कि आदिवासी समुदाय न केवल राष्ट्रीय और राज्य विधानसभाओं में बल्कि जमीनी स्तर के शासन में भी भाग लेते हैं, जिससे शक्ति का विकेंद्रीकरण होता है और निर्णय लेने में प्रत्यक्ष भागीदारी होती है।

अनुच्छेद 243डी हाशिए पर पड़े समूहों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए पंचायतों में आरक्षण का आदेश देता है।⁵⁹² इसमें प्रावधान है कि पंचायत क्षेत्र में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए उनकी आबादी के अनुपात में सीटें आरक्षित की जानी चाहिए, ऐसी सीटें बारी-बारी से आवंटित की जानी चाहिए। इसमें यह भी प्रावधान है कि पंचायत की आरक्षित सीटों में से कम से कम एक तिहाई सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित होनी चाहिए। सभी पंचायत स्तरों पर अध्यक्षों के पद भी अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और महिलाओं के लिए, उनकी आबादी के अनुपात में, महिलाओं के लिए न्यूनतम एक तिहाई आरक्षित के भीतर आरक्षित हैं। इसी तरह, अनुच्छेद 243टी नगरपालिकाओं में सीटों के आरक्षण के लिए समान प्रावधान प्रदान करता है जैसा कि अनुच्छेद 243डी पंचायतों में प्रदान करता है।⁵⁹³

⁵⁹¹The Constitution (Seventy-third Amendment) Act, 1992; The Constitution (Seventy-fourth Amendment) Act, 1992.

⁵⁹²The Constitution of India, 1950, art. 243D: “Reservation of seats. — (1) Seats shall be reserved for — (a) the Scheduled Castes; and (b) the Scheduled Tribes, in every Panchayat and the number of seats so reserved shall bear, as nearly as may be, the same proportion to the total number of seats to be filled by direct election in that Panchayat as the population of the Scheduled Castes in that Panchayat area or of the Scheduled Tribes in that Panchayat area bears to the total population of that area and such seats may be allotted by rotation to different constituencies in a Panchayat. (2) Not less than one-third of the total number of seats reserved under clause (1) shall be reserved for women belonging to the Scheduled Castes or, as the case may be, the Scheduled Tribes. (3) Not less than one-third (including the number of seats reserved for women belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes) of the total number of seats to be filled by direct election in every Panchayat shall be reserved for women and such seats may be allotted by rotation to different constituencies in a Panchayat. (4) The offices of the Chairpersons in the Panchayats at the village or any other level shall be reserved for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and women in such manner as the Legislature of a State may, by law, provide: Provided that the number of offices of Chairpersons reserved for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in the Panchayats at each level in any State shall bear, as nearly as may be, the same proportion to the total number of such offices in the Panchayats at each level as the population of the Scheduled Castes in the State or of the Scheduled Tribes in the State bears to the total population of the State: Provided further that not less than one-third of the total number of offices of Chairpersons in the Panchayats at each level shall be reserved for women: Provided also that the number of offices reserved under this clause shall be allotted by rotation to different Panchayats at each level. (5) The reservation of seats under clauses (1) and (2) and the reservation of offices of Chairpersons (other than the reservation for women) under clause (4) shall cease to have effect on the expiration of the period specified in article 334. (5) Nothing in this Part shall prevent the Legislature of a State from making any provision for reservation of seats in any Panchayat or offices of Chairpersons in the Panchayats at any level in favour of the backward class of citizens.”

⁵⁹³The Constitution of India, 1950, art. 243T: “Reservation of seats. — (1) Seats shall be reserved for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in every Municipality and the number of seats so reserved shall bear, as nearly as may be, the same proportion to the total number of seats to be filled by direct election in that Municipality as the population of the Scheduled Castes in the Municipal area or of the Scheduled Tribes in the Municipal area bears to the total population of that area and such seats may be allotted by rotation to different constituencies in a Municipality. (2) Not less than one-third of the total number of seats reserved under clause (1) shall be reserved for women belonging to the Scheduled Castes or, as the case

इसके पूरक के रूप में, अनुच्छेद 275 में अनुसूचित जनजातियों के कल्याण को बढ़ावा देने और अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन में सुधार के लिए केंद्र से राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रावधान है।⁵⁹⁴ संसद को जनजातीय कल्याण के लिए राज्यों द्वारा शुरू की गई विकास योजनाओं का समर्थन करने और अनुसूचित और गैर-अनुसूचित क्षेत्रों के बीच प्रशासनिक मानकों में समानता सुनिश्चित करने के लिए भारत की संचित निधि से सहायता अनुदान देने का अधिकार है। पूंजी और आवर्ती दोनों तरह के इन अनुदानों का उद्देश्य विकास संबंधी असमानताओं को दूर करना और जनजातीय क्षेत्रों में संस्थागत क्षमता को मजबूत करना है।

इसके अलावा, अनुच्छेद 164 (1) के प्रावधान में छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और ओडिशा राज्यों में

may be, the Scheduled Tribes. (3) Not less than one-third (including the number of seats reserved for women belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes) of the total number of seats to be filled by direct election in every Municipality shall be reserved for women and such seats may be allotted by rotation to different constituencies in a Municipality. (4) The offices of Chairpersons in the Municipalities shall be reserved for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and women in such manner as the Legislature of a State may, by law, provide. (5) The reservation of seats under clauses (1) and (2) and the reservation of offices of Chairpersons (other than the reservation for women) under clause (4) shall cease to have effect on the expiration of the period specified in article 334. (5) Nothing in this Part shall prevent the Legislature of a State from making any provision for reservation of seats in any Municipality or offices of Chairpersons in the Municipalities in favour of the backward class of citizens.”

⁵⁹⁴The Constitution of India, 1950, art. 275: “Grants from the Union to certain States. — (1) Such sums as Parliament may by law provide shall be charged on the Consolidated Fund of India in each year as grants-in-aid of the revenues of such States as Parliament may determine to be in need of assistance, and different sums may be fixed for different States:

Provided that there shall be paid out of the Consolidated Fund of India as grants-in-aid of the revenues of a State such capital and recurring sums as may be necessary to enable the State to meet the costs of such schemes of development as may be undertaken by the State with the approval of the Government of India for the purpose of promoting the welfare of the Scheduled Tribes in that State or raising the level of administration of the Scheduled Areas therein to that of the administration of the rest of the areas of that State: Provided further that there shall be paid out of the Consolidated Fund of India as grants-in-aid of the revenues of the State of Assam sums, capital and recurring, equivalent to — (a) the average excess of expenditure over the revenues during the two years immediately preceding the commencement of this Constitution in respect of the administration of the tribal areas specified in Part I of the table appended to paragraph 20 of the Sixth Schedule; and (b) the cost of such schemes of development as may be undertaken by that State with the approval of the Government of India for the purpose of raising the level of administration of the said areas to that of the administration of the rest of the areas of that State. (1A) On and from the formation of the autonomous State under article 244A, — (i) any sums payable under clause (a) of the second proviso to clause (1) shall, if the autonomous State comprises all the tribal areas referred to therein, be paid to the autonomous State, and, if the autonomous State comprises only some of those tribal areas, be apportioned between the State of Assam and the autonomous State as the President may, by order, specify; (ii) there shall be paid out of the Consolidated Fund of India as grants-in-aid of the revenues of the autonomous State sums, capital and recurring, equivalent to the costs of such schemes of development as may be undertaken by the autonomous State with the approval of the Government of India for the purpose of raising the level of administration of that State to that of the administration of the rest of the State of Assam. (2) Until provision is made by Parliament under clause (1), the powers conferred on Parliament under that clause shall be exercisable by the President by order and any order made by the President under this clause shall have effect subject to any provision so made by Parliament: Provided that after a Finance Commission has been constituted no orders shall be made under this clause by the President except after considering the recommendations of the Finance Commission.”

जनजातीय कल्याण के प्रभारी मंत्री की नियुक्ति को अनिवार्य किया गया है।⁵⁹⁶ यह मंत्री अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों के कल्याण से संबंधित जिम्मेदारियों को भी संभाल सकता है। इस प्रावधान का समावेश राज्य कार्यकारी स्तर पर जनजातीय कल्याण के लिए राजनीतिक प्रतिनिधित्व और प्रशासनिक जवाबदेही सुनिश्चित करने के संवैधानिक इरादे को रेखांकित करता है।

संविधान पाँचवीं और छठी अनुसूचियों के माध्यम से जनजातीय बहुल क्षेत्रों में विशेष सुरक्षा भी प्रदान करता है। कई राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों पर लागू होने वाली पाँचवीं अनुसूची, कल्याणकारी उपायों पर सलाह देने के लिए एक जनजाति सलाहकार परिषद का निर्माण करती है और राज्यपालों को भूमि हस्तांतरण और आवंटन को विनियमित करने का अधिकार देती है ताकि जनजातीय स्वामित्व की रक्षा की जा सके। यह राज्यपाल को संसद या विधायिका के किसी विशेष अधिनियम को अपवादों और संशोधनों के साथ अनुसूचित क्षेत्र में लागू करने का निर्देश देने की भी अनुमति देता है।

छठी अनुसूची, विशेष रूप से असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के पूर्वोत्तर राज्यों के लिए, स्वायत्त जिला और क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना करती है, जो उन्हें निर्दिष्ट क्षेत्रों में विधायी, न्यायिक और वित्तीय शक्तियाँ प्रदान करती है। यह योजना संवैधानिक रूप से जनजातीय लोगों की विशिष्ट सांस्कृतिक और राजनीतिक पहचान को मान्यता देती है और उन्हें शासन में महत्वपूर्ण स्वायत्तता प्रदान करती है। इसके अलावा, नागालैंड के लिए 371ए और मिजोरम के लिए 371जी जैसे अनुच्छेद पारंपरिक कानूनों, प्रथाओं और संस्थानों को संरक्षित करते हैं, जिससे आदिवासी बहुल राज्यों की स्वायत्तता और मजबूत होती है।

3.3.2. न्यायिक व्याख्याएँ

न्यायपालिका ने राजनीतिक प्रतिनिधित्व और शासन की संवैधानिक गारंटी के अर्थ को आकार देने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। *समता बनाम आंध्र प्रदेश राज्य*,⁵⁹⁷ के मामले में उच्चतम न्यायालय ने आंध्र प्रदेश में गैर-जनजातीय निजी कंपनियों को सरकारी और जनजातीय क्षेत्रों के खनन पट्टों के अनुदान से संबंधित मामले की सुनवाई की। दो-न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि अनुसूचित क्षेत्रों में निगमों सहित गैर-आदिवासियों को आदिवासी भूमि का हस्तांतरण पाँचवीं अनुसूची का उल्लंघन है, इस बात पर जोर देते हुए कि भूमि आदिवासी स्वायत्तता के लिए केंद्रीय है।⁵⁹⁸ उद्देश्यपूर्ण व्याख्या और आदिवासियों के बीच वितरण न्याय सुनिश्चित करने के लिए रास्ता देते हुए, अदालत ने कहा: " *किसी भी अन्य व्याख्या से आदिवासियों की स्वायत्तता और उनकी संस्कृति के बिखरने की स्थिति पैदा होगी, और समानता, सम्मान और बराबरी का दर्जा पाने के लिए सामाजिक,*

⁵⁹⁵The Constitution (Ninety-fourth Amendment) Act, 2006, s.2.

⁵⁹⁶The Constitution of India, 1950, art. 164: "Other provisions as to Ministers. —(1) The Chief Minister shall be appointed by the Governor and the other Ministers shall be appointed by the Governor on the advice of the Chief Minister, and the Ministers shall hold office during the pleasure of the Governor: Provided that in the States of Chhattisgarh, Jharkhand, Madhya Pradesh and Odisha there shall be a Minister in charge of tribal welfare who may in addition be in charge of the welfare of the Scheduled Castes and backward classes or any other work."

⁵⁹⁷Samathav. State of Andhra Pradesh (1997) 8 SCC 191.

⁵⁹⁸*Id.* at para. 94.

आर्थिक और राजनीतिक रूप से उनके सशक्तिकरण की कोशिशें नाकाम हो जाएंगी।" ⁵⁹⁹

इससे पहले, *भारत संघ बनाम राकेश कुमार*, ⁶⁰⁰ के मामले में अनुसूचित क्षेत्रों में आरक्षण और झारखंड पंचायत राज अधिनियम, 2001 के कुछ संबंधित प्रावधानों से संबंधित प्रश्नों पर विचार करते हुए, तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने पंचायतों में ऐसे आरक्षण की वैधता को बरकरार रखा। न्यायालय ने 'मूल समानता' ⁶⁰¹ के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि झारखंड पंचायत राज अधिनियम, 2001 के विवादित प्रावधानों के पीछे विधायी उद्देश्य मुख्य रूप से अनुसूचित जनजाति श्रेणी से संबंधित व्यक्तियों के हितों की रक्षा करना है। इसलिए, अनुच्छेद 243-एम (4) (बी) के तहत अनिवार्य असाधारण व्यवहार के कारण अनुसूचित क्षेत्रों में स्थित पंचायतों में 50 प्रतिशत से अधिक सीटों पर कुल आरक्षण की अनुमति है ⁶⁰²

हालाँकि अदालतों का एक उदार दृष्टिकोण रहा है, लेकिन सीमाओं को पार न करने के लिए सावधानी बरती गई है। उदाहरण के लिए, जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, चेब्रो लु लीला प्रसाद राव, ⁶⁰³ के मामले में न्यायालय ने पंचायतों में अनुसूचित जनजातियों के लिए अनुसूचित क्षेत्रों में सीटों के 100 प्रतिशत आरक्षण को अनुच्छेद 14 के तहत असंवैधानिक बताते हुए रद्द कर दिया, हालाँकि इसने फिर से पुष्टि की कि पंचायती राज संस्थानों में अनुसूचित जनजातियों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व अनुच्छेद 243 डी द्वारा अनिवार्य है। ⁶⁰⁴

अन्य मामलों में प्रतिनिधित्व और स्वशासन के संबंधित आयामों को भी संबोधित किया गया है। उदाहरण के लिए, *नागालैंड राज्य बनाम रतन सिंह*, ⁶⁰⁵ के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने नागा पहाड़ियों और अन्य आदिवासी क्षेत्रों में विशेष कानूनी व्यवस्थाओं के लंबे इतिहास का पता लगाया, जिसमें इस बात पर प्रकाश डाला गया कि कैसे औपनिवेशिक और उत्तर औपनिवेशिक कानून के तहत आदिवासी समुदायों के लिए स्व-शासन और न्याय की अलग-अलग प्रणालियाँ विकसित हुई थीं। न्यायालय ने अपनी पाँच न्यायाधीशों की पीठ के माध्यम से यह अभिनिर्धारित किया कि नागा हिल्स जिले, 1937 में न्याय और पुलिस प्रशासन के लिए नियम वैध रूप से अधिनियमित किए गए थे और अनुसूचित जिला अधिनियम, 1874 के निरसन और पिछड़े क्षेत्रों में कानूनी रूप से शासित मुकदमों के बावजूद लागू रहे, जहाँ दंड प्रक्रिया संहिता लागू नहीं थी। ⁶⁰⁶ यह ध्यान दिया गया कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता जैसे सामान्य कानूनों को जानबूझकर इन 'पिछड़े क्षेत्रों' से रोक दिया गया था, और इसके बजाय, बनाए गए नियमों जैसे नियमों ने एक सरल प्रक्रिया प्रदान की, जो प्रथागत प्रथाओं के करीब और स्थानीय आबादी के लिए सुलभ थी। इसने अत्यधिक प्रत्यायोजन या अनुच्छेद 14 और 21 के उल्लंघन के तर्कों को खारिज कर दिया, यह देखते हुए कि पिछड़े क्षेत्रों के लिए विभिन्न कानूनी ढाँचे उनकी अनूठी शर्तों और मुख्यधारा की कानूनी प्रणाली में क्रमिक एकीकरण को देखते हुए उचित थे। ⁶⁰⁷ इसलिए, पारंपरिक जनजातीय संस्थानों की स्वायत्तता

⁵⁹⁹ *Id.* at para. 86.

⁶⁰⁰ *Union of India v. Rakesh Kumar* (2010) 4 SCC 50.

⁶⁰¹ *Id.* at para. 37.

⁶⁰² *Id.* at para. 58.

⁶⁰³ *Chebrolu Leela Prasad Rao v. State of Andhra Pradesh* (2020) SCC OnLine SC 383.

⁶⁰⁴ *Id.* at para. 122.

⁶⁰⁵ *State of Nagaland v. Ratan Singh* (1966) SCC OnLine SC 114.

⁶⁰⁶ *Id.* at para. 28.

⁶⁰⁷ *Id.* at paras. 30-36.

की पुष्टि करते हुए, अनुच्छेद 371ए के तहत नागालैंड के विशेष संवैधानिक दर्जे को बरकरार रखा गया।

इन प्रावधानों और न्यायिक व्याख्याओं को एक साथ देखने पर एक संतुलन का पता चलता है। एक ओर, संविधान प्रतिनिधि निकायों में आरक्षण और अनुसूचित क्षेत्रों में स्वशासन दोनों के माध्यम से अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व और स्वायत्तता के संरचनात्मक सुरक्षा की गारंटी देता है। दूसरी ओर, अदालतों ने जोर देकर कहा है कि इस तरह के उपाय समानता और लोकतंत्र के व्यापक संवैधानिक ढांचे के भीतर रहने चाहिए, यह सुनिश्चित करते हुए कि संवैधानिक सिद्धांतों को कम किए बिना जनजातीय अधिकारों की रक्षा की जाए।

3.4. भूमि और संसाधनों पर स्वायत्तता

संविधान के तहत जनजातीय लोगों के अधिकारों का एक महत्वपूर्ण आयाम स्वायत्तता और प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण है। संविधान आदिवासी समुदायों को उनकी भूमि और प्राकृतिक संसाधनों के साथ साझा किए जाने वाले विशिष्ट संबंधों को मान्यता देता है, जिससे उन्हें विशेष सुरक्षा मिलती है। इन प्रावधानों को उन संसाधनों पर आदिवासी आबादी की स्वायत्तता को संरक्षित करने के लिए तैयार किया गया था जो उनकी सांस्कृतिक पहचान, आजीविका और स्व-शासन का आधार हैं।

3.4.1. संवैधानिक आधार

इसकी अभिव्यक्ति मुख्य रूप से अनुच्छेद 244 और 244ए के साथ पठित पांचवीं और छठी अनुसूचियों में मिलती है, जो अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों के शासन के लिए एक अद्वितीय संवैधानिक ढांचा प्रदान करते हैं। जैसा कि पहले ही चर्चा की जा चुकी है, पांचवीं अनुसूची अधिकांश राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण को नियंत्रित करती है, राज्यपाल को कानूनों के अनुप्रयोग को प्रतिबंधित या संशोधित करने और यह सुनिश्चित करने के लिए विशेष शक्तियां प्रदान करती है कि भूमि और संसाधनों में जनजातीय हितों को कम न किया जाए। दूसरी ओर, छठी अनुसूची विशेष रूप से असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों पर लागू होती है, जो भूमि, वन, जल और स्थानीय शासन जैसे मामलों पर विधायी, कार्यकारी और न्यायिक शक्तियों के साथ स्वायत्त जिलों और क्षेत्रीय परिषदों का निर्माण करती है। साथ में, ये प्रावधान संवैधानिक रूप से जनजातीय स्वायत्तता की रक्षा करने और उनके संसाधनों को अनियंत्रित राज्य और निजी शोषण से बचाने के सिद्धांतों को जोड़ते हैं।

3.4.2. न्यायिक व्याख्याएँ

इन संरक्षणों को मजबूत करने में न्यायिक व्याख्या महत्वपूर्ण रही है। जैसा कि चर्चा की गई है, समता,⁶⁰⁸ के निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि अनुसूचित क्षेत्रों में सरकारी भूमि, वन भूमि और जनजातीय भूमि को निजी खनन कंपनियों को शोषण के लिए पट्टे पर नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि इस तरह का हस्तांतरण पांचवीं अनुसूची के सुरक्षात्मक ढांचे का उल्लंघन करेगा। न्यायालय ने कहा कि आदिवासी जीवन को बचाने, गैर-आदिवासियों और साहूकारों द्वारा आदिवासियों के शोषण को रोकने और एजेंसी क्षेत्रों या अनुसूचित क्षेत्रों में गैर-आदिवासियों

⁶⁰⁸ Samathav. State of Andhra Pradesh (1997) 8 SCC 191.

की घुसपैठ को रोकने के लिए कानून के माध्यम जो सुरक्षा उपाय अपनाए गए, वे तीन मुख्य आधारों पर निर्भर थे:

(क) एक आदिवासी द्वारा गैर-आदिवासी को इस शर्त के साथ कि ऐसा भूमि हस्तांतरण का निषेध अमान्य होगा। (ख) सरकार को उसमें निहित भूमि को गैर-आदिवासियों को आवंटित करने से प्रतिबंधित करना। (ग) सरकार की किसी गैर-जनजातीय को उस भूमि से बेदखल करने की शक्ति जो एक शून्य विक्रय विलेख के माध्यम से उसके कब्जे में आती है और उसे आदिवासी या उसके उत्तराधिकारियों को बहाल करती है।⁶⁰⁹ इस प्रकार, यह निर्णय इस सिद्धांत को रेखांकित करता है कि संसाधनों पर जनजातीय स्वायत्तता संवैधानिक रूप से वाणिज्यिक शोषण से सुरक्षित है।

इसी प्रकार, एस. जगन्नाथ बनाम भारत संघ,⁶¹⁰ के मामले में उच्चतम न्यायालय की दो-न्यायाधीशों की पीठ ने नाजुक तटीय पारिस्थितिकी तंत्रों के साथ गहन झींगा खेती और उन तटों पर रहने वाले मछुआरों के अधिकारों के बीच संतुलन स्थापित किया। इस प्रकार, न्यायालय ने वाणिज्यिक जलीय कृषि के कारण होने वाले पर्यावरणीय क्षरण को संबोधित किया।⁶¹¹ इस बात पर जोर दिया कि स्थानीय समुदायों की आजीविका और अधिकारों की परवाह किए बिना प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करना अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का उल्लंघन है।⁶¹² इस तरह, संसाधनों पर स्वायत्तता की समझ को और व्यापक बनाया गया है; इसे जीवन के अधिकार की संवैधानिक गारंटी से जोड़ा गया है, जिसमें स्वच्छ और स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार भी शामिल है।

2013 में सर्वोच्च न्यायालय को उड़ीसा खनन निगम द्वारा दायर एक रिट का सामना करना पड़ा था, जिसमें पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा बॉक्साइट अयस्क के खनन के लिए 660.749 हेक्टेयर वन भूमि को मोड़ने के लिए वन मंजूरी को खारिज करने के आदेश को रद्द करने के लिए दायर किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने उड़ीसा खनन निगम लिमिटेड बनाम पर्यावरण और वन मंत्रालय,⁶¹³ जिसे नियमगिरी निर्णय के रूप में जाना जाता है, के फैसले में कहा कि क्या अनुसूचित जनजातियों और अन्य पारंपरिक वनवासियों (ओटीएफडी) का नियम गिरी पहाड़ियों पर कोई धार्मिक अधिकार है, इस सवाल पर ग्राम सभा द्वारा विचार किया जाना चाहिए। इस प्रकार, तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि अनुसूचित जनजातियों के धार्मिक और सांस्कृतिक अधिकारों को प्रभावित करने वाले मामलों, विशेष रूप से खनन परियोजनाओं के संबंध में निर्णय लेने का अंतिम अधिकार ग्राम सभा के पास है।⁶¹⁴ ग्राम सभा की प्रधानता की इस मान्यता ने इस बात की पुष्टि की कि अनुसूचित क्षेत्रों में संसाधन प्रशासन के लिए सामुदायिक सहमति अभिन्न है।

पांचवीं और छठी अनुसूचियों, अनुच्छेद 244 और 244ए, और समता, नियमगिरी और एस. जगन्नाथ जैसी न्यायिक घोषणाओं को मिलाकर जनजातीय लोगों के अधिकारों के इर्द-गिर्द एक संवैधानिक और न्यायिक कवच बुना जाता है। वे न केवल भूमि और संसाधनों पर अपनी स्वायत्तता को सुरक्षित करते हैं, बल्कि यह भी सुनिश्चित करते हैं कि कोई भी हस्तक्षेप, चाहे वह राज्य या निजी कर्ताओं द्वारा हो, समानता, गरिमा और सांस्कृतिक

⁶⁰⁹ *Id.* at para. 165.

⁶¹⁰ *S. Jagannath v. Union of India* (1997) 2 SCC 87.

⁶¹¹ *Id.* at para. 31.

⁶¹² *Id.* at paras. 49-50.

⁶¹³ *Orissa Mining Corporation Limited v. Ministry of Environment and Forest* (2013) 6 SCC 476.

⁶¹⁴ *Id.* at paras. 64-67.

समानता, गरिमा और सांस्कृतिक अस्तित्व की संवैधानिक गारंटी के अनुरूप होना चाहिए। इस प्रकार यह ढांचा इस बात की पुष्टि करता है कि संसाधनों पर जनजातीय स्वायत्तता स्वशासन और मौलिक अधिकारों के संरक्षण दोनों के लिए केंद्रीय है।

3.5 सांस्कृतिक और धार्मिक स्वतंत्रताएँ

भारत में जनजातीय लोगों की सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान उनकी भूमि, वनों और सामुदायिक जीवन से अविभाज्य है। मुख्यधारा के धर्मों के विपरीत, आदिवासी धर्मों की जड़ें प्रकृति की पूजा, पैतृक अनुष्ठान और प्रथागत प्रथाओं में निहित हैं, जो अक्सर विशिष्ट पहाड़ियों, नदियों या जंगलों से जुड़ी होती हैं जो पवित्र अर्थ रखते हैं। इन प्रथाओं की रक्षा करना केवल धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा करने का मामला नहीं है, बल्कि भारत की बहुलवादी विरासत का एक अनिवार्य हिस्सा बनने वाली आदिवासी संस्कृतियों के अस्तित्व को सुनिश्चित करने का भी मामला है।

3.5.1. संवैधानिक आधार

संविधान सभी व्यक्तियों के सांस्कृतिक और धार्मिक अधिकारों के संरक्षण पर जोर देता है। संविधान के अनुच्छेद 25 से 29 में धार्मिक स्वतंत्रता के प्रावधानों पर चर्चा की गई है।

संविधान का अनुच्छेद 25 सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन विवेक की स्वतंत्रता और स्वतंत्र रूप से धर्म का पालन करने और प्रचार करने के अधिकार की गारंटी देता है।⁶¹⁵ अनुच्छेद 26 प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या वर्ग के लिए अपने धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने के साथ-साथ चल और अचल संपत्ति हासिल करने की स्वतंत्रता का भी प्रावधान करता है।⁶¹⁶ अनुच्छेद 27 राज्य को किसी विशिष्ट धर्म के प्रचार या रखरखाव के लिए धन जुटाने के लिए कर लगाने से रोकता है।⁶¹⁷ हालांकि इन अनुच्छेदों में विशेष रूप से अनुसूचित जनजातियों का उल्लेख नहीं है, वे सामूहिक रूप से सभी व्यक्तियों और प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय की धार्मिक पहचान की रक्षा करते हुए संविधान के धर्मनिरपेक्ष और बहुलवादी लोकाचार को बनाए रखते हैं।

⁶¹⁵The Constitution of India, 1950, art. 25: "Freedom of conscience and free profession, practice and propagation of religion. —

(1) Subject to public order, morality and health and to the other provisions of this Part, all persons are equally entitled to freedom of conscience and the right freely to profess, practice and propagate religion. (2) Nothing in this article shall affect the operation of any existing law or prevent the State from making any law — (a) regulating or restricting any economic, financial, political or other secular activity which may be associated with religious practice; (b) providing for social welfare and reform or the throwing open of Hindu religious institutions of a public character to all classes and sections of Hindus. Explanation I. — The wearing and carrying of kirpans shall be deemed to be included in the profession of the Sikh religion. Explanation II. — In sub-clause (b) of clause (2), the reference to Hindus shall be construed as including a reference to persons professing the Sikh, Jaina or Buddhist religion, and the reference to Hindu religious institutions shall be construed accordingly."

⁶¹⁶The Constitution of India, 1950, art. 26: "Freedom to manage religious affairs. — Subject to public order, morality and health, every religious denomination or any section thereof shall have the right — (a) to establish and maintain institutions for religious and charitable purposes; (b) to manage its own affairs in matters of religion; (c) to own and acquire movable and immovable property; and (d) to administer such property in accordance with law."

⁶¹⁷The Constitution of India, 1950, art. 27: "Freedom as to payment of taxes for promotion of any particular religion. — No person shall be compelled to pay any taxes, the proceeds of which are specifically appropriated in payment of expenses for the promotion or maintenance of any particular religion or religious denomination."

अनुच्छेद 28 शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित है। यह व्यक्तियों, धार्मिक समूहों और धार्मिक समारोहों में उपस्थिति के अधिकारों की रक्षा करता है। यह सुनिश्चित करते हुए कि सरकार द्वारा वित्त पोषित सार्वजनिक शैक्षणिक संस्थान धर्मनिरपेक्ष रहें और धार्मिक शिक्षा प्रदान न करें, यह राज्य द्वारा प्रशासित लेकिन किसी भी बंदोबस्ती या ट्रस्ट के तहत स्थापित शैक्षणिक संस्थानों को धार्मिक निर्देश प्रदान करने की भी अनुमति देता है।⁶¹⁸ अनुच्छेद 29 आगे सांस्कृतिक अधिकारों की रक्षा करता है।⁶¹⁹ यह "नागरिकों के किसी भी वर्ग" के अधिकारों की रक्षा करता है, जो अनुच्छेद 29 (मसौदा अनुच्छेद 23 (1) (2)) पर संवैधानिक सभा की बहसों से स्पष्ट है, जो अल्पसंख्यकों को कवर करने के इरादे को दर्शाता है जो "तकनीकी अर्थों में अल्पसंख्यक नहीं हैं, लेकिन फिर भी सांस्कृतिक और भाषाई अर्थों में अल्पसंख्यक हैं"।⁶²⁰ इसके द्वारा जनजातीय समुदायों सहित अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति का संरक्षण करना।

इन सुरक्षा उपायों की निरंतरता में, अनुच्छेद 350 में यह प्रावधान है कि प्रत्येक व्यक्ति संघ या राज्य में उपयोग की जाने वाली किसी भी भाषा में संघ या राज्य के किसी भी अधिकारी या प्राधिकरण को शिकायतों के निवारण के लिए प्रतिनिधित्व का हकदार होगा।⁶²¹ इसके अलावा, अनुच्छेद 350ए आदेश देता है कि प्रत्येक राज्य और स्थानीय प्राधिकरण भाषाई अल्पसंख्यक समूहों से संबंधित बच्चों के लिए शिक्षा के प्राथमिक चरण में मातृभाषा में शिक्षा के लिए पर्याप्त सुविधाएं प्रदान करने का प्रयास करेगा।⁶²² इन अनुच्छेदों को सातवें संशोधन,⁶²³ द्वारा पेश किया गया था, इस प्रकार शासन में भाषाई समावेश और न्याय तक पहुंच सुनिश्चित करने के साथ-साथ आदिवासी भाषाओं का संरक्षण और यह सुनिश्चित करना कि शिक्षा सांस्कृतिक निरंतरता का एक साधन बनी रहे, जो आदिवासी समुदायों के लिए विशेष महत्व रखता है।

विशेष संवैधानिक संरक्षण इन गारंटी को सुदृढ़ करते हैं। पांचवीं अनुसूची जनजातीय क्षेत्रों पर लागू होती है और राज्यपालों को यह सुनिश्चित करने के लिए विशेष जिम्मेदारियां सौंपती है कि संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून जनजातीय रीति-रिवाजों, परंपराओं और भूमि अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव न डालें। इसके अतिरिक्त, छठी अनुसूची कुछ पूर्वोत्तर राज्यों में

⁶¹⁸The Constitution of India, 1950, art. 28: "Freedom as to attendance at religious instruction or religious worship in certain educational institutions.—(1) No religious instruction shall be provided in any educational institution wholly maintained out of State funds. (2) Nothing in clause (1) shall apply to an educational institution which is administered by the State but has been established under any endowment or trust which requires that religious instruction shall be imparted in such institution. (3) No person attending any educational institution recognised by the State or receiving aid out of State funds shall be required to take part in any religious instruction that may be imparted in such institution or to attend any religious worship that may be conducted in such institution or in any premises attached thereto unless such person or, if such person is a minor, his guardian has given his consent thereto."

⁶¹⁹The Constitution of India, 1950, art. 29: "Protection of interests of minorities.—(1) Any section of the citizens residing in the territory of India or any part thereof having a distinct language, script or culture of its own shall have the right to conserve the same. (2) No citizen shall be denied admission into any educational institution maintained by the State or receiving aid out of State funds on grounds only of religion, race, caste, language or any of them."

⁶²⁰Constituent Assembly Debates on December 08, 1948, available at: <https://www.constitutionofindia.net/debates/08-dec-1948/#138056> (last visited on Nov. 3, 2025); Anurag Bhaskar, "Education" SSRN eLibrary 13 (Jul. 2022), available at: <https://ssrn.com/abstract=4164728> (last visited on Nov. 3, 2025).

⁶²¹The Constitution of India, 1950, art. 350.

⁶²²The Constitution of India, 1950, art. 350A.

⁶²³The Constitution (Seventh Amendment) Act, 1955, s. 21.

स्वायत्त जिला परिषदों को प्रथागत कानूनों, सामाजिक प्रथाओं और संस्थानों को संरक्षित करने का अधिकार देती है। इसी तरह, नागालैंड के लिए अनुच्छेद 371ए-⁶²⁴ और मिजोरम के लिए अनुच्छेद 371जी-⁶²⁵ राज्य विधानसभाओं को प्रथागत कानून, भूमि और उसके संसाधनों के स्वामित्व और धार्मिक और सामाजिक प्रथाओं से संबंधित मामलों पर विशेष अधिकार प्रदान करते हैं।

ये प्रावधान यह सुनिश्चित करते हैं कि शासन जनजातीय जीवन के अद्वितीय सांस्कृतिक और आध्यात्मिक ताने-बाने पर हावी न हो। इस प्रकार, यह सुनिश्चित करना कि प्रथागत कानूनों को बाहरी हस्तक्षेपों से संरक्षण प्राप्त हो।

3.5.2. न्यायिक व्याख्याएँ

न्यायिक व्याख्या ने लगातार इन संरक्षणों की पुष्टि की है। जैसा कि पहले ही चर्चा की जा चुकी है, नियामगिरी मामले में, ⁶²⁶ सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि नियामगिरी पहाड़ियों को पवित्र मानने वाली डोंगरिया कोंध जनजाति के धार्मिक और सांस्कृतिक अधिकारों का बॉक्साइट खनन परियोजनाओं द्वारा उल्लंघन नहीं किया जा सकता है। न्यायालय ने माना कि आस्था और संस्कृति में निहित जनजातीय दावों की वैधता निर्धारित करने के लिए ग्राम सभा उपयुक्त प्राधिकरण है, जिससे अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 जैसे वैधानिक संरक्षणों के संयोजन के साथ अनुच्छेद 25 और 26 के तहत संवैधानिक गारंटी का संचालन होता है। न्यायालय ने कहा: "संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 के तहत अनुसूचित जनजातियों और पारंपरिक वनवासियों को दी गई धार्मिक स्वतंत्रता का उद्देश्य जीवन और सामाजिक मांगों के समुदाय के लिए एक मार्गदर्शक होना है।" ⁶²⁷ ये अनुच्छेद न केवल आस्था या विश्वास के मामलों का पालन करने और प्रचार करने के अधिकार की गारंटी देते हैं, बल्कि उन सभी अनुष्ठानों और टिप्पणियों की भी गारंटी देते हैं जिन्हें उनके धर्म का एक अभिन्न अंग माना जाता है। इसलिए, देवता नियम-राजा की पूजा करने के उनके अधिकार की रक्षा और संरक्षण किया जाना चाहिए।

अन्य निर्णयों ने भी अप्रत्यक्ष रूप से सांस्कृतिक सुरक्षा को मजबूत किया है। T.N. में गोडावर्मन थिरुमुल्कपद बनाम भारत संघ, ⁶²⁸ हालांकि मुख्य रूप से पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है, न्यायालय ने उन आदिवासियों के लिए जवाबदेह होने की आवश्यकता पर ध्यान दिया जो सामाजिक वानिकी कार्यक्रम का

⁶²⁴The Constitution of India, 1950, art. 371A(1): "Special provision with respect to the State of Nagaland. — (1) Notwithstanding anything in this Constitution, — (a) no Act of Parliament in respect of — (i) religious or social practices of the Nagas; (ii) Nagas customary law and procedure; (iii) administration of civil and criminal justice involving decisions according to Naga customary law; (iv) ownership and transfer of land and its resources, shall apply to the State of Nagaland unless the Legislative Assembly of Nagaland by a resolution so decides."

⁶²⁵The Constitution of India, 1950, art. 371G: "Special provision with respect to the State of Mizoram. — Notwithstanding anything in this Constitution, — (a) no Act of Parliament in respect of — (i) religious or social practices of the Mizos; (ii) Mizo customary law and procedure; (iii) administration of civil and criminal justice involving decisions according to Mizo customary law; (iv) ownership and transfer of land; shall apply to the State of Mizoram unless the Legislative Assembly of the State of Mizoram by a resolution so decides: Provided that nothing in this clause shall apply to any Central Act in force in the Union territory of Mizoram immediately before the commencement of the Constitution (Fifty-third Amendment) Act, 1985; (b) the Legislative Assembly of the State of Mizoram shall consist of not less than forty members."

⁶²⁶Orissa Mining Corporation v. Ministry of Environment and Forests (2013) 6 SCC 476.

⁶²⁷Id. at para. 63.

⁶²⁸T.N. Godavarman Thirumulkpad v. Union of India (1997) 2 SCC 267.

हिस्सा हैं और सरकारी योजना के अनुसार बढ़ना और काटना जारी रख सकते हैं। इस प्रकार, न्यायालयों ने वन-निवासी समुदायों की पारंपरिक और सांस्कृतिक प्रथाओं को पारिस्थितिक संरक्षण के साथ संतुलित किया है।

कुल मिलाकर, इन प्रावधानों और मामलों से एक स्तरित संवैधानिक योजना का पता चलता है, जिसमें मौलिक अधिकार आधार रेखा बनाते हैं, जबकि छठी अनुसूची और अनुच्छेद 371ए और 371जी जैसे विशेष प्रावधान आदिवासी समुदायों के लिए संदर्भ-विशिष्ट सुरक्षा को सुरक्षित करते हैं। न्यायपालिका के साथ, जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, मामलों के माध्यम से, यह रेखांकित करता है कि आदिवासी लोगों के लिए सांस्कृतिक और धार्मिक स्वतंत्रता अमूर्त विश्वास से परे है और उनके पवित्र परिदृश्य, पारंपरिक अनुष्ठानों और सामूहिक विरासत के संरक्षण को शामिल करती है।

4. विधायी संरक्षण

अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों की रक्षा के लिए भारतीय कानूनी ढांचे में कानूनों का एक विस्तृत नेटवर्क शामिल है जो भेदभाव का मुकाबला करने, उनकी भूमि और संसाधनों के शोषण को रोकने और उनकी सांस्कृतिक स्वायत्तता की रक्षा करते हुए सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा देने का प्रयास करता है।

4.1. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (पीओए अधिनियम, 1989) को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों के सदस्यों के खिलाफ अत्याचारों को रोकने और दंडित करने के लिए अधिनियमित किया गया था। पीओए अधिनियम, 1989, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों द्वारा सामना किए जाने वाले ऐतिहासिक उत्पीड़न और सामाजिक बहिष्कार को मान्यता देता है और उनकी जाति या आदिवासी पहचान के कारण उनके खिलाफ किए गए विशिष्ट कृत्यों को अपराधी बनाकर उनकी गरिमा को बनाए रखने का प्रयास करता है। पी. ओ. ए. अधिनियम, 1989, ऐसे अपराधों की सुनवाई के साथ-साथ पीड़ितों की राहत और पुनर्वास के लिए विशेष अदालतों का प्रावधान करता है। यह मुकदमे के दौरान सुरक्षा, स्थानांतरण, खर्च और पुनर्वास सुनिश्चित करता है और अदालतों को पहचान छिपाने, उत्पीड़न को रोकने और सुरक्षात्मक आदेश पारित करने की अनुमति देता है। प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ. आई. आर.) को तुरंत दर्ज किया जाना चाहिए और प्रतियां निःशुल्क प्रदान की जानी चाहिए। सभी कार्यवाही को वीडियो रिकॉर्ड किया जाना है, और राज्यों को राहत, चिकित्सा सहायता, आश्रय, भत्ते, कानूनी सहायता और मामले की स्थिति पर अपडेट प्रदान करने के लिए योजनाएं बनानी चाहिए। पीड़ित और आश्रित सभी चरणों में गैर-सरकारी संगठनों, सामाजिक कार्यकर्ताओं या अधिवक्ताओं से भी सहायता ले सकते हैं।

पी. ओ. ए. अधिनियम, 1989 की धारा 3 अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति समुदायों के सदस्यों के खिलाफ अत्याचार माने जाने वाले अपराधों की एक विस्तृत श्रृंखला को सूचीबद्ध करती है।⁶²⁹ इनमें शामिल हैं:

- किसी सदस्य को अखाद्य या अप्रिय पदार्थों को खाने/पीने के लिए मजबूर करना;
- मलमूत्र, सीवेज, शव या अन्य अप्रिय पदार्थों को उनके परिसर में/उसके पास फेंकना;
- जूतों के साथ माला पहनना, नग्न/अर्ध-नग्न परेड करना, या गरिमा के लिए अपमानजनक इसी तरह के कार्य;⁶²⁹
- उन्हें उनकी भूमि से गलत तरीके से कब्जा/बेदखल करना या उनके वन या जल अधिकारों में हस्तक्षेप करना;

⁶²⁹The Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989, s.3.

- बेगार, बंधुआ श्रम, हाथ से मैला निकालना या शव निपटान के लिए मजबूर करना;
- अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की महिलाओं को देवदासी के रूप में या इसी तरह की किसी भी प्रथा के लिए समर्पित करना;
- मतदान के अधिकार, नामांकन या पंचायत/नगरपालिका कर्तव्यों के प्रदर्शन को रोकना या मजबूर करना; अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी भी सदस्य को मतदान, नामांकन दाखिल करने या समर्थन करने सहित चुनावी अधिकारों का प्रयोग करने से धमकी देना, मजबूर करना या रोकना;
- उन्हें पंचायतों/नगर पालिकाओं के सदस्यों या अध्यक्षों के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन करने से रोकना या डराना; चुनाव के बाद उन पर हमला करना, बहिष्कार करना या सार्वजनिक सेवाओं से वंचित करना;
- लोक सेवकों को गलत जानकारी देना और इस तरह अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को चोट पहुंचाना या परेशान करना;
- सार्वजनिक रूप से जाति के नाम से जानबूझकर उनका अपमान करना, उन्हें अपमानित करना या गाली देना; अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति समुदायों द्वारा पवित्र मानी जाने वाली वस्तुओं को अपवित्र करना/नुकसान पहुंचाना;
- अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के खिलाफ शत्रुता या नफरत को बढ़ावा देना, जिसमें उनके सम्मानित नेताओं का अनादर करना शामिल है;
- अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की महिलाओं का यौन उत्पीड़न या हमला (प्राप्तकर्ता की सहमति के बिना यौन प्रकृति के स्पर्श, शब्द, कार्य या इशारे) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति द्वारा आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले जल स्रोतों को भ्रष्ट करना या दूषित करना;
- अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति द्वारा उपयोग किए जाने वाले जल स्रोतों को सार्वजनिक स्थानों, पूजा स्थलों, शिक्षा, स्वास्थ्य केंद्रों, या सार्वजनिक उपयोगिताओं तक पहुंच से इनकार करना;
- सार्वजनिक स्थानों पर दफनाने की प्रक्रिया के उपयोग जैसे अधिकारों को बाधित करना, सार्वजनिक आवासों में कपड़े पहनना या जादू-टोना पहनना, आर्थिक बहिष्कार करना;
- अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति द्वारा आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले जल स्रोतों को भ्रष्ट करना या दूषित करना;
- सार्वजनिक स्थानों, पूजा स्थलों, शिक्षा, स्वास्थ्य केंद्रों या सार्वजनिक उपयोगिताओं तक पहुंच से इनकार

पीओए अधिनियम, 1989 के कुछ प्रावधानों की संवैधानिक वैधता को चुनौती देते हुए, *मध्य प्रदेश राज्य बनाम राम कृष्ण बालोतिया* ⁶³⁰ के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि पीओए अधिनियम, 1989 के तहत “अपराध एक अलग वर्ग का गठन करते हैं और दंड संहिता के तहत अन्य अपराधों के साथ उनकी तुलना नहीं की जा सकती है” सर्वोच्च न्यायालय ने कहा ये अपराध अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों को अपमानित करने और उन्हें गुलाम बनाए रखने के इरादे से उनके ऊपर अपना

⁶³⁰ *State of Madhya Pradesh v. Ram Krishna Balothia* (1995) 3 SCC 221.

वर्चस्व कायम करने के लिए किए जाते हैं।⁶³¹

पाटन जमाल वली बनाम आंध्र प्रदेश राज्य,⁶³² के मामले में उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया कि वैधानिक भाषा पी. ओ. ए. अधिनियम, 1989 की धारा 3 (2) के तहत 'केवल आधार पर' नहीं बल्कि 'आधार पर' वाक्यांश का उपयोग करती है। इस प्रकार, 'केवल' शब्द को सम्मिलित करने से विधायिका द्वारा इच्छित संरक्षण का दायरा अनुचित रूप से सीमित हो जाएगा। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि एक पारस्परिक दृष्टिकोण के लिए इस मान्यता की आवश्यकता होती है कि उत्पीड़न अक्सर एक एकल, पृथक आधार के बजाय जाति, लिंग और विकलांगता जैसी कई, अतिव्यापी पहचानों का उत्पाद होता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि कानून का सुरक्षात्मक इरादा कमजोर न हो और सबसे हाशिए पर रहने वालों के अनुभव अदृश्य न हों।⁶³³ यह तर्क अनुसूचित जनजातियों के संदर्भ में भी समान रूप से प्रासंगिक है, जहां भेदभाव और हिंसा केवल जनजातीय पहचान से ही नहीं, बल्कि भूमिहीनता, विस्थापन या लिंग जैसे कारकों के साथ इसके प्रतिच्छेदन से भी हो सकती है। इसलिए, इस पारस्परिकता को स्वीकार करने से यह सुनिश्चित होता है कि सामाजिक बहिष्कार और संरचनात्मक असमानताओं दोनों द्वारा आकार दिए गए आदिवासी समुदायों की जीवित वास्तविकताओं को सार्थक रूप से संबोधित किया जाए।

पी. ओ. ए. अधिनियम, 1989 के तहत अभियोजन में, धारा 8 सबूत का भार अभियुक्त पर डालती है। इसके अलावा, विशेष अदालतें यह मान लेंगे कि यदि आरोपी ने किए गए अत्याचार के संबंध में वित्तीय सहायता प्रदान की, तो उसने उकसाया है, यदि अपराध एक समूह द्वारा किया गया था, तो सामान्य इरादे का अनुमान लगाते हैं, और जाति/आदिवासी पहचान का ज्ञान मानते हैं यदि आरोपी पीड़ित या पीड़ित के परिवार को व्यक्तिगत रूप से जानता था, जब तक कि इसके विपरीत साबित न हो जाए।⁶³⁴ इस प्रकार धारा 8 खंडन योग्य उपधारणाओं के माध्यम से जाति/जनजाति आधारित अत्याचारों में इरादे या ज्ञान को साबित करने की ऐतिहासिक कठिनाई को पहचानती है और उससे निपटती है।

त्वरित सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए, धारा 14 में एक या अधिक जिलों के लिए विशेष न्यायालयों और विशेष विशेष न्यायालयों की स्थापना का प्रावधान है। धारा 14 में यह भी प्रावधान है कि पीओए अधिनियम, 1989 के तहत अपराधों से संबंधित कोई भी मुकदमा आरोप पत्र दाखिल करने की तारीख से दो महीने की अवधि के भीतर पूरा

⁶³¹ *Id.* at para. 10.

⁶³² *Patan Jamal Valiv. State of Andhra Pradesh* (2021) SCC OnLine 343.

⁶³³ *Id.* at paras. 54-59.

⁶³⁴ The Scheduled Castes and The Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989, s. 8: "Presumption as to offences. — In a prosecution for an offence under this Chapter, if it is proved that— (a) the accused rendered any financial assistance in relation to the offences committed by a person accused of, or reasonably suspected of, committing, an offence under this Chapter, the Special Court shall presume, unless the contrary is proved, that such person had abetted the offence; (b) a group of persons committed an offence under this Chapter and if it is proved that the offence committed was a sequel to any existing dispute regarding land or any other matter, it shall be presumed that the offence was committed in furtherance of the common intention or in prosecution of the common object; (c) the accused was having personal knowledge of the victim or his family, the Court shall presume that the accused was aware of the caste or tribal identity of the victim, unless the contrary is proved."

भीतर पूरा किया जाएगा।⁶³⁵

धारा 15ए पीड़ितों, उनके आश्रितों और गवाहों को धमकी, जबरदस्ती या हिंसा से बचाने के लिए राज्य के कर्तव्य को स्थापित करती है। यह निर्दिष्ट किया गया है कि पीड़ितों के साथ निष्पक्षता और गरिमा के साथ व्यवहार किया जाना चाहिए और जमानत, पैरोल, दोषसिद्धि या सजा सहित सभी कार्यवाही के बारे में सूचित किया जाना चाहिए। उन्हें कार्यवाही में भाग लेने, साक्ष्य तलब करने और लिखित प्रस्तुतियाँ दायर करने का अधिकार है। इस खंड के महत्व और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सामने आने वाली बाधाओं को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा *हरिराम भाम्भी बनाम सत्यनारायण* के मामले में उजागर किया गया था।⁶³⁶ न्यायालय ने पीओए अधिनियम, 1989 के तहत न्याय प्राप्त करने में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों के सदस्यों के सामने आने वाली प्रणालीगत समस्याओं को रेखांकित किया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि पीड़ित अक्सर प्रतिशोध, अज्ञानता या पुलिस की उदासीनता के डर से शिकायत दर्ज करने में संकोच करते हैं। यहां तक कि जब शिकायतें दर्ज की जाती हैं, तब भी उन्हें गलत तरीके से दर्ज किया जा सकता है। इसके अलावा, जांच और अभियोजन अक्सर लापरवाही करते हैं, जिससे दोषसिद्धि की दर कम हो जाती है। इससे पीओए अधिनियम, 1989 के दुरुपयोग की गलत धारणा पैदा होती है, जबकि वास्तव में, कई दोषमुक्तियां दोषपूर्ण आपराधिक प्रक्रियाओं से उत्पन्न होती हैं।⁶³⁷ इसे स्वीकार करते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि धारा 15ए जैसे प्रावधान, जो पीड़ितों को कार्यवाही के विभिन्न चरणों में सुनवाई के अधिकार की गारंटी देते हैं, न्याय तक सार्थक पहुंच सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण हैं।⁶³⁸

धारा 18 और 18ए पीओए अधिनियम, 1989 के तहत अपराधों के संबंध में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 के तहत अग्रिम जमानत देने पर रोक लगाती है।⁶³⁹ धारा 18 और 18ए आगे स्पष्ट करते हैं कि प्राथमिकी दर्ज करने के लिए किसी प्रारंभिक जांच की आवश्यकता नहीं है और जांच अधिकारियों को किसी आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है। धारा 18 और 18ए मामलों के त्वरित पंजीकरण और जांच को सुनिश्चित करते हुए किसी

⁶³⁵The Scheduled Castes and The Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989, s. 14: “Special Court and Exclusive Special Court. — (1) For the purpose of providing for speedy trial, the State Government shall, with the concurrence of the Chief Justice of the High Court, by notification in the Official Gazette, establish an Exclusive Special Court for one or more Districts: Provided that in Districts where less number of cases under this Act is recorded, the State Government shall, with the concurrence of the Chief Justice of the High Court, by notification in the Official Gazette, specify for such Districts, the Court of Session to be a Special Court to try the offences under this Act: Provided further that the Courts so established or specified shall have power to directly take cognizance of offences under this Act. (2) It shall be the duty of the State Government to establish an adequate number of Courts to ensure that cases under this Act are disposed of within a period of two months, as far as possible. (3) In every trial in the Special Court or the Exclusive Special Court, the proceedings shall be continued from day-to-day until all the witnesses in attendance have been examined, unless the Special Court or the Exclusive Special Court finds the adjournment of the same beyond the following day to be necessary for reasons to be recorded in writing: Provided that when the trial relates to an offence under this Act, the trial shall, as far as possible, be completed within a period of two months from the date of filing of the chargesheet.”

⁶³⁶Hariram Bhambhiv. Satyanarayan, 2021 INSC 701.

⁶³⁷Id. at para. 12.

⁶³⁸Id. at para. 13.

⁶³⁹The Scheduled Castes and The Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989, s. 18: “Section 438 of the Code not to apply to persons committing an offence under the Act. — Nothing in section 438 of the Code shall apply in relation to any case involving the arrest of any person on an accusation of having committed an offence under this Act.”

भी विपरीत न्यायिक निर्देशों को भी अधिभावी करती हैं।⁶⁴⁰ ये धाराएँ विवाद में रही हैं और सर्वोच्च न्यायालय ने कई मामलों के माध्यम से अपना रुख स्पष्ट किया है। सुभाष काशीनाथ महाजन बनाम महाराष्ट्र राज्य,⁶⁴¹ के मामले में उच्चतम न्यायालय ने चिंता व्यक्त की कि पी. ओ. ए. अधिनियम, 1989 के कार्यकरण का परिणाम जातिवाद को कायम रखने में नहीं होना चाहिए, जिसका समाज के एकीकरण और संवैधानिक मूल्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।⁶⁴² इसमें यह माना गया कि उन मामलों में अग्रिम जमानत देने के खिलाफ कोई पूर्ण प्रतिबंध नहीं है जहां कोई प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनता है या जहां न्यायिक जांच पर शिकायत प्रथम दृष्टया दुर्भावनापूर्ण पाई जाती है।⁶⁴³ सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि किसी निर्दोष के झूठे निहितार्थ से बचने के लिए, यह पता लगाने के लिए कि क्या आरोप लगाए गए हैं, संबंधित पुलिस उपाधीक्षक द्वारा प्रारंभिक जांच की जा सकती है।⁶⁴⁴

इन निर्देशों के पारित होने के बाद, संसद ने इन दिशानिर्देशों के प्रभाव को पूर्ववत करने के लिए पीओए अधिनियम, 1989 में संशोधन किया। इन संशोधनों को प्रथम राज चौहान बनाम भारत संघ,⁶⁴⁵ के मामले में असफल रूप से चुनौती दी गई थी, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था: "जब तक अधिनियम के प्रावधानों को उनके सच्चे अक्षर और भावना में, अत्यंत गंभीरता और प्रेषण के साथ लागू नहीं किया जाता है, तब तक एक जातिविहीन समाज का सपना और आदर्श केवल एक सपना, एक मरीचिका ही रहेगा। एससी/एसटी समुदायों का हाशिए पर रहना एक स्थायी बहिष्कार है और यह लगभग पूरी तरह से जाति की पहचान पर आधारित है।"⁶⁴⁶

भारत संघ बनाम महाराष्ट्र राज्य के मामले में समीक्षा याचिका में सुभाष महाजन के निर्देशों को पहले ही वापस ले लिया गया था।⁶⁴⁷ उच्चतम न्यायालय का विचार था कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति "अभी भी देश के विभिन्न क्षेत्रों में समानता और नागरिक अधिकारों के प्रयोग के लिए संघर्ष कर रहे हैं।"⁶⁴⁸ उच्चतम न्यायालय ने आगे कहा कि ऐसा कोई अनुमान नहीं है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों के सदस्य पीओए अधिनियम, 1989 के प्रावधानों का दुरुपयोग कर सकते हैं; इसके बजाय, अपने पिछड़ेपन के कारण, वे शायद ही एक प्राथमिकी दर्ज करने का साहस करते हैं, बहुत कम एक झूठी। तदनुसार, सर्वोच्च न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को बदला लेने या किसी अन्य प्रकार के लाभ के लिए झूठी रिपोर्ट दर्ज करने के लिए प्रवण माना जाना मानव

⁶⁴⁰The Scheduled Castes and The Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989, s. 18A: "No enquiry or approval required. — (1) For the purposes of this Act, — (a) preliminary enquiry shall not be required for registration of a First Information Report against any person; or (b) the investigating officer shall not require approval for the arrest, if necessary, of any person, against whom an accusation of having committed an offence under this Act has been made and no procedure other than that provided under this Act or the Code shall apply. (2) The provisions of section 438 of the Code shall not apply to a case under this Act, notwithstanding any judgment or order or direction of any Court."

⁶⁴¹Subhash Kashinath Mahajan v. The State of Maharashtra (2018) 6 SCC 454.

⁶⁴²Id. at para. 38.

⁶⁴³Id. at para. 79.2.

⁶⁴⁴Id. at para. 79.4.

⁶⁴⁵Prathvi Raj Chauhan v. Union of India (2020) 4 SCC 727.

⁶⁴⁶Id. at para. 34.

⁶⁴⁷Union of India v. State of Maharashtra (2020) 4 SCC 761.

⁶⁴⁸Id. at para. 44.

समानता के मौलिक सिद्धांतों के विपरीत है।⁶⁴⁹

इसके अलावा, धारा 21 सरकार को पीओए अधिनियम, 1989 के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए बाध्य करती है। राज्य सरकारों को आवश्यक उपाय करने चाहिए, जैसे कि पीड़ितों और गवाहों के लिए कानूनी सहायता, यात्रा और रखरखाव खर्च प्रदान करना; अत्याचार पीड़ितों का आर्थिक और सामाजिक पुनर्वास; अभियोजन की देखरेख के लिए अधिकारियों की नियुक्ति; समितियों का गठन; आवधिक सर्वेक्षण करना; और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कमजोर क्षेत्रों की पहचान करनी चाहिए। केंद्र सरकार को आगे इन प्रयासों का समन्वय करने का काम सौंपा गया है और उसे केंद्र और राज्यों दोनों द्वारा किए गए उपायों पर वार्षिक रूप से संसद को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी चाहिए।⁶⁵⁰

अदालतों ने पीओए अधिनियम, 1989 के कार्यान्वयन में सरकार के कर्तव्य पर भी जोर दिया है। दलित मानवाधिकारों पर राष्ट्रीय अभियान बनाम भारत संघ,⁶⁵¹ के मामले में उच्चतम न्यायालय ने पी. ओ. ए. अधिनियम, 1989 को लागू न करने से व्यथित एक रिट याचिका पर विचार किया। न्यायालय ने अधिनियम के गैर-कार्यान्वयन के बारे में गहरी चिंता व्यक्त की और कहा कि "पीओए अधिनियम, 1989 के प्रावधानों के अनुपालन में संबंधित अधिकारियों की ओर से विफलता हुई है",⁶⁵² इस प्रकार, अधिकारियों के उदासीन रवैये पर भी ध्यान दिया और अंत में राज्य और केंद्र सरकारों को पीओए अधिनियम को लागू करने में अपनी भूमिका को सख्ती से निभाने का निर्देश दिया।

4.2. पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996

पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996 (पेसा अधिनियम, 1996) के प्रावधानों को संविधान के भाग IX के प्रावधानों के विस्तार और संविधान के अनुच्छेद 243 एम के अनुसार पांचवीं अनुसूची क्षेत्रों में इसकी प्रयोज्यता के लिए अधिनियमित किया गया था। भूरिया समिति की सिफारिशों ने पेसा अधिनियम, 1996 के अधिनियमन का मार्ग प्रशस्त किया, जबकि भूरिया आयोग ने पांचवीं अनुसूची से लेकर आदिवासी भूमि और वन, स्वास्थ्य और शिक्षा, पंचायतों के कामकाज और आदिवासी महिलाओं की स्थिति तक कई मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया।⁶⁵³

जनजातीय मामलों के मंत्रालय की 2023-2024 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, वर्तमान में, पांचवीं अनुसूची के क्षेत्र 10 राज्यों आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश,

⁶⁴⁹*Id.* at paras. 52-54.

⁶⁵⁰*The Scheduled Castes and The Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989*, s. 21.

⁶⁵¹*National Campaign on Dalit Human Rights v. Union of India* (2017) 2 SCC 432.

⁶⁵²*Id.* at para. 18.

⁶⁵³Ministry of Tribal Affairs, *Report of the High Level Committee on Socioeconomic, Health and Educational Status of Tribal Communities of India* (May 2014), available at: <https://ruralindiaonline.org/en/library/resource/report-of-the-high-level-committee-on-socio-economic-health-and-educational-status-of-the-tribals-of-india/> (last visited on Nov. 12, 2025)

महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान और तेलंगाना में मौजूद हैं।⁶⁵⁴ इस प्रकार, पेसा अधिनियम, 1996, प्राकृतिक संसाधनों, विकास योजना और सामाजिक-सांस्कृतिक मामलों पर व्यापक अधिकार के साथ अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभाओं और पंचायतों को सशक्त बनाकर अनुसूचित जनजातियों के लिए स्वशासन के सिद्धांतों को कार्यान्वित करता है।

पेसा अधिनियम, 1996 की धारा 4 संविधान के भाग IX में संशोधनों को निर्धारित करती है। धारा 4 (ए) में कहा गया है कि अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों पर राज्य के कानूनों को प्रथागत कानूनों, सामाजिक और धार्मिक प्रथाओं और सामुदायिक संसाधनों के पारंपरिक प्रबंधन का सम्मान करना चाहिए।⁶⁵⁵ गाँव को धारा 4 (बी)⁶⁵⁶ के तहत रीति-रिवाजों के अनुसार मामलों का प्रबंधन करने वाली बस्ती या बस्तियों के समूह के रूप में परिभाषित किया गया है और धारा 4 (सी) के अनुसार प्रत्येक गाँव में सभी मतदाताओं की एक ग्राम सभा है।⁶⁵⁷

धारा 4 (घ) के तहत ग्राम सभाओं को परंपराओं, सांस्कृतिक पहचान, सामुदायिक संसाधनों और विवाद समाधान प्रथाओं की रक्षा करने का काम सौंपा गया है।⁶⁵⁸ उड़ीसा खनन निगम लिमिटेड बनाम पर्यावरण और वन मंत्रालय के मामले में उच्चतम न्यायालय ने उल्लेख किया कि पेसा अधिनियम, 1996 संविधान के भाग IX के प्रावधानों को अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तारित करता है, जिसमें धारा 4 (घ) विशेष रूप से प्रत्येक ग्राम सभा को सशक्त बनाती है। तदनुसार, अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006, जिसे पेसा अधिनियम, 1996 के साथ पढ़ा जाता है, के तहत कार्य करने वाली ग्राम सभा का कर्तव्य इन अधिकारों की रक्षा करना है।⁶⁵⁹

धारा 4 (ई) और 4 (एफ) में यह भी निर्दिष्ट किया गया है कि ग्राम सभाओं को विकास योजनाओं को मंजूरी देनी चाहिए और कल्याणकारी योजनाओं के तहत लाभार्थियों की पहचान करनी चाहिए और पंचायतों द्वारा धन के उपयोग को प्रमाणित करना चाहिए।⁶⁶⁰ धारा 4 (छ) आगे

⁶⁵⁴ Government of India, "Annual Report 2023-24" (Ministry of Tribal Affairs, 2024); Ministry of Panchayat Raj, *State wise details of notified Fifth Schedule Areas*, available at: <https://panchayat.gov.in/en/state-wise-details-of-notified-fifth-schedule-areas/> (last visited on Oct. 15, 2025).

⁶⁵⁵ The Panchayats (Extension to the Scheduled Areas) Act, 1996, s. 4: "(a) a State legislation on the Panchayats that may be made shall be in consonance with the customary law, social and religious practices and traditional management practices of community resources."

⁶⁵⁶ The Panchayats (Extension to the Scheduled Areas) Act, 1996, s. 4: "(b) a village shall ordinarily consist of a habitation or a group of habitations or a hamlet or a group of hamlets comprising a community and managing its affairs in accordance with traditions and customs."

⁶⁵⁷ The Panchayats (Extension to the Scheduled Areas) Act, 1996, s. 4: "(c) every village shall have a Gram Sabha consisting of persons whose names are included in the electoral rolls for the Panchayat at the village level."

⁶⁵⁸ The Panchayats (Extension to the Scheduled Areas) Act, 1996, s. 4: "(d) every Gram Sabha shall be competent to safeguard and preserve the traditions and customs of the people, their cultural identity, community resources and the customary mode of dispute resolution."

⁶⁵⁹ *Orissa Mining Corporation Limited v. Ministry of Environment and Forest* (2013) 6 SCC 476, para. 57.

⁶⁶⁰ The Panchayats (Extension to the Scheduled Areas) Act, 1996, s. 4: "(e) every Gram Sabha shall — (i) approve the plans, programmes and projects for social and economic development before such plans, programmes and projects are taken up for implementation by the Panchayat at the village level; (ii) be responsible for the identification or selection of persons as beneficiaries under the poverty alleviation and other programmes."

जनजातीय आबादी के अनुपात में अनुसूचित क्षेत्रों में सीटों के आरक्षण को अनिवार्य करती है, जिसमें कम से कम आधा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित होता है और सभी स्तरों पर सभी अध्यक्ष पद अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित होते हैं।⁶⁶¹ अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों के संबंध में, अनुच्छेद 243 एम (4) (बी) लचीलापन प्रदान करता है जो पेसा अधिनियम, 1996 के अधिनियमन को सक्षम बनाता है, जो आमतौर पर आनुपातिक प्रतिनिधित्व के मानदंड का पालन करता है, लेकिन अनुसूचित जनजातियों के हितों को सुरक्षित करने के लिए जानबूझकर इससे अलग हो जाता है।

इस विचलन को भारत संघ बनाम राकेश कुमार,⁶⁶² में उच्चतम न्यायालय द्वारा बरकरार रखा गया था, जहां न्यायालय ने मान्यता दी थी कि उन क्षेत्रों में भी जहां अनुसूचित जनजातियां बहुसंख्यक हैं, वे अक्सर शासन में कम प्रतिनिधित्व करते हैं और गैर-जनजातीय आबादी के प्रभुत्व के लिए अतिसंवेदनशील रहते हैं। न्यायालय ने कहा कि भूमि पर कब्जा, विकास परियोजनाओं के कारण विस्थापन और प्राकृतिक संसाधनों के दोहन जैसे संरचनात्मक नुकसानों के लिए सुरक्षा उपायों को बढ़ाने की आवश्यकता है। इसलिए, आनुपातिक प्रतिनिधित्व पर अनुसूचित जनजातियों को प्राथमिकता देने के लिए विधायिका के विकल्प का एक तर्कसंगत आधार पाया गया, जिसका उद्देश्य औपचारिक समावेश के बजाय पर्याप्त सशक्तिकरण सुनिश्चित करना था।

इसके अलावा, धारा 4 (एम) (ii) एक महत्वपूर्ण प्रावधान है जो जनजातीय अधिकारों को मान्यता देता है, जिसमें कहा गया है कि ग्राम सभाओं में स्पष्ट रूप से लघु वन उपज पर स्वामित्व निहित है। इस प्रकार, धारा 4 (एम) (i) से (vii) में बताया गया है कि ग्राम सभाओं और पंचायतों को मादक पदार्थों को विनियमित करने, भूमि अलगाव को रोकने, ग्राम बाजारों का प्रबंधन करने, आदिवासियों को धन-ऋण देने पर नियंत्रण करने और स्थानीय योजनाओं और सामाजिक क्षेत्र के संस्थानों की देखरेख करने की शक्तियां दी गई हैं।⁶⁶³

राज्य विधानसभाओं को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि उच्च-स्तरीय पंचायतें धारा 4 (एन)⁶⁶⁴ के अनुसार निचली पंचायतों या ग्राम सभाओं की शक्तियों को ग्रहण न करें, जिसमें धारा 4 (ओ) विधायिका को छठी अनुसूची पर

The Panchayats (Extension to the Scheduled Areas) Act, 1996, s.4:“(f) every Panchayat at the village level shall be required to obtain from the Gram Sabha a certification of utilisation of funds by that Panchayat for the plans, programmes and projects referred to in clause (e).”

⁶⁶¹*The Panchayats (Extension to the Scheduled Areas) Act, 1996, s.4:“(g) the reservation of seats in the Scheduled Areas at every Panchayat shall be in proportion to the population of the communities in that Panchayat for whom reservation is sought to be given under Part IX of the Constitution: Provided that the reservation for the Scheduled Tribes shall not be less than one-half of the total number of seats: Provided further that all seats of Chairpersons of Panchayats at all levels shall be reserved for the Scheduled Tribes.”*

⁶⁶²*Union of India v. Rakesh Kumar* (2010) 4 SCC 50, paras. 36-37.

⁶⁶³*The Panchayats (Extension to the Scheduled Areas) Act, 1996, s.4:“(m) while endowing Panchayats in the Scheduled Areas with such powers and authority as may be necessary to enable them to function as institutions of self-government, a State Legislature shall ensure that the Panchayats at the appropriate level and the Gram Sabha are endowed specifically with— (i) the power to enforce prohibition or to regulate or restrict the sale and consumption of any intoxicant; (ii) the ownership of minor forest produce; (iii) the power to prevent alienation of land in the Scheduled Areas and to take appropriate action to restore any unlawfully alienated land of a Scheduled Tribe; (iv) the power to manage village markets by whatever name called; (v) the power to exercise control over money lending to the Scheduled Tribes; (vi) the power to exercise control over institutions and functionaries in all social sectors; (vii) the power to control over local plans and resources for such plans including tribal subplans.”*

⁶⁶⁴*The Panchayats (Extension to the Scheduled Areas) Act, 1996, s.4:“(n) the State legislations that may endow Panchayats with powers and authority as may be necessary to enable them to function as institutions of self-government shall contain safeguards to ensure that Panchayats at the higher level do not assume the powers and authority of any Panchayat at the lower level or of the Gram Sabha.”*

प्रशासनिक व्यवस्था करने का निर्देश देती है।⁶⁶⁵

4.3. अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006, जिसे वन अधिकार अधिनियम, 2006 (एफआरए, 2006) के रूप में भी जाना जाता है, को वन-निवासी अनुसूचित जनजातियों और अन्य पारंपरिक वनवासियों को पहचानने और अधिकार देने के लिए अधिनियमित किया गया था, जो पीढ़ियों से ऐसे जंगलों में रह रहे हैं।

एफ. आर. ए., 2006, 'वन में रहने वाली अनुसूचित जनजातियों' को "अनुसूचित जनजातियों के सदस्य या समुदाय के रूप में परिभाषित करता है जो मुख्य रूप से रहते हैं और जो वास्तविक आजीविका की जरूरतों के लिए जंगलों या वन भूमि पर निर्भर हैं और इसमें अनुसूचित जनजाति के चरवाहे समुदाय शामिल हैं।"⁶⁶⁶ इस परिभाषा में स्पष्ट रूप से अनुसूचित जनजाति के पशुपालक समुदाय,⁶⁶⁷ समूह शामिल हैं जो मौसमी रूप से भूमि के व्यापक क्षेत्रों में पालतू जानवरों के झुंडों का प्रबंधन और चराई करते हैं, जिससे न केवल बसे हुए वनवासियों को सुरक्षा मिलती है। एफआरए, 2006 इस प्रकार यह सुनिश्चित करता है कि वनों पर जनजातीय निर्भरता के विविध पैटर्न, चाहे निवास, खेती, चराई या देहाती गतिविधियों के लिए, औपचारिक रूप से इसके कानूनी ढांचे के भीतर स्वीकार किए जाते हैं।

वन-निवास अनुसूचित जनजातियों के साथ, एफआरए, 2006, ओटीएफडी को भी परिभाषित करता है। धारा 2 (ओ) के तहत ओटीएफडी में कोई भी सदस्य या समुदाय शामिल है, जो कम से कम तीन पीढ़ियों के लिए, जो 75 वर्ष से कम की अवधि नहीं है, मुख्य रूप से वन या वन भूमि में रहता है और अपनी वास्तविक आजीविका की जरूरतों के लिए उस पर निर्भर है।⁶⁶⁸ वन-निवासी अनुसूचित जनजातियों के विपरीत, ओटीएफडी अधिकारों की एक स्वचालित धारणा का आनंद नहीं लेते हैं; उन्हें निर्धारित साक्ष्य के माध्यम से निरंतर निवास और वन निर्भरता का प्रदर्शन करना चाहिए। यह अंतर यह सुनिश्चित करता है कि एफआरए, 2006 में लंबे समय से बसे वन-निर्भर समुदायों को शामिल किया गया है, लेकिन यह अस्थायी या हाल ही में रहने वालों द्वारा दुरुपयोग को रोकता है।

एफआरए, 2006 की धारा 3 (1) वन-निवासी अनुसूचित जनजातियों और ओटीएफडी के निम्नलिखित मूल अधिकारों को मान्यता देती है और उनकी रक्षा करती है:⁶⁶⁹

⁶⁶⁵The Panchayats (Extension to the Scheduled Areas) Act, 1996, s.4: "(o) the State Legislatures shall endeavour to follow the pattern of the Sixth Schedule to the Constitution while designing the administrative arrangements in the Panchayats at district levels in the Scheduled Areas."

⁶⁶⁶The Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006, s.2(c).

⁶⁶⁷Centre for Pastoralism, available at: <https://centreforpastoralism.org/> (last visited on Oct. 7, 2025).

⁶⁶⁸The Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006, s.2(o).

⁶⁶⁹The Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006, s.3: "Forest rights of forest dwelling Scheduled Tribes and other traditional forest dwellers.-(1) For the purposes of this Act, the following rights, which secure individual or community tenure or both, shall be the forest rights of forest dwelling Scheduled Tribes and other traditional forest dwellers on all forest lands, namely:-(a) right to hold and live in the forest land under the

- निवास या स्व-खेती के लिए वन भूमि पर रहने और रहने का अधिकार;
- निस्तार जैसे सामुदायिक अधिकार और मछली पकड़ने, चराई और जल संसाधनों तक पहुंच;
- लघु वन उपज का स्वामित्व और निपटान;
- आदिम समूहों के लिए आवास और निवास के सामुदायिक कार्यकाल;
- पट्टों या पट्टा को टाइटल और वन गांवों को राजस्व गांवों में बदलने का अधिकार;
- सामुदायिक वन संसाधनों की रक्षा, फिर से उगाने, संरक्षण और प्रबंधन का अधिकार;
- बौद्धिक संपदा और पारंपरिक ज्ञान का अधिकार, और जैव विविधता तक पहुंच;
- 13 दिसंबर 2005 से पहले अवैध बेदखली के मामलों में यथास्थिति पुनर्वास।

सुप्रीम कोर्ट, T.N. के मामले में। गोडावर्मेन तिरुमुलपद बनाम भारत संघ ने राजस्थान के पवित्र उपवनों/ओरानों के संरक्षण पर एक अंतर्वर्ती आवेदन की सुनवाई करते हुए माना कि एफआरए, 2006, धारा 3 के तहत, "स्पष्ट रूप से प्रथागत वन संसाधनों पर सामुदायिक अधिकारों को स्वीकार करता है और उनके संरक्षण को अनिवार्य करता है।"⁶⁷⁰ हालांकि, धारा 3 (2), ग्राम सभा के अनुमोदन के अधीन, स्कूलों और औषधालयों जैसी सार्वजनिक सुविधाओं के लिए वन भूमि के सीमित व्यपवर्तन की अनुमति देती है।⁶⁷¹

individual or common occupation for habitation or for self-cultivation for livelihood by a member or members of a forest dwelling Scheduled Tribe or other traditional forest dwellers; (b) community rights such as nistar, by whatever name called, including those used in erstwhile Princely States, Zamindari or such intermediary regimes; (c) right of ownership, access to collect, use, and dispose of minor forest produce which has been traditionally collected within or outside village boundaries; (d) other community rights of uses or entitlements such as fish and other products of water bodies, grazing (both settled or transhumant) and traditional seasonal resource access of nomadic or pastoralist communities; (e) rights including community tenures of habitat and habitation for primitive tribal groups and pre-agricultural communities; (f) rights in or over disputed lands under any nomenclature in any State where claims are disputed; (g) rights for conversion of Pattas or leases or grants issued by any local authority or any State Government on forest lands to titles; (h) rights of settlement and conversion of all forest villages, old habitation, unsurveyed villages and other villages in forests, whether recorded, notified or not into revenue villages; (i) right to protect, regenerate or conserve or manage any community forest resource which they have been traditionally protecting and conserving for sustainable use; (j) rights which are recognised under any State law or laws of any Autonomous District Council or Autonomous Regional Council or which are accepted as rights of tribals under any traditional or customary law of the concerned tribes of any State; (k) right of access to biodiversity and community right to intellectual property and traditional knowledge related to biodiversity and cultural diversity; (l) any other traditional right customarily enjoyed by the forest dwelling Scheduled Tribes or other traditional forest dwellers, as the case may be, which are not mentioned in clauses (a) to (k) but excluding the traditional right of hunting or trapping or extracting apart of the body of any species of wild animal; (m) right to insitu rehabilitation including alternative land in cases where the Scheduled Tribes and other traditional forest dwellers have been illegally evicted or displaced from forest land of any description without receiving their legal entitlement to rehabilitation prior to the 13th day of December, 2005."

⁶⁷⁰ In Re: T.N. Godavarman Thirumulpad v. Union of India, 2024 INSC 997, para. 43.

⁶⁷¹ The Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006, s. 3: "Forest rights of Forest dwelling Scheduled Tribes and other traditional forest dwellers. — (2) Notwithstanding anything contained in the Forest (Conservation) Act, 1980 (59 of 1980), the Central Government shall provide for diversion of forest land for the following facilities managed by the Government which involve felling of trees not exceeding seventy-five trees per hectare, namely:— (a) schools; (b) dispensary or hospital; (c) anganwadis; (d) fair price shops; (e) electric and telecommunication lines; (f) tanks and other minor water bodies; (g) drinking water supply and water pipelines; (h) water or rain water harvesting structures; (i) minor irrigation canals; (j) non-conventional source of energy; (k) skill upgradation or vocational training centres; (l) roads; and (m) community centres: Provided that such diversion of forest land shall be allowed only if, — (i) the

धारा 4 (3)-(4) 13 दिसंबर 2005 से पहले व्यवसाय की मान्यता को प्रतिबंधित करती है और दोनों पति-पत्नियों के नाम पर संयुक्त रूप से पंजीकृत होने के लिए अधिकारों को वंशानुगत लेकिन गैर-हस्तांतरणीय बनाती है।⁶⁷² धारा 4 (5) मान्यता और सत्यापन पूरा होने तक बेदखली को प्रतिबंधित करती है।⁶⁷³ धारा 4 (6) व्यक्तिगत अधिकारों को चार हेक्टेयर तक सीमित करती है।⁶⁷⁴ धारा 5 वन अधिकार धारकों और ग्राम सभाओं को वन्यजीवों, वनों, जैव विविधता और सांस्कृतिक विरासत की रक्षा करने का अधिकार देती है। सर्वोच्च न्यायालय ने, धारा 5 को ध्यान में रखते हुए, *T.N. गोडावर्मान तिरुमुलपद बनाम भारत संघ*⁶⁷⁵ के मामले में अवलोकन किया कि, उन्हें पहुंच को विनियमित करने और हानिकारक गतिविधियों को रोकने का अधिकार देने से उनकी 'नेतृत्व' की विरासत को संरक्षित किया जा सकेगा और भविष्य की पीढ़ियों के लिए स्थायी संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा।⁶⁷⁶

इसी प्रकार, *उड़ीसा खनन निगम लिमिटेड बनाम पर्यावरण और वन मंत्रालय* में, उच्चतम न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि ग्राम सभा का अधिकार एफआरए, 2006 की धारा 5 (डी) में उल्लिखित जिम्मेदारियों के साथ संरेखित होता है। इस प्रावधान के तहत, ग्राम सभा के पास सामुदायिक वन संसाधनों तक पहुंच को विनियमित करने और जंगली जानवरों, वनों और जैव विविधता को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने वाली किसी भी गतिविधि को रोकने की शक्ति है। उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया कि इस तरह के प्रतिकूल प्रभाव

forestland to be diverted for the purposes mentioned in this sub-section is less than one hectare in each case; and (ii) the clearance of such developmental projects shall be subject to the condition that the same is recommended by the Gram Sabha."

⁶⁷²The Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006, s.4: "Recognition of, and vesting of, forest rights in forest dwelling Scheduled Tribes and other traditional forest dwellers. – (3) The recognition and vesting of forest rights under this Act to the forest dwelling Scheduled Tribes and to other traditional forest dwellers in relation to any State or Union territory in respect of forest land and their habitat shall be subject to the condition that such Scheduled Tribes or tribal communities or other traditional forest dwellers had occupied forest land before the 13th day of December, 2005. (4) A right conferred by sub-section (1) shall be heritable but not alienable or transferable and shall be registered jointly in the name of both the spouses in case of married persons and in the name of the single head in the case of a household headed by a single person and in the absence of a direct heir, the heritable right shall pass on to the next-of-kin."

⁶⁷³The Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006, s.4: "Recognition of, and vesting of, forest rights in forest dwelling Scheduled Tribes and other traditional forest dwellers. – (5) Save as otherwise provided, no member of a forest dwelling Scheduled Tribe or other traditional forest dwellers shall be evicted or removed from forest land under his occupation till the recognition and verification procedure is complete."

⁶⁷⁴The Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006, s.4: "Recognition of, and vesting of, forest rights in forest dwelling Scheduled Tribes and other traditional forest dwellers. – (5) Where the forest rights recognised and vested by sub-section (1) are in respect of land mentioned in clause (a) of sub-section (1) of section 3 such land shall be under the occupation of an individual or family or community on the date of commencement of this Act and shall be restricted to the area under actual occupation and shall in no case exceed an area of four hectares."

⁶⁷⁵The Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006, s.5: "Duties of holders of forest rights. – The holders of any forest right, Gram Sabha and village level institutions in areas where there are holders of any forest right under this Act are empowered to – (a) protect the wild life, forest and biodiversity; (b) ensure that adjoining catchments area, water sources and other ecological sensitive areas are adequately protected; (c) ensure that the habitat of forest dwelling Scheduled Tribes and other traditional forest dwellers is preserved from any form of destructive practices affecting their cultural and natural heritage; (d) ensure that the decision taken in the Gram Sabha to regulate access to community forest resources and to any activity which adversely affects the wild animals, forest and the biodiversity are complied with."

⁶⁷⁶In *Re: T.N. Godavarman Thirumulpad v. Union of India*, 2024 INSC 997, para. 58(i).

पैदा करने वाली किसी भी गतिविधि को संबंधित अधिनियमों के प्रावधानों के अनुसार संबोधित किया जाना चाहिए।⁶⁷⁷

एफआरए, 2006 के तहत वन-निवासी अनुसूचित जनजातियों और ओटीएफडी के प्रथागत और धार्मिक अधिकारों की रक्षा के लिए, धारा 6 ग्राम सभा को 'व्यक्तिगत' या 'सामुदायिक अधिकारों' की प्रकृति और सीमा निर्धारित करने की शक्तियां प्रदान करती है।⁶⁷⁸ यह अधिकारों की मान्यता के लिए एक त्रिस्तरीय संरचना प्रदान करता है, जिसमें ग्राम सभा, फिर एक उप-मंडल समिति और अंत में एक जिला समिति शामिल है, जिसकी निगरानी एक राज्य निगरानी समिति द्वारा की जाती है।⁶⁷⁹ धारा 11 जनजातीय मामलों के मंत्रालय को नोडल एजेंसी के रूप में नामित करती है।⁶⁸⁰ धारा 13 स्पष्ट करती है कि एफ. आर. ए., 2006 अन्य लागू कानूनों के अतिरिक्त है।⁶⁸¹

इस प्रकार, एफआरए, 2006, अनुसूचित जनजातियों और ओटीएफडी के लिए भूमि कार्यकाल, आजीविका और समुदाय के नेतृत्व वाले वन प्रशासन की सुरक्षा सुनिश्चित करने में एक मील का पत्थर है।

4.4. भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्वास में उचित मुआवजे और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013

भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्वास में उचित मुआवजे और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (एलएआरआर अधिनियम, 2013) को भूमि अधिग्रहण के लिए एक निष्पक्ष, पारदर्शी और सहभागी प्रक्रिया बनाने के लिए अधिनियमित किया गया था। यह स्थानीय स्वशासन और ग्राम सभाओं के परामर्श से किया जाना है ताकि औद्योगीकरण, बुनियादी ढांचे के विकास और शहरीकरण से कम से कम व्यवधान पैदा हो। यह प्रभावित परिवारों के उचित मुआवजे, उचित पुनर्वास और पुनर्वास को सुनिश्चित करने का प्रयास करता है, जिससे वे प्रगति में भागीदार बन सकें और अधिग्रहण के बाद उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थितियों में सुधार हो सके। एल. ए. आर. अधिनियम, 2013 ने पुराने भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 को बदलने की मांग की है।

एलएआरआर अधिनियम, 2013 के परिभाषा खंड के तहत, 'प्रभावित परिवार' में विशेष रूप से अनुसूचित जनजाति और ओटीएफडी शामिल हैं, जिन्होंने भूमि अधिग्रहण के कारण एफआरए, 2006 के तहत मान्यता प्राप्त अपने किसी भी वन अधिकार को खो दिया है।⁶⁸² परिभाषा खंड एक 'भूमि मालिक' की भी व्याख्या करता है, जिसमें कोई भी व्यक्ति जिसे

⁶⁷⁷Orissa Mining Corporation Limited v. Ministry of Environment and Forest (2013) 6 SCC 476, para. 57(iv)(e).

⁶⁷⁸Id. at paras. 56, 57(iii)(a).

⁶⁷⁹The Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006, s. 6: "Authorities to vest forest rights in forest dwelling Scheduled Tribes and other traditional forest dwellers and procedure thereof."

⁶⁸⁰The Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006, s. 11: "Nodal agency.—The Ministry of the Central Government dealing with Tribal Affairs or any officer or authority authorised by the Central Government on this behalf shall be the nodal agency for the implementation of the provisions of this Act."

⁶⁸¹The Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006, s. 13: "Act not in derogation of any other law.—Save as otherwise provided in this Act and the Provisions of the Panchayats (Extension to the Scheduled Areas) Act, 1995 (40 of 1995), the provisions of this Act shall be in addition to and not in derogation of the provisions of any other law for the time being in force."

⁶⁸²The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013, s. 3: "Definition.—In this Act, unless the context otherwise requires, — (c) "affected family" includes — (iii) the Scheduled Tribes and other traditional forest dwellers who have lost any of their forest rights recognised under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2005 (20 of 2007) due to acquisition of land"

एफआरए, 2006 के तहत या किसी अन्य कानून के तहत वन अधिकार दिए गए हैं, को भी शामिल किया गया है।⁶⁸³ परिभाषा खंड में अनुसूचित जनजातियों और ओटीएफडी को शामिल करने के लिए 'इच्छुक व्यक्ति' की भी व्याख्या की गई है, जिन्होंने एफआरए, 2006 के तहत मान्यता प्राप्त कोई भी अधिकार खो दिया है।⁶⁸⁴

धारा 4 सरकार से सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए भूमि अधिग्रहण करने से पहले सामाजिक प्रभाव आकलन (एस. आई. ए.) करने की अपेक्षा करती है। एस. आई. ए. को संबंधित पंचायत, ग्राम सभा, नगर पालिका या नगर निगम के परामर्श से किया जाना चाहिए और छह महीने के भीतर पूरा किया जाना चाहिए। यह आकलन करता है कि क्या अधिग्रहण वास्तव में एक सार्वजनिक उद्देश्य को पूरा करता है, प्रभावित और विस्थापित परिवारों की संख्या का अनुमान लगाता है, प्रभावित भूमि और संपत्तियों की सीमा की जांच करता है, और विकल्पों पर विचार करता है। एस. आई. ए. को आजीविका, सामुदायिक परिसंपत्तियों, उपयोगिताओं, जनजातीय संस्थानों, कब्रिस्तानों और स्थानीय बुनियादी ढांचे पर अधिग्रहण के प्रभावों का भी मूल्यांकन करना चाहिए और इन प्रभावों को दूर करने के लिए विशिष्ट उपायों के साथ एक सामाजिक प्रभाव प्रबंधन योजना तैयार करनी चाहिए, जिससे कम से कम मौजूदा केंद्रीय या राज्य योजनाओं के बराबर सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।⁶⁸⁵

इंदौर विकास प्राधिकरण बनाम मनोहरलाल,⁶⁸⁶ के मामले में भी इसका उल्लेख किया गया है, जिसमें उच्चतम न्यायालय की पांच-न्यायाधीशों की पीठ ने एल. ए. आर. आर. अधिनियम, 2013 की धारा 24 की व्याख्या पर विचार किया था, जिसमें भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 के अधीन कुछ भूमि अधिग्रहण प्रक्रियाओं की मानित चूक का उपबंध किया गया था। यह उल्लेख किया गया कि पुराने भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 से विशेष रूप से एस. आई. ए., पुनर्वास और पुनर्वास योजना आदि से संबंधित विभिन्न परिवर्तन किए गए हैं। यह न केवल यह सुनिश्चित करता है कि उच्च मुआवजा प्रदान किया जाए, बल्कि 'सार्वजनिक' को भी परिभाषित करता है और सहमति के प्रावधान करता है। एल. ए. आर. आर. अधिनियम, 2013, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के हितों की पर्याप्त रक्षा के लिए भी कदम उठाता है। जहां विभिन्न समितियों और प्राधिकरणों का गठन किया गया है, वहीं 'प्रभावित परिवारों' की परिभाषा का भी विस्तार किया गया है। इस प्रकार, यह आवश्यक हो जाता है कि न्यायालय प्रावधानों की भाषा और अवधि को ध्यान में रखते हुए विधायी आशय को पूर्ण और सार्थक प्रभाव देने के लिए अपने प्रावधानों की व्याख्या करे।⁶⁸⁷

इसके अलावा, एलएआरआर अधिनियम, 2013 की धारा 31 का विस्तार कलेक्टर द्वारा प्रभावित परिवारों के लिए पुनर्वास और पुनर्वास पुरस्कार पर किया गया है। यह निर्दिष्ट किया गया है कि पुरस्कार में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष प्रावधानों का विवरण भी शामिल होगा। विस्थापित आदिवासी परिवारों के लिए,

⁶⁸³The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013, s. 3: "Definition.- (r) "land owner" includes any person, - (ii) any person who is granted forest rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2005 (2 of 2007) or under any other law for the time being in force"

⁶⁸⁴The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013, s. 3: "Definition.- (x) (ii) the Scheduled Tribes and other traditional forest dwellers, who have lost any forest rights recognised under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2005 (2 of 2007)"

⁶⁸⁵The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013, s. 4.

⁶⁸⁶Indore Development Authority v. Manoharlal (2020) 8 SCC 129.

⁶⁸⁷Id. at paras. 93.9-94.

यह आवास स्थलों और आवास, कृषि भूमि, एकमुश्त निर्वाह और परिवहन भत्तों के आवंटन और पशुशालाओं या छोटी दुकानों के लिए भुगतान तक फैला हुआ है। जनजातीय समुदायों के कारीगर और छोटे व्यापारी अपनी आजीविका को फिर से स्थापित करने के लिए एकमुश्त अनुदान के हकदार हैं। एल. ए. आर. आर. वार्षिकी और अन्य दीर्घकालिक हक के साथ-साथ प्रत्येक प्रभावित परिवार के एक सदस्य को अनिवार्य रोजगार की भी गारंटी देता है। यह मछली पकड़ने के अधिकारों जैसे प्रथागत अधिकारों को मान्यता देने का भी प्रावधान करता है, जो आदिवासी समूहों के लिए गहरा सामाजिक-सांस्कृतिक और आजीविका महत्व रखते हैं।⁶⁸⁸ ये सुरक्षा उपाय न केवल मुआवजे के रूप में बल्कि आदिवासी समुदायों की रक्षा के लिए बनाए गए हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि उनका विस्थापन उनकी सांस्कृतिक और आर्थिक नींव को नष्ट न करे।

सर्वोच्च न्यायालय ने आदिवासी समूहों से भूमि अधिग्रहण पर विचार करते हुए पुनर्वास और पुनर्वास को अनुच्छेद 21 से भी जोड़ा है। *नर्मदा बचाओ आंदोलन बनाम भारत संघ*,⁶⁸⁹ के मामले में उच्चतम न्यायालय ने नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध के निर्माण के इर्द-गिर्द घूमती एक याचिका पर सुनवाई की। यह अभिनिर्धारित किया गया था कि विस्थापन के परिणामस्वरूप मौलिक या अन्य अधिकारों का उल्लंघन नहीं होगा, बशर्ते कि प्रभावित लोगों का पहले से बेहतर परिस्थितियों में पुनर्वास किया जाए। यह बेहतर सुविधाओं और समाज की मुख्यधारा में धीरे-धीरे आत्मसात होने के अवसरों के साथ हो सकता है।⁶⁹⁰

इसी प्रकार, *केरल राज्य बनाम पीपुल्स यूनिन फॉर सिविल लिबर्टीज*,⁶⁹¹ के मामले में न्यायालय ने केरल अनुसूचित जनजाति अधिनियम, 1999 द्वारा भूमि के अंतरण और पुनर्स्थापना पर प्रतिबंध पर विचार करते हुए स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 21 को जनजातीय भूमि के अधिग्रहण को पूरी तरह से प्रतिबंधित करने के लिए नहीं पढ़ा जा सकता है, बल्कि यह आवश्यक है कि विस्थापित जनजातीय समुदायों को उचित पुनर्वास प्रदान किया जाए।⁶⁹² हाल ही में, *संपदा अधिकारी, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण बनाम निर्मला देवी*,⁶⁹³ के मामले में उच्चतम न्यायालय की दो-न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि “पुनर्वास केवल उन व्यक्तियों के लिए होना चाहिए जो

⁶⁸⁸The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013, s. 31: “Rehabilitation and Resettlement Award for affected families by Collector.—(1) The Collector shall pass Rehabilitation and Resettlement Awards for each affected family in terms of the entitlements provided in the Second Schedule. (2) The Rehabilitation and Resettlement Award shall include all of the following, namely:—(a) rehabilitation and resettlement amount payable to the family; (b) bank account number of the person to which the rehabilitation and resettlement award amount is to be transferred; (c) particulars of house site and house to be allotted, in case of displaced families; (d) particulars of land allotted to the displaced families; (e) particulars of one time subsistence allowance and transportation allowance in case of displaced families; (f) particulars of payment for cattle shed and petty shops; (g) particulars of one-time amount to artisans and small traders; (h) details of mandatory employment to be provided to the members of the affected families; (i) particulars of any fishing rights that may be involved; (j) particulars of annuity and other entitlements to be provided; (k) particulars of special provisions for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes to be Provided: Provided that in case any of the matters specified under clauses (a) to (k) are not applicable to any affected family the same shall be indicated as “not applicable”: Provided further that the appropriate Government may, by notification increase the rate of rehabilitation and resettlement amount payable to the affected families, taking into account the rise in the price index.”

⁶⁸⁹*Narmada Bachao Andolan v. Union of India* (2000) 10 SCC 664.

⁶⁹⁰*Id.* at para. 62.

⁶⁹¹*State of Kerala v. Peoples Union for Civil Liberties* (2009) 8 SCC 46.

⁶⁹²*Id.* at para. 103.

⁶⁹³*Haryana Urban Development Authority v. Nirmala Devi* (2025) SCC OnLine SC 1409.

भूमि अधिग्रहण के परिणामस्वरूप निवास या आजीविका के नुकसान के कारण बेसहारा हो गए हैं” इसका मतलब होगा कि जिनका जीवन और आजीविका “ आंतरिक रूप से भूमि से जुड़ी हुई है” / ⁶⁹⁴ एक साथ लिए जाने पर, इन निर्णयों से यह स्थापित होता है कि अधिग्रहण की अनुमति है, विस्थापित व्यक्ति, विशेष रूप से आदिवासी, संवैधानिक रूप से संबंधित नीतियों के अनुसार पुनर्वास और पुनर्वास के हकदार हैं।

एल. ए. आर. आर. अधिनियम की धारा 41 और 42 में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए विस्थापन और भूमि के नुकसान की उनकी भेद्यता की मान्यता में अनुरूप सुरक्षा उपाय निर्धारित किए गए हैं। धारा 41 निर्देश देती है कि जहां तक संभव हो, अनुसूचित क्षेत्रों में कोई भूमि अधिग्रहण नहीं होना चाहिए। जहां अपरिहार्य हो, इसे अंतिम उपाय के रूप में माना जाना चाहिए और केवल ग्राम सभाओं, पंचायतों या स्वायत्त जिला परिषदों की पूर्व सहमति से किया जाना चाहिए, यहां तक कि तात्कालिकता के मामलों में भी।

जब अधिग्रहण के परिणामस्वरूप अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति परिवारों का अनैच्छिक विस्थापन होता है, तो एल. ए. आर. आर. अधिनियम एक विकास योजना तैयार करने का आदेश देता है। इस योजना को विस्थापित आदिवासी समुदायों को बनाए रखने के लिए पांच वर्षों के भीतर अस्थिर भूमि अधिकारों का निपटान, अलग-थलग पड़ी आदिवासी भूमि की बहाली और ईंधन, चारा और गैर-लकड़ी वन उपज जैसे वैकल्पिक संसाधनों का प्रावधान सुनिश्चित करना चाहिए। इसके लिए विशेष मुआवजा और पुनर्वास उपाय भी निर्धारित किए गए हैं। कब्जा लेने से पहले मुआवजे का कम से कम एक तिहाई भुगतान किया जाना चाहिए, और अनुसूचित जनजाति परिवारों को उनकी सांस्कृतिक, भाषाई और जातीय पहचान को संरक्षित करने के लिए एक ही अनुसूचित क्षेत्र के भीतर कॉम्पैक्ट ब्लॉकों में पुनर्स्थापित किया जाना चाहिए। ⁶⁹⁵

पुनर्वास क्षेत्रों में सामुदायिक भूमि सामाजिक और सांस्कृतिक समारोहों के लिए निःशुल्क प्रदान की जानी है। इसके अलावा, जनजातीय भूमि के किसी भी अवैध अलगाव को अमान्य घोषित किया जाता है, और मूल भूमि मालिक पुनर्वास और पुनर्वास लाभों के हकदार हैं। आजीविका के अतिरिक्त अधिकारों की भी रक्षा की जाती है। विस्थापित अनुसूचित जनजाति, ओटीएफडी और अनुसूचित जाति जो परियोजनाओं के कारण मछली पकड़ने के अधिकार खो देते हैं, वे परियोजना के जलाशयों में मछली पकड़ने के अधिकार के हकदार हैं। जहां अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के परिवारों को उनके जिले से बाहर स्थानांतरित किया जाता है तो उन्हें 25 प्रतिशत अतिरिक्त पुनर्वास और बसावट से जुड़े लाभों के साथ-साथ 50,000 रुपये की एकमुश्त सहायता राशि पाने का अधिकार है। ⁶⁹⁶

धारा 42 पुनर्वास क्षेत्रों में आरक्षण और वैधानिक लाभों की निरंतरता सुनिश्चित करती है। यदि जनजातीय परिवारों को अनुसूचित या छठी अनुसूची क्षेत्रों से बाहर स्थानांतरित किया जाता है, तो एलएआरआर अधिनियम, 2013 के तहत सभी सुरक्षा उपाय और हक नई बस्ती में लागू होते रहते हैं। इसके अलावा, एफआरए, 2006 के तहत मान्यता प्राप्त सामुदायिक अधिकारों का मुद्रीकरण किया जाना चाहिए और विस्थापित व्यक्तियों को आनुपातिक रूप से वितरित किया जाना चाहिए। ⁶⁹⁷

⁶⁹⁴ *Id.* at para.95(x).

⁶⁹⁵ The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013, ss.41(4)-(6).

⁶⁹⁶ *Id.* ss.41(8)-(11).

⁶⁹⁷ *Id.* s.42

महानदी कोल फील्ड्स लिमिटेड बनाम मथियास ओराम,⁶⁹⁸ के मामले में उच्चतम न्यायालय ने अपनी तीन-न्यायाधीशों की पीठ के माध्यम से कोयला खनन उद्देश्यों के लिए आदिवासी भूमि के अधिग्रहण के मामले पर विचार किया। न्यायालय ने इस बात पर प्रकाश डाला कि एलएआरआर अधिनियम, 2013 के तहत विशेष प्रावधान अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जातियों की कठिनाइयों को कम करने के लिए किए गए हैं। अदालत ने कहा कि धारा 41 में भूमि अधिग्रहण के दौरान अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जाति समुदायों को कम से कम नुकसान पहुंचाने की आवश्यकता है और आदिवासी भूमि के अवैध अलगाव को अमान्य घोषित करते हुए विकास योजनाओं को अनिवार्य किया गया है। धारा 42 यह भी सुनिश्चित करती है कि प्रभावित क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जातियों के लिए उपलब्ध सभी वैधानिक और आरक्षण लाभ पुनर्वास क्षेत्रों में जारी रहने चाहिए, भले ही उन्हें अनुसूचित क्षेत्रों से बाहर स्थानांतरित किया गया हो।⁶⁹⁹ न्यायालय ने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि विस्थापित व्यक्तियों को अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जाति के रूप में उनकी स्थिति से वंचित करके उनके लाभों पर पूर्वाग्रह न हो। इस प्रकार, विस्थापित अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जाति परिवारों को स्थानांतरण के कारण उनकी जाति या जनजातीय स्थिति से वंचित नहीं किया जा सकता है, और इन सुरक्षाओं को संरक्षित करना राज्य का बाध्यकारी कर्तव्य है।⁷⁰⁰

धारा 45 में आगे कहा गया है कि 100 एकड़ या उससे अधिक भूमि अधिग्रहण के लिए, सरकार को कलेक्टर की अध्यक्षता में एक पुनर्वास और पुनर्वास समिति का गठन करना चाहिए। यह निकाय कार्यान्वयन की निगरानी करता है, ग्राम सभाओं या नगर पालिकाओं के साथ सामाजिक लेखा परीक्षा आयोजित करता है और इसमें अधिकारियों के साथ-साथ महिलाओं, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, स्थानीय निकायों, स्वैच्छिक संगठनों, बैंकों, विधायकों और अधिग्रहण करने वाले निकाय के प्रतिनिधि शामिल होते हैं।⁷⁰¹

एलएआरआर, 2013 अधिनियम की दूसरी अनुसूची में यह भी प्रावधान है कि सिंचाई परियोजनाओं में, प्रभावित परिवार जो कृषि भूमि खो देते हैं या अधिग्रहण के कारण सीमांत या भूमिहीन स्थिति में आ जाते हैं, वे परियोजना के कमान क्षेत्र में कम से कम एक एकड़ भूमि के हकदार हैं। हालांकि, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए, भूमि आवंटन अधिग्रहित भूमि के बराबर या 2.5 एकड़ तक, जो भी कम हो, होना चाहिए।

यह भी प्रावधान किया गया है कि जहां तक संभव हो, अनुसूचित क्षेत्रों से विस्थापित अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को उनकी आजीविका, संस्कृति, भाषा और सामुदायिक जीवन की रक्षा के लिए समान पारिस्थितिक क्षेत्रों में पुनर्स्थापित किया जाना चाहिए।⁷⁰²

केंद्रीय कानून के अलावा, महत्वपूर्ण आदिवासी आबादी वाले कई राज्यों ने आदिवासी भूमि को गैर-आदिवासियों को हस्तांतरित करने से बचाने के लिए अपने स्वयं के भूमि अलगाव कानून बनाए हैं। ये कानून इस मान्यता में निहित हैं कि भूमि आदिवासी समुदायों के सामाजिक-आर्थिक और सांस्कृतिक अस्तित्व का आधार है, और इसके अलगाव से अक्सर शोषण, विस्थापन और पारंपरिक आजीविका का क्षरण होता है।

⁶⁹⁸*Mahanadi Coal Fields Limited v. Mathias Oram*, 2022 INSC 1158.

⁶⁹⁹*Id.* at para. 66.

⁷⁰⁰*Id.* at para. 67.

⁷⁰¹The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013, s. 45(1).

⁷⁰²*Id.* sch. II(2), (5).

उदाहरण के लिए, झारखंड में छोटानागपुर किरायेदारी अधिनियम, 1908 और संथाल परगना किरायेदारी अधिनियम, 1949 सक्षम अधिकारियों की पूर्व मंजूरी के बिना गैर-आदिवासियों को आदिवासी भूमि के हस्तांतरण पर रोक लगाते हैं। इसी तरह, आंध्र प्रदेश अनुसूचित क्षेत्र भूमि अंतरण विनियमन, 1959, जैसा कि 1970 में संशोधित किया गया था, आदिवासियों से गैर-आदिवासियों को भूमि के हस्तांतरण पर रोक लगाता है, जिसमें उल्लंघन में लेनदेन को अमान्य घोषित किया जाता है। ओडिशा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों ने भी आदिवासी भूमि के हस्तांतरण को विनियमित करने या प्रतिबंधित करने के लिए सुरक्षात्मक कानून बनाए हैं, जिसमें गैरकानूनी अलगाव के मामले में बहाली के लिए तंत्र हैं।

4.5. खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957

खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (एमएमडीआर अधिनियम, 1957) को संघ के नियंत्रण में खानों और खनिजों के विकास और विनियमन का प्रावधान करने के लिए अधिनियमित किया गया है। जबकि मुख्य रूप से विनियामक प्रकृति का है, अधिनियम का अनुसूचित जनजातियों और वन-निवासी समुदायों के लिए महत्वपूर्ण निहितार्थ है, क्योंकि भारत के अधिकांश खनिज-समृद्ध क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्रों और आदिवासी बस्तियों के साथ ओवरलैप करते हैं। एमएमडीआर अधिनियम, 1957 के तहत, केंद्र सरकार नीति बनाती है, जबकि राज्य सरकारें केंद्र की मंजूरी के अधीन खनिज रियायतें देती हैं।

एमएमडीआर अधिनियम, 1957 2015 में किए गए संशोधन के माध्यम से धारा 9बी के तहत एक जिला खनिज फाउंडेशन (डीएमएफ) की स्थापना करता है।⁷⁰³ डी. एम. एफ. खनन से संबंधित कार्यों से प्रभावित किसी भी जिले में राज्य सरकार द्वारा स्थापित एक गैर-लाभकारी निकाय के रूप में कार्य करता है। डी. एम. एफ. इस तरह के कार्यों से प्रभावित व्यक्तियों और क्षेत्रों के हित और लाभ के लिए काम करता है। इस धारा के तहत यह निर्दिष्ट किया गया है कि राज्य सरकार डीएमएफ के कार्य के साथ-साथ इसकी संरचना और कार्य के लिए नियम बनाती है,⁷⁰³

⁷⁰³The Mines and Minerals (Development and Regulation) Act 1957, s.9B: “District Mineral Foundation.—(1) In any district affected by mining related operations, the State Government shall, by notification, establish a trust, as a non-profit body, to be called the District Mineral Foundation. (2) The object of the District Mineral Foundation shall be to work for the interest and benefit of persons, and areas affected by mining related operations in such manner as may be prescribed by the State Government. (3) The composition and functions of the District Mineral Foundation shall be such as may be prescribed by the State Government. (4) The State Government while making rules under sub-sections (2) and (3) shall be guided by the provisions contained in article 244 read with Fifth and Sixth Schedules to the Constitution relating to administration of the Scheduled Areas and Tribal Areas and the Provisions of the Panchayats (Extension to the Scheduled Areas) Act, 1995 (40 of 1995) and the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2005 (2 of 2007). (5) The holder of a mining lease or a prospecting licence-cum-mining lease granted on or after the date of commencement of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Amendment Act, 2015, shall, in addition to the royalty, pay to the District Mineral Foundation of the district in which the mining operations are carried on, an amount which is equivalent to such percentage of the royalty paid in terms of the Second Schedule, not exceeding one-third of such royalty, as may be prescribed by the Central Government. (6) The holder of a mining lease granted before the date of commencement of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Amendment Act, 2015, shall, in addition to the royalty, pay to the District Mineral Foundation of the district in which the mining operations are carried on, an amount not exceeding the royalty paid in terms of the Second Schedule in such manner and subject to the categorisation of the mining leases and the amounts payable by the various categories of lease holders, as may be prescribed by the Central Government.”

लेकिन इसे पेसा अधिनियम, 1996 और एफआरए, 2006 के प्रशासन से संबंधित संविधान की पांचवीं और छठी अनुसूचियों के साथ पठित अनुच्छेद 244 में निहित प्रावधानों द्वारा निर्देशित किया जाना चाहिए।

सर्वोच्च न्यायालय ने फेडरेशन ऑफ इंडियन मिनेरल इंडस्ट्रीज बनाम भारत संघ,⁷⁰⁴ के मामले में तीन न्यायाधीशों की पीठ के माध्यम से 12 जनवरी 2015 से डीएमएफ के कामकाज के मुद्दों पर विचार किया। ऐसा करते हुए, पीठ ने कहा कि डीएमएफ का उद्देश्य खनन से संबंधित कार्यों से प्रभावित व्यक्तियों और क्षेत्रों के हित और लाभ के लिए काम करना है। इसने नोट किया कि "एमएमडीआर अधिनियम की धारा 9बी का उद्देश्य और डीएमएफ का उद्देश्य खनन संबंधी कार्यों से प्रभावित लोगों के लिए सामाजिक न्याय के उद्देश्य को आगे बढ़ाना है, जिसमें आदिवासी भी शामिल हैं जो विस्थापित हो सकते हैं या अपने निवास स्थान से विस्थापित हो सकते हैं।" इस प्रकार, यह नोट किया गया कि "उन्हें एक ऐसे लाभ से वंचित करना जो केवल इसलिए उनका अधिकार है क्योंकि राज्य सरकार डीएमएफ की स्थापना में ढिलाई बरत रही है, उनके साथ अन्याय करना होगा।"

4.6. व्यक्तिगत कानून

भारत में विवाह, उत्तराधिकार, गोद लेने और संरक्षकता को नियंत्रित करने वाले व्यक्तिगत कानूनों को मुख्य रूप से हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 (एचएमए, 1955), हिंदू अल्पसंख्यक और संरक्षकता अधिनियम, 1956 (एचएमजीए, 1956), हिंदू गोद लेने और रखरखाव अधिनियम, 1956 (एचएमए, 1956) और हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 (एचएसए, 1956) के माध्यम से संहिताबद्ध किया गया है। ये अधिनियम आम तौर पर हिंदुओं, बौद्धों, जैनों और सिखों पर लागू होते हैं। तथापि, एच. एम. ए., 1955 की धारा 2 (2);⁷⁰⁶ एच. ए. एम. ए., 1956 और एच. एस. ए., 1956 के अधीन और एच. एम. जी. ए., 1956,⁷⁰⁷ की धारा 3 (2) के अधीन उपबंध किसी अनुसूचित जनजाति के सदस्यों पर तब तक लागू नहीं होते जब तक कि केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, अन्यथा निर्देश न दे। तदनुसार, अनुसूचित जनजातियों के बीच विवाह, गोद लेने, रखरखाव, संरक्षकता और उत्तराधिकार जैसे मामले उनके प्रथागत कानूनों और प्रयोगों द्वारा शासित होते रहते हैं।

इनके अलावा, विशेष विवाह अधिनियम, 1954 (एस. एम. ए., 1954) विवाह और तलाक के लिए एक धर्मनिरपेक्ष ढांचा प्रदान करता है जो सभी भारतीय नागरिकों पर लागू होता है, चाहे वह किसी भी धर्म या समुदाय के हो। एसएमए, 1954 की धारा 4 के तहत, किसी भी दो व्यक्तियों के बीच विवाह किया जा सकता है यदि निम्नलिखित शर्तों को पूरा किया जाता है: किसी भी पक्ष का विवाह के समय जीवित जीवनसाथी नहीं है; दोनों पक्ष मानसिक रूप से स्वस्थ हों और सही सहमति देने में सक्षम हों; पुरुष ने इक्कीस वर्ष और महिला ने अठारह वर्ष की आयु पूरी कर ली है; और पक्षकार निषिद्ध संबंध के स्तर के भीतर नहीं हैं।

⁷⁰⁴ *Federation of Indian Mineral Industries v. Union of India* (2017) 16 SCC 186.

⁷⁰⁵ *Id.* at para. 43.

⁷⁰⁶ The Hindu Marriage Act, 1955, s. 2: "Application of Act. — (2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), nothing contained in this Act shall apply to the members of any Scheduled Tribe within the meaning of clause (25) of article 355 of the Constitution unless the Central Government, by notification in the Official Gazette, otherwise directs." ⁷⁰⁷ The Hindu Minority and Guardianship Act, 1956, s. 3: "Application of Act. — (2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1) nothing contained in this Act shall apply to the members of any scheduled Tribe within the meaning of clause (25) of article 355 of the Constitution unless the Central Government, by notification in the Official Gazette, otherwise directs."

जब तक कि उनकी प्रथा द्वारा अनुमति न दी जाए।⁷⁰⁸ धारा 4 का स्पष्टीकरण आगे स्पष्ट करता है कि, किसी जनजाति, समुदाय, समूह या परिवार से संबंधित व्यक्ति के संबंध में, 'रिवाज' शब्द किसी भी नियम को संदर्भित करता है जिसे राज्य सरकार, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, उस जनजाति, समुदाय, समूह या परिवार⁷⁰⁹ के सदस्यों पर लागू होने के रूप में निर्दिष्ट करती है। तदनुसार, अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों को इस अधिनियम के संचालन से बाहर नहीं रखा गया है और वे इसके तहत अपने विवाह कर सकते हैं।

इसके अतिरिक्त, भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 (आईएसए, 1925) भारत में निर्वसीयत और वसीयती उत्तराधिकार से संबंधित कानून को समेकित करता है। यह एक धर्मनिरपेक्ष कानून है जो आम तौर पर उन व्यक्तियों पर लागू होता है जो किसी विशिष्ट व्यक्तिगत कानून द्वारा शासित नहीं होते हैं। अनुसूचित जनजातियों के संदर्भ में, जबकि उनके प्रथागत कानून अपने समुदायों के भीतर विरासत और संपत्ति के अधिकारों को विनियमित करना जारी रखते हैं, विशेष विवाह अधिनियम के तहत विवाहित व्यक्ति उत्तराधिकार के मामलों में आईएसए, 1925 के प्रावधानों के अधीन हो जाते हैं।⁷¹⁰

हालांकि, आईएसए, 1925 की धारा 3 राज्य सरकार को विशेष नस्लों, संप्रदायों या जनजातियों को अधिनियम के कुछ प्रावधानों के संचालन से छूट देने का अधिकार देती है।⁷¹¹ इस प्रकार, यह स्वीकार करते हुए कि उत्तराधिकार कानून का समान अनुप्रयोग सभी समुदायों, विशेष रूप से विशिष्ट प्रथागत प्रथाओं द्वारा शासित समुदायों के लिए संभव नहीं हो सकता है।

व्यक्तिगत कानूनों की प्रयोज्यता से संबंधित मामलों में, उदाहरण के लिए, विरासत और उत्तराधिकार, सर्वोच्च न्यायालय ने भी न्याय, समानता और अच्छे विवेक की अवधारणाओं पर आधारित दृष्टिकोण के लिए सक्रिय रूप से उपदेश दिया है। उदाहरण के लिए, *मधु किश्वर* .

⁷⁰⁸The Special Marriage Act, 1954, s. 4.

⁷⁰⁹The Special Marriage Act, 1954, s. 4: "Conditions relating to solemnization of special marriages.—Explanation.—In this section, "custom", in relation to a person belonging to any tribe, community, group or family, means any rule which the State Government may, by notification in the Official Gazette, specify in this behalf as applicable to members of that tribe, community, group or family: Provided that no such notification shall be issued in relation to the members of any tribe, community, group or family, unless the State Government is satisfied—(i) that such rule has been continuously and uniformly observed for a long time among those members; (ii) that such rule is certain and not unreasonable or opposed to public policy; and (iii) that such rule, if applicable only to a family, has not been discontinued by the family."

⁷¹⁰The Special Marriage Act, 1954, s. 21: "Succession to property of parties married under Act.—Notwithstanding any restrictions contained in the Indian Succession Act, 1925 (39 of 1925), with respect to its application to members of certain communities, succession to the property of any person whose marriage is solemnized under this Act and to the property of the issue of such marriage shall be regulated by the provisions of the said Act and for the purposes of this Act shall have effect as if Chapter III of Part V (Special Rules for Parsi Intestates) had been omitted therefrom."

⁷¹¹The Indian Succession Act, 1925, s. 3: "Power of State Government to exempt any race, sect or tribe in the State from operation of Act.—(1) The State Government may, by notification in the Official Gazette, either retrospectively from the sixteenth day of March, 1855, or prospectively, exempt from the operation of any of the following provisions of this Act, namely, sections 5 to 49, 58 to 191, 212, 213 and 215 to 359, the members of any race, sect or tribe in the State, or of any part of such race, sect or tribe, to whom the State Government considers it impossible or inexpedient to apply such provisions or any of them mentioned in the order. (2) The State Government may, by a like notification, revoke any such order, but not so that the revocation shall have retrospective effect. (3) Persons exempted under this section or exempted from the operation of any of the provisions of the Indian Succession Act, 1855 (10 of 1855), under section 332 of that Act are in this Act referred to as "exempted persons"."

बनाम बिहार राज्य,⁷¹² में पुरुष वंश को संपत्ति का उत्तराधिकार सीमित करने वाले छोटा नागपुर किरायेदारी अधिनियम, 1908 के प्रावधानों को चुनौती देते हुए बहुमत ने कहा कि एचएसए, 1956 पक्षों पर लागू नहीं होता है, क्योंकि वे अनुच्छेद 366 (25) के अर्थ के भीतर एक अधिसूचित अनुसूचित जनजाति थे हालाँकि, न्यायमूर्ति रामास्वामी द्वारा दी गई असहमतिपूर्ण राय ने आदिवासी रीति-रिवाजों और संवैधानिक समानता के बीच संतुलन के बारे में अधिक प्रगतिशील और अधिकार-उन्मुख दृष्टिकोण अपनाया। उन्होंने कहा: "कानून के शासन को एक ऐसे समाज में सामंजस्यपूर्ण अस्तित्व के लिए एक समान पैटर्न स्थापित करना चाहिए जहाँ प्रत्येक व्यक्ति उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए अपने सर्वोत्तम लाभ के अधिकारों का प्रयोग करेगा, जो सुरक्षात्मक भेदभाव के अधीन होगा। एक व्यक्ति का सबसे अच्छा लाभ दूसरे के लिए सबसे बुरा नुकसान हो सकता है। कानून इस तरह की खामियों को दूर करने के लिए कदम उठाता है और व्यक्तियों के साथ साथ समूह की स्वतंत्रता के लिए सुरक्षा की समानता सुनिश्चित करता है।.... मेरा मानना है कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 और भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 के प्रावधान हालाँकि संदर्भ में अनुसूचित जनजातियों पर लागू नहीं होंगे, लेकिन उनमें निहित सामान्य सिद्धांत न्याय, समानता, निष्पक्षता, न्याय और सद्भावना के अनुरूप होंगे" ⁷¹³ इस प्रकार, यह देखते हुए कि अनुसूचित जनजाति की महिलाएं एचएसए, 1956 के सामान्य सिद्धांतों के अनुसार और तदनुसार जनजातीय ईसाइयों के लिए आईएसए, 1925 के तहत पुरुष उत्तराधिकारियों के साथ समान हिस्सेदारी और पूर्ण स्वामित्व अधिकारों का आनंद लेते हुए, निर्वसीयत उत्तराधिकार के माध्यम से कानूनी उत्तराधिकारी के रूप में अपने माता-पिता, भाइयों या पतियों की संपत्ति के उत्तराधिकारी होने की हकदार हैं।

सर्वोच्च न्यायालय ने आदिवासी महिलाओं को हिंदू व्यक्तिगत कानूनों के दायरे में लाने के बारे में सवाल उठाया है ताकि वे विरासत में मिली संपत्तियों पर अधिकार का दावा कर सकें। *कमला नेती बनाम भूमि अधिग्रहण अधिकारी*,⁷¹⁴ के मामले में उच्चतम न्यायालय ने अधिग्रहित पैतृक भूमि के लिए मुआवजे के विभाजन से संबंधित विवाद पर विचार किया, जहाँ एक आदिवासी महिला ने पांचवें हिस्से का दावा किया था। उनके दावे को अदालतों द्वारा इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि पक्षकार एक अनुसूचित जनजाति से संबंधित थे, और इस प्रकार एचएसए, 1956 लागू नहीं था। यह अभिनिर्धारित किया गया था कि एचएसए, 1956 की धारा 2 (2) के अधीन अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों को इसके आवेदन से बाहर रखा गया था; इस प्रकार, आवेदक, एक आदिवासी महिला होने के नाते, उत्तरजीविता के किसी भी अधिकार का हकदार नहीं था। हालाँकि, अदालत ने यह देखते हुए कि "महिला आदिवासी को निर्वसीयत उत्तराधिकार में पुरुष आदिवासी के साथ समानता का हकदार है", ⁷¹⁵ केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह "इस मामले पर विचार करे और यदि आवश्यक हो, तो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के उन प्रावधानों में संशोधन करे जिनके तहत यह अधिनियम अनुसूचित जनजाति के सदस्यों पर लागू नहीं होता है... और ऐसा करते समय भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के तहत गारंटीकृत समानता के अधिकार को ध्यान में रखे।" ⁷¹⁶

तत्पश्चात, *तिरुथ कुमार बनाम दादूराम*,⁷¹⁷ के मामले में उच्चतम न्यायालय ने अनुसूचित जनजाति से संबंधित पक्षों के लिए एच. एस. ए., 1956 की प्रयोज्यता के मूल मुद्दे पर विचार किया, विशेष रूप से जब वे 'पर्याप्त रूप से हिंदू हो गए थे', ⁷¹⁸ ने आदिवासी समुदाय के एक भाग के रूप में अपने रीति-रिवाजों को छोड़ दिया था।

⁷¹² *Madhu Kishwar v. State of Bihar* (1996) 5 SCC 125.

⁷¹³ *Id.* at paras. 38-56.

⁷¹⁴ *Kamla Neti v. Land Acquisition Officer* (2023) 3 SCC 528.

⁷¹⁵ *Id.* at para. 17.

⁷¹⁶ *Id.* at paras. 17-18.

⁷¹⁷ *Tirith Kumar v. Daduram*, 2024 INSC 1005.

⁷¹⁸ *Id.* at para. 1.

न्यायालय ने अनुसूचित जनजाति की महिला के कानूनी उत्तराधिकारियों के अपने नाना की पैतृक संपत्ति में समान हिस्से के अधिकार को बरकरार रखा। ऐसा करते हुए, इसने संसद से एचएसए, 1956 में आवश्यक संशोधन करके महिला आदिवासियों के उत्तरजीविता के अधिकार को सुरक्षित करने के लिए मार्ग तलाशने का आग्रह किया।

इसके अलावा, भारतीय न्याय संहिता, 2023 के तहत, द्विविवाह, किसी के पति या पत्नी के जीवन के दौरान फिर से शादी करने का कार्य, धारा 82 के तहत दंडित किया गया है।⁷¹⁹ हालांकि, इस प्रावधान को अलग-अलग तरीके से लागू किया गया है, जो पार्टियों को नियंत्रित करने वाले व्यक्तिगत या प्रथागत कानूनों पर निर्भर करता है। इस रुख के समर्थन में प्रमुख मामला डॉ. सूरजमणि स्टेला कुजुर बनाम दुर्गा चरण हंसदा के मामले में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय है।⁷²⁰ सर्वोच्च न्यायालय की दो-न्यायाधीशों की पीठ का सामना इस बात का आकलन करने के लिए किया गया था कि क्या उरांव और संधाल के बीच विवाह हिंदू कानून के तहत आ सकता है और क्या पति को द्विविवाह (तब भारतीय दंड संहिता, 1860 (आईपीसी, 1860) की धारा 494) के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है क्योंकि उसने पहले के निर्वाह के दौरान दूसरी शादी की थी। अदालत ने कहा कि दोनों पक्ष आदिवासी थे, और एचएमए, 1955 की धारा 2 (2) के तहत, अधिनियम के प्रावधान तब तक अनुसूचित जनजातियों पर लागू नहीं होते जब तक कि केंद्र सरकार द्वारा विशेष रूप से अधिसूचित नहीं किया जाता है। चूंकि ऐसी कोई अधिसूचना मौजूद नहीं थी, इसलिए उनकी शादी पूरी तरह से पारंपरिक आदिवासी प्रथाओं द्वारा शासित थी, न कि एच. एम. ए. द्वारा। यह भी देखा गया कि "कोई भी प्रथा अपराध पैदा नहीं कर सकती क्योंकि यह अनिवार्य रूप से पक्षों के नागरिक अधिकारों से संबंधित है और किसी भी व्यक्ति को आरोपित अधिनियम के आयोग के समय लागू कानून के उल्लंघन के अलावा किसी भी अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। पक्षकारों के नागरिक अधिकारों के निर्धारण के लिए प्रथा को साबित किया जा सकता है, जिसमें उनकी स्थिति भी शामिल है, जिसकी स्थापना का उपयोग अपराध के तत्वों को साबित करने के उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है..."⁷²¹ न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि धारा 494, आई. पी. सी., 1860 के लिए लागू करने के लिए, शिकायतकर्ता को यह स्थापित करना चाहिए कि दूसरा विवाह प्रथा या कानून के कारण अमान्य था और "केवल एक ही विवाह के लिए जोर देने वाली प्रथा का अभिवचन तब तक पर्याप्त नहीं था जब तक कि यह आगे नहीं कहा गया था कि दूसरा विवाह ऐसे पति या पत्नी के जीवन के दौरान होने के कारण अमान्य था।"⁷²²

यह निर्णय इस सिद्धांत को मजबूत करता है कि प्रथागत कानून अनुसूचित जनजातियों के वैवाहिक संबंधों को नियंत्रित करता है

⁷¹⁹The Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023, s.82: "Marrying again during lifetime of husband or wife. — (1) Whoever, having a husband or wife living, marries in any case in which such marriage is void by reason of it taking place during the life of such husband or wife, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to seven years, and shall also be liable to fine. Exception. — This sub-section does not extend to any person whose marriage with such husband or wife has been declared void by a Court of competent jurisdiction, nor to any person who contracts a marriage during the life of a former husband or wife, if such husband or wife, at the time of the subsequent marriage, shall have been continually absent from such person for the space of seven years, and shall not have been heard of by such person as being alive within that time provided the person contracting such subsequent marriage shall, before such marriage takes place, inform the person with whom such marriage is contracted of the real state of facts so far as the same are within his or her knowledge. (2) Whoever commits the offence under sub-section (1) having concealed from the person with whom the subsequent marriage is contracted, the fact of the former marriage, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to ten years, and shall also be liable to fine."

⁷²⁰Dr. Surajmani Stella Kujur v. Durga Charan Hansdah (2001) 3 SCC 13.

⁷²¹Id. at para. 08.

⁷²²Id. at para. 14.

जब तक कि अधिसूचना द्वारा संहिताबद्ध व्यक्तिगत कानूनों के दायरे में नहीं लाया जाता है। यह इस बात को भी रेखांकित करता है कि आपराधिक दायित्व केवल रीति-रिवाजों पर आधारित नहीं हो सकता; इस तरह यह आदिवासी रीति-रिवाजों की स्वायत्तता को बनाए रखता है और साथ ही संवैधानिक ज़रूरत का भी पालन करता है कि अपराधों को कानूनी तौर पर परिभाषित किया जाना चाहिए।।

इसलिए, जबकि अनुसूचित जनजातियों को आम तौर पर हिंदू व्यक्तिगत कानून के संचालन से छूट दी जाती है, वे अपनी व्यक्तिगत पसंद और परिस्थितियों के आधार पर धर्मनिरपेक्ष कानूनों द्वारा शासित होने का विकल्प रखते हैं। इस प्रकार ये प्रावधान अपनी सांस्कृतिक और कानूनी विविधता को समायोजित करने के लिए आवश्यक लचीलेपन को बनाए रखते हैं।

4.7. श्रम कानून

भारत में श्रम कानून आदिवासी समुदायों के अधिकारों की रक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो अक्सर श्रम के असंगठित, मौसमी या शोषक रूपों में लगे रहते हैं। उनमें से कई कम मजदूरी, असुरक्षित काम करने की स्थिति और ऋण या सामाजिक पदानुक्रम के कारण बंधन जैसी कमजोरियों का सामना करते हैं। भारतीय कानूनी प्रणाली अनुसूचित जनजातियों सहित इस तरह की शोषक श्रम प्रथाओं के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करने वाले कई श्रम कानूनों का प्रावधान करती है।

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 यह सुनिश्चित करता है कि सभी को उचित पारिश्रमिक मिले। अधिनियम की धारा 2 (i) के तहत, एक 'कर्मचारी' को मोटे तौर पर किसी भी अनुसूचित रोजगार में किसी भी काम, कुशल या अकुशल, मैनुअल या लिपिक को करने के लिए किराए या पुरस्कार के लिए नियोजित किसी भी व्यक्ति को शामिल करने के लिए परिभाषित किया गया है।⁷²³ इस व्यापक परिभाषा से जनजातीय श्रमिकों, यहां तक कि मौसमी या आकस्मिक रूपों में काम करने वालों को भी न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के सुरक्षात्मक दायरे में लाना संभव हो जाता है।

बंधुआ श्रम प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम, 1976, ऋण बंधन के मुद्दे को संबोधित करता है, जो आदिवासी क्षेत्रों में ऐतिहासिक रूप से प्रचलित एक प्रथा है, जिसमें लोग अनुबंध किए गए ऋणों या प्राप्त अग्रिमों को चुकाने के लिए काम करते हैं, भले ही वे जो काम करते हैं उसका मूल्य उनके ऋण की राशि से अधिक हो।⁷²⁴ यह अधिनियम किसी भी प्रकार के बंधुआ श्रम को अपराधी बनाता है और आगे मुक्त किए गए मजदूरों के पुनर्वास को अनिवार्य करता है। बंधुआ श्रम प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम, 1976 के तहत गठित सतर्कता समिति अधिनियम के प्रावधानों के

⁷²³The Minimum Wages Act, 1948, s. 2: "Interpretations. - (i) "employee" means any person who is employed for hire or reward to do any work, skilled or unskilled, manual or clerical, in a scheduled employment in respect of which minimum rates of wages have been fixed; and includes an out-worker to whom any articles or materials are given out by another person to be made up, cleaned, washed, altered, ornamented, finished, repaired, adapted or otherwise processed for sale for the purposes of the trade or business of that other person where the process is to be carried out either in the home of the out-worker or in some other premises not being premises under the control and management of that other person; and also includes an employee declared to be an employee by the appropriate Government; but does not include any member of the Armed Forces of the Union."

⁷²⁴United Nations Human Rights Office of the High Commissioner, Debt bondage remains the most prevalent form of forced labour worldwide (Sep. 15, 2016), available at: <https://www.ohchr.org/en/press-releases/2016/09/debt-bondage-remains-most-prevalent-form-forced-labour-worldwide-new-un> (last visited on Nov. 12, 2025).

कार्यान्वयन पर निष्पक्ष पर्यवेक्षण सुनिश्चित करने के लिए अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति समुदायों से संबंधित तीन व्यक्तियों के नामांकन का भी प्रावधान करती है।⁷²⁵ इसी तरह, बाल श्रम (निषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986, बच्चों को खतरनाक व्यवसायों में संलग्न करने पर प्रतिबंध लगाता है, जिसमें बाल वेश्यावृत्ति या कालीन बुनाई, ईट भट्टों और बीड़ी, माचिस और आतिशबाजी उत्पादन जैसे उद्योगों में बंधुआ श्रम शामिल हैं।⁷²⁶ यह कृषि और वृक्षारोपण जैसे अन्य क्षेत्रों में उनकी काम करने की स्थितियों को भी नियंत्रित करता है।⁷²⁷ अनुसूचित जनजाति समुदायों के बच्चे अक्सर गरीबी, पलायन और शैक्षिक पहुंच की कमी के कारण इन क्षेत्रों में काम करते पाए जाते हैं। इस प्रकार यह अधिनियम ऐसे असुरक्षित और शोषणकारी वातावरण में उनके रोजगार को रोककर उनके शिक्षा, स्वास्थ्य और बचपन के अधिकार की रक्षा करने का प्रयास करता है।

बागान, निर्माण और खनन जैसे उद्योगों में काम करने वाले आदिवासियों को बागान श्रम अधिनियम, 1951, खान अधिनियम, 1952 और भवन और अन्य निर्माण श्रमिक (रोजगार का विनियमन और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1996 जैसे क्षेत्र-विशिष्ट कानूनों के तहत भी संरक्षित किया जाता है, जो उनकी सुरक्षा, कल्याण, आवास और सामाजिक सुरक्षा उपायों का प्रावधान करते हैं।

5. संस्थागत पहल

इन समुदायों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, विभिन्न मंत्रालयों और संबद्ध एजेंसियों के तत्वावधान में कई योजनाएं, कार्यक्रम और संस्थागत तंत्र बनाए गए हैं।

ये पहल शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका संवर्धन, वित्तीय समावेशन, कौशल विकास और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण सहित क्षेत्रों पर केंद्रित हैं। इन उपायों के साथ-साथ प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए विशेष संगठनों की भी स्थापना की गई है। साथ में, उनका उद्देश्य देश भर में जनजातीय समुदायों के लिए समावेशी विकास, न्याय और सतत विकास को बढ़ावा देना है।

5.1. प्रमुख कल्याणकारी योजनाएं

5.1.1. अनुसूचित जनजाति के लिए विकास कार्य योजना, 1974

अनुसूचित जनजातियों के लिए विकास कार्य योजना (डीएपीएसटी)⁷²⁸ को जनजातीय विकास में तेजी लाने के लिए पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 1974-75 में शुरू किया गया था। इसका प्राथमिक उद्देश्य विकास के सभी क्षेत्रों, विशेष रूप से अनुसूचित जनजाति की आबादी को धन और लाभ देना है। डीएपीएसटी वित्त पोषण का एक समर्पित स्रोत प्रदान करता है, जिसमें 42 केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों ने जनजातीय कल्याण के लिए अपनी योजना आवंटन का 4.3 प्रतिशत से 17.5 प्रतिशत के बीच रखा है।

⁷²⁵The Bonded Labour System (Abolition) Act, 1976, s. 13(2)(b).

⁷²⁶Child Labour (Prohibition and Regulation) Act, 1986, s. 3, sch. part. B.

⁷²⁷Abdul Latheef Naha, "Tribal Children Engaged in Plantation Labour" *The Hindu*, Jul. 22, 2023.

⁷²⁸Ministry of Tribal Affairs, *Development Action Plan for Scheduled Tribes, Scheduled Tribe Component (STC) Monitoring System*, available at: <https://stcmis.gov.in/> (last visited on Sep. 30, 2025).

जनजातीय कार्य मंत्रालय एक ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से डीएपीएसटी के कार्यान्वयन और निगरानी की देखरेख करता है, जो सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के आंकड़ों का उपयोग करके निधि उपयोग, परियोजना स्थानों, लाभार्थियों और परिणामों पर नज़र रखता है निधि निर्धारण 2010 टास्क फोर्स द्वारा अनुशंसित मानदंडों और वित्त मंत्रालय और नीति आयोग द्वारा बाद में किए गए संशोधनों द्वारा निर्देशित किया जाता है, जिसमें कौशल विकास, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास, पशुपालन, बिजली और खाद्य प्रसंस्करण जैसे नए मंत्रालय डीएपीएसटी के तहत शामिल हैं।

5.1.2. राष्ट्रीय वन नीति, 1988

राष्ट्रीय वन नीति, 1988-⁷²⁹ ने वन प्रशासन के प्रति भारतीय दृष्टिकोण में बदलाव को चिह्नित किया। यह नीति स्पष्ट रूप से एक प्रमुख प्राथमिकता के रूप में आदिवासियों और वन-निवासी समुदायों के अधिकारों और रियायतों की रक्षा करती है। नीति की एक प्रमुख विशेषता में स्थानीय और आदिवासी समुदायों और वनों के बीच संबंधों पर जोर देना शामिल है। यह नीति ग्रामीण और आदिवासी आबादी की बुनियादी आजीविका की जरूरतों को पूरा करने का प्रयास करती है, जिसमें ईंधन की लकड़ी, चारा, लघु वन उत्पाद (एमएफपी) और छोटी लकड़ी शामिल हैं, साथ ही यह सुनिश्चित करती है कि पारिस्थितिक प्राथमिकताओं से समझौता न किया जाए। यह बड़े पैमाने पर वनीकरण और सामाजिक वानिकी कार्यक्रमों पर जोर देता है, विशेष रूप से खराब भूमि पर, और इसका उद्देश्य वन संरक्षण को एक जन आंदोलन में बदलना है, जिसमें महिलाओं की भागीदारी पर विशेष जोर दिया जाता है। महत्वपूर्ण रूप से, इसने पेसा अधिनियम, 1996 और एफआरए, 2006 जैसे बाद के कानूनी विकास की नींव भी रखी, दोनों ने जनजातीय भागीदारी और वन-आधारित स्व-शासन के अपने दृष्टिकोण को कार्यान्वित किया।

5.1.3. प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना, 1997

प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना (पीएमएएजीवाई) ⁷³⁰ पहले की जनजातीय उप-योजना के लिए विशेष केंद्रीय सहायता से विकसित हुई, जिसे 1977-78 में शुरू किया गया था और योजना और गैर-योजना व्यय के विलय के बाद 2017 में इसका नाम बदल दिया गया था। इस योजना ने अधिसूचित अनुसूचित जनजाति आबादी वाले राज्यों को शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, कौशल विकास और रोजगार जैसे क्षेत्रों में विकास अंतराल को दूर करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की, जो केंद्र और राज्य के कार्यक्रमों के पूरक हैं।

2019-20 में, जनगणना 2011 और मिशन अंत्योदय ⁷³¹ के आंकड़ों का उपयोग करते हुए एक अंतर विश्लेषण ने लगभग 145,000 आदिवासी गांवों की पहचान की, जहां 25 प्रतिशत या उससे अधिक अनुसूचित जनजाति की आबादी में बुनियादी ढांचे और सेवाओं की कमी है। इसे संबोधित करने के लिए, योजना को पीएमएएजीवाई में पुनर्गठित किया गया था, जो आदिवासी

⁷²⁹ Ministry of Environment, Forest and Climate Change, *Aim and Objectives under Forest Policy, 1988* (Jan. 19, 2020), available at: <https://www.pib.gov.in/news/ereelcontent.aspx?relid=57051> (last visited on Oct. 7, 2025).

⁷³⁰ Ministry of Social Justice and Empowerment, *Pradhan Mantri Adi Adarsh Gram Yojana*, available at: <https://pmagv.gov.in/> (last visited on Oct. 12, 2025).

⁷³¹ Mission Antyodaya was launched by the Ministry of Rural Development with the goal to realise the vision of poverty-free India by 2022-23. Ministry of Rural Development, *Mission Antyodaya*, available at: <https://missionantyodaya.dord.gov.in/> (last visited on Oct. 11, 2025).

गांवों के एकीकृत सामाजिक-आर्थिक विकास पर केंद्रित है।⁷³² 2021-22 और 2025-26 के बीच, कम से कम 50 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति की आबादी वाले 36,428 गांवों और 500 अनुसूचित जनजाति निवासियों को लक्षित किया गया है।

पीएमएएजीवाई स्थानीय जरूरतों और आकांक्षाओं को दर्शाते हुए ग्राम विकास योजनाओं को तैयार करने, व्यक्तिगत और परिवार लाभ योजनाओं के कवरेज को अधिकतम करने और सड़कों, दूरसंचार, स्कूलों, आंगनवाड़ियों, स्वास्थ्य केंद्रों, पेयजल, जल निकासी और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे में सुधार पर जोर देता है। रुपये का प्रावधान। राज्यों को अनुसूचित जनजाति घटक निधियों और अन्य उपलब्ध वित्तीय स्रोतों से संसाधनों को एकत्रित करने के लिए प्रोत्साहित करने के साथ अंतराल भरने की गतिविधियों के लिए प्रति गांव 2.20 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

5.1.4. एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय, 1997

आदिवासी बच्चों को उनके वातावरण में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए 2018-19 में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस)⁷³³ योजना को संशोधित किया गया था। 50 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जनजाति की आबादी और कम से कम 20,000 जनजातीय व्यक्तियों वाले प्रत्येक ब्लॉक में ईएमआरएस स्थापित किए जा रहे हैं। स्कूलों को नवोदय विद्यालयों की तर्ज पर तैयार किया गया है, जिसमें खेल, कौशल विकास और समग्र शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया है। 2023-2024 के लिए जनजातीय मामलों के मंत्रालय की रिपोर्ट से पता चलता है कि शुरू में, 288 स्कूलों को मंजूरी दी गई थी, लेकिन संशोधित योजना ने 452 नए स्कूलों को मंजूरी दी, जिससे 2025 तक कुल लक्ष्य 740 स्कूलों तक पहुंच गया।⁷³⁴

प्रत्येक ईएमआरएस में आधुनिक कक्षाओं, प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों, छात्रावासों, स्टाफ क्वार्टरों और खेल सुविधाओं के साथ 480 छात्रों को समायोजित किया जाना है। खेलों के लिए 15 उत्कृष्टता केंद्र भी स्थापित किए जा रहे हैं। प्रति स्कूल पूंजीगत लागत को संशोधित कर एक लाख रुपये कर दिया गया है। मैदानी इलाकों में 37.8 करोड़ रु. पहाड़ी/उत्तर-पूर्वी/वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में 48 करोड़ रुपये, जबकि आवर्ती लागत को बढ़ाकर 48 करोड़ रुपये कर दिया गया है। 1.09 लाख प्रति छात्र वार्षिक।

31 मार्च, 2024 तक 699 ईएमआरएस स्वीकृत किए जा चुके हैं और 404 कार्यरत हैं। राज्य 15 एकड़ बोझ मुक्त भूमि प्रदान करने और दो साल के भीतर निर्माण पूरा करने के लिए जिम्मेदार हैं, या निर्माण पूरा होने तक उपयुक्त किराए के भवनों से वैकल्पिक रूप से स्कूल चलाने के लिए जिम्मेदार हैं। कार्यान्वयन की देखरेख जनजातीय छात्रों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा सोसायटी (एनईएसटीएस) द्वारा की जाती है

⁷³²Ministry of Tribal Affairs, Pradhan Mantri Aadi Asha Gram Yojana aims at transforming villages with significant tribal populations into model village, available at: <https://www.pib.gov.in/Pressreleaseshare.aspx?PRID=1882862> (last visited on Sep. 23, 2025)

⁷³³Ministry of Tribal Affairs, Eklavya Model Residential Schools, available at: <https://tribal.nic.in/EMRS.aspx> (last visited on Oct. 4, 2025).

⁷³⁴Government of India, "Annual Report 2023-24" (Ministry of Tribal Affairs, 2024), p.no. 77.

5.1.5. विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों का विकास, 1998

विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के विकास की योजना (पीवीटीजी) ⁷³⁵ में 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के 75 चिन्हित समूह शामिल हैं, जो सबसे कमजोर जनजातीय समुदायों के सामाजिक-आर्थिक उत्थान पर ध्यान केंद्रित करते हैं। यह योजना लचीली है, जिससे राज्यों को शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, पोषण, आजीविका, संस्कृति और विरासत के संरक्षण और निवास अधिकारों जैसे क्षेत्रों में स्थानीय जरूरतों के अनुरूप संरक्षण-सह-विकास (सीसीडी) योजनाएं तैयार करने की अनुमति मिलती है।

ये योजनाएं सूक्ष्म-स्तरीय योजना के माध्यम से तैयार की जाती हैं, जिसमें लैंगिक समानता पर जोर दिया जाता है, जिसके लिए आवश्यक है कि कम से कम एक तिहाई लाभार्थी महिलाएं या लड़कियां हों। स्वीकृत सी. सी. डी. योजनाओं के आधार पर प्रतिवर्ष धनराशि जारी की जाती है, जिसमें राज्यों को मूल्यांकन स्तर पर लिंग-विभाजित लाभार्थी डेटा प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है।

5.1.6. अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए मैट्रिक के बाद छात्रवृत्ति, 2006

पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना ⁷³⁶ अनुसूचित जनजाति के छात्रों को भारत में कहीं भी वरिष्ठ-माध्यमिक और उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है यह योजना अनुसूचित जनजाति के उन छात्रों के लिए है जिनके माता-पिता की सालाना आय 2.5 लाख रुपये से ज्यादा नहीं है और जो संबंधित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के निवासी हैं। यह योजना राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासनों के माध्यम से लागू की जाती है, जो छात्रवृत्ति की पहचान, सत्यापन और समय पर वितरण के लिए जिम्मेदार हैं। वित्त पोषण का अनुपात केंद्र और राज्यों के बीच 75:25, पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों के लिए 90:10 और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 100 प्रतिशत केंद्रीय वित्त पोषण है। इस योजना में राज्य शुल्क नियामक समितियों द्वारा निर्धारित ट्यूशन शुल्क पूरी तरह से शामिल है, इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों के लिए सालाना 2.5 लाख रुपये, एमबीबीएस/एमएस/एमडी पाठ्यक्रमों के लिए 6 लाख रुपये और अन्य पाठ्यक्रमों के लिए जिसकी अधिकतम सीमा रु1 लाख है। इसके अलावा, पाठ्यक्रम के आधार पर वार्षिक रूप से रखरखाव भत्ता प्रदान किया जाता है। विकलांग अनुसूचित जनजाति के छात्रों को डे स्कॉलर के लिए 600 रुपये प्रति माह। छात्रावासों के लिए 800 प्रति माह भी 5 लाख रुपये का अतिरिक्त अनुदान मिलता है

5.1.7. राष्ट्रीय छात्रवृत्ति (शीर्ष श्रेणी) योजना, 2007

राष्ट्रीय छात्रवृत्ति (शीर्ष वर्ग) योजना ⁷³⁷ वर्ष 2007-08 में शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य अनुसूचित जनजाति के मेधावी छात्रों जिनके परिवारों की सालाना आय 6 लाख रुपये से ज्यादा नहीं है, को

⁷³⁵Ministry of Tribal Affairs, Welfare of particularly vulnerable Tribal groups, available at: <https://www.pib.gov.in/Pressreleaseshare.aspx?PRID=1577166> (last visited on Oct. 7, 2025).

⁷³⁶Ministry of Minority Affairs, Post-Matric Scholarship Scheme, available at: <https://www.minorityaffairs.gov.in/> (last visited on Oct. 8, 2025).

⁷³⁷Ministry of Tribal Affairs, Pre-Matric Scholarship Scheme, available at: <https://tribal.nic.in/ScholarshiP.aspx> (last visited on Sep. 8, 2025).

प्रोत्साहित करना था ताकि वे 265 अनुसूचित संस्थानों में स्नातक और स्नातकोत्तर अध्ययन करने के लिए 6 लाख। जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा पूरी तरह से वित्त पोषित, इस योजना में सरकारी या सरकारी वित्त पोषित संस्थानों में ट्यूशन और गैर-वापसी योग्य शुल्क शामिल हैं, जिसकी अधिकतम सीमा रु। निजी संस्थानों के लिए सालाना 2.5 लाख। इसके अलावा, अनुसूचित जनजाति के छात्रों को रुपये के वजीफे के रूप में वित्तीय सहायता प्राप्त होती है। इसके अलावा, अनुसूचित जनजाति के छात्रों को हर साल 36,000 रुपये का एकमुश्त अनुदान और किताबों और स्टेशनरी के लिए 5,000 रुपये, कंप्यूटर व सहायक उपकरण के लिए एक बार में 45,000 रुपये की ग्रांट के रूप में आर्थिक मदद मिलती है। स्टाइपेंड और कंप्यूटर ग्रांट के लिए पैसे सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजे जाते हैं इस योजना के तहत साल 2023-24 में 230 करोड़ रुपये का पूरी तरह से उपयोग किया गया, जिसमें राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल के माध्यम से जमा किए गए नए और नवीनीकरण दोनों आवेदन शामिल थे।⁷³⁸ पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित करने के लिए, मंत्रालय ने योजना को पीएफएमएस व्यय अग्रिम हस्तांतरण मॉड्यूल,⁷³⁹ के साथ भी एकीकृत किया है, जो कार्यक्रम कार्यान्वयन एजेंसियों को सरकारी योजनाओं के भीतर व्यय फाइलिंग, धन हस्तांतरण, अग्रिम और इसके निपटान का प्रबंधन और रिपोर्ट करने की अनुमति देता है, जिससे निधि की निगरानी और कार्यान्वयन मजबूत होता है।

5.1.8. अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति, 2012

कक्षा IX और X में पढ़ने वाले अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना⁷⁴⁰ का उद्देश्य प्राथमिक से माध्यमिक शिक्षा में जाने के दौरान ड्रॉपआउट दर को कम करना और मैट्रिक के बाद के स्तर पर प्रगति करने की उनकी संभावनाओं में सुधार करना है। यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसे राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के माध्यम से लागू किया जाता है, जिसमें पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों को छोड़कर जहाँ यह अनुपात 90:10 है, केंद्र और राज्य के बीच 75:25 के अनुपात में धन साझा किया जाता है और जिन केंद्र-शासित प्रदेशों में विधानसभा नहीं है, वहाँ केंद्र का हिस्सा 100 प्रतिशत होता है। यह योजना अनुसूचित जनजाति के उन छात्रों के लिए खुली है जिनके माता-पिता की आय रुपये से अधिक नहीं है। 2.5 लाख प्रति वर्ष, बशर्ते वे सरकारी या सरकारी मान्यता प्राप्त स्कूलों में नियमित पूर्णकालिक छात्र हों और किसी अन्य केंद्रीय प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति का लाभ नहीं उठा रहे हों।

इस योजना के तहत, डे-स्कॉलर्स को 10 महीने तक हर महीने ₹225 और छात्रावासों को ₹525 मिलते हैं। साथ ही, उन्हें क्रमशः ₹750 और ₹1000 की बुक और तदर्थ अनुदान भी मिलती है। इसके अलावा, दिव्यांग छात्रों को डे-स्कॉलर्स के लिए ₹600 प्रति माह और छात्रावासों के लिए ₹800 प्रति माह की अतिरिक्त अनुदान के हकदार हैं। यह योजना अच्छे आचरण और नियमित उपस्थिति के अधीन एक निरंतर मासिक छात्रवृत्ति प्रदान करती है।

⁷³⁸Government of India, "Annual Report 2023-24" (Ministry of Tribal Affairs, 2024), p.no.102.

⁷³⁹Ministry of Finance, *Public Financial Management System*, available at: <https://pfms.nic.in/Home.aspx> (last visited on Oct. 2, 2025).

⁷⁴⁰Ministry of Tribal Affairs, *Pre-Matric Scholarship Scheme*, available at: <https://dbttribal.gov.in/> (last visited on Sept. 8, 2025).

5.1.9. अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए राष्ट्रीय विदेशी छात्रवृत्ति, 2014

नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम ⁷⁴¹ भारत सरकार की एक पहल है जिसे अनुसूचित जनजाति के छात्रों को मास्टर, Ph.D. और पोस्ट-डॉक्टरल स्तरों पर विदेश में उच्च अध्ययन करने में सहायता करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। वार्षिक रूप से, 17 अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों और पीवीटीजी से 3 उम्मीदवारों का चयन किया जाता है। पात्रता के लिए परिवार की आय 6.00 लाख प्रति वर्ष, रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। योग्यता परीक्षा में न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक, और मास्टर के लिए 32 वर्ष की ऊपरी आयु सीमा का पालन, पीएच.डी के लिए 35 वर्ष, और पोस्ट-डॉक्टरल पाठ्यक्रमों के लिए 38 वर्ष की ऊपरी उम्र सीमा का पालन करना होगा। अनुदान का वितरण विदेशों में भारतीय मिशनों/दूतावासों के माध्यम से किया जाता है।

छात्रवृत्ति में वार्षिक रखरखाव भत्ता (संयुक्त राज्य अमेरिका में USD 15,400, यूनाइटेड किंगडम में £ 9,900) आकस्मिकता और उपकरण भत्ता (संयुक्त राज्य अमेरिका में USD 1,532, यूनाइटेड किंगडम में £ 1,116) ट्यूशन शुल्क, चिकित्सा बीमा, वीजा शुल्क, आकस्मिक यात्रा व्यय, हवाई मार्ग और स्थानीय यात्रा लागत सहित व्यापक लाभ शामिल हैं। आवेदनों को समर्पित पोर्टल के माध्यम से आमंत्रित किया जाता है, और पहुंच को आसान बनाने के लिए, योजना को उमंग ऐप, ⁷⁴² के साथ भी एकीकृत किया गया है, जिससे छात्र डिजिटल रूप से आवेदन कर सकते हैं और आवेदनों को ट्रैक कर सकते हैं।

5.1.10. अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति, 2015

अनुसूचित जनजाति छात्रों के लिए राष्ट्रीय फेलोशिप ⁷⁴³ एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जो पूरी तरह से भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है जिसका उद्देश्य अनुसूचित जनजाति के उन छात्रों को आर्थिक मदद देना है जो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों, संस्थानों और कॉलेजों से (जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) अधिनियम, 1956 के तहत आते हैं, यूजीसी सहायता प्राप्त करने वाले डीम्ड विश्वविद्यालयों, सरकार द्वारा वित्त पोषित संस्थानों और राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों से एम.फिल. और पीएचडी जैसी उच्च अध्ययन कर रहे हैं। इस फेलोशिप में एम.फिल के लिए दो साल और पीएचडी के छात्रों के लिए पांच साल तक की अवधि शामिल है, और इसकी दरें यूजीसी के नियमों के अनुसार संशोधित की गई हैं। एम.फिल स्कॉलर्स के लिए फेलोशिप ₹37,000 प्रति माह है, साथ ही आकस्मिक सहायता ₹10,000 (मानविकी/सामाजिक विज्ञान के लिए) और ₹12,000 (विज्ञान/इंजीनियरिंग/प्रौद्योगिकी के लिए) मिलता है। पीएचडी स्कॉलर्स के लिए फेलोशिप पहले दो साल के लिए ₹37,000 प्रति माह और बाकी तीन साल के लिए ₹42,000 है, साथ ही आकस्मिक सहायता ₹20,500 (मानविकी/सामाजिक विज्ञान के लिए) और ₹25,000 (विज्ञान/इंजीनियरिंग/प्रौद्योगिकी के लिए) मिलता है। इसके अलावा, छात्रों को यू. जी. सी. दरों पर मकान किराया भत्ता मिलता है और विकलांग छात्र 2000 प्रति माह के अनुरक्षण भत्ता (विकलांग व्यक्तियों के

⁷⁴¹Ministry of Tribal Affairs, About the National Overseas Scholarship for Scheduled Tribe Students and Portal, available at: <https://overseas.tribal.gov.in/> (last visited on Oct. 8, 2025).

⁷⁴²UMANG provides a single platform for all Indian Citizens to access pan-India e-Gov services ranging from Central to Local Government bodies. Ministry of Electronics and Information Technology, UMANG, available at: <https://web.umang.gov.in/landing/> (last visited on Oct. 12, 2025).

⁷⁴³Ministry of Tribal Affairs, About the National Fellowship Scheme and Portal, available at: <https://fellowship.tribal.gov.in/> (last visited on Oct. 8, 2025).

लिए एक परिचर के यात्रा खर्च को कवर करने के लिए वित्तीय सहायता) के हकदार हैं।

5.1.11. जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को सहायता, 2017

जनजातीय अनुसंधान संस्थान (टीआरआई) ⁷⁴⁴ राज्य समर्थित संस्थान हैं जो जनजातीय सामाजिक-आर्थिक विकास में चुनौतियों की पहचान करने के साथ-साथ जनजातीय संस्कृति, परंपराओं और ज्ञान प्रणालियों को संरक्षित करने के लिए अनुसंधान, मूल्यांकन अध्ययन और डेटा संग्रह में लगे हुए हैं। वे साक्ष्य-आधारित नीति, विधायी इनपुट और क्षमता निर्माण के लिए ज्ञान केंद्र के रूप में कार्य करते हैं। इन संस्थानों को मजबूत करने के लिए, जनजातीय कार्य मंत्रालय केंद्र प्रायोजित योजना 'टीआरआई को सहायता' को लागू करता है, जो बुनियादी ढांचे, अनुसंधान, प्रलेखन, प्रशिक्षण और सांस्कृतिक संवर्धन के लिए 100 प्रतिशत अनुदान सहायता प्रदान करता है।

इस योजना के तहत, टीआरआई आदिवासी संग्रहालयों, पुस्तकालयों और डिजिटल भंडारों की स्थापना, आदिवासी भाषाओं, रीति-रिवाजों और औषधीय प्रथाओं का दस्तावेजीकरण करने के साथ-साथ सरकारी हस्तक्षेपों की निगरानी और मूल्यांकन करने जैसी गतिविधियों का संचालन करते हैं। टीआरआई आदिवासियों को प्रभावित करने वाले कानूनों (जैसे एफआरए, 2006; पेसा अधिनियम, 1996; पीओए अधिनियम, 1989 और एलएआरआर अधिनियम, 2013) से संबंधित आदिवासियों और जनजातीय मामलों से जुड़े व्यक्तियों/संस्थानों दोनों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रमों पर भी ध्यान केंद्रित करते हैं। दिल्ली में स्थापित राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान (एनटीआरआई) के साथ देश भर में 28 टीआरआई हैं। यह वित्त पोषण टीआरआई द्वारा प्रस्तुत वार्षिक कार्य योजनाओं पर आधारित है और जनजातीय कार्य मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में परियोजना अनुमोदन समिति द्वारा अनुमोदित है। ⁷⁴⁵

5.1.12. वन धन योजना, 2018

वन धन योजना ⁷⁴⁶ एक जनजातीय आजीविका पहल है जो ग्राम स्तर पर वन धन स्व-सहायता समूहों (वीडीएसएचजी) की स्थापना करती है, जिसमें प्रत्येक में 20 वनवासी शामिल होते हैं जो एमएफपी, कृषि उत्पादों और औषधीय पौधों को इकट्ठा करने, प्रसंस्करण और मूल्यवर्धन में लगे होते हैं। 15 वीडीएसएचजी को एक वन धन विकास केंद्र (वीडीवीके) में समूहीकृत किया गया है, जो प्रशिक्षण, कच्चे माल के एकत्रीकरण, ब्रांडिंग, पैकेजिंग और विपणन में पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं से लाभान्वित होने के लिए 300 सदस्यों को एक साथ लाता है। यह योजना स्थायी आय और उद्यमिता के अवसर प्रदान करते हुए समुदाय-आधारित उद्यम बनाने के लिए जनजातीय ज्ञान और कौशल का लाभ उठाती है। भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ प्रशिक्षण, टूलकिट, कच्चा माल और बाजार पहुंच के साथ वीडीवीके का समर्थन करता है, जबकि राज्य सरकारें केंद्रों के लिए भूमि या भवन प्रदान करती हैं। योजना के तहत प्रशिक्षण कार्यक्रम जनजातीय उद्यमिता को मजबूत करने के लिए मूल्यवर्धन, पैकेजिंग, ब्रांडिंग और विपणन को भी एकीकृत करते हैं। राज्य स्तर की वकालत और नोडल विभागों के साथ समन्वय प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करता है,

⁷⁴⁴Ministry of Tribal Affairs, Tribal Research Institute, available at: <https://tribal.gov.in/> (last visited on Oct. 9, 2025).

⁷⁴⁵Government of India, "Annual Report 2023-24" (Ministry of Tribal Affairs, 2024), p.no. 20.

⁷⁴⁶Ministry of Tribal Affairs, Pradhan Mantri Van Dhan Yojana, available at: <https://tribal.gov.in/hi/pmvdya> (last visited on Nov. 5, 2025).

जिसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य तंत्र के तहत एमएफपी का विपणन और सभी स्वीकृत वीडिबीके का संचालन शामिल है।

5.1.13. प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महा अभियान, 2023

भारत सरकार ने 15 नवंबर, 2023 को पीवीटीजी की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों में सुधार के लिए लगभग 24,000 करोड़ रुपये के खर्च से प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम-जनमान) ⁷⁴⁷ की शुरुआत की। यह मिशन नौ मंत्रालयों/विभागों में 11 महत्वपूर्ण हस्तक्षेपों पर केंद्रित है, जिसका उद्देश्य पीवीटीजी परिवारों और बस्तियों को आवास, स्वच्छ पेयजल, स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण, सड़क और दूरसंचार संपर्क और स्थायी आजीविका के अवसर जैसी बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना है। प्रगति की निगरानी के लिए, जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा ब्लॉक स्तर के अधिकारियों द्वारा वास्तविक समय में रिपोर्टिंग के लिए एक पीएम-जनमान पोर्टल विकसित किया गया है, जो सूचना, शिक्षा और संचार अभियानों, शिविरों, लाभार्थियों और परिणामों का विवरण अपलोड करते हैं।

5.1.14. प्रधानमंत्री जन जातीय विकास मिशन, 2023

प्रधानमंत्री जन जातीय विकास मिशन (पीएमजेवीएम) ⁷⁴⁸ को जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा दो मौजूदा आजीविका योजनाओं के विलय के माध्यम से शुरू किया गया है, अर्थात् 'न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के माध्यम से एमएफपी के विपणन के लिए तंत्र और एमएफपी के लिए मूल्य श्रृंखला का विकास' और 'जनजातीय उत्पादों/उत्पादों के विकास और विपणन के लिए संस्थागत समर्थन'। योजना के लिए दिशा-निर्देश 27 मार्च 2023 को अधिसूचित किए गए थे।

यह योजना चयनित एम. एफ. पी. के लिए एम. एस. पी. के निर्धारण और घोषणा का प्रावधान करती है। अधिसूचित एमएसपी पर खरीद और विपणन संचालन नामित राज्य एजेंसियों द्वारा किया जाता है जब भी मौजूदा बाजार मूल्य निर्धारित एमएसपी से कम हो जाता है। तत्काल खरीद उपायों के साथ-साथ, यह योजना दीर्घकालिक चिंताओं को भी संबोधित करती है, जैसे कि स्थायी संग्रह प्रथाएं, मूल्यवर्धन, बुनियादी ढांचे का विकास, क्षमता निर्माण और जनजातीय उत्पादों के लिए एक मजबूत ज्ञान और बाजार खुफिया आधार का निर्माण।

पीएमजेवीएम के तहत, जनजातीय कार्य मंत्रालय ने 87 एमएफपी/वस्तुओं के लिए एमएसपी को अधिसूचित किया है। एमएसपी निर्धारण या संशोधन और एमएसपी सूची में वस्तुओं को जोड़ने या हटाने की सिफारिश करने के लिए 29 फरवरी 2024 को एक लघु वन उपज मूल्य निर्धारण प्रकोष्ठ का गठन किया गया था। राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों या नोडल विभागों द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार खरीद के लिए 100 प्रतिशत

⁷⁴⁷ Ministry of Tribal Affairs, Pradhan Mantri Janjati Adivasi Nyaya Maha Abhiyan, available at: <https://tribal.nic.in/PM-JANMAN.aspx> (last visited on Oct. 3, 2025).

⁷⁴⁸ Ministry of Tribal Affairs, Pradhan Mantri Janjatiya Vikas Mission, available at: <https://tribal.nic.in/sites/default/files/2023-06/PMJVM%20Guidelines%2027.03.2023.pdf> (last visited on Oct. 9, 2025).

केंद्रीय वित्त पोषित आवर्ती निधि प्रदान की जाती है। खरीद संचालन में होने वाले किसी भी नुकसान को केंद्र और राज्यों के बीच 75:25 के अनुपात में साझा किया जाता है।

5.1.15. धरती आभा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, 2025

धरती आभा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान ⁷⁴⁹ एक पहल है जिसका उद्देश्य जनजातीय क्षेत्रों में निरंतर विकास संबंधी रहने वाली समस्याओं को दूर करना है। यह बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और आजीविका सृजन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करके एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाता है। यह विभिन्न सरकारी योजनाओं के अभिसरण पर जोर देता है, यह सुनिश्चित करता है कि लाभ बिना दोहराव या बहिष्कार के जमीनी स्तर तक पहुंचे। यह पहल लक्षित हस्तक्षेपों के माध्यम से समग्र जनजातीय विकास को चलाने के लिए एस. डी. जी. के साथ संरेखित है। इनमें शामिल हैं:

- पक्का आवास, पाइप से पानी, बिजली, तरल पेट्रोलियम गैस और आदिवासी परिवारों के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा।
- गाँव के स्तर पर सभी मौसम की सड़कें, इंटरनेट की सुविधा और बेहतर स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा सुविधाएं।
- स्किल इंडिया ⁷⁵⁰ के माध्यम से कौशल विकास, उद्यमिता और व्यावसायिक पाठ्यक्रम
- पर्यटकों के आवास के माध्यम से आजीविका को मजबूत करना और कृषि, पशुपालन और मत्स्य पालन के लिए समर्थन, स्थायी आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करना।
- समग्र शिक्षा अभियान के माध्यम से शिक्षा की पहुंच और गुणवत्ता का विस्तार, बेहतर बुनियादी ढांचे के साथ (स्कूल से उच्च शिक्षा तक निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए छात्रावासों सहित) डिजिटल पहुंच, और सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक शिक्षा।
- शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर और टीकाकरण में राष्ट्रीय मानकों को प्राप्त करने पर विशेष ध्यान देने के साथ मोबाइल मेडिकल इकाइयों और सिकल सेल रोग के लिए लक्षित हस्तक्षेपों के माध्यम से स्वास्थ्य सेवा को मजबूत करना, इस प्रकार स्वस्थ जीवन और गरिमापूर्ण उम्र सुनिश्चित करना।

5.1.16. जनजातीय अनुसंधान सूचना, शिक्षा, संचार और कार्यक्रम

जनजातीय अनुसंधान सूचना, शिक्षा, संचार और कार्यक्रम (टीआरआई-ईसीई) ⁷⁵¹ एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसका उद्देश्य जनजातीय मुद्दों, संस्कृति और परंपराओं पर अनुसंधान, प्रलेखन और सूचना के प्रसार को बढ़ावा देना है।

⁷⁴⁹Ministry of Tribal Affairs, Launch of Dharti Aabha Janjatiya Gram Utkarsh Abhiyan, available at: <https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2130598> (last visited on Oct. 7, 2025).

⁷⁵⁰Skill India Digital Hub is a platform to skill, reskill and upskill Indian individual through an online training platform, API-based trusted skill credentials, payment and discovery layers for jobs and entrepreneurial opportunities. Ministry of Skill Development & Entrepreneurship, About, Skill India Digital Hub, available at: <https://www.skillindiadigital.gov.in/about-us> (last visited on Oct. 2, 2025).

⁷⁵¹Ministry of Tribal Affairs, Tribal Research, Information, Education, Communication and Events, available at: <https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2159087> (last visited on Oct. 10, 2025).

इस योजना के तहत, प्रतिष्ठित अनुसंधान संस्थानों, विश्वविद्यालयों और संगठनों को अध्ययन करने, पुस्तकों के प्रकाशन, श्रव्य-दृश्य सामग्री बनाने और आदिवासी परंपराओं, भाषाओं, कृषि प्रथाओं, कला रूपों और लोककथाओं का दस्तावेजीकरण करने में सहायता प्रदान की जाती है। यह योजना जनजातीय व्यक्तियों और संस्थानों के लिए सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रमों, साहित्यिक समारोहों, प्रतियोगिताओं और क्षमता निर्माण की पहल की सुविधा भी प्रदान करती है।

ऑनलाइन या भौतिक रूप से प्रस्तुत की गई परियोजनाओं का मूल्यांकन टीआरआई विभाग द्वारा किया जाता है और जनजातीय मामलों के सचिव की अध्यक्षता में परियोजना अनुमोदन समिति द्वारा अनुमोदित किया जाता है। इस योजना के प्रमुख उद्देश्यों में जनजातीय जीवन और आजीविका पर कार्य-उन्मुख अनुसंधान को बढ़ावा देना, सतत विकास के लिए नवीन रणनीतियां तैयार करना, पारिस्थितिक संरक्षण का समर्थन करना, सरकारी हस्तक्षेपों के बारे में जागरूकता फैलाना, विकास कार्यक्रमों का मूल्यांकन करना और जनजातीय संस्कृति और संबंधित नीतिगत उपायों की समझ बढ़ाने के लिए कार्यक्रम, प्रशिक्षण, सेमिनार और एक्सपोजर विजिट का आयोजन करना शामिल है।

जनजातीय कार्य मंत्रालय भी मौखिक लोककथाओं सहित आदिवासी संस्कृति पर काम लिखने या अनुवाद करने के लिए प्रतिष्ठित लेखकों, विद्वानों या संस्थानों को प्रति परियोजना 30,000 तक का अनुदान प्रदान करता है। इस योजना के तहत वित्तीय सहायता राज्य सरकारों, शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों, सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों, सार्वजनिक-निजी भागीदारी और अनुसंधान और विकास में उत्कृष्टता केंद्रों को भी दी जाती है।

5.2. सरकारी निकाय

5.2.1. ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (ट्राइफेड)⁷⁵² एक बहु-राज्य सहकारी समिति है जिसकी स्थापना 1987 में बहु-राज्य सहकारी समिति अधिनियम, 1984 के तहत की गई थी। यह जनजातीय उत्पादों के लिए एक सेवा प्रदाता और एक बाजार विकासकर्ता दोनों के रूप में कार्य करता है। "ट्राइब्स इंडिया" ब्रांड के तहत अपने खुदरा नेटवर्क के माध्यम से, ट्राइफेड देश भर में जनजातीय उत्पादों का विपणन करता है। इसके अलावा, यह अनुसूचित जनजाति के कारीगरों और एम. एफ. पी. संग्रहकर्ताओं को प्रशिक्षण प्रदान करके एक क्षमता निर्माता के रूप में कार्य करता है।

ट्राइफेड 14 क्षेत्रीय कार्यालयों के नेटवर्क के माध्यम से काम करता है और देश भर में 118 ट्राइब्स इंडिया आउटलेट्स के माध्यम से आदिवासी उत्पादों का विपणन करता है। इनमें आवधिक प्रदर्शनियों के अलावा 99 अपने बिक्री केंद्र, 11 खेप बिक्री केंद्र और 8 फ्रेंचाइजी आउटलेट शामिल हैं। आउटरीच का विस्तार करने के लिए, ट्राइफेड ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से आदिवासी उत्पादों को भी बढ़ावा देता है। जनजातीय कारीगरों के लिए स्थायी आजीविका के अवसर सुनिश्चित करने के लिए, ट्राइफेड विपणन प्रणालियों के लिए एक संस्थागत ढांचा बनाने में सक्रिय रूप से लगा हुआ है। इसने 3,069 जनजातीय आपूर्तिकर्ताओं को सूचीबद्ध किया है, जिसमें व्यक्तिगत जनजातीय कलाकार, स्वयं सहायता

⁷⁵² Ministry of Tribal Affairs, Tribal Cooperative Marketing Development Federation of India Limited, available at: <https://tribefed.tribal.gov.in/home> (last visited on Sep. 27, 2025).

समूह (एसएचजी),⁷⁵³ सहकारी समितियां और राज्य सरकार के संगठन शामिल हैं। इन आपूर्तिकर्ताओं को संरचित बाजारों से जोड़कर, ट्राइफेड का उद्देश्य आय सृजन को बढ़ाना, उद्यमिता को बढ़ावा देना और पारंपरिक आदिवासी शिल्प को संरक्षित करना है।

5.2.2. राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम

10 अप्रैल 2001 को स्थापित राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम (एन. एस. टी. एफ. डी. सी.)⁷⁵⁴, अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक विकास के लिए समर्पित जनजातीय कार्य मंत्रालय के तहत एक शीर्ष संगठन है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के तहत एक सरकारी कंपनी के रूप में निगमित, इसका प्रबंधन एक निदेशक मंडल द्वारा किया जाता है जिसमें केंद्र सरकार, राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियां (एससीए)⁷⁵⁵ राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, ट्राइफेड और प्रतिष्ठित जनजातीय प्रतिनिधि शामिल हैं। एनएसटीएफडीसी अनुसूचित जनजाति समुदायों के बीच स्व-रोजगार, कौशल विकास और आय सृजन को बढ़ावा देने के लिए रियायती वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

एन. एस. टी. एफ. डी. सी. के उद्देश्यों में अनुसूचित जनजातियों के लिए व्यवहार्य आर्थिक गतिविधियों की पहचान करना, कौशल बढ़ाने के लिए संस्थागत और नौकरी पर प्रशिक्षण प्रदान करना, एससीए और अन्य एजेंसियों को मजबूत करना, परियोजना निर्माण और कार्यान्वयन में सहायता करना और वित्त पोषित योजनाओं के परिणामों की निगरानी करना शामिल है। इस सहायता के लिए वे अनुसूचित जनजाति के सदस्य और स्वयं-सहायता समूह (SHG) पात्र हैं जिनकी सालाना पारिवारिक आय 3 लाख रुपये तक (ग्रामीण और शहरी) है। साथ ही, ऐसी सहकारी समितियां भी पात्र हैं जिनमें कम से कम 80 प्रतिशत सदस्य अनुसूचित जनजाति के हों और जो आय की इसी शर्त को पूरा करती हों।

एन. एस. टी. एफ. डी. सी. उद्योग, कृषि और सेवा जैसे क्षेत्रों में व्यवहार्य आय पैदा करने वाली परियोजनाओं के लिए सावधि ऋण सहित कई योजनाएं चलाता है; 90 प्रतिशत तक वित्तीय सहायता के साथ प्रति यूनिट 50 लाख रुपये तक का ऋण, पात्र अनुसूचित जनजाति महिलाओं के आर्थिक विकास के लिए रियायती योजना आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना के तहत अनुसूचित जनजाति की महिलाओं को 2 लाख रुपये तक की राशि, माइक्रो क्रेडिट योजना अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की छोटी ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 50, 000 प्रति अनुसूचित जनजाति सदस्य या प्रति एसएचजी 5 लाख रुपये तक का ऋण दिया जाता है; आदिवासी शिक्षा ऋण योजना

⁷⁵³ Self Help Groups (SHGs) are profit-making groups whose members all belong to Scheduled Tribes and have annual family incomes below twice the poverty line. These groups can receive micro-credit financial assistance through State Channelizing Agencies, provided they maintain eligibility throughout the loan period and include only Scheduled Tribe members from the state or union territory where the tribe is officially recognized.

⁷⁵⁴ Ministry of Tribal Affairs, *National Scheduled Tribes Finance and Development Corporation*, available at: <https://nstfdc.tribal.gov.in> (last visited on Oct. 4, 2025).

⁷⁵⁵ State Channelizing Agencies are bodies nominated by state governments that act as intermediaries to implement schemes by national-level financial institutions ensuring funds and assistance reach individual beneficiaries for economic development and skill enhancement. Ministry of Social Justice and Empowerment, *Channel Partners*, available at: <https://nsfdc.nic.in/channel-partners/scas> (last visited on Sep. 24, 2025).

अध्ययन करने वाले अनुसूचित जनजाति के पेशेवर/तकनीकी अध्ययन करने वाले छात्रों के लिए 10 लाख रुपये तक का ऋण दिया जाता है जिसमें शिक्षा मंत्रालय से ब्याज पर सब्सिडी का सपोर्ट भी मिलता है।

5.2.3. अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एनसीएसटी)⁷⁵⁶ का गठन 19 फरवरी 2004 को संविधान (89वां संशोधन) अधिनियम, 2003 के माध्यम से किया गया था, जिसने संविधान में एक नया अनुच्छेद 338ए⁷⁵⁷ जोड़ा था। यह भारत में अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों की रक्षा के लिए जिम्मेदार शीर्ष संवैधानिक निकाय है। एनसीएसटी में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और तीन सदस्य (एक महिला सहित) होते हैं आयोग का मुख्य कर्तव्य अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों से संबंधित सभी मामलों की जांच और निगरानी करना और ऐसे सुरक्षा उपायों के कामकाज का मूल्यांकन करना और अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों और सुरक्षा उपायों से वंचित होने के संबंध में विशिष्ट शिकायतों की जांच करना है।

एन. सी. एस. टी. के कार्यों में, जैसा कि अनुच्छेद 338ए (5) में निर्धारित किया गया है, अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रदान किए गए संवैधानिक और कानूनी सुरक्षा उपायों से संबंधित सभी मामलों की जांच और निगरानी और उनके कार्यान्वयन का मूल्यांकन करना शामिल है। एन. सी. एस. टी. को अनुसूचित जनजाति के अधिकारों से वंचित करने के संबंध में विशिष्ट शिकायतों की जांच करने का अधिकार है। यह सामाजिक-आर्थिक विकास की योजना प्रक्रिया में भी सलाह देता है और भाग लेता है और केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर ऐसी पहलों की प्रगति का मूल्यांकन करता है। इसके अलावा, यह इन सुरक्षा उपायों पर भारत के राष्ट्रपति को वार्षिक और विशेष रिपोर्ट प्रस्तुत करता है और उनके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सिफारिशें करता है।

इन जिम्मेदारियों के निर्वहन के लिए, एनसीएसटी को अनुच्छेद 338ए (8) के तहत दीवानी अदालत की शक्तियां प्राप्त हैं इनमें गवाहों को बुलाना और उनसे पूछताछ करना, दस्तावेजों की खोज और पेश करने की आवश्यकता, हलफनामों पर साक्ष्य प्राप्त करना, सार्वजनिक रिकॉर्ड की मांग करना और गवाहों और दस्तावेजों की जांच के लिए आयोग जारी करना शामिल है। इसके अलावा, अनुच्छेद 338ए (9) के तहत केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को अनुसूचित जनजातियों को प्रभावित करने वाले सभी प्रमुख नीतिगत मामलों पर एनसीएसटी से परामर्श करने के लिए संवैधानिक रूप से अनिवार्य किया गया है।

एन. सी. एस. टी. अतिरिक्त कार्य भी करता है। इनमें एम. एफ. पी. पर आदिवासियों के स्वामित्व अधिकारों को सुरक्षित करने, खनिज और जल संसाधनों पर उनके अधिकारों की रक्षा करने और व्यवहार्य आजीविका रणनीतियों को विकसित करने के उपाय शामिल हैं। एनसीएसटी विकास परियोजनाओं से विस्थापित जनजातीय समूहों की प्रभावी राहत और पुनर्वास सुनिश्चित करने, भूमि अलगाव को रोकने और पहले से ही प्रभावित लोगों के पुनर्वास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

यह वन संरक्षण और सामाजिक वनीकरण में जनजातीय भागीदारी बढ़ाने, पेसा अधिनियम, 1996 के पूर्ण कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने और

⁷⁵⁶The National Commission for Scheduled Tribes, available at: <https://ncst.nic.in/> (last visited on Sep. 17, 2025).

⁷⁵⁷The Constitution of India, 1950, art. 338A: “National Commission for Scheduled Tribes—(1) There shall be a Commission for the Scheduled Tribes to be known as the National Commission for the Scheduled Tribes.....”

भूमि क्षरण और आर्थिक अक्षमता का कारण बनने वाली खेती की प्रथाओं पर निर्भरता को कम करने के लिए काम करता है।

5.2.4. जनजातीय छात्रों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा सोसायटी

नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स (एनईएसटीएस) ⁷⁵⁸ भारत सरकार के जनजातीय मामलों के मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संगठन है। इसे 2019 में सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत एक सोसायटी के रूप में पंजीकृत किया गया था, जिसमें ईएमआरएस की योजना को लागू करने का प्राथमिक अधिदेश था। सोसायटी का नेतृत्व एन. ई. एस. टी. एस. के आयुक्त द्वारा किया जाता है, जो भारत सरकार के संयुक्त सचिव के पद का अधिकारी होता है। ई. एम. आर. एस. की स्थापना के माध्यम से अनुसूचित जनजाति के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से एन. ई. एस. टी. एस. की स्थापना की गई है।

इस प्रकार, इसके संचालन को सुव्यवस्थित करने और देश भर में ईएमआरएस के प्रभावी कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए, एनईएसटीएस द्वारा कई पहल की गई हैं। इनमें खेल, संस्कृति, मूल्य शिक्षा, कंप्यूटर कौशल, व्यक्तित्व विकास और प्रदर्शन यात्राओं पर केंद्रित कार्यक्रम शामिल हैं। 'जयकर अंतरिक्ष शिक्षा कार्यक्रम' ⁷⁵⁹ के तहत भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन और छात्रवृत्ति प्रशिक्षण के लिए दक्षिण फाउंडेशन जैसे संस्थानों के साथ साझेदारी का उद्देश्य सीखने के अवसरों का विस्तार करना है। ⁷⁶⁰ एनईएसटीएस ने अकादमिक और तकनीकी शिक्षा को बढ़ाने के लिए कौशल अधिग्रहण और आजीविका संवर्धन के लिए ज्ञान जागरूकता के तहत स्मार्ट क्लासरूम, कौशल प्रयोगशालाएं, ⁷⁶¹ और अकादमिक प्रतिभा और शिक्षण सहायता केंद्र भी शुरू किए हैं। इसके अलावा, राष्ट्रीय खेल बैठकें, सांस्कृतिक और साहित्यिक उत्सव, छठी कक्षा के छात्रों के लिए ब्रिज कोर्स और अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण संस्थान और संबद्ध खेल जैसे संस्थानों के माध्यम से साहसिक कार्यक्रम आदिवासी छात्रों के बीच आत्मविश्वास, टीम वर्क और एक्सपोजर को बढ़ावा देते हैं। ⁷⁶²

एनईएसटीएस का उद्देश्य ऐसे स्कूल स्थापित करना है जो ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभाशाली आदिवासी बच्चों को उनकी सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना गुणवत्तापूर्ण आधुनिक शिक्षा प्रदान करते हैं। ये स्कूल एक सामान्य पाठ्यक्रम, अंतर-क्षेत्रीय आदान-प्रदान और शिक्षाविदों, खेलों और व्यावसायिक कौशल में उत्कृष्टता के माध्यम से राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा देते हुए मूल्य-आधारित शिक्षा, पर्यावरण जागरूकता, खेल और सांस्कृतिक संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करते हैं। रिकॉर्ड के अनुसार, एनईएसटीएस में वर्तमान में 728 स्वीकृत ईएमआरएस और 495 कार्यात्मक

⁷⁵⁸ National Education Society for Tribal Students, *Tribal Transformation Through Education*, available at: <https://nests.tribal.gov.in/> (last visited on Oct. 5, 2025).

⁷⁵⁹ National Education Society for Tribal Students, *JAYAKAR (Jan Jatiya Yuva Antriksha Karyakram) is a space education programme undertaken for selected EMRS students in collaboration with ISRO*, available at: https://nests.tribal.gov.in/show_content.php?lang=1&level=1&ls_id=709&lid=370 (last visited on Nov. 5, 2025).

⁷⁶⁰ Dakshana Foundation, a non-government organisation, works towards reducing poverty through education by identifying talented yet underprivileged students and offering them rigorous 1-2 years' coaching to prepare for IIT and medical entrance examinations.

⁷⁶¹ Ministry of Skill Development and Entrepreneurship, *SANKALP*, available at: <https://www.sankalp.msde.gov.in/#/web/web-home> (last visited on Oct. 9, 2025).

⁷⁶² Atal Bihari Vajpayee Institute of Mountaineering and Allied Sports, available at: <https://abvimas.org/> (last visited on Oct. 9, 2025).

ईएमआरएस हैं, जिनमें 147,609 छात्र हैं।⁷⁶³ व्यय विभाग ने 740 ईएमआरएस के लिए 38,480 पदों के सृजन को मंजूरी दी है, जिसमें से 10,391 शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया पहले चरण में ही शुरू की जा चुकी है।

5.2.5. राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान

राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान (एनटीआरआई)⁷⁶⁴ का उद्घाटन 7 जून 2022 को भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली में किया गया था। यह जनजातीय अनुसंधान और नीति समर्थन के लिए एक राष्ट्रीय स्तर के केंद्र के रूप में कार्य करता है। यह अनुसंधान, मूल्यांकन अध्ययन, प्रशिक्षण और जागरूकता पहल में गुणवत्ता और एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए राज्य टीआरआई का मार्गदर्शन करता है। यह संस्थान साक्ष्य-आधारित अनुसंधान, क्षमता निर्माण और भाषाओं, आवासों और संस्कृति सहित आदिवासी विरासत को प्रदर्शित करने पर केंद्रित है। वर्तमान में उत्तराखंड के टीआरआई द्वारा मार्गदर्शित, एनटीआरआई ने देश भर में जनजातीय अनुसंधान के समन्वय और प्रबंधन को मजबूत करने के लिए प्रभावी कार्यक्रमों और कार्यक्रमों का आयोजन करना शुरू कर दिया है।

⁷⁶³ National Education Society for Tribal Students, *Tribal Transformation Through Education*, available at: <https://nests.tribal.gov.in/> (last visited on Oct. 5, 2025).

⁷⁶⁴ Ministry of Tribal Affairs, *National Tribal Research Portal*, available at: <https://tribal.gov.in/> (last visited on Oct. 3, 2025); Indian Institute of Public Administration, *National Tribal Research Institute*, available at: <https://www.iipa.org.in/cms/public/page/ntri> (last visited on Oct. 3, 2025).

अध्याय IV. तुलनात्मक संवैधानिक, विधायी और संस्थागत उपाय

यह अध्याय दुनिया के नॉर्डिक, ओशिनिया, उत्तरी अमेरिकी और दक्षिण अमेरिकी क्षेत्रों में चुनिंदा क्षेत्राधिकारों द्वारा अपने घरेलू क्षेत्रों में मौजूद स्वदेशी लोगों के (अंतर्निहित और अन्य) अधिकारों के संरक्षण की दिशा में अपनाए गए विभिन्न संवैधानिक, विधायी और नीतिगत दृष्टिकोण का सारांश प्रदान करता है, जिसमें निम्नलिखित विषय शामिल हैं: स्वदेशी लोगों के रूप में मान्यता व्यक्त करें; आत्म-निर्धारण, स्व-शासन, भागीदारी और परामर्श; भूमि, वन और प्राकृतिक संसाधनों का स्वामित्व और/या उपयोग; संस्कृति, परंपरा, धर्म और भाषा का संरक्षण; प्रथागत कानून और कानूनी प्रणालियाँ; और गैर-भेदभाव और सकारात्मक कार्यवाई।

1. नॉर्डिक देश

1.1. नॉर्वे

1.1.1. ऐतिहासिक उपचार

सामी लोग साप्मी बेल्ट के मूल निवासी हैं, जो नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड के उत्तरी हिस्सों और रूसी कोला प्रायद्वीप में फैला हुआ क्षेत्र है।⁷⁶⁵ राष्ट्रीय सीमाओं से विभाजित होने के बावजूद, उनकी पहचान एक है और वे ऐतिहासिक, सांस्कृतिक व भाषाई रूप से आपस में जुड़े हुए हैं।⁷⁶⁶ वर्षों से, सामी लोगों ने एक अर्ध-घुमंतू जीवन शैली का पालन किया है, जो पारंपरिक रूप से शिकार, मछली पकड़ने, खेती, बारहसिंगा पालन और हस्तशिल्प पर निर्भर है।⁷⁶⁷ सामी लोग सामूहिक रूप से सीडा प्रणाली के अनुसार संगठित होते हैं, जो विवाद समाधान, सामी व्यक्तियों के बीच भूमि, पानी और संसाधनों के वितरण और बारहसिंगा झुंडों, शिकार और मछली पकड़ने के प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।⁷⁶⁸

सामी लोगों के अधिकारों और दायित्वों को 1751 से 'लैप कोडिसिल' में संहिताबद्ध किया गया है, जो नॉर्वे और स्वीडन के बीच सीमा समझौते से जुड़ा एक संशोधन है, जिसके बारे में सामी लोगों का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत इसे एक बाध्यकारी संधि का कानूनी दर्जा प्राप्त है।⁷⁶⁹ लैप कोडिसिल

⁷⁶⁵International Work Group for Indigenous Affairs, *The Indigenous World 2025* (39th edn., 2025), p.no.499.

⁷⁶⁶United Nations Human Rights Council, *Report of the Special Rapporteur on the Rights of Indigenous Peoples, The Situation of the Sami People in the Sápmi region of Norway, Sweden and Finland*, UN Doc A/HRC/18/35/Add.2 (2011), para. 3.

⁷⁶⁷*Id.* at para. 5; International Work Group for Indigenous Affairs, *The Indigenous World 2025* (39th edn., 2025), p.no. 499.

⁷⁶⁸United Nations Human Rights Council, *Report of the Special Rapporteur on the Rights of Indigenous Peoples, The Situation of the Sami People in the Sápmi region of Norway, Sweden and Finland*, UN Doc A/HRC/18/35/Add.2 (2011), para. 6.

⁷⁶⁹Adrienne Davidson and Veldon Coburn, "Multiculturalism Policy Index: Indigenous Peoples: Indigenous Peoples Index Evidence 2021", *Queen's University* (2021), p.nos.32, 51, 59.

ने सामी लोगों को राष्ट्रीय क्षेत्रीय रेखा के दोनों ओर भूमि तक पहुंच के उनके पहले से मौजूद अधिकार की स्वीकृति में मुक्त मार्ग की गारंटी दी।⁷⁷⁰ हालाँकि, 19वीं शताब्दी के अंत में, टैक्सड लैंड सिस्टम के तहत, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड ने सामी पैतृक भूमि को जब्त कर लिया और उसमें संपत्ति के खिताब पूरी तरह से क्राउन में निहित कर दिए, इस प्रकार सामी लोगों के स्वामित्व अधिकारों को रद्द कर दिया गया।⁷⁷¹ 20वीं शताब्दी के मध्य तक, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड ने सामी लोगों के साथ इस तरह से व्यवहार करना जारी रखा जिससे वे नॉर्डिक क्षेत्र में बहुसंख्यक समुदायों के साथ घुलमिल गए।⁷⁷²

सामी परिषद, जिसकी स्थापना 1956 में विभिन्न देशों में सामी राष्ट्रीय संगठनों के गठबंधन के रूप में की गई थी, पहली अखिल-सामी संस्था थी, जो सपमी क्षेत्र में सामी लोगों के लिए प्रमुख प्रतिनिधि निकाय थी।⁷⁷³ सामी संसदीय परिषद की स्थापना बाद में 2000 में की गई थी, जो नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड की सामी संसदों से बनी थी, ताकि भाषा, शिक्षा, अनुसंधान और आर्थिक विकास के मुद्दों पर सामी लोगों की सीमा पार चिंताओं को उठाया जा सके।⁷⁷⁴ हालाँकि सामी लोगों ने एक नॉर्डिक सामी कन्वेंशन विकसित करने का प्रयास किया, एक क्षेत्रीय संधि जो सामी लोगों को नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड के एकमात्र स्वदेशी लोगों के रूप में मान्यता देती है, और आत्मनिर्णय, स्व-शासन, भूमि और प्राकृतिक संसाधनों, संस्कृति और भाषा संरक्षण, शिक्षा और आजीविका, और गैर-भेदभाव के उनके अधिकारों को सुरक्षित करती है,⁷⁷⁵ लेकिन इसे अभी तक मंजूरी नहीं मिली है।⁷⁷⁶

1.1.2. संवैधानिक मान्यता

फिर भी, यू. एन. डी. आर. आई. पी. के समर्थन पर नॉर्वे की सरकार द्वारा सामियों को नॉर्वे के स्वदेशी लोगों के रूप में स्वीकार किया गया है।⁷⁷⁷ इसके अलावा, संविधान में हाल ही में एक संशोधन के बाद, सामी को अब नॉर्वे में एक स्वदेशी लोगों के रूप में स्पष्ट रूप से मान्यता दी गई है। अनुच्छेद 108 (जिसे मूल रूप से 1988 में अनुच्छेद 110ए के रूप में अपनाया गया) सामी लोगों,

⁷⁷⁰*Ibid.*

⁷⁷¹*Id.* at 30, 57, 60.

⁷⁷²United Nations Human Rights Council, *Report of the Special Rapporteur on the Rights of Indigenous Peoples, The Situation of the Sami People in the Sápmi region of Norway, Sweden and Finland*, UN Doc A/HRC/18/35/Add.2 (2011), para. 7.

⁷⁷³*Id.* at para. 9.

⁷⁷⁴*Id.* at para. 10; International Work Group for Indigenous Affairs, *The Indigenous World 2025* (39th edn., 2025), p. no. 499.

⁷⁷⁵United Nations Human Rights Council, *Report of the Special Rapporteur on the Rights of Indigenous Peoples, The Situation of the Sami People in the Sápmi region of Norway, Sweden and Finland*, UN Doc A/HRC/18/35/Add.2 (2011), paras. 11, 12.

⁷⁷⁶Hester Swift, "Rights of Indigenous Peoples in Europe: Introduction and Starting Points for Research", *Institute of Advanced Legal Studies* (Jan. 6, 2025).

⁷⁷⁷United Nations Department of Public Information, *General Assembly Adopts Declaration on Rights of Indigenous Peoples: 'Major Step Forward' Towards Human Rights for All, Says President* (Sep. 13, 2007), available at: <https://press.un.org/en/2007/ga10612.doc.htm> (last visited on Nov. 11, 2025).

उनकी संस्कृति और पारंपरिक आजीविका की सुरक्षा को अनिवार्य करता है: ⁷⁷⁸ "सामी लोगों को अपनी भाषा, संस्कृति और जीवन शैली को संरक्षित करने और विकसित करने में सक्षम बनाने की जिम्मेदारी राज्य की है" ⁷⁷⁹ 2023 में, अनुच्छेद 108 को "सामी लोगों" को "सामी लोगों, एक स्वदेशी लोगों के रूप में" में संशोधित करने के लिए संशोधित किया गया था, जिससे उनकी स्वदेशी पहचान को स्पष्ट रूप से स्वीकार किया जा सके। ⁷⁸⁰

1.1.3. संस्कृति और परंपराओं का संरक्षण

नॉर्वे ने आई. सी. सी. पी. आर. को मानवाधिकार अधिनियम, 1999 के माध्यम से अपने घरेलू कानूनी ढांचे में शामिल किया है, जो संघर्ष की स्थिति में अन्य घरेलू कानूनों पर वरीयता रखता है। ⁷⁸¹ इसका अनुच्छेद 27 अल्पसंख्यकों को संविधान के अनुच्छेद 108 के समान सांस्कृतिक प्रथाओं को समान सुरक्षा प्रदान करता है: ⁷⁸²... "जातीय, धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यकों को... अपनी संस्कृति का आनंद लेने, अपने धर्म का पालन करने या अपनी भाषा का उपयोग करने के अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा" इसलिए स्वदेशी लोगों की "संस्कृति का ज़रूरी हिस्सा" है, तो झुंड रेनडियर, मछली और शिकार के अधिकार अनुच्छेद 27 के तहत संरक्षित हैं। ⁷⁸³ हाल ही में नॉर्वे के सर्वोच्च न्यायालय ने *फोसेन विंडमिल पार्क* मामले में सामी लोगों के संदर्भ में इसकी पुष्टि की थी। ⁷⁸⁴ एक ऐसे क्षेत्र में पवन ऊर्जा संयंत्रों के निर्माण के लिए दिए गए लाइसेंस के संबंध में जिसका उपयोग सामी लोग रेनडियर के शीतकालीन चराई के लिए करते हैं, इस प्रकार उनकी संस्कृति और पारंपरिक आजीविका पर प्रभाव डालते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि कोई भी हस्तक्षेप जिसका "सांस्कृतिक आनंद की संभावना पर ठोस, नकारात्मक प्रभाव पड़ता है" अनुच्छेद 27 का उल्लंघन करता है। ⁷⁸⁵ सर्वोच्च न्यायालय ने आगे फैसला सुनाया कि नॉर्वे के घरेलू कानून के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत स्वदेशी सांस्कृतिक अधिकारों का संरक्षण पूर्ण था; और परिणामस्वरूप, सामी लोगों

⁷⁷⁸ UN Human Rights Council, *Report of the Special Rapporteur on the Rights of Indigenous Peoples, The Situation of the Sami People in the Sápmi region of Norway, Sweden and Finland*, UN Doc A/HRC/18/35/Add.2 (2011), para. 14; Adrienne Davidson and Veldon Coburn, "Multiculturalism Policy Index: Indigenous Peoples: Indigenous Peoples Index Evidence 2021", *Queen's University* (2021), p. nos. 54, 55.

⁷⁷⁹ The Constitution of the Kingdom of Norway, 1814, art. 108.

⁷⁸⁰ Elin Hofverberg, "Norway Parliament Includes Indigenous People Designation in Constitution", *Law Library of Congress* (Jun. 8, 2023), available at: <https://www.loc.gov/item/global-legal-monitor/2023-06-07/norway-parliament-includes-indigenous-people-designation-in-constitution/> (last visited on Sep. 22, 2025).

⁷⁸¹ United Nations Human Rights Council, *Report of the Special Rapporteur on the Rights of Indigenous Peoples, The Situation of the Sami People in the Sápmi region of Norway, Sweden and Finland*, UN Doc A/HRC/18/35/Add.2 (2011), para. 20; Norwegian Human Rights Institution, "Chapter 7: Protection of Indigenous Rights under the ICCPR" in *Canary in the Coal Mine*, available at: <https://www.nhri.no/en/report/canary-in-the-coal-mine/7-protection-of-indigenous-rights-under-the-iccpr/> (last visited on Sep. 22, 2025).

⁷⁸² *The Sara Case*, HR-2017-2428-A (2017), para. 53.

⁷⁸³ Norwegian Human Rights Institution, "Chapter 7: Protection of Indigenous Rights under the ICCPR" in *Canary in the Coal Mine*, available at: <https://www.nhri.no/en/report/canary-in-the-coal-mine/7-protection-of-indigenous-rights-under-the-iccpr/> (last visited on Sep. 22, 2025); Human Rights Council, *General Comment No. 23* (CCPR/C/21/Rev.1/Add.5), para. 9.3; Human Rights Council, *Kitok v. Sweden* (CCPR/C/33/D/197/1985), paras. 9.6, 9.8; Human Rights Council, *Poma Poma v. Peru* (CCPR/C/95/D/1457/2006) paras. 7.2-7.4; Human Rights Council, *Apirana Mahuika et. al. v. New Zealand* (CCPR/C/70/D/547/1993), para. 9.3.

⁷⁸⁴ *The Fosen Case*, HR-2021-1975-S (2021).

⁷⁸⁵ *Id.* at para. 135.

के बारहसिंगा पालन के अधिकार को जलवायु हितों द्वारा अधिभावी नहीं किया जा सकता है: ⁷⁸⁶ "अल्पसंख्यक आबादी का संरक्षण अप्रभावी होगा, अगर बहुसंख्यक आबादी अपनी वैध जरूरतों के आधार पर इसे सीमित करने में सक्षम होती।" ⁷⁸⁷

हालांकि, यदि अनुच्छेद 27 अन्य मौलिक अधिकारों (जैसे कि एक स्वच्छ और स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार) के साथ संघर्ष करता है, तो अधिकारों को आनुपातिकता विश्लेषण के अनुसार "एक दूसरे के खिलाफ संतुलित और सामंजस्यपूर्ण" होना चाहिए। ⁷⁸⁸ तदनुसार, हाल का पारदर्शिता अधिनियम, 2022 व्यवसायों को सामी क्षेत्रों में विकास की योजना बनाते समय अनुच्छेद 27 के अनुरूप मूल्यांकन सहित उचित परिश्रम करने के लिए अनिवार्य करता है, और उन परियोजनाओं के कार्यान्वयन के साथ आगे बढ़ने से बचता है जो सामी सांस्कृतिक प्रथाओं और आजीविका पर पर्याप्त नकारात्मक प्रभाव डालने के लिए दृढ़ हैं। ⁷⁸⁹

1.1.4. प्रथागत कानून और कानूनी प्रणालियाँ

नॉर्वे के सर्वोच्च न्यायालय ने फेमंड सिजेटे मामले में ⁷⁹⁰ में कहा कि अनुच्छेद 108, जो आई. सी. सी. पी. आर. के अनुच्छेद 27 पर आधारित है, ⁷⁹¹ "एक स्वतंत्र कानूनी आधार का गठन करता है जहां कानून के अन्य स्रोत कोई जवाब नहीं देते हैं" ⁷⁹² और तब से, कई अवसरों पर, कानूनी नियमों की व्याख्या और पारंपरिक रीति-रिवाजों को लागू करने में इसके महत्व को दोहराया है। ⁷⁹³ फिर भी, सामी प्रथागत कानून और भूमि और पानी के लिए सामी प्रथागत अधिकारों को नॉर्वे द्वारा मान्यता नहीं दी गई है। ⁷⁹⁴ ये काफी हद तक अनिर्दिष्ट हैं, लेकिन पारंपरिक रूप से सामी लोगों के साझा ज्ञान के भीतर हैं। ⁷⁹⁵ फिर भी, 2004 में, नॉर्वे ने सामी प्रथागत कानून की रक्षा के उद्देश्य से सामी क्षेत्रों के लिए एक विशेष जिला अदालत की स्थापना की,

⁷⁸⁶ *Id.* at para. 127.

⁷⁸⁷ *Id.* at para. 129.

⁷⁸⁸ *Id.* at para. 130.

⁷⁸⁹ Norwegian Human Rights Institution, "Chapter 10: Business responsibilities to respect Sami rights in the context of climate change", in *Canary in the Coal Mine*, available at: <https://www.nhri.no/en/report/canary-in-the-coal-mine/10-business-responsibility-to-respect-sami-rights-in-the-context-of-climate-change/> (last visited on Sep. 22, 2025); The Transparency Act, 2022, s. 4(b).

⁷⁹⁰ *The Femundsjø*, HR-2018-872-A(2018), para. 39.

⁷⁹¹ *The Fosen Case*, HR-2021-1975-S(2021), para. 35.

⁷⁹² *The Femundsjø*, HR-2018-872-A(2018), para. 39.

⁷⁹³ Norwegian Human Rights Institution, "Chapter 2: International conventions and their status in Norwegian Law" in *Canary in the Coal Mine*, available at: <https://www.nhri.no/en/report/human-rights-protection-against-interference-in-traditional-sami-areas/2-international-conventions-and-their-status-in-norwegian-law/> (last visited on Sep. 22, 2025); Norwegian Human Rights Institution, "Chapter 4: Human Rights Protection Against Interference—The supreme Court" in *Canary in the Coal Mine*, available at: <https://www.nhri.no/en/report/human-rights-protection-against-interference-in-traditional-sami-areas/4-human-rights-protection-against-interference-the-supreme-court/> (last visited on Sep. 22, 2025).

⁷⁹⁴ Asbjørn Eide, "Legal and Normative Bases for Saami Claims to Land in the Nordic" 8 *International Journal on Minority and Group Rights* 135 (2001).

⁷⁹⁵ Terje Brantenberg, "Indigenous Rights and Norwegian Law: The Problem of Sami Customary Law and Pastoral Rights in Norway", 5th *Common Property Conference of the International Association for the Study of Common Property* (May 1995).

जो सामी भाषा और संस्कृति से अच्छी तरह वाकिफ न्यायाधीशों से बनी थी।⁷⁹⁶

1.1.5. आत्मनिर्णय, स्व-शासन, भागीदारी और परामर्श

सामी अधिनियम, 1987, सामी लोगों के उन मुद्दों पर परामर्श करने के अधिकार की रक्षा करता है जो सीधे और स्पष्ट रूप से उनसे संबंधित हों- यानी ऐसे विधायी, नियामक और प्रशासनिक उपाय जो विशेष रूप से सामी हितों को प्रभावित कर सकते हैं, अच्छे विश्वास में प्रारंभिक परामर्श के अधीन होना चाहिए।⁷⁹⁷ इस उद्देश्य के लिए, नॉर्वे की सामी संसद की स्थापना⁷⁹⁸ में एक प्रतिनिधि, सलाहकार और सलाहकार निकाय के रूप में की गई है और यह सामी संप्रभुता,⁷⁹⁹ आत्मनिर्णय और स्व-शासन के लिए प्रमुख माध्यम के रूप में कार्य करती है।⁸⁰⁰ सामी संसद एक राजनीतिक निकाय के रूप में कार्य करती है जिसमें सामी लोगों द्वारा हर चार साल में चुने गए 39 सदस्य शामिल होते हैं,⁸⁰¹ जबकि संबंधित नॉर्वेजियन अधिकारियों द्वारा इसे सौंपे गए कर्तव्यों का पालन करते हैं, और उन मुद्दों पर सिफारिशें देते हैं जो सामी लोगों को प्रभावित कर सकते हैं।⁸⁰² हालाँकि सामी क्षेत्रों पर इसकी कोई विधायी शक्तियाँ या प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र नहीं हैं,⁸⁰³ सामी संसद सामी लोगों को निर्णय लेने में सीधे बोलने की अनुमति देती है।⁸⁰⁴

सामी संसद और नॉर्वे की सरकार ने विधायी और प्रशासनिक उपायों से संबंधित परामर्श प्रक्रियाओं पर एक समझौता भी किया है, इस समझौते के तहत, नॉर्वे के अधिकारियों के लिए यह ज़रूरी है कि वे "उन संबंधित मामलों के बारे में पूरी जानकारी दें जिनका सामी लोगों पर सीधा असर पड़ सकता है, और साथ ही ऐसे मामलों से निपटने के हर चरण पर संबंधित चिंताओं के बारे में भी जानकारी दें।"⁸⁰⁵

इस समझौते की शर्तें आईएलओ कन्वेंशन नं. 169,⁸⁰⁶ के अनुरूप हैं। यह भी

⁷⁹⁶ Øyvind Ravna, "The Legal Protection of the Rights and Culture of Indigenous Sami People in Norway" 11 (6) *Journal of Siberian Federal University* 1578 (2013).

⁷⁹⁷ The Sámi Act, 1987, s.4.

⁷⁹⁸ *Id.* ss.1.2,2.

⁷⁹⁹ Hester Swift, "Rights of Indigenous Peoples in Europe: Introduction and Starting Points for Research", *Institute of Advanced Legal Studies* (Jan.6,2025).

⁸⁰⁰ United Nations Human Rights Council, *Report of the Special Rapporteur on the Rights of Indigenous Peoples, The Situation of the Sami People in the Sápmi region of Norway, Sweden and Finland*, UN Doc A/HRC/18/35/Add.2 (2011), para. 37.

⁸⁰¹ The Sámi Act, 1987, ss.2.3,2.4.

⁸⁰² United Nations Human Rights Council, *Report of the Special Rapporteur on the Rights of Indigenous Peoples, The Situation of the Sami People in the Sápmi region of Norway, Sweden and Finland*, UN Doc A/HRC/18/35/Add.2 (2011), para. 16.

⁸⁰³ Hester Swift, "Rights of Indigenous Peoples in Europe: Introduction and Starting Points for Research", *Institute of Advanced Legal Studies* (Jan.6,2025).

⁸⁰⁴ Adrienne Davidson and Veldon Coburn, "Multiculturalism Policy Index: Indigenous Peoples: Indigenous Peoples Index Evidence 2021", *Queen's University* (2021), p.no.51.

⁸⁰⁵ The Procedures for Consultations between the State Authorities and The Sami Parliament of Norway (May 11,2005), s.3.

⁸⁰⁶ United Nations Human Rights Council, *Report of the Special Rapporteur on the Rights of Indigenous Peoples, The Situation of the Sami People in the Sápmi region of Norway, Sweden and Finland*, UN Doc A/HRC/18/35/Add.2 (2011), para. 16.

सिफारिश करता है कि जब तक सामी संसद और नॉर्वेजियन अधिकारी किसी सहमति पर पहुँचने की उम्मीद रखते हैं, तब तक बातचीत बंद नहीं की जानी चाहिए।⁸⁰⁷ नॉर्वे ने यह सुनिश्चित करने के लिए सह-प्रबंधन व्यवस्था भी की है कि प्राकृतिक संसाधनों और संरक्षित क्षेत्रों के संबंध में निर्णय लेने में सामी दृष्टिकोण और पारंपरिक ज्ञान का पर्याप्त रूप से ध्यान रखा जाए।⁸⁰⁸ हालाँकि, सारा मामले में, नॉर्वे के सर्वोच्च न्यायालय ने पाया कि 'प्रभावी भागीदारी' के लिए आवश्यक नहीं है कि स्वदेशी लोगों की भागीदारी वास्तव में निर्णय लेने को प्रभावित करे।⁸⁰⁹

1.1.6. क्षेत्रों, वनों और प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग

रेनडियर पालन अधिनियम, 1978 (जिसमें 2007 में संशोधन किया गया था) के तहत, सामी लोगों को चरागाह वाले इलाकों में रेनडियर चराने का विशेष अधिकार (उपयोग का अधिकार) दिया गया है (चाहे उन ज़मीनों का मालिक कोई भी हो), बशर्ते कि सामी व्यक्तियों का रेनडियर चराने वाले परिवार से ज़रूरी पारिवारिक संबंध हो।⁸¹⁰ 2007 में लागू किए गए संशोधनों ने घरेलू कानून और पारंपरिक सामी भूमि प्रबंधन रीति-रिवाजों के बीच की खाई को कम करने के लिए सीडा को रेनडियर पालन के लिए एक महत्वपूर्ण प्रबंधन उपकरण के रूप में फिर से स्थापित किया।⁸¹¹

वन संसाधनों के स्थायी प्रबंधन को बढ़ावा देने और जैविक विविधता को सुरक्षित करने के उद्देश्य से अधिनियमित वानिकी अधिनियम, 2005 में कहा गया है कि इसके प्रावधान "सामी रेनडियर चरवाहों के लकड़ी और ईंधन के अधिकारों के उल्लंघन में लागू नहीं किए जा सकते हैं।"⁸¹² समुद्री संसाधन अधिनियम, 2010, मछली पकड़ने की प्रथाओं के विनियमन में सामी संस्कृति को भी ध्यान में रखता है।⁸¹³ फिर भी, नॉर्वे और फिनलैंड ने 2017 में अफसोसजनक रूप से डीटनु/ताना समझौते में प्रवेश किया, जिसने नॉर्वे और फिनलैंड की सामी संसदों के कड़े विरोध के बावजूद पारंपरिक सामी मछली पकड़ने के तरीकों, विशेष रूप से नेट-फिशिंग को गंभीर रूप से प्रतिबंधित कर दिया।⁸¹⁴

1.1.7. पैतृक भूमि का शीर्षक

नॉर्वे की सरकार, नगर पालिकाओं के सहयोग से, मूल रूप से भूमि और संसाधनों के

⁸⁰⁷The Procedures for Consultations between the State Authorities and The Sami Parliament of Norway (May 11, 2005), s.6.

⁸⁰⁸Ole Kristian Fauchald and Lars H. Gulbrandsen, "The Norwegian reform of protected areas management: A grand experiment with delegation of authority?" 17(2) *Local Environment* 204 (2012).

⁸⁰⁹The Sara Case, HR-2017-2428-A (2017).

⁸¹⁰United Nations Human Rights Council, Report of the Special Rapporteur on the Rights of Indigenous Peoples The Situation of the Sami People in the Sápmi region of Norway, Sweden and Finland, UN Doc A/HRC/18/35/Add.2 (2011), para. 19.

⁸¹¹*Ibid.*

⁸¹²The Forestry Act, 2005, preamble, s.2.

⁸¹³The Marine Resources Act, 2010, s.7(g).

⁸¹⁴Adrienne Davidson and Veldon Coburn, "Multiculturalism Policy Index: Indigenous Peoples: Indigenous Peoples Index Evidence 2021", *Queen's University* (2021), p.no.33.

प्रबंधन के लिए जिम्मेदार थी।⁸¹⁵ सामी संसद और नॉर्वे की संसद के सहयोगात्मक प्रयासों से उपजे फिनमार्क अधिनियम, 2005 के अधिनियमन तक इस संबंध में सामी लोगों के सामूहिक अधिकारों को मान्यता नहीं दी गई थी।⁸¹⁶ फिनमार्क अधिनियम, 2005 में यह निर्धारित किया गया है कि सामी लोगों (साथ ही साथ नॉर्वे में कुछ जातीय अल्पसंख्यकों) ने भूमि और पानी के अपने प्रथागत उपयोग के माध्यम से इस पर अधिकार प्राप्त कर लिए हैं,⁸¹⁷ इस प्रकार फिनमार्क काउंटी में राज्य के स्वामित्व के तहत अधिकांश भूमि और प्राकृतिक संसाधनों का प्रशासन,⁸¹⁸ लेकिन स्वामित्व नहीं, फिनमार्क एस्टेट को हस्तांतरित किया गया है,⁸¹⁹ छह व्यक्तियों के बोर्ड द्वारा शासित एक स्वायत्त कानूनी इकाई है, जिनमें से तीन सामी संसद द्वारा चुने गए हैं।⁸²⁰ तदनुसार, सामी लोगों और अन्य जातीय अल्पसंख्यकों को मछली पकड़ने, लकड़ी काटने, कुछ पेड़ों को काटने, शिकार करने, चारा उगाने और बारहसिंगा पालन करने का अधिकार है।⁸²¹ फिनमार्क अधिनियम, 2005 में यह भी अपेक्षा की गई है कि फिनमार्क संपदा के भीतर भूमि और प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन के संबंध में निर्णय लेने में सामी लोगों से परामर्श किया जाए।⁸²² विशेष रूप से, फिनमार्क अधिनियम, 2005 ने फिनमार्क आयोग की स्थापना की, जिसे फिनमार्क काउंटी,⁸²³ के भीतर भूमि के लिए सामी प्रथागत अधिकार की जांच और दस्तावेजीकरण का काम सौंपा गया और फिनमार्क के लिए अनकल्टिवेटेड लैंड ट्रिब्यूनल के समक्ष भूमि दावों के निपटान के लिए कानूनी ढांचा निर्धारित किया गया।⁸²⁴ हालांकि, करास्जोक मामले में नॉर्वे के सर्वोच्च न्यायालय के एक हालिया निर्णय में फैसला सुनाया कि करास्जोक नगर पालिका में आम भूमि के लिए संपत्ति का अधिकार फिनमार्क एस्टेट में निहित था, लेकिन सामी लोगों या समग्र रूप से नगर पालिका की सामान्य आबादी में निहित नहीं था।⁸²⁵

1.1.8. भाषा का संरक्षण

सामी अधिनियम, 1987 नॉर्वेजियन और सामी दोनों भाषाओं को आधिकारिक भाषाओं के रूप में मान्यता देता है:
"सामी और

⁸¹⁵United Nations Human Rights Council, *Report of the Special Rapporteur on the Rights of Indigenous Peoples, The Situation of the Sami People in the Sápmi region of Norway, Sweden and Finland*, UN Doc A/HRC/18/35/Add.2 (2011), para. 18.

⁸¹⁶*Id.* at para. 44.

⁸¹⁷The Finnmark Act, 2005, s.5.

⁸¹⁸Ministry of Justice and the Police and the Ministry of Local Government and Regional Development, "The Finnmark Act – A Guide", Publication No. G-0381B+S.

⁸¹⁹Adrienne Davidson and Veldon Coburn, "Multiculturalism Policy Index: Indigenous Peoples: Indigenous Peoples Index Evidence 2021", *Queen's University* (2021), p.no.50; John Bernhard Henriksen, "The Continuous Process of Recognition and Implementation of the Sami People's Right to Self-Determination" 21(1) *Cambridge Review of International Affairs* 32-33 (2008).

⁸²⁰The Finnmark Act, 2005, ss.6,7.

⁸²¹*Id.* s.23.

⁸²²Adrienne Davidson and Veldon Coburn, "Multiculturalism Policy Index: Indigenous Peoples: Indigenous Peoples Index Evidence 2021", *Queen's University* (2021), p.no.54; The Finnmark Act, 2005, s.28.

⁸²³The Finnmark Act, 2005, s.29.

⁸²⁴*Id.* ss.36-43

⁸²⁵*The Finnmark Estate v. Karasjok Sami Association*, HR-2024-982-S (2024), para.208.

नॉर्वेजियन समान मूल्य की भाषाएँ हैं।⁸²⁶ सामी भाषा अधिनियम, 1992, सामी आबादी वाले क्षेत्रों में सामी भाषा (यूनेस्को द्वारा लुप्तप्राय के रूप में वर्गीकृत)⁸²⁷ के उपयोग को और अधिकृत करता है, इस प्रकार सामी लोगों को अपनी मूल भाषा में नॉर्वेजियन अधिकारियों के साथ संवाद करने का अधिकार देता है।⁸²⁸ प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा और प्रशिक्षण अधिनियम, 1999 सामी जिलों के भीतर प्राथमिक और निम्न माध्यमिक विद्यालयों में सामी भाषा में अध्ययन करने के सामी बच्चों के अधिकार की रक्षा करता है।⁸²⁹ सामी जिलों के बाहर भी, 10 या अधिक सामी छात्र सामूहिक रूप से यह मांग करने के अधिकारी हैं कि उन्हें सामी भाषा में पढ़ाया जाए।⁸³⁰

1.1.9. गैर-भेदभाव और सकारात्मक कार्रवाई

हालाँकि नॉर्वे ने सामी लोगों के खिलाफ सकारात्मक कार्रवाई करने वाले विशिष्ट कानूनों को नहीं अपनाया है,⁸³¹ वे समानता को बढ़ावा देने, समान अधिकारों और अवसरों को सुनिश्चित करने और भेदभाव को प्रतिबंधित करने के उद्देश्य से अधिनियमित भेदभाव विरोधी अधिनियम, 2006 से लाभान्वित होते हैं।⁸³² भेदभाव विरोधी अधिनियम, 2006 सार्वजनिक प्राधिकरणों, सार्वजनिक नियोक्ताओं, निजी नियोक्ताओं (50 से अधिक कर्मचारियों वाले) और नियोक्ता/कर्मचारी संगठनों को वेतन, काम करने की स्थिति, पदोन्नति, विकास के अवसरों और उत्पीड़न के खिलाफ सुरक्षा से संबंधित मामलों में विधायी इरादे को पूरा करने की दिशा में व्यवस्थित रूप से, सक्रिय रूप से और लक्षित तरीके से काम करने का आदेश देता है।⁸³³ भेदभाव विरोधी अधिनियम, 2006 भी नियोक्ताओं को रोजगार समानता के लिए सकारात्मक कदम उठाने की अनुमति देता है।⁸³⁴ नॉर्वे ने शैक्षणिक संस्थानों, विशेष रूप से चिकित्सा क्षेत्र में सामी छात्रों के लिए सीटों के आरक्षण के लिए भी उपाय किए हैं।⁸³⁵

2018 में, नॉर्वे ने एक संयुक्त सत्य आयोग की स्थापना की, जिसमें नॉर्वेजियन संसद द्वारा नियुक्त 12 विशेषज्ञ शामिल थे, सामी लोगों, केंस और फॉरेस्ट फिन्स (नॉर्वे में दो अल्पसंख्यक समुदाय) के लिए नॉर्वेजियनकरण नीति के

⁸²⁶The Sámi Act, 1987, s.1.5.

⁸²⁷United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation, *Atlas of the World's Languages in Danger* (2010), p. no.35.

⁸²⁸Adrienne Davidson and Veldon Coburn, "Multiculturalism Policy Index: Indigenous Peoples: Indigenous Peoples Index Evidence 2021", *Queen's University* (2021), p. no. 52; Kelly Gallagher-Mackay, "Affirmative Action and Aboriginal Government: The Case for Legal Education in Nunavut" 14(2) *Canadian Journal of Law and Society* 21-75 (1999).

⁸²⁹The Primary and Secondary Education and Training Act, 1999, s.6.2.

⁸³⁰*Ibid.*

⁸³¹Adrienne Davidson and Veldon Coburn, "Multiculturalism Policy Index: Indigenous Peoples: Indigenous Peoples Index Evidence 2021", *Queen's University* (2021), p.no.55.

⁸³²The Anti-Discrimination Act, 2006, s.1.

⁸³³The Norwegian Ministry of Children and Equality, *Action Plan to Promote Equality and Prevent Ethnic Discrimination* (2009), p.no.58.

⁸³⁴The Anti-Discrimination Act, 2006, s.8.

⁸³⁵M. Gaski, B. Abelsen and T. Hasvold, "Forty years of allocated seats for Sami medical students—has preferential admission worked?" 8(2) *Rural and Remote Health* 1 (2008).

ऐतिहासिक और निरंतर प्रभावों की जांच करने के उद्देश्यों के साथ, सामी लोगों को हुए नुकसान को संबोधित करना, और इस तरह की कठोर आत्मसात नीति के परिणामस्वरूप सामी लोगों (सामूहिक और व्यक्तिगत रूप से) के प्रतिकूल अनुभवों की ओर ध्यान आकर्षित करना।⁸³⁶

1.2. स्वीडन

1.2.1. संवैधानिक और कानूनी मान्यता

सामी को पहली बार 1977 में स्वीडिश संसद⁸³⁷ द्वारा एक स्वदेशी लोगों के रूप में मान्यता दी। 2011 में संविधान में एक संशोधन के अनुसार, सामी लोगों को अब स्वीडन में एक स्वदेशी लोगों (अन्य अल्पसंख्यकों से अलग) के रूप में संवैधानिक रूप से मान्यता दी गई है, और उन्हें अपनी पारंपरिक जीवनशैली की सुरक्षा का अधिकार प्राप्त है।⁸³⁸ अनुच्छेद 2 में कहा गया है: "सामी लोगों और जातीय, भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों के अपने सांस्कृतिक और सामाजिक जीवन को संरक्षित करने और विकसित करने के अवसरों को बढ़ावा दिया जाएगा।"⁸³⁹ सामी लोगों को भी स्वीडन सरकार अधिनियम, 1998 में राष्ट्रीय अल्पसंख्यकों के तहत एक राष्ट्रीय जातीय अल्पसंख्यक का दर्जा प्राप्त है।

⁸⁴⁰

1.2.2. आत्मनिर्णय, स्व-शासन, भागीदारी और परामर्श

सामी संसद अधिनियम, 1992 ने स्वीडिश सरकार के लिए एक प्रशासनिक एजेंसी के रूप में दोहरी भूमिका के साथ स्वीडन की सामी संसद की स्थापना की, और एक निर्वाचित निकाय जिसमें हर चार साल में सामी लोगों द्वारा चुने गए 31 प्रतिनिधि शामिल थे।⁸⁴¹ सामी संसद का प्राथमिक कार्य सामी संगठनों और गतिविधियों के लिए राज्य निधि आवंटित करने, सामी भाषा को संरक्षित और बढ़ावा देने, सामुदायिक विकास में भाग लेने, जिसमें रेनडियर पशुपालन और भूमि और पानी के उपयोग के संबंध में, और सामी जीवन स्थितियों पर रिपोर्टिंग के माध्यम से "स्वीडन में सामी

⁸³⁶International Work Group for Indigenous Affairs, *The Indigenous World 2023* (37th edn., 2023), p.no.467.

⁸³⁷Adrienne Davidson and Veldon Coburn, "Multiculturalism Policy Index: Indigenous Peoples: Indigenous Peoples Index Evidence 2021", *Queen's University* (2021), p. no. 62; Implementation of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, *Fifth periodic report submitted by States parties under Article 15 and 17 of the Covenant: Finland*, UN Doc E/C.12/FIN/5 (Jan. 16, 2008).

⁸³⁸United Nations Human Rights Council, *Report of the Special Rapporteur on the Rights of Indigenous Peoples, The Situation of the Sami People in the Sápmi region of Norway, Sweden and Finland*, UN Doc A/HRC/18/35/Add.2 (2011), para.21.

⁸³⁹The Constitution of Sweden, art.2.

⁸⁴⁰Adrienne Davidson and Veldon Coburn, "Multiculturalism Policy Index: Indigenous Peoples: Indigenous Peoples Index Evidence 2021", *Queen's University* (2021), p.no.62.

⁸⁴¹The Sámi Parliament Act, 1992, ch.2, s.2, ch.3, s.1; United Nations Human Rights Council, *Report of the Special Rapporteur on the Rights of Indigenous Peoples, The Situation of the Sami People in the Sápmi region of Norway, Sweden and Finland*, UN Doc A/HRC/18/35/Add.2 (2011), para. 42.

⁸⁴²The Sámi Parliament Act, 1992, ch. 1, s.1; United Nations Human Rights Council, *Report of the Special Rapporteur on the Rights of Indigenous Peoples, The Situation of the Sami People in the Sápmi region of Norway, Sweden and Finland*, UN Doc A/HRC/18/35/Add.2 (2011), paras.23,42.

संस्कृति से संबंधित मुद्दों की निगरानी⁸⁴² करना है।⁸⁴³ हालाँकि, सामी संसद को स्वीडिश सरकार और स्वीडिश संसद के अधिकार के तहत रखा गया है और इसे कानूनों, अध्यादेशों, दिशानिर्देशों और निर्णयों द्वारा नियंत्रित किया जाता है।⁸⁴⁴ सामी संसद इसलिए सामी शासन के संबंध में स्वीडिश सरकार द्वारा जारी निर्देशों और इस संबंध में स्वीडिश संसद द्वारा तैयार की गई नीतियों को लागू करने के लिए बाध्य है।⁸⁴⁵

इसलिए, सामी संसद, हालांकि एक सलाहकार की भूमिका वाला एक सलाहकार तंत्र है, जमीन पर वास्तविक प्रभाव का अभाव है-स्वीडिश अधिकारी कानूनी रूप से सामी संसद के साथ परामर्श करने के लिए बाध्य नहीं हैं, और सामी संसदीय सुनवाई के बाद अनिवार्य कार्रवाई नहीं की जाती है।⁸⁴⁶ सामी संसद को निर्णय लेने या विधायी मामलों में भाग लेने का भी अधिकार नहीं है, उसे प्रशासनिक निर्णयों पर वीटो करने का कोई अधिकार नहीं है, और सामी हितों के मामलों में 'अनिवार्य रेफरल निकाय' का दर्जा नहीं है।⁸⁴⁷ स्वीडन फिर भी स्वीकार करता है कि स्वदेशी लोगों को आईसीसीपीआर और आईसीईएससीआर के अनुच्छेद 1 के अनुसार आत्मनिर्णय का अधिकार है, लेकिन स्वीडन की क्षेत्रीय अखंडता और राजनीतिक एकता के अधीन है।⁸⁴⁸

1.2.3. क्षेत्रों, वन और प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग और पैतृक भूमि का शीर्षक

रेनडियर चराई अधिनियम, 1886 को अपनाने के साथ, सामी लोगों के अपने पारंपरिक क्षेत्रों, जल और प्राकृतिक संसाधनों पर पहले से मान्यता प्राप्त अधिकारों को समाप्त कर दिया गया था, और उसमें संपत्ति का अधिकार विशेष रूप से स्वीडिश क्राउन में निहित था।⁸⁴⁹ हालाँकि, स्वीडन के सर्वोच्च न्यायालय ने कराधान वाले पहाड़ों के मामले में अपने ऐतिहासिक निर्णय में फैसला सुनाया कि सामी लोगों के पास न केवल बारहसिंगा पालन के लिए भूमि का उपयोग करने का अधिकार था, बल्कि वे पारंपरिक सामी आर्थिक गतिविधियों के लिए अपने उपयोग का प्रदर्शन करके ऐसी भूमि पर अधिकार का दावा भी कर सकते थे।⁸⁵⁰

हालाँकि स्वीडिश सरकार ने बाद में सामी लोगों से

⁸⁴³The Sámi Parliament Act, 1992, ch.2, s.1; United Nations Human Rights Council, *Report of the Special Rapporteur on the Rights of Indigenous Peoples, The Situation of the Sami People in the Sápmi region of Norway, Sweden and Finland*, UN Doc A/HRC/18/35/Add.2 (2011), para. 24.

⁸⁴⁴*Ibid.*; Adrienne Davidson and Veldon Coburn, "Multiculturalism Policy Index: Indigenous Peoples: Indigenous Peoples Index Evidence 2021", *Queen's University* (2021), p.no.58.

⁸⁴⁵United Nations Human Rights Council, *Report of the Special Rapporteur on the Rights of Indigenous Peoples, The Situation of the Sami People in the Sápmi region of Norway, Sweden and Finland*, UN Doc A/HRC/18/35/Add.2 (2011), para. 42.

⁸⁴⁶Adrienne Davidson and Veldon Coburn, "Multiculturalism Policy Index: Indigenous Peoples: Indigenous Peoples Index Evidence 2021", *Queen's University* (2021), p.no.61.

⁸⁴⁷Ombudsman against Ethnic Discrimination, *Discrimination of the Sami – the rights of the Sami from a discrimination perspective*, DO:s rapportserie 2008.1 eng, p.no.23.

⁸⁴⁸Adrienne Davidson and Veldon Coburn, "Multiculturalism Policy Index: Indigenous Peoples: Indigenous Peoples Index Evidence 2021", *Queen's University* (2021), p.no.63.

⁸⁴⁹*Id.* at 57.

⁸⁵⁰*Taxed Mountains*, NJA 1981 s.1 (1981)

उनकी पैतृक भूमि से जबरन विस्थापन के लिए माफी मांगी, स्वीडन ने अभी तक उन्हें स्पष्ट रूप से भूमि अधिकार देने के लिए कानून नहीं बनाया है।⁸⁵¹ फिर भी, स्वीडन के सर्वोच्च न्यायालय ने, नोर्डमलिंग निर्णय में, सामी रेनडियर चरवाहों को अपनी पैतृक भूमि पर अपने रेनडियर को चराने के लिए प्रथागत कानूनी अधिकार प्रदान किए, भले ही वे ऐसी भूमि पर कानूनी अधिकार नहीं रखते हों और इस संबंध में दिशानिर्देश निर्धारित किए।⁸⁵² वानिकी अधिनियम, 1993 में यह भी सिफारिश की गई है कि वन प्रबंधन उपायों की योजना बनाते और उन्हें लागू करते समय सामी लोगों को पर्याप्त मात्रा में वनस्पति के साथ पर्याप्त चराई क्षेत्रों तक वार्षिक पहुंच दी जानी चाहिए।⁸⁵³

1.2.4. संस्कृति और परंपराओं का संरक्षण

रेनडियर पशुपालन अधिनियम, 1971 ने सेमबी नामक सामी गाँवों की धारणा बनाई, जो किसी दिए गए भौगोलिक क्षेत्र में सामी स्व-शासन के लिए एक आर्थिक और प्रशासनिक इकाई है, जिसके सदस्यों को अपने स्वयं के भीतर, झुंड रेनडियर, शिकार और मछली को अपनी पारंपरिक आजीविका के रूप में, साथ ही अपने लिए और अपने रेनडियर के लिए भूमि और पानी का उपयोग करने का एकमात्र अधिकार है।⁸⁵⁴ हालाँकि, न तो वे और न ही उनके सदस्य दूसरों को शिकार और मछली पकड़ने के अधिकार पट्टे पर देने के लिए अधिकृत हैं; यह काउंटी प्रशासनिक बोर्डों के अधिकार क्षेत्र के भीतर है।⁸⁵⁵ फिर भी, गिरजा के निर्णय में, आईएलओ कन्वेंशन नं। 169 (जिसकी स्वीडन ने पुष्टि नहीं की है) स्वीडन के सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि गिरजा समुदाय को प्राचीन काल से भूमि के अपने पारंपरिक उपयोग और कब्जे के आधार पर (स्वीडिश सरकार के नुकसान के लिए) अनन्य अधिकार था, इसमें स्वीडन सरकार की मंजूरी के बिना दूसरों को छोटे जानवरों के शिकार और मछली पकड़ने के अधिकार देने का हक भी शामिल था।⁸⁵⁶ इस प्रकार ये स्वीडिश अदालतों के माध्यम से सामी लोगों, विशेष रूप से भूमि उपयोग और शिकार से संबंधित लोगों के अधिकारों को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।⁸⁵⁷

1.2.5. भाषा का संरक्षण

सार्वजनिक प्राधिकरणों और न्यायालयों के साथ व्यवहार में सामी भाषा का उपयोग करने का अधिकार अधिनियम, 1999 (अब राष्ट्रीय अल्पसंख्यक और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक भाषा अधिनियम, 2009 द्वारा प्रतिस्थापित) औपचारिक रूप से

⁸⁵¹ Adrienne Davidson and Veldon Coburn, "Multiculturalism Policy Index: Indigenous Peoples: Indigenous Peoples Index Evidence 2021", *Queen's University* (2021), p. no. 57.

⁸⁵² *Nordmaling*, T4028-07(2011), p. no. 12; Anett Sasvari and Hugh Beach, "The 2011 Swedish Supreme Court Ruling: A Turning Point for Saami Rights" 15(2) *Nomadic Peoples* 132 (2011).

⁸⁵³ The Forestry Act, 1993, s. 31; United Nations Human Rights Council, *Report of the Special Rapporteur on the Rights of Indigenous Peoples, The Situation of the Sami People in the Sápmi region of Norway, Sweden and Finland*, UN Doc A/HRC/18/35/Add.2 (2011), p. no. 19.

⁸⁵⁴ Adrienne Davidson and Veldon Coburn, "Multiculturalism Policy Index: Indigenous Peoples: Indigenous Peoples Index Evidence 2021", *Queen's University* (2021), p. nos. 58-60.

⁸⁵⁵ The Reindeer Husbandry Act, 1971, s. 26; International Work Group for Indigenous Affairs, *The Indigenous World* 2021 (35th edn., 2021), p. no. 514.

⁸⁵⁶ *The Girjas Case*, T853-18(2020); International Work Group for Indigenous Affairs, *The Indigenous World* 2021 (35th edn., 2021), p. no. 514.

⁸⁵⁷ Adrienne Davidson and Veldon Coburn, "Multiculturalism Policy Index: Indigenous Peoples: Indigenous Peoples Index Evidence 2021", *Queen's University* (2021), p. no. 58.

सामी भाषा को स्वीडन में एक आधिकारिक अल्पसंख्यक भाषा का दर्जा प्रदान करता है।⁸⁵⁸ तदनुसार, सामी लोगों को सामी प्रशासनिक क्षेत्रों के भीतर, सभी कार्यवाही में सामी भाषा में स्वीडिश प्रशासनिक और न्यायिक अधिकारियों के साथ संवाद (मौखिक और लिखित रूप में) करने का अधिकार है, साथ ही सामी भाषा के माध्यम से पूर्वस्कूली शिक्षा और बुजुर्गों की देखभाल तक पहुंच है।⁸⁵⁹ सामी प्रशासनिक क्षेत्रों के बाहर भी, सामी लोग सामी भाषा में चुनिंदा स्वीडिश संस्थानों के साथ काम करने के हकदार हैं।⁸⁶⁰ फिर भी, स्वीडिश अभी भी स्वीडन में "प्रमुख" भाषा है, जैसा कि भाषा अधिनियम, 2009 द्वारा घोषित किया गया है।⁸⁶¹

1.2.6. गैर-भेदभाव और सकारात्मक कार्रवाई

हालाँकि स्वीडन ने अभी तक सामी लोगों के खिलाफ सकारात्मक कार्रवाई के लिए कानून या नीतियां लागू नहीं की हैं, फिर भी भेदभाव अधिनियम, 2008, उन्हें काम के अवसरों और वेतन में जातीय मूल के आधार पर भेदभाव से बचाता है।⁸⁶²

2021 में, स्वीडन ने सामी संसद और सामी संगठनों के परामर्श से, स्वीडिश सरकार के हाथों सामी लोगों द्वारा झेले गए प्रणालीगत अन्यायों की जांच करने के लिए एक सत्य आयोग (12 आयुक्तों सहित) की स्थापना की और यह आकलन किया कि कैसे स्वीडिश नीतियों, जिसमें सामी चरवाहों को उनकी पैतृक भूमि से जबरन स्थानांतरित करना, 'खानाबदोश' स्कूलों की स्थापना, सामी लोगों को 'नस्लीय जीव विज्ञान' के अध्ययन के अधीन करना, सामी क्षेत्रों का औद्योगिकीकरण, और सामी भाषा बोलने या उनके धर्म का पालन करने पर प्रतिबंध, ने उन्हें व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से प्रभावित किया।⁸⁶³ सत्य आयोग सामी लोगों से गवाही प्राप्त करने, उनके अनुभवों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और क्षतिपूर्ति और सुलह के उपायों का प्रस्ताव करने के लिए जिम्मेदार है।⁸⁶⁴

1.3. फिनलैंड

1.3.1. संवैधानिक और कानूनी मान्यता

फिनलैंड का संविधान सामी लोगों को एक स्वदेशी लोगों के रूप में मान्यता देता है, साथ ही भाषाई और सांस्कृतिक स्वशासन के उनके अधिकारों की गारंटी देता है। धारा 17 में कहा गया है: "सामी, एक स्वदेशी लोगों के रूप में...

⁸⁵⁸ Adrienne Davidson and Veldon Coburn, "Multiculturalism Policy Index: Indigenous Peoples: Indigenous Peoples Index Evidence 2021", *Queen's University* (2021), p.no.60.

⁸⁵⁹ The National Minorities and National Minority Languages Act, 2009, ss.1,8,13-18.

⁸⁶⁰ *Id.* s.9.

⁸⁶¹ The Language Act, 2009, s.4.

⁸⁶² Adrienne Davidson and Veldon Coburn, "Multiculturalism Policy Index: Indigenous Peoples: Indigenous Peoples Index Evidence 2021", *Queen's University* (2021), p.no.63.

⁸⁶³ International Work Group for Indigenous Affairs, *The Indigenous World 2023* (37th edn., 2023), p.no.468;

International Work Group for Indigenous Affairs, *The Indigenous World 2022* (36th edn., 2022), p.no.502.

⁸⁶⁴ International Work Group for Indigenous Affairs, *The Indigenous World 2023* (37th edn., 2023), p.no.468.

को अपनी भाषा और संस्कृति को बनाए रखने और विकसित करने का अधिकार है।”⁸⁶⁵ इसी तर्ज पर, सामी संसद अधिनियम, 1995 में प्रावधान किया गया है कि “ एक स्वदेशी लोगों के रूप में सामियों को... उनकी भाषा और संस्कृति से संबंधित मामलों में उनकी मातृभूमि के भीतर सांस्कृतिक स्वायत्तता सुनिश्चित की जाएगी, साथ ही एक स्वदेशी लोगों के रूप में उनकी स्थिति से संबंधित मामलों का ध्यान रखा जाएगा।”⁸⁶⁶ इसके अलावा, सामी संसद अधिनियम, 1995 सामी मातृभूमि,⁸⁶⁷ का गठन करने वाले क्षेत्रों को परिभाषित करता है और यह निर्धारित करने के लिए मानदंड निर्धारित करता है कि कोई व्यक्ति सामी है या नहीं, जो मुख्य रूप से आत्म-पहचान और सामी वंश पर आधारित होते हैं।⁸⁶⁸

1.3.2. आत्मनिर्णय, स्व-शासन, भागीदारी और परामर्श

सामी संसद अधिनियम, 1995 ने भी फिनलैंड की सामी संसद की स्थापना की, जिसने पिछली सामी संसद की जगह ली, जो 1972 से 1995 तक संचालित थी (नॉर्डिक क्षेत्र में पहली निर्वाचित सामी इकाई)।⁸⁶⁹ सामी संसद, सामी लोगों का एक प्रतिनिधि निकाय है, जो हर चार साल में सामी लोगों द्वारा चुने गए 21 सदस्यों और चार उपाध्यक्षों से बना है।⁸⁷⁰ सामी संसद को सामी मातृभूमि के भीतर, प्रस्ताव और पहल करने, फिनिश अधिकारियों को बयान जारी करने और “ उन सभी दूरगामी और महत्वपूर्ण उपायों पर बातचीत करने का काम सौंपा गया है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एक स्वदेशी लोगों के रूप में सामी की स्थिति, विशेष रूप से, भाषा, संस्कृति, और भूमि के प्रबंधन, उपयोग, पट्टे और आवंटन को प्रभावित कर सकते हैं”,⁸⁷¹

हालाँकि, सामी संसद केवल एक सलाहकार निकाय है, जिसके पास कार्यकारी शासन की शक्तियों का प्रयोग करते हुए सामी लोगों के मामलों को प्रशासित करने का अधिकार नहीं है।⁸⁷² सामी संसद भी फिनिश संसद के समक्ष वीटो के अधिकार की हकदार नहीं है।⁸⁷³ इसके अलावा, सामी संसद को फिनिश सरकार के अधिकार के तहत रखा गया है (लेकिन यह फिनिश प्रशासनिक तंत्र का

⁸⁶⁵The Constitution of Finland, 1999, s.17, para.3.

⁸⁶⁶United Nations Human Rights Council, Report of the Special Rapporteur on the Rights of Indigenous Peoples, The Situation of the Sami People in the Sápmi region of Norway, Sweden and Finland, UN Doc A/HRC/18/35/Add.2 (2011), para. 28.

⁸⁶⁷The Sami Parliament Act, 1995, ch.1, s.4.

⁸⁶⁸Id. ch.1, s.3; Adrienne Davidson and Veldon Coburn, “Multiculturalism Policy Index: Indigenous Peoples”, Queen’s University (2021), p.no.34.

⁸⁶⁹The Sami Parliament Act, 1995, ch.1, s.1; United Nations Human Rights Council, Report of the Special Rapporteur on the Rights of Indigenous Peoples, The Situation of the Sami People in the Sápmi region of Norway, Sweden and Finland, UN Doc A/HRC/18/35/Add.2 (2011), para. 27.

⁸⁷⁰The Sami Parliament Act, 1995, ch. 3, s. 10 and United Nations Human Rights Council, Report of the Special Rapporteur on the Rights of Indigenous Peoples, The Situation of the Sami People in the Sápmi region of Norway, Sweden and Finland, UN Doc A/HRC/18/35/Add.2 (2011), para. 27.

⁸⁷¹United Nations Human Rights Council, Report of the Special Rapporteur on the Rights of Indigenous Peoples, The Situation of the Sami People in the Sápmi region of Norway, Sweden and Finland, UN Doc A/HRC/18/35/Add.2 (2011), para. 28.

⁸⁷²Adrienne Davidson and Veldon Coburn, “Multiculturalism Policy Index: Indigenous Peoples”, Queen’s University (2021), p.no.31.

⁸⁷³Ibid.

हिस्सा नहीं है) इस प्रकार सामी लोगों से संबंधित मामलों में इसकी स्वतंत्रता, स्वायत्तता और निर्णय लेने की शक्तियों को प्रभावी ढंग से सीमित कर देता है।⁸⁷⁴ फिर भी, संसद की प्रक्रिया के फिनिश नियमों के अनुसार, सामी को सीमित परिस्थितियों में फिनलैंड की संसद द्वारा सीधे सुना जा सकता है।⁸⁷⁵ व्यवहार में, फिनिश सरकार सामी लोगों को प्रभावित करने वाले कानूनों, नीतियों और रणनीतियों के निर्माण में सामी संसद के साथ भी बातचीत करती है।⁸⁷⁶ फिनलैंड ने सामी लोगों के कानूनी, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और रोजगार स्थितियों के विकास की निगरानी के लिए सामी मामलों पर एक सलाहकार बोर्ड का भी गठन किया है, जिसमें 12 सदस्य (सामी संसद द्वारा छह नामित और फिनिश सरकार द्वारा छह नामित) शामिल हैं।⁸⁷⁷

सामी स्वशासन के अधिकार को फिनलैंड के सर्वोच्च प्रशासनिक न्यायालय के निर्णयों की एक कड़ी से भी खतरा पैदा हो गया है, जिसने उन व्यक्तियों को जोड़ने का निर्देश दिया, जिनकी पहचान सामी के रूप में की गई थी, लेकिन सामी समुदाय और सामी संसद द्वारा उन्हें मतदाता सूची में मान्यता नहीं दी गई थी, जिससे उन्हें सामी संसद चुनावों में मतदान करने का अधिकार मिला।⁸⁷⁸ इन फैसलों ने चिंता जताई कि सामी संसद सामी लोगों के लिए एक प्रतिनिधि निकाय के रूप में अपना चरित्र खो सकती है।⁸⁷⁹ सामी संसद अधिनियम, 1995 की भी इसी तरह 'सामी' को इस तरह से परिभाषित नहीं करने के लिए आलोचना की गई है जो सामी लोगों की अपनी सदस्यता और राजनीतिक भागीदारी से संबंधित मामलों पर उनके विचारों को ध्यान में रखता है।⁸⁸⁰

1.3.3. क्षेत्रों, वन और प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग और पैतृक भूमि का शीर्षक

फिनलैंड भी सामी लोगों को उनकी पैतृक भूमि पर स्वामित्व का कोई अधिकार नहीं देता है, और न ही यह व्यापक रूप से सामी प्रथागत कानून को मान्यता देता है। रेनडियर पशुपालन⁸⁸¹ अधिनियम, 1990, नॉर्वे और स्वीडन में इसी तरह के कानून के विपरीत, सामी लोगों को अपनी मातृभूमि के भीतर या बाहर

⁸⁷⁴United Nations Human Rights Council, *Report of the Special Rapporteur on the Rights of Indigenous Peoples, The Situation of the Sami People in the Sápmi region of Norway, Sweden and Finland*, UN Doc A/HRC/18/35/Add.2 (2011), para. 37.

⁸⁷⁵Adrienne Davidson and Veldon Coburn, "Multiculturalism Policy Index: Indigenous Peoples", *Queen's University* (2021), p.no.33.

⁸⁷⁶*Id.* at 34.

⁸⁷⁷United Nations Human Rights Council, *Report of the Special Rapporteur on the Rights of Indigenous Peoples, The Situation of the Sami People in the Sápmi region of Norway, Sweden and Finland*, UN Doc A/HRC/18/35/Add.2 (2011), para. 11.

⁸⁷⁸Adrienne Davidson and Veldon Coburn, "Multiculturalism Policy Index: Indigenous Peoples", *Queen's University* (2021), p.no.31.

⁸⁷⁹United Nations Human Rights Committee, *Views adopted by the Committee under Article 5(4) of the Optional Protocol*, CCPR/C/124/D/2950/2017 (Dec. 18, 2019), para. 3.2.

⁸⁸⁰*Id.* at para.11.

⁸⁸¹Adrienne Davidson and Veldon Coburn, "Multiculturalism Policy Index: Indigenous Peoples", *Queen's University* (2021), p.no.33; Mattias Ahren, "Indigenous People's Culture, Customs, and Tradition and Customary Law—The Saami People's Perspective" 21(1) *Arizona Journal of International and Comparative Law* 63-112 (2004).

रेनडियर पशुपालन, शिकार या मछली पकड़ने जैसी पारंपरिक आजीविका का अभ्यास करने के लिए भूमि और पानी का उपयोग करने का विशेष अधिकार नहीं देता है; सामी मातृभूमि में स्थायी रूप से रहने वाले किसी भी व्यक्ति को ऐसे क्षेत्र में रेनडियर पालन, शिकार या मछली पकड़ने का अधिकार है।⁸⁸² रेनडियर पशुपालन अधिनियम, 1990, केवल फिनिश अधिकारियों को भूमि से संबंधित उपायों को अपनाते समय सामी रेनडियर पशुपालन सहकारी समितियों के प्रतिनिधियों से परामर्श करने का आदेश देता है, जिसका रेनडियर पशुपालन पर पर्याप्त प्रभाव पड़ेगा।⁸⁸³ वन अधिनियम, 1996 इसी प्रकार फिनिश सरकार से वन प्रबंधन के लिए विनियम जारी करते समय सामी संसद से परामर्श करने की अपेक्षा करता है।⁸⁸⁴ हालाँकि, सामी भूमि अधिकारों को और कम करते हुए, फिनलैंड के सर्वोच्च प्रशासनिक न्यायालय ने फैसला सुनाया कि सामी रेनडियर चरवाहों, सामी रेनडियर चरवाहों की सहकारी समितियों और सामी संसद को खनन अधिनियम, 2011 के तहत, अपनी मातृभूमि में खनन आरक्षण के खिलाफ अपील करने का अधिकार नहीं है।⁸⁸⁵ नतीजतन, बाल अधिकार समिति ने फिनलैंड से अपने घरेलू कानून में एफ. पी. आई. सी. को शामिल करने का आह्वान किया, ताकि सामी मातृभूमि को प्रभावित करने वाली परियोजनाओं और गतिविधियों के लिए सामी लोगों की सहमति की गारंटी दी जा सके।⁸⁸⁶ इसी तरह, सी. ई. एस. सी. आर. ने फिनलैंड को निर्देश दिया कि वह सामूहिक स्वामित्व सहित स्वदेशी भूमि अधिकारों को कानूनी रूप से मान्यता दे, सामी लोगों द्वारा पारंपरिक क्षेत्रों और प्राकृतिक संसाधनों का आनंद सुनिश्चित करने के लिए उपाय करे, और सी. आई. डी. ए. को उनकी पैतृक भूमि को प्रभावित करने वाले कानूनी मामलों में एक इच्छुक पक्ष के रूप में स्वीकार करे।⁸⁸⁷

1.3.4. भाषा का संरक्षण

सामी भाषा अधिनियम, 2003 सामी लोगों को सार्वजनिक प्राधिकरणों और अदालतों के साथ अपने सभी संचार और व्यवहार में सामी भाषा का उपयोग करने के अधिकार की गारंटी देता है।⁸⁸⁸ शिक्षा और संस्कृति के वित्तपोषण पर अधिनियम, 2009 के तहत, सामी लोग सामी मातृभूमि के भीतर सामी भाषा के माध्यम से शिक्षित

⁸⁸² Adrienne Davidson and Veldon Coburn, "Multiculturalism Policy Index: Indigenous Peoples", *Queen's University*, (2021), p. nos. 32, 33; United Nations Human Rights Council, *Report of the Special Rapporteur on the Rights of Indigenous Peoples, The Situation of the Sami People in the Sápmi region of Norway, Sweden and Finland*, UN Doc A/HRC/18/35/Add.2 (2011), paras. 29, 30; Yle Sampi, "Fishers rejoice over court decision in Finland: The court has now declared that we Sámi have right to our culture" *The Barents Observer* (Mar. 7, 2019).

⁸⁸³ United Nations Human Rights Council, *Report of the Special Rapporteur on the Rights of Indigenous Peoples, The Situation of the Sami People in the Sápmi region of Norway, Sweden and Finland*, UN Doc A/HRC/18/35/Add.2 (2011), para. 30.

⁸⁸⁴ The Forest Act, 1996, s. 12(1).

⁸⁸⁵ Thomas Nilsen, "Miners hunting for metal to battery cars threaten Sami reindeer herders' homeland" *The Barents Observer* (2020); Adrienne Davidson and Veldon Coburn, "Multiculturalism Policy Index: Indigenous Peoples", *Queen's University* (2021), p. no. 30; United Nations Human Rights Council, *Report of the Special Rapporteur on the Rights of Indigenous Peoples, The Situation of the Sami People in the Sápmi region of Norway, Sweden and Finland*, UN Doc A/HRC/18/35/Add.2 (2011), para. 30.

⁸⁸⁶ International Work Group for Indigenous Affairs, *The Indigenous World 2022* (36th edn., 2022), p. nos. 776, 777.

⁸⁸⁷ United Nations Human Rights Council, *Report of the Special Rapporteur on the Rights of Indigenous Peoples, The Situation of the Sami People in the Sápmi region of Norway, Sweden and Finland*, UN Doc A/HRC/18/35/Add.2 (2011), para. 41.

⁸⁸⁸ The Sami Language Act (1086/2003), ch. 2; United Nations Human Rights Council, *Report of the Special Rapporteur on the Rights of Indigenous Peoples, The Situation of the Sami People in the Sápmi region of Norway, Sweden and Finland*, UN Doc A/HRC/18/35/Add.2 (2011), para. 66.

होने के भी हकदार हैं, जिसके लिए सब्सिडी दी जाती है।⁸⁸⁹ इसलिए फिनिश सरकार सामी लोगों के इन भाषाई अधिकारों को बढ़ावा देने और लागू करने के लिए कर्तव्यबद्ध है।⁸⁹⁰

1.3.5. गैर-भेदभाव और सकारात्मक कार्रवाई

फिनलैंड ने अभी तक सामी लोगों के खिलाफ सकारात्मक कार्रवाई के लिए कानून या नीतियां लागू नहीं की हैं।⁸⁹¹ हालाँकि, 2021 में, सामी संसद और स्कॉल्ट सामी सीडा परिषद (स्कॉल्ट सामी अल्पसंख्यक का पारंपरिक प्रतिनिधि निकाय) के साथ घनिष्ठ सहयोग में फिनलैंड ने सत्य और सुलह आयोग का गठन किया, जिसमें पांच आयुक्त शामिल थे, जिनमें से दो को सामी संसद द्वारा, एक को स्कॉल्ट सामी सीडा परिषद द्वारा और दो को फिनिश सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है।⁸⁹² सत्य और सुलह आयोग को सामी लोगों द्वारा सामना किए जाने वाले ऐतिहासिक और वर्तमान भेदभाव की पहचान करने और दस्तावेजीकरण करने और सामी संस्कृति और अनुभवों के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने का काम सौंपा गया है।⁸⁹³

2. ओशिनिया

2.1. आओटेरोआ (न्यूजीलैंड)

2.1.1. ऐतिहासिक उपचार और कानूनी मान्यता

माओरी, आओटेरोआ न्यूजीलैंड के स्वदेशी लोगों को, 1840 में माओरी प्रमुखों और ब्रिटिश क्राउन के बीच संपन्न न्यूजीलैंड के संस्थापक दस्तावेज, वैयांगी की संधि में मान्यता दी गई है।⁸⁹⁴ वैयांगी की संधि को अंग्रेजी और माओरी दोनों में निष्पादित किया गया था, लेकिन अंग्रेजी और माओरी संस्करणों के प्रावधान उनके अर्थों में भिन्न हैं, जिससे एक ओर राज्य अधिकारियों और दूसरी ओर माओरी लोगों ने इसके अलग-अलग मतलब निकाले हैं।⁸⁹⁵ अनुच्छेद 2 (माओरी संस्करण) माओरी को "उनकी भूमि, गाँवों और उनके सभी खजाने पर उनके प्रमुखता के अयोग्य अभ्यास" की गारंटी देता है,⁸⁹⁶ हालाँकि स्वदेशी क्षेत्रों पर शासन करने का अधिकार (लेकिन संप्रभुता से कम) रानी को अनुच्छेद 1 (माओरी संस्करण) द्वारा प्रदान किया गया है।⁸⁹⁷ हालाँकि, अनुच्छेद 1 (अंग्रेजी संस्करण) के अनुसार रानी के पास स्वदेशी क्षेत्रों पर संप्रभुता

⁸⁸⁹ United Nations Human Rights Council, *Report of the Special Rapporteur on the Rights of Indigenous Peoples, The Situation of the Sami People in the Sápmi region of Norway, Sweden and Finland*, UN Doc A/HRC/18/35/Add.2 (2011), para. 70.

⁸⁹⁰ The Sami Language Act, 2003, s.1.

⁸⁹¹ Adrienne Davidson and Veldon Coburn, "Multiculturalism Policy Index: Indigenous Peoples", *Queen's University* (2021), p.no.35.

⁸⁹² International Work Group for Indigenous Affairs, *The Indigenous World 2023* (37th edn., 2023), p.no.468.

⁸⁹³ International Work Group for Indigenous Affairs, *The Indigenous World 2022* (36th edn., 2022), p.no.503.

⁸⁹⁴ International Work Group for Indigenous Affairs, *The Indigenous World 2021* (35th edn., 2021), p.no.581.

⁸⁹⁵ *Ibid.*

⁸⁹⁶ Te Tiriti o Waitangi, 1840, art.2.

⁸⁹⁷ *Id.* art.1.

है (न कि केवल शासन करने का अधिकार);⁸⁹⁸ और अनुच्छेद 2 (अंग्रेजी संस्करण) माओरी को "उनकी भूमि और संपदाओं, जंगलों, मत्स्य पालन और अन्य संपत्तियों का पूर्ण अनन्य और निर्बाध कब्जा प्रदान करता है, जो वे सामूहिक रूप से या व्यक्तिगत रूप से तब तक रख सकते हैं जब तक कि यह उनकी इच्छा और इच्छा है कि वे इसे अपने कब्जे में रखें।"⁸⁹⁹ अनुच्छेद 3 (अंग्रेजी और माओरी संस्करण) माओरी को रानी की सुरक्षा और ब्रिटिश प्रजा को दिए गए सभी अधिकारों का आश्वासन देता है।⁹⁰⁰

न्यूजीलैंड के अलिखित संविधान,⁹⁰¹ का हिस्सा मानी जाने वाली वैतांगी की संधि का तब तक कोई बाध्यकारी कानूनी प्रभाव नहीं है जब तक कि इसे विधायी कार्रवाई के माध्यम से न्यूजीलैंड के घरेलू कानून में शामिल नहीं किया जाता है या घरेलू अदालतों द्वारा लागू नहीं किया जाता है।⁹⁰² वैतांगी की संधि के अंतर्निहित मौलिक सिद्धांतों को अब कई विधायी अधिनियमों और न्यायिक निर्णयों में कानूनी रूप से अनुमोदित किया गया है।⁹⁰³ न्यूजीलैंड के सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी माना है कि वैतांगी की संधि में निहित मौलिक सिद्धांतों को "एक व्यापक और उदार निर्माण दिया जाना चाहिए"।⁹⁰⁴ वैतांगी संधि अधिनियम, 1975 के पारित होने के साथ, माओरी को अब पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ न्यूजीलैंड के स्वदेशी लोगों के रूप में मान्यता दी गई है, यह स्वीकार करते हुए कि माओरी अस्तित्व वैतांगी की संधि के समापन से पहले का है।⁹⁰⁵

2.1.2. आत्मनिर्णय, स्व-शासन, भागीदारी और परामर्श

वैतांगी की संधि के अनुच्छेद 2 की माओरी व्याख्या के अनुसार, जबकि रानी ने माओरी पर शासन का अधिकार बरकरार रखा है, फिर भी माओरी अपनी भूमि, संसाधनों और अन्य खजाने पर स्वायत्तता के हकदार हैं।⁹⁰⁶ वैतांगी की संधि और वैतांगी की संधि के संचालन का आकलन करने और इसके तहत क्राउन के दायित्वों के कार्यान्वयन और प्रवर्तन (या उल्लंघनों) से संबंधित माओरी दावों पर गैर-बाध्यकारी सिफारिशें करने के उद्देश्य से वैतांगी की संधि अधिनियम, 1975 के तहत स्थापित एक स्थायी जांच आयोग, वैतांगी न्यायाधिकरण ने पाया कि माओरी ने वैतांगी की संधि के तहत रानी को अपनी संप्रभुता नहीं सौंपी थी।⁹⁰⁷ इस निष्कर्ष

⁸⁹⁸ The Treaty of Waitangi, 1840, art.1.

⁸⁹⁹ Adrienne Davidson and Veldon Coburn, "Multiculturalism Policy Index: Indigenous Peoples", Queen's University (2021), p.no.42.

⁹⁰⁰ Te Tiriti o Waitangi and The Treaty of Waitangi, 1840, art.3.

⁹⁰¹ United Nations Human Rights Council, Report of the Special Rapporteur on the Rights of Indigenous Peoples, The Situation of Maori People in New Zealand, UN Doc A/HRC/18/35/Add.4 (2011), para.7.

⁹⁰² Ministry of Justice, New Zealand, Te Tiriti o Waitangi - Treaty of Waitangi, available at: <https://www.justice.govt.nz/about/learn-about-the-justice-system/how-the-justice-system-works/the-basis-for-all-law/treaty-of-waitangi/> (last visited on Nov. 11, 2025).

⁹⁰³ International Work Group for Indigenous Affairs, The Indigenous World 2025 (39th edn., 2025), p.no.539.

⁹⁰⁴ Trans-Tasman Resources Limited v. The Taranaki-Whanganui Conservation Board, NZSC 127 (2021), para.151.

⁹⁰⁵ Adrienne Davidson and Veldon Coburn, "Multiculturalism Policy Index: Indigenous Peoples", Queen's University (2021), p.no.48.

⁹⁰⁶ Te Tiriti o Waitangi, 1840, art.2.

⁹⁰⁷ Adrienne Davidson and Veldon Coburn, "Multiculturalism Policy Index: Indigenous Peoples", Queen's University (2021), p.no.43.

को न्यूजीलैंड द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था, हालांकि यह आत्मनिर्णय के माओरी अधिकार का समर्थन करता है।⁹⁰⁸ फिर भी, न्यूजीलैंड ने वैतांगी की संधि से उपजे ऐतिहासिक दावों पर बातचीत करने और उनका निपटारा करने के उद्देश्य से न्याय मंत्रालय के तहत संधि निपटान कार्यालय की स्थापना की है।⁹⁰⁹

न्यूजीलैंड ने माओरी सामाजिक और आर्थिक उन्नति अधिनियम, 1945 भी लागू किया है, जो माओरी को स्व-शासन का एक सीमित अधिकार प्रदान करता है जो समुदायों में संगठित हैं।⁹¹⁰ इसके अलावा, संसाधन प्रबंधन अधिनियम, 1991 स्थानीय परिषदों को अपने अधिकार और कार्यों को संगठित माओरी समुदायों को हस्तांतरित करने की अनुमति देता है।⁹¹¹ नागाती तुवारेतोआ वाइकाटो क्षेत्रीय परिषद से ताओपो झील के लिए पानी की गुणवत्ता की निगरानी करने वाला पहला माओरी प्राधिकरण है, जो संघीय सरकार और माओरी के बीच बढ़े हुए शक्ति-साझाकरण का संकेत है।⁹¹²

19वीं शताब्दी के बाद से, माओरी को न्यूजीलैंड संसद में आरक्षित माओरी सीटें भी दी गई हैं, माओरी प्रतिनिधित्व अधिनियम के अनुसार, 1867,⁹¹³ प्रतिनिधियों को माओरी मतदाताओं (एक अलग माओरी मतदाता सूची पर पंजीकृत) द्वारा चुना जाता है, इस प्रकार उनके राजनीतिक प्रतिनिधित्व को सामान्य मतदाताओं से अलग सुनिश्चित किया जाता है।⁹¹⁴ हालांकि यह आवश्यक नहीं है कि ऐसे प्रतिनिधि स्वयं माओरी हों, व्यवहार में, इन सीटों के लिए चुनाव लड़ने वाले ऐसे उम्मीदवारों के बावजूद एक गैर-माओरी कभी भी माओरी सीटों के लिए नहीं चुने गए हैं।⁹¹⁵ न्यूजीलैंड संसद में आरक्षित माओरी सीटों की संख्या निश्चित नहीं है, लेकिन माओरी चुनावी आबादी की ताकत के आधार पर लचीली है।⁹¹⁶ वर्तमान में, माओरी मतदाता न्यूजीलैंड संसद में सात आरक्षित सीटों के हकदार हैं।⁹¹⁷

वैतांगी की संधि में निहित 'भागीदारी' का सिद्धांत, क्राउन और माओरी के बीच पारस्परिक रूप से सम्मानजनक, सहकारी और रचनात्मक संबंध की परिकल्पना करता है, जो माओरी को परामर्श करने का अधिकार प्रदान करता है।⁹¹⁸ तदनुसार क्राउन, माओरी को अपने विचार प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर देने के बाद, सद्भावना से सूचित निर्णय लेने के लिए

⁹⁰⁸ *Ibid.*

⁹⁰⁹ *Id.* at 43, 44.

⁹¹⁰ *Id.* at 43; The Maori Social and Economic Advancement Act, 1945, s.12(iv).

⁹¹¹ The Resource Management Act, 1991, s.33.

⁹¹² Tūwharetoa Māori Trust Board, Section 33 Transfer with Waikato Regional Council, available at: <https://www.tuwharetoa.co.nz/ngati-tuwharetoa-set-to-become-first-iwi-to-utilise-a-section-33-transfer-with-waikato-regional-council/> (last visited Nov. 11, 2025).

⁹¹³ The Māori Representation Act, 1867, s.5.

⁹¹⁴ Adrienne Davidson and Veldon Coburn, "Multiculturalism Policy Index: Indigenous Peoples", *Queen's University* (2021), p.no.47.

⁹¹⁵ *Id.* at 43, 44.

⁹¹⁶ United Nations Human Rights Council, Report of the Special Rapporteur on the Rights of Indigenous Peoples, *The Situation of Maori People in New Zealand*, UN Doc A/HRC/18/35/Add.4 (2011), para.12.

⁹¹⁷ New Zealand Parliament, *MPs and Electorates*, available at: <https://www3.parliament.nz/en/mps-and-electrates/> (last visited Nov. 11, 2025).

⁹¹⁸ *New Zealand Maori Council v. Attorney General*, NZLR 641 (1987), p.no.33.

लेने के लिए बाध्य है।⁹¹⁹ माओरी कल्याण अधिनियम, 1962 ने माओरी को प्रभावित करने वाले नीतिगत मुद्दों पर सरकार को सलाह देने के लिए एक राष्ट्रीय माओरी परिषद की स्थापना की।

⁹²⁰ स्थानीय सरकार अधिनियम, 2002 संसाधन प्रबंधन, सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और भूमि अधिकारों के संरक्षण जैसे उनके अधिकारों और हितों को (संभावित रूप से) प्रभावित करने वाले मुद्दों पर माओरी के साथ परामर्श को अनिवार्य करता है।⁹²¹ न्यूजीलैंड ने 1992 में माओरी विकास मंत्रालय अधिनियम, 1991 के तहत माओरी से संबंधित नीतियों की निगरानी करने और सरकार को माओरी मुद्दों पर सलाह देने के उद्देश्य से माओरी विकास मंत्रालय की स्थापना की।⁹²² माओरी विकास मंत्रालय ने माओरी लोगों को उनके सामूहिक संसाधनों, ज्ञान और कौशल को बढ़ाने और उनका लाभ उठाने में सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से माओरी संभावित दृष्टिकोण योजना तैयार की।⁹²³

ट्रांस-तस्मान रिसोर्सेज लिमिटेड बनाम तारानाकी-वांगानुई संरक्षण बोर्ड के मामले में, न्यूजीलैंड के सर्वोच्च न्यायालय ने इस आधार पर लोहे की रेत के खनन की अनुमति के लिए ट्रांस-तस्मान रिसोर्सेज लिमिटेड के आवेदन के अनुमोदन को रद्द करने के निर्णय की पुष्टि की कि अनुमोदन परियोजना के प्रभाव पर पर्याप्त रूप से विचार करने में विफल रहा।⁹²⁴ 2023 में, क्राउन और माओरी ने राष्ट्रीय उद्यान के प्रबंधन के लिए एक सह-शासन व्यवस्था को लागू करने के लिए एक सामूहिक निवारण पैकेज पर सहमति व्यक्त की, जहां तारानाकी के पहाड़ स्थित हैं, जिसे हाल ही में तारानाकी मौंगा सामूहिक निवारण अधिनियम, 2025.⁹²⁵ द्वारा प्रभावी किया गया है।

2.1.3. पैतृक भूमि का शीर्षक

संधि का अनुच्छेद 2 (माओरी संस्करण) स्वदेशी क्षेत्रों का स्वामित्व माओरी को प्रदान करता है, जो ऐसी भूमि को केवल रानी के लिए अलग कर सकते हैं। ते रुनंगा ओ व्हारेकौरी रेकोहू इंक बनाम अटॉर्नी-जनरल,⁹²⁶ में न्यूजीलैंड की अपील अदालत ने पाया कि "[भूमि के लिए] भारतीय अधिकार की अनोखी प्रकृति है, और क्राउन द्वारा ग्रहण की गई ऐतिहासिक शक्तियां और जिम्मेदारी... एक प्रत्ययी दायित्व का स्रोत है", जिसे न्यूजीलैंड के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वाकाटू बनाम अटॉर्नी-जनरल के मालिकों में पुष्टि की गई थी।⁹²⁷ वैतांगी (राज्य उद्यम) अधिनियम, 1988

⁹¹⁹United Nations Human Rights Council, *Report of the Special Rapporteur on the Rights of Indigenous Peoples, The Situation of Maori People in New Zealand*, UN Doc A/HRC/18/35/Add.4 (2011), para. 6.

⁹²⁰The Māori Welfare Act, 1962, s. 17; Adrienne Davidson and Veldon Coburn, "Multiculturalism Policy Index: Indigenous Peoples", *Queen's University* (2021), p. no. 43.

⁹²¹The Local Government Act, 2002, s. 82.2.

⁹²²Maori Development Act, 1991, s. 5.1.b.

⁹²³Adrienne Davidson and Veldon Coburn, "Multiculturalism Policy Index: Indigenous Peoples", *Queen's University* (2021), p. no. 47.

⁹²⁴*Trans-Tasman Resources Limited v. The Taranaki-Whanganui Conservation Board*, NZSC 127 (2021), para. 26.

⁹²⁵International Work Group for Indigenous Affairs, *The Indigenous World 2025* (39th edn., 2025), p. nos. 542-543.

⁹²⁶*Te Runanga o Wharekauri Rekohu Inc v. Attorney-General*, 2NZLR 301 (CA) (1993).

⁹²⁷*Proprietors of Wakatū v. Attorney-General*, NZSC 17 (2017).

1988 भूमि और संसाधनों के प्रबंधन में माओरी अधिकारों और हितों की रक्षा की गई।⁹²⁸ इसके अलावा, माओरी भूमि अधिनियम, 1993 ने माओरी फ्रीहोल्ड और सामान्य ज़मीनों वाले इलाकों, साथ ही क्राउन (सरकार) के अधिकार वाले उन क्षेत्रों को 'माओरी रिज़र्वेशन' के तौर पर चिह्नित किया गया, जिनका माओरी लोगों के लिए ऐतिहासिक, आध्यात्मिक, धार्मिक या भावनात्मक महत्व है।⁹²⁹ न्यूजीलैंड 'माओरी रिज़र्व' को भी मान्यता देता है, जो माओरी रिज़र्वेशन से अलग हैं।⁹³⁰ माओरी रिज़र्व वे इलाके हैं, जिन्हें द्वारा सीमांकित किए गए क्षेत्र हैं और मालिकों (जो माओरी हो भी सकते हैं और नहीं भी) को स्थायी रूप से पट्टे पर दिए गए हैं, लेकिन जिन पर माओरी लोगों को फ्रीहोल्ड का अधिकार दिया गया है।⁹³¹

वैतांगी अधिनियम, 1975 की संधि ने एक माओरी भूमि न्यायालय का निर्माण किया, जो एक न्यायाधिकरण की शक्तियों के साथ माओरी भूमि के दावों (स्वामित्व, प्रशासन और स्वामित्व के हस्तांतरण) के उत्तराधिकार, स्वामित्व में सुधार और माओरी भूमि के अलगाव पर निर्णय लेने के लिए निहित था, जो मुख्य रूप से माओरी भूमि को जब्त करने के उद्देश्य से मूल भूमि अधिनियम, 1865-⁹³² के तहत स्थापित मूल भूमि न्यायालय की जगह ले रहा था।⁹³³ समुद्री तल और तट का माओरी अधिकार बेहद विवादास्पद रहा है। व्यापक विरोध के जवाब में, न्यूजीलैंड ने 'कोई स्वामित्व नहीं' सिद्धांत के आधार पर समुद्री तटीय क्षेत्र अधिनियम, 2011-⁹³⁴ के तहत समुद्र तल और तट से क्राउन के स्वामित्व को रद्द कर दिया, इस प्रकार माओरी को न्यायिक प्रक्रियाओं या सरकार के साथ बातचीत के माध्यम से प्रथागत अधिकार प्राप्त करने में सक्षम बनाया।⁹³⁵ समुद्री तटीय क्षेत्र अधिनियम, 2011 भी माओरी को समुद्री और तटीय क्षेत्रों के संरक्षण में भाग लेने का अधिकार देता है।⁹³⁶

2.1.4. संस्कृति और परंपराओं का संरक्षण

संधि का अनुच्छेद 2 (अंग्रेजी और माओरी संस्करण) भी माओरी वाणिज्यिक और गैर-वाणिज्यिक मछली पकड़ने के अधिकारों की गारंटी देता है। संधि का अनुच्छेद 2 (अंग्रेजी संस्करण) उन माओरी मत्स्य पालन की भी रक्षा करता है जिन पर माओरी शीर्षक है। माओरी लोगों को शिकार करने, मछली पकड़ने और भोजन इकट्ठा करने का भी अधिकार है।⁹³⁷ मत्स्य पालन अधिनियम, 1983 (निरस्त होने के बाद से) के माध्यम से मछली पकड़ने के माओरी प्रथागत अधिकार को स्वीकार किया गया था।⁹³⁸ ते वीही बनाम क्षेत्रीय मत्स्य अधिकारी में, न्यूजीलैंड के सर्वोच्च न्यायालय ने भी पुष्टि की कि माओरी

⁹²⁸ The Treaty of Waitangi (State Enterprises) Act, 1988, preamble, s.9.

⁹²⁹ The Māori Land Act, 1993, s.338.

⁹³⁰ Adrienne Davidson and Veldon Coburn, "Multiculturalism Policy Index: Indigenous Peoples", *Queen's University* (2021), p.no.42.

⁹³¹ *Ibid.*

⁹³² The Native Lands Act, 1865, s.5.

⁹³³ Treaty of Waitangi Act, 1975, s.6AA.

⁹³⁴ The Marine and Coastal Area (Takutai Moana) Act, 2011, s.5.

⁹³⁵ Adrienne Davidson and Veldon Coburn, "Multiculturalism Policy Index: Indigenous Peoples", *Queen's University* (2021), p.no.43.

⁹³⁶ *Ibid.*

⁹³⁷ Adrienne Davidson and Veldon Coburn, "Multiculturalism Policy Index: Indigenous Peoples", *Queen's University* (2021), p.no.45.

⁹³⁸ *Ibid.*

को मछली पकड़ने का प्रथागत अधिकार है।⁹³⁹ मछली पकड़ने के प्रथागत माओरी अधिकार की अब वैतांगी संधि (मत्स्य पालन दावा) निपटान अधिनियम, 1992 द्वारा स्पष्ट रूप से गारंटी दी गई है।⁹⁴⁰ इसके अलावा, निपटान विलेख, 1992 के तहत, न्यूजीलैंड माओरी प्रथागत मत्स्य पालन प्रबंधन प्रथाओं और मछली के पारंपरिक संग्रह को सुविधाजनक बनाने के लिए बाध्य है।⁹⁴¹ मछली पकड़ने का माओरी अधिकार मत्स्य पालन अधिनियम 1996,⁹⁴² माओरी मत्स्य पालन अधिनियम, 2004,⁹⁴³ और माओरी वाणिज्यिक जलीय कृषि दावा निपटान अधिनियम, 2004 द्वारा भी विनियमित है।⁹⁴⁴ न्यूजीलैंड ने यह सुनिश्चित करने के लिए मत्स्य संधि रणनीति भी तैयार की है कि मत्स्य पालन और जलीय कृषि से संबंधित वैतांगी की संधि के तहत माओरी के प्रति उसके दायित्वों को पूरा किया जाए।⁹⁴⁵

2.1.5. प्रथागत कानून और कानूनी प्रणालियाँ

माओरी (टिकंगा माओरी के रूप में भी संदर्भित) कानून और रीति-रिवाज जो लंबे समय से और सार्वभौमिक रूप से चले आ रहे हैं, उन्हें 'निरंतरता की धारणा' के आधार पर कानून की शक्ति के रूप में मान्यता दी जाती है और तदनुसार कानून और समानता में उपलब्ध उपचारों के माध्यम से लागू किए जा सकते हैं।⁹⁴⁶ वैतांगी की संधि टिकंगा माओरी की रक्षा करती है; न्यूजीलैंड टिकंगा माओरी को संधि कानून के स्रोत के रूप में स्वीकार करता है।⁹⁴⁷ टिकंगा माओरी सजा सुनाने, पारिवारिक संरक्षण के दावों, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और उपयोग और भूमि के प्रशासन को नियंत्रित करता है।⁹⁴⁸ माओरी भूमि न्यायालय भूमि दावों के निपटारे के लिए टिकंगा माओरी को लागू करता है; उदाहरण के लिए, फ्रीहोल्ड भूमि (कई मालिकों के साथ) से संबंधित विवादों के लिए माओरी भूमि न्यायालय टिकंगा माओरी के अनुसार माओरी द्वारा आयोजित भूमि को 'माओरी प्रथागत भूमि' मान सकता है।⁹⁴⁹

न्यूजीलैंड को माओरी रीति-रिवाजों और सांस्कृतिक मूल्यों और किसी दी गई स्थिति में उनके अनुप्रयोग को समझने के लिए सामान्य घरेलू अदालतों की भी आवश्यकता होती है।⁹⁵⁰ न्यूजीलैंड के सर्वोच्च न्यायालय ने *एलिस बनाम आर में* अभिनिर्धारित किया कि "आओटेरोआ/न्यूजीलैंड के कॉमन लॉ के विकास में 'टिकंगा' को उन मामलों में मान्यता दी गई है और आगे भी दी जाती रहेगी जहाँ यह प्रासंगिक है", कि यह अक्सर "कानूनों और नियमों में शामिल किए जाने के कारण न्यूजीलैंड के कानून का हिस्सा बन जाता है" और यह "[न्यायिक] विवेचनाओं

⁹³⁹ *Te Weehiv. Regional Fisheries Officer*, 1 N.Z.L.R. 682 (1986).

⁹⁴⁰ The Treaty of Waitangi (Fisheries Claims) Settlement Act, 1992, s. 10(c).

⁹⁴¹ The Deed of Settlement, 1992, s. 3.5.1.1.

⁹⁴² The Fisheries Act, 1996, s. 5.

⁹⁴³ The Maori Fisheries Act, 2004, s. 3.

⁹⁴⁴ The Māori Commercial Aquaculture Claims Settlement Act, 2004, s. 3.

⁹⁴⁵ Adrienne Davidson and Veldon Coburn, "Multiculturalism Policy Index: Indigenous Peoples", *Queen's University* (2021), p. no. 45.

⁹⁴⁶ *Id.* at 46.

⁹⁴⁷ *Ibid.*

⁹⁴⁸ *Ibid.*

⁹⁴⁹ *Ibid.*

⁹⁵⁰ *Ellis v. R.*, NZSC 114 (2020), para. 279.

का इस्तेमाल करते समय एक महत्वपूर्ण विचार हो सकता है।"⁹⁵¹ मामला इस बात से निपटता है कि क्या आपराधिक दोषसिद्धि के खिलाफ अपील का अधिकार अपीलार्थी की मृत्यु के साथ समाप्त हो जाता है, सामान्य कानून और टिकंगा माओरी परस्पर विरोधी उत्तर देते हैं।⁹⁵² माओरी सामुदायिक विकास अधिनियम, 1962 ने माओरी जिला समितियों (*स्थानीय माओरी समितियों से बनी*), माओरी जिला परिषदों और न्यूजीलैंड की राष्ट्रीय माओरी परिषद (*माओरी जिला समितियों से बनी*) की स्थापना की।⁹⁵³ माओरी सामुदायिक विकास अधिनियम, 1962 के तहत, माओरी जिला समितियों को माओरी प्रथागत कानून के आधार पर कार्य करने के लिए अधिकृत किया गया है, लेकिन वे न्यूजीलैंड में माओरी मामलों के मंत्री के निर्देशन और नियंत्रण में काम करती हैं।⁹⁵⁴

2.1.6. भाषा का संरक्षण

माओरी भाषा अधिनियम, 1987 न्यूजीलैंड में माओरी भाषा को एक आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता देता है,⁹⁵⁵ इस प्रकार माओरी को कानूनी कार्यवाही में अपनी मूल भाषा में मौखिक रूप से संवाद करने का अधिकार देता है।⁹⁵⁶ हालाँकि, माओरी लोगों को माओरी भाषा में संबोधित किए जाने या उत्तर दिए जाने पर जोर देने का अधिकार नहीं है।⁹⁵⁷ माओरी भाषा अधिनियम, 1987 ने माओरी भाषा आयोग की भी स्थापना की, जिसे "*विशेष रूप से, माओरी भाषा को बढ़ावा देने, और एक जीवित भाषा के रूप में और संचार के एक सामान्य साधन के रूप में इसके उपयोग*" का काम सौंपा गया था।⁹⁵⁸ न्यूजीलैंड ने 2003 में माओरी भाषा को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से माओरी भाषा रणनीति की शुरुआत की।⁹⁵⁹ माओरी भाषा अधिनियम, 2016 के पारित होने के साथ, माओरी भाषाओं को आधिकारिक दर्जा प्रदान किया गया है, इस प्रकार आधिकारिक सूचनाओं, कानूनी कार्यवाही और व्यावसायिक लेनदेन में उनके उपयोग को सक्षम बनाया गया है।⁹⁶⁰

2.1.7. गैर-भेदभाव और सकारात्मक कार्रवाई

अधिकार विधेयक अधिनियम, 1990 और मानवाधिकार अधिनियम, 1993 नस्ल के आधार पर

⁹⁵¹ *Id.* at para. 19.

⁹⁵² *Id.* at paras. 24-26, 312.

⁹⁵³ The Māori Community Development Act, 1962, s. 15.

⁹⁵⁴ Adrienne Davidson and Veldon Coburn, "Multiculturalism Policy Index: Indigenous Peoples", *Queen's University* (2021), p. no. 43; The Māori Community Development Act, 1962, s. 3.

⁹⁵⁵ The Māori Language Act, 1987, s. 3.

⁹⁵⁶ *Id.* s. 4(1).

⁹⁵⁷ Adrienne Davidson and Veldon Coburn, "Multiculturalism Policy Index: Indigenous Peoples", *Queen's University* (2021), p. no. 45.

⁹⁵⁸ The Māori Language Act, 1987, s. 7.

⁹⁵⁹ Ministry of Maori Development, *The Māori Language Strategy, Te Puni Kokiri*, available at: <https://www.tpk.govt.nz/en/o-matou-mohiotanga/te-reo-maori/the-maori-language-strategy> (last visited on Oct. 5, 2025).

⁹⁶⁰ The Māori Language Act, 2016, s. 5; Adrienne Davidson and Veldon Coburn, "Multiculturalism Policy Index: Indigenous Peoples", *Queen's University* (2021), p. no. 45.

भेदभाव को प्रतिबंधित करते हैं।⁹⁶¹ मानवाधिकार अधिनियम 1993 यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट करते हुए सकारात्मक कार्रवाई को मंजूरी देता है कि वंचित समुदायों को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से अपनाए गए वैधानिक या नीतिगत उपाय भेदभाव के बराबर नहीं हैं।⁹⁶² हालांकि, 1980 के दशक की शुरुआत में, न्यूजीलैंड ने सार्वजनिक क्षेत्र के रोजगार में माओरी का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए माओरी और प्रशांत द्वीपवासी भर्ती योजना जैसे उपाय शुरू किए थे।⁹⁶³ हाल ही में, न्यूजीलैंड ने लोक सेवा अधिनियम, 2020 लागू किया, जिसमें कहा गया कि नियोक्ता को माओरी की आकांक्षाओं, उद्देश्यों और आवश्यकताओं को पहचानने का प्रयास करना चाहिए और सार्वजनिक सेवा में माओरी की बढ़ती भागीदारी के लिए प्रयास करना चाहिए।⁹⁶⁴ शिक्षा अधिनियम, 1989 विश्वविद्यालयों को सकारात्मक कार्रवाई को आगे बढ़ाने के लिए 'भेदभावपूर्ण' उपायों का सहारा लेने का अधिकार भी देता है।⁹⁶⁵ न्यूजीलैंड ने माओरी के लिए चिकित्सा और कानूनी अध्ययन में प्रवेश में, 'विशेष प्रवेश कोटा' तैयार करने वाली नीतियां स्थापित की हैं।⁹⁶⁶

2.2. ऑस्ट्रेलिया

2.2.1. संवैधानिक मान्यता

ऑस्ट्रेलिया के स्वदेशी आदिवासी और टोरेस स्ट्रेट आइलैंडर लोगों को विशेष रूप से संविधान में संदर्भित नहीं किया गया है।⁹⁶⁷ 1901 में अपनाई गई धारा 51(xxvi) के तहत, राष्ट्रमंडल को यह विधायी शक्ति दी गई थी कि वह ज़रूरत पड़ने पर "किसी भी राज्य में मूल निवासी के अलावा, किसी जाति, अन्य जाति के लोगों" के लिए विशेष कानून बना सके।⁹⁶⁸ इसके अलावा, धारा 127 में यह प्रावधान था कि "राष्ट्रमंडल के लोगों की संख्या की गिनती करते समय... आदिवासी मूल निवासियों को नहीं गिना जाएगा"।⁹⁶⁹ हालांकि, 1967 में एक जनमत संग्रह के ज़रिए संविधान में संशोधन करके धारा 127 को हटा दिया गया, जिससे चुनावी प्रतिनिधित्व के लिए ऑस्ट्रेलिया की राष्ट्रीय आबादी में आदिवासी जातियों को भी शामिल करने की अनुमति मिल गई।⁹⁷⁰ इस संशोधन ने "किसी भी राज्य में आदिवासी मूल-निवासियों के अलावा" वाक्यांश को हटाकर, धारा 51(xxvi) के तहत

⁹⁶¹ The New Zealand Bill of Rights Act, 1990, s.19; The Human Rights Act, 1993, s.21.

⁹⁶² Adrienne Davidson and Veldon Coburn, "Multiculturalism Policy Index: Indigenous Peoples", *Queen's University* (2021), p. nos. 48, 49; The Human Rights Act, 1993, s.73.

⁹⁶³ Marilyn E. Lashley, "Remedying Racial and Ethnic Inequality in New Zealand: Reparative and Distributive Policies of Social Justice", in Samuel L. Myers and Bruce P. Corrie (eds.), *Racial and Ethnic Economic Inequality: An International Perspective* 138 (Peter Land Publishing, 1996).

⁹⁶⁴ The Public Service Act, 2020, ss.14, 75.

⁹⁶⁵ The Education Act, 1989, s.16.

⁹⁶⁶ Adrienne Davidson and Veldon Coburn, "Multiculturalism Policy Index: Indigenous Peoples", *Queen's University* (2021), p. no. 49.

⁹⁶⁷ Australian Human Rights Commission, *About Constitutional Recognition*, available at: <https://humanrights.gov.au/our-work/aboriginal-and-torres-strait-islander-social-justice/about-constitutional-recognition> (last visited on Oct. 5, 2025).

⁹⁶⁸ The Constitution of Australia, s.51(xxvi).

⁹⁶⁹ *Id.* s.127.

⁹⁷⁰ Constitution Alteration (Aboriginals), 1967, s. 3.

आदिवासी मूल-निवासियों के संबंध में राष्ट्रमंडल की विधायी शक्तियों का भी विस्तार किया।⁹⁷¹ इस तरह के परिवर्तन के परिणामस्वरूप, 'आदिवासी जातियों' का उल्लेख संविधान से पूरी तरह से हटा दिया गया था।

हालाँकि 2024 में संविधान में आदिवासी और टोरेस स्ट्रेट आइलैंडर लोगों को 'ऑस्ट्रेलिया के पहले लोग' के रूप में मान्यता देने और उन्हें प्रभावित करने वाले कानूनों और नीतियों पर विशेषज्ञ सलाह प्रदान करने के लिए संवैधानिक रूप से स्थापित प्रतिनिधि तंत्र के माध्यम से संसद में एक स्वदेशी आवाज हासिल करने के लिए एक जनमत संग्रह आयोजित किया गया था, लेकिन इसे पारित नहीं किया गया था।⁹⁷² फिर भी, ऑस्ट्रेलिया के छह राज्यों में से प्रत्येक, आदिवासी लोगों को उनके संबंधित संविधानों में मान्यता देता है; क्वींसलैंड का संविधान टोरेस स्ट्रेट आइलैंडर लोगों को मान्यता देता है।⁹⁷³ 2008 में, ऑस्ट्रेलियाई संसद ने "क्रमिक संसदों और सरकारों के कानूनों और नीतियों के लिए माफ़ी मांगी, जिन्होंने आदिवासी और टोरेस स्ट्रेट आइलैंडर लोगों पर गहरा दुख, पीड़ा और नुकसान पहुंचाया है"।⁹⁷⁴

2.2.2. पैतृक भूमि का शीर्षक

संविधान के मसौदे के समय, ऑस्ट्रेलिया को एक ऐसी भूमि माना जाता था जो यूरोपीय बस्तियों की स्थापना तक किसी की नहीं थी। नतीजतन, आदिवासी और टोरेस स्ट्रेट आइलैंडर लोगों का अपने पैतृक क्षेत्रों पर ऑस्ट्रेलियाई राष्ट्र के निर्माण में कोई योगदान नहीं था।⁹⁷⁵ हालाँकि, उच्च न्यायालय द्वारा अपने माबो निर्णयों में आदिवासी लोगों को 'ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी' के तौर पर दी गई है। न्यायालय ने टेरा नलिस' उस धारणा को साफ तौर पर खारिज कर दिया है, जिसके अनुसार उपनिवेशीकरण से पहले ऑस्ट्रेलिया एक खाली ज़मीन थी। साथ ही, कोर्ट ने स्पष्ट रूप से माना है कि कॉमन लॉ, ऑस्ट्रेलियाई ज़मीन और जल पर आदिवासी और टोरेस स्ट्रेट आइलैंडर लोगों के पुराने और अभी भी जारी पारंपरिक और रीति-रिवाज़ों पर आधारित अधिकार को मान्यता देता है। एबोरिजिनल एंड टोरेस स्ट्रेट आइलैंडर पीपुल्स रिकग्निशन एक्ट, 2013 ने इस समझ को कानून में संहिताबद्ध किया: "संसद, ऑस्ट्रेलिया के लोगों की ओर से, यह मानती है कि महाद्वीप और अब ऑस्ट्रेलिया के रूप में जाने जाने वाले द्वीपों पर पहले एबोरिजिनल और टोरेस स्ट्रेट आइलैंडर लोगों का कब्जा था... आदिवासी और टोरेस स्ट्रेट आइलैंडर

⁹⁷¹ Australian Human Rights Commission, *About Constitutional Recognition*, available at: <https://humanrights.gov.au/our-work/aboriginal-and-torres-strait-islander-social-justice/about-constitutional-recognition> (last visited on Oct. 5, 2025).

⁹⁷² *Ibid.*

⁹⁷³ United Nations Human Rights Council, *Report of the Special Rapporteur on the Rights of Indigenous Peoples on her visit to Australia*, UN Doc A/HRC/36/46/Add.2 (2017), para. 18.

⁹⁷⁴ Adrienne Davidson and Veldon Coburn, "Multiculturalism Policy Index: Indigenous Peoples", *Queen's University* (2021), p. no. 13.

⁹⁷⁵ Australian Human Rights Commission, *About Constitutional Recognition*, available at: <https://humanrights.gov.au/our-work/aboriginal-and-torres-strait-islander-social-justice/about-constitutional-recognition> (last visited on Oct. 5, 2025).

⁹⁷⁶ *Mabo v. Queensland (No. 2)*, 175 CLR 1 F.C. 92/014 (1992).

*अपनी पारंपरिक भूमि और जल के साथ निरंतर संबंधों को स्वीकार करते हैं।*⁹⁷⁷

माबो के फैसलों से पहले भी, कई राज्य और संघीय क्षेत्रीय कानूनों ने ने आदिवासी और टोरेस स्ट्रेट आइलैंडर लोगों के उनके अपने पैतृक क्षेत्रों के अधिकारों को मान्यता दे दी थी। उदाहरण के लिए, दक्षिण ऑस्ट्रेलिया के आदिवासी भूमि न्यास अधिनियम, 1966 ने भूमि के आदिवासी स्वामित्व की अनुमति दी 'कॉमन लॉ नेटिव टाइटल' (पारंपरिक ज़मीनी अधिकार) को मान्यता नहीं दी।⁹⁷⁸ इसके बाद, आदिवासी भूमि अधिकार (उत्तरी) क्षेत्र अधिनियम, 1976 पहला ऐसा कानून बना जिसने ज़मीन का दावा किए बिना आदिवासियों के ज़मीन पर मालिकाना हक को मान्यता दी और उन्हें 'इनएलियनेबल फ्रीहोल्ड टाइटल' (ऐसा मालिकाना हक जिसे किसी और को नहीं सौंपा जा सकता) कानूनी तौर पर दिया।⁹⁷⁹ नतीजतन, 'आदिवासी रिज़र्व' को 'आदिवासी ज़मीन' में बदल दिया गया।⁹⁸⁰

दक्षिण ऑस्ट्रेलिया के पितजंतजातजारा भूमि अधिकार अधिनियम, 1981 के अनुसार, सभी पितजंतजातजारों को "भूमि तक पहुंच के अप्रतिबंधित अधिकार" दिए गए।⁹⁸¹ यह कानून "राज्य के कानूनों में बदलाव करने के एक विशेष उपाय के तौर पर लाया गया था, ताकि अनंगु पितजंतजातजारा लोगों के उन पारंपरिक इलाकों पर उनके दावों को कानूनी मान्यता और सुरक्षा दी जा सके"।⁹⁸² तब से सभी ऑस्ट्रेलियाई राज्यों ने आदिवासी अधिकार और भूमि के अधिकार को संबोधित करने वाले कानून बनाए हैं। राष्ट्रमंडल द्वारा नेटिव टाइटल एक्ट, 1993-93 के पारित होने के साथ, पहले से मौजूद देशी शीर्षक और भूमि और पानी के आदिवासी अधिकारों को स्पष्ट रूप से मान्यता दी गई। नेटिव टाइटल एक्ट, 1993 ने भूमि के मूल अधिकार को प्रभावित करने वाले कृत्यों के लिए मुआवजे की मांग के लिए वैधानिक ढांचा भी निर्धारित किया; इसके अलावा, 1998 में एक बाद के संशोधन के माध्यम से, आदिवासी लोगों द्वारा संभावित भूमि दावों पर कई सीमाएं लगाई गईं।⁹⁸⁴ हाल ही में, पूर्वी मार राष्ट्र, बारह प्रेरितों के पारंपरिक मालिकों, जिन्हें ग्रेट ओशन रोड और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 2020 के तहत मान्यता प्राप्त है, ने एक सफल भूमि दावे के अनुसार, इस क्षेत्र पर सफलतापूर्वक कब्जा कर लिया।⁹⁸⁵

2.2.3. स्वशासन

ऑस्ट्रेलिया में, आदिवासी लोग आदिवासी भूमि परिषदों के माध्यम से सीमित सीमा

⁹⁷⁷The Aboriginal and Torres Strait Islander Peoples Recognition Act, 2013, s.3.

⁹⁷⁸The Aboriginal Land Trust Act, 1966, s.5; Christa Scholtz, "Federalism and Policy Change: An Analytic Narrative of Indigenous Land Rights Policy in Australia (1966-1978)" 46(2) *Canadian Journal of Political Science* 406 (2013).

⁹⁷⁹ Adrienne Davidson and Veldon Coburn, "Multiculturalism Policy Index: Indigenous Peoples", *Queen's University* (2021), p.no.7.

⁹⁸⁰ *Ibid.*

⁹⁸¹ The Pitjantjatjara Land Rights Act, 1981, s.18.

⁹⁸² *David Alan Gerhardt v. Robert John Brown*, 59 A.L.J.R. 311 (1985).

⁹⁸³ The Native Title Act, 1993, s.10.

⁹⁸⁴ Adrienne Davidson and Veldon Coburn, "Multiculturalism Policy Index: Indigenous Peoples", *Queen's University* (2021), p.no.7.

⁹⁸⁵ *Austin on behalf of the Eastern Maar People v. State of Victoria*, FCA 237 (2023).

तक स्थानीय स्तर पर स्व-शासन का प्रयोग करने के हकदार हैं।⁹⁸⁶ आदिवासी लोग आदिवासी भूमि परिषदों के सदस्यों का चुनाव करते हैं, जिन्हें निगमित, वैधानिक संस्थाओं के रूप में संगठित किया जाता है जो मूल शीर्षक के प्रबंधन में प्रत्येक राज्य और संघीय क्षेत्र में आदिवासी भूमि मालिकों का प्रतिनिधित्व करते हैं। आदिवासी भूमि परिषदें आदिवासी लोगों को आवास, कानूनी मामलों, रोजगार, प्रशिक्षण, संपत्ति अधिग्रहण और प्रबंधन सहित सेवाओं के वितरण की भी देखरेख करती हैं।⁹⁸⁷ आदिवासी भूमि परिषदें लोगों के प्रवेश, यातायात का विनियमन, शराब, पदार्थों और हथियारों पर नियंत्रण और अपशिष्ट निपटान जैसे मामलों से संबंधित आदिवासी भूमि और भंडारों के शासन पर उपनियम भी बना सकती हैं और उन्हें लागू कर सकती हैं।⁹⁸⁸

राज्य स्तर पर, आदिवासी क्षेत्रीय प्राधिकरणों ने आदिवासी राजनीतिक समूहों को मान्यता देने और आदिवासी मामलों की नीतियों के पीछे प्रेरक शक्ति के रूप में आदिवासी आत्मनिर्णय को स्थापित करने की दिशा में भी कदम उठाए हैं। उदाहरण के लिए, एबोरिजिनल एंड टोरेस स्ट्रेट आइलैंडर कमीशन एक्ट, 1989 (अब एबोरिजिनल एंड टोरेस स्ट्रेट आइलैंडर एक्ट, 2005)⁹⁸⁹ ने स्थानीय और सरकारी सेवाओं के प्रावधान के माध्यम से टोरेस स्ट्रेट आइलैंड्स का प्रशासन करने और टोरेस स्ट्रेट आइलैंड्स के लिए राजनीतिक प्रतिनिधि संरचना के रूप में काम करने और क्षेत्र के आर्थिक, सांस्कृतिक और सामाजिक विकास को मजबूत करने के लिए टोरेस स्ट्रेट रीजनल अथॉरिटी की स्थापना की, जिसमें 20 निर्वाचित प्रतिनिधि शामिल थे। इससे पहले के टोरेस स्ट्रेट आइलैंड्स एक्ट, 1939⁹⁹⁰ ने भी टोरेस स्ट्रेट आइलैंड्स को वोट देने का अधिकार और स्थानीय सरकार के प्रतिनिधियों का चुनाव करने का अधिकार दिया था, जिसमें उनके अपने अध्यक्ष और पार्षद शामिल थे। आज, सभी आदिवासी और टोरेस स्ट्रेट आइलैंडर लोगों को वोट देने का अधिकार है, साथ ही निर्वाचित कार्यालय के लिए उम्मीदवारों के रूप में चुनाव लड़ने का भी अधिकार है।

2.2.4. संस्कृति और परंपराओं का संरक्षण

आदिवासी और टोरेस स्ट्रेट आइलैंडर पीपुल्स रिकग्निशन एक्ट, 2013 "*आदिवासी और टोरेस स्ट्रेट आइलैंडर लोगों की निरंतर संस्कृतियों, भाषाओं और विरासत*" की रक्षा करता है।⁹⁹¹ आदिवासी और टोरेस स्ट्रेट आइलैंडर हेरिटेज प्रोटेक्शन एक्ट, 1984⁹⁹² उन स्थानों, क्षेत्रों और वस्तुओं की रक्षा करता है जो आदिवासी और आदिवासी और टोरेस स्ट्रेट आइलैंडर हेरिटेज प्रोटेक्शन एक्ट, 1984⁹⁹² उन स्थानों, क्षेत्रों और वस्तुओं की रक्षा करता है जो आदिवासी और टोरेस स्ट्रेट आइलैंडर लोगों के लिए सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण हैं। राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1975 आदिवासी लोगों को "*शिकार के लिए, भोजन एकत्र करने (बिक्री के उद्देश्यों के अलावा) और रीति-रिवाज और धार्मिक उद्देश्यों के लिए भूमि या पानी के किसी भी क्षेत्र*

⁹⁸⁶Government of Australia, *Aboriginal Land and Permits*, available at: <https://nt.gov.au/property/land/aboriginal-land-management/aboriginal-land-and-permits/land-council-roles-and-contacts> (last visited on Oct. 5, 2025).

⁹⁸⁷Jens Korff, "Aboriginal Land Councils" *Creative Spirits* (Jul. 17, 2020).

⁹⁸⁸Adrienne Davidson and Veldon Coburn, "Multiculturalism Policy Index: Indigenous Peoples", *Queen's University* (2021), p. no. 8.

⁹⁸⁹The Aboriginal and Torres Strait Islander Act, 2005, s. 142 A.

⁹⁹⁰The Torres Strait Islanders Act, 1939, s. 11.

⁹⁹¹The Aboriginal and Torres Strait Islander Peoples Recognition Act, 2013, s. 3.

⁹⁹²The Aboriginal and Torres Strait Islander Heritage (Interim Protection) Act, 1984, s. 4.

को 'पारंपरिक रूप में उपयोग' का अधिकार प्रदान करता है।⁹⁹³ राज्यों और संघीय क्षेत्रों में भी आदिवासी संस्कृति और विरासत, पारंपरिक शिकार और मछली पकड़ने की प्रथाओं और अपने स्वदेशी क्षेत्रों में वनस्पतियों और जीवों से निपटने के अधिकार की रक्षा करने वाले समान कानून हैं। आदिवासी लोगों के मछली पकड़ने के पारंपरिक अधिकार को टोरेस स्ट्रेट संधि,⁹⁹⁴ में भी मान्यता दी गई है, जो 1978 में ऑस्ट्रेलिया और पापुआ न्यू गिनी के बीच हुई एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है।⁹⁹⁵ आज, ऑस्ट्रेलियाई मानवाधिकार आयोग, एक स्वतंत्र वैधानिक निकाय है जिसे मानवाधिकारों के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने और ऑस्ट्रेलिया के घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दायित्वों पर मार्गदर्शन देने का काम सौंपा गया है, आदिवासी और टोरेस स्ट्रेट आइलैंडर लोगों को 'देश के पारंपरिक संरक्षक' के रूप में मान्यता देता है और "भूमि, जल और संस्कृति के साथ उनके निरंतर संबंध को मान्यता देता है।"⁹⁹⁶

2.2.5. भाषा का संरक्षण

ऑस्ट्रेलिया ने आदिवासी भाषाओं के संरक्षण के लिए भी कई उपाय किए हैं। स्वदेशी भाषाओं और अभिलेख कार्यक्रम का रखरखाव समुदाय आधारित स्वदेशी भाषा केंद्रों और भाषा संगठनों, भाषा परियोजनाओं और नीतिगत पहलों के एक सक्रिय नेटवर्क के निर्माण में सहायता करता है।⁹⁹⁷ राष्ट्रीय स्वदेशी भाषा नीति का उद्देश्य जागरूकता बढ़ाना, लुप्तप्राय भाषाओं को पुनर्जीवित करना और स्कूलों में स्वदेशी भाषा कार्यक्रमों का समर्थन करना है।⁹⁹⁸

ऑस्ट्रेलिया में पहली बार, न्यू साउथ वेल्स ने आदिवासी भाषाओं के संरक्षण के लिए कानून बनाया था।⁹⁹⁹ आदिवासी भाषा अधिनियम, 2017, न केवल आदिवासी भाषाओं के महत्व पर प्रकाश डालता है, बल्कि यह भी स्वीकार करता है कि आदिवासी भाषाओं का विलुप्त होना सरकार की कार्रवाई का परिणाम है।¹⁰⁰⁰ यह अधिनियम आदिवासी भाषाओं के प्रचार और रखरखाव के लिए आदिवासी भाषा न्यास की भी स्थापना करता है।¹⁰⁰¹

⁹⁹³The National Parks and Wildlife Conservation Act, 1975, s.70.1.

⁹⁹⁴The Torres Strait Treaty, 1978, art.10.3.

⁹⁹⁵Adrienne Davidson and Veldon Coburn, "Multiculturalism Policy Index: Indigenous Peoples", *Queen's University* (2021), p.no.10.

⁹⁹⁶Australian Human Rights Commission, available at: <https://humanrights.gov.au/> (last visited on Nov.11, 2025).

⁹⁹⁷The Maintenance of Indigenous Languages and Records program, available at: https://ourlanguages.org.au/wp-content/uploads/2010/06/milr_funding.pdf (last visited on Oct. 5, 2025); Department of the Environment, Water, Heritage and the Arts, *Social Justice Report 2009 Appendix 5* (2010), available at: https://humanrights.gov.au/sites/default/files/content/social_justice/sj_report/sjreport09/pdf/sjr_nx5.pdf (last visited on Oct. 5, 2025).

⁹⁹⁸Department of the Environment, Water, Heritage and the Arts, *Social Justice Report 2009 Appendix 3* (2010), available at: https://humanrights.gov.au/sites/default/files/content/social_justice/sj_report/sjreport09/pdf/sjr_nx5.pdf (last visited on Oct. 5, 2025).

⁹⁹⁹Adrienne Davidson and Veldon Coburn, "Multiculturalism Policy Index: Indigenous Peoples", *Queen's University*, (2021) p. no. 10.

¹⁰⁰⁰The Aboriginal Languages Act, 2017, preamble.

¹⁰⁰¹*Id.* s.5.

2.2.6. प्रथागत कानून और कानूनी प्रणालियाँ

ऑस्ट्रेलियाई कानून में आदिवासी प्रथागत कानूनों और प्रथाओं को शायद ही कभी मान्यता दी गई है, भले ही आदिवासी लोग अपने पारंपरिक मानदंडों को अपनाना और उनसे प्रभावित होना जारी रखते हैं।¹⁰⁰² हालांकि, माबो निर्णय में, उच्च न्यायालय ने स्वदेशी लोगों के भूमि के प्रथागत अधिकारों को मान्यता दी थी, इस प्रकार यह स्वीकार किया था कि स्वदेशी प्रथागत कानून का ऑस्ट्रेलिया में कानूनी बल है।¹⁰⁰³ घरेलू अदालतों के समक्ष जमानत और सजा के निर्णयों में प्रथागत कानून को भी ध्यान में रखा जाता है।¹⁰⁰⁴ राष्ट्रमंडल और राज्य कानून भी, एक सीमित सीमा तक, आदिवासी विवाह, बाल देखभाल प्रथाओं, विरासत और पवित्र और सांस्कृतिक स्थलों के संरक्षण से संबंधित स्वदेशी प्रथागत कानूनों और परंपराओं को मान्यता देते हैं।¹⁰⁰⁵ पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में, आदिवासी समुदाय अधिनियम, 1979¹⁰⁰⁶ आदिवासी लोगों को अपनी प्रथागत परंपराओं से प्राप्त अपने स्वयं के उपनियम बनाने का अधिकार देता है। इसके अलावा, आदिवासी भूमि अधिकार (उत्तरी क्षेत्र) अधिनियम, 1976 के तहत, आदिवासी लोग भूमि के अपने प्रथागत स्वामित्व के आधार पर राजसत्ता पर दावा करने के हकदार हैं।¹⁰⁰⁷

2.2.7. परामर्श

हालाँकि आदिवासी और टोरेस स्ट्रेट आइलैंडर लोगों ने उन नीतियों और विधानों पर परामर्श लेने के अपने अधिकार के संवैधानिक संरक्षण की वकालत की है जो उन्हें प्रभावित करते हैं, 2024 के जनमत संग्रह की विफलता के कारण, संसद में एक स्वदेशी आवाज की गारंटी नहीं दी जा सकी।¹⁰⁰⁸ हालांकि, ऑस्ट्रेलिया ने 1990 में आदिवासी और टोरेस स्ट्रेट आइलैंडर आयोग (एटीएसआईसी) की स्थापना एक सरकारी निकाय के रूप में की थी, जिसे देश भर के स्वदेशी लोगों को लक्षित करने वाली नीति निर्माण और सेवा वितरण का काम सौंपा गया था।¹⁰⁰⁹ ए. टी. एस. आई. सी. 35 क्षेत्रीय परिषद सदस्यों के साथ-साथ

¹⁰⁰² Adrienne Davidson and Veldon Coburn, "Multiculturalism Policy Index: Indigenous Peoples", *Queen's University* (2021), p.no.11.

¹⁰⁰³ *Mabov. Queensland* (No.2), 175 CLR 1 F.C.92/014 (1992).

¹⁰⁰⁴ Adrienne Davidson and Veldon Coburn, "Multiculturalism Policy Index: Indigenous Peoples", *Queen's University* (2021), p.no.11.

¹⁰⁰⁵ *Ibid.*

¹⁰⁰⁶ The Aboriginal Communities Act, 1979, ss.7,8.

¹⁰⁰⁷ Adrienne Davidson and Veldon Coburn, "Multiculturalism Policy Index: Indigenous Peoples", *Queen's University* (2021), p.no.11.

¹⁰⁰⁸ Tiffanie Turnbull, "Voice referendum: What is Australia's Voice to Parliament proposal?" *BBC News*, Oct.14, 2023; Australian Human Rights Commission, *About Constitutional Recognition: Recognition of Aboriginal and Torres Strait Islander Peoples in the Australian Constitution*, available at: <https://humanrights.gov.au/our-work/aboriginal-and-torres-strait-islander-social-justice/about-constitutional-recognition> (last visited on Oct.5, 2025).

¹⁰⁰⁹ The Centre of Democracy, *The Aboriginal and Torres Strait Islander Commission*, available at: <https://www.centreofdemocracy.sa.gov.au/milestone/aboriginal-and-torres-strait-islander-commission-atsic/> (last visited on Oct. 5, 2025).

एक राष्ट्रीय आयुक्त मंडल से बना था, जिसे आदिवासी और टोरेस स्ट्रेट आइलैंडर लोगों द्वारा चुना गया था।¹⁰¹⁰ तथापि, ए. टी. एस. आई. सी. को 2005 में समाप्त कर दिया गया था, और इसके कार्यों को परिवार, आवास, सामुदायिक सेवा और स्वदेशी मामलों के विभाग के तहत एक सरकारी प्रभाग स्वदेशी नीति समन्वय कार्यालय (ओ. आई. पी. सी.) द्वारा ले लिया गया था (और इसलिए इसमें एक प्रतिनिधि प्रकृति का अभाव था)।¹⁰¹¹ ओ. आई. पी. सी. राष्ट्रमंडल को आदिवासी मुद्दों पर नीतिगत सलाह प्रदान करता है और आदिवासी लोगों को सेवाओं के वितरण का समन्वय करता है।¹⁰¹² इसके बाद, हालांकि ATSIC को बदलने के लिए एक राष्ट्रीय प्रतिनिधि निकाय, नेशनल कांग्रेस ऑफ ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट पीपुल्स की स्थापना की गई थी, लेकिन इसने 2019 में अपना संचालन बंद कर दिया।¹⁰¹³ इसलिए, आदिवासी और टोरेस स्ट्रेट आइलैंडर लोगों का कानूनी रूप से गारंटीकृत परामर्श के अपने अधिकार के लिए संघर्ष जारी है।¹⁰¹⁴

2.2.8. गैर-भेदभाव और सकारात्मक कार्रवाई

ऑस्ट्रेलिया ने विभिन्न नीतियों और कानूनों के माध्यम से, आदिवासी और टोरेस स्ट्रेट आइलैंडर लोगों के लिए परिणामों में सुधार के उद्देश्य से सकारात्मक कार्रवाई उपायों और विशिष्ट पहलों को लागू किया है।¹⁰¹⁵ ये प्रयास ऐतिहासिक नुकसानों को दूर करने और रोजगार, आर्थिक विकास और सामाजिक कल्याण जैसे क्षेत्रों में समानता को बढ़ावा देने के लिए बनाए गए हैं। ऑस्ट्रेलिया में कई राष्ट्रमंडल और राज्य कानून आदिवासी और टोरेस स्ट्रेट आइलैंडर लोगों के लाभ के लिए सकारात्मक कार्रवाई की गारंटी देते हैं।¹⁰¹⁶ समान रोजगार अवसर (राष्ट्रमंडल प्राधिकरण) अधिनियम, 1987, भेदभाव को समाप्त करने और भर्ती में समान अवसर को बढ़ावा देने के उद्देश्य से "ऑस्ट्रेलिया की आदिवासी जाति के सदस्यों या टोरेस स्ट्रेट द्वीप समूह के स्वदेशी निवासियों के वंशज व्यक्तियों" को एक "नामित समूह" के रूप में मान्यता देता है।¹⁰¹⁷ इसके अलावा, राष्ट्रमंडल नस्लीय भेदभाव अधिनियम, 1975,¹⁰¹⁸ उन समूहों को काम पर रखने की प्रथाओं में विशेष उपचार प्रदान करके, जो ऐतिहासिक रूप से

¹⁰¹⁰The Parliament of Australia, *Evolution of ATSIC*, available at: https://www.aph.gov.au/Parliamentary_Business/Committees/Senate/Former_Committees/indigenousaffairs/report/final/c02 (last visited on Oct. 5, 2025).

¹⁰¹¹Adrienne Davidson and Veldon Coburn, "Multiculturalism Policy Index: Indigenous Peoples", *Queen's University* (2021), p. no. 12.

¹⁰¹²*Ibid.*

¹⁰¹³Australian Human Rights Commission, *The History of Aboriginal and Torres Strait Islander Peoples Advocating for the Right to be Heard*, available at: <https://humanrights.gov.au/our-work/aboriginal-and-torres-strait-islander-social-justice/history-aboriginal-and-torres-strait> (last visited on Oct. 5, 2025).

¹⁰¹⁴Adrienne Davidson and Veldon Coburn, "Multiculturalism Policy Index: Indigenous Peoples", *Queen's University* (2021), p. no. 12.

¹⁰¹⁵*Id.* at 14, 15.

¹⁰¹⁶Australian Public Service Commission, *Affirmative Measure for Recruiting Aboriginal and Torres Strait Islander Australians: A guide for agencies*, available at: <https://www.apsc.gov.au/working-aps/diversity-and-inclusion/aboriginal-and-torres-strait-islander-workforce/affirmative-measure-recruiting-aboriginal-and-torres-strait-islander-australians-guide-agencies> (last visited on Oct. 5, 2025).

¹⁰¹⁷The Equal Employment Opportunity (Commonwealth Authorities) Act, 1987, s. 3.

¹⁰¹⁸The Commonwealth Racial Discrimination Act, 1975, s. 8.

मानवाधिकारों से वंचित हैं, नस्लीय भेद को ध्यान में रखते हुए उपचारात्मक उपायों को अपनाने की अनुमति देता है। ऑस्ट्रेलिया ने हिरासत में स्वदेशी मौतों की उच्च दर के जवाब में 1987 में हिरासत में आदिवासी मौतों पर एक शाही आयोग की भी स्थापना की।¹⁰¹⁹ राज्य स्तर पर, तस्मानियाई राज्य सेवा अधिनियम, 1984 जैसे अधिनियम आदिवासी और टोरेस स्ट्रेट आइलैंडर लोगों को 'समान रोजगार अवसर' के लिए निर्दिष्ट लक्ष्य के रूप में मान्यता देते हैं, जिससे अधिकारियों को राज्य सार्वजनिक सेवा में कुछ 'आदिवासी पहचान वाले पदों' को निर्धारित करने की आवश्यकता होती है, जिन्हें केवल आदिवासी लोगों द्वारा भरा जा सकता है।¹⁰²⁰

राष्ट्रमंडल ने आदिवासी लोगों की आर्थिक स्थितियों में सुधार के उद्देश्य से नीतिगत उपायों को भी अपनाया है, जिसमें स्वदेशी खरीद नीति,¹⁰²¹ शामिल है, जो आदिवासी व्यवसायों के लिए कुछ खरीद अनुबंधों को सुरक्षित रखती है, और रोजगार समानता पहल¹⁰²² का उद्देश्य आदिवासी और टोरेस स्ट्रेट आइलैंडर लोगों को अतिरिक्त नौकरियां प्रदान करना है।¹⁰²³ 2007 के बाद से, आदिवासी और टोरेस स्ट्रेट आइलैंडर लोगों के सामने आने वाले नुकसान की पहचान करने और उन पर काबू पाने के लिए एक राष्ट्रमंडल पहल (ऑस्ट्रेलियाई सरकारों और आदिवासी और टोरेस स्ट्रेट आइलैंडर संगठनों के बीच साझेदारी में विकसित) 'क्लोजिंग द गैप' पर राष्ट्रीय समझौते के माध्यम से, आदिवासी लोगों के जीवन और कल्याण के लिए 17 महत्वपूर्ण सामाजिक-आर्थिक परिणामों के खिलाफ उत्पादकता आयोग द्वारा समय-समय पर प्रगति पर नज़र रखी जा रही है, ताकि यह आकलन किया जा सके कि क्या आदिवासी और टोरेस स्ट्रेट आइलैंडर लोगों के जीवन की गुणवत्ता में समय के साथ सुधार हो रहा है। इसके अलावा, आदिवासी लोगों के मानवाधिकार परिणामों की निगरानी आदिवासी और टोरेस स्ट्रेट आइलैंडर सामाजिक न्याय आयुक्त द्वारा की जाती है, जो ऑस्ट्रेलियाई संसद के समक्ष एक वार्षिक रिपोर्ट पेश करते हैं।¹⁰²⁴ 2024 में, ऑस्ट्रेलिया ने आदिवासी बच्चों, युवाओं और उनके परिवारों के अधिकारों, हितों और कल्याण के लिए बेहतर परिणामों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आदिवासी और टोरेस स्ट्रेट आइलैंडर बच्चों और युवाओं के लिए राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की।¹⁰²⁵

इन प्रगति के बावजूद, संविधान स्पष्ट रूप से नस्लीय भेदभाव की अनुमति देता है:

¹⁰¹⁹National Archives of Australia, *Royal Commission into Aboriginal Deaths in Custody*, available at: <https://www.naa.gov.au/explore-collection/first-australians/royal-commission-aboriginal-deaths-custody> (last visited on Oct. 5, 2025).

¹⁰²⁰Adrienne Davidson and Veldon Coburn, "Multiculturalism Policy Index: Indigenous Peoples", *Queen's University*, p. no.14 (2021).

¹⁰²¹National Indigenous Australians Agency, *The Indigenous Procurement Policy*, available at: <https://www.niaa.gov.au/our-work/employment-and-economic-development/indigenous-procurement-policy-ipp> (last visited on Oct. 5, 2025).

¹⁰²²Adrienne Davidson and Veldon Coburn, "Multiculturalism Policy Index: Indigenous Peoples", *Queen's University* (2021), p. nos. 14-15.

¹⁰²³*Id.* at 14.

¹⁰²⁴Closing the Gap, *National Agreement on Closing the Gap: At a Glance*, available at: <https://www.closingthegap.gov.au/national-agreement> (last visited on Oct. 5, 2025).

¹⁰²⁵Prime Minister and Cabinet Portfolio, *Establishment of the National Commission for Aboriginal and Torres Strait Islander Children and Young People*, available at: <https://ministers.pmc.gov.au/mccarthy/2024/establishment-national-commission-aboriginal-and-torres-strait-islander-children-and-young-people> (last visited on Oct. 5, 2025).

धारा 51 (xxvi), जो "किसी भी जाति के लोगों" के लिए विशेष कानूनों के अधिनियमन की अनुमति देती है, की बहुत आलोचना हुई है क्योंकि यह भेदभावपूर्ण कानून पारित करने का आधार देता है, जैसे कि में नेटिव टाइटल एक्ट और नॉर्दर्न टेरेटरी इमरजेंसी रिस्पांस में संशोधन।¹⁰²⁶ इसके अलावा, धारा 25 राज्यों को इस आशय के कानून बनाकर विशिष्ट नस्लों के लोगों को चुनाव में मतदान करने से रोकने की अनुमति देती है।¹⁰²⁷

3. उत्तरी अमेरिका के देश

3.1. कनाडा

3.1.1. ऐतिहासिक उपचार

फर्स्ट नेशंस, मैटिस और इनुइट सहित कई अलग-अलग स्वदेशी समुदाय उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी हैं।¹⁰²⁸ कनाडा ने राजकीय उद्घोषणा, 1763 में पहली बार अपनी स्वदेशी आबादी के अस्तित्व को स्वीकार किया, जिसने "भारतीयों के कई राष्ट्रों या जनजातियों" को मान्यता दी।¹⁰²⁹

प्रारंभ में, कनाडा में स्वदेशी अधिकारों को ब्रिटिश उत्तरी अमेरिका अधिनियम, 1867 द्वारा शासित किया गया था, जिसने संघीय सरकार को "भारतीयों और भारतीयों के लिए आरक्षित भूमि" पर कानून बनाने के लिए अधिकृत किया था।¹⁰³⁰

3.1.2. संवैधानिक और कानूनी मान्यता

इसके बाद, संविधान अधिनियम, 1982 ने 'आदिवासी लोगों' को स्पष्ट रूप से मान्यता दी। धारा 35 (2) 'आदिवासी लोगों' को कनाडा के भारतीय (प्रथम राष्ट्रों को संदर्भित करने वाला कानूनी शब्द) इनुइट और मैटिस लोगों को शामिल करने के रूप में परिभाषित करती है।¹⁰³¹ संविधान अधिनियम, 1982, हालांकि, स्वदेशी अधिकारों को निर्धारित नहीं करता है, लेकिन धारा 35 (1) प्रावधान करती है: "कनाडा के आदिवासी लोगों के मौजूदा आदिवासी और संधि अधिकारों को एतद्वारा मान्यता दी जाती है और पुष्टि की जाती है", इस प्रकार यह मान्यता दी जाती है कि आदिवासी लोग और उनके अधिकार संविधान अधिनियम, 1982 से पहले के हैं।¹⁰³² संविधान अधिनियम, 1982 की धारा 35 (1) के अनुसार, चूंकि केवल स्वदेशी लोगों में निहित पहले से मौजूद आदिवासी और संधि अधिकार धारा 35 द्वारा संरक्षित हैं, इसलिए ऐसे अधिकार क्या हैं, यह निर्धारित करने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी न्यायालयों को दी गई है।¹⁰³³

आदिवासी अधिकार आदिवासी लोगों के सामूहिक अधिकारों को संदर्भित करते हैं, जो कनाडा के मूल निवासियों के रूप में उनकी स्थिति से उत्पन्न होते हैं। आर बनाम वान डेर पीट में, कनाडा के सर्वोच्च न्यायालय ने कहा: "एक आदिवासी अधिकार होने के लिए एक गतिविधि एक प्रथा, प्रथा या परंपरा का एक तत्व

¹⁰²⁶The Constitution, s.51(xxvi).

¹⁰²⁷*Id.* s.25.

¹⁰²⁸Government of Canada, *Indigenous peoples and communities*, available at: <https://www.rcaanc-cirnac.gc.ca/eng/1100100013785/1529102490303> (last visited on Oct. 5, 2025).

¹⁰²⁹The Royal Proclamation, 1763, para.13.

¹⁰³⁰The British North America Act, 1867, s.91(24).

¹⁰³¹The Constitution Act, 1982, s.35(2).

¹⁰³²*Id.* s.35(1).

¹⁰³³University of British Columbia, *Constitution Act, 1982 Section 35*, available at: https://indigenousfoundations.arts.ubc.ca/constitution_act_1982_section_35/ (last visited on Nov.11, 2025)

होना चाहिए जो अधिकार का दावा करने वाले आदिवासी समूह की विशिष्ट संस्कृति का अभिन्न अंग है।”¹⁰³⁴ संधि अधिकारों में वे अधिकार शामिल हैं जो अब मौजूद हैं या क्राउन के साथ समझौतों के माध्यम से भविष्य में प्राप्त किए जा सकते हैं। 1701 की शुरुआत में, प्रथम राष्ट्रों के विशिष्ट समूहों, मैटिस या इनुइट ने क्रमशः क्राउन (संघीय, प्रांतीय और क्षेत्रीय सरकारों) के साथ कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौते किए हैं, जिन्हें ऐतिहासिक संधियों के रूप में संदर्भित किया गया है, जो आदिवासी लोगों के अधिकारों को मान्यता देते हैं। पहली ऐतिहासिक संधि के तहत, आदिवासी लोगों ने भंडार, वार्षिक भुगतान, चिकित्सा देखभाल और शिक्षा सहित लाभों के बदले में भूमि में अपने हितों को आत्मसमर्पण कर दिया।¹⁰³⁵ 1973 में, कनाडा के सर्वोच्च न्यायालय ने काल्डर एट में पहली बार भूमि के लिए आदिवासी अधिकार को कानूनी अधिकार के रूप में मान्यता दी। *अल बनाम ब्रिटिश कोलंबिया के महान्यायवादी*,¹⁰³⁶ ने पहली आधुनिक संधि, जेम्स बे और उत्तरी क्यूबेक समझौते का मार्ग प्रशस्त किया, जिस पर 1975 में हस्ताक्षर किए गए थे।¹⁰³⁷

तब से, कई आधुनिक संधियों को निष्पादित किया गया है, जो संघीय सरकार और स्वदेशी लोगों के बीच एक संवैधानिक रूप से मजबूत प्रतिबद्धता को दर्शाता है और राज्य संप्रभुता के साथ पहले से मौजूद स्वदेशी संप्रभुता के सामंजस्य को आगे बढ़ाता है, विशेष रूप से भूमि स्वामित्व के संबंध में स्वदेशी अधिकारों की पुष्टि के माध्यम से, स्वदेशी संस्कृति, विरासत और भाषाओं का संरक्षण, संसाधन प्रबंधन और विकास में भागीदारी, सामाजिक-आर्थिक कल्याण, और स्व-शासन, राजनीतिक मान्यता और प्रतिनिधित्व।¹⁰³⁸ ऑटारियो बनाम रेस्टौल में, कनाडा के सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि संघीय सरकार अपने संधि दायित्वों का उल्लंघन कर रही थी, जब वह रॉबिन्सन-सुपरियर प्रथम राष्ट्रों को वार्षिकी भुगतान बढ़ाने पर विचार करने में विफल रही, इस प्रावधान के बावजूद कि वार्षिकी भुगतान समय के साथ बढ़ाया जाएगा यदि ऐसा क्राउन को नुकसान पहुंचाए बिना किया जा सकता है।¹⁰³⁹ सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि यह विफलता "ऊपरी महान झीलों के अनिशिनाबे के लिए क्राउन की संधि के वादे का मजाक था।"¹⁰⁴⁰ इसके अलावा, आर बनाम मैकफर्सन में, कनाडा के सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय सुनाया कि प्रांतीय कानून जो आदिवासी लोगों के अधिकारों के खिलाफ हैं, उन्हें उनके लिए लागू नहीं माना जाना चाहिए।¹⁰⁴¹

कैनेडियन चार्टर ऑफ राइट्स एंड फ्रीडम्स (संविधान अधिनियम, 1982 का एक भाग)¹⁰⁴² धारा 25 में निर्धारित करता है कि व्यक्तिगत अधिकारों और स्वतंत्रताओं की गारंटी का इस तरह से अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि

¹⁰³⁴ *Rv. VanderPeet*, 2S.C.R.507(1996), para.46.

¹⁰³⁵ Government of Canada, *What are treaties with Indigenous peoples, available at: <https://www.rcaanc-cirnac.gc.ca/eng/1100100028574/1529354437231>* (last visited on Oct. 5, 2025).

¹⁰³⁶ *Calder et al. v. Attorney-General of British Columbia*, SCR313(1973).

¹⁰³⁷ Adrienne Davidson and Veldon Coburn, “Multiculturalism Policy Index: Indigenous Peoples”, *Queen’s University* (2021), p.no.17.

¹⁰³⁸ Government of Canada, *Canada’s Collaborative Modern Treaty Implementation Policy, available at: <https://www.rcaanc-cirnac.gc.ca/eng/1672771319009/1672771475448>* (last visited on Nov.11, 2025).

¹⁰³⁹ *Ontario (Attorney General) v. Restoule*, SCC27(2024).

¹⁰⁴⁰ *Id.* at para.2.

¹⁰⁴¹ Adrienne Davidson and Veldon Coburn, “Multiculturalism Policy Index: Indigenous Peoples”, *Queen’s University* (2021), p.no.18.

¹⁰⁴² The Constitution Act, 1982, part I.

वे कनाडा के आदिवासी लोगों से संबंधित किसी भी आदिवासी, संधि या अन्य अधिकारों या स्वतंत्रताओं को निरस्त या अपमानित करते हैं।”¹⁰⁴³ इस प्रकार धारा 25 यह सुनिश्चित करती है कि कनाडा में स्वदेशी लोगों के सामूहिक अधिकारों और स्वतंत्रताओं को एक अलग अल्पसंख्यक के रूप में संरक्षित किया जाए। उदाहरण के लिए, डिक्सन बनाम वुंटुट ग्विचिन फर्स्ट नेशन (वीजीएफएन) में कनाडा के सर्वोच्च न्यायालय को चार्टर की धारा 15 (1) के तहत समानता के अधिकार और धारा 25 के तहत स्वदेशी अधिकारों के बीच अंतर्संबंध के मुद्दे का सामना करना पड़ा, यह मामला वीजीएफएन संविधान में चुनावी निवास की शर्त से जुड़ा था, जिसमें कुछ पदों पर चुनाव लड़ने के लिए वीजीएफएन की ज़मीन पर रहने को ज़रूरी शर्त बताया गया था।¹⁰⁴⁴ कनाडा के सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि हालांकि निवास की आवश्यकता समानता के अधिकार का उल्लंघन थी, लेकिन इसे धारा 25 द्वारा संरक्षण प्राप्त था, जो स्वदेशी सरकारों के स्वशासन के अधिकार के प्रयोग में किए गए निर्णयों की रक्षा करता है।¹⁰⁴⁵

कनाडा ने स्वदेशी लोगों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र घोषणा अधिनियम, 2021 के माध्यम से संघीय कानून यूएनडीआरआईपी को भी अपनाया है, इस प्रकार कनाडा ऐसा करने वाले पहले देशों में से एक बन गया है।¹⁰⁴⁶ इसकी प्रस्तावना में कहा गया है कि यूएनडीआरआईपी सुलह, न्याय और शांति के लिए एक ढांचा स्थापित करता है, और खोज और टेरा नुलियस के सिद्धांतों को “नस्लवादी, वैज्ञानिक रूप से गलत, कानूनी रूप से अमान्य, नैतिक रूप से निंदनीय और सामाजिक रूप से अन्यायपूर्ण” के रूप में निंदा करता है।¹⁰⁴⁷ स्वदेशी लोगों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र घोषणा अधिनियम, 2021 के लिए आवश्यक है कि यह कनाडा के संघीय कानून यूएनडीआरआईपी के अनुरूप हों।¹⁰⁴⁸ स्वदेशी लोगों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र घोषणा अधिनियम, 2021, आगे स्पष्ट रूप से पुष्टि करता है कि यूएनडीआरआईपी “कनाडाई कानून में आवेदन के साथ एक सार्वभौमिक अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार साधन है”,¹⁰⁴⁹ इस प्रकार कनाडाई अदालतों को घरेलू कानून¹⁰⁵⁰ (संविधान अधिनियम, 1982 सहित) की व्याख्या में यूएनडीआरआईपी को लागू करने की आवश्यकता होती है, जिससे इसे ‘अर्ध-संवैधानिक’ दर्जा प्राप्त होता है।¹⁰⁵¹

3.1.3. पैतृक भूमि पर स्वामित्व का अधिकार

कई ऐतिहासिक संधियों ने आदिवासी लोगों को भूमि और क्षेत्र के अधिकार की गारंटी दी है। कनाडा के उच्चतम न्यायालय ने डेलगामुक बनाम ब्रिटिश कोलंबिया के मामले में स्पष्ट रूप से निर्णय दिया कि संविधान अधिनियम, 1982 की धारा 35 द्वारा भूमि के आदिवासी अधिकार

¹⁰⁴³ *Id.* s.25.

¹⁰⁴⁴ *Dickson v. Vuntut Gwitchin First Nation*, SCC10 (2024).

¹⁰⁴⁵ *Id.* at para.503.

¹⁰⁴⁶ Government of Canada, *Backgrounder: United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples Act*, available at: <https://www.justice.gc.ca/eng/declaration/about-apropos.html> (last visited on Oct.5, 2025).

¹⁰⁴⁷ International Work Group for Indigenous Affairs, *The Indigenous World 2024* (38th edn., 2024), p.no.484.

¹⁰⁴⁸ The United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples Act, 2021, s.5.

¹⁰⁴⁹ *Id.* s.4(a).

¹⁰⁵⁰ *Id.* s.4(b).

¹⁰⁵¹ Human Rights Council, *Constitutions, laws, legislation, policies, judicial decisions and other mechanisms through which States have taken measures to achieve the ends of the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, in accordance with article 38 of the Declaration*, UN Doc A/HRC/57/62 (Aug.2, 2024), para.16.

और स्वामित्व की पुष्टि की गई है, आदिवासी लोग अपने स्वदेशी क्षेत्रों के अनन्य कब्जे और उपयोग के हकदार हैं यदि यह साबित किया जा सकता है कि ऐसी भूमि पर उनका कब्जा ब्रिटिश संप्रभुता के दावे से पहले का है और तब से जारी है।¹⁰⁵² भूमि के आदिवासी अधिकार को कई कानूनों में भी स्वीकार किया गया है। भारतीय अधिनियम, 1876 के तहत, भूमि प्रथम राष्ट्रों के लिए आरक्षित की गई है, जिन पर उन्हें सांप्रदायिक स्वामित्व दिया गया है (केवल क्राउन के पक्ष में हस्तांतरणीय) हालांकि शीर्षक क्राउन में निहित है।¹⁰⁵³ मैनिटोबा अधिनियम, 1870 के अनुसार, मैटिस को भूमि आवंटित की गई थी,¹⁰⁵⁴ और अल्बर्टा का मैटिस सेटलमेंट अधिनियम, 1990 मैटिस के सामूहिक भूमि आधार की रक्षा करता है।¹⁰⁵⁵ इनुइट के भूमि अधिकारों की गारंटी जेम्स बे और उत्तरी क्यूबेक समझौते, इनुवियल्यूट अंतिम समझौते (पश्चिमी आर्कटिक दावा निपटान), लैब्राडोर इनुइट भूमि दावा समझौते-सिद्धांत और नुनावुत भूमि दावा समझौता अधिनियम के तहत दी जाती है।¹⁰⁵⁶

जहां भूमि का आदिवासी अधिकार और स्वामित्व संधि, विधान या न्यायिक घोषणाओं द्वारा शासित नहीं होता है, कनाडा की सरकार ने आदिवासी लोगों के साथ भूमि दावा वार्ता में शामिल होने की मांग की है।¹⁰⁵⁷ हैडा राष्ट्र मान्यता अधिनियम, 2024 के पारित होने के बाद, ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा का पहला प्रांत बन गया जिसने कानून के माध्यम से भूमि के आदिवासी अधिकार को स्पष्ट रूप से मान्यता दी। हालांकि,¹⁰⁵⁸ कनाडा अपनी एकतरफा रूप से लागू की गई कुछ नीतियों में सुधार करने में विफल रहा है, जो व्यापक भूमि दावों और स्व-सरकार नीतियों के अंतर्निहित अधिकार सहित आदिवासी अधिकारों और स्वामित्व को समाप्त कर देती हैं।¹⁰⁵⁹ इसके अलावा, आरक्षित नीति,¹⁰⁶⁰ में जोड़, जो प्रथम राष्ट्रों को अपने भंडार में भूमि जोड़ने की अनुमति देता है, का व्यवहार में सीमित कार्यान्वयन हुआ है, जिसमें पिछले कुछ वर्षों में देश भर में अनुमोदनों में लगातार गिरावट आई है।¹⁰⁶¹

3.1.4. स्व-शासन, भागीदारी और परामर्श

कनाडा की सरकार स्वीकार करती है कि आदिवासी लोगों को अपनी भूमि, संसाधनों, संस्कृतियों, परंपराओं, भाषाओं और संस्थानों के मामलों में स्व-शासन का अंतर्निहित अधिकार है,

¹⁰⁵² *Delgamuukw v. British Columbia*, 3 SCR 1010 (1997), paras. 114, 189-192.

¹⁰⁵³ *The Indian Act*, 1876.

¹⁰⁵⁴ *The Manitoba Act*, 1870.

¹⁰⁵⁵ *The Métis Settlements Act of Alberta*, 1990.

¹⁰⁵⁶ Adrienne Davidson and Veldon Coburn, "Multiculturalism Policy Index: Indigenous Peoples", *Queen's University* (2021), p.no.17.

¹⁰⁵⁷ *Id.* at 16.

¹⁰⁵⁸ International Work Group for Indigenous Affairs, *The Indigenous World 2025* (39th edn., 2025), p.no.523.

¹⁰⁵⁹ Government of Canada, *The Government of Canada's Approach to Implementation of the Inherent Right and the Negotiation of Aboriginal Self-Government*, available at: <https://www.rcaanc-cirnac.gc.ca/eng/1100100031843/1539869205136> (last visited on Oct. 5, 2025).

¹⁰⁶⁰ Government of Canada, *Additions to Reserve*, available at: <https://www.sac-isc.gc.ca/eng/1332267668918/1611930372477> (last visited on Oct. 5, 2025).

¹⁰⁶¹ Government of Canada, *Additions to Reserve: Policy Redesign*, available at: <https://www.rcaanc-cirnac.gc.ca/eng/1702578996213/1702579033924> (last visited on Nov. 11, 2025).

जो संविधान अधिनियम, 1982 की धारा 35 द्वारा संरक्षित है।¹⁰⁶² तथापि, इसे न तो विधान में मान्यता प्राप्त है और न ही कनाडा के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों में।¹⁰⁶³ कनाडा भी संघीय और प्रांतीय स्तरों पर संसद या विधानमंडलों में आदिवासी लोगों के गारंटीकृत प्रतिनिधित्व को बर्दाश्त नहीं करता है। फिर भी कनाडा ने आदिवासी लोगों के स्वशासन के अधिकार को स्वीकार करते हुए नीतिगत उपायों को अपनाया है।¹⁰⁶⁴ उदाहरण के लिए, एजेंडा फॉर एक्शन विद फर्स्ट नेशंस में कहा गया है कि "इस देश की स्थापना से पहले हजारों वर्षों तक आदिवासी लोगों ने सरकार के अपने रूपों का आनंद लिया और उनको स्वशासन का अंतर्निहित अधिकार बना हुआ है। संघीय सरकार प्रथम राष्ट्रों को स्वीकार्य सहमति की गति से सरकार-से-सरकार संबंधों पर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है।"¹⁰⁶⁵

भारतीय अधिनियम, 1876, जिसके तहत प्रथम राष्ट्र अपने समुदायों के लिए उपनियम तैयार करने के हकदार हैं, लेकिन भारतीय मामलों के मंत्री के अनुमोदन से, प्रथम राष्ट्रों को स्वशासन का सीमित अधिकार भी प्रदान किया गया था।¹⁰⁶⁶ उदाहरण के लिए, भूमि और अन्य संपत्तियों के प्रशासन से संबंधित या ऐतिहासिक संधि दायित्वों को पूरा न करने से संबंधित, जब क्राउन-स्वदेशी संबंधों और उत्तरी मामलों के मंत्री के पास शिकायत की जाती है, तो प्रथम राष्ट्रों के साथ बातचीत के माध्यम से अदालत प्रणाली के बाहर अतिरिक्त न्यायिक रूप से हल किया जाता है।¹⁰⁶⁷ संघीय सरकार ने आदिवासी समूहों के साथ 25 से अधिक स्वशासन समझौते भी किए हैं, इस प्रकार उन्हें स्व-शासन के लिए संधि-संबंधी अधिकार दिए गए हैं।¹⁰⁶⁸ निसगा अंतिम समझौता अधिनियम, 1999 निसगा सरकार की स्थापना करता है और इसे प्रांतीय कानून के अनुसार निसगा मामलों का संचालन करने, अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने और प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन करने का अधिकार प्रदान करता है।¹⁰⁶⁹ कनाडा के उच्चतम न्यायालय के कई निर्णयों में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि संविधान अधिनियम, 1982 की धारा 35 के अधीन कनाडा का कर्तव्य है कि वह उन मामलों पर, जो आदिवासी या संधि अधिकारों को प्रभावित कर सकते हैं, परमिट, प्राधिकरण या वित्त पोषण जारी

¹⁰⁶² Government of Canada, *The Government of Canada's Approach to Implementation of the Inherent Right and the Negotiation of Aboriginal Self-Government*, available at: <https://www.rcaanc-cirnac.gc.ca/eng/1100100031843/1539869205136> (last visited on Oct. 5, 2025).

¹⁰⁶³ Government of Canada, *Aboriginal Rights*, available at: <https://www.justice.gc.ca/eng/csj-sjc/ijr-dja/35pedia-wiki35/p6.html> (last visited on Nov. 11, 2025).

¹⁰⁶⁴ Adrienne Davidson and Veldon Coburn, "Multiculturalism Policy Index: Indigenous Peoples", *Queen's University* (2021), p. no. 20.

¹⁰⁶⁵ Shin Imai, *Aboriginal Law Handbook* 117 (Thomson Canada Ltd., 1999).

¹⁰⁶⁶ Government of Canada, *Self-government*, available at: <https://www.rcaanc-cirnac.gc.ca/eng/1100100032275/1529354547314> (last visited on Nov. 11, 2025).

¹⁰⁶⁷ Government of Canada, *Specific Claims*, available at: <https://www.rcaanc-cirnac.gc.ca/eng/1100100030291/1539617582343> (last visited on Oct. 5, 2025).

¹⁰⁶⁸ Adrienne Davidson and Veldon Coburn, "Multiculturalism Policy Index: Indigenous Peoples", *Queen's University* (2021), p. nos. 16-18.

¹⁰⁶⁹ The Nisga'a Final Agreement Act, 1999.

करने से संबंधित निर्णय लेने में स्वदेशी समूहों से सार्थक रूप से परामर्श करे और जहां उपयुक्त हो, उन्हें समायोजित करे।¹⁰⁷⁰ जहां आदिवासी अधिकारों और स्वतंत्रताओं में संशोधनों पर विचार-विमर्श किया जा रहा है, सरकार इस प्रकार प्रक्रियात्मक सुरक्षा के रूप में अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से आदिवासी लोगों की भागीदारी को आमंत्रित करने के लिए बाध्य है।¹⁰⁷¹ प्रथम राष्ट्रों, मैटिस और इनुइट का प्रतिनिधित्व क्षेत्रीय, प्रांतीय और संघीय स्तरों पर कई प्रतिनिधि संगठनों द्वारा किया जाता है, जिसमें प्रथम राष्ट्रों की सभा, मैटिस राष्ट्रीय परिषद और इनुइट तापिरिट कनाटामी शामिल हैं।¹⁰⁷²

कनाडा ने आदिवासी परामर्श और आवास: संघीय अधिकारियों के लिए परामर्श करने की कानूनी कर्तव्य को पूरा करने के लिए अंतरिम दिशानिर्देश भी तैयार किए हैं। हैडा नेशन बनाम ब्रिटिश कोलंबिया (वन मंत्री)¹⁰⁷³ के ऐतिहासिक निर्णय में कनाडा के सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संघीय और प्रांतीय दोनों सरकारों का कर्तव्य है कि वे आदिवासी लोगों से परामर्श करें और आदिवासी अधिकारों या अधिकार से संबंधित दावों को निपटाने से पहले उनकी आशांकाओं को ध्यान में रखें, ताकि आदिवासी और अन्य हितों के बीच सामंजस्य स्थापित किया जा सके। हालांकि, मिकिसेव क्री फर्स्ट नेशन बनाम कनाडा (गवर्नर जनरल इन काउंसिल)¹⁰⁷⁴ में कनाडा के सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि परामर्श करने का कानूनी कर्तव्य केवल मौजूदा कानूनों के तहत राज्य के व्यवहार तक ही सीमित है, न कि नए कानूनों के विचार-विमर्श और अधिनियमन के लिए विधायी प्रक्रिया तक है, हालांकि सरकारें नीति के रूप में आदिवासी लोगों के साथ बातचीत कर सकती हैं।

3.1.5. संस्कृति और परंपराओं का संरक्षण

आदिवासी लोगों का अपनी संस्कृति की रक्षा करने का अधिकार संविधान अधिनियम, 1982 की धारा 35 में निहित है। आर बनाम स्पैरो में, एक भारतीय के संबंध में जिसे मत्स्य पालन अधिनियम, 1970 के तहत निर्धारित मछली पकड़ने के नियमों का उल्लंघन करने के लिए दोषी ठहराया गया था, कनाडा के सर्वोच्च न्यायालय ने पाया कि किसी भी गैर-खतरनाक तरीकों के माध्यम से सैल्मन मछली पकड़ने में शामिल होने का आदिवासी अधिकार हमेशा उनकी विशिष्ट संस्कृति का एक अभिन्न अंग रहा है और इसलिए संविधान अधिनियम, 1982 की धारा 35 द्वारा संरक्षित है।¹⁰⁷⁵ इसने आगे कहा कि आदिवासी अधिकारों को केवल सम्मोहक कारण के लिए ही सीमित किया जा सकता है, और और वह भी तब जब यह पाबंदी उनके अधिकारों में कम से कम दखल देने वाले तरीके से लगाई जाए।¹⁰⁷⁶ शिकार, ट्रेपिंग और मछली पकड़ने के साथ-साथ उनके धर्म के अभ्यास सहित आदिवासी लोगों के सांस्कृतिक अधिकारों को भी संधियों में स्पष्ट रूप से मान्यता दी गई है। आर बनाम सिउई में, कनाडा के सर्वोच्च न्यायालय ने "अंग्रेजों के साथ अपने धर्म, रीति-रिवाजों और व्यापार के स्वतंत्र अभ्यास" के संधि के अधिकार

¹⁰⁷⁰ *R. v. Sparrow*, 1SCR1075 (1990); *Haida Nation v. British Columbia (Minister of Forests)*, 3S.C.R.511 (2004); *Mikisew Cree First Nation v. Canada (Governor General in Council)*, 2SCR765 (2018).

¹⁰⁷¹ Government of Canada, *Government of Canada and the duty to consult*, available at: <https://www.rcaanc-cimac.gc.ca/eng/1331832510888/1609421255810> (last visited on Oct. 5, 2025).

¹⁰⁷² International Work Group for Indigenous Affairs, *The Indigenous World 2025* (39th ed., 2025), p.no.478.

¹⁰⁷³ *Haida Nation v. British Columbia (Minister of Forests)*, 3S.C.R.511 (2004).

¹⁰⁷⁴ *Mikisew Cree First Nation v. Canada (Governor General in Council)*, 2SCR 765 (2018).

¹⁰⁷⁵ *R. v. Sparrow*, 1SCR1075 (1990), p.no.1094.

¹⁰⁷⁶ *Id.* at 1113.

की पुष्टि की।¹⁰⁷⁷ इसके अलावा, कनाडा में देशीय अदालतों परंपरिक विवाह और गोद लेने सहित आदिवासी प्रथागत कानून और प्रथाओं को मान्यता देती हैं। प्रथागत विवाहों को प्रांतीय कानूनों के तहत संपन्न विवाहों के बराबर माना जाता है।¹⁰⁷⁸

3.1.6. गैर-भेदभाव और सकारात्मक कार्रवाई

कनाडा ने आदिवासी लोगों को लाभान्वित करने वाली सकारात्मक कार्रवाई की दिशा में कई विधायी और नीतिगत उपायों को अपनाया है। रोजगार समानता अधिनियम, 1995 प्रत्येक नियोक्ता को "ऐसी सकारात्मक नीतियों और प्रथाओं को स्थापित करके और इस तरह के उचित आवास बनाकर संघीय सार्वजनिक सेवा में इक्विटी को लागू करने के लिए अनिवार्य करता है जो यह सुनिश्चित करेगा कि नामित समूहों में व्यक्ति नियोक्ता के कार्यबल में प्रत्येक व्यावसायिक समूह में प्रतिनिधित्व की एक डिग्री प्राप्त करें जो कनाडा के कार्यबल में उनके प्रतिनिधित्व को दर्शाता है।"¹⁰⁷⁹ हालांकि प्रांतीय और क्षेत्रीय स्तरों पर आदिवासी लोगों के पक्ष में सकारात्मक कार्रवाई करने वाला कोई विशिष्ट कानून नहीं है, फिर भी नियोक्ताओं को भर्ती और मजदूरी में उनकी नस्लीय पहचान के आधार पर आदिवासी लोगों के साथ भेदभाव करने से प्रतिबंधित किया गया है।¹⁰⁸⁰

क्षेत्रीय स्तर पर, क्षेत्रीय सार्वजनिक सेवाओं में इनुइट, मैटिस या डेने वंश के आदिवासी लोगों के लिए रोजगार समानता सुनिश्चित करने के लिए कई सकारात्मक कार्य योजनाएं शुरू की गई हैं।¹⁰⁸¹ ब्रेकिंग ट्रेल टुगेदर कार्यक्रम के माध्यम से, आदिवासी लोगों को काम पर रखने में प्राथमिकता दी जाती है ताकि क्षेत्रीय सार्वजनिक सेवा में आदिवासी कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि हो सके।¹⁰⁸² इसके अलावा, नुनावुत भूमि दावा समझौते के तहत, संघीय और क्षेत्रीय सरकारें सरकारी पदों के लिए इनुइट को काम पर रखने और प्रशिक्षित करने का प्रयास करती हैं।¹⁰⁸³ कनाडा ने संघीय मानव संसाधन और कौशल विकास विभाग के तत्वावधान में आदिवासी कौशल और रोजगार साझेदारी और आदिवासी कौशल और रोजगार प्रशिक्षण रणनीति भी तैयार की है, जो आदिवासी लोगों और निजी नियोक्ताओं को आदिवासी कर्मचारियों के लिए तैयार करने, भर्ती करने और बनाए रखने में सहायता करती है।¹⁰⁸⁴

¹⁰⁷⁷ *R.v. Sioui*, 1SCR1025(1990), p.no.1026

¹⁰⁷⁸ Adrienne Davidson and Veldon Coburn, "Multiculturalism Policy Index: Indigenous Peoples", *Queen's University* (2021), p.no.19.

¹⁰⁷⁹ The Employment Equity Act, 1995, s.5.

¹⁰⁸⁰ Adrienne Davidson and Veldon Coburn, "Multiculturalism Policy Index: Indigenous Peoples", *Queen's University* (2021), p.no.22.

¹⁰⁸¹ *Ibid.*

¹⁰⁸² Yukon Public Service, *Breaking Trail Together - Strategic Plan 2019-2029*, available at: https://yukon.ca/sites/default/files/2025-04/psc_breaking-trail-together-strategic-plan-2019-29.pdf (last visited on Oct. 3, 2025).

¹⁰⁸³ Government of Canada Publication, *Nunavut Land Claim Agreement*, available at: <https://publications.gc.ca/collections/Collection/R32-134-1993E.pdf> (last visited on Oct. 6, 2025).

¹⁰⁸⁴ Government of Canada, *Evaluation of the Aboriginal Skills and Employment Training Strategy and the Skills and Partnership Fund*, available at: <https://www.canada.ca/en/employment-social->

3.2. संयुक्त राज्य अमेरिका

3.2.1. संवैधानिक और कानूनी मान्यता

संयुक्त राज्य अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका के स्वदेशी लोगों को कानूनी रूप से 'भारतीय' कहा जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान के अनुच्छेद 1 के साथ-साथ संविधान के चौदहवें संशोधन की धारा 2 में स्पष्ट रूप से 'भारतीयों' और 'भारतीय जनजातियों' का उल्लेख किया गया है।¹⁰⁸⁵ कई स्थानीय कानून भी समान या समान विरासत वाले लोगों को नामित करने के लिए 'जनजाति' या 'बैंड' शब्दों का उपयोग करते हैं, जो एक विशेष क्षेत्र में रहते हैं, और एक नेतृत्व के तहत एक समुदाय के रूप में एकजुट होते हैं।¹⁰⁸⁶ आज, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्वदेशी लोगों का वर्णन करने के लिए 'मूल निवासी समूह' वाक्यांश का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है।¹⁰⁸⁷ 'अलास्का मूल निवासी' और 'मूल हवाई निवासी' विशेष रूप से क्रमशः अलास्का और हवाई के क्षेत्रों के मूल निवासियों को संदर्भित करते हैं।¹⁰⁸⁸ हालांकि, संयुक्त राज्य अमेरिका में सभी मूल समूहों को आधिकारिक रूप से मान्यता प्राप्त नहीं है।¹⁰⁸⁹ जबकि संघीय सरकार ने कई मूल निवासियों के समूहों को अमेरिकी भारतीय या अलास्का मूल निवासियों के रूप में मान्यता दी है, मूल निवासियों को समान रूप से मान्यता नहीं दी गई है। संघीय रूप से मान्यता प्राप्त मूल निवासी समुदायों के अलावा, राज्य सरकारें कुछ अन्य मूल निवासी समुदायों को भी मान्यता दे सकती हैं।¹⁰⁹⁰ देशी समूहों की संघीय या राज्य मान्यता व्यक्तिगत जीवन और मामलों पर देशी सरकारी नियंत्रण की सीमा, किसी विशेष क्षेत्र पर देशी समूह किस हद तक राजनीतिक अधिकार का प्रयोग करता है और देशी समूह के इतिहास की निरंतरता जैसे कारकों पर निर्भर करती है।¹⁰⁹¹

संविधान का अनुच्छेद 1 स्पष्ट रूप से कांग्रेस को 'भारतीय जनजातियों' के साथ वाणिज्य को विनियमित करने की पूर्ण शक्ति प्रदान करता है।¹⁰⁹² संयुक्त राज्य अमेरिका बनाम एंटेलोप, ¹⁰⁹³ में संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया: "भारतीय जनजातियों को स्पष्ट रूप से कानून के विषयों के रूप में वर्गीकृत करने वाले वर्गीकरण संविधान में स्पष्ट रूप से प्रदान किए गए हैं और भारतीयों के साथ संघीय सरकार के संबंधों के इतिहास का भी समर्थन प्राप्त है।"¹⁰⁹⁴

देशी समूहों पर इस तरह की संवैधानिक रूप से स्वीकृत पूर्ण शक्ति का प्रयोग करते हुए,

[development/corporate/reports/evaluations/aboriginal-skills-employment-training-strategy-skills-partnership-fund.htm](https://www.development/corporate/reports/evaluations/aboriginal-skills-employment-training-strategy-skills-partnership-fund.htm) (last visited on Oct. 6, 2025).

¹⁰⁸⁵The Constitution of the United States, 1789, art. 1, s. 8; The Constitution of the United States (Fourth Amendment) 1979, s. 2.

¹⁰⁸⁶Legal Information Institute, "American Indian Law" Cornell Law School, available at: https://www.law.cornell.edu/wex/american_indian_law (last visited on Oct. 5, 2025).

¹⁰⁸⁷International Work Group for Indigenous Affairs, *The Indigenous World 2025* (39th edn., 2025), p. no. 528.

¹⁰⁸⁸Legal Information Institute, "American Indian Law" Cornell Law School, available at: https://www.law.cornell.edu/wex/american_indian_law (last visited on Oct. 5, 2025).

¹⁰⁸⁹International Work Group for Indigenous Affairs, *The Indigenous World 2025* (39th edn., 2025), p. no. 528.

¹⁰⁹⁰Legal Information Institute, "American Indian Law" Cornell Law School, available at: https://www.law.cornell.edu/wex/american_indian_law (last visited on Oct. 5, 2025).

¹⁰⁹¹*Ibid.*

¹⁰⁹²The Constitution, 1789, art. 1, s. 8.

¹⁰⁹³*United States v. Antelope*, 430 U.S. 641 (1977).

¹⁰⁹⁴Adrienne Davidson and Veldon Coburn, "Multiculturalism Policy Index: Indigenous Peoples", *Queen's University* (2021), p. no. 69.

कई संघीय कानून पारित किए गए हैं, जिनमें से पहला भारतीय गैर-संभोग अधिनियम, 1790 था, जिसने मूल राष्ट्रों के साथ संघियों को समाप्त करने के लिए संघीय सरकार की शक्ति की पुष्टि की, मूल निवासियों की भूमि के अंदर और बाहर 'भारतीयों और गैर-भारतीयों' के अधिकारों को परिभाषित किया, और "संयुक्त राज्य अमेरिका की मंजूरी के बिना" मूल निवासियों की भूमि की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया।¹⁰⁹⁵ फिर भी, यह केवल भारतीय नागरिकता अधिनियम, 1924 के पारित होने के बाद ही संयुक्त राज्य अमेरिका के इलाके में पैदा हुए मूल निवासियों को नागरिकों (उनके मूल राष्ट्रों की नागरिकता के अलावा) के रूप में मान्यता दी गई, जिन्हें विशेष सुरक्षा के अलावा अन्य नागरिकों के समान अधिकार और लाभ थे।¹⁰⁹⁶ संघीय, राज्य और स्थानीय चुनावों में मतदान करने के लिए मूल निवासियों के समूहों के अधिकारों की पुष्टि बहुत बाद में मतदान अधिकार अधिनियम, 1965 द्वारा वैधानिक रूप से की गई।¹⁰⁹⁷ आज, मूल निवासियों को सार्वजनिक पद पर चुने जाने का अधिकार है।¹⁰⁹⁸

3.2.2. आत्मनिर्णय, स्व-शासन, भागीदारी और परामर्श

सिद्धांत रूप में, संघीय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मूल निवासी समूहों या 'मूल निवासी राष्ट्रों' को संघीय और राज्य सरकारों से अलग, खुद पर स्वतंत्र रूप से शासन करने का अधिकार (संप्रभुता) प्राप्त है।¹⁰⁹⁹ चैरोकी नेशन बनाम जॉर्जिया में ऐतिहासिक निर्णय में, संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि मूल राष्ट्रों को "घरेलू आश्रित राष्ट्रों" के रूप में माना जाना चाहिए जिनके पास विशेषाधिकार और उन्मुक्ति है और "संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ जनजातियों का संबंध 'संरक्षित व्यक्ति और उसके संरक्षक' के समान है।¹¹⁰⁰ मूल निवासियों के समूहों पर संघीय सरकार का विश्वास या संरक्षकता की जिम्मेदारी संयुक्त राज्य अमेरिका और मूल निवासियों के समूहों द्वारा 1778 और 1871 के बीच संपन्न ऐतिहासिक संधियों से उपजी है, जिसके अनुसार मूल निवासियों के लिए कुछ सुरक्षा, लाभ और सेवाओं के साथ-साथ उनकी संप्रभुता के सम्मान के बदले में मूल निवासियों के समूहों ने अपनी स्वतंत्रता पर अपने पैतृक क्षेत्रों के बड़े हिस्से को संयुक्त राज्य अमेरिका को सौंप दिया।¹¹⁰¹ फिर भी, संयुक्त राज्य अमेरिका बनाम व्हीलर में, संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यूरोपीय लोगों के आने से पहले मूल निवासी समूह "स्व-शासित संप्रभु राजनीतिक समुदाय" थे और उन्होंने अपनी पूर्ण संप्रभुता को नहीं छोड़ा है।¹¹⁰²

तदनुसार, हालांकि मूल राष्ट्रों का संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ शासन-से-शासन संबंध है,¹¹⁰³ लेकिन उन्हें संघीय सरकार के वार्ड के रूप में भी देखा जाता है, इस वजह से

¹⁰⁹⁵ The Indian Non-Intercourse Act, 1790, s.4.

¹⁰⁹⁶ Angela Harmon, "Native American Rights" *Research Starters* (2024), available at: <https://www.ebsco.com/research-starters/politics-and-government/native-american-rights> (last visited on Oct. 5, 2025).

¹⁰⁹⁷ Voting Rights Act, 1965, s.2.

¹⁰⁹⁸ Library of Congress, *Native American Voting Rights, Voters and Elections*, available at: <https://www.loc.gov/classroom-materials/elections/voters/native-americans/> (last visited on Oct. 5, 2025).

¹⁰⁹⁹ *Ibid.*

¹¹⁰⁰ *Cherokee Nation v. Georgia*, 30 U.S. 1 (1831), p.no. 17.

¹¹⁰¹ Adrienne Davidson and Veldon Coburn, "Multiculturalism Policy Index: Indigenous Peoples", *Queen's University* (2021), p.no.65.

¹¹⁰² *Id.* at 68; *United States v. Wheeler* 435 U.S. 313 (1978), p.no.323-324.

¹¹⁰³ Adrienne Davidson and Veldon Coburn, "Multiculturalism Policy Index: Indigenous Peoples", *Queen's University*, (2021), p. nos. 65, 68.

उनकी संप्रभुता एक प्रबल संघीय शक्ति के अधीन है, जिसमें मूल समूहों के अधिकारों को सीमित करने, संशोधन करने या रद्द करने का अधिकार शामिल है। देशी समूहों के मामलों को विनियमित करने का संघीय सरकार का ऐसा अधिकार 'अनन्य' है; ¹¹⁰⁴ इस संबंध में राज्यों द्वारा अधिकार का प्रयोग देशी राष्ट्र पर लागू नहीं होता है। वर्सेस्टर बनाम जॉर्जिया में, संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया: "चेरोकी नेशन एक अलग समुदाय है जो अपने खुद के इलाके में रहता है... जहाँ जॉर्जिया के कानून लागू नहीं हो सकते, और जहाँ जॉर्जिया के नागरिकों को प्रवेश करने का कोई अधिकार नहीं है, सिवाय तब जब खुद चेरोकी लोगों की सहमति हो, या फिर संधियों और कांग्रेस के कानूनों के अनुसार ऐसा किया जाए। संयुक्त राज्य अमेरिका और इस समुदाय के बीच सभी तरह के संबंध, हमारे संविधान और कानूनों के तहत, अमेरिकी सरकार के अधिकार क्षेत्र में आते हैं।" ¹¹⁰⁵

संयुक्त राज्य अमेरिका बनाम मजूरी में, मूल निवासियों के संप्रभुता को स्वीकार करते हुए, संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय ने कहा: "भारतीय जनजातियाँ द्वितीय समूह हैं जो अपने सदस्यों और अपने क्षेत्र दोनों पर संप्रभुता के अधिकार हैं... 'भारतीय देश' के भीतर भारतीय जनजातियाँ 'निजी, स्वैच्छिक संगठनों' की तुलना से कहीं बढ़कर हैं।" ¹¹⁰⁶ इसी तरह, देशी संप्रभुता की प्रकृति के बारे में, संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय ने संयुक्त राज्य अमेरिका बनाम क्लैलर में स्पष्ट किया, "भारतीय जनजातियों की शक्तियाँ, सामान्य रूप से, एक सीमित संप्रभुता की वे अंतर्निहित शक्तियाँ हैं जो कभी समाप्त नहीं हुई हैं।" ¹¹⁰⁷ भारतीय पुनर्गठन अधिनियम, 1934 स्पष्ट रूप से देशी समूहों को उनके क्षेत्रों पर संप्रभुता और स्वशासन का अधिकार प्रदान करता है: "किसी भी एक ही आरक्षण पर रहने वाली भारतीय जनजाति, या जनजातियों, को अपने सामान्य कल्याण के लिए संगठित करने का अधिकार होगा।" ¹¹⁰⁸

भारतीय पुनर्गठन अधिनियम, 1934 के तहत मूल निवासी समुदायों के लिए यह ज़रूरी था वे अपने स्वयं के संविधानों (संघीय सरकार के अनुमोदन के अधीन) को अपनाएँ और उन्हें अनुसमर्थन दें, इस प्रकार देशी सरकारों की नींव रखी गई। ¹¹⁰⁹ देशी सरकारें देशी समूहों द्वारा अलग-अलग चुनावों के माध्यम से चुनी जाती हैं, जिन्हें देशी मामलों के विनियमन का काम सौंपा जाता है, और वे संघीय निरीक्षण के तहत काम करती हैं। ¹¹¹⁰ देशी सरकारों को कानून लागू करने, कर लगाने और एकत्र करने, देशी नागरिकता निर्धारित करने और विभिन्न अन्य गतिविधियों को विनियमित करने का अधिकार है, लेकिन मुद्रा छापने, युद्ध की घोषणा करने या विदेशी मामलों में शामिल होने का अधिकार नहीं है। ¹¹¹¹ भारतीय आत्मनिर्णय और शिक्षा सहायता अधिनियम, 1975 ने मूल निवासियों को लक्षित करने वाले

¹¹⁰⁴ Gregory Ablavsky, "Beyond the Indian Commerce Clause" 124 *The Yale Law Journal* 882 (2015).

¹¹⁰⁵ *Worcester v. Georgia*, 31 U.S. 515 (1832), p.no. 31.

¹¹⁰⁶ *United States v. Mazurie*, 419 U.S. 544 (1975), p.no. 557; Adrienne Davidson and Veldon Coburn, "Multiculturalism Policy Index: Indigenous Peoples", *Queen's University* (2021), p.no. 65.

¹¹⁰⁷ Adrienne Davidson and Veldon Coburn, "Multiculturalism Policy Index: Indigenous Peoples", *Queen's University*, (2021), p.no. 65; *United States v. Wheeler*, 435 U.S. 313 (1978), p.no. 322.

¹¹⁰⁸ Adrienne Davidson and Veldon Coburn, "Multiculturalism Policy Index: Indigenous Peoples", *Queen's University*, (2021), p.no. 65; *The Indian Reorganisation Act, 1934*, s.17(h)(1).

¹¹⁰⁹ *The Indian Reorganisation Act, 1934*, s.16(a).

¹¹¹⁰ *Id.* s.16.

¹¹¹¹ Adrienne Davidson and Veldon Coburn, "Multiculturalism Policy Index: Indigenous Peoples", *Queen's University* (2021), p.nos. 64, 65.

संघीय कल्याण कार्यक्रमों के प्रशासन में मूल निवासियों की भागीदारी को बढ़ावा दिया।¹¹¹² बाद में, जनजातीय स्वशासन अधिनियम, 1994 के अधिनियमन के साथ, भारतीय मामलों के 'ब्यूरो ऑफ़ इंडियन अफेयर्स' ने नीति निर्माण और प्रशासन की जिम्मेदारी मूल सरकारों को सौंप दी।¹¹¹³

देशी समूहों को 2000 के कार्यकारी आदेश 13175 के माध्यम से संघीय सरकार द्वारा परामर्श किए जाने के अधिकार की गारंटी दी गई है, जो "जनजातीय प्रभाव वाली संघीय नीतियों के विकास में जनजातीय अधिकारियों के साथ नियमित और सार्थक परामर्श और सहयोग का निर्देश देता है, ताकि भारतीय जनजातियों के साथ संयुक्त राज्य शासन-से-शासन के संबंधों को मजबूत किया जा सके, और भारतीय जनजातियों पर बिना धन के जनादेश के अधिरोपण को कम किया जा सके।"¹¹¹⁴ परामर्श की आवश्यकता विशिष्ट संघीय विधान में भी अंतर्निहित है, जैसे कि राष्ट्रीय ऐतिहासिक संरक्षण अधिनियम, 1996, जो किसी भी उपक्रम पर मूल निवासियों के साथ परामर्श को अनिवार्य करता है जो उनके लिए सांस्कृतिक या धार्मिक महत्व के साथ ऐतिहासिक संपत्तियों को प्रभावित कर सकता है।¹¹¹⁵ इसके अलावा, जनजातीय कानून और व्यवस्था अधिनियम, 2010, भारतीय मामलों के ब्यूरो और न्याय सेवा कार्यालय से उन विनियामक नीतियों के विकास में देशी समूहों के साथ परामर्श के लिए नीतियां, प्रक्रियाएं और दिशानिर्देश तैयार करने की अपेक्षा करता है जो उन्हें प्रभावित करते हैं। 2013 में, ऐतिहासिक संरक्षण पर सलाहकार परिषद ने अपने कार्यक्रमों, नीतियों और पहलों में एफपीआईसी की आवश्यकता को शामिल करने के लिए कदम उठाए।¹¹¹⁶

3.2.3. क्षेत्रों, वन और प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग और पैतृक भूमि पर स्वामित्व

वॉर्सेस्टर बनाम जॉर्जिया में, संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय ने कहा: "संयुक्त राज्य अमेरिका की संधियाँ और कानून भारतीय क्षेत्र को राज्यों के क्षेत्र से पूरी तरह से अलग मानते हैं।"¹¹¹⁷ चूंकि कई मूल निवासियों के समूहों ने ऐतिहासिक संधियों के तहत अपने पैतृक क्षेत्रों को संयुक्त राज्य अमेरिका को सौंप दिया था, इसलिए भारतीय पुनर्गठन अधिनियम, 1934 में घोषणा की गई है कि मूल निवासियों की भूमि संघीय सरकार द्वारा मूल निवासियों के विश्वास में रखी गई है।¹¹¹⁸ यद्यपि भारतीय पुनर्गठन अधिनियम, 1934 ने उनके पैतृक क्षेत्रों के लिए संघीय रूप से मान्यता प्राप्त जनजातियों के खिताब को मान्यता दी, जैसे कि उनकी मूल भूमि को एकतरफा रूप से जब्त नहीं किया जा सकता है, पारंपरिक रूप से अन्य मूल समूहों द्वारा कब्जा किए गए पैतृक क्षेत्रों (संघीय मान्यता नहीं रखने वाले) को संघीय सरकार द्वारा जब्त किए बिना जब्त किया जा सकता है।¹¹¹⁹ भारतीय पुनर्गठन अधिनियम, 1934, आगे यह निर्धारित करता है कि मूल भूमि को केवल संयुक्त राज्य अमेरिका से अलग

¹¹¹²Id.at65.

¹¹¹³Id.at66.

¹¹¹⁴Executive Order 13175—Consultation and Coordination with Indian Tribal Government, 2000, preamble.

¹¹¹⁵The National Historic Preservation Act, 1996, s.106

¹¹¹⁶United Nations General Assembly, Report of the Special Rapporteur on the rights of indigenous peoples on her mission to the United States of America, UN Doc A/HRC/36/46/Add.1 (Aug. 9, 2017), para. 22.

¹¹¹⁷Worcester v. Georgia, 31 U.S. 515 (1832).

¹¹¹⁸Howard University, "A Brief History of Civil Rights in the United States: The Self-Government Era (1934-1953)" Vernon E. Jordan Law Library (Jan. 6, 2023), available at: <https://library.law.howard.edu/civilrightshistory> (last visited on Oct. 7, 2025).

¹¹¹⁹Vine Deloria, The Indian Reorganization Act: Congress and Bills (University of Oklahoma Press, 2002).

किया जा सकता है।¹¹²⁰

मूल निवासियों को जल और जलमार्गों के उपयोग के अंतर्निहित अधिकार के साथ-साथ मूल भूमि के भीतर धाराओं, नदियों और अन्य जल स्रोतों के संरक्षण का भी अधिकार है, जैसा कि संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा *विटर्स बनाम संयुक्त राज्य अमेरिका* में पुष्टि की गई है।¹¹²¹ इसके अलावा, स्वच्छ जल अधिनियम, 1972 के तहत, देशी समूहों को अपने जल संसाधनों (राज्यों के समान) को विनियमित करने का अधिकार है और अपस्ट्रीम उपयोगकर्ताओं को अपने स्वयं के मानकों के अधीन कर सकते हैं, बशर्ते कि ऐसे मानकों को पर्यावरण संरक्षण एजेंसी द्वारा अनुमोदित किया गया हो।¹¹²² भारतीय दावा आयोग, जिसकी स्थापना 1946 में हुई थी और बाद में 1970 में यूएस कोर्ट ऑफ क्लेम द्वारा प्रतिस्थापित किया गया, ने देशी भूमि दावों पर निर्णय लिया। हालांकि, जहां एक दावा सफल रहा, भारतीय दावा आयोग को केवल भूमि स्वामित्व के बदले मौद्रिक मुआवजा देने के लिए अधिकृत किया गया था, लेकिन भूमि अधिकारों को बहाल करने का अधिकार नहीं था।¹¹²³

भारतीय खनिज पट्टा अधिनियम, 1938 सहित संघीय विधान द्वारा देशी समूहों के भूमि अधिकारों पर भी प्रतिबंध लगाए गए हैं, जिसमें यह प्रावधान है कि "किसी भी भारतीय आरक्षण के भीतर गैर-आवंटित भूमि या संघीय अधिकार क्षेत्र के तहत किसी भी जनजाति, समूह या भारतीयों के समूह के स्वामित्व वाली भूमि... आंतरिक सचिव के अनुमोदन से खनन उद्देश्यों के लिए पट्टे पर दी जा सकती है।"¹¹²⁴ बाद के भारतीय खनिज विकास अधिनियम, 1982 ने मूल निवासियों के समूहों को अपने पैतृक क्षेत्रों में होने वाले खनिजों के दोहन के लिए संयुक्त उद्यम समझौतों (संघीय अनुमोदन के अधीन) को समाप्त करने में सक्षम बनाकर मूल निवासियों की भूमि पर प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन में अधिक स्वायत्तता प्रदान की।¹¹²⁵ ऊर्जा नीति अधिनियम, 2005, देशी समूहों को अपने पैतृक क्षेत्रों पर मार्ग का अधिकार प्रदान करने वाले समझौतों (संघीय अनुमोदन के अधीन) में प्रवेश करके मूल भूमि पर ऊर्जा विकास में स्वायत्तता का प्रयोग करने के लिए अधिकृत करता है।¹¹²⁶ हालांकि, *हेल्पिंग एक्सपीडाइट एंड एडवांस रिस्पॉन्सिबल ट्राइबल होम ओनरशिप एक्ट*, 2012 के तहत, मूल सरकारों को संघीय अनुमोदन के बिना, अपने स्वयं के मूल नियमों के अनुसार मूल भूमि के पट्टे देने का अधिकार दिया गया है।¹¹²⁷

3.2.4. संस्कृति और परंपराओं का संरक्षण

कई संघीय और राज्य विधान और अन्य साधन मूल निवासियों के धार्मिक, सांस्कृतिक और भाषाई अधिकारों को संरक्षण प्रदान करते हैं। राष्ट्रीय ऐतिहासिक संरक्षण अधिनियम, 1966

¹¹²⁰ Adrienne Davidson and Veldon Coburn, "Multiculturalism Policy Index: Indigenous Peoples", *Queen's University* (2021), p.no.65.

¹¹²¹ *Ibid.*

¹¹²² *Ibid.*

¹¹²³ *Id.* at 64.

¹¹²⁴ The Indian Mineral Leasing Act, 1938, s.396a.

¹¹²⁵ United Nations General Assembly, *Report of the Special Rapporteur on the rights of indigenous peoples on her mission to the United States of America*, UN Doc A/HRC/36/46/Add.1 (Aug.9, 2017), para.16.

¹¹²⁶ *Id.* at para.17.

¹¹²⁷ *Id.* at para.18.

मूल निवासियों के धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों की सुरक्षा करता है।¹¹²⁸ नेटिव अमेरिकन ग्रेव्स प्रोटेक्शन एंड रिपेट्रिएशन एक्ट, 1990 देशी पैतृक अवशेषों और पवित्र कलाकृतियों के संरक्षण और प्रत्यावर्तन की गारंटी देता है।¹¹²⁹ भारतीय नागरिक अधिकार अधिनियम, 1968 देशी समूहों को स्वतंत्र रूप से अपने धर्म की स्थापना और प्रयोग करने के अधिकार की गारंटी देता है। हालाँकि,¹¹³⁰ स्थानीय सरकारों को मूल निवासियों को किसी विशेष धर्म का पालन करने के लिए मजबूर करने या उनकी धार्मिक मान्यताओं के लिए उन्हें दंडित करने से प्रतिबंधित किया गया है।¹¹³¹ संयुक्त राज्य अमेरिका ने कई वैधानिक और नीतिगत उपायों को भी अपनाया है "अमेरिकी भारतीयों के लिए अमेरिकी भारतीय, एस्किमो, अलेउत और मूल हवाई लोगों के पारंपरिक धर्मों में विश्वास करने, व्यक्त करने और अभ्यास करने के स्वतंत्रता के उनके अंतर्निहित अधिकार की रक्षा और संरक्षण किया गया है, इसमें पवित्र स्थलों तक पहुंच, पवित्र वस्तुओं का उपयोग और कब्जा, और समारोहों और पारंपरिक संस्कारों के माध्यम से पूजा करने की स्वतंत्रता तक सीमित नहीं है।"¹¹³² तदनुसार, संघीय रूप से मान्यता प्राप्त देशी समूहों को प्रवासी पक्षी संधि अधिनियम, 1918 के तहत बाज़ के पंख रखने के कानूनी अभियोजन से छूट दी गई है।¹¹³³ इसी तरह के अपवाद स्थानीय धार्मिक और सांस्कृतिक उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाने वाले चील और चील के हिस्सों को लेने के लिए बनाए गए हैं।¹¹³⁴

देशी समूहों को भी अपने पैतृक क्षेत्रों में शिकार करने और मछली पकड़ने का पारंपरिक अधिकार है, जब तक कि इस तरह के अधिकारों को संघीय सरकार द्वारा स्पष्ट रूप से सीमित नहीं किया गया हो या मूल समूहों द्वारा स्वयं स्पष्ट रूप से त्याग नहीं किया गया हो।¹¹³⁵ मूल भूमि के भीतर, मूल सरकारें शिकार और मछली पकड़ने पर विशेष अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करती हैं, हालाँकि, संघीय संरक्षण नियमों के अधीन आता है। राज्य सरकारों को अपनी मूल भूमि के भीतर इस संबंध में मूल निवासियों के समूहों को विनियमित करने का अधिकार नहीं है।¹¹³⁶ स्थानीय समूहों को संधियों, कानूनों और अंतर-सरकारी समझौतों के माध्यम से सार्वजनिक वन भूमि (लेकिन निजी, विकसित या खेती की भूमि नहीं) पर शिकार, मछली पकड़ने और फंसाने के लिए अतिरिक्त रूप से अधिकृत किया गया है।¹¹³⁷ उदाहरण के लिए, नवाजो संधि मूल निवासियों को सैन जुआन काउंटी में खाली जमीन पर शिकार करने की अनुमति देती है।¹¹³⁸

नेटिव अमेरिकन लैंग्वेज एक्ट, 1990, नेटिव भाषाओं की रक्षा करता है: "कांग्रेस ने पाया कि नेटिव अमेरिकन्स की संस्कृतियों और भाषाओं की स्थिति अद्वितीय है और संयुक्त राज्य अमेरिका की

¹¹²⁸ Adrienne Davidson and Veldon Coburn, "Multiculturalism Policy Index: Indigenous Peoples", *Queen's University* (2021), p. no. 67; The National Historic Preservation Act, 1966, § 300101.

¹¹²⁹ Howard University, "A Brief History of Civil Rights in the United States: The Self-Government Era (1934-1953)" (Jan. 6, 2023), available at: <https://library.law.howard.edu/civilrightshistory> (last visited on Oct. 7, 2025); The Native American Graves Protection and Repatriation Act, 1990, §§ 3002, 3005.

¹¹³⁰ Adrienne Davidson and Veldon Coburn, "Multiculturalism Policy Index: Indigenous Peoples", *Queen's University* (2021), p. no. 67; The Indian Civil Rights Act, 1968, s. 1302(a)(1).

¹¹³¹ Adrienne Davidson and Veldon Coburn, "Multiculturalism Policy Index: Indigenous Peoples", *Queen's University* (2021), p. no. 67.

¹¹³² 95th Congress, Joint Resolution, *American Indian Religious Freedom*, Public Law 95-341 (Aug. 11, 1978), p. no. 1.

¹¹³³ Adrienne Davidson and Veldon Coburn, "Multiculturalism Policy Index: Indigenous Peoples", *Queen's University* (2021), p. no. 67.

¹¹³⁴ *Ibid.*

¹¹³⁵ *Ibid.*

¹¹³⁶ *Ibid.*

¹¹³⁷ *Ibid.*

¹¹³⁸ Treaty with the Navajo, 1868, art. 9.

जिम्मेदारी है कि वह इन अनूठी संस्कृतियों और भाषाओं के अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए नेटिव अमेरिकन्स के साथ मिलकर काम करे।” ¹¹³⁹

3.2.5. प्रथागत कानून और कानूनी प्रणालियाँ

भारतीय जनजातीय न्याय अधिनियम, 1993 ने यह दोहराते हुए कि "भारतीय जनजातियों की संस्कृति और पहचान को बनाए रखने के लिए पारंपरिक जनजातीय न्यायिक प्रथाएं आवश्यक हैं", मूल निवासियों के कानूनों को मान्यता प्रदान की और मूल निवासियों के समूहों के लिए विशेष रूप से अद्वितीय न्याय प्रणालियों के अनुसार उनके मामलों से संबंधित कुछ मामलों पर निर्णय लेने के लिए मूल निवासियों के न्यायालयों के अधिकार की पुष्टि की।¹¹⁴⁰ संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय ने 1883 में, एक्स पार्टें क्रो डॉग मामले में ऐतिहासिक निर्णय में, सामान्य अपराध अधिनियम, 1834 पर भरोसा करते हुए फैसला सुनाया कि संघीय सरकार को अपने मूल क्षेत्रों के भीतर मूल निवासियों द्वारा किए गए अपराधों पर अधिकार क्षेत्र नहीं है।¹¹⁴¹

हालांकि, प्रमुख अपराध अधिनियम, 1885 के अधिनियमन के साथ, स्थानीय अदालतों को अब अपने मूल निवासियों के बीच उनके मूल मानदंडों, रीति-रिवाजों या प्रथाओं के आधार पर किए गए हिंसक अपराधों (हत्या, बलात्कार, अपहरण, हत्या, हत्या, बलात्कार, हत्या के इरादे से हमला, आगजनी, चोरी और लूटपाट) पर मुकदमा चलाने का अधिकार नहीं था; इसके बजाय, ऐसे अपराध संघीय अदालतों के एकमात्र अधिकार क्षेत्र के अधीन थे, जिसमें राज्य का अधिकार क्षेत्र शामिल नहीं था।¹¹⁴² ओक्लाहोमा में स्थित क्रीक नेशन क्षेत्र के भीतर एक बच्चे के खिलाफ किए गए यौन अपराधों के लिए एक क्रीक नेशन व्यक्ति की सजा के संबंध में मैकगर्ट बनाम ओक्लाहोमा में संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा हाल ही में इस बात की पुष्टि की गई थी: "जब कांग्रेस ने [प्रमुख अपराध अधिनियम] को अपनाया, तो इसने कई संधिवादों को तोड़ दिया, जिन्होंने एक बार क्रीक जैसी जनजातियों को अपने सदस्यों पर मुकदमा चलाने की अनुमति दी थी। लेकिन, बदले में, कांग्रेस ने राज्यों को अनुमति न देकर केवल संघीय सरकार को, बड़े अपराधों के लिए आदिवासी सदस्यों पर पर मुकदमा चलाने की अनुमति दी।¹¹⁴³ हालांकि, संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय के एक बाद के निर्णय ओक्लाहोमा बनाम कास्त्रो-हुर्ता¹¹⁴⁴ ने स्पष्ट किया कि जब मूल भूमि पर एक मूल निवासी पीड़ित के खिलाफ एक गैर-मूल निवासी व्यक्ति द्वारा अपराध किए जाते हैं, तो संघीय और राज्य दोनों सरकारों के पास ऐसे अपराधों पर मुकदमा चलाने के लिए समवर्ती अधिकार क्षेत्र होता है।¹¹⁴⁵

आम तौर पर, स्थानीय न्यायालय मूल निवासी व्यक्तियों पर अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने के हकदार नहीं हैं, जैसा

¹¹³⁹ Adrienne Davidson and Veldon Coburn, "Multiculturalism Policy Index: Indigenous Peoples", *Queen's University* (2021), p.no.67; Native American Language Act, 1990, s.102(1).

¹¹⁴⁰ The Indian Tribal Justice Act, 1993, s.2(7).

¹¹⁴¹ HeinOnline Blogger, "Court Cases Involving Indigenous Rights in U.S. History" *HeinOnline Blog* (Nov.13, 2024); *Ex Parte Crow Dog*, 109 U.S. 556 (1883), p.no.561.

¹¹⁴² Howard University, "A Brief History of Civil Rights in the United States: The Self-Government Era (1934-1953)" *Vernon E. Jordan Law Library* (Jan.6, 2023), available at: <https://library.law.howard.edu/civilrightshistory> (last visited on Oct. 7, 2025).

¹¹⁴³ Martha F. Davis, "American Indians and Indigenous Peoples in State Constitutions" *State Court Report* (Aug.5, 2025); *McGirt v. Oklahoma*, No.18-9526 (2020), p.no.38.

¹¹⁴⁴ *Oklahoma v. Castro-Huerta*, No.21-429 (2022).

¹¹⁴⁵ Martha F. Davis, "American Indians and Indigenous Peoples in State Constitutions" *State Court Report* (Aug.5, 2025).

कि संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ओलिफैंट बनाम सुकामिश भारतीय जनजाति में फैसला सुनाया गया है।¹¹⁴⁶ हालांकि, महिलाओं के खिलाफ हिंसा प्राधिकरण अधिनियम, 2013 के अधिनियमन के साथ, स्थानीय अदालतों को महिलाओं के खिलाफ किए गए अहिंसक अपराधों के लिए गैर-मूल निवासी व्यक्तियों पर मुकदमा चलाने का अधिकार दिया गया है।¹¹⁴⁷ बाद में महिलाओं के खिलाफ हिंसा प्राधिकरण अधिनियम, 2022 ने गैर-मूल निवासी व्यक्तियों द्वारा किए गए अन्य अपराधों, जैसे कि स्थानीय पुलिस अधिकारियों का पीछा करना और उन पर हमला करना, को शामिल करने के लिए देशी अदालतों के अधिकार क्षेत्र का विस्तार किया।¹¹⁴⁸ सिविल मामलों में, विलियम्स बनाम ली में, संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय ने निर्धारित किया कि राज्य मूल निवासियों के खिलाफ गैर-मूल निवासियों द्वारा की गई कार्रवाइयों के संबंध में मूल निवासियों के भीतर अधिकार क्षेत्र का प्रयोग नहीं कर सकते हैं; ऐसे विवाद मूल निवासियों की अदालतों के अनन्य अधिकार क्षेत्र के भीतर हैं, जिन्हें केवल संघीय सरकार द्वारा प्रतिबंधित किया जा सकता है।¹¹⁴⁹

4. दक्षिण अमेरिकी देश

4.1. इक्वाडोर

4.1.1. संवैधानिक और कानूनी मान्यता

इक्वाडोर में आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त 18 आदिवासी समुदाय और 14 राष्ट्र हैं।¹¹⁵⁰ संविधान इक्वाडोर को एक बहुराष्ट्रीय और अंतर सांस्कृतिक राज्य के रूप में वर्णित करता है, जो विभिन्न राष्ट्रों और समुदायों से बना है।¹¹⁵¹ संविधान स्वदेशी लोगों पर इक्वाडोर की राष्ट्रीयता निहित करता है, स्वदेशी राष्ट्रों से उनकी संबद्धता की परवाह किए बिना,¹¹⁵² स्वदेशी लोगों को इक्वाडोर का एक अभिन्न अंग मानता है,¹¹⁵³ उनके व्यक्तिगत और सामूहिक अधिकारों की रक्षा करता है,¹¹⁵⁴ और सभी सार्वजनिक कार्यों के लिए 'सुमक कवासय' (आदिवासी दर्शन - 'जीवन जीने का अच्छा तरीका') को मूल उद्देश्य के रूप में स्थापित करता है।¹¹⁵⁵ संविधान इक्वाडोर द्वारा मंजूर किए गए अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कानूनों को देश के भीतर सीधे

¹¹⁴⁶ *Oliphant v. Suquamish Indian Tribe*, 435 U.S. 191 (1978).

¹¹⁴⁷ Howard University, "A Brief History of Civil Rights in the United States: The Self-Government Era (1934-1953)" *Vernon E. Jordan Law Library* (Jan. 6, 2023), available at <https://library.law.howard.edu/civilrightshistory> (last visited on Oct. 7, 2025); Violence Against Women Reauthorization Act, 2013, s. 204(b)(1).

¹¹⁴⁸ Howard University, "A Brief History of Civil Rights in the United States: The Self-Government Era (1934-1953)" *Vernon E. Jordan Law Library* (Jan. 6, 2023), available at <https://library.law.howard.edu/civilrightshistory> (last visited on Oct. 7, 2025).

¹¹⁴⁹ *Williams v. Lee*, 358 U.S. 217 (1959), p. no. 358.

¹¹⁵⁰ United Nations General Assembly, Human Rights Council, *Visit to Ecuador, Report of the Special Rapporteur on the Rights of Indigenous Peoples*, UN Doc A/HRC/42/37/(Jul. 4, 2019) para. 7.

¹¹⁵¹ *Id.* at para. 16.

¹¹⁵² The Constitution of Ecuador, 2008, art. 6.

¹¹⁵³ *Id.* art. 3.8.

¹¹⁵⁴ *Id.* arts. 34, 343, 358.

¹¹⁵⁵ *Id.* preamble.

¹¹⁵⁶ *Id.* arts. 14, 250, 275, 387.

लागू करने की व्यवस्था भी करता है।¹¹⁵⁷

4.1.2. आत्मनिर्णय, स्व-शासन, भागीदारी और परामर्श

संविधान, विशेष रूप से, स्वदेशी लोगों को एक विकेंद्रीकृत मॉडल का पालन करते हुए, स्वदेशी क्षेत्रीय सरकारों द्वारा प्रशासित होने के लिए क्षेत्रीय जिलों का निर्माण करने के लिए अधिकृत करता है ताकि उनकी संस्कृति को संरक्षित किया जा सके।¹¹⁵⁸ प्रादेशिक संगठन, स्वायत्तता और विकेंद्रीकरण पर जैविक संहिता, 2010, इन स्वदेशी जिलों के निर्माण को नियंत्रित करने वाले नियमों को निर्धारित करती है।¹¹⁵⁹ यह स्वदेशी लोगों के साथ पिछले संविधान के व्यवहार के बिल्कुल विपरीत है, जिसमें कहा गया था: "उनकी संविधान सभा इस निर्दोष, नीच और दयनीय वर्ग के पक्ष में अपने दान मंत्रालय को प्रोत्साहित करके आदरणीय पादरी पुजारियों को मूल निवासियों के संरक्षक और स्वाभाविक माता-पिता के रूप में नियुक्त करती है।"¹¹⁶⁰

संविधान में दिए गए अधिकारों को लागू करने के लिए 'समानता परिषद अधिनियम, 2014'¹¹⁶¹ के तहत समानता परिषदें बनाई गईं।¹¹⁶² 2016 में बनाई गई 'लोगों और राष्ट्रों की समानता के लिए राष्ट्रीय परिषद' इक्वाडोर में निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में मूल निवासियों का प्रतिनिधित्व करती है; हालाँकि, इसमें स्वदेशी लोगों के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व के लिए कोई तंत्र नहीं है, इस प्रकार इसकी स्वायत्तता सीमित हो जाती है।¹¹⁶³ संविधान, फिर भी, स्वदेशी लोगों के सामाजिक संगठन और उनके प्राधिकरणों के तरीकों को संरक्षित करने और विकसित करने के अधिकार को मान्यता देता है;¹¹⁶⁴ लेकिन स्वदेशी लोगों के कानूनों, बोर्डों और शासी परिषदों को एक नागरिक समाज संगठन के रूप में उसी तरह से पंजीकृत किया जाना आवश्यक है ताकि राज्य एजेंसियों द्वारा वैध प्राधिकरणों के रूप में स्वीकार किया जा सके,¹¹⁶⁵ जिससे स्वदेशी लोगों के स्वायत्तता और स्व-शासन के अधिकार को और सीमित हो जाते हैं। फिर भी, स्वायत्त संस्थान जैसे इक्वाडोर के राष्ट्रों और लोगों की उन्नति के लिए परिषद, स्वदेशी राष्ट्रों और इक्वाडोर के लोगों के लिए विकास कोष और अंतर सांस्कृतिक स्वास्थ्य के लिए राष्ट्रीय निदेशालय स्वदेशी संगठनों द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं।¹¹⁶⁶

संविधान स्वदेशी लोगों को गैर-नवीकरणीय संसाधन परियोजनाओं के संदर्भ में स्वतंत्र, पूर्व और

¹¹⁵⁷*Id.* art. 417.

¹¹⁵⁸*Id.* art. 60; United Nations General Assembly, Human Rights Council, *Visit to Ecuador, Report of the Special Rapporteur on the Rights of Indigenous Peoples*, UN Doc A/HRC/42/37 (Jul. 4, 2019), para. 23.

¹¹⁵⁹ United Nations General Assembly, Human Rights Council, *Visit to Ecuador, Report of the Special Rapporteur on the Rights of Indigenous Peoples*, UN Doc A/HRC/42/37 (Jul. 4, 2019), para. 23.

¹¹⁶⁰ The Constitution, 1830, art. 68.

¹¹⁶¹ The Constitution, 2008, arts. 156, 157.

¹¹⁶² United Nations General Assembly, Human Rights Council, *Visit to Ecuador, Report of the Special Rapporteur on the Rights of Indigenous Peoples*, UN Doc A/HRC/42/37 (Jul. 4, 2019), para. 18.

¹¹⁶³ *Ibid.*

¹¹⁶⁴ The Constitution, 2008, arts. 57.1, 57.9

¹¹⁶⁵ United Nations General Assembly, Human Rights Council, *Visit to Ecuador, Report of the Special Rapporteur on the Rights of Indigenous Peoples*, UN Doc A/HRC/42/37 (Jul. 4, 2019), para. 44.

¹¹⁶⁶ *Id.* at para. 8.

पूर्व और सूचित परामर्श (लेकिन सहमति नहीं) के सामूहिक अधिकारों की गारंटी देता है, और कानूनों के अधिनियमन से पहले पूर्व-विधायी परामर्श की गारंटी देता है जो उनके सामूहिक अधिकारों पर प्रभाव डाल सकते हैं।¹¹⁶⁷ सिनांगो समुदाय के ऐ कोफान स्वदेशी लोगों के पैतृक क्षेत्रों पर खनन रियायतों के प्रभाव को स्वीकार करते हुए, इक्वाडोर के संवैधानिक न्यायालय ने ए 'आई कोफान मामले में फैसला सुनाया: "मामला गंभीर है क्योंकि खनन गतिविधि, यदि पर्याप्त रूप से परामर्श, सूचित, योजनाबद्ध और निष्पादित नहीं की जाती है, तो उनके पैतृक क्षेत्रों को प्रभावित कर सकती है, क्योंकि यह उनके जीवन के तरीकों में एक क्रांतिकारी परिवर्तन को प्रेरित करेगा और प्रकृति, जल, पर्यावरण, संस्कृति, क्षेत्र और स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा करेगा।"¹¹⁶⁸ संवैधानिक न्यायालय ने आगे कहा: "पूर्व परामर्श का दायित्व केवल उन योजनाओं या परियोजनाओं के लिए नहीं है जो स्वदेशी समुदायों या लोगों की भूमि के भीतर स्थित हैं... बल्कि उन लोगों के लिए भी है जो, भले ही वे अपनी भूमि पर नहीं हैं, उन्हें सीधे पर्यावरणीय या सांस्कृतिक रूप से प्रभावित कर सकते हैं क्योंकि वे अपने प्रभाव क्षेत्र के भीतर हैं... किसी भी परिस्थिति में ऐसी परियोजना नहीं की जा सकती है जिसके परिणामस्वरूप समुदायों और प्रकृति के सामूहिक अधिकारों के लिए अत्यधिक दोहन हो।"¹¹⁶⁹

4.1.3. पैतृक भूमि का स्वामित्व

संविधान स्वदेशी लोगों को सांप्रदायिक भूमि पर स्थायी स्वामित्व का अधिकार भी प्रदान करता है, जो अविभाज्य, गैर-अभिग्रहण और अविभाज्य (और शुल्क और करों से मुक्त) होने के साथ-साथ पैतृक भूमि पर कब्जा बनाए रखने और स्वामित्व रखने का अधिकार है।¹¹⁷⁰ संविधान स्वदेशी लोगों के अपनी भूमि पर मौजूद नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग, आनंद, प्रशासन और संरक्षण में भाग लेने के अधिकारों की भी रक्षा करता है।¹¹⁷¹ हालांकि, राज्य के पास गैर-नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधनों का अनन्य स्वामित्व है,¹¹⁷² और संरक्षित क्षेत्रों में शामिल भूमि और क्षेत्रों पर नियंत्रण रखता है।¹¹⁷³ फिर भी, संविधान स्वदेशी लोगों के अपनी पैतृक भूमि से विस्थापित नहीं होने के अधिकार और क्षेत्रीय संगठन के पैतृक रूप में सामुदायिक इकाई के सामूहिक स्वामित्व की रक्षा करता है।¹¹⁷⁴ ग्रामीण भूमि और पैतृक क्षेत्रों पर जैविक अधिनियम, 2016 और उसके विनियम ग्रामीण संपत्तियों और पैतृक क्षेत्रों

¹¹⁶⁷The Constitution, 2008, art. 57.7.

¹¹⁶⁸A'ICofán Community of Sinangoe v. Ministerio of Energy and Non-Renewable Natural Resources, No. 273-19-JP/22 (2022).

¹¹⁶⁹Amnesty International, Ecuador: Constitutional Court Ruling to Protect Indigenous Peoples from Mining Projects Affecting Their Human Rights (Feb. 10, 2022).

¹¹⁷⁰The Constitution, 2008, arts. 57.4, 57.5; United Nations General Assembly, Human Rights Council, Visit to Ecuador, Report of the Special Rapporteur on the Rights of Indigenous Peoples, UN Doc A/HRC/42/37 (Jul. 4, 2019), para. 21.

¹¹⁷¹The Constitution, 2008, art. 57.6; United Nations General Assembly, Human Rights Council, Visit to Ecuador, Report of the Special Rapporteur on the Rights of Indigenous Peoples, UN Doc A/HRC/42/37 (Jul. 4, 2019), para. 21.

¹¹⁷²United Nations General Assembly, Human Rights Council, Visit to Ecuador, Report of the Special Rapporteur on the Rights of Indigenous Peoples, UN Doc A/HRC/42/37 (Jul. 4, 2019), para. 24.

¹¹⁷³The Constitution, 2008, art. 261.7.

¹¹⁷⁴Id. arts. 42, 57.11.

कानूनी मान्यता दिलाने की प्रक्रिया तय करते हैं, लेकिन इन्हें मूल निवासियों से परामर्श किए बिना ही लागू किया गया था।¹¹⁷⁵

4.1.4. संस्कृति और परंपराओं का संरक्षण

विशेष रूप से, संविधान प्रकृति के विशिष्ट अधिकारों (पाचा मामा या धरती माता) को कानूनी व्यक्तित्व के साथ एक जीवित विषय के रूप में मान्यता देता है, ¹¹⁷⁶ इस प्रकार स्वदेशी लोगों को अपने सांस्कृतिक या धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण पैतृक क्षेत्रों को निकालने, औद्योगिक या अवसंरचनात्मक परियोजनाओं के परिणामस्वरूप शोषण या विनाश से बचाने के लिए एक अतिरिक्त कानूनी आधार प्रदान करता है। इक्वाडोर ने हाल ही में पर्यावरण कानून के अनुपालन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से संरक्षित क्षेत्रों के सुदृढ़ीकरण के लिए जैविक कानून, 2025 पारित किया है, लेकिन यह सैन्य और कानून प्रवर्तन एजेंसियों को खनन, लॉगिंग, पशु पालन या जंगलों में नशीली दवाओं की तस्करी में लगे आपराधिक समूहों से निपटने के लिए संरक्षित क्षेत्रों में हस्तक्षेप करने का अधिकार देता है। ¹¹⁷⁷ पूर्व विधायी परामर्श के बिना अधिनियमित किए जाने, पैतृक क्षेत्रों को राज्य के स्वामित्व वाली भूमि के रूप में मानते हुए सामूहिक अधिकारों का उल्लंघन करने, स्वदेशी लोगों के अपराधीकरण को जोखिम में डालने और राज्य और निजी संस्थाओं पर पैतृक क्षेत्रों के प्रशासन को लागू करने के लिए स्वदेशी लोगों द्वारा इसकी व्यापक रूप से आलोचना की गई है। ¹¹⁷⁸ संविधान और अंतरसांस्कृतिक शिक्षा पर जैविक अधिनियम, 2011, स्वदेशी लोगों के द्विभाषी अंतरसांस्कृतिक शिक्षा के अधिकार की रक्षा करता है। ¹¹⁷⁹ उच्च शिक्षा पर जैविक अधिनियम, 2010, उच्च शिक्षा में अंतर-संस्कृति को शामिल करने का प्रावधान करता है। ¹¹⁸⁰ इक्वाडोर ने शिक्षा मंत्रालय के तहत द्विभाषी अंतरसांस्कृतिक शिक्षा के लिए सचिवालय की भी स्थापना की, जो प्रशासनिक, तकनीकी, शैक्षिक, परिचालन और वित्तीय स्वायत्तता के साथ निहित था। ¹¹⁸¹ संविधान पैतृक चिकित्सा और स्वदेशी लोगों की पारंपरिक चिकित्सा प्रथाओं को भी मान्यता देता है। ¹¹⁸² इक्वाडोर ने स्वदेशी दाइयों के साथ अंतरसांस्कृतिक स्वास्थ्य और प्रसव में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य मंत्रालय के तहत अंतरसांस्कृतिक स्वास्थ्य के लिए राष्ट्रीय निदेशालय बनाया है। ¹¹⁸³

¹¹⁷⁵ United Nations General Assembly, Human Rights Council, *Visit to Ecuador, Report of the Special Rapporteur on the Rights of Indigenous Peoples*, UN Doc A/HRC/42/37 (Jul. 4, 2019), para. 22.

¹¹⁷⁶ The Constitution, 2008, preamble, art. 71.

¹¹⁷⁷ Maxwell Radwin, "Ecuador's new protected areas law sparks debate over security, development" *Mongabay*, available at: <https://news.mongabay.com/2025/07/ecuadors-new-protected-areas-law-sparks-debate-over-security-development/> (last visited on Oct. 6, 2025).

¹¹⁷⁸ *Ibid.*

¹¹⁷⁹ The Constitution, 2008, art. 57.14; The Organic Act on Intercultural Education, 2011, arts. 77, 78.

¹¹⁸⁰ United Nations General Assembly, Human Rights Council, *Visit to Ecuador, Report of the Special Rapporteur on the Rights of Indigenous Peoples*, UN Doc A/HRC/42/37 (Jul. 4, 2019), para. 60; The Organic Act on Higher Education, 2010, art. 3.

¹¹⁸¹ United Nations General Assembly, Human Rights Council, *Visit to Ecuador, Report of the Special Rapporteur on the Rights of Indigenous Peoples*, UN Doc A/HRC/42/37 (Jul. 4, 2019), para. 62.

¹¹⁸² The Constitution, 2008, arts. 57.12, 362.

¹¹⁸³ United Nations General Assembly, Human Rights Council, *Visit to Ecuador, Report of the Special Rapporteur on the Rights of Indigenous Peoples*, UN Doc A/HRC/42/37 (Jul. 4, 2019), para. 64.

संविधान स्पष्ट रूप से स्वैच्छिक अलगाव में स्वदेशी लोगों को संदर्भित करता है, उनकी भूमि को पैतृक संपत्ति के रूप में मान्यता देता है, राज्य को यह सुनिश्चित करना है कि वे अपने आत्म-निर्णय के अधिकार का इस्तेमाल करते हुए जो फैसले लें, उनका सम्मान हो; और उनके इलाकों में संसाधनों के दोहन वाली गतिविधियों पर रोक लगाई गई है।¹¹⁸⁴ अपनी मर्जी से अलग-थलग रहने वाले मूल निवासियों के इन अधिकारों का उल्लंघन 'नस्लीय नरसंहार' (किसी समुदाय या संस्कृति को खत्म करने की कोशिश) जैसा अपराध माना जाता है।¹¹⁸⁵ स्वैच्छिक अलगाव में स्वदेशी लोगों की सुरक्षा के लिए, इक्वाडोर ने अपने पारंपरिक क्षेत्रों को घेरते हुए अलंघनीय 'संरक्षित क्षेत्र' भी बनाए हैं, जो 'बफर ज़ोन' से जुड़े हुए हैं, जहां नए बुनियादी ढांचे और अन्य परियोजनाओं का विकास जो उनके जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है, प्रतिबंधित है।¹¹⁸⁶ इक्वाडोर ने स्वैच्छिक अलगाव में स्वदेशी लोगों के संरक्षण के लिए एक निदेशालय की भी स्थापना की है।¹¹⁸⁷ हाल के दिनों में, हालांकि, इक्वाडोर ने संरक्षित क्षेत्रों के भीतर संरक्षित वनों में खनन रियायतें दी हैं, इस प्रकार स्वदेशी लोगों के अधिकारों को उनके एफपीआईसी प्राप्त किए बिना नष्ट कर दिया है।¹¹⁸⁸

4.1.5. प्रथागत कानून और कानूनी प्रणालियाँ

संविधान स्वदेशी न्याय प्रणाली (जो स्वतंत्र रूप से काम करती है) को मान्यता देता है और सामान्य न्याय प्रणाली के साथ इसके पर्याप्त समन्वय और सहयोग का आह्वान करता है।¹¹⁸⁹ स्वदेशी अधिकारी न्यायिक जिम्मेदारियों को निभाने और पारंपरिक नियमों और प्रक्रियाओं को लागू करने के लिए अधिकृत हैं जो स्वदेशी क्षेत्रों के भीतर संविधान और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त मानवाधिकारों के अनुरूप हैं।¹¹⁹⁰ इक्वाडोर की घरेलू दंड प्रणाली में दोहरे खतरे के सिद्धांत के अनुप्रयोग में स्वदेशी न्यायालयों के निर्णयों पर विचार किया जाना है।¹¹⁹¹ इक्वाडोर स्वदेशी अदालतों के फैसलों का सम्मान करने के लिए भी बाध्य है; हालांकि, फैसले संवैधानिक समीक्षा के अधीन हैं।¹¹⁹² हालांकि स्वदेशी अदालतों के अधिकार क्षेत्र पर कोई संवैधानिक सीमाएँ नहीं हैं, इक्वाडोर के संवैधानिक न्यायालय ने ला कोचा मामले में निर्णय दिया कि सामान्य अदालतों ने जीवन के खिलाफ अपराधों पर विशेष अधिकार क्षेत्र बनाए रखा, जिन पर स्वदेशी अधिकारियों को निर्णय लेने से रोक दिया गया था।¹¹⁹³ इक्वाडोर की सामान्य न्याय प्रणाली फिर भी स्वदेशी लोगों के लिए खुली है।¹¹⁹⁴ स्वदेशी अभियोजकों के कार्यालयों की स्थापना 2008 में न्याय तक पहुंच की सुविधा के लिए की गई थी

¹¹⁸⁴The Constitution, 2008, art. 57.

¹¹⁸⁵*Ibid.*

¹¹⁸⁶United Nations General Assembly, Human Rights Council, *Visit to Ecuador, Report of the Special Rapporteur on the Rights of Indigenous Peoples*, UN Doc A/HRC/42/37 (Jul. 4, 2019), para. 65.

¹¹⁸⁷*Id.* at para. 66.

¹¹⁸⁸*Id.* at para. 71.

¹¹⁸⁹The Constitution, 2008, art. 171; United Nations General Assembly, Human Rights Council, *Visit to Ecuador, Report of the Special Rapporteur on the Rights of Indigenous Peoples*, UN Doc A/HRC/42/37 (Jul. 4, 2019), para. 51.

¹¹⁹⁰The Constitution, 2008, art. 171.

¹¹⁹¹*Id.* art. 76.7(i).

¹¹⁹²*Id.* art. 171.

¹¹⁹³*Victor Manuel Olivio Pallo v. La Cocha Community Case* 0731-10-EP (2014).

¹¹⁹⁴United Nations General Assembly, Human Rights Council, *Visit to Ecuador, Report of the Special Rapporteur on the Rights of Indigenous Peoples*, UN Doc A/HRC/42/37 (Jul. 4, 2019), para. 50.

हालाँकि, मूल निवासियों की न्याय प्रणाली में बेवजह दखल देने और टकराव पैदा करने के लिए इनकी कड़ी आलोचना की गई है।¹¹⁹⁵

4.2. कोलंबिया

4.2.1. संवैधानिक मान्यता

कोलंबिया में, 115 से अधिक स्वदेशी लोग हैं, जिनकी विशिष्ट ऐतिहासिक उत्पत्ति है।¹¹⁹⁶ भाषाओं और सांस्कृतिक प्रथाओं, जिनमें से अधिकांश कानूनी रूप से गठित 896 स्वदेशी भंडार के भीतर रहते हैं।¹¹⁹⁷ कोलंबिया का संविधान स्वदेशी लोगों को उनके सामूहिक भूमि भंडार के अधिकार, और सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक अखंडता की मान्यता देता है,¹¹⁹⁸

4.2.2. पैतृक भूमि का स्वामित्व

रिजर्व स्वदेशी लोगों के संवैधानिक रूप से औपचारिक पैतृक क्षेत्रों को संदर्भित करता है; इन पर सामूहिक मालिकाना हक होता है और इन्हें ज़ब्त नहीं किया जा सकता, न ही इन पर किसी और का अधिकार हो सकता है और न ही इन्हें किसी और को सौंपा जा सकता है।¹¹⁹⁹ इसमें न केवल मूल निवासियों के बसे हुए, इस्तेमाल किए जा रहे या कानूनी अधिकार वाले इलाके शामिल हैं, बल्कि वे पारंपरिक जगहें भी शामिल हैं जहाँ उनकी जीवन-दृष्टि, आर्थिक व्यवस्था, संसाधन और संगठन जुड़े हुए हैं।¹²⁰⁰ कोलंबिया के संवैधानिक न्यायालय ने स्पष्ट रूप से इस समझ की पुष्टि की है: "मूल निवासियों के लिए ज़मीन का जो खास महत्व है, उसे देखते हुए उनके इलाके की सुरक्षा केवल उन ज़मीनों तक सीमित नहीं है जिनके कागज़ात उनके नाम हैं; बल्कि यह एक कानूनी अवधारणा है जो उस पूरे इलाके तक फैली हुई है जो उनकी सांस्कृतिक, धार्मिक और आर्थिक गतिविधियों को पूरी आज़ादी के साथ करने के लिए ज़रूरी है, जिस तरह से वे पूर्वजों द्वारा किए गए हैं।"¹²⁰¹ इस प्रकार स्वदेशी लोगों द्वारा उनके पैतृक क्षेत्रों के पारंपरिक कब्जे को कोलंबियाई राज्य द्वारा निहित हक के बराबर माना जाता है।¹²⁰² तथापि, राज्य अपने पास उप-मृदा और गैर-नवीकरणीय संसाधनों का स्वामित्व रखता है।¹²⁰³

1994 का अधिनियम सं. 160, स्वदेशी लोगों को भंडारों की स्थापना, विस्तार, समेकन, पुनर्वास और पुनर्गठन के माध्यम से भूमि प्रदान करता है।¹²⁰⁴ स्वैच्छिक अलगाव में रहने वाले स्वदेशी लोग,

¹¹⁹⁵ *Ibid.*

¹¹⁹⁶ United Nations General Assembly, Human Rights Council, *Visit to Colombia, Report of the Special Rapporteur on the Rights of Indigenous Peoples*, UN Doc A/HRC/57/47 (Sep. 10, 2024), para. 5.

¹¹⁹⁷ International Work Group for Indigenous Affairs, *The Indigenous World 2025* (39th edn., 2025).

¹¹⁹⁸ The Constitution of Colombia, 1991, arts. 246, 321, 329, 330.

¹¹⁹⁹ *Id.* art. 63; International Work Group for Indigenous Affairs, *The Indigenous World 2024* (38th edn., 2024), p. no. 339.

¹²⁰⁰ International Work Group for Indigenous Affairs, *The Indigenous World 2024* (38th edn., 2024), p. no. 339.

¹²⁰¹ *Future Generations v. Ministry of Environment*, T-849 (2014).

¹²⁰² International Work Group for Indigenous Affairs, *The Indigenous World 2024* (38th edn., 2024), p. no. 339.

¹²⁰³ The Constitution, 1991, art. 332.

¹²⁰⁴ United Nations Economic and Social Council, *Human rights and indigenous issues, Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights and fundamental freedoms of indigenous people*, UN Doc E/CN.4/2005/88/Add.2 (Nov. 10, 2004), para. 12.

2011 का डिक्री नं. 4633 उन्हें अपनी संस्कृति के अनुसार, हस्तक्षेप या विस्थापन के अधीन हुए बिना, अपने पैतृक क्षेत्रों में स्वतंत्र रूप से रहने के उनके अधिकार की गारंटी देता है।¹²⁰⁵ हालाँकि स्वदेशी लोगों के ज़मीन पर सामूहिक अधिकार को मान्यता दी गई है, फिर भी मालिकाना हक देने और रिज़र्व का दायरा बढ़ाने में प्रक्रियात्मक देरी हुई है; साथ ही, बड़े पैमाने पर संसाधन निकालने और एग्रो-इंडस्ट्रियल मेगा-प्रोजेक्ट्स के कारण स्वदेशी लोगों को अक्सर उनके कानूनी रूप से बने गठित भंडार से बेदखल कर दिया जाता है।¹²⁰⁶ उदाहरण के लिए, कोलंबिया के संवैधानिक न्यायालय द्वारा 2021,¹²⁰⁷ में कैनामोमो लोमाप्रिएटा आरक्षण के एम्बेरा चामी लोगों के स्वामित्व और संबंधित अधिकारों को मान्यता देने के बावजूद, कोलंबियाई अधिकारियों ने निर्णय को लागू करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया है, और एम्बेरा चामी लोग तीसरे पक्षों द्वारा अपने स्वदेशी क्षेत्रों में की गई खनन गतिविधियों से प्रभावित होना जारी है।¹²⁰⁸

हालाँकि, कोलंबिया ने राष्ट्रीय विकास योजना 2022-2026 को अपनाया, जिसमें भूमि के मालिकाना हक (टाइटलिंग) शीर्षक में देरी को कम करने और स्वदेशी लोगों के उल्लंघन किए गए व्यक्तिगत और सामूहिक अधिकारों को बहाल करने का वादा किया।¹²⁰⁹ इसके अलावा, सामूहिक क्षेत्रीय अधिकारों के प्रभावी कब्जे और आनंद को सुनिश्चित करने के लिए स्वदेशी क्षेत्रों के राष्ट्रीय आयोग (कोलंबियाई सरकार और स्वदेशी लोगों के प्रतिनिधियों से बना) के साथ एक समझौता किया गया था,¹²¹⁰ जिसमें 'लैंड रेस्टीट्यूशन यूनिट' और 'यूनिट फॉर अटेंशन एंड इंटीग्रल रिपेरेशन' के साथ मिलकर स्वदेशी भंडार की स्थापना, विस्तार, समेकन, नियमित और पुनर्स्थापना शामिल है।¹²¹¹ स्वदेशी क्षेत्रों के राष्ट्रीय आयोग को स्वैच्छिक अलगाव में रहने वाले स्वदेशी लोगों की भूमि के स्वामित्व को प्राथमिकता देने के लिए अनिवार्य किया गया है ताकि उनके सामूहिक क्षेत्रीय अधिकारों की प्रभावी ढंग से रक्षा की जा सके।¹²¹² कोलंबिया में आंतरिक सशस्त्र संघर्ष के संदर्भ में, पीड़ित और भूमि बहाली अधिनियम, 2011 स्वदेशी लोगों को सहायता, व्यापक निवारण और भूमि अधिकारों की बहाली प्रदान करने के उपायों को अधिकृत करता है।¹²¹³

4.2.3. आत्मनिर्णय, स्व-शासन, भागीदारी और परामर्श

संविधान में कहा गया है कि स्वदेशी भंडार क्षेत्रीय निकाय (राज्य के राजनीतिक और

¹²⁰⁵The Amazon Conservation Team, *Indigenous Land Titling Guide: Reserve Establishment and Expansion Processes in Colombia* (1st edn., 2018), p. no. 13.

¹²⁰⁶International Work Group for Indigenous Affairs, *The Indigenous World 2024* (38th edn., 2024), p.no.340.

¹²⁰⁷Judgment T-530 (2016).

¹²⁰⁸United Nations General Assembly, Human Rights Council, *Visit to Colombia, Report of the Special Rapporteur on the Rights of Indigenous Peoples*, UN Doc A/HRC/57/47/Add.1 (Sep.10, 2024), paras.74-75.

¹²⁰⁹International Work Group for Indigenous Affairs, *The Indigenous World 2024* (38th edn., 2024), p.no.344.

¹²¹⁰*Id.* at 341.

¹²¹¹*Id.* at 342.

¹²¹²The Amazon Conservation Team, *Indigenous Land Titling Guide: Reserve Establishment and Expansion Processes in Colombia* (1st edn., 2018), p. no. 13.

¹²¹³United Nations General Assembly, Human Rights Council, *Visit to Colombia, Report of the Special Rapporteur on the Rights of Indigenous Peoples*, UN Doc A/HRC/57/47/Add.1 (Sep.10, 2024), para.7.

प्रशासनिक ढांचे का हिस्सा) हैं, जिन्हें खुद को नियंत्रित करने, अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने, भूमि और संसाधनों का प्रबंधन करने और राष्ट्रीय राजस्व में भाग लेने की स्वायत्तता है।¹²¹⁴ स्वदेशी क्षेत्रीय संस्थाओं को पारंपरिक स्वदेशी प्रणालियों और ज्ञान के अनुसार स्वदेशी परिषदों द्वारा शासित किया जाना है।¹²¹⁵ स्वदेशी परिषदों को भूमि उपयोग की निगरानी करने, सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए उपाय तैयार करने, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण की देखरेख करने, सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करने और कोलंबियाई सरकार के समक्ष स्वदेशी क्षेत्रीय संस्थाओं का प्रतिनिधित्व करने का अधिकार है।¹²¹⁶

बहुत लंबे समय तक, कोलंबिया ने अपने स्वयं के कानूनी व्यक्तित्व के साथ स्वायत्त राजनीतिक संस्थाओं के रूप में स्वदेशी क्षेत्रों की स्थापना और मान्यता के लिए आवश्यक कानून नहीं बनाया था,¹²¹⁷ हालांकि इस संबंध में 2014 का डिक्री लॉ नं. 1953 और 2018 का डिक्री लॉ नं. 632¹²¹⁸ कुछ अंतरिम व्यवस्था किए गए थे। इस विफलता को स्वीकार करते हुए, कोलंबिया के संवैधानिक न्यायालय ने कहा: "ऐसा कोई वैध संवैधानिक कारण नहीं है जो स्वदेशी क्षेत्रीय संस्थाओं से संबंधित अनुच्छेद 329 के संवैधानिक जनादेश से संबंधित इस तरह के लंबे समय तक विधायी चूक को उचित ठहराता हो। इस तरह की मुखर चुप्पी न केवल एक कानूनी शून्य पैदा करती है, बल्कि स्वदेशी समुदायों के लिए संवैधानिक क्षेत्रीय और शासन डिजाइन की प्रभावशीलता को भी महत्वपूर्ण रूप से कमजोर करती है।"¹²¹⁹

हालांकि, हाल ही में, कोलंबिया ने 2025 का डिक्री लॉ नं. 488 स्वदेशी क्षेत्रों के कामकाज और अन्य क्षेत्रीय संस्थाओं के साथ उनके समन्वय को विनियमित करता है जो, राजनीतिक, प्रशासनिक और वित्तीय स्वायत्तता के साथ स्वदेशी क्षेत्रीय संस्थाओं की औपचारिक मान्यता के लिए एक कानूनी ढांचा निर्धारित करता है; विशेष रूप से, उन परियोजनाओं और गतिविधियों को वीटो करने का अधिकार जो उनकी पैतृक भूमि को प्रभावित कर सकते हैं।¹²²⁰ स्वशासन के लिए इस तरह के विकेंद्रीकृत मॉडल के अलावा, संविधान स्वदेशी लोगों को सीनेट के दो अतिरिक्त सदस्यों को चुनने का अधिकार भी प्रदान करता है, जो चुनावी भागफल की प्रणाली के अधीन है,¹²²¹ और हाउस ऑफ़ रिप्रेजेंटेटिव्स का एक सदस्य विशेष आदिवासी निर्वाचन क्षेत्र से चुनने का अधिकार देता है।¹²²² हालांकि, सीनेट का सदस्य बनने की इच्छा रखने वाले आदिवासी लोगों के लिए ज़रूरी है कि उन्होंने "अपने समुदाय में पारंपरिक अधिकार वाले पद पर काम किया हो या किसी आदिवासी संगठन के नेता रहे हों"।¹²²³

¹²¹⁴The Constitution, 1991, art. 361, para. 2.

¹²¹⁵*Id.* art. 329.

¹²¹⁶*Ibid.*

¹²¹⁷United Nations General Assembly, Human Rights Council, *Visit to Colombia, Report of the Special Rapporteur on the Rights of Indigenous Peoples*, UN Doc A/HRC/57/47/Add.1 (Sep. 10, 2024), para. 52.

¹²¹⁸Gordon and Betty Foundation, *The Status and Future of Rights-Based Conservation in the Amazon of Colombian and Peru* (2022), p. no. 45.

¹²¹⁹Judgment C-054 (2023).

¹²²⁰Marzia Genovese, "Legal Pluralism in Practice: Colombia's New Framework for Indigenous Territorial Self-Government" *EJIL:Talk!* (Jul. 3, 2025), available at: <https://www.ejiltalk.org/legal-pluralism-in-practice-colombias-new-framework-for-indigenous-territorial-self-government/> (last visited on Nov. 11, 2025).

¹²²¹The Constitution, 1991, art. 171, paras. 2, 4.

¹²²²*Id.* art. 176, para. 4.

¹²²³*Id.* art. 171, para. 5.

संविधान ने यह भी प्रावधान किया है कि मूल निवासी समुदाय की भूमि क्षेत्रों के भीतर प्राकृतिक संसाधनों के दोहन से संबंधित निर्णय निर्माण प्रक्रिया में सहभागिता प्रदान की जाएगी।¹²²⁴ इसके अलावा, कोलंबिया के संवैधानिक न्यायालय ने बार-बार दोहराया है कि प्रशासनिक और विधायी निर्णयों के संबंध में पूर्व परामर्श स्वदेशी लोगों का एक मौलिक अधिकार है: *"पूर्व परामर्श जातीय समूहों के संबंध में पर्यावरणीय न्याय की उचित-वितरण समानता और भागीदारी की आवश्यकताओं की एक विशिष्ट गारंटी का गठन करता है-एक ऐसी अवधारणा है जो राजनीतिक संविधान के अनुच्छेद 330 के पैराग्राफ को एक प्रारंभिक बिंदु के रूप में लेती है, जो अपने क्षेत्रों में प्राकृतिक संसाधनों के दोहन से पहले स्वदेशी समुदायों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए राज्य के दायित्व को स्थापित करती है।"*¹²²⁵ कोलंबिया के संवैधानिक न्यायालय ने पाया कि स्वदेशी लोगों के पूर्व परामर्श के अधिकार का उल्लंघन किया गया था जब संबंधित स्वदेशी लोगों से परामर्श किए बिना अमेज़न क्षेत्र में स्वदेशी क्षेत्रों पर कोका फसलों का हवाई छिड़काव किया गया था।¹²²⁶ कोलंबिया का संवैधानिक न्यायालय प्रभावित स्वदेशी लोगों के साथ बातचीत के बिना स्थायी वन प्रबंधन परियोजनाओं के कार्यान्वयन के संबंध में एक समान निष्कर्ष पर पहुंचा।¹²²⁷ कोलंबिया ने पूर्व परामर्श को विनियमित करने वाले कई फरमान जारी किए हैं (हालांकि स्वदेशी लोगों तक ही सीमित नहीं है) और 2010 का राष्ट्रपति निर्देश 001 स्वदेशी लोगों को पूर्व परामर्श के मौलिक अधिकार की गारंटी देता है।¹²²⁸ राष्ट्रीय विकास योजना 2022-2026 ने स्वदेशी भूमि पर प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन और नियंत्रण में स्वायत्तता और आत्मनिर्णय के लिए स्वदेशी लोगों के अधिकारों को बनाए रखने की दिशा में स्वदेशी लोगों के साथ पूर्व परामर्श के लिए प्रक्रिया भी तैयार की।¹²²⁹

4.2.4. संस्कृति और परंपराओं का संरक्षण

संविधान विशेष रूप से यह आदेश देता है कि स्वदेशी क्षेत्रों में प्राकृतिक संसाधनों का दोहन स्वदेशी लोगों की सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक अखंडता को प्रभावित किए बिना किया जाना चाहिए।¹²³⁰ कोलंबिया ने 2024 का राष्ट्रपति डिक्री 1275 भी पारित किया, जो *"पर्यावरणीय मामलों में स्वदेशी क्षेत्रों के प्रबंधन और स्वदेशी अधिकारियों की पर्यावरणीय शक्तियों के विकास और अन्य अधिकारियों के साथ उनके प्रभावी समन्वय के लिए मानदंडों की स्थापना के लिए नियम तय करता है"*¹²³¹ यह उन स्वदेशी लोगों और संगठनों की मांगों के जवाब में था जिनमें उनके पैतृक

¹²²⁴ *Id.* art. 330.

¹²²⁵ Judgment T-660 (2015).

¹²²⁶ *Organization of Indigenous Peoples of the Colombian Amazon (OPIAC) v. Presidency of the Republic*, SU-383/03 (2003).

¹²²⁷ *Grupo de Interés Público Universidad de Los Andes et al. v. Congreso de Colombia*, C-355/07 (2008).

¹²²⁸ William Yeffe Vivas Lloreda, "Prior consultation as a fundamental right of collective ownership of indigenous, afro-descendant, rum and tribal peoples and its ineffectiveness in the protection of protected territories" 10(16) *Cathedra* 50 (2021-2022).

¹²²⁹ International Work Group for Indigenous Affairs, *The Indigenous World 2025* (39th edn., 2025), p. no. 361.

¹²³⁰ The Constitution, 1999, art. 330, para. 2.

¹²³¹ International Work Group for Indigenous Affairs, *The Indigenous World 2025* (39th edn., 2025), p. no. 361.

क्षेत्रों के भीतर 'पर्यावरण प्राधिकरणों' के रूप में पहचान देने की माँग की गई थी।¹²³² आने वाली पीढ़ियों के लिए अपने प्राकृतिक और सांस्कृतिक वातावरण के संरक्षण की दिशा में, 2024 का राष्ट्रपति डिक्री 1275 स्वदेशी लोगों को अपने पारंपरिक ज्ञान के अनुप्रयोग में, अपने संसाधनों, जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के माध्यम से अपने पैतृक क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए विनियम जारी करने, बजट की योजना बनाने और भूमि उपयोग से संबंधित मामलों पर निर्णय लेने का अधिकार देता है।¹²³³

2024 का राष्ट्रपति का फरमान 1275 स्वदेशी लोगों को, उनके आत्मनिर्णय के अधिकार के अनुसार, अपनी पैतृक भूमि पर निष्कर्षण गतिविधियों और परियोजनाओं के लिए लाइसेंस के अनुदान पर नियंत्रण रखने में सक्षम बनाता है।¹²³⁴ पर्यावरण पर स्वदेशी समुदायों के संरक्षकता के अधिकार की पुष्टि कोलंबिया के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सेंटर फॉर सोशल जस्टिस स्टडीज एट अल बनाम गणराज्य की प्रेसीडेंसी में ऐतिहासिक निर्णय के ज़रिए पर्यावरण पर मूल निवासी समुदायों के संरक्षण के अधिकार की पुष्टि की है और इसे, 'जैविक सांस्कृतिक अधिकार' करार देते हुए कहा, "जैविक सांस्कृतिक अधिकार, उनकी सरलतम परिभाषा में, उन अधिकारों को संदर्भित करते हैं जो जातीय समुदायों को अपने क्षेत्रों पर स्वायत्त संरक्षकता का प्रशासन और प्रयोग करना होता है-अपने स्वयं के कानूनों और रीति-रिवाजों के अनुसार-और प्राकृतिक संसाधन जो उनके निवास स्थान को बनाते हैं, जहां उनकी संस्कृति, उनकी परंपराएं और उनके जीवन के तरीके पर्यावरण और जैव विविधता के साथ उनके विशेष संबंध के आधार पर विकसित किए जाते हैं। ये अधिकार प्रकृति, उसके संसाधनों और जातीय व स्वदेशी समुदायों की संस्कृति के बीच मौजूद गहरे और स्वाभाविक संबंध को मान्यता के परिणामस्वरूप हैं।"¹²³⁵

4.2.5. प्रथागत कानून और कानूनी प्रणालियाँ

संविधान स्वदेशी अधिकारियों को अपने क्षेत्रों के भीतर अपने प्रथागत कानूनों और प्रक्रियाओं के अनुसार अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने का भी अधिकार देता है, बशर्ते कि ये कोलंबिया में संविधान और अन्य कानूनों के अनुरूप हों।¹²³⁶ हालांकि, कई अवसरों पर, जहां स्वदेशी अदालतों के निर्णय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त मानवाधिकारों के साथ संघर्ष में रहे हैं, कोलंबिया के संवैधानिक न्यायालय ने हस्तक्षेप किया है।¹²³⁷ उदाहरण के लिए, नासा अधिकारियों द्वारा लगाए गए गंभीर शारीरिक दंड के संबंध में, कोलंबिया के संवैधानिक न्यायालय ने माना कि इस तरह की अत्यधिक शारीरिक हिंसा क्रूर व्यवहार के खिलाफ संवैधानिक निषेध का उल्लंघन है।¹²³⁸ हाल ही में, स्वदेशी समुदायों से संबंधित नाबालिग लड़कियों के प्रथागत विवाह

¹²³² *Id.* at 360.

¹²³³ Aimee Gabay, "Colombia decree recognizes Indigenous people as environmental authorities" *Mongabay* (Oct. 3, 2025), available at: <https://news.mongabay.com/2024/10/colombia-decree-recognizes-indigenous-people-as-environmental-authorities/> (last visited on Nov. 11, 2025).

¹²³⁴ *Ibid.*

¹²³⁵ *Center for Social Justice Studies et al. v. Presidency of the Republic et al.*, T-622/16 (2016).

¹²³⁶ The Constitution, 1991, art. 246.

¹²³⁷ Sebastian Machado Ramirez, "Legal Pluralism in Practice? The Gaps and Challenges of Colombia's Indigenous Territorial Decree" *Voelkerrechtsblog* (Jul. 27, 2025), available at: <https://voelkerrechtsblog.org/legal-pluralism-in-practice/> (last visited on Nov. 11, 2025).

¹²³⁸ *Paez Indigenous Community Case*, Judgment T-523/97 (1997).

के मामले में, कोलंबिया के संवैधानिक न्यायालय ने फैसला सुनाया कि ऐसे सभी सिविल विवाह और रिश्ते रद्द कर दिए गए, क्योंकि ये बच्चों के अधिकारों और ज़बरदस्ती की शादियों से सुरक्षा का उल्लंघन करते थे।¹²³⁹

4.3. ब्राज़ील

4.3.1. संवैधानिक मान्यता

ब्राज़ील 266 से अधिक स्वदेशी लोगों का घर है, जिसमें कई अलग-थलग समुदाय शामिल हैं, जो मुख्य रूप से अमेज़न क्षेत्र में केंद्रित हैं,¹²⁴⁰ जिन्हें "भारतीय" के रूप में संदर्भित किया जाता है और संविधान द्वारा संरक्षित किया जाता है।¹²⁴¹

4.3.2. क्षेत्रों, वनों और प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग

संविधान में कहा गया है कि 'भारतीयों' को "उन भूमि पर उनके मूल अधिकार होंगे जिन पर वे पारंपरिक रूप से कब्जा करते हैं"।¹²⁴² 'पारंपरिक रूप से कब्जा की गई भूमि' को मोटे तौर पर "उन भूमि के रूप में परिभाषित किया गया है जिन पर (भारतीय) स्थायी आधार पर रहते हैं, जिनका उपयोग उनकी उत्पादक गतिविधियों के लिए किया जाता है, जो उनके कल्याण के लिए आवश्यक पर्यावरणीय संसाधनों के संरक्षण के लिए अपरिहार्य हैं और जो उनके भौतिक और सांस्कृतिक प्रजनन के लिए उनके उपयोग, रीति-रिवाजों और परंपराओं के अनुसार, आवश्यक हैं,"¹²⁴³ संविधान यह भी निर्धारित करता है कि ऐसी पारंपरिक रूप से कब्जा की गई भूमि अविभाज्य और गैर-हस्तांतरणीय है, और इसके अधिकार सीमाओं के क़ानून से अप्रभावित हैं।¹²⁴⁴ तदनुसार, स्वदेशी लोगों को अपनी पारंपरिक रूप से कब्जा की गई भूमि पर स्थायी कब्जा करने और उसमें मिट्टी, नदियों और झीलों पर विशेष रूप से उपयोग करने का अधिकार है।¹²⁴⁵ राष्ट्रीय लोक हित को छोड़कर, ब्राज़ील सरकार द्वारा पारंपरिक रूप से कब्जा की गई भूमि पर कब्जा, प्रभुत्व और कब्जा अमान्य है।¹²⁴⁶ इस प्रकार स्वदेशी लोगों को उनकी पारंपरिक रूप से कब्जा की गई भूमि पर होने वाले प्राकृतिक संसाधनों के दोहन और विनाश, महामारी या राष्ट्रीय संप्रभुता के हित को छोड़कर, वहां से बेदखल या जबरन हटाने के खिलाफ संरक्षित किया जाता है, जिसमें जोखिम समाप्त होने पर उन्हें तुरंत उनकी पारंपरिक रूप से कब्जा की गई भूमि पर वापस कर दिया जाना चाहिए।¹²⁴⁷

¹²³⁹Nullity of civil marriages and unions involving minor girls in indigenous communities, Judgment C-039/25(2025).

¹²⁴⁰International Work Group for Indigenous Affairs, *The Indigenous World 2024* (38th edn., 2024) p.no.320. ¹²⁴¹The Constitution of the Federative Republic of Brazil, 1988, title VIII – the Social Order, ch. VIII – Indians. ¹²⁴²*Id.* art. 231.

¹²⁴³*Id.* art. 231, para. 1.

¹²⁴⁴*Id.* art. 231, para. 4.

¹²⁴⁵*Id.* art. 231, para. 2.

¹²⁴⁶*Id.* art. 231, para. 6.

¹²⁴⁷*Id.* art. 231, para. 5.

4.3.3. पैतृक भूमि का स्वामित्व

संविधान ब्राजील की सरकार को भौगोलिक रूप से सीमांकन करने और पारंपरिक रूप से स्वदेशी लोगों द्वारा कब्जा की गई भूमि के स्वामित्व को नामित करने के साथ-साथ "उनकी सभी संपत्ति की रक्षा और सम्मान सुनिश्चित करने" के लिए बाध्य करता है।¹²⁴⁸ न्याय मंत्रालय के तहत स्वदेशी लोगों का राष्ट्रीय फाउंडेशन (फुनाई) पारंपरिक रूप से कब्जा की गई भूमि के परिसीमन के लिए जिम्मेदार है।¹²⁴⁹

विशेष रूप से, सांता कैटरीना राज्य और ज़ोकलेंग लोगों के बीच पारंपरिक रूप से कब्जा की गई भूमि के शीर्षक से संबंधित विवाद के संबंध में एक ऐतिहासिक निर्णय में, ब्राजील के सर्वोच्च न्यायालय ने 'मार्को टेम्पोरल' सिद्धांत को खारिज कर दिया, जिसे मूल रूप से ब्राजील के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 2009 में रैपोसा/सेरा डो सोल मामले में प्रस्तावित किया गया था।¹²⁵⁰ 'मार्को टेम्पोरल' सिद्धांत यह बताता है कि स्वदेशी लोगों को अपनी पारंपरिक रूप से कब्जा की गई भूमि के शीर्षक का अधिकार केवल तभी है जब वे संविधान लागू होने के दिन, यानी 5 अक्टूबर 1988 को इस तरह के क्षेत्र में शारीरिक रूप से मौजूद थे।¹²⁵¹ चूंकि कई स्वदेशी लोग ऐतिहासिक रूप से अपनी पैतृक भूमि से विस्थापित हुए थे और इस कट-ऑफ तिथि तक उनके पास कब्जा नहीं था, इसलिए क्षेत्रीय सीमांकन के लिए उनके वैध दावे 'मार्को टेम्पोरल' सिद्धांत के अनुसार अमान्य होंगे।¹²⁵² हालांकि ब्राजील के सर्वोच्च न्यायालय ने 'मार्को टेम्पोरल' सिद्धांत को असंवैधानिक घोषित करके ऐसे स्वदेशी लोगों के भूमि अधिकारों की रक्षा करने की मांग की, राष्ट्रीय कांग्रेस ने तुरंत राष्ट्रपति के वीटो के बावजूद 2023 के कानून 14.701 द्वारा इसे विधायी रूप से प्रवेश करने के लिए आगे बढ़ाया।¹²⁵³

2023 के कानून 14.701 की संवैधानिक वैधता को बाद में ब्राजील के सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी।¹²⁵⁴ हालांकि, ब्राजील के सर्वोच्च न्यायालय ने 2023 के कानून 14.701 के आवेदन को उसके गुण-दोष पर निर्णय लेने तक निलंबित करने से इनकार कर दिया, इसके बजाय, अंतरिम तौर पर ब्राजील सरकार, कृषि व्यवसायों और स्वदेशी लोगों के प्रतिनिधियों वाले एड हॉक स्पेशल सुलह कमीशन के तहत स्वदेशी लोगों के

¹²⁴⁸Id.art.231.

¹²⁴⁹ María Lourdes Alcántara, "Serious Deterioration of Human Rights and Indigenous Rights Conditions in Brazil" IWGLA (Mar.14,2019), available at: <https://iwglia.org/en/brazil/3320-serious-deterioration-of-human-rights-and-indigenous-> (last visited on Oct.6,2025)

¹²⁵⁰Raposa Serra do Sol, ADI 3239 (2009); Andrea Carvalho, "Indigenous Peoples Secure Decisive Victory in Brazil" Human Rights Watch, available at: <https://www.hrw.org/news/2023/09/25/indigenous-peoples-secure-decisive-victory-brazil> (last visited on Oct. 6, 2025).

¹²⁵¹International Work Group for Indigenous Affairs, *The Indigenous World 2024* (38th edn., 2024), p. no. 320; Albert K. Barume, *Brazil must abandon "Marco Temporal" doctrine once and for all*, says UN expert, OHCHR (Jun. 11, 2025).

¹²⁵²Constance Malleret, "Controversial Brazil Law Curbing Indigenous Rights Comes into Force" *The Guardian*, Dec.28, 2023.

¹²⁵³International Work Group for Indigenous Affairs, *The Indigenous World 2024* (38th edn.,2024),p.no.323; Francisco Cali Tzay, *Brazil must protect Indigenous Peoples' lands, territories and resources*, says Special Rapporteur, OHCHR (Jul. 11,2024).

¹²⁵⁴Francisco Cali Tzay, *Brazil must protect Indigenous Peoples' lands, territories and resources*, says Special Rapporteur, OHCHR (Jul. 11, 2024).

साथ मध्यस्थता का निर्देश दिया।¹²⁵⁵ चूंकि स्वदेशी प्रतिनिधि अल्पमत में थे और विशेष सुलह आयोग को बहुमत के आधार पर निर्णय लेने की अनुमति दी गई थी (यहां तक कि स्वदेशी प्रतिनिधियों की भागीदारी के अभाव में भी) वे बाद में मध्यस्थता प्रक्रिया से हट गए।¹²⁵⁶ एक अभूतपूर्व कदम में, ब्राजील के सर्वोच्च न्यायालय ने 'मार्को टेम्पोरल' सिद्धांत को संवैधानिक रूप से स्थापित करने के साथ-साथ पारंपरिक रूप से कब्जा की गई भूमि पर निर्माण, विकास और शोषण के संबंध में स्वदेशी लोगों की वीटो शक्ति को छीनने के लिए एक विधेयक पेश किया, जहां कोई तकनीकी और स्थानीय विकल्प नहीं है।¹²⁵⁷

4.3.4. संस्कृति और परंपराओं का संरक्षण

संविधान यह निर्धारित करके स्वदेशी संस्कृति की रक्षा करता है कि 'भारतीयों' को "उनके सामाजिक संगठन, रीति-रिवाजों, भाषाओं, पंथों और परंपराओं को मान्यता दी जाएगी"।¹²⁵⁸ इसके अलावा, संविधान स्वदेशी लोगों को शिक्षा में अपनी मूल भाषाओं और सीखने की प्रक्रियाओं का उपयोग करने का अधिकार प्रदान करता है।¹²⁵⁹ संविधान स्वदेशी संस्कृति की अभिव्यक्तियों की भी रक्षा करता है।¹²⁶⁰ ब्राजील ने भाषाई और सांस्कृतिक संरक्षण के लिए कई संस्थागत उपायों को भी अपनाया है, जिसमें स्वदेशी भाषा पाठ की पेशकश, स्वदेशी परंपराओं का दस्तावेजीकरण, स्वदेशी कलाकृतियों (मुख्य रूप से फ्रांस, इटली और पुर्तगाल से) को वापस भेजना और ब्राजील के कानूनों का मूल भाषाओं में अनुवाद करना शामिल है।¹²⁶¹ 2024 में, स्वदेशी समुदायों के स्थायी आर्थिक विकास के लिए शुरू की गई नीतियों के अलावा, ब्राजील ने यह प्रमाणित करने के लिए 'स्वदेशी मुहर' पेश की कि एक विशेष उत्पाद (कृषि, कारीगर या निकालने वाला) एक स्वदेशी व्यक्ति द्वारा उनकी पैतृक भूमि पर खेती या कटाई की गई थी, और उत्पादक और स्वदेशी क्षेत्र की जातीयता को इंगित करता है जहां से यह उत्पन्न होता है।¹²⁶²

4.3.5. भागीदारी और परामर्श

संविधान स्वदेशी लोगों को जल संसाधनों के उपयोग और स्वदेशी भूमि पर खनिजों के दोहन में परामर्श के अधिकार की गारंटी देता है।¹²⁶³ संविधान स्वदेशी लोगों और उनके संगठनों

¹²⁵⁵ Daula Vargas, "“ALuta Continua!” Brazil’s Indigenous Peoples Resist Attacks on Their Rights” *Amazon Watch*, Oct. 31, 2024.

¹²⁵⁶ Francisco Cali Tzay, *Brazil must protect Indigenous Peoples’ lands, territories and resources, says Special Rapporteur*, OHCHR (Jul. 11, 2024).

¹²⁵⁷ International Work Group for Indigenous Affairs, *The Indigenous World 2024* (38th edn., 2024), p.no.326.

¹²⁵⁸ The Constitution, 1988, art. 231.

¹²⁵⁹ *Id.* art. 210, para. 2.

¹²⁶⁰ *Id.* art. 215, para. 1.

¹²⁶¹ Sônia Guajajara, “Brazil’s First Minister of Indigenous Peoples” *Chandler Institute of Governance* (Sept. 25, 2023), available at: <https://www.chandlerinstitute.org/governancematters/brazils-first-minister-of-indigenous-peoples> (last visited on Sep. 25, 2025).

¹²⁶² *Ibid.*

¹²⁶³ The Constitution, 1988, art. 231, para. 3.

को अपने अधिकारों की रक्षा के लिए मुकदमा करने की कानूनी क्षमता प्रदान करता है, और लोक अभियोजक को सभी प्रासंगिक मामलों में स्वदेशी लोगों की ओर से हस्तक्षेप करने के लिए अधिकृत करता है।¹²⁶⁴

2022 में, ब्राजील ने अपनी स्वदेशी नीति को महत्वपूर्ण रूप से संशोधित किया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि स्वदेशी लोगों की न सिर्फ बात सुनी जाए, बल्कि वे अपनी जीवन और पारंपरिक इलाकों से संबंधित निर्णय लेने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं।¹²⁶⁵ 2023 में स्वदेशी लोगों के मंत्रालय की स्थापना की गई थी, जिसे संबोधित करने का काम सौंपा गया था स्वदेशी लोगों की विशेष आवश्यकताएँ, उनके अधिकारों की रक्षा, और उनकी स्वायत्तता, संस्कृतियों की रक्षा और परंपराएं।¹²⁶⁶ इसके अलावा, स्वदेशी नेताओं को FUNAI समेत अहम रणनीतिक पदों पर नियुक्त किया गया था जिससे नीति निर्माण में स्वदेशी लोगों की प्रत्यक्ष भागीदारी को मजबूत करना, लाभ उठाना स्वदेशी ज्ञान और सामाजिक न्याय को बढ़ावा मिला।¹²⁶⁷ इसके अलावा, ब्राजील ने राष्ट्रीय परिषद को भी फिर से शुरू किया, जो स्वदेशी नीति (सी. एन. पी. आई.) के लिए एक सहभागी और परामर्शी निकाय हैं, जिसमें 30-30 प्रतिनिधि शामिल हैं, स्वदेशी लोगों को लक्षित करने वाली सार्वजनिक नीतियों की समीक्षा करना और उनके कार्यान्वयन की निगरानी करना¹²⁶⁸ CNPI के स्वदेशी प्रतिनिधियों को प्रत्येक राज्य के मूल निवासियों द्वारा चुने जाते हैं।¹²⁶⁹

¹²⁶⁴ *Id.* art. 232.

¹²⁶⁵ International Work Group for Indigenous Affairs, *The Indigenous World 2024* (38th edn., 2024), p. no. 321.

¹²⁶⁶ *Ibid.*

¹²⁶⁷ *Ibid.*

¹²⁶⁸ Sônia Guajajara, "Brazil's First Minister of Indigenous Peoples" *Chandler Institute of Governance* (Sept. 25, 2023), available at: <https://www.chandlerinstitute.org/governancematters/brazils-first-minister-of-indigenous-peoples> (last visited on Sep. 25, 2025).

¹²⁶⁹ *Ibid.*

Annexure C: Suggested Further Readings

Nordic region: Norway, Sweden, Finland

1. Ludger Müller-Wille, "The Sámi Parliament in Finland: A Model for Ethnic Minority Management?" 3(2) *Études/Inuit/Studies* 63-72 (1979).
2. David Corson, "Norway's 'Sámi Language Act': Emancipatory Implications for the World's Aboriginal Peoples" 24(4) *Language in Society* 493-514 (1995).
3. Jon Todal, "The Sámi School System in Norway and International Cooperation" 39(2) *Comparative Education* 185-192 (2003).
4. Kari Lie, "Sámi Heritage Language Program Models: Balancing Indigenous Traditions and Western Ideologies within the Norwegian Educational System" 75(2) *Scandinavian Studies* 273-292 (2003).
5. Charles Peterson, "Sámi Culture and Media" 75(2) *Scandinavian Studies* 293-300 (2003).
6. Hans Petter Graver and Geir Ulfstein, "The Sámi People's Right to Land in Norway" 11(4) *International Journal on Minority and Group Rights* 337-377 (2004).
7. Lars-Anders Baer, "The Rights of Indigenous Peoples—A Brief Introduction in the Context of the Sámi" 12(2) *International Journal on Minority and Group Rights* 245-267 (2005).
8. Anne Silviken, T. Haldorsen, et. al., "Suicide among Indigenous Sámi in Arctic Norway, 1970-1998" 21(9) *European Journal of Epidemiology* 707-713 (2006).
9. Rauna Kuokkanen, "Self-Determination and Indigenous Women—'Whose Voice Is It We Hear in the Sámi Parliament?'" 18(1) *International Journal on Minority and Group Rights* 39-62 (2011).
10. Else Grete Broderstad, "The Promises and Challenges of Indigenous Self-Determination: The Sámi Case" 66(4) *International Journal* 893-907 (2011).
11. Thomas R. Hilder, "Repatriation, Revival and Transmission: The Politics of a Sámi Musical Heritage" 21(2) *Ethnomusicology Forum* 161-179 (2012).
12. Hanne Hagtvedt Vik and Anne Julie Semb, "Who Owns the Land? Norway, the Sámi and the ILO Indigenous and Tribal Peoples Convention" 20(4) *International Journal on Minority and Group Rights* 517-550 (2013).
13. Øyvind Ravna, "The Fulfilment of Norway's International Legal Obligations to the Sámi – Assessed by the Protection of Rights to Lands, Waters and Natural Resources" 21(3) *International Journal on Minority and Group Rights* 297-329 (2014).
14. David Bunikowski, "Indigenous peoples, their rights and customary laws in the North: The case of the Sámi people" 43(1) *Nordia Geographical Publication* 75-85 (2013).
15. Veli-Pekka Lehtola, "Sámi Histories, Colonialism, and Finland" 52(2) *Arctic Anthropology* 22-36 (2015).

16. Wilfrid Greaves, “Arctic (in) Security and Indigenous Peoples: Comparing Inuit in Canada and Sámi in Norway” 47(6) *Security Dialogue* 461-480 (2016).
17. Guðrún Rós Árnadóttir, “Who Is Sámi? A Case Study on the Implementation of Indigenous Rights in Sweden”, in *Peacebuilding and the Rights of Indigenous Peoples: Experience and strategies for the 21st Century* 143-154 (Springer International Publishing, 2016).
18. Jérémie Gilbert, “Indigenous Peoples, Human Rights, and Cultural Heritage: Towards a Right to Cultural Integrity” in Alexandra Xanthakiet. al. (eds.), *Indigenous Peoples’ Cultural Heritage: Rights, Debates, Challenges* 20-38 (Brill Nijhoff, 2017).
19. Øyvind Ravna, “Links between Lands, Territories, Environment and Cultural Heritage – The Recognition of Sámi Lands in Norway” in Alexandra Xanthakiet. al. (eds.), *Indigenous Peoples’ Cultural Heritage: Rights, Debates, Challenges* 175-198 (Brill Nijhoff, 2017).
20. Leena Heinämäki, Thora Herrmann, et. al., “Towards Sámi Self-Determination over Their Cultural Heritage: The UNESCO World Heritage Site of Laponia in Northern Sweden” in Alexandra Xanthaki et. al. (eds.), *Indigenous Peoples’ Cultural Heritage: Rights, Debates, Challenges* 78-103 (Brill Nijhoff, 2017).
21. Tanja Joona, “ILO Convention No. 169 and the governance of indigenous identity in Finland: recent developments” 24(2-3) *The International Journal of Human Rights* 241-256 (2019).
22. Zia Akhtar, “Sámi Peoples Land Claims in Norway, Finnmark Act and Proving Legal Title” 7 *The Indigenous Peoples’ Journal of Law, Culture, and Resistance* 115-138 (2022).
23. Christina Allard, “Sámi Land Rights: Recent Developments in Swedish Case Law” 19(1) *European Yearbook of Minority Issues Online* 221-238 (2022).
24. Merle Ecker and Sabine Mannitz, “The Situation of Sámi Peoples in Sweden since 1977” in *Views about the Sámi Truth Commission: An Analysis of Public Discourse in Swedish Media 2008-2023* 8-13 (Peace Research Institute Frankfurt, 2023).
25. Sanna Valkonen, Jarno Valkonen, et. al., “An Ontological Politics of and for the Sámi Cultural Heritage – Reflections on Belonging to the Sámi Community and the Land” in *Indigenous Peoples’ Cultural Heritage: Rights, Debates, Challenges* 149-174 (Brill Nijhoff, 2017).
26. Margarita Bukovska, Alexander Shaparov and Maria Pitukhina, “Political representation of the Sámi in the countries of northern Europe” 17(1) *Baltic Region* 44-64 (2025).

Oceania region: Aotearoa (New Zealand) and Australia

1. Karen E. Bravo, "Balancing Indigenous Rights to Land and the Demands of Economic Development: Lessons from the United States and Australia" 30(4) *Columbia Journal of Law and Social Problems* 529-586 (1997).
2. Steven C. Bourassa and Ann Louise Strong, "Restitution of Land to New Zealand Maori: The Role of Social Structure" 75(2) *Pacific Affairs* 227-260 (2002).
3. Charlene Yates, "Conceptualising Indigenous Land Rights in the Commonwealth" 8(4) *Australian Indigenous Law Reporter* 96-101 (2004).
4. Michael A. Murphy, "Representing Indigenous Self-Determination" 58(2) *University of Toronto Law Journal* 185-216 (2008).
5. Rodolfo Stavenhagen, "Building Intercultural Citizenship through Education: A Human Rights Approach" 43(2) *European Journal of Education* 161-179 (2008).
6. Alexandra Xanthaki and Dominic O'Sullivan, "Indigenous Participation in Elective Bodies: The Maori in New Zealand" 16(2) *International Journal on Minority and Group Rights* 181-207 (2009).
7. Dr Maria Bargh, "Indigenous Peoples and Foreign Policy: The New Zealand Experience" 3 *Te Tai Haruru Journal* 89-98 (2010).
8. Roger Geertz González and Patricia Colangelo, "The Development of Indigenous Higher Education: A Comparative Historical Analysis between Australia, Canada, New Zealand, and the U.S., 1880-2005" 49(3) *Journal of American Indian Education* 3-23 (2010).
9. Jane Robbins, "A Nation within? Indigenous Peoples, Representation and Sovereignty in Australia" 10(2) *Ethnicities* 257-274 (2010).
10. Antony Barac and Kelly Loretta, "Affirmative Action as a Form of Special Measures in Australia: Canvassing the Hidden Issues" 17(2) *Australian Indigenous Law Review* 56-78 (2013).
11. Megan Davis, "Australia's Reconciliation Process in its International Context: Recognition and the Health & Wellbeing of Australia's Aboriginal & Torres Strait Islander Peoples" 18(2) *Australian Indigenous Law Review* 56-66 (2014).
12. Shireen Morris, "Lessons from New Zealand: Towards a better Working Relationship between Indigenous Peoples and the State" 18(2) *Australian Indigenous Law Review* 67-87 (2014).
13. Alison Vivian, Miriam Jorgensen, et al., "Indigenous Self-Government in the Australian Federation" 20 *Australian Indigenous Law Review* 215-242 (2017).
14. Katherine Smits, "Multiculturalism, Biculturalism, and National Identity in Aotearoa/New Zealand" in Richard T. Ashcroft, Mark Bevir et al. (eds.), *Multiculturalism in the British Commonwealth: Comparative Perspectives on Theory and Practice* 104-124 (University of California Press, 2019).

15. Samantha Battams, Tony Delany-Crowe, *et. al.*, “Applying Crime Prevention and Health Promotion Frameworks to the Problem of High Incarceration Rates for Aboriginal and Torres Strait Islander Populations: Lessons from a Case Study from Victoria” 12(2) *International Indigenous Policy Journal* 1-29 (2021).
16. Sofie Van Canegem, “Renewable Energy and Indigenous Peoples’ Rights: A Comparative Study of New Zealand, Norway and Canada” 25 *New Zealand Journal of Environmental Law* 61-94 (2021).
17. Karinna Saxby, Joshua Byrnes, *et. al.*, “Does affirmative action reduce disparities in healthcare use by Indigenous peoples? Evidence from Australia’s Indigenous Practice Incentives Program” 32(4) *Health Economics* 853-872 (2023).
18. Claire Charters, “A Deeper Understanding of the Constitutional Status of Māori and Their Rights Required: A Reply to Christian Riffel” 35(2) *European Journal of International Law* 469-478 (2024).
19. Emalee A. Vandermale, Jordyn Bogetti and Courtney W. Mason, “Land Use Policy Frameworks in Canada and Aotearoa New Zealand: Examining the Opportunities and Barriers of Indigenous-Led Conservation and Protected Areas” 13(6) *Land* 886 (2024).
20. Asmi Wood, “Self-Determination Under International Law and Some Possibilities for Australia’s Indigenous Peoples” in Laura Rademaker, Tim Rowse (eds.), *Indigenous Self-Determination in Australia: Histories and Historiography* 269-292 (ANUPress, 2024).
21. Jane Simpson, “Self-Determination with Respect to Language Rights” in Laura Rademaker, Tim Rowse (eds.), *Indigenous Self-Determination in Australia: Histories and Historiography* 293-314 (Australian National University Press, 2024).
22. Cathy Bow, “The Role of Universities in Training Indigenous Language Workers: Developing an Australian Indigenous Languages Institute” in John Kinder, Nicola Frascini *et. al.* (eds.), *Enabling Learning: Language Teaching for Australian Universities* 93-122 (ANUPress, 2024).
23. Ed Wensing and Bhiamie Williamson, “From Land Reparation to Land Justice: Reframing Relationships to Place Using Indigenous Australians’ Wisdom” in Nick Gkartziou *et. al.* (eds.), *Postcapitalist Countryside: From Commoning to Community Wealth Building* 213-236 (UCL Press, 2025).

North America: Canada and the United States

1. William L. Leap, "American Indian Language Maintenance" 10 *Annual Review of Anthropology* 209-236 (1981).
2. Robert S. Michaelsen, "'We Also Have a Religion: The Free Exercise of Religion among Native Americans'" 7(3) *American Indian Quarterly* 111-142 (1983).
3. Judith Resnik, "Dependent Sovereigns: Indian Tribes, States, and the Federal Courts" 56(2) *The University of Chicago Law Review* 671-759 (1989).
4. Roger Buffalohead, "Reflections on Native American Cultural Rights and Resources" 16(2) *American Indian Culture and Research* 197-200 (1992).
5. David Corson, "Official-Language Minority and Aboriginal First-Language Education: Implications of Norway's Sámi Language Act for Canada" 21(1) *Canadian Journal of Education* 84-104 (1996).
6. Karen E. Bravo, "Balancing Indigenous Rights to Land and the Demands of Economic Development: Lessons from the United States and Australia" 30(4) *Columbia Journal of Law and Social Problems* (1997).
7. Teresa L. McCarty, "Revitalising Indigenous Languages in Homogenising Times" 39(2) *Comparative Education* 147-163 (2003).
8. Paul Joffe, "UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples: Canadian Government Positions Incompatible with Genuine Reconciliation" 26(2) *National Journal of Constitutional Law* 121-229 (2010).
9. Michael A. Murphy, "Representing Indigenous Self-Determination" 58(2) *The University of Toronto Law Journal* 185-216 (2008).
10. Susan A. Miller, "Native Historians Write Back: The Indigenous Paradigm in American Indian Historiography" 24(1) *Wicazo Sa Review* 25-45 (2009).
11. Ken Coates and Greg Poelzer, "Defining Indigenous Space: The Constitutional Development of Aboriginal Property and Resource Rights in Canada" 11(1) *Georgetown Journal of International Affairs* 7-15 (2010).
12. James (Sa'ke'j) Youngblood Henderson, "Constitutional Vision and Judicial Commitment: Aboriginal and Treaty Rights in Canada" 14(2) *Australian Indigenous Law Review* 24-48 (2010).
13. Roger Geertz González and Patricia Colangelo, "The Development of Indigenous Higher Education: A Comparative Historical Analysis between Australia, Canada, New Zealand, and the U.S., 1880-2005" 49(3) *Journal of American Indian Education* 3-23 (2010).
14. Inter-American Commission on Human Rights, "Indigenous and Tribal Peoples' Rights Over their Ancestral Lands and Natural Resources: Norms and Jurisprudence of the Inter-American Human Rights System" 35(2) *American Indian Law Review* 263-496 (2011).

15. Priscila Ribeiro Prado Barros, “Recognizing Indigenous Peoples’ Rights: A Comparative Study between Brazil and Canada” 38(1) *Canadian Journal of Latin American and Caribbean Studies* 35-49 (2013).
16. Samuel E. Ennis and Caroline P. Mayhew, “Federal Indian Law and Tribal Criminal Justice in the Self-Determination Era” 38(2) *American Indian Law Review* 421-476 (2013).
17. Teresa L. McCarty and Sheilah E. Nicholas, “Reclaiming Indigenous Languages: A Reconsideration of the Roles and Responsibilities of Schools” 38 *Review of Research in Education* 106-136 (2014).
18. Bruce Granville Miller and Gustavo Menezes, “Anthropological Experts and the Legal System: Brazil and Canada” 39(4) *American Indian Quarterly* 391-430 (2015).
19. Wilfrid Greaves, “Arctic (in) Security and Indigenous Peoples: Comparing Inuit in Canada and Sámi in Norway” 47(6) *Security Dialogue* 461-480 (2016).
20. Maura Hanrahan, “Making Indigenous Culture the Foundation of Indigenous Governance Today: The Mi’kmaq Rights Initiative of Nova Scotia, Canada” 3(1) *Native American and Indigenous Studies* 75-95 (2016).
21. Jennifer Hendry and Melissa L. Tatum, “Human Rights, Indigenous Peoples, and the Pursuit of Justice” 34(2) *Yale Law and Policy Review* 351-386 (2016).
22. Øyvind Ravna and Nigel Bankes, “Recognition of Indigenous Land Rights in Norway and Canada” 24(1) *International Journal on Minority and Group Rights* 70-117 (2017).
23. Stephen Wilmot, “Cultural Rights and First Nations Health Care in Canada” 20(1) *Health and Human Rights* 283-293 (2018).
24. Dominique Leydet, “The Power to Consent: Indigenous Peoples, State and Development” 69(3) *The University of Toronto Law Journal* 371-403 (2019).
25. Brenda L. Gunn, “Remedies for Violations of Indigenous Peoples’ Human Rights” 69 *The University of Toronto Law Journal* 150-170 (2019).
26. Roberta Rice, “The Politics of Free, Prior and Informed Consent: Indigenous Rights and Resource Governance in Ecuador and Yukon, Canada” 27(2) *International Journal on Minority and Group Rights* 336-356 (2020).
27. Kristen A. Carpenter, “Aspirations: The United States and Indigenous Peoples’ Human Rights” 36 *Harvard Human Rights Journal* 41-88 (2023).
28. Rebecca Tsosie, “Climate Change and Indigenous Peoples: Comparative Models of Sovereignty” 26(2) *Tulane Environmental Law Journal* 239-257 (2013).
29. Clarita Lefthand-Begay, Lauren Redmore, *et. al.*, “From paternalism to self-determination: examining evolving tribal-federal relationships and co-management arrangements through three case studies” 12(1) *Humanities and Social Science Community* 30 (2025).

South America: Ecuador, Colombia, Brazil

1. Georgia O. Carvalho, "The Politics of Indigenous Land Rights in Brazil" 19(4) *Bulletin of Latin American Research* 461-478 (2000).
2. Maria Guadalupe Moog Rodrigues, "Indigenous Rights in Democratic Brazil" 24(2) *Human Rights Quarterly* 487-512 (2002).
3. Anthony Stocks, "Too Much for Too Few: Problems of Indigenous Land Rights in Latin America" 34(1) *Annual Review of Anthropology* 85-104 (2005).
4. J.E. Jackson, "Rights to Indigenous Culture in Colombia", in Mark Goodale and Sally Engle Merry (eds.), *The Practice of Human Rights: Tracking Law between the Global and the Local* 204-241 (Cambridge University Press, 2007).
5. Peter Wade, "Blacks and Indigenous People in Latin America" *Race and Ethnicity in Latin America* 24-40 (2010).
6. Andréa Zhouri, "'Adverse Forces' in the Brazilian Amazon: Developmentalism Versus Environmentalism and Indigenous Rights" 19(3) *The Journal of Environment and Development* 252-273 (2010).
7. Kenneth P. Jameson, "The Indigenous Movement in Ecuador: The Struggle for a Plurinational State" 38(1) *Latin American Perspectives* 63-73 (2011).
8. Rachel Sieder, "The Challenge of Indigenous Legal Systems: Beyond Paradigms of Recognition" 18(2) *The Brown Journal of World Affairs* 103-114 (2012).
9. Priscila Ribeiro Prado Barros, "Recognizing Indigenous Peoples' Rights: A Comparative Study between Brazil and Canada" 38(1) *Canadian Journal of Latin American and Caribbean Studies* 35-49 (2013).
10. Marcela Tovar-Restrepo and Clara Irazábal, "Indigenous Women and Violence in Colombia: Agency, Autonomy, and Territoriality" 41(1) *Latin American Perspectives* 39-58 (2014).
11. Enrique Uribe-Jongbloed and Carl Edlund Anderson, "Indigenous and Minority Languages in Colombia: The Current Situation" 48 *Zeszyty Łużyckie* 217-242 (2014).
12. Bruce Granville Miller and Gustavo Menezes, "Anthropological Experts and the Legal System: Brazil and Canada" 39(4) *American Indian Quarterly* 391-430 (2015).
13. Pedro Calafate, "The Rights of the Indigenous Peoples of Brazil: Historical Development and Constitutional Acknowledgement" 25(2) *International Journal on Minority and Group Rights* 183-209 (2018).
14. Juan José Guzmán, "Decolonizing Law and Expanding Human Rights: Indigenous Conceptions and the Rights of Nature in Ecuador" *Deusto Journal of Human Rights* 59-86 (2019).
15. Roberta Rice, "The Politics of Free, Prior and Informed Consent: Indigenous Rights and Resource Governance in Ecuador and Yukon, Canada" 27(2) *International Journal on Minority*

and Group Rights 336-356 (2020).

16. Schilling-Vacaflor, Almut, and Riccarda Flemmer, "Mobilising Free, Prior and Informed Consent (FPIC) from Below: A Typology of Indigenous Peoples' Agency" 27(2) *International Journal on Minority and Group Rights* 291-313 (2020).
17. Mohammadreza Jodyvash, "The Role of Cultural Pluralism in Indigenous Peoples' Defence of Nature's Rights: A Case Study of Ecuador" 15(4) *Oñati Socio-Legal Series* 1552-1580 (2025)
18. Gray Clark and Richard Bilborrow, "Stability and Change Within Indigenous Land Use in the Ecuadorian Amazon" 63 *Global Environmental Change* (2020).
19. Rossano Lopes Bastos, Cristiane Derani, *et. al.*, "Cultural Heritage and Traditional Knowledge: Some Reflexions About Indigenous Rights In Brazil" 7(2) *Brazilian Journal of Development* 12030-12043 (2021).
20. José Aldemar Álvarez Valencia and Manuela Wagner, "Roadblocks to Intercultural Mobility: Indigenous Students' Journeys in Colombian Universities" 4(1) *Intercultural Communication Education* 6-21 (2021).
21. L. Etchart, "Indigenous Peoples and International Law in the Ecuadorian Amazon" 11(4) *Laws* 55 (2022).
22. Edison Luzuriaga, Julio López, *et. al.*, "Interpretation of the Historical Evolution of Indigenous Law in Ecuador and its Paradigmatic Constitutional Location" 15(5) *University and Society: Towards a Process of Continuous Improvement* 587-596 (2023).
23. Eva Davtyan, "Language and Representation of Indigenous Knowledge in Ecuadorian Radio Programs" 3(1) *Journal of Linguistics and Communication Studies* 10-17 (2024).
24. M.A. Ramírez-Salazar, O.A. Guirette-Barbosa, *et. al.*, "Assessing Progress on Indigenous Self-Determination Rights: Comparative Insights from Chile, Colombia, and Mexico" 14(11) *Societies* 218 (2024).
25. Carlos Acosta, Carlos Llucca, *et. al.*, "The Principle of Innocence in the Administration of Indigenous Justice in Ecuador" 5(2) *International Journal of Interdisciplinary Studies* 1-8 (2024).
26. Caroline Martinez, "Indigenous Identity and Struggles for State Recognition in Ecuador" *Sociology of Race and Ethnicity* (2025).
27. Enrique Ferruzola-Gómez, Claudia Chávez-Morales, *et. al.*, "Intergenerational gaps and linguistic decline in Ecuador's indigenous communities: A socio-legal analysis" 8(2) *International Journal of Innovative Research and Scientific Studies* 3917-3927 (2025).
28. Gisele Jabur and Carlos Frederico Marés de Souza Filho, "The State and the Rights of Isolated Indigenous Peoples: Lessons from Brazil and Colombia" 19(9) *Revista de Gestão Social e Ambiental* (2025).
29. Jennifer M. Piscopo and Kristin N. Wylie, "Gender, Race, and Political Representation in Latin America" *Oxford Research Encyclopaedia of Politics* (2020).

30. Angela Marcela Olarte Delgado, “Attempts in Strengthening Indigenous Justice Systems in Colombia Through Transitional Justice” 14(2) *International Journal for Crime, Justice and Social Democracy* 83-95 (2025).

अध्याय V: निष्कर्ष

यह संदर्भ नियमावली भारत पर विशेष ध्यान देने के साथ अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर स्वदेशी लोगों के अधिकारों की रक्षा करने वाले कानूनी, संवैधानिक और संस्थागत ढांचे की व्यापक और महत्वपूर्ण जांच प्रदान करने का प्रयास करती है। इस उद्देश्य की दिशा में, यह संदर्भ नियमावली अंतर्राष्ट्रीय मानकों को समय के साथ विकसित करती गई है, स्वदेशी लोगों की सुरक्षा को विनियमित करती है, और नॉर्डिक, ओशिनिया, उत्तर अमेरिकी और दक्षिण अमेरिकी क्षेत्रों में चुनिंदा क्षेत्राधिकारों के तुलनात्मक परिदृश्य के साथ भारत के दृष्टिकोण को बेहतर बनाने का प्रयास करती है। इस प्रक्रिया में, यह संदर्भ नियमावली स्वदेशी लोगों के अस्तित्व, गरिमा और उन्नति के लिए प्रासंगिक विषयों को संबोधित करती है, जिसमें आत्मनिर्णय, स्व-शासन, भागीदारी और परामर्श, पैतृक भूमि का अधिकार, पारंपरिक क्षेत्रों, वनों और संसाधनों पर कब्जा, सांस्कृतिक प्रथाओं, भाषा और धर्म का संरक्षण; व्यक्तिगत कानूनों और न्यायिक प्रणालियों के लिए स्वीकृति, गैर-भेदभाव और सकारात्मक कार्रवाई शामिल हैं।

इस संदर्भ ने ऐतिहासिक न्यायोचित ज्ञान की पुष्टि करते हुए दुनिया भर के स्वदेशी लोगों की जीवित वास्तविकताओं को आकार दिया है। अपने इलाकों के मूल निवासी और प्राकृतिक पर्यावरण के संरक्षक होने के बावजूद, मूल निवासियों को लंबे समय से व्यवस्थित रूप से हाशिए पर धकेला गया है, उनसे उनकी ज़मीन छीनी गई है और उनकी संस्कृति को मिटाने की कोशिश की गई है। ऐसा उपनिवेशवाद, जीत, बसावट और/या कब्जे के कारण हुआ है। नतीजतन, अपनी पैतृक ज़मीन, संप्रभुता और पारंपरिक जीवन शैली पर मूल निवासियों के जन्मसिद्ध अधिकारों को काफी हद तक नज़रअंदाज़ किया गया है, जिससे वे ऐसे मामलों में कोई फ़ैसला लेने की क्षमता से वंचित हो गए हैं जो सीधे तौर पर उन्हें प्रभावित करते हैं। विदेशी शासन प्रणालियों, कानूनी मानदंडों और तौर-तरीकों, जीवन शैलियों को थोपने, साथ ही उनके पारंपरिक इलाकों पर कब्जा करने—जिसका मकसद मूल निवासियों को 'मुख्यधारा' के समाज में 'मिलाना' या 'शामिल करना' और ज़बरदस्ती 'आधुनिक' बनाना था, ने असल में उन्हें अलग-थलग कर दिया है, उन्हें 'पराया' बना दिया है और यहाँ तक कि उनके मानवाधिकारों का भी व्यापक का कारण बना है।

ऊपर बताई गई बातों को ध्यान में रखते हुए, यह शोध नियमावली अंतर्राष्ट्रीय कानूनी उपकरणों के विकास का पता लगाती है, जो प्रारंभिक वर्षों में, स्वदेशी अधिकारों की गारंटी देने का प्रयास करते हुए, स्वदेशी लोगों की समस्याग्रस्त अवधारणाओं को विकास के "कम उन्नत चरण" में होने के रूप में भी प्रचारित करती है, जो पूर्ववर्ती दृष्टिकोण को दर्शाती है। धीरे-धीरे, स्वदेशी नेताओं और समूहों द्वारा दशकों की वकालत के बाद, एक अधिक व्यापक, व्यापक अधिकार-आधारित ढांचे से महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं जो स्वदेशी लोगों की स्वायत्तता, सम्मान और विशिष्टता की पुष्टि करता है। इस बदलाव में मुख्य बातें ये हैं: किसी की स्वदेशी पहचान को परिभाषित करने के लिए प्राथमिक मानदंड के रूप में आत्म-पहचान की स्थापना, उनकी भूमि, क्षेत्रों और संसाधनों के लिए उनके सामूहिक अधिकारों की स्पष्ट मान्यता, आत्म-निर्धारण के लिए सम्मान, सांस्कृतिक और भाषाई पहचान का संरक्षण, निर्णय में सार्थक भागीदारी का अधिकार; भूमि और संसाधनों पर सुरक्षा।

यह वैश्विक परिवर्तनवाद अधिकांश राष्ट्रीय क्षेत्राधिकारों की घरेलू प्रणालियों में असंवैधानिक, विधायी और संस्थागत उपायों के माध्यम से प्रकट हुआ। भारत पर खास तौर पर ध्यान देते हुए, यह संदर्भ पुस्तिका उन सदियों के उत्पीड़न का वर्णन करती है जो आदिवासी समुदायों को झेलना पड़ा है, जो ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन की उपज नहीं थी, लेकिन प्राचीन भारतीय मानस में व्यवस्थित रूप से स्थापित थी। हालाँकि, ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के तहत आदिवासी समुदायों के अधीनता तेज हो गई, जिसने प्रकृति के साथ उनके पारंपरिक सहजीवी संबंधों को बाधित कर दिया। ब्रिटिश भारतीय राज्य ने आपराधिक जनजाति अधिनियम, 1871, 1911 और 1924 जैसे कानून बनाए, इस प्रकार पूरे आदिवासी समुदायों को अपराधियों के रूप में ब्रांडिंग करके और उन्हें व्यवस्थित पंजीकरण, निगरानी और नियंत्रण के अधीन करके पहले से मौजूद पूर्वाग्रहों को संस्थागत बना दिया। अनुसूचित ज़िला अधिनियम, 1874 और भारत सरकार अधिनियम, 1919 और 1935 के तहत अलग-अलग प्रशासनिक प्रभागों का निर्माण, मुख्य रूप से आदिवासी समुदायों द्वारा बसे क्षेत्रों के लिए उन्हें मुख्यधारा के समाज से अलग करने का कारण बना। यह दृष्टिकोण, व्यवहार में, असल में, इस तरीके ने संसाधनों से भरपूर आदिवासी इलाकों पर औपनिवेशिक नियंत्रण को मज़बूत किया और वहाँ के निवासियों को ऐसे अलग-थलग और हाशिए पर रहने वाले लोगों के तौर पर देखा जिन पर सिर्फ़ शासन किया जाना था, न कि ऐसे नागरिकों के तौर पर जिनके पास जन्मसिद्ध अधिकार हों।

औपनिवेशिक विरासत ने आज़ादी के बाद इस बात पर होने वाली चर्चा को गहराई से प्रभावित किया कि आदिवासी समुदायों को संवैधानिक सुरक्षा कैसे दी जानी चाहिए। जयपाल सिंह मुंडा जैसे प्रमुख आदिवासी नेताओं का हस्तक्षेप, जिन्होंने संविधान सभा की बहसों में औपनिवेशिक दमन-आदिवासी समुदायों की व्यापक रूप से आलोचना की और इस बात पर जोर दिया कि उनके अधिकार को "हर भारतीय के समान" माना जाता है, जो भारत के संविधान, 1950 के तहत महत्वपूर्ण थे, मान्यता और संरक्षण-आदिवासी समुदायों को मज़बूती प्रदान करते थे। भारत का संविधान, 1950 अनुच्छेद 366(25) के तहत (कुछ, लेकिन सभी नहीं) आदिवासी समुदायों को 'अनुसूचित जनजाति' के रूप में मान्यता देता है, जो एक अलग कानूनी श्रेणी है और जिसे विशेष अधिकार और सुरक्षा मिलती है। इनमें न केवल अनुच्छेद 14, 15 और 17 के तहत समानता और गैर-भेदभाव के सार्वभौमिक अधिकार शामिल हैं, बल्कि शिक्षा और सार्वजनिक रोजगार में आरक्षण के लिए प्रावधानों को निर्दिष्ट करना भी शामिल है, जिनकी न्यायिक रूप से व्याख्या समानता के अपवाद के रूप में नहीं की गई है। चुनावी सीटों के आरक्षण के ज़रिए राजनीतिक प्रतिनिधित्व भी सुनिश्चित किया जाता है। ज़मीन और संसाधनों पर स्वायत्तता (खुद का नियंत्रण) के महत्व को समझते हुए, संविधान की पाँचवीं और छठी अनुसूचियाँ उन इलाकों में स्व-शासन और स्वायत्तता के लिए व्यवस्था करती हैं जहाँ आदिवासी आबादी ज़्यादा है। यह संदर्भ पुस्तिका न्यायपालिका की अहम भूमिका पर भी ज़ोर देती है, जो यह सुनिश्चित करती है कि अनुसूचित जनजातियों के मौलिक और संवैधानिक अधिकारों को प्रभावी ढंग से लागू किया जाए और वे केवल कागज़ पर ही सीमित न रह जाएँ।

यह संदर्भ पुस्तिका समानता, न्याय और निष्पक्षता के संवैधानिक वादों को लागू करने वाली विधायी रूपरेखा को आगे बढ़ाता है। पीओए अधिनियम, 1989 अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के साथ अक्सर होने वाले दुर्व्यवहार और हिंसा के खिलाफ कानूनी साधन प्रदान करता है। पेसा, 1996 स्व-शासन के सिद्धांत को लागू करता है;

यह मानता है कि सार्थक स्वायत्तता की शुरुआत समुदाय के स्तर से होनी चाहिए, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहां आदिवासी जीवन स्थानीय भूमि, रीति-रिवाजों और परंपराओं के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है। एफआरए, 2006 अनुसूचित जनजातियों और ओटीएफडी पर वनों के कब्जे, उपयोग और शोषण से संबंधित अधिकार निहित करता है। अंत में, एल. ए. आर. अधिनियम, 2013 जैसे कानूनों में विशेष प्रावधान शामिल हैं जो सहमति को अनिवार्य करते हैं और भूमि अधिग्रहण के मामलों में अनुसूचित जनजातियों के लिए सुरक्षा बढ़ाते हैं। इन अधिनियमों के साथ-साथ इससे उपजी न्यायिक मिसालें केवल एकीकरण से आगे बढ़ने और अधिकारों की रक्षा करने, पहचान को संरक्षित करने और स्वायत्तता को बढ़ावा देने वाले ढांचे का निर्माण करने के एक व्यापक प्रयास को दर्शाती हैं।

इस संदर्भ नियमावली का अंतिम भाग उन विशिष्ट तरीकों के तुलनात्मक विश्लेषण से प्राप्त अंतर्दृष्टि का दस्तावेजीकरण करता है जिनमें स्वदेशी लोगों को उनके संबंधित घरेलू ढांचे के भीतर पहचाना और संरक्षित किया जाता है। नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड के नॉर्डिक देशों में, संवैधानिक मान्यता और सामी संसदों की स्थापना के माध्यम से स्वदेशी सामी लोगों के अधिकारों को मजबूत किया गया है, हालांकि उनकी शक्तियां काफी हद तक परामर्शात्मक बनी हुई हैं। पूरे ओशिनिया क्षेत्र में, स्वदेशी-राज्य संबंध एक तीव्र विरोधाभास प्रस्तुत करते हैं। जबकि आओटेरोआ (न्यूजीलैंड) में राज्य और स्वदेशी माओरी के बीच संबंधों की मध्यस्थता वैतांगी की संधि के माध्यम से की जाती है, जिससे सह-शासन और माओरी प्रथागत कानून की मान्यता के लिए एक अनूठा स्थान बनता है, ऑस्ट्रेलिया ने आदिवासी और टोरेस जलडमरूमध्य के लोगों को संघीय संवैधानिक मान्यता देने के लिए संघर्ष किया है।

इस बीच, उत्तरी अमेरिका अंतर्निहित संप्रभुता और शासन-से-शासन संबंधों की अवधारणाओं पर आधारित एक मॉडल प्रदान करता है। कनाडा में, संविधान अधिनियम, 1982, प्रथम राष्ट्रों, इनुइट और मैटिस लोगों के मौजूदा "आदिवासी और संधि अधिकारों" को स्पष्ट रूप से मान्यता देता है और उनकी पुष्टि करता है, जिससे ऐतिहासिक और आधुनिक संधियों की दोहरी प्रणाली को जन्म मिलता है जो भूमि, संसाधनों और स्वशासन के अधिकारों को परिभाषित करती है। इसी तरह, संयुक्त राज्य अमेरिका संघीय रूप से कुछ जनजातियों को स्वशासन की अंतर्निहित शक्तियों के साथ "घरेलू आश्रित राष्ट्रों" के रूप में मान्यता देता है, हालांकि यह संप्रभुता संघीय कांग्रेस की पूर्ण शक्ति के अधीन है। दक्षिण अमेरिका में, इक्वाडोर और कोलंबिया जैसे देशों के संविधान एक बहुराष्ट्रीय राज्य, स्वदेशी न्याय प्रणालियों और प्रकृति के संबंध में स्वदेशी लोगों के अधिकारों की प्रगतिशील मान्यता के लिए उल्लेखनीय हैं। ब्राजील का संविधान भी स्वदेशी भूमि के लिए मजबूत सुरक्षा प्रदान करता है; हालांकि, ये अधिकार गंभीर खतरे में आ गए हैं, जिसका उदाहरण 'मार्को टेम्पोरल' सिद्धांत के संबंध में राजनीतिक और न्यायिक संघर्ष है।

इन मॉडलों की जांच से कुछ पैटर्न का पता चलता है: स्वदेशी अधिकारों के मामले में सार्थक प्रगति करने वाले देशों ने मजबूत गैर-कमजोर सुरक्षा प्रदान की है, जिन्हें ज्यादातर संवैधानिक गारंटी के रूप में संस्थागत किया गया है। इसके अतिरिक्त, भूमि और संसाधन अधिकार लगातार वास्तविक स्वदेशी स्वायत्तता की आधारशिला के रूप में उभरते हैं। पैतृक क्षेत्रों पर सुरक्षित नियंत्रण के बिना, अन्य अधिकार नाजुक बने रहते हैं। इस नज़रिए से देखें तो, स्वदेशी अधिकारों की मान्यता और संरक्षण पर अंतर्राष्ट्रीय, भारतीय और तुलनात्मक दृष्टिकोण को एक साथ लाने वाला यह संदर्भ नियमावली संकलन

से कहीं ज़्यादा है। यह कई प्रासंगिक प्रश्न उठाता है जिनके लिए आगे आलोचनात्मक विचार की आवश्यकता होती है: स्वदेशी लोगों को अलग-थलग किए बिना स्वायत्तता की रक्षा कैसे की जा सकती है? वास्तविक भागीदारी कैसे सुनिश्चित की जाए? मूल रूप से, इन अधिकारों को स्वदेशी लोगों के लिए जीवित वास्तविकताओं में कैसे बदला जाए? इस संदर्भ नियमावली द्वारा दी गई अंतर्दृष्टि एक सामान्य संदेश को पुष्ट करती है: स्वदेशी अधिकारों की गारंटी देने वाला कोई भी ढांचा अनिवार्य रूप से स्वदेशी लोगों के सम्मान, उनकी अपनी एजेंसी और अपने भविष्य को आकार देने की वास्तविक क्षमता पर बनाया जाना चाहिए, जो पुराने एकीकरणवादी और एकीकरणवादी दृष्टिकोण से बिल्कुल अलग और नया नज़रिया है।